वार्षिक रिपोर्ट

2009 - 2010

विदेश मंत्रालय

भारत सरकार

द्वारा प्रकाशित:
नीति नियोजन और अनुसंधान विभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

यह वार्षिक रिपोर्ट इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:
www.mea.gov.in

आवरण:
श्री काशी नाथ दास द्वारा पानी के रंगों से चित्रित केन्द्रीय सचिवालय के भवन

रूपरेखा एवं मुद्रण:
साइबरआर्ट इनफारमेशंस प्रा. लि.
1517 हेमकुन्ट चैम्बरस, 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110 019
ईमेल: cyberart.mail@gmail.com
वैबसाइट: www.cyberart.co.in / 0120-4231676

विषय सूची

प्रस्तावना और सारांश		i-xix
1	भारत के पड़ोसी देश	1
2	दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत	19
3	पूर्व एशिया	28
4	यूरेशिया	35
5	खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका	42
6	अफ्रीका (सहारा से दक्षिण)	52
7	यूरोप	70
8	अमरीका	92
9	संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	109
10	निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामले	127
11	बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	132
12	सार्क प्रभाग	138
13	तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग तथा विकास भागीदारी	140
14	निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन	143
15	ऊर्जा सुरक्षा	145
16	नीति आयोजना और अनुसंधान	146
17	प्रोतोकोल	149
18	कोंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं	157
19	प्रशासन और स्थापना	160
20	समन्वय	164
21	विदेश प्रचार	165
22	लोक राजनय प्रभाग	168
23	विदेश सेवा संस्थान	171
24	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार	173
25	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	176
26	भारतीय विश्व कार्य परिषद	180
27	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	183
28	पुस्तकालय	188

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	वर्ष 2009-10 के दौरान मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों में संवर्ग संख्या (इनमें वाणिज्य मंत्रालय के बजट से प्रदान किए गए पद और संवर्ग बाह्य पद इत्यादि शामिल हैं)।	193
परिशिष्ट II	विदेश मंत्रालय में अप्रैल 2009 से नवम्बर 2009 तक सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति और सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ की गई भर्ती संबंधी आंकड़े।	194
परिशिष्ट III	विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की संख्या	195
परिशिष्ट IV	1 जनवरी से 30 नवंबर 2009 तक प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदन पत्रों और तत्काल योजना सहित जारी किए गए पासपोर्टों, विविध आवेदन पत्रों की संख्या और प्रदत्त सेवाएं एवं राजस्व (तत्काल योजना के तहत राजस्व सहित) और पासपोर्ट कार्यालयों के व्यय संबंधी आंकड़े को दर्शाने वाला विवरण।	196
परिशिष्ट V	विदेश मंत्रालय का वास्तविक व्यय और 2004-09, ब.प्रा. व सं.प्रा. (2009-2010) (राजस्व और पूंजी)	197
परिशिष्ट VI	वर्ष 2009-10 में मुख्य क्षेत्रवार आबंटन (संशोधित प्राक्कलन) (राजस्व और पूंजी)	198
परिशिष्ट VII	भारत के सहायता कार्यक्रमों के मुख्य गंतव्य	199
परिशिष्ट VIII	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विदेश मंत्रालय संबंधी रिपोर्ट से उद्घृत अंश	200
परिशिष्ट IX	की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी की स्थिति (वित्तीय वर्ष-2003-2009)	201
परिशिष्ट X	वर्ष 2009 में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत की गयी संधियां/अभिसमय/करार	202
परिशिष्ट XI	1 जनवरी, 2009 से दिसंबर, 2009 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए पूर्ण अधिकार के दस्तावेज	209
परिशिष्ट XII	1 जनवरी, 2009 से दिसंबर, 2009 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेज	210
परिशिष्ट XIII	अवधि के दौरान नीति नियोजन तथा अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वित्त पोषित की गई संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित/आयोजित सम्मेलन/संगोष्ठियां/अध्ययन परियोजनाएं	211
परिशिष्ट XIV	आइटेक भागीदार देशों की सूची	212
परिशिष्ट XV	पैनल में शामिल आइटेक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची	214
परिशिष्ट XVI	संगोष्ठियां/सम्मेलन/व्याख्यान/बैठकें: अप्रैल 2009-मार्च 2010	215
परिशिष्ट XVII	आरआईएस द्वारा आयोजित संगोष्ठिया	218
	संक्षिप्तियाँ	219

प्रस्तावना और सारांश

भारत की विदेश नीति देश की बुनियादी सुरक्षा और विकास संबंधी प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह जुड़ी है। हम एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की इच्छा रखते हैं, जिसमें भारत के हित सुनिश्चित हो; भारत की निर्णय लेने संबंधी स्वायत्तता के लिए सुरक्षोपाय हों; और जो इन सबसे ऊपर देश के त्वरित, दीर्घकालिक तथा सर्वव्यापी सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए सहायक हो। इस उद्देश्य के लिए भारतीय विदेश नीति में हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति एक दृढ़ वचनबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हुए बदलाव की सक्रिय अनुकूलता के गुण विद्यमान हैं।

हमारे नीतिगत उद्देश्यों का केंद्र एक शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित पड़ोस, प्रमुख शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं संतुलित संबंध और विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभकारी भागीदारी है। हमारे समय के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे शांति और सुरक्षा, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे का सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन भी शामिल हैं, का वैश्विक आयाम है और इसके लिए सहयोगी वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है।

वर्ष 2009-10 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की स्थिति में विदेश नीति क्षेत्र चुनौतियों का साक्षी रहा। इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया गया और साथ ही अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की गईं।

भारत की हमारे उपमहाद्वीप के सभी पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ और अच्छे पड़ोसी संबंधों के प्रति वचनबद्धता समानता और परस्पर सम्मान के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। भारत भूटान को अपने नवीन स्थापित लोकतंत्र को एकजुट करने में सहयोग करने के प्रति वचनबद्ध है। दिसंबर 2009 में भूटान के पांचवें नरेश महामहिम जिग्मे खेशर नामग्यांल वांग्चुक की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ एवं सुदृढ़ हुए। भारत ने नेपाल को एक स्थायी, शांतिपूर्ण और सम्पन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित होने में अपना मजबूत समर्थन जारी रखा। अगस्त 2009 में प्रधान मंत्री माधव कुमार नेपाल की भारत यात्रा और फरवरी 2010 में राष्ट्रपति राम बरन यादव की यात्रा से मैत्रीपूर्ण सहयोग की प्रगाढ़ता में मजबूती और नेपाल के साथ हमारे विलक्षण एवं बहुआयामी संबंध सुदृढ़ हुए। बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का बांग्लादेश के साथ सहयोग के कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव रहा। जनवरी 2010 में प्रधान मंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत हुए। बांग्लादेश में अवसंरचना विकास के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण देने की भारत की वचनबद्धता और प्रधान मंत्री हसीना का यह आश्वासन कि बांग्लादेश की भूमि से भारत विरोधी कार्यकलाप चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इस ऐतिहासिक यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिणाम थे। वर्ष 2009-10 के दौरान अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का सहयोग और योगदान और सुदृढ़ हुआ। श्रीलंका के साथ भारत के संबंध और विकसित तथा भारत एवं श्रीलंका ने उच्चस्तरीय संबंध बनाए रखा एवं भारत ने तमिल अल्पसंख्यकों के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापित करने तथा देश के युद्ध पीड़ित क्षेत्रों के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता की पेशकश की।

भारत ने अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के अलावा सार्क के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर सार्क को क्षेत्रीय एकजुटता के प्रभावी साधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्य करना जारी रखा।

भारत चीन के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। इस संबंध की जटिल प्रकृति के बावजूद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय राजनैतिक तालमेल जारी रहे। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ के साथ येकातेरिनबर्ग (जून 2009) में और प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ के साथ हुआ हिन (अक्तूबर 2009) में मुलाकात हुई। इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच सभी मसलों पर होने वाले संस्थागत वार्ता तंत्र में प्रगति हुई। दोनों देशों ने डब्ल्यूटीओ वार्ता का दोहा दौर, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक संकट इत्यादि जैसे मसलों पर एक जैसी चिंता होने के कारण वैश्विक मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत करना जारी रखा।

अमरीका और रूस के साथ भारत के संबंध न केवल मजबूत हुए हैं अपितु सामरिक सहयोग के नए क्षेत्रों के शामिल होने के साथ ही उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। अमरीका के साथ भारत के कार्यकलापों में आपसी रुचि के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं विश्व स्तर पर विस्तार हुआ है। भारत और अमरीका, दोनों देशों की नई सरकारों ने मौजूदा राजनीतिक एवं आर्थिक सहभागिता

को सुदृढ़ करने और उसे पारस्परिक लाभ के लिए नए मुकाम तक ले जाने की अपनी-अपनी ठोस प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन की जुलाई 2009 में हुई यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संयुक्त रूप से भारत-अमरीका संबंधों की एक नई कार्य सूची की घोषणा की। भारत-अमरीकी सामरिक साझेदारी को प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की नवंबर 2009 की अमरीका यात्रा से और बल मिला। यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. सिंह और राष्ट्रपति ओबामा द्वारा भारत और अमरीका के बीच वैश्विक सामरिक साझेदारी का एक नया चरण शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि के दौरान अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना रहा। सामान और सेवाओं के क्षेत्र में जनवरी-अक्तूबर 2009 की अवधि के दौरान सामग्रियों और सेवाओं में भारत-अमरीका द्विपक्षीय व्यापार कुल 59.8 बिलियन अमरीकी डालर रहा।

सितंबर 2009 में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील की रूस की राजकीय यात्रा, प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की ब्राजील-रूस-भारत-चीन (ब्रिक) और शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक के लिए जून 2009 में और वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए पुनः दिसंबर में रूस की यात्रा से भारत-रूस संबंधों में निरंतर मजबूती आयी है। प्रधान मंत्री की दिसंबर में हुई यात्रा के दौरान सामरिक भागीदारी को और व्यापक बनाने पर संयुक्त घोषणापत्र जारी करने, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु एक करार पर स्वीकृति देने और रक्षा से संबंधित सहयोग पर करारों से दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध मजबूत होना दर्शाता है।

2009-10 के दौरान भारत-यूरोपीय संघ सामरिक भागीदारी को नई ऊर्जा प्रदान की गई। यूरोपीय संघ के साथ भारत के बहु-आयामी रिश्ते विभिन्न क्षेत्रों में गहन हुए, जो प्रतिरक्षा और सुरक्षा से लेकर संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों तक फैले रहे। 10वां भारत-यूरोपीय संघ सम्मेलन नई दिल्ली में 6 नवंबर, 2009 को आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों की समीक्षा की गयी और सहयोग के ठोस क्षेत्रों की पहचान की गयी।

यूरोप के देशों के साथ संबंध उच्च स्तरीय दौरों, संसदीय आदान-प्रदानों, सिविल समाज वार्ताओं आदि से पूर्ण रहे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने अप्रैल में स्पेन की और अक्तूबर, 2009 में यूके की यात्रा की। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जी-8/जी-5 की शिखर बैठक के लिए इटली की और जुलाई 2009 में बैस्टाइल दिवस समारोह के लिए फ्रांस की यात्रा की।

विगत वर्ष के दौरान, भारत ने पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और लाटीन अमरीकी देशों के साथ अपने राजनीतिक व आर्थिक संबंधों को बढ़ाना जारी रखा। पूर्वी एशिया और प्रशांत देशों के साथ संबंध भारत की 'पूर्वोन्मुख' नीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है। पूर्वी एशिया के साथ हमारे संबंध जापानी प्रधान मंत्री श्री यूकियो हातोयामा (दिसंबर 2009), मलेशियाई प्रधान मंत्री डेटो श्री मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रजाक (जनवरी 2010) और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री ली म्यंग-बैक (जनवरी 2010) की भारत यात्रा से सुदृढ़ हुए। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ हमारे संबंध अनेक क्षेत्रों में सुदृढ़ हुए हैं। निकटपूर्व के फिलीस्तीनी शरणार्थियों (यूएनआरडब्ल्यूए) के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी में भारत का वार्षिक अंशदान 20,000 अमरीकी डालर से बढ़कर 1 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। खाड़ी क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण हित रहा है, जहां लगभग 4.5 मिलियन भारतीय रहते हैं और कार्य करते हैं। भारत, तेल और गैस के अपने आयात को बढ़ाते हुए खाड़ी के अलग-अलग देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है।

भारत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। संबंधों में सिर्फ विविधता ही नहीं आयी है, अपितु शीर्ष स्तर पर उसका परिपोषण किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील सितंबर 2009 में राजकीय यात्रा पर तजाकिस्तान गयीं और वर्ष के दौरान विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की यात्रा की।

भारत अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को समेकित करने में लगा रहा। 53 अफ्रीकी संघ देशों में से 47 देश भारत सरकार के पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना में शामिल हुए हैं और दूरस्थ शिक्षा और दूरस्थ-चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। संबंधों की गति उच्चस्तरीय दौरों के माध्यम से भी बनाए रखी गयी है। नामीबिया के राष्ट्रपति ने (30 अगस्त-3 सितंबर 2009 तक) भारत का राजकीय दौरा किया। भारत के उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने 5-11 जनवरी, 2010 तक जांबिया, मलावी और बोत्सवाना की यात्रा की।

लातीन अमरीकी तथा कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंध सक्रिय बहुक्षेत्रीय वार्ता के माध्यम से वर्ष के दौरान चलते रहे। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नवंबर 2009 में चोगम सम्मेलन के लिए त्रिनिदाद और टोबेगो की यात्रा की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति डॉ. क्रिस्टीना के फर्नान्डेज किर्चनेर ने अक्तूबर 2009 में भारत की राजकीय यात्रा की। लातीन अमरीकी और कैरेबियाई क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंध अवधि के दौरान बढ़े।

वर्ष 2009-10 के दौरान भारत के बहुपक्षीय आर्थिक क्रियाकलाप और व्यापक तथा विविधतापूर्ण हुए हैं। यह प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जी-8 आउटरीच और जी-5 शिखर बैठक (8-10 जुलाई, 2009), ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) का प्रथम औपचारिक शिखर बैठक (15-17 जून, 2009), जी-20 पीट्सबर्ग (सितंबर, 2009) भारत-आसियान शिखर बैठक

और पूर्वी-एशिया शिखर बैठक (24-25 अक्तूबर, 2009) में भागीदारी से स्पष्ट हो गया। भारत एएसईएम, बीआईएमएसटीईसी, मेकांग-गंगा सहयोग, आईओआर-एआरसी और जी-15 जैसे क्षेत्रीय समूहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा है। सामानों के भारत-आसियान एफटीए पर हस्ताक्षर जो कि 1 जनवरी, 2010 से प्रकार्यात्मक हो गया है, विश्व के साथ वर्ष 2009 में भारत के आर्थिक क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण मीलस्तंभ रहा।

वित्तीय एवं आर्थिक संकट के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने अन्य देशों की तुलना में बेहतर विकास किया और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज बढ़ने वालों में एक बना रहा, जिसके विकास की दर 2009-10 के दौरान 7% से अधिक पहुंच जाने की संभावना है। भारत जी-20 का एक सक्रिय सदस्य है और जी-20 के शिखर बैठकों के निर्णयों, जिनमें सितंबर 2009 में हुए पीट्सबर्ग सम्मेलन में मंदी को रोकने तथा विश्व अर्थव्यवस्था की त्वरित बहाली एवं पुनर्जीवित करने संबंधी निर्णय भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन को महत्व प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में भारत ने यह सुनिश्चित करने की इच्छा प्रकट की है कि वैश्विक आर्थिक मुद्दों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय निर्माण को लोकतांत्रिक रूप दिया जाए, ताकि उनके मौजूदा वास्तविकताओं को प्रदर्शित किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन का मुद्दा इस अवधि के दौरान भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख मुद्दा रहा। इस मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण हमेशा से भारत के विकास की गुंजाइश को कायम रखना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने की अनिवार्यता द्वारा निर्देशित होने का रहा है। यद्यपि दिसंबर 2009 में कोपनहेगन में आयोजित शिखर बैठक में जलवायु परिवर्तन पर एक विधिसम्मत बाध्यकारी करार पर सहमति नहीं हो सकी है, किंतु भारत कोपनहेगन समझौते को निष्पादित करने में अमरीका के साथ-साथ चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (बेसिक समूह) के साथ अग्रणी देशों में शामिल रहा। भारत इस समझौते को यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत कोपनहेगन के बाद की प्रक्रिया में वार्ता को सुगम बनाने के एक राजनैतिक दस्तावेज के रूप में देखता है।

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने के लिए कार्य करता रहा। इस अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार करने सहित उसमें व्यापक सुधार लाने और उसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए दवाब डालने के अपने प्रयासों को भारत ने जारी रखा।

पड़ोसी देश

अफगानिस्तानः वर्ष के दौरान अफगानिस्तान के बढ़ते तालिबानीकरण और अफगानिस्तान में हमारे कार्मिकों, प्रतिष्ठानों और परियोजनाओं पर होते हमलों के कारण आंतरिक सुरक्षा परिस्थितियों में निरंतर आती गिरावट भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रही। काबुल स्थित भारतीय राजदूतावास को लक्ष्य बनाकर 9 अक्तूबर, 2009 को किए गए हमले के पश्चात भारत सरकार ने भारतीय और अफगानिस्तान के लोगों और उनकी चिरस्थायी मैत्री के विरुद्ध लक्ष्य बना कर किए गए कायरतापूर्ण हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने हमले के तत्काल बाद काबुल का दौरा किया और राष्ट्रपति करजई, विदश मंत्री स्पांटा और अन्य नेताओं से मुलाकात की। 26 फरवरी, 2010 को काबुल में हुए आतंकी हमले में सात भारतीयों सहित कई लोग मारे गए एवं कई अन्यों को गंभीर चोटें आईं। जीवन की हुई क्षति पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए सरकार ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के ऐसे कायरतापूर्ण हमलों की परवाह किए बगैर अफगानिस्तान के साथ उसके विकास भागीदार के रूप में कार्य करता रहेगा।

भारत अफगानिस्तान की सरकार और लोगों को एक स्थिर, लोकतांत्रिक और बहुलवादी समाज का निर्माण करने में सहायता देने में अग्रणी देश रहा है। अफगानिस्तान की सरकार के साथ गहन राजनीतिक परामर्श और उसके नेतृत्व के साथ नियमित उच्चस्तरीय संपर्क होते रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान में 20 अगस्त, 2009 को हुए राष्ट्रपति के और प्रांतीय परिषद के चुनावों के सफल आयोजन का स्वागत किया है। 19 नवंबर, 2009 को आयोजित नव-निर्वाचित राष्ट्रपति करजई के शपथ-ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा शामिल हुए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री डॉ. ददफार रांगीन स्पांटा ने द्विपक्षीय चर्चा करने के लिए 26-27 जुलाई, 2009 को भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा और तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में सक्रियाता से लगा रहा। भारत द्वारा अफगानिस्तान को द्विपक्षीय सहायता 1.3 बिलियन अमरीकी डालर पार कर गया (जबकि हमारी वचनबद्धता 1.2 बिलियन अमरीकी डालर की थी)।

बांग्लादेशः बांग्लादेश में बहु-दलीय लोकतंत्र की बहाली के पश्चात भारत और बांग्लादेश ने कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए सक्रियता से कार्य किया है। प्रधान मंत्री शेख हसीना की जनवरी 2010 में भारत की यात्रा से भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक नए अध्याय की शुरूआत हुई। दौरे के दौरान जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों को रेखांकित किया गया। दोनों पक्ष सुरक्षा सहयोग को खासतौर पर आतताई समूहों के खिलाफ बढ़ाने के लिए सहमत हुए। भारत ने बांग्लादेश में अवसंरचना विकास परियोजनाओं, जिनमें रेल अवसंरचना, कोच, लोकोमोटिव, बसें और ड्रेजिंग भी हैं के लिए 1 बिलियन डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण की घोषणा की। भारत के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया, जिससे बांग्लादेश से नेपाल और भूटान तक सड़क और रेल मार्ग की व्यवस्था की गयी और

दोनों पक्षों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग में नए पोर्टों को निर्धारित किया गया। बांग्लादेश ने भी चटगांव और मांगला पोर्ट को भारत द्वारा उपयोग के लिए खोल दिया। भारत भी बांग्लादेश को 250 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति के लिए सहमत हुआ। दोनों देश व्यापार और निवेश, संस्कृति, जल संसाधन और मानव संसाधन विकास में सहयोग बढ़ाने को सहमत हुए। सुरक्षा से जुड़े तीन करारों, एक विद्युत सहयोग पर करार और एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। यात्रा से पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. दीपू मोनी ने सितंबर 2009 में भारत की यात्रा की और विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने भी नवंबर 2009 में बांग्लादेश की यात्रा की थी। इन दोनों यात्राओं से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बेहतर समझ हुई।

भूटानः भारत और भूटान ने गहन चर्चा, विश्वास और परस्पर समझ से पहचाने जाने वाले सौहार्दपूर्ण संबंध कायम रखे। दोनों ओर से कई उच्चस्तरीय दौरे हुए, जिनमें विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा (जून 2009), गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम (अगस्त 2009), संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री श्री पवन कुमार बंसल (अक्तूबर 2009), मुख्य सूचना आयुक्त श्री वजाहत हबीबुल्लाह (मई 2009) प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरन (जुलाई 2009), विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव (सितंबर 2009), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय (सितंबर 2009), मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला (अक्तूबर 2009) और प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन (नवंबर 2009) के दौरे शामिल हैं। इन दौरों के परिणामस्वरूप हमारे द्विपक्षीय आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध सुदृढ़ हुए। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना रहा। भूटान की ओर से भूटान के प्रधान मंत्री लियोनचेन जिग्मे वाई. थिन्ले की 28 जून-3 जुलाई 2009 में भारत की यात्रा और भूटान के पांचवे नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने 21-26 दिसंबर, 2009 तक भारत की यात्रा की। इन यात्राओं से हमारे द्विपक्षीय आर्थिक और राजनैतिक संबंध मजबूत हुए है। भारत, भूटान के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक और सहायता भागीदार बना रहा है।

चीनः यह वर्ष चीन के साथ जारी उच्चस्तरीय तालमेल का साक्षी रहा, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आयोजनों के दौरान अतिरिक्त समय में हुई बैठकें शामिल हैं। एससीओ/ब्रिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 15 जून, 2009 को येकातेरिनबर्ग में चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओं से मुलाकात की। पूर्वी एशिया/आसियान की अक्तूबर 2009 में हुई, शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में हुआ हिन, थाइलैंड में प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ की बैठक हुई। प्रधान मंत्री ने कोप-15 बैठक के दौरान 18 दिसंबर, 2009 को कोपनहेगन में प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ से मुलाकात की। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा चीन के विदेश मंत्री यांग जीयची से 22 जुलाई, 2009 को पूर्वी एशिया शिखर मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान फुकेत (थाइलैंड) में और तत्पश्चात रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान 27 अक्तूबर, 2009 को बंगलुरू में मिले। इन बैठकों के दौरान विचारों का सार्थक आदान-प्रदान हुआ और नेता दोनों देशों के बीच सामरिक एवं सहयोगी साझेदारी की भावना से परस्पर राजनीतिक विश्वास एवं समझ निर्मित करने के लिए प्रयासों को जारी रखने और उसे मजबूत बनाने पर सहमत हुए। भारत और चीन के बीच संस्थागत वार्ता तंत्र की बैठकों में व्यापक मुद्दों पर वर्ष के दौरान निरंतर प्रगति देखने को मिली। डब्ल्यूटीओ वार्ता का दोहा दौर, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर एक जैसी रूचि रखने के साथ दोनों देशों ने वैश्विक मुद्दों पर रचनात्मक तालमेल जारी रखे। वर्ष 2008 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 51.8 बिलियन अमरीकी डालर के साथ चीन अब भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। वर्ष 2009 में व्यापार की मात्रा थोड़ा गिरकर 43.27 बिलियन अमरीकी डालर रह गयी है।

ईरानः ईरान के विदेश मंत्री श्री मनुचेहर मोत्ताकी की 16-17 नवंबर, 2009 की भारत की यात्रा में उच्च स्तरीय दौरों के आदान-प्रदान का क्रम जारी रहा। विदेश सचिव, श्रीमती निरुपमा राव ने विदेश कार्यालय परामर्श हेतु 2-3 फरवरी, 2010 को ईरान की यात्रा की। द्विपक्षीय संबंधों की गति को बरकरार रखते हुए वर्ष 2009-10 में ऊर्जा, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, बैंकिंग, संस्कृति, मीडिया एवं प्रसारण इत्यादि जैसे अनेक क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान के साथ-साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा जारी रही। द्विपक्षीय व्यापार पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में 30.04% बढ़ा और 13.146 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया।

मालदीवः कई उच्चस्तरीय आदान-प्रदान द्वारा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत होना जारी रहा। इनमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की अक्तूबर 2009 में भारत की यात्रा और राष्ट्रपति के विशेष दूत इब्राहिम जाकी की यात्रा और मालदीव के विदेश मंत्री डॉ. अहमद शाहिद की क्रमशः अगस्त 2009 और जुलाई 2009 की यात्रा शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निमंत्रण पर मालदीव के उपराष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद ने 18-24 फरवरी, 2010 तक भारत की यात्रा की। रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटोनी ने अगस्त 2009 में मालदीव की यात्रा की, जिसमें दोनों देशों ने सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की और तटीय सुरक्षा और समुद्री चौकसी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन ने जून 2009 में और विदेश सचिव ने जनवरी, 2010 में मालदीव की यात्रा की। भारत-मालदीव संयुक्त तट रक्षक अभ्यास 'दोस्तिक्स' दिसंबर 2009 में माले में और अक्तूबर में 'एकुवेरिन' अभ्यास आयोजित किए गऐ।

म्यांमाः भारत और म्यांमा के बीच संबंधों में बहुआयामी स्वरूप विकसित होना जारी रहा। उच्च-स्तरीय दौरों की गति बरकरार रही। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए दिसंबर 2009 में म्यांमा की यात्रा की और म्यांमा के प्रधान मंत्री जनरल थेइन सीन से मुलाकात की। विदेश कार्यालय परामर्श हेतु विदेश सचिव 28 फरवरी-2 मार्च 2010 तक म्यांमा की यात्रा करने वाली हैं, जहां पर सहयोग के अनेक क्षेत्रों पर चर्चा किए जाने की आशा है। सीओएससी और सीओएएस के अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने अक्तूबर 2009 में म्यांमा की यात्रा की। म्यांमा के उद्योग मंत्री (नं. 2) वाइस एडमिरल सो ठाने ने दिसंबर 2009 में भारत की यात्रा की। भारत की सहायता से निर्मित तामु-किगोन कलेम्यो सड़क का हिस्सा म्यांमा सरकार को अक्तूबर 2009 में सौंपा गया। कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना और भारत-म्यांमा औद्योगिक व्यापार केंद्र का कार्य तीव्र गति से जारी रहा। दोनों देशों ने तेल एवं प्राकृतिक गैस, लघु जलविद्युत परियोजनाओं, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना विकास एवं कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को संवर्धित करना जारी रखा।

नेपालः नेपाल का एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध देश के रूप में परिवर्तन को सहायता देने के लिए भारत ने नेपाल की सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ गहन विचार-विमर्श करना जारी रखा। व्यापक परामर्शों और उच्च स्तरीय दौरों के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। भारत के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधान मंत्री श्री माधव कुमार नेपाल 18-22 अगस्त, 2009 को राजकीय यात्रा पर भारत आए। विदेश मंत्री श्रीमती सुजाता कोइराला 10-14 अगस्त, 2009 को भारत यात्रा पर आयीं। नेपाल की रक्षा मंत्री श्रीमती विद्या भंडारी ने जुलाई, 2009 में भारत यात्रा की। नेपाल के गृह मंत्री, श्री भीम बहादुर रावल ने 18-22 जनवरी, 2010 तक भारत की यात्रा की। नेपाल के राष्ट्रपति, डॉ. राम बरन यादव ने 15-18 फरवरी, 2010 तक भारत की यात्रा की, जिसके दौरान चार करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए तथा 250 मिलियन अमरीकी डालर की एक रियायती ऋण-श्रृंखला तथा कुछ खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की घोषणा की गयी। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने 27-28 अक्तूबर, 2009 को नेपाल की यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान संशोधित व्यापार संधि और अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया। भारत के भूतपूर्व विदेश सचिव श्री एस. मेनन ने 20-21 जून को और विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने पुनः 14-15 सितंबर, 2009 को नेपाल की यात्रा की। इनकी यात्रा का उद्देश्य परस्पर हित वाले मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करना और नेपाल के प्रधान मंत्री की अगस्त 2009 में भारत यात्रा के दौरान सहमत कार्य सूची का कार्यान्वयन करना था। नेपाल के विकास कार्यों को भारत ने सहायता देना जारी रखा। वर्तमान में भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तत्वावधान में लगभग 357 छोटी एवं बड़ी परियोजनाएं शुरू की गयी है।

पाकिस्तानः मुंबई पर हुए आतंकी हमले के परिणामस्वरूप समग्र वार्ता प्रक्रिया में रुकावट आ गयी है। सरकार के इस आशाय को कि पाकिस्तान मुंबई हमले के षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा और साथ ही हमले के पीछे की गहन साजिश को बेनकाब करेगा शीर्षस्थ स्तर सहित कई अवसरों पर अवगत करा दिया गया है। एससीओ-ब्रिक की 16 जून, 2009 को येकातेरिनबर्ग में हुई शिखर बैठक के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी के साथ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन के दौरान 16 जुलाई, 2009 को शर्म-अल-शेख में प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक सहित कई अवसरों पर भारत की चिंताओं से पाकिस्तान को उपयुक्त रूप से अवगत करा दिया गया है। इसी प्रकार के विचारों से विदेश मंत्री ने भी 26 जून, 2009 को त्रिएस्ते (इटली) में आयोजित जी-8 आउटरीच देशों की बैठकों के दौरान और तत्पश्चात न्यूयार्क में सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ हुई अपनी बैठकों में अवगत कराया है।

भारत के निमंत्रण पर, दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत 25 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गयी। यह बातचीत दोनों देशों के बीच संपर्क सुनिश्चित करने की सरकार की इच्छा के संदर्भ में थी, ताकि भारत के विरुद्ध जारी आतंकवाद से संबंधित प्रमुख मुद्दों और बकाया मानवीय मुद्दों का समाधान किया जा सके।

मुंबई पर हुए आतंकी हमले और डेविड कोलेमन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा की विभिन्न आतंकवादी कार्यों में संलिप्तता, जिसमें कि मुंबई आतंकी हमला भी शामिल है और पाकिस्तान से निरंतर सीमा-पार घुसपैठ और पाकिस्तान के पार नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से युद्धविराम उल्लंघनों के बावजूद लोगों को लोगों के साथ संपर्क जारी रखने की अनुमति दी गयी। कई पाकिस्तानी सांस्कृतिक, शैक्षिक और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की यात्रा की। सरकार ने धार्मिक स्थलों के दौरे के प्रोतोकोल (1974) के अंतर्गत तीर्थस्थलों की यात्रा को भी सुविधाजनक बनाया। वर्ष 2008-09 में पाकिस्तान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 1.78 बिलियन अमरीकी डालर रहा। गुणात्मक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोतरफा व्यापार वर्तमान की अपेक्षाकृत असंतोषजनक स्तर की तुलना में लगभग 10 गुणा हो सकता है।

1 जनवरी, 2010 को भारत और पाकिस्तान ने एक साथ नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच नाभिकीय प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं के

विरुद्ध हमले के निषेध संबंधी करार के अंतर्गत शामिल नाभिकीय प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं की सूची का (19वीं) आदान-प्रदान किया।

श्रीलंकाः भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों में प्रगति जारी रही। उच्च स्तरीय क्रियाकलापों की गति बरकरार रही। राष्ट्रपति राजपक्षा निजी दौरे पर 31 अक्तूबर, 2009 को भारत आए। प्रधान मंत्री रत्नासिरी विक्रमानायके ने सांची में तीर्थयात्री विश्राम गृह का उद्घाटन करने के लिए अक्तूबर 2009 में भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति राजपक्षा के वरिष्ठ सलाहकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जून और तत्पश्चात दिसंबर 2009 में भारत की यात्रा की। चोगम की बैठक के दौरान वर्ष 2009 में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने श्रीलंका के प्रधान मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने भी दो अवसरों पर बहुपक्षीय मंचों पर विदेश मंत्री बोगोल्लागामा से मुलाकात की। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन ने अप्रैल 2009 में श्रीलंका की यात्रा की और तत्पश्चात तमिलनाडु के 10 संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल ने भी श्रीलंका, विशेष रूप से उसके उत्तरी क्षेत्रों और देहाती क्षेत्रों का दौरा किया।

श्रीलंका में युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत ने श्रीलंका को राहत, पुनर्वास, शीघ्र बहाली और दीर्घ-कालिक पुनर्निर्माण में मदद पहुंचाने के लिए हरसंभव सहायता देना जारी रखा। प्रधान मंत्री ने राहत एवं पुनर्वास हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की। वहां छह माह तक एक भारतीय फील्ड हास्पिटल ने कार्य किया और 50,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया। भारतीय सहायता में ऋण-श्रृंखला के जरिए 7 बारूदी सुरंग हटाने वाले दल, 5200 टन आश्रय सामग्री, 70,000 कृषि जनित पैक और रेल इत्यादि जैसे असैनिक अवसंरचना संबंधी कार्य शामिल है। भारत ने तमिलों सहित श्रीलंका के सभी समुदायों को स्वीकार्य एक एकीकृत श्रीलंका के ढांचे के अंतर्गत बातचीत के द्वारा एक शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान प्राप्त करने पर बल देना जारी रखा।

दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत

भारत ने अपनी 'पूर्वोन्मुख' नीति का अनुपालन करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत के देशों के साथ अपने संबंधों में सुधार लाना और उसे सुदृढ़ करना जारी रखा। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों संदर्भों में क्षेत्र के देशों के साथ बहु-आयामी संबंध विकसित करना जारी रहा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बावजूद वर्ष के दौरान क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ भारत के व्यापार में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। 1 जनवरी, 2010 से प्रकार्यात्मक हुए सामानों के भारत-आसियान एफटीए से हमारे आर्थिक संबंधों को और बल मिलेगा। भारत ने केयर्न्स, आस्ट्रेलिया में 40वें प्रशांत द्वीपसमूह मंच शिखर बैठक के पश्चात वहां 21वीं पश्च मंच वार्ता सहभागिता बैठक (7 अगस्त, 2009) में भाग लिया। भारत और क्षेत्र के देशों के बीच रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी सुधार दिखना जारी रहा। 'भारत-महोत्सव' अक्तूबर 2009 में इंडोनेशिया में शुरू हुआ और सितंबर 2009 में बैंकाक में एक नए भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया।

इस अवधि के दौरान कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इनमें से कुछ प्रमुख दौरे हैं- वियतनाम के उप राष्ट्रपति (सितंबर-अक्तूबर 2009); आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री (नवंबर 2009); आस्ट्रेलिया (अगस्त 2009) थाइलैंड (अक्तूबर 2009) और वियतनाम (दिसंबर 2009) के उप प्रधान मंत्री; और आस्ट्रेलिया (अक्तूबर 2009) और थाइलैंड (दिसंबर 2009) के विदेश मंत्री। इसके अलावा टोंगा के शाह (सितंबर 2009), थाई की राजकुमारी महाचक्री सीरिनधोर्न (अगस्त 2009) और मंत्री मेंटर ली कुआन यीव (दिसंबर 2009) ने भी भारत की यात्रा की। भारत की ओर से भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अक्तूबर 2009 में आसियान-भारत और ईएएस शिखर बैठकों में भाग लेने के लिए थाइलैंड की यात्रा की। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने आसियान-भारत और एआरएफ मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों के लिए आस्ट्रेलिया (अगस्त 2009) और थाइलैंड (जुलाई 2009) की यात्रा की।

भारत सरकार ने क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हुए पिछले कुछ वर्षों विशेष रूप से मई 2009 से आस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय पर हुए हमले को गंभीरता से लिया है। आस्ट्रेलिया की सरकार से शीघ्र हमलों की संख्या और हमले करने वालों को सजा दिलाने से संबंधित संपूर्ण आकड़े उपलब्ध कराने का औपचारिक अनुरोध किया गया है। भारत सरकार स्थिति पर गहनता से नजर रख रही है और आस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के साथ-साथ जो वहां पढ़ने की योजना बना रहे हैं उनको कुछ बुनियादी सावधानी बरतने के लिए 5 जनवरी, 2010 को अपना नवीनतम परामर्शी जारी किया है।

भारत ने कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और प्रशांत महाद्वीप के देशों को उनके विकास प्रयासों में सहायता देना जारी रखा। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 14 पीआईएफ देशों में से प्रत्येक को भारतीय वार्षिक सहायता अनुदान में 1,00,000 अमरीकी डालर से वृद्धि कर 1,25,000 अमरीकी डालर कर दिया। आइटेक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत व्यापक रूप से सहयोग कर रहा है और क्षेत्र के देशों के लिए छात्रवृत्ति स्लाटों की संख्या को बढ़ाकर लगभग 350 कर दिया है। सहयोग का एक अन्य क्षेत्र, क्षेत्र के देशों को आपदा राहत प्रदान करना रहा है। भारत ने फिलीपींस में हुए प्राकृतिक आपदा के बाद उसे मानवीय सहायता प्रदान की। क्षेत्रीय तथा आसियान, बिम्सटेक, ईएएस, एमजीसी और एआरएफ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर गहन तालमेल को बढ़ावा देने में भारत के

बढ़ते प्रभाव ने दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को आकर्षित किया है।

पूर्वी एशिया

भारत की 'पूर्वोन्मुख' नीति का अनुसरण करते हुए पूर्वी एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकता रही है। वर्ष के दौरान इन देशों के साथ नवीकृत उच्च स्तरीय संपर्कों और आदान-प्रदान के जरिए भारत के संबंधों में निरंतर और गुणात्मक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की गति बरकरार रखने की कोशिश की गयी। इस संबंध में क्षेत्र के दो राष्ट्राध्यक्षों के भारत के राजकीय दौरे उल्लेखनीय रहे (मंगोलिया और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के क्रमशः सितंबर 2009 और जनवरी 2010 के भारत दौरे) जिस दौरान विविध क्षेत्रों में कार्यात्मक सहयोग का विस्तार करने के लिए कई द्विपक्षीय करार निष्पादित किए गए। क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ आम हित के क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मसलों के प्रति समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में द्विपक्षीय स्तर से आगे संबंधों का विस्तार करने के लिए सहमत होना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। भारत पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में उभरती संरचना के एक अभिन्न भाग के रूप में देखा जाना जारी रहा।

जापानः उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की गति वर्ष 2009 में जारी रही। व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का और अधिक व्यापक आदान-प्रदान और दोनों देशों की प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों के बीच तालमेल के साथ उच्चस्तरीय आदान-प्रदान में काफी वृद्धि हुई। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 अप्रैल, 2009 को लंदन में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान और 10 जुलाई, 2009 को ला ओकिला (इटली) में जी-8 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधान मंत्री मि. तारो असो से मुलाकात की। चुनाव के पश्चात 30 अगस्त, 2009 को कार्यभार ग्रहण करने के शीघ्र बाद प्रधान मंत्री मि. युकियो हातोयामा ने जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीट्सबर्ग में 25 सितंबर, 2009 को प्रधान मंत्री डॉ. सिंह से मुलाकात की। दोनों प्रधान मंत्रियों की 24 अक्तूबर, 2009 को हुआ हिन (थाइलैंड) में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान एक अन्य बैठक हुई। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने सामरिक वार्ता के तीसरे दौर के लिए 3 जुलाई, 2009 को जापान की यात्रा की। वर्ष के अंत में हुई जापान के प्रधान मंत्री मि. युकियो हातोयामा की भारत यात्रा से भारत के गहन तालमेल को और बल मिला और साथ ही सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी को और गहरायी मिली। दोनों प्रधान मंत्री भारत और जापान के बीच कार्य योजना के अनुसार सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने और कार्य-योजना में अंकित उप मंत्रिमंडल/वरीय अधिकारीस्तरीय 2+2 वार्ता में नव स्थापित रूपरेखा के जरिए अपनी चर्चा को गहन बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में विकास के लिए बहुत संभावना है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री एबे की यात्रा के दौरान 2010 तक 20 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करने पर सहमति हुई थी। हाल ही के वर्षों में निवेश की गति में वृद्धि हुई है। भारत में लगभग 627 जापानी कंपनियां प्रचालनरत हैं, जबकि 2005 में इस कम्पनियों की संख्या 300 तक थी। वर्ष 2006 की अपेक्षा विगत वर्ष में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 10 गुना वृद्धि हुई थी। भारत में जापानी निवेश की कुल राशि 5.22 बिलियन अमरीकी डालर थी, जो 2008 में चीन में इसके 3.65 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश से अधिक थी तथा जापान भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। अक्तूबर, 2009 तक भारत में जापानी ओडीए की संचयी वचनबद्धता लगभग 2.9 ट्रिलियन येन (लगभग 113209.77 करोड़ रु.) थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कुल ओडीए 236 बिलियन येन (लगभग 2.5 बिलियन अमरीकी डालर अथवा 11713 करोड़ रु.) थी, जो कि विगत वर्ष से 4.8% अधिक थी तथा जापान की वैश्विक ओडीए की 30% थी।

कोरिया गणराज्यः हाल ही में कोरिया गणराज्य के साथ सहभागिता मुख्य रूप से और घनिष्ठ व विविधीकृत हो गई है। इस अवधि के दौरान कई उच्च स्तरीय यात्राएं, व्यापार आर्थिक सहभागिता करार (सीईपीए) (अगस्त 2009) पर हस्ताक्षर, बढ़ते आर्थिक व वाणिज्यिक संबंध तथा कला व संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ते आदान-प्रदान भारत-कोरिया गणराज्य के मध्य संबंधों की मुख्य विशेषताएं रहे हैं। वर्ष के दौरान भारत व कोरिया गणराज्य में कई उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ था। कोरिया गणराज्य के विदेश कार्य व व्यापार मंत्री, श्री यू म्यूंग-ह्वान ने 23 जून, 2009 को नई दिल्ली की यात्रा की थी तथा विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए थे। वर्ष के दौरान रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्र में भारत-कोरिया गणराज्य सहयोग तीव्र रूप से जारी रहे। वर्ष 2008 में भारत व कोरिया गणराज्य द्विपक्षीय व्यापार में 39% की वृद्धि हुई थी, जो 15.56 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया था। इस प्रकार यह वर्ष 2010 के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 10 बिलियन अमरीकी डालर के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली म्यूंग-बाक ने 24-27 जनवरी, 2010 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया। वे इस वर्ष के हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। एक ओर हमारी आर्थिक चर्चा से भारत-कोरिया गणराज्य संबंध में मजबूती आई है, तो दूसरी ओर विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष सहयोग जैसे अन्य क्षेत्रों में भी हमारी भागीदारी बढ़ी है। अतः भारत-कोरिया गणराज्य संबंध एक 'रणनीतिक भागीदारी' स्तर तक पहुंच गए हैं।

मंगोलियाः वर्ष के दौरान मंगोलिया के साथ भारत के सदियों पुराने संबंधों में और विकास व विविधीकरण जारी रहा, जिसमें रक्षा व सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान व सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के विस्तृत प्रकार क्षेत्र व्याप्त थे। वर्ष के दौरान दोनों देशों में कई उच्च स्तरीय यात्राओं

का आदान-प्रदान हुआ। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर ने मंगोलिया के नए राष्ट्रपति श्री टीएस एल्बेजार्ज के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 17-19 जून, 2009 को मंगोलिया की यात्रा की। मंगोलिया के नव निवार्चित राष्ट्रपति ने 13-16 सितंबर, 2009 को भारत की राजकीय यात्रा की थी। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के स्तर का उन्नयन करके 'व्यापक सहभागिता' स्थापित करने पर सहमत हुए थे। वर्ष के दौरान रक्षा के क्षेत्र में भारत-मंगोलिया सहयोग में पर्याप्त प्रगति हुई। 5वां भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 14-27 सितंबर को किया गया।

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (डीपीआरके): भारत तथा कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, जो कि मानवीय व मानव संसाधन विकास पर केन्द्रित थे। इस वर्ष के दौरान संस्कृति, खेल व शिक्षा के क्षेत्र में सतत प्रगति हुई। डीपीआरके के उप विदेश मंत्री किम यंग द्वितीय ने विदेश कार्य विचार-विमर्श के छठे दौर के लिए अगस्त 2009 में भारत की यात्रा की थी।

यूरेशिया

रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मध्य एशियाई और कौकेसियाई देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय यात्राओं, द्विपक्षीय करारों, बहुपक्षीय संपर्कों, परियोजना विकास तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पर्याप्त प्रगति हुई है। वर्ष के दौरान वार्षिक सम्मेलन (दिसंबर 2009) व एससीओ तथा ब्रिक सम्मेलन (जून 2009) के लिए प्रधान मंत्री की रूस परिसंघ की यात्रा, भारत के राष्ट्रपति की रूस परिसंघ व तजाकिस्तान (सितंबर 2009) यात्रा, बेंगलुरु में भारत, रूस व चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक (अक्तूबर 2009) तथा विदेश मंत्री की बेलारूस व तुर्कमेनिस्तान (सितंबर 2009) तथा रूसी परिसंघ व उज्बेकिस्तान (अक्तूबर 2009) की यात्रा कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे।

भारत तथा रूस ने बहुआयामी रणनीतिक सहभागिता को और मजबूत बनाना जारी रखा। रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा सुरक्षा (हाइड्रो कार्बन्स व परमाणु ऊर्जा सहित) जैसे मुख्य क्षेत्रों में सहयोग में तेजी आई। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील की 2-6 सितंबर, 2009 के दौरान रूस की राजकीय यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी। 6-8 दिसंबर, 2009 को वार्षिक सम्मेलन के लिए प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की मास्को यात्रा के दौरान छह महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर करने के अलावा सामरिक सहभागिता को और मजबूत बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पारित की गई थी। इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित करारों में (i) 2011-2020 की अवधि के दौरान सैन्य व तकनीकी सहयोग (एनटीसी) के लिए कार्यक्रम पर करार (ii) भारत गणराज्य को भेजे जाने वाले रूसी हथियारों व सैन्य उपकरणों के लिए बिक्री पश्चात सहायता पर करार, (iii) बहुउद्देशीय परिवहन विमान के विकास व उत्पादन में सहयोग पर 12 नवंबर, 2007 करार से संबंधित प्रोतोकाल (iv) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग से संबंधित करार (ऊर्जारक्षित), (v) वर्ष 2010-12 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम तथा (vi) रूस को भारत की वस्तुएं व प्रौद्योगिकी उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एग्जिम बैंक द्वारा बीनेशेकोनो बैंक को 100 मिलियन अमरीकी डालर का शृंखलाबद्ध ऋण प्रदान करने के लिए डालर करार शामिल है।

अन्य महत्वपूर्ण मंत्रियों की यात्राओं में वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा (29 सितंबर-अक्तूबर 2009), पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा (2-6 सितंबर, 2009), रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी (14-15 अक्तूबर, 2009) व विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा (20-22 अक्तूबर, 2009) की यात्रा शामिल है। रूस की ओर से उप प्रधानमंत्री तथा व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय व सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अन्तरसरकारी सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के सह-अध्यक्ष, श्री सर्जेई एस. सोबानिन ने 9-12 नवंबर, 2009 को भारत की यात्रा की। विदेश मंत्री श्री सर्जेई लावराव ने 26-27 अक्तूबर, 2009 को भारत-रूस-चीन के विदेश मंत्रियों की नौवीं त्रिपक्षीय बैठक के लिए बेंगलुरु की यात्रा की थी। उप प्रधान मंत्री श्री सरजई एस. सोबियानिन ने 15-16 फरवरी, 2010 के दौरान भारत की यात्रा की, यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री से मुलाकात की और मार्च 2010 में रूसी महासंघ के प्रधान मंत्री व्लादिमीर पुतीन की यात्रा की तैयारी करने के लिए श्री एस. एम. कृष्णा, आईआरआईजीएस-टीईसी के सह-अध्यक्ष के साथ बातचीत की। वर्ष 2009 को 'रूस में भारतीय वर्ष' के रूप में आयोजित किया गया, जिसके दौरान रूस में भारतीय कला व संस्कृति, पेंटिंग व आर्टिफैक्ट तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियां प्रदर्शित करते हुए 150 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

वर्ष के दौरान मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत होते रहे तथा तजाकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान व उज्बेकिस्तान की उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से और सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने 6-8 सितंबर, 2009 को तजाकिस्तान की सरकारी यात्रा की, जोकि मध्य एशियाई क्षेत्र में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की सर्वप्रथम यात्रा थी। विदेश मंत्री, श्री कृष्णा ने 16-17 सितंबर, 2009 को बेलारूस की यात्रा की थी, जोकि बेलारूस में किसी भारतीय विदेश मंत्री की सर्वप्रथम यात्रा थी। विदेश मंत्री श्री कृष्णा ने बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा अपने बेलारूसी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। विदेश मंत्री श्री कृष्णा ने 18-19 सितंबर, 2009 को तुर्किमिनिस्तान की सरकारी यात्रा की थी, जहां उन्होंने तुर्किमान राष्ट्रपति श्री गुरबांगुली बर्डिमुहाम्मादोव से मुलाकात की तथा अपने तुर्किमान समकक्ष के साथ दोनों विदेश मंत्रालयों

के बीच सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री ने 22-23 अक्तूबर, 2009 को उज्बेकिस्तान की सरकारी यात्रा की, जहां उन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री ईस्लाम कारीमोव से मुलाकात की तथा अपने उजबेक समकक्ष के साथ विचार-विमर्श किया। व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत-अजरबैजान अन्तर-सरकारी आयोग का प्रथम सत्र 26 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी सह-अध्यक्षता भारतीय ओर से वाणिज्यिक व उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा अजरबैजान की ओर से पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री हुसेयंगुलू बागीराव द्वारा की गई थी। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने तीसरे भारत-तुर्कमेनिस्तान अंतर-सरकारी आयोग की बैठक की विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव के साथ सह-अध्यक्षता करने के लिए 8-9 फरवरी, 2010 तक अश्गावात की यात्रा की। उनके साथ एक सरकारी और व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी गया। उन्होंने यात्रा के दौरान राष्ट्रपति गुरबांगुली बेर्दी-मुहम्मेदोव से मुलाकता की। आईजीसी बैठक की समाप्ति पर एक संयुक्त प्रोतोकोल पर हस्ताक्षार किया गया।

भारत, रूस व चीन के विदेश मंत्रियों की 9वीं त्रिपक्षीय बैठक 27 अक्तूबर, 2009 को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री, श्री सर्जेई लवराव तथा चीनी विदेश मंत्री महामहिम श्री यांग येची ने विभिन्न क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की समीक्षा तथा वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

खाड़ी, पश्चिम एशिया व उत्तरी अफ्रीका

व्यापार, निवेश, ऊर्जा और मानव शक्ति में सहयोग का अवसर का लाभ उठाते हुए, उच्च स्तरीय दौरों के माध्यम से साझीदारी बनाते हुए, व्यापार वाणिज्यिक और मानवशक्ति ढांचा को सरल बनाते हुए, भारत-जीसीसी राजनीतिक वार्ता, रणनीतिक वार्ता और परामर्श तंत्र के रूप में संस्थागत संबंध स्थापित करते हुए राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में खाड़ी क्षेत्र (जीसीसी देशों, यमन और इराक) के साथ भारत के संबंधों में और विस्तार एवं मजबूती आई। ऊर्जा कूटनीति और निवेश भागीदारी पर नए रूप से बल देना इस वर्ष की मुख्य विशेषता रही है। भारत ने यमन, कतर और ओमान में आयल ब्लॉकों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई है। पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और ऊर्जा सघनता उद्योगों के अनुप्रवाह में संयुक्त उद्यम लगाने के प्रयास जारी हैं। भारत और कतर ने क्षेत्र में निवेश क्षमता को महसूस करते हुए नवंबर 2009 में 5 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश करार पर हस्ताक्षर किए। इसी प्रकार ओमान के साथ 100 मिलियन अमरीकी डालर के समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। निवेश और परियोजना भागीदारी इस वर्ष के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं और फरवरी 2010 में भारत-अरब निवेश परियोजना का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया, जो नौ मंत्रालयी सहभागिता और इस क्षेत्र के और इससे बाहर के बीस से अधिक व्यापार शिष्टमंडलों का साक्षी रहा।

2009 में लगभग 100 बिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार सहित यूएसए के बाद खाड़ी क्षेत्र हमारी बड़े व्यापार साझेदार के रूप में उभरा है। संयुक्त अरब अमीरात हमारा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार के रूप में उभरा है। इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से प्रवासी भारतीय समुदाय की सर्वाधिक संख्या 5 मिलियन से अधिक है, जिनकी प्रतिवर्ष लगभग 30 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित रेमिटैंस सहित 5 मिलियन से ऊपर है। लगभग 75% कच्चे तेल की आवश्यकता की पूर्ति इस क्षेत्र से होती है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत और खाड़ी देश में पर्याप्त रूप से उच्चस्तरीय आदान-प्रदान हुआ है, जिससे बेहतर समझ पैदा हुई है। भारत की ओर से प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 27 फरवरी-1 मार्च 2010 के दौरान उनके शाह के निमंत्रण पर सऊदी अरब का सफल दौरा किया, जिसके दौरान प्रत्यर्पण संधि, सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी करार, एस एंड टी सहयोग करार, संस्कृति और बाहरी अंतरिक्ष में सहयोग सहित 10 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण रियाद घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दो देशों के बीच सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई है। उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी और विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने क्रमशः अप्रैल 2009 और फरवरी 2010 में कुवैत का दौरा किया। वित्त मंत्री ने संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2009 में सऊदी अरब का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री श्री शशि थरूर ने ओमान (फरवरी 2010) यूएई और बहरीन (अक्तूबर 2009) तथा यमन (जून 2009) की यात्रा की, जिसमें आईओआर-एआरसी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उपाध्यक्ष, योजना आयोग श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने अप्रैल 2009 में द्वितीय भारत-ओमान संयुक्त कार्य दल के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव ने नवंबर 2009 में भारत-कतर संयुक्त मानीटरींग तंत्र के लिए कतर की यात्रा की। क्षेत्र की विभिन्न महत्वपूर्ण यात्राओं से द्विपक्षीय संबंधों को पुनः बल मिला, जिसमें ओमान के तेल व गैस मंत्री (मई 2009); सऊदी अरब अमीरात के विदेश मंत्री (जून 2009); बहरीन के विदेश मंत्री (फरवरी 2010); इराक, यूएई तथा कतर के व्यापार मंत्रियों (फरवरी 2010) की यात्राएं शामिल हैं। वाना क्षेत्र के देशों के साथ भारत के परंपरागत मजबूत और विविध संबध अनेक रूपों में और सुदृढ़ हुए। प्रधान मंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति तथा फिलीस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के राष्ट्रपति के साथ बैठकों के द्वारा क्षेत्र में सतत राजनैतिक विचार-विमर्श हुआ। लीबिया के ग्रेट अल फतह आंदोलन की 40वीं वर्षगांठ समारोह में, राज्यसभा के उपसभापति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस्र, इजराइल, जार्डन, मोरक्को, फिलीस्तीन, सूडान

और सीरिया के साथ-साथ विभिन्न अन्य उच्चस्तरीय यात्राओं का भी आदान-प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान भारत ने निकट पूर्व में फिलीस्तीनी शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी में अपने वार्षिक योगदान को 20,000 अमरीकी डालर से 1 मिलियन अमरीकी डालर करके महत्वपूर्ण वृद्धि की।

अफ्रीका

मंत्रालयी स्तर पर कई यात्राओं के आदान व प्रदान से अफ्रीका के साथ भारत के संबंध तीव्र गति से जारी रहे। मुख्य बहुपक्षीय समारोहों के अवसर पर अफ्रीकी नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया था। अफ्रीकी संघ के 53 देशों में से 47 देश भारत सरकार की पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना में शामिल हो चुके हैं तथा उन्होंने दूर-शिक्षा व दूर-चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए शृंखलाबद्ध ऋण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा व क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराए गए थे। अफ्रीकी देशों ने आईटीईसी शिक्षावृत्ति स्थानों तथा आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति का लाभ उठाना जारी रखा। सरकारी-गैर सरकारी साझेदारी को प्रोत्साहित करने की नीति के रूप में मंत्रालय ने मंत्रियों की अफ्रीकी देशों की यात्राओं के दौरान उनके साथ-साथ व्यापार प्रतिनिधमंडलों की मौजूदगी को प्रोत्साहित किया था तथा विदेश से आने वाले प्रतिष्ठित सरकारी पदाधिकारियों की वाणिज्यिक व औद्योगिक निकायों के माध्यम से भारतीय व्यापारियों के साथ वार्ता की व्यवस्था की। भारतीय उद्योग परिसंघ ने 2-4 अगस्त, 2009 को लागोस में भारत-अफ्रीका व्यापार भागीदारी कनक्लेव तथा 5-7 अगस्त, 2009 को नैरोबी में व्यापार मिशन आयोजित किया। अफ्रीका के साथ व्यापार 2001-02 के 5.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2008-09 में 39 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया था।

वर्ष के दौरान भारत ने बामाको (माली) व नियामी (नाइजर) में अपना आवासी मिशन खोला।

भारत के उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने मई 2009 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में डॉ. जैकब जुमा के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत से दक्षिण अफ्रीका में अन्य महत्वपूर्ण यात्राओं में लोक सभा के उपाध्यक्ष श्री करिया मुण्डा के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल की दक्षिण अफ्रीका यात्रा (अगस्त 2009); विज्ञान व प्रौद्योगिकी, संसदीय कार्य, पृथ्वी विज्ञान तथा कार्मिक व प्रशिक्षण के प्रभारी राज्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान की डरबन यात्रा (अक्तूबर 2009) तथा कोयला, सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्यमंत्री श्री श्रीप्रकाश जयसवाल की डरबन यात्रा (अगस्त 2009) शामिल हैं।

उपराष्ट्रपति ने 5-11 जनवरी, 2010 के दौरान जांबिया, मलावी और बोत्सवाना की भी यात्रा की। विदेश राज्यमंत्री डॉ. शशि थरूर 13-14 जनवरी, 2010 के दौरान मोजांबिक की द्विपक्षीय यात्रा पर गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने आदिस अबाबा (27-30 जनवरी, 2010) में आयोजित अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में पर्यवक्षक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, 2008 की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संयुक्त कार्य योजना पर भी अफ्रीकी संघ के साथ चर्चा की गयी।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी ने आदिस अबाबा, इथियोपिया (अक्तूबर) व लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने 28 सितंबर-6 अक्तूबर को अरुषा (तंजानिया) की यात्रा की। भारत से मॉरीशस में बंधुआ श्रमिकों के आगमन पर स्मारक समारोह की 175वीं वर्षगांठ पर राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर की मॉरीशस यात्रा (1-3 नवंबर) तथा सीएचओजीएम, 2009 के अवसर पर नवंबर 2009 को पोर्ट आफ स्पेन में मारीशस गणराज्य के प्रधानमंत्री, डॉ. नवीन रामगुलाम के साथ डॉ. मनमोहन सिंह की बैठक द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय समारोह थे। युगाण्डा के आंतरिक कार्य के राज्य मंत्री श्री मातिया कासेजा व कृषि राज्य मंत्री श्री रवामीरामा के ब्राइट ने क्रमशः जून व अक्तूबर, 2009 में भारत की यात्रा की। भारत ने 1-6 मई, 2009 से हरारे (जिम्बाब्वे) में आयोजित हरारे के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में भाग लिया। जाम्बिया के वाणिज्य व उद्योग मंत्री प्रो. डब्ल्यू. एन. क्यूब ने विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दोहा दौर की अनौपचारिक मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

यूरोप

यूरोपीय संघ में स्वीडन की अध्यक्षता में 6 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत-यूरोपीय संघ शीर्ष सम्मेलन की सफलतापूर्वक समाप्ति के साथ ही भारत-यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को नए सिरे से प्रोत्साहन मिला है। प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की थी तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट इत्यादि जैसे पारस्परिक हित के बहुपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की थी। जारी किया गया संयुक्त वक्तव्य पारस्परिक हित के विविध क्षेत्रों में हमारे दोनों क्षेत्रों के चालू वर्तमान सहयोग को दर्शाता है। वर्ष के दौरान रक्षा, सुरक्षा, असैनिक परमाणु ऊर्जा, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, व्यापार व निवेश, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, संस्कृति व शिक्षा के विविध क्षेत्रों में यूरोपीय संघ के साथ हमारे बहुआयामी वार्तालापों में तेजी आई है। यूरोपीय संघ के कई अलग-अलग सदस्य राज्यों के साथ विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय स्तर पर अच्छे सहयोग हुए हैं।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने अक्तूबर, 2009 में यू.के. की महारानी के निमंत्रण पर यू.के. की सरकारी यात्रा की। उन्होंने अप्रैल 2009 में स्पेन की भी पहली सरकार यात्रा की। भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जुलाई 2009 में फ्रांस की यात्रा की। प्रधान मंत्री ने जी-20 (अप्रैल और सितबर 2009) जी-8 (जुलाई 2009) तथा चोगम (नवंबर 2009) जैसे बहुपक्षीय कार्यक्रमों के अवसर पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने सितंबर, 2009 में रोम में जी-8/जी-5 अध्यक्ष सम्मेलन में भाग लिया। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने जून 2009 में आयरलैंड की यात्रा की।

वर्ष के दौरान अन्य मंत्रालय स्तरीय यात्राओं और वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय यात्राओं का भी आयोजन किया गया और इन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में योगदान दिया। भारत और यूरोपीय देशों के बीच संसदीय आदान-प्रदान और सिविल सोसाइटी वार्ता मुखर रही। वर्ष के दौरान एक-दूसरे के व्यापारिक स्तरीय विचार-विमर्श भी सार्थक रहे।

वर्ष के दौरान भारत में की गयी उच्चस्तरीय यात्राओं में फरवरी 2010 में जर्मनी के राष्ट्रपति हार्स्ट कोहिलर की यात्रा तथा नवंबर, 2009 में स्पेन के युवराज एवं राजकुमारी की यात्रा शामिल थी।

यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग है। इस तथ्य के मद्देनजर सितंबर, 2009 में हेग में एक लघु प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया।

नोरडिक देशों और मध्य तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंध परम्परागत रूप से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। हमारे लोगों के फायदे के लिए एक-दूसरे की क्षमताओं का निर्माण किए जाने हेतु इन देशों के साथ तालमेल बनाए जाने की जरूरत है। मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। नोरडिक देशों के साथ भारत ने जहाज निर्माण, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर बल दिया है।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने श्रीमती डी. पुरनदेश्वरी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री तथा अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों, व्यापारिक प्रतिनिधियों तथा मीडिया व्यक्तियों के साथ 29-31 अक्तूबर 2009 को साइप्रस की सरकारी यात्रा की। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 14-17 सितम्बर 2009 को आस्ट्रीया का दौरा किया। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने भारत-यूरोपीय संघ मंत्रालयी ट्रोएका में भाग लेने के लिए 28-30 जून 2009 को प्राग की यात्रा की। डेनिस प्रधान मंत्री श्री लारस लोके रसमुसेन ने सीओपी15 के मेजबान के रूप में 11 सितम्बर 2009 को भारत की एक दिन की कार्यकारी यात्रा की तथा प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की। लिथुआनिया के विदेश मंत्री श्री व्यागोडस उसाकस, ने अर्थव्यवस्था मंत्री श्री डायनियुस क्रिवीस के साथ 2-5 दिसम्बर, 2009 को भारत की यात्रा की। हंगरी के विदेश मंत्री डॉ. पीटर बालाज ने 17-21 जनवरी, 2010 के दौरान भारत की सरकारी यात्रा की, जिसके दौरान उन्होंने विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा से व्यापक बातचीत की। माल्टा के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री, डॉ. टोनियो बॉर्ग ने 6-11 जनवरी, 2010 के दौरान भारत की सरकारी यात्रा की और विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती प्रनीत कौर और विदेश मंत्री से बातचीत की।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने राज्य मंत्री डॉ. अश्विनी कुमार के साथ 23-26 अप्रैल, 2009 को पोलैंड की सरकारी यात्रा की। आइसलैंड के राष्ट्रपति डॉ. ओलाफुर रगनार ग्रिमसन को 11-17 जनवरी, 2010 ने भारत की सरकारी यात्रा की, जिसके दौरान उन्हें वर्ष 2007 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तुर्की के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला गुल ने बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 7-11 फरवरी, 2010 को भारत की यात्रा की। स्वीडन के प्रधान मंत्री फ्रेडरिक रैनफैल्डट ने विदेश मंत्री कार्ल विल्डट, व्यापार मंत्री ईवा बजोरलिंग तथा एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय तथा भारत-यूरोपीय सम्मेलन बैठकों में भाग लेने के लिए 5-6 नवम्बर, 2009 को भारत की यात्रा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने 18 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 15-16 सितम्बर, 2009 को स्वीडन की यात्रा की। डॉ. एम. एस. गिल, युवा कार्य और खेल मंत्री ने 8-17 अगस्त, 2009 को स्विट्जरलैंड की सरकारी यात्रा की तथा वस्त्र मंत्री श्री दयानिधि मारन के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-28 अक्तूबर को स्विट्जरलैंड की यात्रा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा (सीआईएम) ने 8 सितम्बर, 2009 को आयोजित आर्थिक और तकनीकी सहयोग (जेसीईटीसी) संबंधी संयुक्त समिति के 9वें सत्र में भाग लेने के लिए 7-8 सितम्बर 2009 को अंकारा की यात्रा की। वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 2-7 अक्तूबर को इस्तानबुल में आईएमएफ की वार्षिक बैठक में भाग लिया।

अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीकाः द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर साझा हित के कई क्षेत्रों में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और सुदृढ़ हुए हैं तथा ये संबंध विस्तृत और संवर्द्धित भी हुए। हालांकि, 2009 वह वर्ष था जब विश्व के सबसे पुराने तथा बड़े लोकतंत्र दोनों देशों में नवनिर्वाचित सरकारें

स्थापित हुई, संयुक्त राज्य अमरीका में नए प्रशासन तथा भारत में अपने दूसरे कार्यकाल में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के एकीकृत प्रयास किए गए कि परिवर्तन, निरंतरता और द्विपक्षीय संबंधों के संवर्द्धन द्वारा विनिर्दिष्ट हो। दोनों नई सरकारों ने मौजूदा आर्थिक और राजनैतिक भागीदारियों को सुदृढ़ करने तथा पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग के उच्चतम स्तर तक इनको ले जाने के लिए अपनी सशक्त प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। जुलाई 2009 में अमरीका की विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान दोनों प्रशासनों ने नई रणनीतिक वार्ता की घोषणा की। वाशिंगटन में नवम्बर 2009 में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच वैश्विक रणनीतिक भागीदारी के नए चरण में प्रवेश करने का निर्णय लिया।

इस अवधि के दौरान भारत और अमरीका के बीच उच्च स्तरीय संपर्क जारी रहा। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए के अवसर पर सितम्बर 2009 में अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती क्लिंटन से मुलाकात की। गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन ने क्रमशः सितम्बर और अक्तूबर 2009 में अमरीका की यात्रा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने अमरीका-भारत परिषद की 34 वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए जून 2009 में वाशिंगटन की यात्रा की। अमरीकी पक्ष की ओर से भारत की उच्च स्तरीय यात्राओं में श्री विलियम बर्न्स, अमरीकी अवर सचिव, राजनैतिक कार्य (अक्तूबर 2009) तथा अमरीकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल राजदूत रौन क्रिक (सितम्बर 2009) शामिल हुए।

वर्ष 2008 में सामान और सेवाओं में भारत-अमरीकी द्विपक्षीय व्यापार 69.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा। जनवरी-अक्तूबर, 2009 की अवधि के दौरान सामानों में भारत-अमरीकी द्विपक्षीय व्यापार 31.5 बिलियन रहा। जनवरी-अक्तूबर, 2009 के दौरान भारत ने अमरीका को 17.6 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के सामान का निर्यात किया तथा अमरीका से 13.9 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के सामान का आयात किया। भारत ने 2009 में 28.3 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं का निर्यात किया। अमरीका भारत में अग्रणी विदेशी निवेशकों में से एक है। परमाणु ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी जैसे अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों ने अपने सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार किया है जिनमें महत्व के नए क्षेत्रों को जोड़ा गया है।

वर्ष के दौरान कनाडा के साथ भी महत्वपूर्ण पहलों जैसे सिविल परमाणु करार, द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन करार, मुक्त व्यापार करार करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह तथा विभिन्न अन्य प्रस्तावों और कार्यक्रमों को शुरू किया गया और उन पर कार्रवाई की गई, जिससे दोनों राष्ट्रों के बीच आर्थिक, राजनैतिक तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सुदृढ़ होंगे। प्रधान मंत्री स्टीफन हार्पर की भारत यात्रा (15-18 नवम्बर, 2009) द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर थी। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय कार्यसूची को विस्तृत करने तथा साझा प्राथमिकता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच समानताएं तथा साझा मूल्य और हित निर्मित किए गए। दोनों प्रधान मंत्रियों की उपस्थिति में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अप्रैल 2009 में उपाध्यक्ष, योजना आयोग, डॉ. एम.एस. अहलुवालिया ने 15-17 अप्रैल, 2009 को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा टोरोन्टो में आयोजित कनाडा भारत ऊर्जा फोरम में भाग लेने के लिए अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्री गैराल्ड कैडी, संसदीय सचिव, कैनेडियाई मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने कलकत्ता में कैनेडियाई जोनल व्यापार कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए 1-5 सितम्बर 2009 को भारत की यात्रा की तथा श्री स्टाकवैल डे, कैनेडियाई मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अहमदाबाद में कैनेडियाई व्यापार कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए 25 सितम्बर, 2009 को अहमदाबाद की यात्रा की।

लेटिन अमरीका और कैरेबियाईः लेटिन अमरीका और कैरेबियाई देशों के साथ हमारे संबंधों में 40 देश शामिल हैं तथा वर्ष के दौरान निर्भर क्षेत्र काफी व्यापक रहे हैं। वर्ष के दौरान कई शिखर सम्मेलन और मंत्रालयी स्तर के वार्तालाप सहित क्षेत्र के साथ बहुक्षेत्रीय वार्ताएं रही है। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 27-29 नवम्बर, 2009 को चोगाम शिखर सम्मेलन के लिए त्रिनिडाड और टोबेगो की यात्रा की तथा विभिन्न एचओएस/एचओजी के साथ द्विपक्षीय परामर्श किया। उन्होंने मोस्को में 16 सितम्बर, 2009 को बीआईआईसी शिखर सम्मेलन तथा 24-25 सितम्बर, 2009 को पिट्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने आईबीएसए मंत्रालयी तथा द्विपक्षीय संयुक्त आयोग के लिए 31 अगस्त-1 सितम्बर 2009 को ब्राजील की यात्रा की। अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति डॉ. क्रिस्टीना डी फर्नेनडीज क्रिश्चनर ने 13-14 अक्तूबर, 2009 को भारत की सरकारी यात्रा की। कोलोम्बो के विदेश मंत्री श्री जैमे बरमुडेज ने वाणिज्य, व्यापार और पर्यटन मंत्री श्री ग्युलरमो प्लाटा के साथ 10-11 नवम्बर, 2009 को भारत की सरकारी यात्रा की।

वर्ष के दौरान क्षेत्र के देशों के साथ कुल 11 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2008-09 के दौरान भारत और एलएसी क्षेत्र के बीच 15.63 बिलियन अमरीकी डालर का रिकार्ड द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जोकि भारत के कुल विदेश व्यापार का 3.25 प्रतिशत है। भारतीय कंपनियों ने या तो निवेश किया है अथवा लगभग 11 बिलियन अमरीकी डालर निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारतीय व्यापार/उद्योग संगठनों जैसे सीआईआई तथा फिक्की ने क्षेत्र में भारतीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई व्यापार सेमीनार आयोजित

किए हैं। हमारे 'फोकस एलएसी' के भाग के रूप में क्षेत्र में आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं में सहायता देने के लिए विभिन्न देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने की पहल की गई है। कोस्टारिका और इक्वाडोर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा क्षेत्र के देशों के क्षमता निर्माण पहल में उनको सहायता प्रदान करने के लिए उनके लिए कुछ 416 आईटीईसी छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई है। 12 जनवरी, 2010 को आए हैती को हिला देने वाले भयानक भूकंप को देखते हुए भारत सरकार ने हैती को आपातकालिक राहत कार्यों के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर का नगद योगदान किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर 26 जनवरी, 2010 को हैती के लोगों और वहां की सरकार के प्रति हमदर्दी प्रकट करने के लिए स्वयं हैती गए। वर्ष के दौरान हमने प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हुए नुकसान से निपटने के लिए इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, सेंट लुसिया और ग्वाटेमाला को 1.55 मिलियन अमरीकी डालर की तर्ज पर मानवीय सहायता प्रदान की है। हमारे सांस्कृतिक पहुंच कार्यक्रम के भाग के रूप में हमारे मिशनों द्वारा स्वतंत्र रूपसे अथवा भारतीय सांस्कृतिक कार्य परिषद (आईसीसीआर) की सहायता से क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म समारोह, सेमीनार, सम्मेलन तथा फूड फेस्टीवल आयोजित किए गए।

संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन

भारत बहुपक्षवाद में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीयता को महत्व प्रदान करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए इसको अधिक प्रातिनिधिक और लोकतांत्रिक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने हेतु निरंतर बल देता रहा है। आम सभा के पुनः स्थायित्वकरण, सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सुधार, अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी विषयों के बारे में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका को पुनः बहाल करने तथा शांति बनाए रखने के श्रेष्ठ प्रबंधन और संघर्ष के पश्चात शांति निर्माण प्रक्रियाओं पर सुधार के प्रयास केंद्रित थे। इसके अतिरिक्त भारत ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति के सार्वभौमिक कार्यान्वयन तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय पर वार्तालाप के शीघ्र निर्णय के जरिए आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग में वृद्धि करने पर बल दिया। भारत ने नौ मिशनों में लगभग 8,760 सैनिक कार्मिकों की तैनाती के साथ संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में तीसरे सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ता के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है।

विदेश मंत्री, श्री एस.एम. कृष्णा ने 20-27 सितम्बर, 2009 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा (यूएनजीए) के 64 वें सत्र के उच्च स्तरीय भाग में सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने यूएनजीए के 64वें सत्र में भाग लेने के लिए 19-26 अक्तूबर, 2009 को न्यूयॉर्क की यात्रा की। विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने यूएनजीए सत्र में भाग लेने के लिए 11-20 अक्तूबर, 2009 को न्यूयॉर्क की यात्रा की।

गुट निरपेक्ष आंदोलनः गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 15-16 जुलाई, 2009 को शर्म -अल-शेख, मिस्र में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन (नाम) के पंद्रहवें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश मंत्री, श्री एस. एम. कृष्णा ने नाम शिखर सम्मेलन से पहले 13-14 जुलाई, 2009 को आयोजित नाम की मंत्रालयी बैठक में भाग लिया। श्री ई. अहमद, तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए 29-30 अप्रैल, 2009 को हवाना, क्यूबा में आयोजित नाम समन्वय ब्यूरो की मंत्रालयी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

राष्ट्रमंडलः प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 27-29 नवंबर, 2009 को पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाड और टोबेगो में आयोजित राष्ट्र मंडल देशों की सरकारों के प्रमुखों की बैठक (चोगम) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 25-26 नवंबर, 2009 को पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित पूर्व चोगम के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। चोगम, 2009 के दौरान प्रधान मंत्री ने भारत के आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रमंडल देशों हेतु प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त 250 स्लाटों, राष्ट्रमंडल देशों हेतु राजनयिक प्रशिक्षण मॉड्यूल, जेनेवा में नए स्थापित राष्ट्रमंडल लघु राज्यों के संयुक्त कार्यालय में योगदान, राष्ट्रमंडल मीडिया विकास कोष को दोगुना करना, राष्ट्रमंडल साझेदारी प्लेटफार्म पोर्टल हेतु वित्तीय सहायता, राष्ट्रमंडल सचिवालय में खेल विकास सलाहकार के पद की स्थापना, राष्ट्रीय चुनाव आयोगों के नेटवर्क की स्थापना के लिए राष्ट्रमंडल महासचिव की पहल के लिए सहायता सहित भारत द्वारा विभिन्न नई पहलों की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आधुनिक राष्ट्रमंडल के सृजन की 60वीं वर्षगांठ वर्ष के रूप में संस्मारक डाक टिकट और सिक्के जारी किए।

सामाजिक और आर्थिक विषयः आर्थिक और सामाजिक परिषद का 2009 का मूल सत्र 6-30 जुलाई, 2009 को जिनेवा में आयोजित किया गया था। विदेश राज्य मंत्री, श्रीमती प्रनीत कौर ने इस सत्र के मंत्रालयी भाग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से नई दिल्ली में 22-23 अक्तूबर, 2009 को 'जलवायु परिवर्तनः प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण' पर उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने 22 सितम्बर, 2009 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा आयोजित 'जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन' संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। 7-18 दिसम्बर, 2009 को कोपनहेगन में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी-15) की 15वीं बैठक में अधिकारियों, संसद

सदस्यों, सिविल सोसायटी सदस्यों तथा युवाओं सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। 16-18 दिसम्बर, 2009 को आयोजित सम्मेलन के उच्च स्तरीय भाग तथा जिसमें लगभग 120 देशों के राज्यों/सरकारों के प्रमुखों ने भाग लिया, में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, भारत ने मानव अधिकार परिषद, महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग, वैश्विक फोरम प्रवासन और विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून तथा अंतर-संसदीय संघ संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग जैसे कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क): क्षेत्रीय सहयोग के प्रोत्साहन में सार्क की भूमिका निकट भविष्य में काफी व्यापक होने की आशा है। सार्क में संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा इसकी विभिन्न गतिविधियों को वित्त पोषित करने में सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी से संगठन में नए और मुखर क्षेत्रीय संस्थानों को आकार मिलने की संभावना है- दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय तथा नई दिल्ली में स्थित सार्क वस्त्र और हथकरघा संग्रहालय, ढाका स्थित सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन, पाकिस्तान स्थित सार्क मध्यस्थता परिषद, थिंपू स्थित सार्क विकास निधि सचिवालय, श्रीलंका स्थित सार्क सांस्कृतिक केंद्र आदि।

सार्क गतिविधि में यह वृद्धि सार्क विकास निधि के संरक्षण के अंतर्गत वित्त पोषित और कार्यान्वित क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय परियोजनाओं द्वारा भी संपूरित होंगी। नए क्षेत्रीय संस्थान निर्मित करने तथा मौजूद संस्थानों को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया से दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के आर्थिक उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध संगठन के रूप में सार्क के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सार्क में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में भारत के असममित और गैर-पारस्परिक दृष्टिकोण ने अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ किया है। इसने विकास सहयोग को प्रत्यक्ष रूप से निचले स्तर तक ले जाने में सहायता करके सार्क को घोषणात्मक चरण से कार्यान्वयन चरण में परिवर्तित कर दिया है।

निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

भारत ने वैश्विक गैर-भेदभाव पूर्ण तथा सत्यापनीय परमाणु निरस्त्रीकरण की लंबे और निरंतर समय से चली आ रही वकालत के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उच्चतम प्राथमिकता के रूप में पुनः पुष्टि करना जारी रखा है। भारत ने निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन में विखण्डय सामग्री कट-ऑफ संधि सहित कार्य संबंधी कार्यक्रम को अपनाने का समर्थन किया था। न्यूयॉर्क में आयोजित 64वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन, एकत्रीकरण तथा इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने तथा निर्धारित समय सीमा में उनको पूर्ण रूप से समाप्त करने की व्यवस्था करने हेतु परमाणु हथियार संबंधी अभिसमय हेतु अपने प्रस्ताव को पुनः दोहराया था। भारत ने जैविक हथियार अभिसमय, रासायनिक हथियार अभिसमय तथा कुछ परम्परागत हथियारों संबंधी अभिसमय सहित निरस्त्रीकरण संबंधी विभिन्न बहुपक्षीय बैठकों में रचनात्मक रूप से भाग लिया। भारत ने एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठकों तथा एशिया में विचार-विमर्श और आत्म विश्वास निर्माण उपायों संबंधी सम्मेलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। विभिन्न समस्याओं पर भारत के विचारों के प्रसार हेतु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखे गए ।

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

भारत के बहुपक्षीय आर्थिक संबंधों में वर्ष के दौरान और अधिक विस्तार और प्रगाढ़ता आई क्योंकि वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन बहुपक्षीय मंचों में वार्ता के मुख्य केन्द्र बने रहे। इस वर्ष के बहुपक्षीय संबंधों की प्रमुख विशेषता इटली में आयोजित जी-8-आउटरीच सम्मेलन (जुलाई 2009) में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की भागीदारी; ब्राजील, रूस, भारत और चीन (ब्रिक) के नेताओं की पहली औपचारिक सम्मेलन (जून 2009) भारत-आसियान सम्मेलन और पूर्व एशियाई सम्मेलन (अक्तूबर 2009) में भारत की भागीदारी रही।

जी-8 में अपनी सृजनात्मक भागीदारी को जारी रखते हुए भारत ने जी-8, जी-5 आउटरीच सम्मेलन के दौरान कई मंत्रिस्तरीय बैठकों में मंत्री अथवा सचिव स्तर पर भागीदारी की, जिसमें अफगानिस्तान पर बैठक, श्रम मंत्रियों की बैठक, कृषि मंत्रियों की बैठक, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक और जी-8 सम्मेलन तथा विघटनकारी शक्तियों और परा राष्ट्रीय चुनौतियों पर आउटरीच मंत्रियों की बैठक शामिल थीं।

भारत-आसियान, पूर्व एशिया सम्मेलन, बिम्सटेक, आईबीएसए, एमजीसी, एसीडी, एसेम, जी-15, आईओआर-एआरसी और अन्यों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूहों के साथ संबंध वर्ष के दौरान प्रगाढ़ हुए। भारत द्वारा भागीदारी की गई प्रमुख मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत-आसियान, पूर्व एशिया सम्मेलन, ब्रिक, इब्सा, बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल) जी-5 (ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका), एसेम (एशिया, यूरोप बैठक), एसीडी (एशिया सहयोग वार्ता) और आईओआर-एआरसी (भारतीय समुद्री रिम-क्षेत्रीय सहयोग के लिए संघ) के फारमेट के अंतर्गत होने वाली बैठकें थीं। भारत 2009 में आईओआर-एआरसी का उपाध्यक्ष बना।

वर्ष के दौरान भारत सतत रूप से विभिन्न जी-20 बैठकों में सकारात्मक रूप से और नियमित तौर पर भागीदारी करता रहा। प्रधान मंत्री ने अप्रैल, 2009 में जी-20 लंदन सम्मेलन में और

सितंबर, 2009 में जी-20 पीट्सबर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। जी-20 सम्मेलनों का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और आर्थिक संकट से जुड़े मुद्दे रहे। पीट्सबर्ग सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए जी-20 को 'प्रमुख मंच' के रूप में भी मनोनीत किया गया।

वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के संदर्भ में, जी-20 के अलावा भारत सक्रिय रूप से ब्रिक वित्त मंत्रियों की बैठक में भी शामिल रहा और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ब्राजील, रूस तथा चीन के साथ समन्वय करता रहा।

सितंबर 2009 में विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की भारत द्वारा मेजबानी की गयी, ताकि बहुपक्षीय विचार-विमर्शों के रास्ते आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए एक विस्तृत आधार वाली आम राय विकसित की जा सके और विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय प्रक्रिया को पुनः सजीव बनाने के लिए वार्ता की स्पष्ट दिशा तय की जा सके। यह वर्ष के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही।

तकनीकी और आर्थिक सहयोग तथा विकास भागीदारी

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम और अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम (एससीएएपी) को भारत की विकासशील विश्व के साथ विकास भागीदारी और सहयोग के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पहचान दी गई है। विभिन्न देशों में इन सहयोगी कार्यक्रमों की उपयोगिता तथा सार्थकता की आईटेक कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या की वृद्धि के रूप में देखा गया था जो वास्तव में विकासशील विश्व में एक ब्रैण्ड नेम प्राप्त कर चुका है। माँग आधारित तथा प्रतिक्रिया उन्मुख आईटेक आज भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक तथा सक्रिय अंग हो चुका है जो सहयोग के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। वर्ष 2009-10 के दौरान 158 विकासशील देशों को उनके हित और लाभ के क्षेत्रों में लगभग 5000 सिविलियन प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किये गये। वित्त और लेखा, लेखापरीक्षा, बैंकिंग, शिक्षा, योजना और प्रशासन, संसदीय अध्ययन, अपराध रिकार्ड आदि जैसे क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लाओस, लेसोथो, सेचेलेस, जाम्बिया, इथोपिया और मंगोलिया से आए रक्षा कार्मिकों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन (आईटीपी)

आर्थिक राजनय भारत की विदेश नीति में खासतौर पर वैश्विक आर्थिक संकट की बाद की स्थितियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा। हमारे मिशनों को 9.09 करोड़ रु. तक की अतिरिक्त निधि का आबंटन किया गया, ताकि वे भारतीय उद्योग की बढ़ती मांगों को अधिक प्रभावी ढंग से उत्तर दे सके और बाजार सर्वेक्षण, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं, बिक्रेता- क्रेता बैठकों, उद्योग भागीदारी आदि सहित बाजार विस्तार कार्यकलापों द्वारा व्यापार और निवेश संबंधी अवसरों का लाभ प्राप्त कर सकें।

अप्रैल 2009 से फरवरी 2010 के दौरान 21 विकासशील देशों को 1132.22 मिलियन अमरीकी डालर का रियायती श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान किया गया, जिससे अफ्रीका, लातीन अमरीका और एशिया में हमारे भागीदार विकासशील देशों के आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण के प्रति हमारी ईमानदारीपूर्ण वचनबद्धता प्रकट होती है। इन श्रृंखलाबद्ध ऋणों ने अवसंरचना क्षेत्र में परियोजनाओं को सहयोग देने और सामान के निर्यात तथा अब तक उपयोग न किए गए बाजार को सेवाएं प्रदान करने में मदद की, जिससे देश के प्रति बहुत सद्भावना उत्पन्न हुई। 5 करोड़ रुपए की धनराशि विकासशील देशों को जहां तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है, में श्रृंखलाबद्ध ऋण के अंतर्गत परियोजनाएं चलाने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में सहायता के लिए अलग रखी गयी है।

मंत्रालय ने सुधार और उदारीकरण तथा निवेश एवं व्यापार से संबंधित नीतिगत मामलों में अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर कार्य किया। मंत्रालय की वेबसाइट www.indianbusiness.nic.in के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रचार किया गया।

ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा सुरक्षा इकाई का उन्नयन करके उसे एक सर्व सुविधा सम्पन्न ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग के रूप में विकसित किया गया है। अवधि के दौरान इस नए विषय के प्रभाग द्वारा यूएनजीए, जी-20, नैम, ब्रिक, एसेम आदि जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर ऊर्जा सुरक्षा मामलों पर भारत की स्थिति प्रकट करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। इस प्रभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और ऊर्जा दक्षता एवं सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए भारत की सदस्यता दिलाने में भी सहजता प्रदान की गई और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से संपर्क में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। ऊर्जा मामलों के लिए विदेश मंत्रालय में स्थित एक नोडल बिन्दु के रूप में इस प्रभाग ने ऊर्जा पंक्ति के मंत्रालयों के साथ निकट समन्वयन बनाए रखा और ऊर्जा मुद्दों पर उनके अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलापों में समर्थन प्रदान किया। ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ने देश के ऊर्जा से जुड़े विभिन्न पणधारियों जिनमें निजी क्षेत्र भी शामिल हैं के साथ भी समन्वयन बनाए रखा।

प्रोतोकाल

अप्रैल 2009 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान राष्ट्र प्रमुख, उप राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख और विदेश मंत्री स्तर पर 95 दौरे (73 आने वाले और 22 बाहर जाने वाले) हुए। तीन देशों (बुरुण्डी, गांबिया और जाम्बिया) में इस अवधि के दौरान आवासीय मिशन खोले गए, जिससे नई दिल्ली में आवासीय मिशनों की

कुल संख्या 140 हो गयी। 2009 में इथोपिया और न्यूजीलैंड के लिए मुंबई में नए प्रधान कोंसलावास खोले जाने का अनुमोदन किया गया। 5 देशों को व्यापार कार्यालय खोलने तथा 19 देशों को भारतीय मेट्रो नगरों में मानद कोंसलावास खोलने की अनुमति दी गयी। मुंबई स्थित हंगरी के मानद कोंसुल और बेंगलुरु में आयरलैंड के मानद कोंसुल के दर्जे को क्रमशः जनवरी और फरवरा 2010 में बढ़ाकर मानद प्रधान कोंसुल किया। अप्रैल, 2009 से फरवरी 2010 की अवधि के दौरान विदेशी मिशनों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 157 नए पद सृजित किए गए। एक बड़ी संख्या में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरों, नए मिशनों; कोंसलावासों और व्यापार कार्यालयों को खोले जाने तथा साथ ही राजनयिक मिशनों द्वारा अनेक अतिरिक्त पदों के सृजन से जैसा देखा जा सकता है, भारत के प्रति बढ़ी रुचि विश्व में भारत की सक्रिय और बहुआयामी संलग्नता को प्रकट करती है।

कोंसली, पासपोर्ट तथा वीजा सेवाएं

वर्ष 2009 के दौरान हमारे 37 पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 50.28 लाख पासपोर्ट जारी किए गए। अप्रैल 2009 से 20 जनवरी, 2010 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं के माध्यम से क्रमशः 685.5 करोड़ रुपए और 924.41 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जित हुआ।

पासपोर्ट जारी किये जाने की प्रक्रिया को और सरल तथा तेज बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों और त्वरित डाक केन्द्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकरण, आवदेनों को ऑनलाइन प्राप्त किया जाना, भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम में कुछ नए भवनों को जोड़ा जाना, पासपोर्टों की केन्द्रीकृत छपाई, लोक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाना, सुविधा काउंटरों और सहायता डेस्कों को खोला जाना, शिकायतों के निस्तारण हेतु पासपोर्ट अदालतों को आयोजित किया जाना तथा आरटीआई का सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन शामिल है।

अवधि के दौरान 1803 राजनयिक और 15,082 सरकारी पासपोर्ट तथा 5,606 विदेशी राजनयिकों तथा सरकारी पासपोर्ट धारकों को वीजा जारी किए गए। वर्ष के दौरान, 1,80,000 निजी और शैक्षणिक दस्तावेज और 1,50,000 अन्य दस्तावेज सत्यापित किए गए। एपोस्टिलबद्ध सदस्य देशों द्वारा विदेश में उपयोग हेतु 82000 दस्तावेज एपोस्टिल किए गए।

नई परियोजनाओं में ई-पासपोर्ट जारी करना, पासपोर्ट सेवा परियोजना, वीजा कार्य को बाहरी स्रोतों से कराया जाना तथा 'एपोस्टिल कोवेंसन परियोजना' को शुरू किया जाना शामिल थीं। प्रत्यर्पण संधि पर कजाखस्तान के साथ हस्ताक्षर किए गए। नाम्बिया के साथ एक वीजा अधित्याग करार पर भी हस्ताक्षर किये गये।

समन्वयन प्रभाग

समन्वयन प्रभाग संसद से संबंधित सभी कार्यों, अन्य मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकार के कार्यालयों, संघ शासित प्रदेशों तथा स्वायत्तशासी निकायों के साथ बात-चीत के लिए मंत्रालय के नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करता रहा।

अवधि के दौरान प्रभाग द्वारा दौरों के लिए 2706 राजनैतिक अनापत्तियां जारी की गईं जबकि वर्ष 2008 में यह संख्या 2539 थी। इसके द्वारा गैर-अनुसूचित विदेशी उड़ानों के लिए भी 996 अनापत्तियां जारी की गईं जबकि 2008 के दौरान यह संख्या 971 थी। प्रभाग द्वारा भारतीय खेल टीमों की विदेशों में भागीदारी, विदेशी राष्ट्रिकों को पद्म पुरस्कार दिए जाने से संबंधित अनेक आवेदनों पर भी कार्रवाई की गईं और फरवरी, 2010 में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी 'डेफएक्स्पो इंडिया-2010' के लिए भी रक्षा मंत्रालय की सहायता की गई। भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1345 विदेशी आवेदकों को भी अनापत्तियाँ जारी की गईं।

प्रशासन और स्थापना

विदेशों में 173 आवासीय भारतीय मिशन और पोस्ट स्थित हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान बमैको (माली), नियामी (नाइजर) और ग्वाटेमाला सिटी (ग्वाटेमाला) में तीन नए मिशन खोले गए।

प्रशासनिक तंत्र को सुचारु बनाने के लिए निर्णय लेने की शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करने तथा नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा उनमें सुधार लाने के लिए प्रयास किए गए। इसके अंतर्गत कतिपय नियमों का उदारीकरण तथा कुछ अन्य रियायतों को जोड़ना भी शामिल है। सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नतियों और सीमित विभागीय परीक्षा जिनमें आरक्षित रिक्तियों पर की गई भर्ती भी शामिल है के माध्यम से भर्तियां भी की गई।

जहाँ तक मिशनों के सहयोग से विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का मामला है, हिन्दी पुस्तकों, शिक्षण सामग्रियों और साफ्टवेयर की आपूर्ति लगभग 70 मिशनों/पोस्टों को की गई, हिन्दी पत्रिकाएं 100 मिशनों/पोस्टों को भेजी गईं और बेलारूस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका आयरलैंड, सूरीनाम, वियतनाम और हंगरी स्थित हमारे मिशनों/पोस्टों को वित्तीय सहयोग प्रदान की गयी। संसदीय राजभाषा समिति में विशाखापत्तनम, चेन्नै, पुणे, सूरत और गाजियाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के दौरे किया। इस निरीक्षण से संबंधित कार्यों का समन्वयन मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा किया गया।

सूचीकरण योजनो के अंतर्गत विदेश भत्ते की वार्षिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के साथ समन्वयन करके की गई और 'प्रतिपूरक

भत्ते' का तत्व शुरू किया गया। चाणक्यपुरी स्थित 100 आवासीय इकाइयों वाले विदेश मंत्रालय आवासीय परिसर को प्रचालित कर दिया गया है और के. जी. मार्ग तथा गोल मार्केट स्थित विदेश मंत्रालय छात्रावासों के मरम्मत का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हो चुका है।

इस अवधि के दौरान मस्कट तथा तोक्यो (राजदूतावास आवास तथा अन्य आवासीय भवन) स्थित भारतीय राजदूतावास परिसर के लिए निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। काबुल, काठमाण्डू, बीजिंग, लंदन, इस्लामाबाद, सिंगापुर और बुडापेस्ट स्थित चांसरी और/अथवा आवासीय भवनों जैसी बड़ी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान कुवैत, टोरोण्टो, मेड्रिड स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में पासपोर्ट और वीजा सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण तथा भारतीय राजदूतावास, मास्को तथा वैंकुवर में वीजा और पासपोर्ट सेवा को बाहरी स्रोतों से कराने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

सूचना का अधिकार

अप्रैल-दिसंबर 2009 की अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुल 804 आवेदन प्राप्त किए गए। इन आवेदनों के अंतर्गत निजी शिकायतें, हज तीर्थयात्रा, कैलाश-मानसरोवर यात्रा, खाड़ी युद्ध मुआवजा, विदेश नीति, आर्थिक मुद्दे जैसे विषय शामिल थे। इसी अवधि के दौरान इन आवेदनों में से आवेदकों द्वारा 238 अपीलें मंत्रालय के अपिलीय प्राधिकारी के पास दायर की गई।

लोक राजनय

इस प्रभाग के अधिदेश में अन्य बातों के साथ-साथ भारत और विदेश में श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रण प्रचार के माध्यम से आउटरीच कार्यकलाप शामिल हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रभाग सिविल नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, विचारकों, अनुसंधान व शैक्षणिक संस्थानों तथा व्यापार व उद्योग के सहयोग से अथवा इसके लिए विदेश नीति संबंधी मुद्दों पर सम्मेलन व ब्रीफिंग आयोजित करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन आइटरीच कार्यकलापों में यू.के. से कोन्जरवेटिव पार्टी के 'भारत के मित्र' समूह के दो प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा व लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया समूह से एक अन्य प्रतिनिधिमंडल, स्लोवानिया संसदीय समूह से प्रतिनिधिमंडल की यात्रा, प्रोफेसर सुदर्शन इयंगार, उप कुलपति गुजरात विद्यापीठ, स्लोवानिया, विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का अयोजन तथा खाड़ी अनुसंधान केन्द्र दुबई द्वारा आयोजित 'भारत-जीसीसी संबंध' पर चालू अनुसंधान परियोजना शामिल है।

प्रभाग ने फिल्म उत्सवों व भारतीय फिल्म सप्ताहों में भाग लेना भी जारी रखा तथा संस्कृति व फोटो प्रदर्शनी आयोजित की। कई वृत्तचित्र प्रारंभ किए गए हैं और उन्हें पूरा किया जा रहा है। मंत्रालय की फ्लैगशिप पत्रिका 'इंडिया पर्सपेक्टिव' का सुधार और विस्तार किया जा रहा है तथा प्रभाग ने हमारे मिशनों के प्रयोग के लिए पुस्तकों का उत्पादन तथा उनकी खरीद जारी रखा।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर)

आईसीसीआर को भारत व अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध व पारस्परिक सूझ-बूझ स्थापित करने, पुनरुद्धार करने व मजबूत बनाने को अधिदेश प्राप्त है। दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय, भारत में 14 क्षेत्रीय कार्यालय तथा विदेश स्थित कई सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से परिषद के अन्य कार्यकलापों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रशासन तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाना शामिल है। वर्ष के दौरान परिषद ने अफगानी विद्यार्थियों के लिए 675 छात्रवृत्तियों तथा अफ्रीकी देशों से 526 छात्रवृत्तियों सहित 2226 नई छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। भारतीय भाषाओं और भारत पर केन्द्रित सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाने के लिए उन्नीस दीर्घकालिक पीठों का संचालन करते रहने के अलावा परिषद विभिन्न देशों में 11 क्रमागत/अल्पकालिक पीठों का भी संचालन कर रहा है।

आईसीसीआर ने स्विट्जरलैण्ड, मलेशिया, मारीशस, यूएसए, पाकिस्तान, यू.के, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, स्पेन, मिस्र, तंजानिया, पारागुआ, ब्राजील, ईरान, कोलम्बिया, पुर्तगाल, पोलैंड, त्रिनिदाद व टोबेगो व वेनेजुएला सहित भारत में प्रस्तुतीकरण करने वाले कई विदेशी कलाकारों की यात्राएं प्रायोजित कीं। परिषद ने विभिन्न देशों में भारतीय कलाकारों/समूहों की यात्राएं भी प्रायोजित कीं। परिषद ने कई सम्मेलनों व संगोष्ठियों के आयोजन में सहयोग किया तथा कई देशों में सांस्कृतिक सप्ताह व प्रसिद्ध कवियों के आदान-प्रदान समारोह भी आयोजित किए तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए आईआईटी, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय व जामिया मीलिया जैसे प्रमुख संस्थानों व कई संगठनों की सहायता की।

आईसीसीआर द्वारा आयोजित भारतीय उत्सवों में 'रूस में भारतीय वर्ष', 'अर्जेंटीना में भारतीय वर्ष' तथा 'इण्डोनेशिया में भारतीय वर्ष' शामिल हैं।

भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए)

भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) विदेश मामलों संबंधी एक विचार केन्द्र और इस संबंध में बहस और विचार-विमर्श के

लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित होता रहा। पूरे वर्ष के दौरान आईसीडब्ल्यूए भारत के महत्वपूर्ण विदेश नीति हितों से संबंधित संगोष्ठियों और सम्मेलनों तथा प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों की यात्राओं और व्याख्यानों में लगा रहा। नौ विदेशी प्रतिनिधि सप्रू हाउस आए और उन्होंने विदेश नीति से जुड़े अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामरिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, पूर्व-राजनयिकों और मीडिया प्रतिनिधियों की एक बड़ी जमात को संबोधित किया। इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप भारतीय विश्व कार्य परिषद ने उपयोगी विषयों पर शोधपत्र प्रकाशित करना शुरू किया। भारत के अपने निकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ संबंध पर शोध कार्य को अत्यधिक बल दिया गया और अगस्त 2009 से कार्यरत भारतीय विश्व कार्य परिषद की नई शोध टीम ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करना आरंभ किया। भारतीय विश्व कार्य परिषद ने भारत तथा विदेशों में संगोष्ठियों का आयोजन भी किया, उनमें भागीदारी भी की और शैक्षिक आदान-प्रदानों के परिणामस्वरूप संस्था की रूपरेखा का विस्तार हुआ जो 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' का रूप धारण कर ली। विदेशी प्रतिभागियों के साथ सात द्विपक्षीय सामरिक वार्ताएं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की संस्थाओं में की गईं। नवंबर 2009 के दौरान दिल्ली में 'एशियाई संबंध सम्मेलन' की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूरे विश्व से आए विद्वानों ने हिस्सा लिया। भारतीय विश्व कार्य परिषद ने एशिया एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग संबंधी परिषद (सीएससीएपी) के कार्यकलापों में अपनी भागीदारी को मूर्त रूप प्रदान किया। भारतीय विश्व कार्य परिषद ने सप्रू हाउस परिसर का व्यापक पुनरुद्धार करने के लिए भी कार्य किया- जो लगभग पचपन वर्ष पहले देश के प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रोत्साहन से जो निर्मित धरोहर भवन के रूप में निर्मित/स्थापित की गयी है। भारतीय विश्व कार्य परिषद को देश के विदेश नीति के मुद्दों पर एक प्रमुख विचार केन्द्र के रूप में पुनर्स्थापित करने के प्रयास जारी रखे जाएंगे।

अनुसंधान व सूचना प्रणाली (आरआईएस)

आरआईएस मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी विचार केन्द्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध व विकास सहयोग में विशेषज्ञता प्राप्त है। इसे बहुपक्षीय आर्थिक व सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामलों पर सरकार के परामर्शदायी निकाय के रूप में कार्य करने का अधिदेश प्राप्त है।

अवधि के दौरान अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा गुट निरपेक्ष सम्मेलन, पूर्व एशिया सम्मेलन (ईएएस), सार्क सम्मेलन, आईबीएसए सम्मेलन, बिमस्टेक सम्मेलन, अंकटाड मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों और विश्व व्यापार संगठन सम्मेलनों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रमुख शोध अध्ययन तैयार किए गए। आरआईएस कई क्षेत्रीय पहलों में ट्रैक-II प्रक्रिया में लगा रहा, जिसमें पूर्व एशिया में व्यापक आर्थिक भागीदारी का ट्रैक-II अध्ययन समूह भी शामिल था। रिपोर्ट अवधि के दौरान आरआईएस द्वारा आसियान-भारत मुक्त व्यापार करार, सीईपीईए, एशियाई सहयोग वार्ता, सार्क सियांग-माई पहल और ईएएस, आईओआर-एआसी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी संयुक्त अध्ययन समूह तथा हेलिडेंडमन प्रक्रिया जैसी महत्वपूर्ण बैठकों एवं वार्ताओं के लिए अध्ययन आयोजित कराए गए एवं नीति निर्माताओं को आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी। आरआईएस विचार-भंडार के क्षेत्रीय नेटवर्क में सक्रिय रहा, जिसमें संगठन को भारत के फोकल प्वाइंट के रूप में नामित किया गया है। इनमें आसियान एवं पूर्व-एशिया आर्थिक अनुसंधान संस्थान (इरिया) और बिमस्टेक विचार केन्द्र नेटवर्क शामिल है। दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन आरआईएस द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसके द्वारा दक्षिण एशिया में प्रमुख नीति अनुसंधान संस्थाओं को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय एकजुटता को प्रगाढ़ एवं विस्तृत बनाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए एक मंच पर लाया गया।

विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय

मंत्रालय के पुस्तकालय में 1,00,000 से अधिक पुस्तकें, बहुमूल्य स्रोत सामग्रियों और मानचित्रों का एक बड़ा संकलन तथा सरकारी दस्तावेज रखे गए हैं। पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद समेत पुस्तकालय के कामकाज की देखरेख के लिए एक पुस्तकालय समिति है। प्रलेखन और बिब्लियोग्राफी सेवाओं सहित पुस्तकालयों के सभी तरह के संचालनों एवं सेवाओं को कंप्यूटरीकृत किया गया। विदेश मामलों संबंधी डेटाबेस में नियमित आधार पर पुस्तकों, मानचित्रों, माइक्रोफिल्मों, पत्रिकाओं से लिए गए चुनिंदा लेखों को जोड़ा जाता है। पुस्तकालय नियमित तौर पर विदेश मामले प्रलेखन बुलेटिन, हाल के संकलनों, घटनाक्रमों, लेख-सचतेकों, पुस्तक-सचेतकों एवं ई-मेल सेवाओं को तैयार करके जारी किया जाता है।

विदेश प्रचार

विदेश प्रचार प्रभाग ने भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ आदान-प्रदान के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत सरकार के विचारों/पक्षों का प्रचार करना जारी रखा। प्रभाग के मुख्य कार्यकलापों को भारत के निकटवर्ती पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के मुख्य देशों के साथ भारत के संबंधों पर सूचना के प्रसार पर केन्द्रित किया गया। 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के उपरान्त सीमापार से आने वाले आतंकियों के संबंध में भारत की चिंता को प्रकट करने के लिए एक सतत प्रचार अभियान शुरू किया गया था।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आने-जाने वाले दोनों तरह के दौरों के प्रेस कवरेज को सुगम बनाया गया। इस अवसर का उपयोग द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भारत की स्थिति को प्रमुखता से पेश करने के लिए भी किया गया। प्रभाग ने प्रमुख

मुद्दों पर नियमित ब्रीफिंग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ संपर्क बनाए रखा। सरकारी प्रवक्ता ने भारत की विदेश नीति के संबंध में दिन-प्रति-दिन के घटनाक्रमों पर सूचना प्रसारित की तथा नियमित मीडिया ब्रीफिंग की व्यवस्था की गई और साथ ही प्रेस विज्ञप्तियों, ब्रीफिंग बिंदु और वक्तव्य के प्रसारण की भी व्यवस्था की गयी।

प्रभाग ने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट को अद्यतन करने, मंत्रालय की वेबसाइट के हिंदी खंड को अद्यतन करने, विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्तियों के उर्दू अनुवाद के लिए एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) से व्यवस्था करने, भारत-अफ्रीका कनेक्ट वेबसाइट शुरू करने विदेशी पत्रकारों की यात्राओं की जानकारी प्रदान करने, वृत्तचित्र और फिल्मों का निर्माण करने, प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सम्मेलनों और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने और आम चुनावों पर एक समूची और रंगीन हैंडबुक प्रकाशित करने के संबंध में भी पहल की।

नीति नियोजन व अनुसंधान

नीति नियोजन व अनुसंधान प्रभाग के मुख्य कार्यकलापों में विदेश नीति व विश्वव्यापी मामलों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं व अध्ययनों का प्रसंस्करण, विचार केन्द्रों, अनुसंधान निकायों, विश्वविद्यालय इत्यादि के डाटा बेस को तैयार करना/अद्यतन बनाना, भारत की विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), तथा इसके द्वारा मान्यता प्राप्त व विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों के साथ आदान-प्रदान करना,विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान में विशेषज्ञता प्राप्त करना तथा मंत्री/राज्यमंत्री व अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के भाषण के प्रारूप तैयार करना शामिल है। इस अवधि के दौरान मासिक सारांशों को नियमित रूप से जारी करना जारी रखा गया तथा वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 को तैयार व परिचालित किया गया था।

विगत वर्ष के दौरान प्रभाग का मुख्य कार्यकलाप अगस्त 2009 में मिशन प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित करना था जिसमें लगभग 120 राजदूतों व उच्च आयुक्तों ने भाग लिया। नीति नियोजन प्रभाग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में विदेश नीति अध्ययन संस्थान का समन्वय व अनुवीक्षण किया, जिसकी स्थापना विदेश मंत्रालय की वित्तीय सहायता से की गई थी।

नीति नियोजन व अनुसंधान प्रभाग ने स्थिति कक्ष व सीमा कक्ष के कार्य का पर्यवेक्षण भी किया। इस अवधि के दौरान स्थिति कक्ष ने पीएमआई, न्यूयार्क, भारतीय राजदूतावास, वाशिंगटन तथा भारतीय राजदूतावास मास्को में स्थित हमारे मिशनों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित कीं तथा भारतीय उच्चायोग माले, पीएमआई, जनेवा व सीजीआई शंघाई में इन सुविधाओं से संबंधित कार्य शुरू किया।

विदेश सेवा संस्थान

विदेश सेवा संस्थान ने भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षानार्थियों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों व कर्मचारियों, मंत्रिमंडल सचिवालय व अन्य मंत्रालय/विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। वर्ष के दौरान संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए प्रथम अनिवार्य मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए ई-मेल आधारित मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मालदीव से राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, आसियान के राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम और विदेशी राजनयिकों के लिऐ दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

■■

भारत के पड़ोसी देश 1

अफगानिस्तान

2009-10 में भारत और अफगानिस्तान के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास के कार्य में सक्रिय रूप से लगा रहा। आर्थिक और सामाजिक विकासात्मक कार्यकलापों के लगभग सभी क्षेत्रों में अफगानिस्तान के लिए हमारी द्विपक्षीय सहायता 1.3 बिलियन अमेरिकी डालर (1.2 बिलियन अमेरिकी डालर की वचनबद्धता की तुलना में) को पार कर गई। इस सहायता में भारतीय कालेजों में पढ़ने वाले अफगानी छात्रों के लिए वार्षिक छात्रवृत्तियों की संख्या में 35% तक की वृद्धि (675 तक) और भारत में अफगान राष्ट्रिकों के लिए प्रशिक्षण स्लाटों में इसी प्रकार की वृद्धि (500 से 675 तक) की गई है।

निरुत्साहित संभारतंत्रीय एवं सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद पुले-ए-खुमारी से काबुल तक 220 के वी ट्रांसमीशन लाइन और चिमतला में सबस्टेशन का निर्माण पूरा किया गया जो कि काबुल के निवासियों के लिए बिजली के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अफगानिस्तान के नये संसद भवन का निर्माण, जिसे बहुलवाद और प्रजातंत्र के प्रति हमारे दोनों देशों की आम वचनबद्धता के प्रतीक के रूप में देखा गया, में भी प्रगति हो रही है। कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में अन्य भारतीय परियोजनाएं भी संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रही हैं। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण प्रयास में हमारे सहयोग की पूरे अफगानिस्तान के लोगों द्वारा काफी सराहना की गई है जोकि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर निर्मित है जिससे दोनों देश जुड़े हुए हैं। अफगान दृष्टिकोण के संबंध में हाल ही में कराये गए त्वरित सर्वेक्षण में इस बात पर बल दिया गया था। यह पूछे जाने पर कि अफगानिस्तान की स्थिति का समाधान करने में विभिन्न समूह अथवा देश क्या भूमिका निभा रहे थे, तो सर्वेक्षण में अधिकांश उत्तर देने वालों ने पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका का उल्लेख किया।

काबुल स्थित भारतीय दूतावास को निशाना बनाते हुए 8 अक्तूबर, 2009 को एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें कम से कम सत्रह अफगानी मारे गए। दो आई टी बी पी कार्मिक गोले से घायल हुए। विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने इस धमाके के तुरंत बाद काबुल का दौरा किया और राष्ट्रपति करजई, विदेश मंत्री स्पांटा और अन्य नेताओं से मुलाकात की। अफगान नेताओं ने उन्हें बताया कि यह हमला अफगानिस्तान के बाहरी तत्वों द्वारा किया गया था, जिनका उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के मध्य विद्यमान उत्कृष्ट संबंधों को क्षति पहुँचाना था। भारत सरकार अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों की हिफाजत एवं सुरक्षा के संबंध में अफगानिस्तान सरकार से लगातार संपर्क बनाये हुए है।

26 फरवरी, 2010 की सुबह काबुल में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा उपयोग की जा रही आवासीय सहूलियतों को निशाना बनाया गया। छः भारतीय जिसमें आर्मी मेडिकल कोर्प और आर्मी एडुकेशन कोर्प (ए ई सी), के चिकित्सा और मानवीय कार्य के जुटे हुए एक-एक अधिकारी, हेरात और कंधार में भारत के महाकौंसलावास से एक कर्मचारी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक मंडली में जाने वाले व्यक्तियों के एक सदस्य और पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी उस दिन इस हमले का शिकार हुए। ए ई सी के एक और अधिकारी ने बाद में (3 मार्च को) दम तोड़ दिया। 27 फरवरी को घायल व्यक्तियों एवं मारे गए व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को एक विशेष भारतीय वायु सेना के विमान से लाया गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने 27 फरवरी को प्रधान मंत्री को टेलीफोन करके शोक व्यक्त किया और इस हमले की पूरी जांच कराने का आश्वासन दिया। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति करजई से अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री जलमे रसूल ने 26 फरवरी को विदेश मंत्री से मुलाकात की और इस आतंकवादी हमले की निंदा की और आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों में वृद्धि की जाएगी। विदेश मंत्री ने इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार ऐसे हमलों से डरने वाली नहीं है।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री रांगीन ददफार स्पांटा ने 26-27 जुलाई, 2009 के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन से मुलाकात की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच चालू कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं व्यापक विकास सहयोग के लिए वृहत्तर संस्थागत

सहायता का उपयोग करने के वास्ते राजनैतिक परामर्श, क्षमता विकास और शिक्षा, विद्युत एवं जल, संस्कृति, व्यापार और उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी पृथक समूहों को शामिल करते हुए भारत-अफगानिस्तान सहभागिता परिषद् का गठन करने का निर्णय लिया गया।

विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में नई अवधि के लिए पदभार संभालने के अवसर पर 19 नवम्बर, 2009 को काबुल में राष्ट्रपति करजई के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति करजई ने बताया कि अफगानिस्तान का भारत के साथ सामरिक संबंध है और साथ ही हमारी द्विपक्षीय सहायता और भारत में अध्ययनरत बड़ी संख्या में अफगानी छात्रों का भी हवाला दिया। भारत ने अफगानी लोगों एवं सरकार के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए अपना संकल्प दोहराया क्योंकि वे एक शांतिपूर्ण, प्रजातांत्रिक एवं बहुलवादी अफगानिस्तान का निर्माण करते है।

1 दिसम्बर, 2009 को अपने देश की अफगान-पाक रणनीति की समीक्षा के संबंध में अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा के भाषण के बाद भारत ने अफगानिस्तान सरकार और अफगान सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने का स्वागत किया। भारत ने आतंकवाद का चौतरफा मुकाबला करने की आवश्यकता और पाकिस्तान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना कि वह अपने भूभाग में आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना नहीं बनाने देगा, के संबंध में राष्ट्रपति ओबामा की बात का भी स्वागत किया।

अफगानिस्तान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 28 जनवरी, 2010 को लंदन में आयोजित किया गया, जिसकी संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार और ब्रिटेन सरकार द्वारा संयुक्त रूप से मेजबानी की गई। विदेश मंत्री ने इस सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन के पश्चात जारी की गई विज्ञप्ति के माध्यम से अफगानिस्तान के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दीर्घावधिक वचनबद्धता और अफगानिस्तान सरकार तथा देश की सुरक्षा, विकास और शासन के लिए इसके समर्थन पर जोर दिया गया। इस बात पर सहमति हुई कि इस वर्ष के बाद अफगानिस्तान सरकार की मेजबानी में काबुल सम्मेलन के पश्चात लंदन सम्मेलन होगा।

बांगलादेश

भारत ने बांगलादेश सरकार के साथ सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर संपर्क बनाये रखा। जनवरी, 2009 में प्रधान मंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार के गठन के पश्चात भारत और बंगलादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम मिला। दोनों सरकारों ने पारगमन, संपर्क बहाल करने, सुरक्षा इत्यादि सहित कई मुद्दों पर आगे बातचीत की। दोनों सरकारों के बीच उच्च स्तरीय मंत्रालयी एवं अधिकारी स्तरीय संपर्क अप्रैल-दिसंबर 2009 तक स्थापित किये गए। विदेश सचिव श्री शिव शंकर मेनन ने 12-13 अप्रैल, 2009 के दौरान ढाका का दौरा किया और बंगलादेश के विदेश मंत्री डा. दीपु मोनी ने 7-10 सितम्बर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा के साथ उनकी बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने व्यापार सुविधा संपर्क, पारगमन, विद्युत आदि सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद रोकने की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति जताई और इसे सुदृढ़ करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। डा. दीपु मोनी ने प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल से भी मुलाकात की। विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव अपने समकक्ष के साथ प्रगति की समीक्षा करने के लिए 14-15 नवम्बर, 2009 के दौरान ढाका में थीं। उन्होंने बंगलादेश के प्रधान मंत्री से मुलाकात की।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रही। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर जून 2009 में न्यूयार्क में बंगलादेश के विदेश मत्री डा. दीपु मोनी से मिली बाद में विदेश मंत्री डा. दीपु मोनी और बंगलादेश के प्रधान मंत्री के सलाहकार श्री एच टी इमाम ने कोलंबो जाते समय नई दिल्ली में प्रवास के दौरान 9 जुलाई, 2009 को विदेश मत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठक के अवसर पर शरम-एल-शेख (मिस्र) में 15 जुलाई, 2009 को बंगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। विदेश राज्य मंत्री डा. शशि थरूर ने भी विदेश मंत्री डा. दीपु मोनी के साथ बैठक की। इन उच्च स्तरीय बातचीत से यह सुनिश्चित हुआ कि दोनों पक्षों का द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर विचारों का नियमित रूप से आदान-प्रदान हुआ।

भारत सुरक्षा संबंधी अपनी चिंताओं पर विशेष तौर पर भारतीय विद्रोही समूहों (आई आई जी एस) और अन्य देश आतंकवादियों द्वारा बंगलादेश भूभाग का इस्तेमाल करने के मामले में बंगलादेश के साथ बात करता रहा है। 30 नवम्बर-2 दिसम्बर 2009 के दौरान नई दिल्ली में द्विपक्षीय गृह सचिव स्तरीय वार्ता हुई जिसमें आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता से संबद्ध करार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी का मुकाबला करने संबंधी करार और सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए।

संबंधित सुरक्षा बलों के महानिदेशक स्तर का पिछला सीमा समन्वय सम्मेलन 11-14 जुलाई, 2009 के दौरान आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन के अनेक मुद्दों पर चर्चा की और सीमापार अपराधों की रोक थाम के लिए संयुक्त प्रयासों को सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की।

अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री डॉ. रंगजिन स्पाण्टा ने 27 जुलाई, 2009 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की।

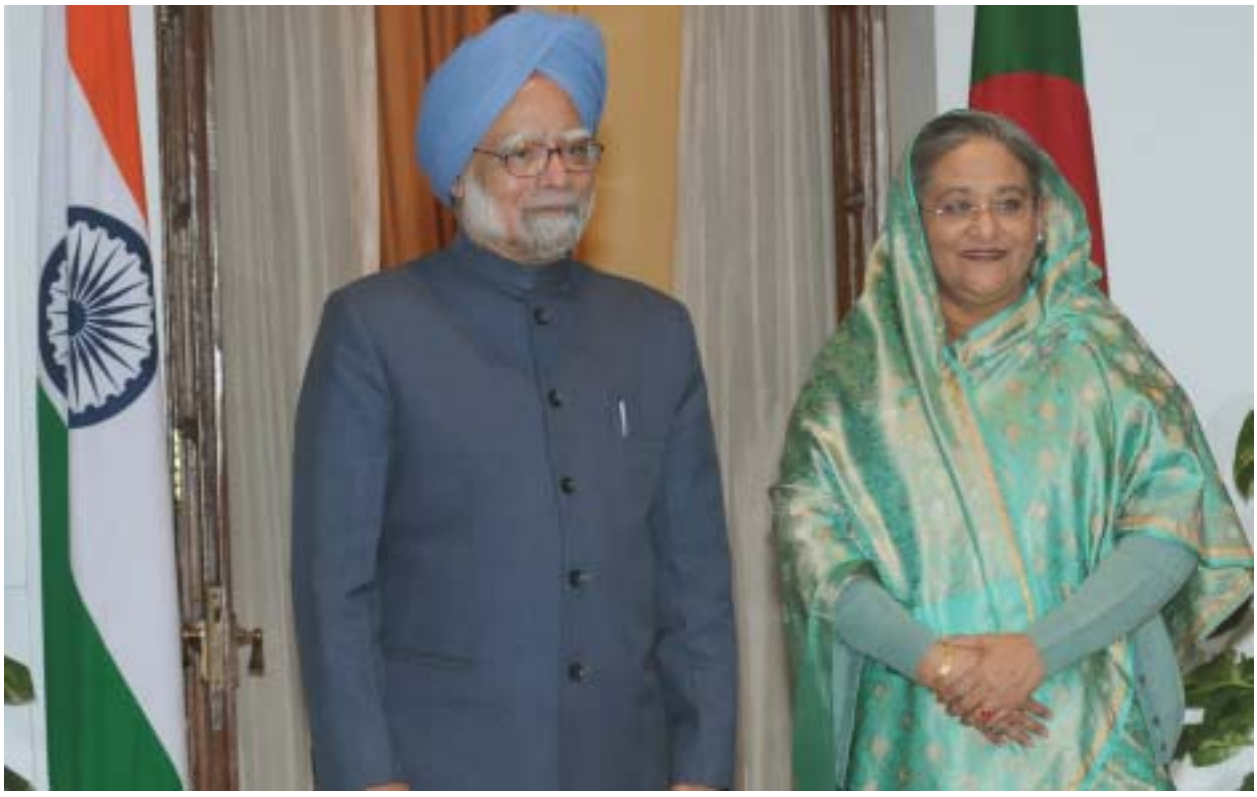

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की 11 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री श्रीमती शेख हसीना से मुलाकात।

पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय पण्य व्यापार तेजी से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान बंगलादेश का भारत के साथ 3273.70 मिलियन अमेरीकी डालर का आयात और 358.08 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात हुआ। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, बंगलादेश को भारत से 2841.06 मिलियन अमेरीकी डालर का आयात हुआ जोकि बंगलादेश के वैश्विक आयात का लगभग 13% है। बंगलादेश का भारत के साथ 276.85 मिलियन अमेरीकी डालर का निर्यात हुआ।

भारत को बंगलादेशी उत्पाद के निर्यात में सहायता करने के लिए कई एकपक्षीय पहल की गई हैं, जिनमें त्रिपुरा को 28 मिलियन अमरीकी डालर की निर्माण वाली ईंटों के निर्यात का करार शामिल है। व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्तूबर 2009 में बेलोनिया फेनी एल सी एस खोल दिया गया है। व्यापार से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए अगस्त, 2009 में व्यापार संबंधी संयुक्त कार्य दल की बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के व्यवसाय समुदाय द्वारा सामना की गई उप-शुल्क एवं गैर-शुल्क समस्याओं से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। भारत ने बंगलादेश मानक जांच संस्थान को उन्नत करने एवं क्षमता निर्माण में मदद करने का वादा किया।

अन्तर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (आई डब्ल्यू टी टी) संबंधी प्रोतोकाल के अंतर्गत स्थायी समिति की 11वीं बैठक अक्तूबर, 2009 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और बंगलादेश के बीच एक अन्तर-सरकारी रेल बैठक मई, 2009 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।

वर्ष 2009 के दौरान, संस्कृति के क्षेत्रों में आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से दोनों देशों के बीच लोगों में आपसी संपर्क बढ़े हैं। इनमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) द्वारा प्रतिनियुक्ति पर बंगलादेश भेजे गए भारतीय शिक्षकों द्वारा संगीत, नृत्य एवं थियेटर प्रदर्शन, कला प्रदर्शनियों और योग की कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण का आयोजन करना, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत, मणिपुरी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त भारत में विविध क्षेत्रों में अध्ययन के लिए बंगलादेश से आए छात्रों को आई सी सी आर की 'बंगलादेश छात्रवृत्ति स्कीम', 'कोलंबो योजना' 'आयुष स्कीम' के अंतर्गत सहित 100 से अधिक छात्रवृत्तियां दी गई।

आई सी सी और के सांस्कृतिक केन्द्र के फरवरी, 2010 में ढाका में औपचारिक रूप से उद्घाटन किए जाने की संभावना है।

बंगलादेश एक महत्वपूर्ण आई टी ई सी भागीदार देश है। आई टी ई सी कार्यक्रम और कोलंबो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम के अंतर्गत 2009-10 में बंगलादेश के सहभागियों के लिए कुल 100 स्लाट्स प्रदान किए गए हैं। लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग में सामान्य पाढ्यक्रम और संस्कृति, नाटक, संगीत, ललित कला और खेद कूद आदि में भी विशेष पाढ्यक्रम चलाने के लिए आई सी सी आर द्वारा बंगलादेश के छात्रों को प्रत्येक वर्ष 100 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

भूटान

भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जोकि विश्वास, समझ, आपसी हित और कल्याण पर आधारित हैं। वर्ष के दौरान दोनों ही देशों से कई उच्चस्तरीय दौरे किए गए। द्विपक्षीय बातचीत में जलविद्युत, परिवहन, संचार, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आई टी, उद्योग, दवा और कृषि के क्षेत्र शामिल हैं।

भूटान की ओर से उच्च स्तरीय दौरों में जून-जुलाई 2009 में भूटान के प्रधान मंत्री श्री लियोन्चेन जिग्मी वाई थिनले का भारत दौरा शामिल है। भारत की ओर से भूटान के उच्चस्तरीय दौरों में विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा (जून 2009), गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम (अगस्त 2009), संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री श्री पवन कुमार बंसल (अक्तूबर 2009) मुख्य सूचना आयुक्त श्री वजाहत हबीबुल्लाह (मई 2009), प्रधानमंत्री के विशेष राजदूत श्री श्याम सरन (जुलाई 2009), विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव (सितम्बर 2009), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय (सितम्बर 2009) और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला (अक्तूबर 2009) के दौरे शामिल थे।

भूटान की शाही सरकार (आर जी ओ बी) के प्रधानमंत्री लियोन्चेन जिग्मी वाई थिन्ले ने 28 जून-3 जुलाई 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान द्विपक्षीय बातचीत में भारत-भूटान संबंधों के विभिन्न आयाम एवं संबंधों को और आगे बढ़ाने के उपाय शामिल थे। क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं अप्रैल 2010 में थिम्पू में आगामी 16वें सार्क शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा की गई। भूटान में अचानक आई बाढ से हुई जान व माल की क्षति पर सहानुभूति प्रकट करते हुए भारत के प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने एकजुटता की भावना से अचानक आई बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की।

भारत के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वांग्चुक ने 21-26 दिसम्बर, 2009 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया। श्री उगयेन शेरिंग, विदेश मंत्री, श्री खांडू वांग्चुक, आर्थिक कार्य मंत्री और शाही सरकार के अन्य अधिकारी भूटान नरेश के साथ थे। यह भूटान नरेश का नवम्बर 2008 में औपचारिक राज्याभिषेक के बाद विदेश का प्रथम राजकीय दौरा था।

सातवीं भारत-आसियान शिखर वार्ता के दौरान 24 अक्तूबर, 2009 को प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह चीन के प्रधान मंत्री श्री वेन जिया बाओ से हाथ मिलाते हुए।

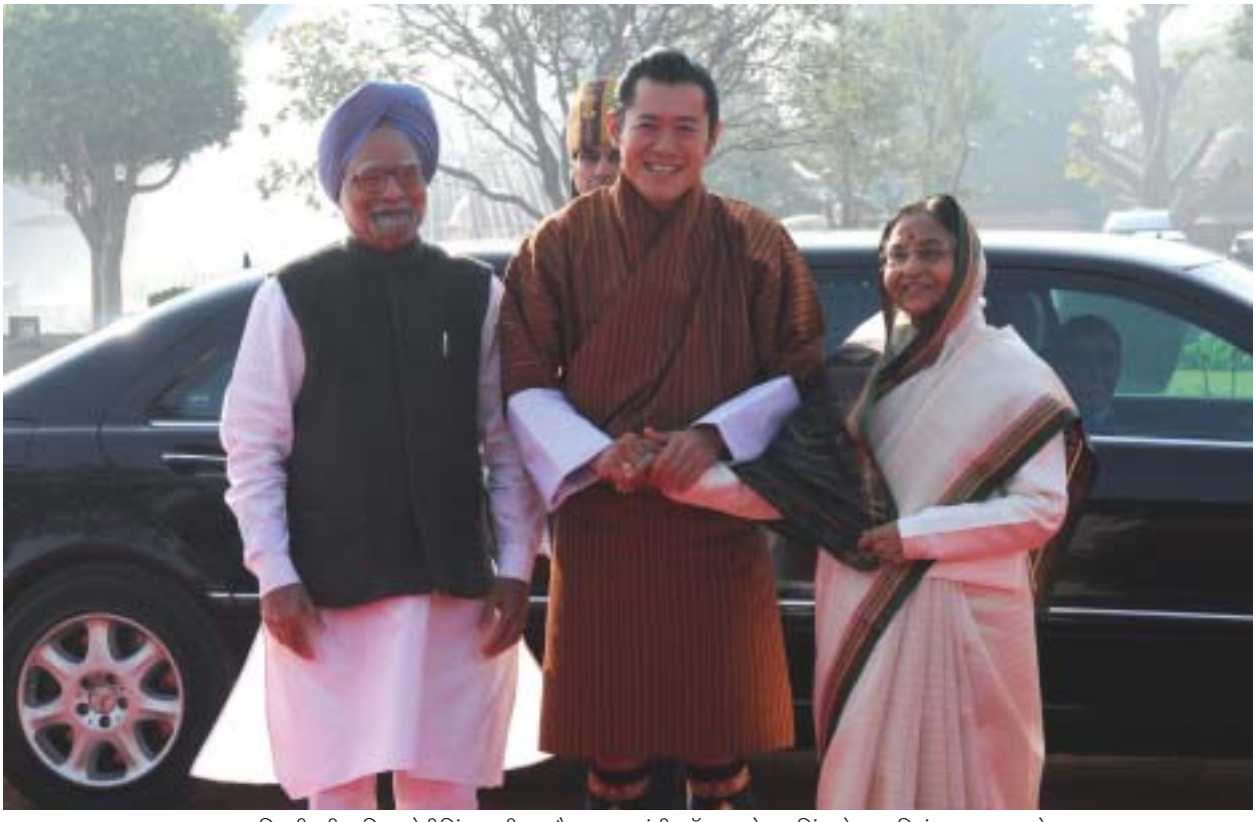

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर, 2009 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भूटान नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का समारोहपूर्वक स्वागत किया।

भारत में प्रवास के दौरान भूटान नरेश ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यू पी ए अध्यक्ष, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव के साथ आपसी बैठकें बहुत मैत्रीपूर्ण, गर्मजोशी एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई, जिससे विश्वास, सहयोग और भारत और भूटान के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों का संकेत मिलता हैं। परिचर्चा में जल विद्युत क्षेत्र, आई टी, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन आदि एवं क्षेत्रीय एवं बहुविध मुद्दों सहित आपसी हित, और द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे शामिल थे।

इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 12 करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। हमारे प्रधान मंत्री ने भूटान में सितम्बर 2009 में आये भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपए की सहायता देने की वचनबद्धता दोहराई। दौरे के दौरान भूटान नरेश ने एक फोटो प्रदर्शनी 'भूटान एन आई टू हिस्ट्री ' जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पर भारत-भूटान संबंधों को चित्रित करता है, का उद्घाटन किया और 'चेंजिंग टाइम एण्ड टाइमलेस वैल्यूज' के संबंध में माधवराव सिंधिया स्मारक व्याख्यान दिया।

भूटान की शाही सरकार के विदेश मंत्री ल्यून्पो उगयेन शेरिंग ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के साथ कोलकाता में रायल भूटान कंसुलेट का उद्घाटन करने के लिए 17 दिसम्बर, 2009 को, जिस दिन संयोगवश भूटान का 102वां राष्ट्रीय दिवस भी पड़ता है, कोलकाता का दौरा किया।

भूटान की शाही सरकार के आर्थिक कार्य मंत्री ल्योन्पो खांडु वांग्चुक ने पुनातसांग्चु-I जल विद्युत प्राधिकरण की सातवीं बैठक में भाग लेने के लिए 4-8 जनवरी, 2010 के दौरान भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान भूटान के मांगडेचु और पुनातसांग्चु में दो नई जल विद्युत परियोजनाओं के करारों के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दिया गया।

भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने 18-19 जून, 2009 के दौरान भूटान का दौरा किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात यह उनका पहला विदेश दौरा था। दौरे के दौरान विदेश मंत्री का भूटानी नेता एवं भूटानी समकक्ष के साथ विचारों का गहन आदान-प्रदान हुआ और दोनों ने संयुक्त रूप से पारो-बागडोगरा ड्रंक एअर फ्लाइट का उद्घाटन किया और नेहरू-वांग्चुक छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया।

गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 21-24 अगस्त, 2009 के दौरान भूटान का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान, आपसी सुरक्षा चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रधान मंत्री के विशेष राजदूत श्री श्याम सरन ने 27-31 जुलाई, 2009 के दौरान भूटान का दौरा किया, उस दौरान उन्होंने भूटान में आगामी सार्क शिखर सम्मेलन, जिसका मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन था, के लिए संभावित कार्यसूची एवं कार्यकलापों पर चर्चा की।

विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने 12-14 सितम्बर, 2009 के दौरान भूटान का दौरा किया, विदेश सचिव के रूप में पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा था। उन्होंने आपसी हित के मामलों पर व्यापक चर्चा की।

श्री पवन कुमार बंसल, संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री ने अक्तूबर, 2009 में 'डीपनिंग एण्ड सस्टेनिंग डेमोक्रेसी इन एशिया 'विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला ने अक्तूबर, 2009 में भूटान का दौरा किया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय ने सितम्बर 2009 में भूटान का दौरा किया, मुख्य सूचना आयुक्त श्री वजाहत हबीबुल्लाह ने मई, 2009 में भूटान का दौरा किया और प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन ने नवम्बर, 2009 में भूटान का दौरा किया।

सीमा सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी भारत-भूटान संयुक्त कार्यकारी दल की छमाही बैठक 8-9 सितम्बर, 2009 के दौरान थिम्पू में आयोजित की गई। सचिव (सीमा प्रबंधन), भारत सरकार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारत भूटान का निरंतर सबसे बड़ा व्यापार एवं विकास साझेदार रहा है। भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (एफ वाई पी) के दौरान 3400 करोड़ रुपये की सहायता दी। इसमें परियोजना से संबंधित सहायता (मुख्य आर्थिक क्षेत्रों में 65 परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये), कार्यक्रम अनुदान (700 करोड़ रुपये) और लघु विकास परियोजनाएं (700 करोड़ रुपये) शामिल हैं। 10वीं योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में उच्चतम न्यायालय भवन का निर्माण, सांविधानिक कार्यालयों, जैसे शाही प्राधिकरण, चुनाव आयोग, भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग एवं महाधिवक्ता का सुदृढ़ीकरण, प्रमुख जौंग का नवीकरण, वृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी, बड़ी सड़कों को चौड़ा करना, ई-गर्वनैंस, छात्रवृत्ति और तृतीयक शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार शामिल है।

भारत सरकार जलविद्युत क्षेत्र में विकास के लिए भूटान को सहायता प्रदान करने और 2020 तक भूटान से कम से कम 10,000 मेगावाट विद्युत खरीदने पर सहमत थी। इस प्रयोजन के लिए दोनों देशों द्वारा दस जलविद्युत परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं।

भारत ने कई भूटानी छात्रों एवं अधिकारियों को छात्रवृत्ति एवं क्षमता विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भूटान को तकनीकी सुविज्ञता एवं विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की। 10वीं योजना के अंतर्गत अन्डर

ग्रेजुएट स्लॉट में प्रतिवर्ष 85 तक और पोस्टग्रेजुएट स्लॉट में 77 तक वृद्धि हुई है।

नौवां सार्क व्यापार मेला 11-14 सितम्बर, 2009 के दौरान थिम्पू में आयोजित किया गया। भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका की 150 से अधिक कंपनियों ने इस मेले में भाग लिया। भारत की ओर से, इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन (आई टी पी ओ) ने टाटा मोटर्स, भेल, एल एण्ड टी, एच सी सी, विभिन्न हेंडीक्राफ्ट्स एण्ड टेक्सटाइल एस एम ई एस सहित लगभग 40 भारतीय कंपनियों की भागीदारी की व्यवस्था की।

चीन जनवादी गणराज्य

इस वर्ष में चीन के साथ निरंतर उच्च स्तरीय बातचीत हुई और साथ ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाओं के बारे में अलग से भी बैठकें की गई हैं। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने एस सी ओ/बी आर आई सी शिखर बैठक के अवसर पर 15 जून, 2009 को येकतरिनबर्ग में चीन के राष्ट्रपति श्री हू जिन्ताओं से मुलाकात की। प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ की अक्तूबर, 2009 में पूर्वी एशिया/एशियाई शिखर बैठक के अवसर पर हुवा हिन में बैठक हुई। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने 22 जुलाई, 2009 को पूर्वी एशिया शिखर मंत्रालयी बैठक के अवसर पर फुकेट (थाइलैंड) में और उसके बाद रूस-भारत-चीन (आर आई सी) त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर 27 अक्तूबर, 2009 को बंगलुरू में चीन के विदेश मंत्री श्री यांग जियाची से मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान, विचारों का सार्थक आदान-प्रदान किया गया और दोनों देशों के बीच रणनीतिक एवं सहयोगपूर्ण साझीदारी की भावना से आपसी राजनीतिक विश्वास और समझ पैदा करने के प्रयास जारी रखने एवं सुदृढ़ करने पर दोनों नेता सहमत थे। नेताओं ने दोनों देशों द्वारा सामना किए जा रहे है वैश्विक मुद्दों जैसे नई वैश्विक संरचना का सृजन, जलवायु परिवर्तन, विकास, दूसरे शब्दों में स्थाई विकास और नये वैश्विक वित्तीय क्रम से संबद्ध रणनीतियों से उत्पन्न द्विपक्षीय संबंधों एवं सामंजस्य के व्यापक क्षेत्र का भी उल्लेख किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन और चीनी राज्य काउंसलर देयी बिनगुआ के बीच सीमा प्रश्न पर भारत-चीन की विशेष प्रतिनिधि स्तर की तेरहवें चरण की वार्ता 7-8 अगस्त, 2009 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई। दो विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा प्रश्न के समाधान के लिए समाधान की रूपरेखा पर चर्चा जारी रखी। दोनों देशों के नेताओं ने विभिन्न अवसरों पर उचित, उपयुक्त और आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों पक्षों ने यह घोषणा की है कि सीमा प्रश्न के शीघ्र समाधान से दोनों देशों के आधारभूत हित आगे आएंगे, अतः इन पर रणनीतिक उद्देश्य के रूप में कार्रवाई की जाए। इसी बीच, 1993, 1996 और 2005 में हस्ताक्षर किए गए संगत करारों के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन बहाल है, जिसके परिणामस्वरूप सीमा समाधान के मुद्दे के संबंध में चर्चा पर प्रगति के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल पैदा हुआ है।

चीन फिलहाल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2008 में 51.8 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ जिसमें 2007 की तुलना में 34% वृद्धि दर्ज हुई है। चीनी सीमा शुल्क गणना के अनुसार, जनवरी-अक्तूबर 2009 की अवधि के दौरान व्यापार 34.30 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँच गया और इस प्रकार व्यापार घाटा 12.84 बिलियन अमरीकी डालर रहा। वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप कुल व्यापार में 2008 के सदृश आंकड़ों की तुलना में 26.52% गिरावट आई। चीन के साथ व्यापार घाटे में वृद्धि भारत के लिए चिंता का विषय है और इस मामले के बारे में चीनी नेतृत्व को उच्च स्तर पर अवगत करा दिया गया है। चीन के प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री को आश्वासन दिया है कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि अधिक से अधिक भारतीय उत्पाद चीन पहुँचे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने भारत-चीन संयुक्त आर्थिक दल (जे ई जी) की आठवीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जो 19 जनवरी, 2010 को बीजिंग में आयोजित की गई। जे ई जी ने आपसी चिंता के अन्य मामलों के साथ-साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा की।

2008 में बीजिंग ओलंपिक और पैराओलंपिक के संबंध में चीनी प्राधिकारियों द्वारा लगाये गए अस्थाई प्रतिबंधों के पश्चात 2009 में नाथू ला, लिपुलेख पास और शिप कीला के रास्ते सीमा पार व्यापार प्रारंभ किया गया।

वर्ष के दौरान भारत और चीन के बीच रक्षा सहयोग में काफी गति आई। नौसेना अध्यक्ष ने 21-24 अप्रैल, 2009 के दौरान क्विंगडेव में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट समीक्षा 2009 में भाग लिया। भारतीय भागीदारी में गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रायर आई एन एस मुंबई, आई एन एस रणबीर, गाइडेड मिसाइल कोरविट आई एन एस खंजर और टैंकर आई एन एस ज्योति शामिल थे। चीनी 'शेंचेन' मिसाइल डेस्ट्रायर ने 8-11 अगस्त, 2009 के दौरान कोच्चि पत्तन की यात्रा की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दिसम्बर 2009 में भारत का दौरा किया। रक्षा सचिव ने 6 जनवरी, 2009 को बीजिंग में आयोजित तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता में भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

वर्ष के दौरान कई मुद्दों को शामिल करते हुए भारत और चीन के बीच संस्थागत वार्ता तंत्र ने तीव्र प्रगति दर्शायी। दो देशों के बीच

दूसरे चक्र की कांसुलर वार्ता 5 मार्च, 2009 को बीजिंग में आयोजित की गई। चर्चा के दौरान विभिन्न बकाया द्विपक्षीय कौंसली और वीजा मामलों पर जोर दिया गया। सीमा पार नदियों के संबंध में भारत-चीन विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की तीसरी बैठक 21-25 अप्रैल, 2009 के दौरान बीजिंग में आयोजित की गई। दोनों देशों ने 9 अक्तूबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोजन वार्ता के तहत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मामलों पर विचारों का सार्थक आदान-प्रदान किया।

डब्ल्यू टी ओ वार्ता के दोहा दौर, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक वित्तीय संकट आदि जैसे मुद्दों पर दोनों देशों ने वैश्विक मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत जारी रखी। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सम्मेलनों के दौरान उच्च स्तरीय बैठकें भी संबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता बनी रहीं। दोनों पक्ष ने सदस्य और प्रेक्षक के रूप में पूर्वी एशिया शिखर बैठक आसियन-भारत शिखर बैठक, आर आई सी, एस सी ओ आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों पर भी बातचीत की।

अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों में सहयोग संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

- परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. अनिल काकोडकर ने आई ए ई ए द्वारा 20-22 अप्रैल, 2009 के दौरान बीजिंग में आयोजित परमाणु ऊर्जा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालयी सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम की मेजबानी चीनी सरकार ने चीन परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के माध्यम से की और इसका सह-प्रायोजन ओ ई सी डी की परमाणु ऊर्जा एजेंसी और चीन परमाणु ऊर्जा एसोसिएशन ने किया।

- तत्कालीन युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्री अरुण यादव 15-24 जून, 2009 के दौरान चीन गए तथा चौथे 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अखिल चीन युवा संघ के उपाध्यक्ष श्री हे जुंके के नेतृत्व में चौथे चीनी युवा प्रतिनिधिमंडल ने 19-28 नवम्बर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया।

- पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने 24-27 अगस्त, 2009 के दौरान बीजिंग का दौरा किया और दिसम्बर, 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन मुद्दों के संबंध में चीन के साथ परामर्श किया। उन्होंने बी ए एस आई सी देशों की बैठक में भाग लेने के लिए 27-28 नवम्बर, 2009 के दौरान चीन का भी दौरा किया, उस दौरान चीन के प्रधान मंत्री श्री वेन जियाबाओ से मुलाकात की।

- विदेश मंत्रालय और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग (एम ई ए - आई एल डी कार्यक्रम) के बीच 2004 में आयोजित आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री बी.एस. येदुरेप्पा ने सितम्बर 2009 में चीन का दौरा किया।

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने एस सी ओ हेड ऑफ गवर्नमेंट कांउसिल बैठक में भाग लेने के लिए अक्तूबर, 2009 में चीन का दौरा किया।

- सिचुएन पार्टी सचिव लियू क्विबाउ ने नवम्बर 2009 में भारत का दौरा किया, उस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री से मुलाकात की और बंगलुर में कर्नाटक के मुख्य मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई।

मालदीव

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बने रहे। दोनों देश उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से इन संबंधों को और मजबूत बनाने में लगे रहे।

श्री मोहम्मद नशीद, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति ने 22-23 अक्तूबर, 2009 के दौरान आयोजित 'जलवायु परिवर्तनः प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण संबंधी दिल्ली उच्च स्तरीय सम्मेलन' में सम्मानीय अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर अक्तूबर 2009 में भारत का दौरा किया।

भारत के उप राष्ट्रपति श्री हामिद मोहम्मद अंसारी के निमंत्रण पर मालदीव के उप राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद वहीद ने 18-24 फरवरी, 2010 के दौरान भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान डॉ0 वहीद ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील और उप राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा से मुलाकात की। इस यात्रा से भारत और मालदीव के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में और मजबूती आई।

डा. अहमद शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री ने 27-30 जुलाई, 2009 के दौरान भारत का सरकारी दौरा किया। उन्होंने 28 जुलाई, 2009 को विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। श्री इब्राहिम हुसैन जकी, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति के विशेष दूत ने 22-24 अप्रैल, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान श्री जकी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन, विदेश सचिव श्री शिव शंकर मेनन और प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरन से मुलाकात की। श्री जकी ने अगस्त 2009 में भारत का पुनः दौरा किया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री अमीन फैसल ने 27-31 अक्तूबर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान श्री फैसल ने रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ भारतीय रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा के दौरान विभिन्न रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय

मालदीव के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद नसीद की 22 अक्तूबर, 2009 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 19 अगस्त, 2009 को नई दिल्ली में नेपाल के प्रधान मंत्री श्री माधव कुमार नेपाल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करते हुए।

सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया गया। मालदीव के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अब्दुल्लाह सईद ने भी 19-23 सितंबर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया और सीमापार निवेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम और विधिक पहलुओं पर क्षेत्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली में भाग लिया। दौरे के दौरान मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्लाह सईद ने विधि एवं न्याय मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी मुलाकात की।

रक्षा मंत्री ने 20-22 अगस्त, 2009 के दौरान मालदीव का सरकारी दौरा किया। दोनों देशों ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें तटसुरक्षा और समुद्री निगरानी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल है। इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डा. मोहम्मद वहीद हसन मानिक से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने मालदीव के रक्षामंत्री से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29-30 जून, 2009 के दौरान मालदीव में भारत के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने मालदीव के राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की।

विदेश सचिव ने 22-25 जनवरी, 2010 के दौरान मालदीव का दौरा किया । दौरे के दौरान विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव ने मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की । उन्होंने हनीमाधु द्वीप का भी दौरा किया जहां पर जी एम आर एअरपोर्ट की स्थापना में जुटा हुआ है ।

श्री मोहम्मद शिहाब, मालदीव के गृह मंत्री ने 3-8 फरवरी, 2010 के दौरान भारत का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान श्री शिहाब ने केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और पुलिस से संबंधित कुछ संस्थानों का दौरा किया। थल सेना अध्यक्ष ने 11-14 फरवरी, 2010 के दौरान मालदीव का दौरा किया।

भारत ने मालदीव के विकासात्मक प्रयासों में सहायता प्रदान करना जारी रखा। भारत के एक विशेषज्ञ दल ने 6-11 जुलाई, 2009 के दौरान मालदीव का दौरा किया और मालदीव में पुलिस अकादमी स्थापित करने के लिए मालदीव के प्राधिकारियों के साथ बातचीत की। भारत ने सिविल एवं सुरक्षा संबंधी दोनों क्षेत्रों में मालदीव के राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना भी जारी रखा।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9-11 अगस्त, 2009 के दौरान माले में इन्दिरा गांधी मेमोरियल होस्पीटल (आई जी एम एच), माले के संबंध में संयुक्त समिति की प्रथम बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस संयुक्त समिति ने आई जी एम एच द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार करने संबंधी कई उपायों पर सहमति प्रकट की। इसमें भारत के चिकित्सा विशेषज्ञों की तैनाती, चिकित्सा उपयोज्य वस्तुएं एवं उपस्कर उपलब्ध कराना, मौजूदा आई जी एम एच संरचना आदि के नवीकरण में सहायता प्रदान करना शामिल है।

भारत-मालदीव सैन्य दल के संयुक्त अभ्यास 'इकुवेरिन' 18-30 अक्तूबर, 2009 के दौरान बेलगांव सिटी के रोहिदेश्वर कैंप में आयोजित किया गया। मालदीव के रक्षा मंत्री श्री अमीन फैसल ने अंतिम दिन माड्रिल देखा और अभ्यास को भारत और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग को गहन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और ऐसे अभ्यास करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।

भारत-मालदीव संयुक्त तटरक्षक अभ्यास, दोस्ती-एक्स 1-4 दिसम्बर, 2009 के दौरान माले में आयोजित किया गया। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक ने दिसम्बर, 2009 में मालदीव का दौरा किया, संयोगवश उसी समय उपरोक्त अभ्यास चल रहे थे। महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल ने मालदीव के अन्य विशिष्ट लोगों से मिलने के अलावा मालदीव के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की।

दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। वर्ष 2008-09 के पहले दस महीनों में 5783.20 लाख रुपये का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, दिसम्बर, 2009 में जो कि विगत वर्ष के सदृश्य अवधि में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) माले ने मालदीव मुद्रा प्राधिकरण (एम एम ए) द्वारा जारी 100 मिलियन अमरिकी डालर के ट्रेजरी ब्रॉन्ड के संपूर्ण निर्गम को अभिस्त किया।

वर्ष के दौरान कई भारतीय निजी कंपनियों ने भी मालदीव में निवेश परियोजनाएं प्रारंभ करने में अपनी रुचि दिखाई। नवम्बर 2009 में तीन भारतीय कंपनियों नामतः जी एम आर इफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल लिमिटेड, सुजलोन एनर्जी और श्री एडुकेयर प्रा. लि. ने क्रमशः अवसंचरना, स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में मालदीव सरकार के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। अवसंरचना के क्षेत्र में जी एम आर इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल लि., भारत ने अपर नार्थ प्रोविन्स के हनीमाधु में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित करने के लिए एक तकनीकी व्यवहार्यता एवं सुसाध्यता अध्ययन करने के लिए मालदीव की सरकार के साथ 5 नवम्बर, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ऊर्जा क्षेत्र में सुजलोन इनर्जी ने 40 मिलियन डालर की लागत से 25 एम डब्ल्यू विंड फार्म का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। शिक्षा के क्षेत्र में श्री एडु केयर प्रा.लि., दिल्ली ने ग्यासुद्दीन स्कूल, माले के प्रबंधक का अधिकग्रहण करने के लए मालदीव के शिक्षा मंत्रालय के साथ एक करार पर हस्ताक्षर, किया जो कि इस क्षेत्र में सरकार के निजीकरण योजना के अंतर्गत इस प्रकार की प्रथम पहल है।

भारत-मालदीव मैत्री सप्ताहः 63वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के भाग के रूप में 12-21 अगस्त, 2009 के दौरान भारत क्लब, मालदीव के पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय और मालदीव के विदेश मंत्रालय के सहयोग से मिशन द्वारा 'भारत-मालदीव

मैत्री सप्ताह 'मनाया गया। 12 अगस्त को 'सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनः बदलते समाज में संस्कृति का भविष्य' पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें भारत के तीन प्रख्यात वक्ताओं ने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के प्रायोजन में व्याख्यान दिए। उप राष्ट्रपति डा. मोहम्मद वहीद हसन मानिक ने 14 अगस्त, 2009 को औपचारिक रूप से मैत्री सप्ताह का उद्घाटन किया। मैत्री सप्ताह से संबंधित अन्य कार्यकलापों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शांति और मैत्री के प्रयास, खाद्य महोत्सव, अन्तर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित टीम द्वारा प्रस्तुत संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन भारतीय कलाकारों द्वारा लंबाडा संगीत प्रदर्शन और फिल्म महोत्सव शामिल थे जिसमें धीवेही चलचित्रों के साथ-साथ फिल्म प्रभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हिंदी, तमिल, मल्लायम के चलचित्र प्रदर्शित किये गए। 21 अगस्त, 2009 को मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा उप राष्ट्रपति डा. मोहम्मद वहीद हसन मानिक और कई कैबिनेट मंत्रियों एवं मालदीव सरकार के वरिष्ठ कार्यकर्त्ताओं की मौजूदगी में मैत्री सप्ताह के ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

भारत-मालदीव साहित्यिक सोसाइटीः मालदीव के पर्यटन मंत्री डा. अहमद अली सवाद द्वारा 25 जून, 2009 को भारतीय उच्चायोग, मालदीव के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा संयुक्त रूप से माले स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मार्डन आर्ट में भारत-मालदीव साहित्यिक सोसाइटी का उद्घाटन किया गया। उच्चायुक्त ने भी राष्ट्रीय पुस्तकालय में 'इंडियन कोरनर ' के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय पुस्तकालय को 150 पुस्तकें प्रदान की।

पुराना किला, नई दिल्ली में 11-13 दिसम्बर, 2009 के दौरान आयोजित दक्षिण एशियाई बैंड्स महोत्सव के तीसरे संस्करण के लिए आई सी सी आर द्वारा एक पाँच सदस्यीय मालदीवियाई रॉक बैंड का प्रायोजन किया गया था।

म्यांमा

भारत-म्यांमा के संबंधों की जड़ें ऐतिहासिक, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव से जुड़ी हैं। भारत और म्यांमा की लगभग 1640 किमी लम्बी साझी भू-सीमा है और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा से लगती है। भारतीय मूल के काफी बड़ी संख्या में लोग (एक अनुमान के अनुसार लगभग 2.5 मिलियन) म्यांमा में रहते हैं। इसके अतिरिक्त, म्यांमा एक मात्र एशियान देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है। यह भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क है।

वर्ष के दौरान द्विपक्षीय बातचीत और दौरे जारी रहे। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने ने पी ताव में 12वीं बिम्सटेक मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए 10-11 दिसबंर, 2009 के दौरान म्यांमा का दौरा किया। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत करने के लिए म्यांमा के प्रधान मंत्री जनरल थीन सेन से मुलाकात की।

भारी उद्योग मंत्री श्री विलासराव देशमुख के निमंत्रण पर म्यांमा के उद्योग सं. (2) के मंत्री वाइस एडमिरल सोई थाने ने 19-23 दिसंबर, 2009 के दौरान भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान मंत्री ने जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स संयंत्र की यात्रा भी की थी।

रक्षा क्षेत्र में म्यांमा सेना के कार्मिकों के लिए द्विपक्षीय यात्राओं और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आदान-प्रदान जारी रहे। राज्य शांति व विकास परिषद के उपाध्यक्ष वाइस सीनियर जनरल मोंग आई के निमंत्रण पर जनरल दीपक कपूर, सीओएससी एवं सीओएएस के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 12-14 अक्तूबर, 2009 के दौरान म्यांमा की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वाइस सीनियर जनरल मोंग आई के साथ बैठक की तथा एसपीडीसी के अध्यक्ष सीनियर जनरल थांग स्वे से मुलाकात की।

विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव 28 फरवरी-2 मार्च 2010 के दौरान विदेश कार्यालय परामर्श (एफ ओ सी) के लिए म्यांमा की यात्रा की। उन्होंने म्यांमार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की।

सैन्य बल चिकित्सा दल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र सिंह ने 16-20 फरवरी, 2009 के दौरान म्यांमा की यात्रा की। मेजर जनरल शक्ति गुरंग के नेतृत्व में एक 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 35वीं भारत-म्यांमा सीमा संपर्क बैठक में भाग लेने के लिए 23-27 फरवरी, 2009 के दौरान म्यांमा की यात्रा की। सैन्य आसूचना महानिदेशक ले. जनरल बी.एस.बटवाल के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 2-6 मार्च, 2006 के दौरान म्यांमा की यात्रा की। पूर्वी कमान के स्टाफ अध्यक्ष ले. जनरल पी.के. गोयल के नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 18-20 अगस्त, 2009 को म्यांमा की यात्रा की। सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीएमटी) ले. जनरल वी.के. अहलूवालिया ने 2-4 सितंबर, 2009 के दौरान म्यांमा की यात्रा की।

म्यांमा वायु सेना के अध्यक्ष मेजर जनरल खिन आंग मिंट ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय एयरो स्पेस प्रदर्शनी एयरो इंडिया-2009 में भाग लेने के लिए 11-15 फरवरी, 2009 के दौरान भारत की यात्रा की।

भारत म्यांमा में अवस्थापन्न एवं मानव संसाधन विकास में सहायता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध रहा है। दोनों पक्षों के

मध्य कई परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। एचएमटीआई, टाटा मोटर्स, ईआईएल, आईओसीएल, बीएचईएल, एनएचपीसी, राइट्स, आईडब्ल्यूएआई तथा एक्जिम बैंक के कई प्रतिनिधिमंडलों ने म्यांमा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए म्यांमा की यात्रा की थी।

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू), हैदराबाद के दो विशेषज्ञों ने नवंबर, 2009 में म्यांमा-इंडिया सेंटर फार इंगलिश ट्रेनिंग (एमआईसीईएलटी) में अपना कार्यभार ग्रहण किया है।

सड़क विकास परियोजनाओं के संबंध में तामु-कलेवा-कले (टीकेके) सड़क के टेमु-कीगोन-कलेमयो खंड का विस्तार का कार्य अक्तूबर, 2009 में म्यांमा सरकार को सौंप दिया गया है। शेष कीगोन-कलेवा खंड (28 किलोमीटर) में उन्नयन कार्य प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है।

एचएमटी (आई) द्वारा भारत-म्यांमा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईएमआईटीसी) स्थापित किया गया है। एचएमटी (आई) प्रशिक्षण केन्द्र के लिए आवश्यक मशीन और उपस्कर भेजता रहा है। सितंबर-दिसंबर 2009 के दौरान भुवनेश्वर में 11 म्यांमा कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

कलादान बहु मोडल पारगमन परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आई डब्ल्यू ए आई द्वारा सितवे बंदरगाह और कलादान नदी क्षेत्र पर आवश्यक सर्वेक्षण कार्य संपन्न कर लिया गया है। आई डब्ल्यू ए आई ने निविदा आमंत्रित किया है और सितवे बंदरगाह और आई डब्ल्यू टी घटक के लिए बोली आमंत्रित की गई है।

बाप्कोस प्रतिनिधिमंडल ने 10-24 दिसंबर, 2009 के दौरान म्यांमार में चिंद विन नदी में पांच लघु हाइडेल पावर परियोजनाओं के लिए परियोजना स्थलों का दौरा किया।

2008-09 में 950 मिलियन अमेरिकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ और चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल-जुलाई में लगभग 365 मिलियन अमेरिकी डालर का व्यापार हुआ। यांगोन में भारतीय राजदूतावास के सहयोग से म्यांमा चिकित्सा एवं फर्मास्युटिकल्स एसोसिएशन ने जून 2009 में 'भारतीय फर्मास्युटिकल्स प्रदर्शनी 2009' का आयोजन किया। 12 भारतीय और 50 म्यांमा कंपनियों ने प्रदर्शनी और क्रेता एवं बिक्रेता बैठक में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी उत्तर-पूर्वी परिसंघ (एनईआईएफटी) के प्रतिनिधिमंडल ने 28 जुलाई, 2009 को यूनियन ऑफ म्यांमा फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एण्ड कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (यूएमएफसीसी) के साथ बैठक की और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। म्यांमा के मत्स्यपालन विभाग के 15-सदस्यीय मत्स्यपालन प्रतिनिधिमंडल ने 13-20 जुलाई, 2009 के दौरान केन्द्रीय स्वच्छ जल जलकृषि संस्थान (सीआईएफए), भुवनेश्वर में रोह जलकृषि एवं आंध्र प्रदेश में जलकृषि खेतों का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की।

म्यांमा में मानव संसाधन विकास के लिए भारत की सहायता में विस्तार हो रहा है। म्यांमा कोलंबो योजना के आईटीईसी, टीसीएस और आईसीसीआर के जीसीएसएस के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाता रहा है। 2008-09 में म्यांमा प्रशिक्षुओं के लिए स्लॉट निम्नवत थे; आईटीईसी 105, कोलंबो योजना-55; और आईसीसीआर के जीसीएसएस-10। 2009-10 में आईटीईसी स्लॉटों में 140 तक वृद्धि हुई जबकि टीसीएस और जीसीएसएस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्लॉटों का उपयोग उत्कृष्ट रहा है।

भारत और म्यांमा के बीच घनिष्ट सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। बौद्ध धर्म के साथ भारत के जुड़ाव को देखते हुए, विशेषकर बौद्ध समुदायों के बीच संबंधों के प्रति गहरी संवेदना है। विभिन्न सांस्कृतिक मंडलियों ने 2009-10 में दोनों देशों में यात्राएं एवं प्रदर्शन किए हैं। म्यांमा के एक 13-सदस्यीय विद्यार्थी समूह ने भारत में सार्क सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लिया। एक 15-सदस्यीय म्यांमा सांस्कृतिक दल ने 1-5 दिसंबर, 2009 के दौरान कोहिमा में 'प्रसिद्ध होर्नबिल महोत्सव' में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। भारत की एक कव्वाली मंडली ने दिसंबर 2009 के दूसरे सप्ताह में यांगोन,मंडल, मावलमयिन और थानलिन में एक प्रस्तुति प्रस्तुत की। 13-14 दिसंबर, 2009 के दौरान आईसीसीआर द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया बैंड महोत्सव में म्यांमा बैंड ने भाग लिया।

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं जो वर्ष के दौरान और अधिक मजबूत हुए हैं। भारत नेपाल के साथ मौजूदा समझ और सहयोग को मजबूत करने को उच्चतम प्राथमिकता देता है। इस भावना से भारत ने स्थायी, शांतिपूर्ण, समृद्ध और बहुपक्षीय प्रजातंत्र के लिए नेपाल में बदलाव का समर्थन करने की दृष्टि से नेपाल सरकार और प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ गहन परामर्श जारी रखा।

वर्ष के दौरान द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए और विशेष रूप से गहन बातचीत तथा उच्चस्तरीय दौरे आयोजित किए गए।

1 प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के आमंत्रण पर 18-22 अगस्त, 2009 के दौरान भारत की यात्रा की। दोनों देशों के नेताओं की शर्म-अल-शेख में 15वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, मिस्र के दौरान पहले भी बैठक हुई थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने नेपाल और भारत के बीच चिरकालिक, घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी संबंधों पर संतोष व्यक्त किया और उसमें आगे विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने चल रही शांति प्रक्रिया एवं नेपाल में आर्थिक बहदलाव लाने के प्रयास के संबंध में पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में समारोहपूर्ण स्वागत में 16 फरवरी, 2010 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ नेपाल के राष्ट्रपति डॉ. राम बरन यादव और उनकी पुत्री सुश्री अनिता यादव।

शर्म-अल-शेख, मिस्र में 15वें नैम शिखर सम्मेलन के दौरान 16 जुलाई, 2009 को प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महेंद्र राजपक्षे के साथ मुलाकात।

2 रक्षा मंत्री श्रीमती विद्या भंडारी ने जुलाई, 2009 में भारत की यात्रा की जिसके दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री श्री ए.के. एन्टोनी और विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा से मुलाकात की।

3 नेपाल की विदेश मंत्री श्रीमती सुजाता कोइराला ने 10-14 अगस्त, 2009 के दौरान भारत की यात्रा की जिसके दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की।

4 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने 27-28 अक्तूबर, 2009 के दौरान नेपाल का दौरा किया जिसके दौरान अप्राधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार संधि और सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए।

5 संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने नेपाल के सिंचाई मंत्री श्री बाल कृष्ण खांड के साथ कोसी दरार बंद करने के कार्य एवं बैराज का संयुक्त निरीक्षण करने के लिए 11-13 जुलाई, 2009 के दौरान नेपाल का दौरा किया। दोनों मंत्रियों ने कोसी दरार बंध एवं नेपाल में कोसी एफ्लक्स बंध से संबंधित अन्य मरम्मत कार्य को समय पर पूरा किए जाने पर संतोष व्यक्त किया।

6 विदेश सचिव, श्री शिव शंकर मेनन ने 20-21 जून, 2009 के दौरान नेपाल का दौरा किया। विदेश सचिव ने 14-15 सितम्बर, 2009 के दौरान अगस्त 2009 में नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान किये गए निर्णय के अनुसरण में आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए नेपाल का दौरा किया।

7 भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने नेपाल की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सुश्री सुजाता कोइराला के आमंत्रण पर 15-17 जनवरी, 2010 के दौरान नेपाल का सरकारी दौरा किया। दौरे के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं एवं आपसी हित के मुद्दों पर नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ सरकारी बातचीत की। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। चार समझौता ज्ञापनों अर्थात भारतीय सहायता से तराई सड़क का सुदृढ़ीकरण, विज्ञान शिक्षण केन्द्र के निर्माण, सेन्ट्रल डिपोजीटरी सिस्टम की स्थापना और नेपाल में पांच विभिन्न वी डी सी एस के विद्युतीकरण हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

8 गृह मंत्री श्री भीम बहादुर रावल ने 18-21 जनवरी, 2010 के दौरान भारत का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की।

9 नेपाल के राष्ट्रपति श्री राम बरन यादव ने 15-18 फरवरी, 2010 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया। दौरे के दौरान, कई समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनेसे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, बहुआयामी और उत्कृष्ट संबंध प्रतिबिम्बित होते हैं।

इसके अतिरिक्त, कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई, जिनमें गृह सचिव स्तरीय वार्ता (5-7 नवम्बर, 2009), जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति की पांचवीं बैठक (19-22 नवम्बर, 2009), रेल सेवा करार बैठक (12-14 नवम्बर, 2009) और नागरिक उड्डयन वार्ता (7-8 सितम्बर, 2009) तथा सुरक्षा मुद्दों से संबंधित भारत-नेपाल द्विपक्षीय परामर्श दल (4-6 दिसम्बर, 2009) शामिल थीं। इसके परिणामस्वरूप कई द्विपक्षीय मुद्दों पर उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई।

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित करार/दस्तावेज संबंधी कार्य संपन्न हुएः (i) संशोधित व्यापार संधि (ii अप्राधिकृत व्यापार नियंत्रित करने के लिए सहयोग संबंधी करार (iii) संशोधित वायु सेवा करार (ए एस ए) के प्रावधानों को तुरंत लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन।

भारत ने अवसंरचना, स्वास्थ्य, ग्रामीण और सामुदायिक विकास, शिक्षा, आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए नेपाल सरकार के विकास में योगदान जारी रखा। सभी मायनों में भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ की जा रही वर्तमान में 350 से अधिक छोटी एवं बड़ी परियोजनाएं हैं, जो कि कार्यान्वयन के विभिन्न चरण में हैं। भारत, नेपाल के तराई क्षेत्र में एकीकृत चेक पोस्टों, क्रॉस बोर्डर रेल संपर्कों और पोषक एवं शाखा सड़कों के विकास के माध्यम से भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल को उसकी अवसंरचना का विकास करने में सहायता करने पर भी सहमत हो गया है। इससे नेपाल के तराई क्षेत्रों में विकास को और गति मिलेगी तथा आर्थिक समृद्धि आएगी।

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार, विदेशी निवेश का स्रोत और नेपाल में पर्यटकों के आगमन का कारक बना रहा। पिछले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दुगना होकर 2008-09 में 9402 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि का रुझान 2009-10 में जारी रहा।

भारत सरकार द्वारा नेपाल में प्रारंभ किया गया कोसी बराज बंध कार्य संतोषजनक ढ़ंग से समय पर पूरा किया गया। इससे 2009 की बाढ़ के दौरान 3000,000 क्यूसेक से अधिक बाढ़ निस्सरण को नियंत्रित किया गया।

भारत ने भारत और नेपाल में नेपाली छात्रों को कई छात्रवृत्तियां प्रदान करते हुए नेपाल में मानव संसाधन विकास को सहायता देना जारी रखा। नेपाल के अनुरोध पर भारत सरकार 18-22 अगस्त, 2009 के दौरान नेपाल के प्रधान मंत्री के भारत दौरे के दौरान भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे नेपाली छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति को दुगना करने पर सहमत हो गई है।

पाकिस्तान

उच्च स्तरीय बैठक

16 जून, 2009 को येकाटरिनबर्ग में एस सी ओ - बी आर आई सी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आसिफ अली जरदारी के साथ बैठक एवं गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के दौरान 16 जुलाई, 2009 को शर्म-अल-शेख में प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री सैयद युसुफ रजा गिलानी के साथ बैठक सहित कई अवसरों पर पाकिस्तान को भारत की चिंताओं एवं आशाओं से अवगत करा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने हमारे लोगों पर लगातार आतंकी हमलों के कारण गहरा आक्रोश एवं दुःख संप्रेषित किया, प्रधानमंत्री गिलानी से अलग-अलग आतंकी संगठनों के बीच भेद न करने की अपील की और उन्हें कहा कि आतंकी समूहों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई, जिससे भारत में दहशत फैलती है, उसे स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। त्रिस्टे (इटली) में 26 जून, 2009 को जी-8 आउटरीच बैठक के अवसर पर और बाद में न्यूयार्क में 27 सितम्बर, 2009 को यूएनजीए के दौरान विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री शाह महमूद कुरैशी के साथ हुई बैठकों में भी इसी प्रकार के विचारों को संप्रेषित किया गया।

भारत और पाकिस्तान के बीच 25 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की वार्ता हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी नेताओं द्वारा भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी भूभाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने के बार-बार दिये गए आश्वासन को पूरा करने की आवश्यकता दोहरायी। पाकिस्तानी से भारत के विरूद्ध होने वाली आतंकी कृत्यों की जांच और समुचित कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त सूचना पाकिस्तानी पक्ष को सौंपा गया। पाकिस्तानी के विदेश सचिव ने पाकिस्तान में चल रहे मुम्बई हमले के मुकदमे को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास करने की पाकिस्तान सरकार की इच्छा और वचनबद्धता बतायी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी देश के विरूद्ध आतंकी कृत्यों के लिए अपनी भूभाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने के प्रति कृतसंकल्प रहा है और यह भी कहा कि भारत द्वारा उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त सूचना का अध्ययन किया जाएगा। दोनों प्रतिनिधिमंडल ने कुछ तात्कालिक और मानवीय मसलों का समाधान करने की सहमति व्यक्त की। दोनों विदेश सचिव एक दूसरे के संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए।

मुंबई पर आतंकी हमलों के बाद की स्थिति

मुंबई पर आतंकी हमले में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की भूमिका के साक्ष्य सात डोजियरों के रूप में पाकिस्तान को सौंपे गए हैं। मुंबई पर आतंकी हमलें में हाफिज सईद के शामिल होने के कई साक्ष्य भी पाकिस्तान को सौंप दिये गये।

12 फरवरी, 2009 को प्रथम बार यह स्वीकार किया गया था कि 26 नवम्बर, 2008 को मुंबई पर आतंकी हमले की योजना और शुरुआत पाकिस्तान में की गई थी। 11 जुलाई, 2009 के अपने डोजियर में भी यह स्वीकार किया था कि पर्याप्त अभिशंसी साक्ष्य सामने आये हैं, जिससे पाकिस्तानी कस्टडी में लश्करे-ए-तैयबा की पांच दोषियों का सीधा संबंध होने का पता चलता है। बाद में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। 25 नवम्बर, 2009 को पाकिस्तान सरकार ने सात संदिग्ध व्यक्तियों एवं 20 घोषित अपराधियों, जिनकी मुंबई पर आतंकी हमले में भूमिका रही है, के खिलाफ पाकिस्तान में आतंक विरोधी न्यायालय में एक चार्जशीट दायर की।

एफ बी आई द्वारा यू एस में पाकिस्तानी मूल के व्यक्तियों डैविड कोलेमन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। डैविड कोलेमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा के मुंबई आतंकी हमले सहित कई आतंकी कार्रवाइयों में शामिल होने की जांच चल रही है।

भारत पाकिस्तान की ओर से सीमापार घुसपैठ और नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन पर लगातार चिंतित है। मौजूदा तंत्र के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ इन मुद्दों को उठाया गया है।

पाकिस्तान के साथ तभी सार्थक बातचीत हो सकती है जब वह अपनी वचनबद्धता सही मायने में पूरी करे और भारत के खिलाफ अपने भूभाग में किसी भी रूप में आतंकी गतिविधि न होने दे और यह बात कई अवसरों पर दोहराई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा 29 जुलाई, 2009 को संसद में इस संबंध में दिया गया वक्तव्य भी शामिल है।

लोगों के बीच आपसी संपर्क और दौरे

मुंबई पर हुए हमले और पाकिस्तान द्वारा गंभीर भड़काऊ ब्यानबाजी के बावजूद लोगों के बीच आपसी संपर्क बने रहे। समग्र वार्ता के पिछले चक्र में परिवहन संपर्क स्थापित हुए जिसने सफलतापूर्वक कार्य करना जारी रखा, जिससे लोगों की आवाजाही और द्विपक्षीय व्यापार बहाल रहा। नियंत्रण रेखा के पार यात्रा और श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, रावलकोट मार्ग पर व्यापार जारी है। इसके अतिरिक्त, 2005 में भूकम्प के पश्चात मानवीय कार्य बहाल करने की दृष्टि से खोले गए नौसेरी- तिथवल, चकोटी-उरी, हाजीपुर-उरी, रावलकोट-पुंछ और तट्टापानी में मेंधार में पैदल जाने के पांच प्वाइंटों पर पहले की तरह आने जाने की

इजाजत भी दे दी गई है। कई पाकिस्तानी सांस्कृतिक, शैक्षिक और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया। सरकार ने भी धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रोतोकाल (1974) के तहत तीर्थस्थलों की यात्रा को सुविधाजनक बनाया। टाइम्स ऑफ, इंडिया और पाकिस्तान के जंग ग्रुप ने 1 जनवरी, 2010 को गैर-सरकारी अभियान 'अमन की आशा' शुरू किया है। वर्ष के दौरान चलने वाले समारोहों सांस्कृतिक, साहित्यिक और शैक्षणिक बातचीत होती रहेगी।

नेशनल एसेम्बली के स्पीकर के नेतृत्व में पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल

डा. फहमीदा मिर्जा, राष्ट्रीय असेंबली की स्पीकर के नेतृत्व में पाकिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में कामनवेल्थ स्पीकर्स एण्ड प्रिजाइडिंग आफीसर्स के 20वें सम्मेलन के संबंध में 4-9 जनवरी, 2010 के दौरान भारत का दौरा किया।

मानवीय मुद्दे

कई भारतीय कैदी, मछुआरे और नौकाएँ पाकिस्तान के कब्जे में हैं। पाकिस्तान भी भारत की जेलों में उसके राष्ट्रिकों के बारे में चिंतित है। कैदियों एवं मछुआरों संबंधी भारत पाकिस्तान न्यायिक समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के कब्जे में कैदियों एवं मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया गया। पाकिस्तान ने 26 दिसम्बर, 2009 को 100 भारतीय मछुआरे छोड़े। पाकिस्तान के कब्जे में अभी भी 500 से अधिक भारतीय मछुआरे और 400 से अधिक भारतीय मच्छली मारने वाली नावें हैं। भारत द्वारा सभी 553 मछुआरों की राष्ट्रीयता की पुष्टि कर ली गई है जिन्हें, कौंसली संपर्क प्रदान कर दिया गया है। भारत ने 2 जनवरी, 2010 को 31 पाकिस्तानी मछुआरें छोड़े। शेष 19 मछुआरों को छोड़ने के प्रयास जारी हैं, जिनकी राष्ट्रीयता की पाकिस्तान द्वारा पुष्टि कर ली गई है।

वाणिज्य और व्यापार

वर्ष 2008-2009 में 1.78 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पाकिस्तान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2007-2008 की तुलना में 17S (2.14 बिलियन अमेरीकी डालर) कम था। अन्य देशों के माध्यम से गैर-सरकारी व्यापार का भी महत्व है और इससे पाकिस्तान में वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं के लिए लेन - देन की लागत में वृद्धि होती है। एक ओर भारत ने पाकिस्तान को एम एफ एन स्थिति प्रदान की है तो दूसरी ओर पाकिस्तान 1934 मदों की वास्तविक सूची तक भारत से आयात की मदों को रोके हुए है। एस ए एफ टी ए पर, पाकिस्तान ने भारत की वास्तविक सूची के बाहर की मदों पर बातचीत आधारित टैरिफ छूटों में वृद्धि करने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते करार की भावना नकारात्मक रही है क्योंकि निर्यात वास्तविक सूची पर मदों तक ही सीमित हैं।

अन्य मुद्दे/घटनाएं

भारत सरकार ने अगस्त, 2009 में पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगिट वाल्टीस्तान सशक्तिकरण व स्वशासन आदेश 2009 के रूप में पैकेज की घोषणा तथा नवम्बर 2009 में गिलगिट वाल्टीस्तान विधान सभा चुनावों के आयोजन पर जोरदार विरोध जताया है तथा यह कहा है कि घटनाक्रम को कुछ और नहीं मात्र दिखाने की कार्रवाई है जिसका आशय जम्मू व कश्मीर राज्य के क्षेत्रों पर पाकिस्तान के गैर-कानूनी अधिकारी को सही ठहराना था।

श्रीलंका

द्विपक्षीय बातचीत के सभी क्षेत्रों में भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में तेजी से प्रगति हुई। श्रीलंका में उल्लेखनीय विकास में लिट्टे के साथ सैन्य संघर्ष की समाप्ति एवं उसके बाद की स्थिति शामिल थी, जिसमें आंतरिक तौर पर विस्थापित व्यक्तियों (आई डी पी एस) अधिकांशतः तमिलों का पुनर्वास शामिल है। जनवरी 2010 में, राष्ट्रपति राजपक्षा ने अपने प्रतिद्वन्दी पूर्व चीफ ऑफ आर्मी जनरल सारथ फोनसिका को हराते हुए शानदार जीत हासिल की।

दोनों देशों के बीच निकट संबंध स्थापित करते हुए सभी स्तरों पर नियमित द्विपक्षीय संबंध बने रहे। प्रधान मंत्री ने 16 जुलाई, 2009 को मिस्र में 15वें नाम शिखर बैठक के अवसर पर राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षा से मुलाकात की जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने 22 जुलाई, 2009 को फुकेट में और पुनः 22 सितम्बर, 2009 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा में न्यूयार्क में आशियान विदेश मंत्रियों की बैठक में श्रीलंकाई विदेश मंत्री श्री रोहित बोगोलागामा से मुलाकात की। प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री ने सी एच ओ जी एम 2009 के अवसर पर क्रमशः श्रीलंकाई प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की।

श्रीलंकाई पक्ष की ओर से राष्ट्रपति राजपक्षा ने, विदेश मंत्री श्री रोहित बोगोलागामा सहित उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ 31 अक्तूबर, 2009 को भारत का निजी दौरा किया। प्रधान मंत्री रत्नाश्री विक्रमनायके ने सांची में स्थित नव निर्मित बौद्ध तीर्थ स्थलों का उद्घाटन करने के लिए 30 अक्तूबर-1 नवम्बर 2009 के दौरान भारत का दौरा किया।

24 अप्रैल, 2009 को राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार एवं विदेश सचिव ने कोलंबो का दौरा किया। उन्होंने सैन्य विरोध की समाप्ति के तुरंत पश्चात 20-21 मई, 2009 के दौरान पुनः दौरा किया, उनके दौरे के दौरान, इस इस बात पर सहमति बनी की उत्तरी श्रीलंका में आई डी पी एस की राहत, पुनर्वास, पुनर्स्थापना

और सामंजस्य और श्रीलंका में स्थायी व्यवस्थापन सहित सामंजस्य के मुद्दों पर ध्यान देने का यह सही समय था। भारत ने आई डी पी एस के संबंध में अपनी चिंता से अवगत कराया और श्रीलंका सरकार से उन्हें मूलवास स्थान में यथाशीघ्र पुनर्वासित करने की अपील की। श्रीलंका ने 180 दिनों में व्यवस्थापन पूरा करने का अपना इरादा जताया। 10-14 अक्तूबर, 2009 के दौरान, तमिलानाडु से निर्वाचित डीएमके, कांग्रेस और वीसीके सांसदों वाले एक दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने जाफना, देहाती क्षेत्रों एवं वाबुनिया में आई डी पी कैंपों का भी दौरा किया।

श्रीलंका से राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार श्री बासिल राजपक्षा, रक्षा सचिव श्री गोटाबाया राजपक्षा और राष्ट्रपति के सचिव श्री ललित वीरातुंगा समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जून और दिसम्बर 2009 में भारत का दौरा किया। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त श्रीलंका के ढांचे के अंतर्गत नई शुरुआत करने एवं स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढ़ने का समय आ गया है, जिससे कि तमिल समुदाय और अन्य अल्प संख्यकों की न्यायोचित आकांक्षाएं पूरी हो सके।

भारतीय सहायताः अक्तूबर 2008 से भारत, उत्तरी श्रीलंका में सैन्य झड़प से प्रभावित श्रीलंकाई तमिल आम नागरिकों को मानवीय राहत सहायता प्रदान करने में जुटा रहा है। उत्तर में विस्थापित तमिल जनसंख्या को बारी-बारी से 2.5 लाख फेमिली रिलीफ पैक भेजे जा चुके हैं। इन पैकों में सूखा राशन, व्यक्तिगत साफ-सफाई वाली चीजें, कपड़े, बर्तन, जूते, चप्पल और अन्य आवश्यक आपूर्तियां शामिल हैं। लगभग 9.2 करोड़ रुपए की चिकित्सा आपूर्ति के दो प्रेषण श्रीलंका सरकार को आई डी पी एस की जरूरतें पूरी करने के वास्ते उपहार स्वरूप भेजे गए हैं।

आई डी पी एस को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरी श्रीलंका में एक 60-सदस्यीय आपातकालीन क्षेत्र अस्पताल स्थापित किया गया था। इस अस्पताल के माध्यम से मार्च सितम्बर, 2009 के दौरान इसकी तैनाती के समय लगभग 50,000 रोगियों का उपचार किया गया और इसके कार्य की काफी प्रशंसा की गई।

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण को शामिल करने के वास्ते सैनिक शत्रुता की समाप्ति के बाद से श्रीलंका में भारत के मानवीय प्रयासों में तेजी आई है। 9 जून, 2009 को प्रधान मंत्री ने श्रीलंका में राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया के साथ जुड़े रहने की भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की। सरकार ने तदनुसार इस प्रयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। तीव्र पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की प्रक्रिया बहाल करने की दृष्टि से भारत ने उत्तरी श्रीलंका में सात बारूदी सुरंग हटाने वाले दल तैनात किये हैं। भारत ने आई डी पी एस को पुनर्वासित करने के लिए श्रीलंका को 2600 टन शेल्टर सामग्री भेजी है। दूसरी खेप शीघ्र भेजी जाएगी। आई डी पी परिवारों के पुनर्वास के लिए 20,000 एग्रीकल्चर स्टार्टर्स पैक्स भेजे जा रहे है और अन्य 50,000 पैक्स शीघ्र भेजे जा रहे हैं।

भारत श्रीलंका में विभिन्न परियोजनाएं कर रहा है जिससे कि दशकों के संघर्ष के उपरांत उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक पुनरूद्धार में और भारतीय मूल के विस्थापित लोगों को प्रत्यक्षतः लाभ मिलेगा। इनमें कृषि को फिर से शुरू करना, अवसंरचना का पुनर्निर्माण, आजीविका निर्मित होना, क्षमता निमर्मण और कैशल विकास इत्यादि शामिल है।

द्विपक्षीय व्यापार और अर्थव्यवस्थाः द्विपक्षीय रूप से, समीक्षाधीन अवधि के दौरान आर्थिक और व्यापार संबंधों में तेजी आई है। भारत अभी श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है अर्थात इसमें कुल 16.8% अथवा श्रीलंका के व्यापार कारोबार का 1/6वां हिस्सा शामिल है और श्रीलंका दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। एफ टी ए के लागू होने की तारीख से कुल व्यापार कारोबार में पांच गुना वृद्धि हुई है और 2008 में इसने 3.265 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा को छू लिया है। भारत, श्रीलंका में एक सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। पिछले वर्ष, हम श्रीलंका में दूसरे सबसे बड़े निवेशक थे अर्थात 126 मिलियन अमरीकी डालर के हिसाब से निवेश हुआ था। 2009 (जनवरी-सितम्बर) में दोनों के बीच 1.44 बिलियन अमेरिकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ और वैश्विक आर्थिक मंदी से वापसी के संकेत के साथ सुधार होने की आशा है।

श्रीलंका को विकास सहायता भारत का श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय सहायता से पूरी की गई परियोजनाओं में 20 नेनासेलस (अर्थात लर्निंग कियोस्क), पुट्टाल्लम में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वी प्रांत में रेल-बस परियोजना, पेरादेनिया में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तथा मध्य प्रांत में 20 बसें चलाया जाना शामिल है।

शिक्षा के क्षेत्र में, भारत ने मध्य प्रांत में स्कूलों की शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत बनाने की पहल जारी रखी, जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और तमिल रोपण समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना शामिल है।

संस्कृति के क्षेत्र में, मई 2009 में महात्मा गांधी फोटो प्रदर्शनी सहित मतारा में प्रख्यात फोटोग्राफर श्री बिनय बहल द्वारा बौद्ध कला और विरासत स्थलों के छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। सितम्बर 2009 में भारतीय संस्कृति केन्द्र ने सिंघली

में संगीत नृत्य नाटक के रूप में कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' के प्रस्तुतीकरण में सहायता करने के अलावा पोलोनारूआ, बट्टिकलोवा, त्रिकोमली और हैटन में तंजौर (तमिलनाडु) की एक लोक नृत्य मंडली की मेजबानी की। आई सी सी आर ने भी कत्थक एवं भरतनाट्यम मंडली भेजी हैं, जिन्होंने कोलंबो, कैंडी और मध्य प्रांत के आसपास के क्षेत्रों में भी प्रस्तुतीकरण किया है।

■■

दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत 2

आस्ट्रेलिया

भारत-आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होते रहे और वर्ष के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अनेक उच्च स्तरीय दौरे किए गए।

भारत की ओर से की गई यात्राओं में निम्नलिखित दौरे शामिल थेः

- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के उपाध्यक्ष एवं चयनित अध्यक्ष की हैसियत से आईसीसी की बैठक में उपस्थित होने के लिए श्री शरद पवार (कृषि एवं उपभोक्ता कार्यों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री) ने जनवरी-फरवरी 2009 में पर्थ का दौरा किया।
- डॉ एम. एस. गिल, युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारी के संबंध में (25-29 मार्च, 2009) को मेलबोर्न और सिडनी का दौरा किया।
- श्री एस.एम. कृष्णा, विदेश मंत्री ने (अगस्त 2009 में) 7 अगस्त, 2009 को केयर्न्स में हुई, 21वें पोस्ट फॉरम डायलॉग (पीएफडी) भागीदारों की बैठक में भाग लिया।
- श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कोयला, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कोयला खनन एवं कोयला संसाधनों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 30 अगस्त-6 सितम्बर 2009 को आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

आस्ट्रेलिया पक्ष की ओर से

- श्री क्रिस्टोफर वॉगन इवांस (प्रवासन एवं नागरिकता मंत्री), सुश्री जुलिया गिलार्ड, उप-प्रधानमंत्री एवं शिक्षा, रोजगार और कार्यस्थल संबंध मंत्री ने (सितम्बर 2009) में, श्री साइमन क्रेन, व्यापार मंत्री, श्री वायन स्वान, कोषाध्यक्ष (सितम्बर 2009) में, श्री जॉन ब्रूम्बी, विक्टोरिया राज्य के प्रमुख, सुश्री अन्ना बलिग, क्वींसलैंड राज्य के प्रमुख ने (9-10 अत्तूबर, 2009) छठे भारत-आस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता के लिए श्री स्टीफन स्मिथ, विदेश मंत्री ने (12-16 अक्तूबर, 2009) को आस्ट्रेलिया के दौरे किए।
- ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री केविन रुड ने (11-13 नवम्बर, 2009) को भारत की प्रथम यात्रा की। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंध सामरिक हिस्सेदारी तक बढ़ गए। एक संयुक्त वक्तव्य के अलावा इस यात्रा की समाप्ति पर सुरक्षा सहयोग से संबंधित संयुक्त घोषणा जारी की गई। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा पर एक वार्षिक मंत्री स्तरीय वार्ता की प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री केविन रुड ने द्विपक्षीय सामरिक निधि हेतु 50 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर, आस्ट्रेलिया इंडिया सोलर कूलिंग रिसर्च परियोजना के लिए 1 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर तथा भारत में शुष्क भूमि कृषि में अनुसंधान हेतु 20 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर की घोषणा की। हमारे प्रधानमंत्री ने आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों (और समुदाय) की सुरक्षा, बचाव और कल्याण को भारत सरकार द्वारा दी जा रही प्राथमिकता के विषय में अवगत कराया। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आस्ट्रेलिया सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कानून लागू करने को बढ़ावा देने, छात्र कल्याण उपाय लागू करने, सभी शिक्षा प्रदाताओं के पुनर्पंजीकरण, व्यावसायिक-शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की लेखा परीक्षा तथा वीजा प्रणाली की पारदर्शिता को मजबूत करने के प्रयासों पर एक अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराई।
- छात्र गतिशीलता पर भारत और आस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक 6 अक्तूबर, 2009 को नई दिल्ली में हुई।

ब्रुनेई-दारु स्सलाम

इस अवधि में ब्रुनई सुल्तान की मई 2009 में भारत की यात्रा के परिणामों पर ध्यान संकेंद्रित किया गया। पारस्परिक कानून सहायता संधि पर तथा राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों द्वारा वीज़ा अपेक्षाओं से छूट संबंधी एक करार पर ब्रुनेई पक्ष के साथ संपन्न करने के प्रयास जारी रहे।

भारत ने दूसरी ब्रुनेई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी (बीआरआईडीईएक्स 2009, 12-16 अगस्त, 2009 को) में भाग लिया। भारतीय मंडप को सर्वोत्कृष्ट बूथ निर्णीत किया गया। दो भारतीय नौसेना पोतों आईएनएस इरावत और आईएनएस खुकरी ने ब्रुनेई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी के दौरान ही ब्रुनेई की सद्भावना यात्रा की। उन्होंने शाही ब्रुनेई नौसेना के साथ व्यावसायिक अभ्यास भी किए।

बहु-उत्पाद प्रदर्शनी व क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित करने के लिए एक नौ सदस्यीय रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन

परिषद प्रतिनिधिमंडल ने ब्रुनेई दारस्सलाम की यात्रा की। ब्रुनेई शेल पैट्रोलियम (बीएसपी) के लिए वर्ष 2009-10 के लिए कच्चा तेल सीमा अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय तेल निगम से एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्रुनेई का दौरा किया। भारत पैट्रोलियम लि. से ऐसे ही एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्रुनेई का दौरा किया और बीएसपी के साथ एक कच्चा तेल करार पर हस्ताक्षर किए।

कम्बोडिया

भारत और कम्बोडिया के मध्य द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। भारत ने अनुदानों और ऋण सीमाओं के माध्यम से कम्बोडिया को द्विपक्षीय सहायता देना जारी रखा।

विद्युत संप्रेषण लाइनों, सिंचाई और मंदिरों के जीर्णोद्धार के क्षेत्र में भारतीय सहायता के अंतर्गत अनेक परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से आईटीईसी कार्यक्रम के तहत प्रदत्त निधियों से साइम रीप में ता प्रोह्म मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य करवा रहा है। अनुदान सहायता के तहत ग्रामीण कम्बोडिया में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए हैंड पंप लगाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी में विशिष्टता केंद्र की स्थापना- ये दो परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अक्तूबर 2009 में हूआ हिन (थाइलैंड) में अपने समकक्ष श्री ह्यून सेन से मुलाकात की और सातवें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय कार्य-कलापों पर विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी, जल संसाधन प्रबंधन तथा विद्युत संप्रेषण लाइनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भारत की वचनबद्धता को दोहराया।

मई 2009 में पोम पेन्ह में बैंक ऑफ इंडिया ने एक शाखा खोली। व्यवसाय अवसरों का पता लगाने के लिए कई प्रतिनिधिमंडलों (अर्थात मई 2009 में भारतीय सालवेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया (एसई) से 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जुलाई 2009 में श्रीमती रीता मेनन, सचिव (वस्त्र) के नेतृत्व में एक वस्त्र प्रतिनिधिमंडल और अक्तूबर 2009 में एक 23 सदस्यीय काजू व्यापारी, उत्पादक एवं निर्यात प्रतिनिधिमंडल) ने कम्बोडिया की यात्रा की। नवंबर 2009 में पोम पेन्ह में प्रथम भारत-कम्बोडिया व्यापार निवेश व्यवसायी मंच और प्रदर्शनी तथा असम से आईसीसीआर सांस्कृतिक मंडली द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

भारत-कम्बोडिया ने दिसंबर 2005 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराधों तथा मादक दवाओं के अवैध व्यापार का मुकाबला करने संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार के अनुसरण में गृह मंत्रालय द्वारा दो विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमः (1) 'बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच' जुलाई में तथा (2) 'सितंबर में साइबर अपराध और नेटवर्क पाठ्यक्रम' आयोजित किए गए। श्री ओम प्रकाश, उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), ने अक्तूबर 2009 को पोम पेन्ह में औषधि मामलों पर दूसरे आसियान वरिष्ठ कर्मचारी बैठक (एएसओडी) भारत में भाग लिया।

आईटीईसी कार्यक्रम के तहत कम्बोडिया को दिए जाने वाले स्लाट्स 2009 में 75 से बढ़ाकर 85 कर दिए गए तथा 14 शिक्षा छात्रवृत्तियां 10 एमजीसी के अंतर्गत तथा चार सीईपी के जीसीएसएस (प्रत्येक के अंतर्गत दो-दो) अलग से पेशकश की गई हैं। आईटीईसी अंतर्गत विभिन्न विषयों में अब तक 790 कम्बोडियाई राष्ट्रिकों को प्रशिक्षित किया गया है। साइम रीप पर अप्सरा (एपीएसएआरए)प्राधिकारी के सहायतार्थ, जल प्रबंधन में सुविज्ञ एक भारतीय को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। भारत द्वारा आसियान को प्रतिवर्ष ऑफर किए जाने वाले 100 आसियान छात्रों के लिए अध्ययन ऑफर के अंतर्गत 5 कम्बोडियाई छात्रों ने मार्च में भारत का दौरा किया।

रीयर एडमिरल वी.एस. चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) नई दिल्ली से 17 अधिकारियों के एक बैच ने अपने अध्ययन दौरे के भाग के रूप में मई में कम्बोडिया की यात्रा की। नवंबर में उच्चतर हवाई कमान से एक और टीम ने कम्बोडिया की यात्रा की। कम्बोडिया ने वर्ष 2011-12 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सीट पर हमारी उम्मीदवारी के लिए अपना औपचारिक समर्थन सूचित किया। भारत ने विश्व विरासत समिति के लिए कम्बोडिया का समर्थन किया।

फिजी

भारत ने पूर्वोन्मुखी नीति के अनुसार फिजी द्वीपसमूह, टोंगा, तुवालू और कुक आइलैंड के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए सामाजिक और आर्थिक सहायता कार्यक्रमों पर अपना ध्यान संकेन्द्रित रखा।

फिजी के प्रधानमंत्री कोमोडोर वैनीमरामा ने 25-31 मार्च, 2009 को निजी तौर पर भारत की यात्रा की। सचिव (पूर्व) श्री एन. रवि ने (3-5 अगस्त, 2009) को द्विपक्षीय संबंधों पर विचार-विमर्श करने के लिए फिजी द्वीपसमूह की यात्रा की। उन्होंने अटार्नी जनरल और न्याय, निर्वाचन सुधार, सार्वजनिक उद्यम और भ्रष्टाचार विरोध मंत्री, उद्योग, पर्यटन, व्यापार व संचार मंत्री श्री ऐयाज सैयद खय्याम, विदेश मंत्री श्री रत्तु इनॉक कुबुआबुला तथा विदेशी सचिव श्री पेसेली वोशिया से मुलाकात की।

फिजी सरकार के समाज कल्याण, महिला और निर्धनता प्रबोधन मंत्रालय के अनुरोध पर ग्रामीण समुदायों में वंचित महिलाओं एवं अर्धशहरी आदिवासी व्यवस्थापनों के सहायतार्थ मूल पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए नकदी प्रवाह बनाने हेतु भारत ने मार्च-अप्रैल 2009 को वितरण के लिए 200 सिलाई मशीनें प्रदान कीं। फिजी के वित्त मंत्रालय के अनुरोध पर टीसीएस कोलंबो योजना के अंतर्गत एक विशेष सद्भावना के रूप में पांच विशेष स्लाट्स ऑफर किए गए।

इंडोनेशिया

वर्ष के दौरान इंडोनेशिया के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध बने रहे। दोनों देशों के बीच नियमित रूप में उच्च स्तरीय दौरे होते रहे। सितम्बर में जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री ने भारत का दौरा किया। हमारे वाणिज्य मंत्री ने बाली में कैरंस दल की बैठक में भाग लेने के लिए जून में इंडोनेशिया का दौरा किया। राज्य मंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) श्री आनंद शर्मा ने 'मेड इन इंडिया' की व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए अगस्त में इंडोनेशिया का दौरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने एड्स पर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए अगस्त में योगयाकार्ता और बाली की यात्राएं की। आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन एवं पर्यटन मंत्री श्री जयपाल रेड्डी और कुमारी शैलजा ने आवास और शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्रियों के सम्मेलन के दूसरे ब्यूरो की चौथी बैठक में भाग लेने के लिए जकार्ता का दौरा किया। ऊर्जा एवं खनिज संसाधन के इंडोनेशिया के मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता हेतु सितम्बर में भारत का दौरा किया। हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री एम.के. अजागिरी ने इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री और इंडोनेशिया के चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री से विचार विमर्श हेतु नवम्बर में इंडोनेशिया का दौरा किया।

दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय दौरों सहित नियमित रक्षा आदान-प्रदान हुए, जिनके अंतर्गत उच्चस्तरीय दौरों का, पोतों के दौरों, दोनों में से किसी भी देश के स्टाफ कॉलेजों में अध्ययन करने वाले अधिकारियों का दौरा और मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर संयुक्त समन्वित चौकसी का आदान-प्रदान शामिल हैं। नौसेना प्रमुख (मनोनीत) ने अगस्त 2009 में इंडोनेशिया का दौरा किया।

वर्ष 2008 में 10 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार सहित, इंडोनेशिया आसियान में हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया। भारत इंडोनेशिया से पाम तेल तथा कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रमुख खरीददार रहा है। एक प्रमुख पहल में अगस्त 2009 में जकार्ता में एक 'मेड इन इंडिया' शो आयोजित किया गया।

एक प्रमुख पहल में, अक्टूबर में एक 'भारत महोत्सव' शुरू किया गया, जिसमें शास्त्रीय और लोक दोनों दलों की प्रस्तुतिमंडल, एक कला प्रदर्शनी, एक मध्य भारत कला प्रदर्शनी, एक फिल्म सप्ताह, एक फैशन शो, एक लाइफ स्टाइल उत्पाद प्रदर्शनी, एक खाद्य उत्सव तथा भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक सम सामयिक और ऐतिहासिक संबद्धता संगोष्ठियां आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान इंडोनेशिया को आईटीईसी के तहत 75 प्रशिक्षण स्लाटों, कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग स्कीम के अंतर्गत 38 प्रशिक्षण स्लाट, 25 'सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति स्कीम' छात्रवृत्तियां स्लाट्स तथा 2 हिंदी एक वर्षीय पाठ्यक्रम छात्रवृत्तियों की ऑफर की गई थी।

सचिव (कृषि एवं सहकारिता), श्री टी. नंदकुमार ने अप्रैल 2009 में इंडोनेशिया का दौरा किया और कृषि सहयोग के समझौता ज्ञापन के तहत कृषि में सहयोग से संबद्ध एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। अगस्त में योगयाकार्ता में पर्यटन पर एक संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक हुई।

इस समय इंडोनेशिया आसियान के साथ भारत की वार्ता भागीदारी के लिए आसियान समन्वयक है।

लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य

तीन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा दी गई ऋण सीमा के उपयोग से द्विपक्षीय व्यापार में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि इस बात की साक्षी रही कि भारत के साथ लाओ लोकतंत्रीय गणराज्य के संबंध बढ़े है। लाओस अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा मानव संसाधन विकास के लिए भारत की ओर एक सहायता स्रोत के रूप में आशान्वित रहा। भारत द्वारा यह सहायता मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) तथा आईसीसीआर की सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति सहायता योजना (जीसीएसएस) के तहत विश्वविद्यालयीय अध्ययन के लिए 20 छात्रवृत्तियों तथा आईटीईटी और कोलंबो योजना के तहत लगभग 120 छात्रवृत्तियों के माध्यम से दी जाती है। भारतीय राजदूतावास ने लाओ के विकलांग रोगियों को डीआरडीओ द्वारा विकसित हल्के कैलीपर्स फिट करने के लिए दस दिन का एक कैंप आयोजित किया, जिसमें 50 लाओ विस्थापित लोगों ने कैलीपर्स प्राप्त किए। जून में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वाट फोऊ मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया गया। भारत ने 14-17 जुलाई, 2009 को विश्व प्रतिध्वनि/छाया पर्यटन सम्मेलन तथा प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुलतान अहमद ने भारत का नेतृत्व किया।

1 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में लाओ भारतीय संयुक्त आयोग की छठी बैठक हुई। लाओ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप प्रधान मंत्री और लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य के विदेश मंत्री डॉ. थांगलुन सिसोलिथ ने किया तथा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने किया।

मलेशिया

वर्ष के दौरान भारत और मलेशिया के बीच संबंध और मजबूत हुए। मलेशिया के प्रधान मंत्री श्री डाटो मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रज़ाक ने अपने पदभार ग्रहण करने के प्रथम वर्ष में ही 19-23 जनवरी, 2010 को भारत का शासकीय दौरा किया। इस दौरे के दौरान एक प्रत्यर्पण संधि तथा दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु अपनी सरकार का समर्थन भी सूचित किया। इसके अलावा 16 वाणिज्यिक करारों पर भी हस्ताक्षर किए गए। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कॉमनवेल्थ शिक्षा मंत्रियों के 17वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए जून में

मलेशिया का दौरा किया। एक तीन सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने (14-15 नवम्बर, 2009) 7वें एशिया प्रशांत महिला सांसदों और मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्वालालम्पुर की यात्रा की। मलेशिया पर्यटन मंत्री श्री नग येन येन ने 14-17 अगस्त, 2009 को भारत के चार शहरों का दौरा किया। मेलाका के मुख्यमंत्री श्री मोहम्मद अली मोहम्मद रुस्तम ने अगस्त में भारत का दौरा किया। 3-4 सितम्बर, 2009 को नई दिल्ली में हुई अनौपचारिक विश्व व्यापार संगठन मंत्रालयी बैठक में भागीदारी के लिए मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री मुस्तफा मुहम्मद ने भारत का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने 29 अक्तूबर-3 नवम्बर 2009 तक मुम्बई, बैंगलूरू और चेन्नई के व्यापार और निवेश मिशन की अगुआई करने के लिए भारत का दूसरा दौरा किया।

अब मलेशिया सिंगापुर के बाद आसियान में भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभर कर आया है। जनवरी से अगस्त 2009 के दौरान (भारत के 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात व भारत के 3.1 बिलियन अमरीकी डालर के आयात सहित) भारत और मलेशिया के बीच दोतरफा व्यापार 4.6 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है।

मलेशिया की कंपनियों ने भारत में 2.34 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 52 निर्माण परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, जबकि 2.3 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 22 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 2009 के पूर्वाद्ध में मलेशिया में नया भारतीय निवेश 17.3 बिलियन अमरीकी डालर है। मलेशिया में संचयी भारतीय निवेश 2 बिलियन अमरीकी डालर के लगभग है।

भारत और मलेशिया ने व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) को अंतिम रूप देने पर वीडिओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने विचार-विमर्श जारी रखे। दोनों पक्षों ने प्रत्यर्पण संधि के मूल-पाठ को भी अंतिम रूप दे दिया जिस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किया जाएगा। 'भारत में व्यापार करनाः मलेशिया के व्यापार हेतु पुस्तिका' तथा 'मलेशिया में व्यापार करनाः भारत के व्यापार हेतु पुस्तिका' शीर्षक दो पुस्तिकाएं एक एफआईसीसीआई और सीआईआई तथा स्थानीय भागीदारों की सहायता से प्रकाशित की गई। भारतीय पारंपरिक औषधियों पर सर्वप्रथम सम्मेलन तथा उसके बाद क्रेता-विक्रेता बैठक (वीएसएम) 21 जुलाई, 2009 को क्वालालम्पुर में हुई। सामग्री में आसियान-भारत एफटीए से भारतीय और मलेशियाई व्यापार के लिए उभरते अवसरों को उजागर करने के लिए क्वालालम्पुर और पेनांग में दो सेमीनार आयोजित किए गए।

भारत- मलेशिया रक्षा सहयोग में सतत वृद्धि हुई है। स्टाफ समिति के प्रमुखों के अध्यक्ष तथा नौसेना स्टाफ प्रमुख, एडमिरल सुरेश मेहता ने 26-28 मई, 2009 को मलेशिया का सरकारी दौरा किया। शाही मलेशियाई वायुसेना के प्रमुख जनरल तान श्री अज़ीजान बिन अरीफिन ने 27-29 जुलाई, 2009 को भारत का दौरा किया। भारतीय नौसेना और तटरक्षक पोतों ने दक्षिणपूर्व एशिया में अपने विदेश नियोजन के हिस्से के रूप में मलेशिया का दौरा किया। शाही मलेशियाई नौसेना की हाल ही में खरीदी गई पनडुब्बी, 'केडी टुंकु अब्दुल रहमान' फ्रांस से मलेशिया की अपनी प्रथम यात्रा के दौरान 18-20 अगस्त, 2009 में कोचीन पत्तन में पहुंची। मलेशिया ने नौसेना से नौसेना तथा वायुसेना से वायुसेना स्टाफ वार्ताओं की क्रमशः 4-7 अगस्त, 2009 तथा 13-15 अत्तूबर, 2009 को मेजबानी की।

जुलाई 2009 में क्वालालम्पुर में लगभग दस वर्षों के अंतराल में प्रथम 'भारतीय शिक्षा मेला' आयोजित किया गया।

4 नवम्बर, 2009 को क्वालालम्पुर में एक पूर्ण विकसित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (आईसीसी) खोला गया।

भारत और मलेशिया ने जनवरी 2009 में कामगारों के रोजगार पर हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन में विचारित अनुवर्ती उपाय शुरू करने से मलेशिया में भारतीय कामगारों की कार्य-स्थितियों को सुधारने के अपने प्रयास जारी रखे।

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री श्री टिम ग्रोसर ने विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दोहा दौर में 3-4 सितंबर, 2009 को नई दिल्ली में हुई अनौपचारिक मंत्रालयी बैठक में न्यूजीलैंड प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व के लिए वर्ष 2009 में दो बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान श्री ग्रोसर ने यह घोषणा की कि द्विपक्षीय व्यापार व निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड मुम्बई में एक प्रधान कौंसलावास खोलेगा। न्यूजीलैंड के खेल एवं मनोरंजन मंत्री के निमंत्रण पर युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. एम.एस. गिल ने 22-25 मार्च, 2009 को न्यूजीलैंड की यात्रा की। भारत- न्यूजीलैंड विदेश कार्यालय परामर्श; भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सचिव (पूर्व) श्री एन. रवि के साथ 30 मार्च, 2009 को वेलिंग्टन में आयोजित किए गए। आसियान तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाणिज्य विभाग के कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने के एक भाग के रूप में, चमड़ा निर्यात परिषद ने (31 अगस्त-1 सितम्बर 2009) ऑकलैंड में एक क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की।

ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में एक सब्सिडरी खोलने के लिए 1 सितंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा को न्यूजीलैंड रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया। यह सब्सिडरी जनवरी 2010 में खोला जाएगा।

पापुआ-न्यू-गिनी (पीएनजी)

भारत के पापुआ-न्यू-गिनी (एनजी) से संबंध मैत्री पूर्ण बने रहे। पीएनजी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी पद हेतु अपना समर्थन किया।

श्री साम अबल पापुआ-न्यू-गिनी (पीएनडी) के विदेश कार्य, व्यापार और प्रवासी मंत्री ने जुलाई 2009 में भारत की चार दिन की यात्रा की। इस यात्रा का विशेष महत्व रहा, चूंकि यह दो

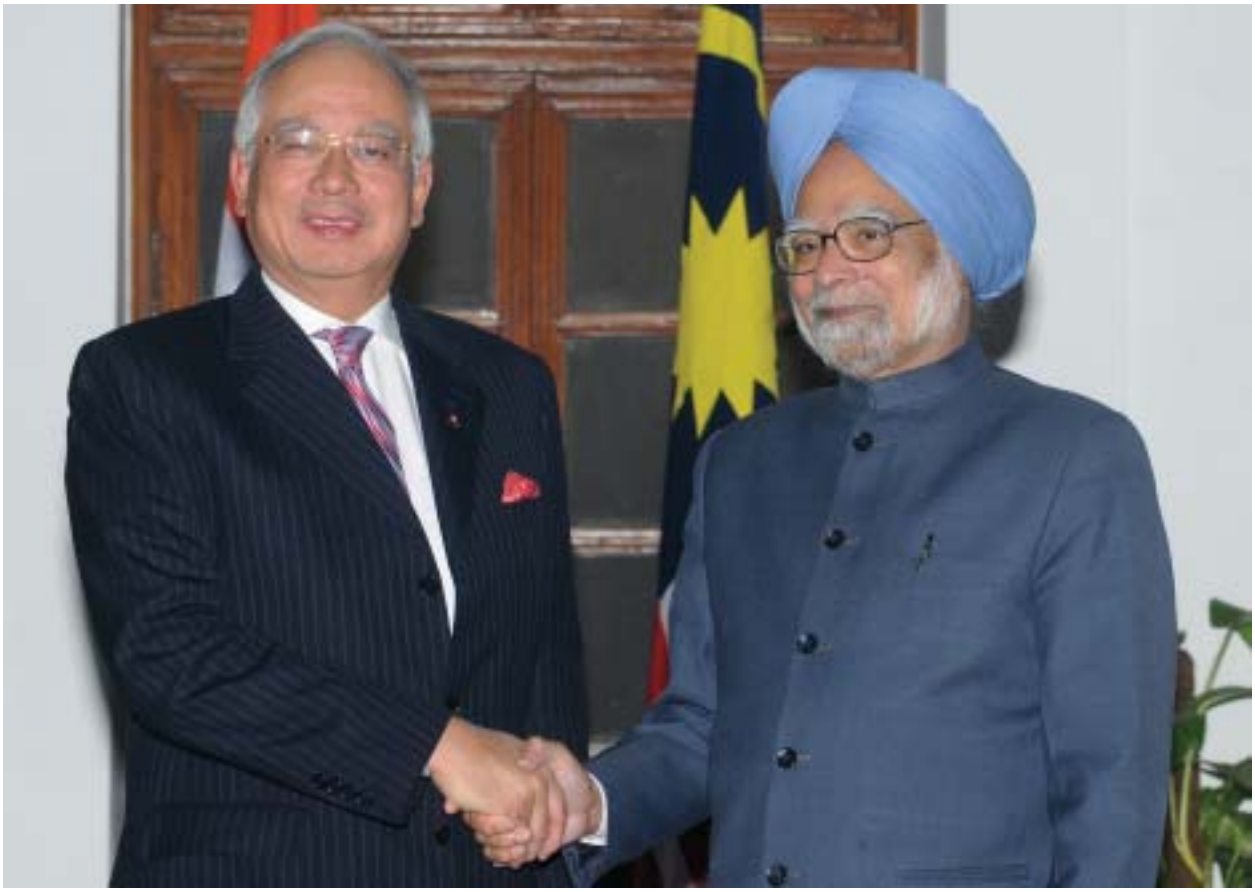

मलेशिया के प्रधान मंत्री श्री मोहम्मद नजीब तुन अब्दुल रजाक ने 20 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की।

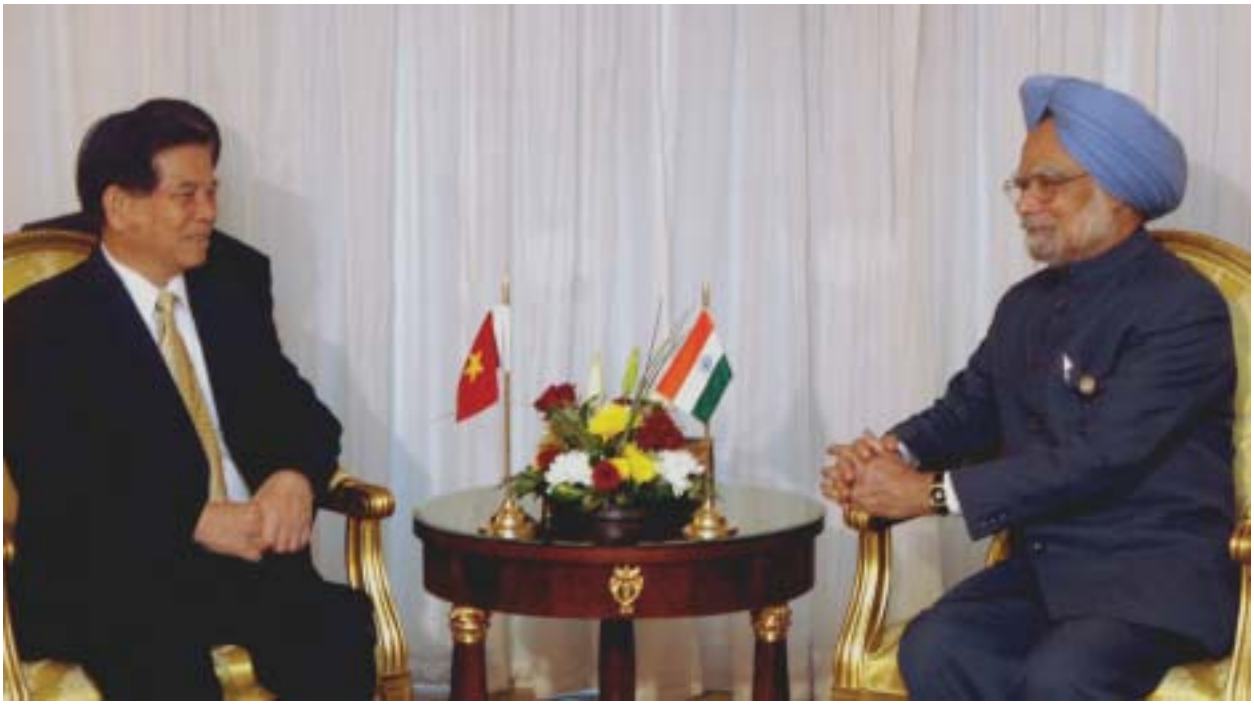

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की 15 जुलाई, 2009 को शर्म-अल-शेख, मिस्र में आयोजित पंद्रहवें नाम शिखर बैठक के दौरान वियतनाम समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री न्गुयेन मिन्ह ट्रीट से मुलाकात।

देशों के बीच की गई मंत्रिस्तरीय प्रथम यात्रा थी। श्री अबल ने विदेश राज्य मंत्री, डॉ. शशि थरूर तथा श्री आनंद शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय समुदाय शिक्षा अनुसंधान और विकास परिषद (आईसीआरडीसीई), चेन्नई जो समाज के वंचित वर्गों के लिए 13 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में पीएनजी की सहायता कर रही है, का दौरा किया।

पीएनजी ने बहुउद्देशीय उपग्रह के निर्माण एवं प्रस्थान में भारतीय सहायता मांगी है, जिसके लिए एन्ट्रीक्स निगम/इसरो के साथ तकनीकी विचार विमर्श करने के लिए पीएनजी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2009 में बंगलुरू की यात्रा की। कनाडा की इंटरऑयल के नेतृत्व में एक एलएनजी परियोजना में भागीदारी की सभावनाओं का पता लगाने के लिए गैस अथारिटी ऑफ इंडिया(जीएआईएल) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर 2009 में पीएनजी की यात्रा की।

पीएनजी को इग्नू (आईजीएनओयू) की कवरेज हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) तथा पीएनजी के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूनीटेक) ने परामर्श शुरू कर दिए हैं।

प्रशांत द्वीपसमूह देशों के लिए भारत सरकार के क्षेत्रीय सहायता पहल के अंतर्गत भारत ने पीएनजी को 125000 अमरीकी डालर की एक नई अनुदान सहायता की पेशकश की है। इसके अलावा एक सूचना प्रौद्योगिकी विशिष्टता केंद्र तथा तीन होल-इन-वाल (ही-वेल) अध्ययन केंद्रों की स्थापना की पेशकश भी की गई है।

आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने पीएनजी को दिए जाने वाले स्लाट्स की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। कोलंबो योजना के टीसीएस के तहत अन्य चार स्लाटों की पीएनजी को पेशकश की गई है।

फिलीपींस

भारत-फिलीपींस द्विपक्षीय संबंधों के लिए वर्ष 2009 बहुत विशेष रहा क्योंकि यह द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए ठीक इस करार के हस्ताक्षर करने के दिन (16 नवंबर, 2009) को दिल्ली में तथा फिलीपींस में मनीला में एक विशेष टिकट जारी की गई। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने नवंबर 2009 को फिलीपींस-भारत मैत्री माह घोषित करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया।

29-30 अक्तूबर, 2009 को मनीला में नौंवा द्विपक्षीय विदेश नीति परामर्श तथा तीसरी सुरक्षा वार्ता बैठक संपन्न हुई। वर्ष के दौरान फिलीपींस में आए प्रचंड तूफानों से हुई क्षति की ओर भारत सरकार ने राहत सहायता के लिए 100,000 अमरीकी डालर की नकद अनुदान राशि दी। फिलीपींस गणराज्य के विदेश सचिव श्री ए. रमूलो ने विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा की सह अध्यक्षता में संयुक्त आयोग की पहली बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए एक प्रतिनिधिमंडल की अगुआई की। दो भारतीय नौसेना पोतों आईएनएस 'ज्योति' और 'खंजर' ने 7-10 अप्रैल, 2009 को फिलीपींस की सद्भावना यात्रा की। व्यापार में बढ़ते भारत-फिलीपींस संबंधों का प्रभाव लक्षित हुआ; फिलीपींस को भारतीय निर्यात 2008-09 में 19 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि इसी अवधि में भारत को फिलीपीन्स का निर्यात 23 प्रतिशत तक बढ़ा।

सिंगापुर

हाल ही के वर्षों में भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों में सतत परिवर्तन; राजनीतिक और शासकीय स्तर पर नियमित संपर्कों तथा सामरिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और निवेश को शामिल करते हुए व्यापक बातचीत से अभिलक्षित है। सिंगापुर हमारा छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार तथा एफडीआई निवेशों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। 2008 में द्विपक्षीय व्यापार टर्नओवर 19.83 बिलियन अमरीकी डालर थी। वैश्विक वित्तीय संकट तथा इसके परिणाम स्वरूप हुई आर्थिक मंदी ने द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित किया है। तथापि अप्रैल 2000 से जुलाई 2009 की अवधि में सिंगापुर से एफडीआई (संचयी) निवेश 8.57 बिलियन अमरीकी डालर हुआ है।

25 अक्तूबर, 2009 को 7वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन तथा पूर्व एशिया सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री श्री सीन लूंग ली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। जुलाई 2009 में शर्म-अल-शेख में गुट निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान तथा सितम्बर 2009 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने विदेश मंत्री श्री जॉर्ज यिओ से मुलाकात की। शर्म-अल-शेख में उनकी बैठक में विदेश मंत्री श्री जॉर्ज यिओ ने विदेश मंत्री को 2011-12 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी पद के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु सिंगापुर सरकार के समर्थन की सूचना दी। अन्य उच्चस्तरीय दौरों में दिसम्बर 2009 में मंत्री मेंटोर ली कुआन यीव का दिसंबर 2009 का दौरा तथा मार्च 2010 में वरिष्ठ मंत्री गोह चोक टांग का दौरा शामिल है।

आधारभूत संरचना और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए अनेक सेमीनार और रोड शो आयोजित किए गए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ द्वारा आयोजित 'भारत में सड़क आधारभूत संरचना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने' पर एक सभा तथा आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज एवं जेएम फाइनेंसियल द्वारा आयोजित एक 'सड़क आधारभूत संरचना सम्मेलन' में भाग लेने के लिए श्री कमलनाथ, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय मंत्री ने 16-19 जुलाई, 2009 को सिंगापुर की यात्रा की। उन्होंने 'भारत में नई सरकार-अगले 5 वर्षों का अवलोकन' पर सार्वजनिक भाषण दिया जो सिंगापुर भारत के वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स (एसआईसीसीआई) तथा दक्षिणी एशिया अध्ययन संस्थान (आईएसएएस) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 सितंबर, 2009 को सिंगापुर में नई अनुसंधान लाइसेंसिंग

नीति के आठवें बोली दौर (एनईएलपी) तथा कोयला बेड मिथेन ब्लाकों के चौथे बोली दौर (सीबीएम) के लिए बोली प्रक्रिया के बारे में सक्षम निवेशकों हेतु एक निवेशक बैठक आयोजित की। श्री जितिन प्रसाद, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री ने निवेशक बैठक में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। भारत में आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेश संभावनाओं को उजागर करने के लिए बीएनपी परिबास, सीआईआई तथा फीडबैक वेन्चर्स ने 11 अगस्त, 2009 को संयुक्त रूप से एक सम्मेलन 'भारतीय आधारभूत संरचना दिवस' का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एक आठ सदस्यीय आधारभूत संरचना प्रतिनिधि मंडल ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन ने 'भारत में आधारभूत संरचना' के लिए 'बाजार और वित्त पोषण चुनौतियाँ' तथा भारत में 'आधारभूत संरचना के लिए नियामक और राजनीतिक चुनौतियां' पर दो विशेष सत्रों की मेजबानी की।

जापान विदेश व्यापार संगठन (जेईटीआरओ), सीआईआई तथा अंतर्राष्ट्रीय उद्यम (आईई) सिंगापुर ने मिलकर 27 अगस्त, 2009 को जापान और सिंगापुर की कंपनियों के लिए भारत में निवेश संभावनाओं पर एक सेमीनार का आयोजन किया। श्री जे. जे. सिंह, राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, 22-26 जून, 2009 को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह (एआईडब्ल्यू) के दूसरे सत्र के प्रमुख वक्ता थे। श्री लाल थन्नावला, मुख्य मंत्री, मिजोरम ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

भारतीय वाणिज्य चैम्बर, कोलकाता ने एसआईसीसीआई तथा आईई सिंगापुर के सहयोग से 21 अक्तूबर, 2009 को एक सेमीनार 'भारत निवेश 2009' का आयोजन किया। श्री कमल नाथ, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विशेष व्याख्यान दिया। श्री डी. डी. लेपंग, मुख्य मंत्री, मेघालय ने भी सेमीनार को संबोधित किया। इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद (भारत) ने सिंगापुर व्यापार परिसंघ तथा सिंगापुर विनिर्माण परिसंघ के साथ संयुक्त रूप से 3 अप्रैल 2009 को सिंगापुर में एक क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इंडस उद्यमियों की केरल सभा से एक 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने व्यवसाय और निवेश संभावनाओं का पता लगाने के लिए 6-9 मई, 2009 को सिंगापुर की यात्रा की। इस प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर व्यवसाय परिसंघ (एसबीएफ) तथा एसआईसीसीआई के साथ बैठकें की।

सिंगापुर के वरिष्ठ व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री एस इसवरान की दिल्ली यात्रा (2-4 अगस्त, 2009 को) के दौरान जैवप्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए भारत और सिंगापुर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान पर्यटन सहयोग पर एक संयुक्त कार्ययोजना पर भी हस्ताक्षर किए गए। वरिष्ठ विदेश राज्य मंत्री डॉ. बालाजी सदाशिवम ने (6-10 सितंबर, 2009) को तमिलनाडु की राजकीय यात्रा की। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, दोनों देशों के मध्य (23-25 नवंबर, 2009 को) नई दिल्ली में छठी रक्षा नीति वार्ता हुई। सिंगापुर में चौथी रक्षा कार्यदल (डीडब्ल्यूजी) की बैठक (6-8 अप्रैल, 2009 को) हुई। इस वर्ष के दौरान तीनों सेवाओं में प्रत्येक के बीच वार्षिक स्टाफ वार्ताएं आयोजित की गई। रक्षा सचिव ने शंग्री-ला-वार्ता के लिए (29-31 मई, 2009 को) एक चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुआई की। उन्होंने सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री एवं रक्षा मंत्री तीयो ची हेंन से मुलाकात की और रक्षा स्थायी सचिव से भी मुलाकात की। 22-25 सितंबर, 2009 को भारत से एक अठारह सदस्यीय राष्ट्रीय रक्षा कालेज प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर की यात्रा की।

जहां फरवरी-मार्च तथा अक्तूबर 2009 में दोनों थल सेनाओं द्वारा बबीना और देवलाली में वार्षिक बख्तर एवं फौजी अभ्यास आयोजित किए गए, वहीं दोनों वायु सेनाओं ने भारत में नवंबर 2009 में अपना दूसरा संयुक्त मिलेट्री प्रशिक्षण (जेएमटी 2009) भी किया। नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास एसआईएमबीईएक्स 2009 मलक्का जलडमरू मध्य तथा सिंगापुर तट पर 24 मार्च-2 अप्रैल 2009 को किया गया। दो भारतीय नौ सेना पोतों, आईएनएस रणवीर तथा आईएनएस ज्योति और एक तटरक्षक पोत ने आईएमडीई एक्स एशिया 2009 में भाग लिया। 11-15 मई, 2009 को चांगी नेवल बेस पर युद्धपोत प्रदर्शित किया गया। 26-29 अगस्त, 2009 को पूर्वी बेड़े से नौसेना पोतों की यात्राओं में आईएनएस ऐरावत (एक अवतरण पोत) तथा खुखरी एक (प्रक्षेपणास्त्र कोर्विट) शामिल थे।

मल्लका जलडमरू मध्य में नौवहन एवं पर्यावरणीय बचाव की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी संगठन (आईएमओ) के तत्वावधान में 'सहयोगी पद्धति' की 'परियोजना सं.1 विध्वंस मूल्यांकन के लिए जल सर्वेक्षणीय प्रशिक्षण' तथा 'परियोजना 4 - प्रवाह, धारा और वायु - मापन प्रणाली स्थापना' को भारत के अंशदान के परिणाम स्वरूप भारत को 12-16 अत्तूबर, 2009 को सिंगापुर में हुई 34वीं त्रिपक्षीय तकनीकी सुविज्ञ दल (टीटीईजी) बैठक, दूसरी सहयोग मंच बैठक तथा दूसरी परियोजना समन्वय समिति की बैठक में भागीदारी के लिए निमंत्रण मिला। चीन और भारत ने संयुक्त रूप से परियोजना 4 के लिए स्थलों का सर्वेक्षण किया तथा सहयोग मंच के दौरान अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत किया।

थाईलैंड

नियमित रूप से उच्चस्तरीय यात्राएं होने से भारत-थाइलैंड संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बने रहे। राजकुमारी महाचक्री सिरीधोर्न ने (फरवरी और अगस्त 2009) में दो बार भारत की यात्रा की। उप प्रधान मंत्री श्री कोर्ब्सक सभावसु ने उप विदेश मंत्री श्री पनिक विकित्स स्ट्रेच के साथ (थाइलैंड को निवेश और पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने के लिए) एक रोड शो में भाग लेने के लिए अक्तूबर 2009 में भारत की यात्रा की। हमारे प्रधान मंत्री ने भी भारत-आसियान तथा भारत-एशिया शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए अक्तूबर के अंत में थाइलैंड की यात्रा की। दोनों देशों की संसद के बीच संबंधों को

बढ़ाने के लिए थाई सांसदों ने एक थाइलैंड-भारत सांसद मैत्री दल बनाया।

द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सितंबर 2009 में बैंकाक में एक नए भारतीय सांस्कृतिक केंद्र ने कार्य करना प्रारंभ किया।

भारत-थाइलैंड द्विपक्षीय व्यापार 6 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया।

तिमोर लेस्ते

भारत ने तिमोर लेस्ते को राष्ट्र निर्माण के उसके प्रयासों में भारतीय सहायता के रूप में तिमोर-लेस्ते को क्षमता निर्माण में तथा आईटीईसी कार्यक्रम तथा जीसीएसएस छात्रवृत्तियों के अंतर्गत प्रशिक्षण स्लाट्स प्रदान कर समर्थन और सहायता की ऑफर की है। (वर्ष 2009-10 के लिए 5 आईटीईसी प्रशिक्षण स्लाट्स तथा 10 जीसीएसएस छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी, यद्यपि तिमोर-लेस्ते सरकार की प्रशिक्षण हेतु अपने कार्मिकों को छोड़ने की अक्षमता के कारण इसका उपयोग कम ही रहा) सतत विकास के लिए उपस्कर और सामग्री की खरीद के लिए वर्ष 2009 में भारत ने तिमोर-लेस्ते को 100,000 अमरीकी डालर प्रदान किए। आईटीईसी के तहत तिमोर-लेस्ते के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण परियोजना विदेश मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है।

आयोग ई 'निर्धनता निरोध, ग्रामीण विकास और क्षेत्रीय एवं लिंग समानता' नामक तिमोर-लेस्ते सरकार के राष्ट्रीय संसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने (7-15 सितंबर, 2009) को भारत की यात्रा की।

वियतनाम

भारत-वियतनाम संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे। वर्ष 2009 में अनेक उच्चस्तरीय यात्राएं हुई जिनसे 'सामरिक भागीदारी' और प्रगाढ़ हुई। भारत और वियतनाम के बीच चौथा विदेशी कार्यालय परामर्श तथा पहला सामरिक वार्ता अक्तूबर 2009 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री ने जुलाई में शर्म-अल-शेख में एनएएम सम्मेलन के दौरान वियतनाम राष्ट्रपति श्री नग्यान मिन्ह ट्रेट से तथा अक्तूबर 2009 को हूआ हिन, थाइलैंड में सातवें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुयेन तान ह्रुंग से मुलाकात की। वियतनाम के उपराष्ट्रपति सुश्री नग्यान थी डोआं ने अक्तूबर में भारत आए एक 70 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त व्यवसाय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नवंबर 2009 में वियतनाम के रक्षामंत्री वरिष्ठ लेफ्टीनेंट जनरल फंग क्वांग यांग की भारतीय यात्रा से रक्षा व सुरक्षा संबंध सुदृढ़ हुए। वियतनाम के संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ली डॉन हॉप ने जुलाई 2009 में भारत की शासकीय यात्रा की। वियतनाम की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, ने फरवरी 2010 में भारत की यात्रा की। (हमारी लोकसभा की अध्यक्ष के समकक्ष) वियतनाम की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष श्री नग्यान फू ट्रांग ने 23-27 फरवरी, 2010 को भारत की यात्रा की।

वैश्विक मंदी के बावजूद 2008 में द्विपक्षीय व्यापार 2.5 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत वियतनाम को सामानों के दसवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभर कर आया है। भारत ने वियतनाम को बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति प्रदान की, जो द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स के परिसंघ (फिक्की) तथा रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद (सीएपीईएक्सआईएल) के नेतृत्व में एक 53 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर में हनोई और हो चि मिन्ह शहर की यात्रा की।

वियतनाम भारतीय कंपनियों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बना रहा। इस्सर खोज एवं उत्पादन लि. को वियतनाम में 114 तेल एवं गैस ब्लाक प्रदान किए गए। मैकलियेड रस्स्ल, भारत के एक प्रमुख चाय उत्पादक ने वियतनाम आधारित फ़ु बेन चाय कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। इसका अपनी उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन किलो से बढ़ाकर 10 मिलियन किलोग्राम (अर्थात दुगना) करने तथा वियतनाम में नए चाय बागान अधिग्रहण का लक्ष्य है। तीन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत ने वियतनाम को 19.5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सीमा विस्तारित की। जनरल फंग क्वांग थांग, रक्षा मंत्री ने 4-8 नवंबर, 2009 को भारत की शासकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों रक्षा मंत्रियों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। लेफ्टीनेंट जनरल नग्यांन चि विंह, उप-रक्षा मंत्री, वियतनाम ने भी 25-28 अगस्त, 2009 को भारत की यात्रा की। वाइस-एडमिरल निर्मल वर्मा एफओ कमांडर-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ने दो नौसेना पोतों आईएनएस मुंबई तथा आईएनएस रणवीर के साथ 7-11 अप्रैल, 2009 को वियतनाम की यात्रा की। थल सेना युद्ध कॉलेज महऊ से थल सेना उच्च कमान पाठ्यक्रम के 16 अधिकारियों के एक अध्ययन दौरे ने 22-27 सितंबर, 2009 को वियतनाम का दौरा किया। रक्षा प्रबंधन कॉलेज, सिकंदराबाद से 22 अधिकारियों के एक उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम के एक और अध्ययन दौरे ने 14-22 नवंबर, 2009 को वियतनाम की यात्रा की।

आईटीईसी तथा अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वियतनामी कर्मचारियों और छात्रों को 100 से अधिक छात्रवृत्तियां ऑफर की गई। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता (भारत) तथा यूनीवर्सिटी ऑफ सोशल सांइसिस एंड ह्यूमेनिटीज (वियतनाम) ने चि मिंह शहर में 27-29 मई को संयुक्त रूप से 'भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संबंध-एक सामरिक वचनबद्धता अथवा क्षेत्रीय एकीकरण' पर एक सम्मेलन आयोजित किया।

प्रशांत द्वीपसमूह

प्रशांत द्वीप देशों में मानव संसाधन विकास प्रोत्साहन पर बल देना जारी रहा। भारत ने केयर्न्स, आस्ट्रेलिया में हुई 40वीं प्रशांत द्वीपसमूह मंच (पीआईएफ) सम्मेलन बैठक के बाद

वहां 7 अगस्त, 2009 को हुई 21वीं पश्च मंच वार्ता (पीएफडी) भागीदारी बैठक में भाग लिया। पीएफडी के दौरान, विदेश मंत्री श्री एस.एम.कृष्णा ने यह सुस्पष्ट किया कि भारत मानव संसाधन विकास तथा संवर्द्धित निवेश और व्यापार पर भारत अपना ध्यान देना जारी रखेगा, ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उनकी अपनी विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप क्षमता निर्माण और परिचालन सहायता में वह प्रशांत द्वीप मंच देशों को सहायता कर सकें।

विदेश मंत्री ने 14 पीआईएफ देशों में प्रत्येक को दी जाने वाली हमारी अनुदान सहायता को 100,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 125,000 करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एफसीआई और आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजनयिकों के लिए पाठ्यक्रम ऑफर करने तथा पूर्व स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अध्ययनों दोनों के लिए एक एक छात्रवृत्ति के प्रस्ताव को भी दोहराया। विदेश मंत्री ने प्रत्येक पीआईएफ देश में सुविधाविहीनों की शिक्षा आवश्यकताओं में सहायतार्थ ही-वेल अध्ययन केंद्र (होल-इन-द-वॉल एजूकेशन लि.) तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशिष्टता केंद्रों की स्थापना की भी घोषणा की।

फिजी, टोंगा और तुव्वालु जनता के मध्य आईटीईसी तथा कोलंबो योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणों का प्रचार किया गया। प्रशांत क्षेत्र में मानव संसाधन विकास क्षमताओं को सुधारने के लिए विदेश मंत्रालय ने सितंबर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन में एक सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम में सभी प्रशांत द्वीप देशों से सरकारी सेवकों ने भाग लिया।

माइक्रोनेसिया परिसंघीय राज्य

भारत-माइक्रोनेसिया परिसंघीय राज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ बने रहे। उनके नारियल उद्योग के लिए मशीनरी की खरीद हेतु भारत द्वारा 73,145 अमरीकी डालर की विकास अनुदान सहायता दी गई।

किरीबाती

किरीबाती गणराज्य के राष्ट्रपति श्री अनोट टोंग ने 5-7 फरवरी, 2010 में दिल्ली में हुए सतत विकास शिखर सम्मेलन (डीएसडीसी) में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

500 किलोवाट के जेनरेटर और ऊपरी केबल्स की खरीद का वित्त पोषण करने के लिए जून 2009 में किरीबाती सरकार को वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 की अनुदान सहायता राशि में से 253793.65 अमरीकी डालर की राशि जारी की गई। आईटीईएफ के तहत वर्ष 2009-10 के लिए चार स्लाट आबंटित किए गए।

इन अनुदान सहायता और आईटीईसी कार्यक्रम के तहत सहायता ने इन द्वीप देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में सहयोग दिया।

नीयू

वर्ष 2008 के लिए अनुदान राशि को दर्शाने वाली 100,000 अमरीकी डालर की एक धनराशि मई 2009 में इन तीन परियोजनाओं को वितरित की गईः (I) लियालगी जीर्णोद्धार परियोजना (चरण-2) (II) तमाकाउटोंगा नव धर्मगुरु निवास परियोजना; तथा (III) सुनेमा प्रशिक्षण केंद्र।

नेउ

मई 2009 में विदेश मंत्रालय ने नेउरु सरकार की नेउरु सरकार प्रवासी कर्मचारी फ्लैट परियोजना के निर्माण के निधियन हेतु नेउरु सरकार को वर्ष 2007 और 2008 के लिए अनुदान राशि में से 186,000 अमरीकी डालर की राशि स्वीकृत की। राशि के 50 प्रतिशत भाग को दर्शाने वाली 93,000 अमरीकी डालर की राशि भारत द्वारा जुलाई 2009 में वितरित की गई। आईटीईसी के तहत वर्ष 2009-10 के लिए 2 स्लाट आबंटित किए गए।

पलाऊ गणराज्य

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की उम्मीदवारी और दृष्टिकोण को पलाऊ द्वारा समर्थन देने के साथ वर्ष के दौरान भारत-पलाऊ गणराज्य संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

मार्शल द्वीप गणराज्य

भारत-मार्शल द्वीप गणराज्य के संबंध घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मार्शल द्वीप भारतीय उम्मीदवारी का समर्थक था।

सामोआ

सामोआ सरकार के लिए सुवाह्य रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली की 6 इकाइयों की खरीद के लिए अप्रैल 2009 में 65,030 न्यूजीलैंड डालर (33877.55 अमरीकी डालर के बराबर) की अनुदान सहायता राशि जारी की गई। वर्ष 2009-10 के लिए आईटीईसी के तहत 10 स्लाट आबंटित किए गए।

टोंगा

टोंगा के शाह ने सितंबर 2009 में भारत का निजी दौरा किया।

■■

3 पूर्व एशिया

जापान

हाल के वर्षों में भारत-जापान संबंधों में महत्वपूर्ण और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, जिसके अंतर्गत नियमित रूप से शिखर स्तरीय सफल आदान-प्रदान हुए हैं। वर्ष 2006 में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के दौरे के अवसर पर हस्ताक्षर किए गए संयुक्त वक्तव्य से भारत-जापान कार्यनीतिक और वैश्विक भागीदारी स्थापित हुई।

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान वर्ष 2009 में पूर्ववत जारी रहा। प्रधान मंत्री ने जापान के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री तारो आसो से 2 अप्रैल, 2009 को लंदन में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान और पुनः 10 जुलाई, 2009 को ला' आकिला (इटली) में जी-8 शिखर बैठक के अवसर पर मुलाकात की। जापान में 30 अगस्त, 2009 को हुए चुनाव के पश्चात प्रधान मंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के शीघ्र बाद डॉ. यूकियो हातोयामा ने 25 सितंबर, 2009 को पीट्सबर्ग में जी-20 शिखर बैठक के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. सिंह से मुलाकात की। दोनों प्रधान मंत्रियों की अगली बैठक 24 अक्तूबर, 2009 को हुआ हिन (थाइलैंड) में पूर्वी एशिया शिखर बैठक के दौरान हुई।

प्रधान मंत्री डॉ यूकियो हातोयामा ने वार्षिक शिखर बैठक के लिए 27-29 दिसंबर, 2009 को भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-जापान कार्यनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के नए चरण और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की एक कार्ययोजना पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर के संयुक्त परियोजना विकास कोष के लिए जापान के अंशदान को औपचारिक रूप दिया गया, जबकि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर के साथ-साथ पर्यावरण-अनुकूल शहरों और सुव्यवस्थित समुदायों के विकास के लिए डीएमआईसी विकास निगम और जापान बाह्य व्यापार संगठन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों पक्षों द्वारा मार्च 2010 तक परियोजना के प्रथम चरण हेतु मुख्य ऋण प्रदान करने के लिए करार निष्पादित करने पर सहमति होने से वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। प्रधान मंत्री डॉ. हातोयामा की प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ प्रतिनिधि-स्तरीय वार्ता हुई तथा उन्होंने मुंबई में भारत के उद्योगजगत के शीर्ष नेताओं से मिलने के अलावा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से भी मुलाकात की।

मार्च 2007 में शुरू हुई वार्षिक विदेश मंत्रिस्तरीय कार्यनीतिक वार्ता नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने कार्यनीतिक वार्ता के तीसरे दौर के लिए 3 जुलाई, 2009 को जापान की यात्रा की। उन्होंने तत्कालीन विदेश मंत्री श्री हीरोफुमी नाकासोने के साथ अनेक मुद्दों पर व्यापक बातचीत की।

जापान के साथ अन्य मंत्रिस्तरीय वार्ताओं में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और जापान के आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्री (एमईटीआई) के बीच भारत-जापान नीति वार्ता और योजना आयोग के उपाध्यक्ष और एमईटीआई मंत्री के बीच भारत-जापान ऊर्जा वार्ता शामिल है। इन दोनों वार्ताओं की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई है। ये वार्ता अब भारत में वर्ष 2010 के प्रारंभ में होनी हैं।

वर्ष 2009 में दोनों देशों से कई मंत्रिस्तरीय दौरे हुए। वस्त्र मंत्री श्री दयानिधि मारन ने 20-23 जुलाई, 2009 को जापान की यात्रा की। भा.सां.सं.परि. के अध्यक्ष डॉ. कर्ण सिंह ने 25-27 सितंबर, 2009 को जापान की यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान टोक्यो में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भी किया। राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय) श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने जापान में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सोसाइटी मंच की बैठक में 4-6 अक्तूबर, 2009 को भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के नारायणन ने जापान की नई सरकार के साथ जापान और भारत की मौजूदा साझेदारी को सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा पर बल देने के लिए प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में 19 अक्तूबर, 2009 को टोक्यो की यात्रा की। उन्होंने मुख्य मंत्रिमंडल सचिव और विरोधी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के साथ अपनी बैठक के अलावा जापान के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटोनी ने जापान के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर 8-10 नवंबर, 2009 तक जापान की यात्रा की। यात्रा के दौरान एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री कमलनाथ ने भारत में परिवहन अवसंरचना के विकास में सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए 17-19 जनवरी, 2010 तक जापान की यात्रा की। जापान की ओर से पर्यावरण मंत्री श्री साकीहीतो ओजावा ने 18-20 अक्तूबर, 2009 तक भारत की यात्रा की। आंतरिक मामले एवं संचार मंत्री मी. काजुहीरो हारागुची ने आईसीटी क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 6-9 जनवरी, 2010 को भारत की यात्रा की। उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, संसदीय प्रतिनिधिमंडल और दोनों देशों की प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों के बीच तालमेल भी हुए।

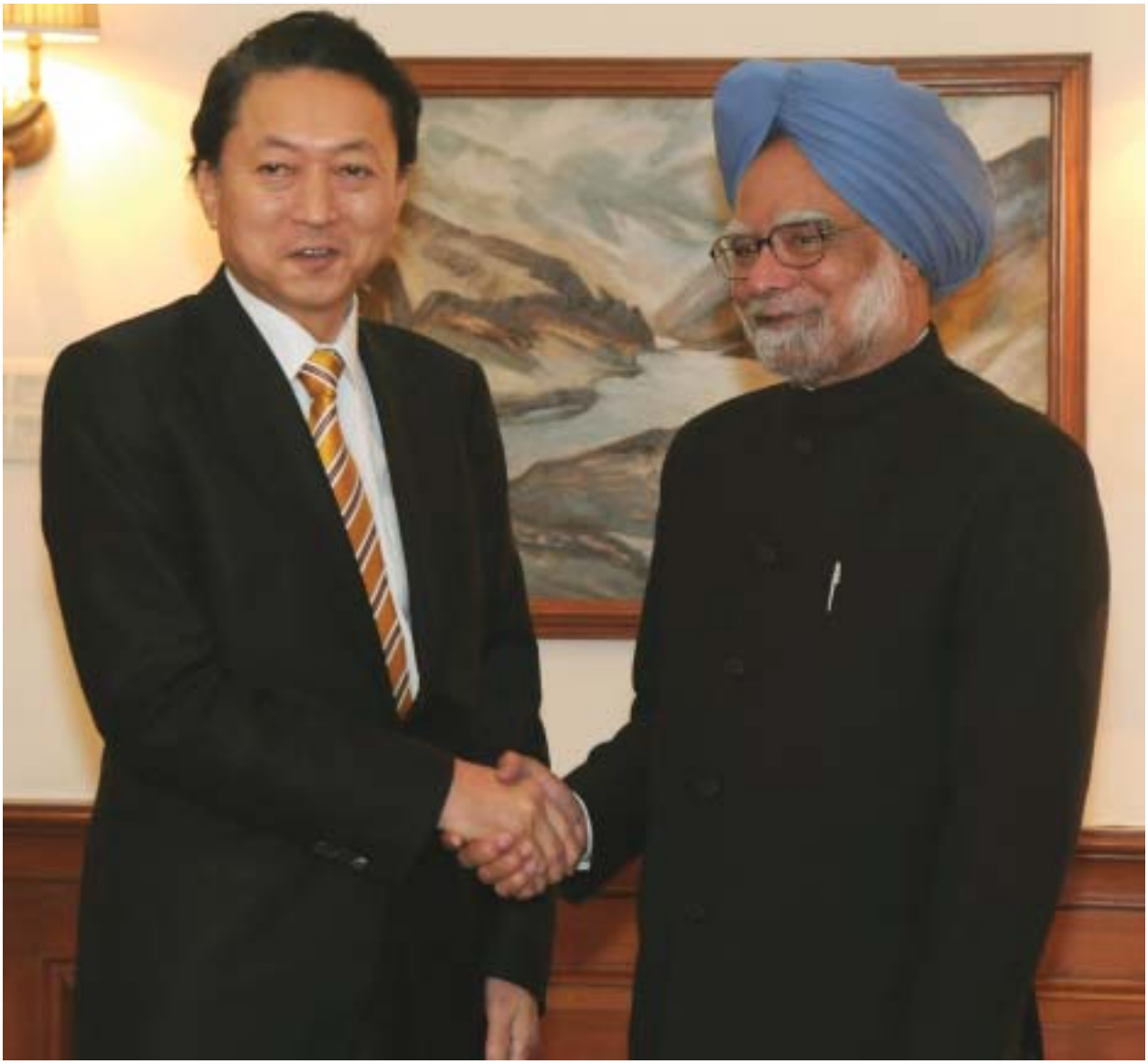

जापान के प्रधान मंत्री श्री यूकियो हैतोयामा की 28 दिसंबर, 2009 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात।

भारत और जापान ने वर्ष 2006 में शुरू हुई विशेष आर्थिक सहभागिता पहल के अंतर्गत कई उच्च-दृष्टिक्षेत्र वाली परियोजनाएं भी शुरू की है।

प्रधान मंत्री की दिसंबर 2006 में जापान की यात्रा के दौरान दोनों देश मुंबई-दिल्ली मार्ग पर एक समर्पित बहुविध हाई एक्सल लोड फ्रेट कॉरीडोर स्थापित करने में सहयोग करने पर सहमत हुए। इस परियोजना में जापान की आर्थिक भागीदारी योजना की विशेष शर्तों के अंतर्गत विदेशी विकास सहायता के जरिए वित्तपोषित मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पत्तन से दिल्ली के तुगलकाबाद/दादरी तक एक रेल फ्रेट कारीडोर का निर्माण किया जाना है। जापान की सरकार ने समूचे समर्पित फ्रेट कॉरीडोर- पश्चिमी (डीएफसी-डब्ल्यू) के लिए वित्तपोषण करने की वचनबद्धता व्यक्त की है। एक सामान्य ठेकेदार को काम पर तैनात कर जापानी सहायता शुरू करने के लिए एक इंजीनियरींग सेवा ऋण करार पर अक्तूबर 2009 में हस्ताक्षर किए गए। जापानी पक्ष ने डीएफसी-डब्ल्यू चरण-II के लिए प्रारंभिक पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं पुनर्वास और बहाली योजना के लिए एक अनुसूची का भी प्रस्ताव दिया है।

प्रधान मंत्री की दिसंबर 2006 की जापान यात्रा के दौरान दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) को विकसित करने के प्रस्ताव पर सहमति हुई। 1483 किमी. डीएमआईसी का संरेखण अहमदाबाद, पालमपुर, फुलेरा, रिवाड़ी और दादरी हो कर है। इसके विस्तृत ब्योरे निर्धारित करने के लिए सचिव, औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग और जापान के आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के उप मंत्री की सह-अध्यक्षता में एक संयुक्त कार्य बल स्थापित किया गया है। अभी तक संयुक्त कार्य बल की सात बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें से अंतिम दो दौर नई दिल्ली में 13 जुलाई, 2009 और 24 दिंसबर, 2010 को हों। डीएमआईसीडीसी ने प्रारंभिक परियोजनाओं की पहचान कर ली है और वह राज्य सरकारों के परामर्श से निवेश क्षेत्र के लिए डीपीआर को अंतिम रूप दे रहा है। दिसंबर, 2009 में प्रधान मंत्री डा. हातोयामा की यात्रा के दौरान परियोजना विकास कोष की जापान की प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया गया।

सकारात्मक द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश की प्रवृत्तियों को गति प्रदान करने के लिए भारत और जापान वर्तमान में एक व्यापक आर्थिक सहभागिता करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं। भारत की ओर से वाणिज्य सचिव और जापान की ओर से उपविदेश मंत्री के नेतृत्व में बातचीत की जा रही है। अभी तक बातचीत के 12 दौर हो चुके हैं। अंतिम दौर टोक्यो में 29 सितम्बर-1 अक्तूबर 2009 को आयोजित किया गया।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अक्तूबर, 2008 में हुई जापान की यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने हैदराबाद में जापान के विभिन्न सहयोगों के जरिए एक नए आईआईटी स्थापित करने में सहयोग करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

जापान के साथ सरकारी स्तर की वार्ता प्रक्रिया सुस्पष्ट है और इसमें व्यापक मुद्दे शामिल है। विदेश सचिव की जापान के उप विदेश मंत्री के साथ वार्ता और उप विदेश मंत्री के साथ विदेश कार्यालय परामर्श, टोक्यो में 4 दिसम्बर, 2009 को आयोजित किए गए। भारत और जापान के बीच अन्य वार्ताओं में निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार पर वार्ता, आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य दल, कोंसली वार्ता, नीति नियोजन वार्ता और ट्रैक 1.5 सामरिक वार्ता शामिल है। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी संबंधित निर्यात नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों का हल करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी के लिए एक द्विपक्षीय परामर्शदात्री तंत्र स्थापित किया है। प्रक्रिया का चौथा दौर 24 अप्रैल, 2009 को टोक्यो में आयोजित हुआ। सभी आर्थिक मसलों पर समग्र वार्ता तंत्र स्थापित करने के लिए उच्च स्तरीय सामरिक आर्थिक वार्ता तंत्र स्थापित किया गया है। इस वार्ता की तीसरी बैठक वित्त सचिव और जापान के उप विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में 16 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में संपन्न हुई । शहरी विकास पर संयुक्त कार्य दल की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए सचिव (शहरी विकास) ने 11-12 जून, 2009 को जापान की यात्रा की।

द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में प्रगति की अपार संभावना है। प्रधान मंत्री एबे की वर्ष 2009 में हुई यात्रा के दौरान वर्ष 2010 तक 20 बिलियन अमेरिकी डालर का व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मिल कर कार्य करने पर सहमति हुई है। लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावना को झटका लगा और वृद्धि की गति धीमी रही। जापान के सरकारी आंकड़े के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार पूर्ववर्ती वर्ष में दर्ज 11.23 बिलियन अमेरिकी डालर से थोड़ी वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान 12.18 बिलियन अमेरिकी डालर पहुंच गया।

जापान, भारत में समुच्चयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में छठा सबसे बड़ा देश है। जापान की कंपनियों ने अप्रैल, 2000 और मार्च, 2009 के बीच 2.530 बिलियन अमेरिकी डालर का वास्तविक निवेश किया है। अवसंरचना एवं उद्योग क्षेत्रों में जापानी निवेशों से डीएफसी और डीएमआईसी परियोजनाओं से पूर्ण होने के बाद काफी बल मिलेगा।

वित्तीय वर्ष 2003-04 से भारत जापानी ओडीए ऋण सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। अक्तूबर, 2009 तक भारत के लिए जापानी ओडीए की समुच्चयीय प्रतिबद्धता लगभग 2.9 ट्रिलियन येन (लगभग 113209.77 करोड़ रुपए) है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल ओडीए 236 बिलियन येन (लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डालर अथवा 11713 करोड़ रुपए) था जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 4.8 प्रतिशत अधिक है और जापान के विश्व ओडीए का 30 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2009-10) के लिए जापान ने पहली खेप के तहत दो ओडीए परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है जिसमें कि 57 बिलियन येन की लागत से दिल्ली और कोलकाता मैट्रो परियोजना शामिल है।

रक्षा एवं सुरक्षा, द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2009 के लिए कार्यक्रम के ब्यौरे को आदान-प्रदान और संस्थागत रूपरेखा के अंतर्गत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतिम रूप दे दिया गया है। रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित मामलों पर वार्ताओं में - सचिव स्तरीय रक्षा नीति वार्ता, व्यापक सुरक्षा वार्ता (सीएसडी), मिलिट्री-टू-मिलिट्री (एम2एम) वार्ता, नेवी-टू-नेवी वार्ता शामिल है। द्वितीय नेवी-टू-नेवी स्टाफ-स्तरीय वार्ता अक्तूबर 2009 में टोक्यो में संपन्न हुई। नई द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में 14 अक्तूबर, 2009 को हुई। जापान और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मालाबार अभ्यास के लिए चार भारतीय युद्धपोत 26-29 अप्रैल, 2009 को जापान गए। जापान के समुद्री स्वरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) पोत कशिमा, शिमायुकी और यूगिरी 6-10 मई, 2009 को गोवा की यात्रा पर आए। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने छठे प्रशांत सेना प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए टोक्यो का दौरा (23-27 अगस्त, 2009) किया। रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटोनी की नवंबर, 2009 में हुई यात्रा के मुख्य परिणामों में - रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक रक्षा सचिव/उप मंत्री की नियमित बैठकों और सेवा प्रमुखों के दौरे के आदान-प्रदान को कार्यक्रमबद्ध करना- शामिल है। दोनों देशों के तट रक्षक बलों के बीच उच्चस्तरीय वार्ता जनवरी, 2010 में संपन्न हुई।

समीक्षाधीन अवधि वर्ष भारत-जापान संबंधों में कई घटनाक्रमों का साक्षी रहा। क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान नियमित उच्च-स्तरीय तालमेल और विभिन्न क्षेत्रों में सतत आदान-प्रदान जारी रहे। दोनों देश जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक वित्तीय स्थिति जैसे वैश्विक मुद्दों पर क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं।

कोरिया गणराज्य

कोरिया के राष्ट्रपति रोह क्यून-ह्वान की वर्ष 2004 की भारत की यात्रा के दौरान कोरिया गणराज्य के साथ स्थापित 'दीर्घकालिक सहयोगात्मक भागीदारी' भारत-कोरिया द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है। यह भागीदारी हाल के वर्षों में और गहन एवं वैविध्यपूर्ण हुई है। वर्ष के दौरान भारत-कोरिया गणराज्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं में कई उच्च-स्तरीय दौरे, व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर, आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्रियाकलापों में बढ़ोत्तरी और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदान-प्रदान का विस्तार शामिल रहे।

वर्ष के दौरान भारत और कोरिया गणराज्य के बीच कई उच्च-स्तरीय दौरे हुए। कोरिया गणराज्य के विदेशी मामलों एवं व्यापार मंत्री मी.यू म्यूंग-ह्वान ने 23 जून, 2009 को नई दिल्ली की यात्रा की और विदेश मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की। इस यात्रा के दौरान कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री ने प्रधान मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से भी मुलाकात की। यह यात्रा जो कि भारत में नई सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों के अंदर हुई थी, दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को दी गई महत्ता को दर्शाता है।

कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ली क्यूंग-बाक 24-27 जनवरी, 2010 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। वे भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ली की प्रधान मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। भारत के उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा से उन्होंने मुलाकात की। राष्ट्रपति ली के सम्मान में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल द्वारा राजकीय भोज आयोजित किया गया। प्रतिनिधि स्तरीय वार्ताओं के पश्चात 25 जनवरी, 2009 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। भारत-कोरिया गणराज्य के संबंधों को एक 'सामरिक साझेदारी' तक ले जाने का निर्णय इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। इस यात्रा के दौरान चार दस्तावेजों नामतः-सजायाफ्ता लोगों के अंतरण पर करार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन, 2010-12 की अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के कार्यक्रम और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद (इसरो) और कोरियन एयरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (केएआरआई) के बीच संपन्न एक अन्य समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय सरकारी एवं व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी था। यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित भारत-कोरिया गणराज्य व्यापार मंच को भी संबोधित किया।

भारत-कोरिया गणराज्य विदेश कार्यालय परामर्श 18 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की विस्तृत श्रृंखला की समीक्षा की और दोनों देशों की रुचिवाले महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश कार्यालय परामर्श के स्तर को उप मंत्री (सचिव) के स्तर तक उठाने का भी निर्णय लिया गया।

भारत-कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग वर्ष के दौरान पूर्ववत् जारी रहा। रक्षा उद्योग एवं संभारीय सहयोग पर वर्ष 2005 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भारत-कोरिया गणराज्य रक्षा सहयोग का खाका है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों देशों ने सहयोग पर एक संयुक्त कार्य दल स्थापित किया जिसकी दो बैठकें हो चुकी है। संयुक्त कार्य दल की तीसरी बैठक शीघ्र ही सियोल में होनी है।

भारत और कोरिया गणराज्य ने 7 अगस्त, 2009 को एक ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) निष्पादित किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने इस महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सियोल की यात्रा की जो कि विशेष रूप से आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत-कोरिया गणराज्य द्विपक्षीय संबंधों में एक नए युग का सूत्रपात करेगी। यह भारत का दूसरा सीईपीए और किसी ओईसीडी देश के साथ संपन्न पहला सीईपीए है। तत्पश्चात सीईपीए का कोरिया गणराज्य

की नेशनल एसेम्बली द्वारा अनुसमर्थन किया जा चुका है और भारतीय पक्ष की प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के पूरा हो जाने के पश्चात 1 जनवरी, 2010 से इस करार के प्रवृत्त हो जाने की आशा है।

अक्तूबर, 2003 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में भारत-कोरिया गणराज्य निवेश संवर्धन समिति की तीसरी बैठक 2-3 सितम्बर, 2009 को सियोल में हुई । भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव ने किया।

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2008 में 15.56 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच कर, 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और इस प्रकार दोनों देशों द्वारा वर्ष 2010 तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित 10 बिलियन अमेरिकी डालर के लक्ष्य को पार कर लिया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण अपार गतिरोध के बावजूद आशा है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारों में वर्ष के दौरान गति बनी रहेगी।

संस्कृति पर संयुक्त समिति की 7वीं बैठक 1-3 सितंबर, 2009 को सियोल में संपन्न हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने वर्ष 2009-12 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया। अप्रैल, 2005 में हस्ताक्षरित युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम पर करार के अंतर्गत दोनों देशों के युवा प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से यात्राएं करते रहे। 20 सदस्यीय एक युवा प्रतिनिधिमंडल ने 24 अगस्त-2 सितंबर, 2009 तक कोरिया गणराज्य की यात्रा की और एक 20 सदस्यीय कोरियाई युवा प्रतिनिधिमंडल ने भी 17-26 सितंबर, 2009 तक भारत की यात्रा की।

मंगोलिया

मंगोलिया के साथ भारत के सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध, जो कि मंगोलिया के प्रधानमंत्री की वर्ष 2004 में हुई भारत यात्रा के दौरान 'भागीदारी' के स्तर तक पहुंच गये थे, उनका रक्षा एवं सुरक्षा, आर्थिक, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में को सम्मिलित करने के लिए विकसित और वैविध्यपूर्ण होना जारी रहा।

दोनों पक्षों ने वर्ष के दौरान कई उच्च स्तरीय दौरों का आदान प्रदान किया। मंगोलिया के नए राष्ट्रपति मी.टीएस एल्बेगडोर्ज के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रणीत कौर ने 17-19 जून, 2009 तक मंगोलिया की यात्रा की।

मंगोलिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति की 13-16 सितंबर, 2009 को भारत की राजकीय यात्रा से भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बल मिला है। मंगोलिया के राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मंगोलिया के नेता की यह पहली विदेश यात्रा थी। दोनों पक्षों ने संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विचार-विमर्श किया और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के स्तर को 'गहन भागीदारी' स्तर तक उन्नत करने पर सहमति व्यक्त की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पांच करार/समझौता ज्ञापन, नामतः स्थिरीकरण ऋण सहायता करार, सांख्यिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, रेडियोधर्मी खनिजों एवं नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर समझौता ज्ञापन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और वर्ष 2009-12 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। मंगोलिया पक्ष के अनुरोध पर भारत सरकार ने मंगोलिया को विश्व आर्थिक संकट के मद्देनजर अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता दी है। भारत ने मंगोलिया को विशेष सरल शर्तों पर 20 मिलियन अमेरिकी डालर की परियोजना विशेष ऋण-श्रृंखला देने पर भी सहमति दी है।

सहयोग पर भारत-मंगोलिया संयुक्त समिति (जेसीसी) की दूसरी बैठक 11 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रणीत कौर ने भारतीय पक्ष की ओर से बैठक की सह-अध्यक्षता की जबकि मंगोलिया पक्ष की ओर से वहां के शिक्षा, संस्कृति एवं विज्ञान मंत्री मी.योन्डोन्जीन ओट्गोंबायर ने बैठक की सह अध्यक्षता की। जेसीसी ने मंगोलिया के राष्ट्रपति एल्बेगडोर्ज की सितंबर, 2009 में हुई भारत की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा किए गए अनुवर्ती उपायों की समीक्षा की। इस दौरान सहयोग के और क्षेत्रों की पहचान और चर्चा भी हुई (कृषि, पशुपालन, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, मंगोलियाई शिक्षकों के प्रशिक्षण इत्यादि)। भारत द्वारा मंगोलिया को 20 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण-श्रृंखला का, उपयोग कर एक भारत-मंगोलिया संयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं आउटसोर्सिंग केंद्र स्थापित करने का मंगोलिया पक्ष ने एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की।

वर्ष के दौरान रक्षा के क्षेत्र में भारत-मंगोलिया सहयोग में काफी प्रगति देखने को मिली। पांचवां भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 14-27 सितंबर, 2009 तक मंगोलिया में आयोजित किया गया। भारत ने 3-31 अगस्त, 2009 तक मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय शांतिरक्षण अभ्यास 'खान क्वेस्ट' में भी भाग लिया। मंगोलिया के अनुरोध पर भारत ने मंगोलिया के सैन्य बलों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना के चार अधिकारियों को एक वर्ष की अवधि के लिए मंगोलिया में प्रतिनियुक्त किया है।

वर्ष के दौरान भारत और मंगोलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच नियमित तालमेल जारी रहा। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच वार्षिक वार्ता के लिए कार्यकारी सचिव श्री टीएस. एंख्तुवशीन के नेतृत्व में मंगोलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने 31 अगस्त-2 सितंबर, 2009 तक भारत की यात्रा की।

भारत और मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के बीच भी दौरों का नियमित आदान-प्रदान और सहयोग कार्यक्रम

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 25 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री ली म्युंग बैक के साथ।

कोरिया के राष्ट्रपति श्री ली म्युंग बैक, उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 26 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 'एट होम ' समारोह के अवसर पर श्रीमती किम यून ओक, डॉ. देवी सिंह राम सिंह शेखावत और श्रीमती गुरशरण कौर भी उपस्थित थे।

जारी रहे। मंगोलिया पक्ष के अनुरोध पर सीमा सुरक्षा बल ने 7 सितंबर-14 दिसंबर, 2009 तक मंगोलिया के सीमा अधिकारियों के लिए दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

वर्ष के दौरान दोनों पक्ष रेडियोधर्मी खनिज एवं नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग करने के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए। परमाणु ऊर्जा विभाग और मंगोलिया में यूरेनियम की खोज और खनन में लगी मंगोलिया सरकार की इकाई मोनाटोम के बीच दौरों के आदान-प्रदान हुए। मंगोलिया के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान सितंबर, 2009 में असैनिक नाभिकीय सहयोग पर अंतर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर होने से इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आइटेक) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगोलिया एक प्रमुख लाभप्राप्तकर्ता देश के रूप में उभरा है। राष्ट्रपति एलेबेग्डोर्स की सितंबर, 2009 में हुई भारत यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने मंगोलिया के लिए आइटेक स्लॉटों की संख्या 60 से दोगुनी कर 120 करने की घोषणा की। विदेश सेवा संस्थान प्रति वर्ष मंगोलिया के एक राजनयिक को विदेशी राजनयिकों के व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2009-10 से स्लॉटों की संख्या को बढ़ाकर तीन करने का निर्णय लिया गया है।

कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य

भारत और कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) के बीच संबंध मानवीय विषयों एवं मानव संसाधन विकास सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। वर्ष के दौरान संस्कृति, खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान में प्रगति होना जारी है।

विदेश कार्यालय परामर्श के छठे दौर के लिए डीपीआरके के उप विदेश मंत्री किम युंग II की अगस्त, 2009 में हुई भारत की यात्रा के साथ दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आदान-प्रदान जारी रखे। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, परस्पर रूचि के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान, छह दलीय वार्ता प्रक्रिया और भावी सहयोग के चरण चर्चा में शामिल रहे।

डीपीआरके में मानव संसाधनों के विकास के लिए भारतीय सहायता जारी है। वर्ष 2009-10 के लिए आइटेक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत डीपीआरके को 18 स्लॉट आबंटित किए गए। भारत स्थित रक्षा संस्थान (एईसी प्रशिक्षण संस्थान) में अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दो अतिरिक्त आइटेक स्लॉटों की भी पेशकश डीपीआरके को की गई।

■■

यूरेशिया 4

रूसी परिसंघ

यह वर्ष भारत और रूस के बीच सभी स्तरों पर हाइड्रोकार्बन और परमाणु ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान और संस्कृति सहित राजनीतिक वार्ता, व्यापार और निवेश, उर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी और जारी बहुविध सहयोग के क्षेत्रों में और विविधता तथा दृढ़ीकरण के उद्देश्य से सघन चर्चा का साक्षी रहा।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वार्षिक भारत-रूस शिखर वार्ता के लिए 6-8 दिसंबर, 2009 के दौरान मास्को का दौरा किया; चूंकि वर्ष 2000 में सामरिक साझीदारी की घोषणा से द्विपक्षीय संबंध पुनः सक्रिय हुआ इसलिए ये शिखर सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित होते रहे हैं। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति श्री दामित्री मेदवेदेव और प्रधानमंत्री श्री ब्लादीमिर पुतिन दोनों से मुलाकात की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई और आपसी हित के बड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-रूस सीईओएस परिषद की बैठक को संबोधित किया (भारत-रूस सीईओएस परिषद के सह-अध्यक्ष भारतीय पक्ष की ओर से रिलायंस उद्योग लि. के श्री मुकेश अंबानी और रूसी पक्ष की ओर से श्री ब्लादीमिर इण्टूशेनकोव हैं) । प्रधान मंत्री की प्रख्यात रूसी विद्वानों एवं भारतविदों से अलग से बातचीत हुई। भारतीय प्रधान मंत्री और रूस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गएः (i) 2011-2020 की अवधि के दौरान सेना एवं तकनीकी सहयोग के लिए कार्यक्रम पर भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच करार; (ii) भारत के गणराज्य को दिये गए रूसी हथियारों और सैन्य उपस्करों के लिए आफ्टर सेल्स सपोर्ट के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच करार; (iii) 12 नवंबर, 2007 के मल्टी-रोल ट्रांसपोर्ट एअरक्राफ्ट के विकास और उत्पादन में सहयोग के संबंध में भारत के गणराज्य की सरकार और रूसी महासंघ की सरकार के करार का प्रोतोकाल; (iv) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच करार (आद्याक्षरित); और (v) वर्ष 2010-12 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रम, तथा (vi) रूस को भारतीय सामान और प्रौद्योगिकी उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से नेशेकोनोम बैंक को एक्सिम बैंक द्वारा 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान करने के लिए डालर करार। शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर 'वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामरिक भागीदारी के सुदृढ़ीकरण' संबंधी संयुक्त घोषणा भी की गई। रूस और सीआईएस देशों में हाइड्रोकार्बन ब्लाक अन्वेषण के लिए संयुक्त बोली के लिए ओएनजीसी विदेश लि. और सिस्टीमा के बीच करार पर अलग से हस्ताक्षर किए गए।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने 2-6 सितंबर, 2009 के दौरान रूस का दौरा किया, उस दौरान दमित्री मेदवदेव, प्रधानमंत्री श्री ब्लादीमिर पुतिन, फेडरेशन काउंसिल के अध्यक्ष श्री सरगेई मीरोनोव और स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष श्री बोरिस ग्रिजलोव तथा अन्य महानुभावों से मुलाकात की।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरे किए गएः

- रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव श्री निकोलई पतरूशेव ने 14-17 मई, 2009 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधी बातचीत की।
- प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 15-16 जून, 2009 को ब्राजील-रूस-भारत-चीन (बीआरआईसी) और शंघाई सहयोग संगठन (एसटीओ) शिखर सम्मेलन बैठक में भाग लेने के लिए येकाटरिनबर्ग का दौरा किया। इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने द्विपक्षीय चर्चा के लिए रूस के राष्ट्रपति श्री दमित्री मेदवेदेव से मुलाकात की।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा, जो 2-6 सितंबर, 2009 के दौरान रूस के राजकीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति के साथ थे, ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में रूसी प्राधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही उन्होंने टोमस्क क्षेत्र का दौरा किया जहां पर एनजीसी विदेश लि. ने इम्पीरियल एनर्जी से ऑयल ब्लाक प्राप्त किए हैं।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने 29 सितंबर-3 अक्तूबर 2009 के दौरान भारत-रूस व्यापार एवं निवेश मंच की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया। उन्होंने आर्थिक विकास मंत्री श्रीमती एलविरा साखिप्जादोवना नबीउलीना से मुलाकात की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की प्रधानमंत्री पुतिन एवं उद्योग एवं

व्यापार मंत्री श्री विक्टर बोरीसोविच ख्रिस्टेन्को के साथ भी द्विपक्षीय बैइक हुई। दौरे के दौरान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ' ईयर आफ इंडिया इन रशिया ' समारोह के भाग के रूप में 150 से अधिक व्यावसायिक हस्तियों की सहभागिता सहित सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंडिया शो का भी उद्घाटन किया।

- रक्षा मंत्री श्री ए. के. एंटनी ने सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 9वें सत्र में भाग लेने के लिए 14-15 अक्तूबर, 2009 को मास्को का दौरा किया। दौरे के दौरान, उन्होंने रक्षा और सैन्य सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर रूसी समकक्ष श्री अनातोली इडुवार्डोविच सर्डियूकोव के साथ चर्चा की।

- विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने रूस के उप प्रधान मंत्री श्री सरजई एस. सोबियानिन के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरजीसी-टीईसी) के 15वें सत्र की सह-अध्यक्षता के लिए 20-22 अक्तूबर, 2009 के दौरान मास्को का दौरा किया। वार्ता की समाप्ति पर बैठक के दौरान हुई चर्चा को दर्शाने वाले प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने अपने रूसी समकक्ष श्री सरजई लवरोन के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और राष्ट्रपति श्री दइसनेमित्री मेदवेदेव से भी मुलाकात की। आईआरआईजीसी-टीईसी बैठक से पहले अंतर-सरकारी आयोग के अंतर्गत विभिन्न कार्यकारी समूहों की बैठकें आयोजित की गईं जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों में संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। इनमें व्यापार एवं अर्थव्यवस्था संबंधी कार्यकारी समूह (मास्को, 28 सितंबर, 2009); धातु-विज्ञान एवं खनन संबंधी कार्यकारी समूह (मास्को, 8-9 अक्तूबर, 2009); बैंकिंग एवं वित्तीय मामले संबंधी उप समूह (हैदराबाद, 5-7 अक्तूबर, 2009); सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी कायकारी समूह (नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2009); और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यकारी समूह (मास्को, 20 अक्तूबर, 2009) शामिल हैं। ऊर्जा संबंधी कार्यकारी दल की मास्को में 23-24 नवंबर, 2009 को बैठक हुई।

- रूसी विदेश मंत्री श्री सरजई लवरोव ने 26-27 अक्तूबर, 2009 के दौरान भारत-रूस-चीन द्विपक्षीय विदेश मंत्रियों की 9वीं बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु का दौरा किया। भारत और रूस के बीच कोई द्विपक्षीय चर्चा नहीं हुई।

- रूस के प्रथम उप विदेश मंत्री श्री अन्द्रेयी ए. देनीसोव ने विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव के साथ विदेश कार्यालय परामर्श करने के लिए 10 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली का दौरा किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की और आपसी चिंता से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, दोनों विदेशी कार्यालयों ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों पर परामर्श कियाः (i) यूएन से संबंधित मुद्दे एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर सहयोग (मास्को, अगस्त, 2009); (ii) चीन और पूर्व एशिया (नई दिल्ली, मार्च, 2009); (iii) ईरान और अफगानिस्तान (नई दिल्ली, नवंबर, 2009); दक्षिण एशिया (मास्को, अक्तूबर, 2009); (iv) कौंसली मुद्दे (मास्को, 12 और 13 नवंबर, 2009); और (v) मध्य पूर्व और इराक (मास्को, 22 जनवरी, 2010)।

- रूसी उप प्रधान मंत्री श्री सरजई सोबियानिन ने 9-12 नवंबर, 2009 के दौरान भारत के अपने प्रथम दौरे के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की और विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा; और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा के साथ बैठक की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सीआईआई द्वारा आयोजित भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और बेंगलोर में इन्फोसिस और रूसी सहयोग से कुंदनकुलम में निर्माणाधीन सिविलियन सुविधाओं का दौरा किया।

- रूसी उप प्रधान मंत्री श्री सरजई सोबियानिन ने मार्च, 2010 के मध्य में निर्धारित रूसी प्रधान मंत्री श्री ब्लादीमिर पुतिन के दौरे की तैयारी करने के लिए 15-17 फरवरी, 2010 के दौरान भारत का अपना दूसरा दौरा किया। आईआरआईजीसी-टीईसी के सह-अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उनके भारतीय समकक्ष, विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा से मुलाकात की और द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों की समीक्षा की।

रूस में भारतीय कला एवं संस्कृति, चित्रकला और कला वस्तुओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में उपलब्धियों को दर्शाते हुए 150 से अधिक कार्यक्रमों के आयोजन सहित इस वर्ष को 'रूस में भारत वर्ष' के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उनके रूसी समकक्ष श्री दमित्री मेदवेदेव के साथ मास्को में बोलशोई थियेटर के नये मंच पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। रूस में भारत वर्ष का समापन समारोह जो 7 दिसंबर, 2009 को निर्धारित था और जिसमें भारत और रूस के प्रधानमंत्रियों के भाग लेने की आशा थी, वह रूस के पर्म शहर में अग्नि त्रासदी से शिकार हुए लोगों के सम्मान में अस्थगित कर दिया गया।

द्विपक्षीय व्यापार जो रूसी आंकड़ों के मुताबिक 2008 में 7 बिलियन अमेरिकी डालर पर ठहर गया था उसमें तेजी आ रही है। प्रारम्भिक प्राक्कलन वर्ष 2009 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 8(वृद्धि दर्शाते हैं। अक्तूबर, 2009 में मास्को में आयोजित आईआरआई जीसी-टीईसी के 15वें सत्र के दौरान द्विपक्षीय व्यापार टर्नओवर में 2010 तक 10 बिलियन अमेरिकी डालर से

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह रूस की मेजबानी में येकातेरिनबर्ग में आयोजित ब्रिक और एससीओ शिखर बैठकों के दौरान 16 जून, 2009 को रूस के राष्ट्रपति श्री दमित्री अनातोलीविच मेदवेदेव से मुलाकात।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति श्री दमित्री अनातोलीविच मेदवेदेव 7 दिसंबर, 2009 को मास्को, रूस में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में।

2015 तक 20 बिलियन अमेरिकी डालर तक वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। ट्रेड बास्केट के विविधता जैसे कई स्थायी उपायों के जरिए एवं अधिक क्षमता वाले अप्रयुक्त क्षेत्रों जैसे आईटी, उच्च प्रौद्योगिकी, कच्चे हीरे और औषधियों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, सीईओ की परिषद (जिसके अध्यक्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री मुकेश अंबानी एवं सिस्टीमा के अध्यक्ष, श्री ब्लादीमीर इण्टूशेन्कोव हैं) की 7 दिसंबर, 2009 को मास्को में इसकी पहली पूर्ण बैठक हुई और इसने आशवस्त क्षेत्र के रूप में दूर संचार, अवसंरचना निवेश (भारत में) और फर्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र अभिज्ञात किए।

आर्मेनिया

भारत और आर्मेनिया के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बना रहा और विभिन्न स्तरों पर आपसी समझ कायम रही। मई, 2009 में येरेवान में हुए विदेशी कार्यालय परामर्श से जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा के साथ-साथ संभावित सहयोग के नये क्षेत्रों की पहचान के उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हुए।

भारत ने आर्मेनिया के विकासात्मक प्रयासों में योगदान देने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। इस संबंध में, आर्मेनिया में ग्रामीण विकास परियोजना के लिए 2,15,000 अमेरिकी डालर की भारत की सहायता के लिए 19 मई, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए; आर्मेनिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में विकास के उद्देश्य से 7.6 करोड़ रु. की लागत से सूचना और संचार भारत-आर्मेनिया उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना के लिए 26 जून, 2009 को दूसरे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद, उन्नत संगठन विकास केन्द्र (सी-डैक) के एक चार-सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने येरेवान का दौरा किया और परियोजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए आर्मेनिया में उनके समकक्षों के साथ विस्तार से सार्थक बातचीत की।

बागवानी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई; भारत के उद्यान-विज्ञान बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के चुनिंदा क्षेत्रों में खूबानी खेती के लिए परीक्षण के उद्देश्य से खूबानी के पौद्यों की आर्मेनियाई किस्मों की खरीद के लिए नवंबर, 2009 में येरेवान का दौरा किया।

आर्मेनिया में आर्मेनियाई लोगों की हिन्दी भाषा और संस्कृति में रूचि और आकंक्षाओं के जवाब में भारत ने हिन्दी भाषा और संस्कृति पीठ की स्थापना के लिए येरेवान स्टेट लिंग्विस्टिक यूनीवर्सिटी 'ब्रुसोव' के साथ 11 नवंबर, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हिन्दी भाषा और साहित्य पीठ ने 12 जनवरी, 2010 को हिन्दी शिक्षिका सुश्री अनिता वर्मा के जाने पर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। पूर्व में आईसीसीआर प्रायोजित सांस्कृतिक मंडली ने अप्रैल, 2009 में आर्मेनिया का दौरा किया।

अजरबैजान

भारत ने वर्तमान में अजरबैजान के साथ मित्रतापूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित किए।

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधी अन्तर-सरकारी आयोग की प्रथम बैठक 26 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष की सह-अध्यक्षता माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया ने की तथा अजरबैजान का प्रतिनिधित्व श्री हुसेंगुलु बाजीरोव, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधान मंत्री ने किया। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और सार्थक बनाने के लिए प्रोतोकाल के मसौदे पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों की ओर से कई वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडलों की यात्राएं हुईं। उनमें प्रमुख एक 11 सदस्यीय आजेरी व्यापार प्रतिनिधि मंडल था जिसमें 20-23 फरवरी, 2009 के दौरान गोवा में आयोजित आईआईजेएस हस्ताक्षर 2009 में भागीदारी के लिए रत्न एवं जेवरात के क्षेत्र में प्रख्यात व्यवसायीगण, 25-26 फरवरी, 2009 के दौरान नई दिल्ली में केपिकसल प्रायोजित प्रदर्शनी में एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और इलेक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएससी) द्वारा प्रायोजित इंडिया साफ्ट-2009 में एक-सदस्यीय भागीदारी शामिल है।

इस अवधि के दौरान कई द्विपक्षीय सांस्कृतिक गतिविधियां हुईं। उनमें से प्रख्यात थी तनुश्री शंकर के नेतृत्व में एक आईसीसीआर प्रायोजित समकालीन नृत्य मंडली जिसने सितंबर, 2009 में अपनी प्रथम प्रस्तुति की और अक्तूबर, 2009 में अजरबैजान भाषा विश्वविद्यालय के रेक्टर की अध्यक्षता में 'द रैलीवैंस ऑफ गांधी एण्ड वैल्यूज ' शीषर्क पर एक सेमिनार आयोजित किया गया।

बेलारूस

2009-10 के दौरान भारत के बेलारूस के साथ संबंध विकसित हुए और उसमें और विविधता आई।

विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने 16-17 सितंबर, 2009 के दौरान मिंस्क का दौरा किया जोकि भारत के किसी विदेश मंत्री का बेलारूस का पहला दौरा था। विदेश मंत्री ने अपने बेलारूसी समकक्ष श्री सरजई मार्टिनोव, विदेश मंत्री के साथ बैठकें की और श्री एलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इस दौरे के दौरान दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए- (i) शारीरिक प्रशिक्षण एवं खेलकूद के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में करार; और (ii) एचटी पार्क, मिंस्क में एक डिजीटल लर्निंग सेन्टर की स्थापना के संबंध में समझौता ज्ञापन। रक्षा राज्य मंत्री श्री एम.एम. पल्लम राजू ने 25-28 अक्तूबर, 2009 के दौरान बेलारूस का दौरा किया। रक्षा राज्य मंत्री ने कर्नल जनरल, लिवनिद एस. माल्टसेव, बेलारूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री के.जी. बालकृष्णन ने मार्च, 2009 में बेलारूस का दौरा किया। बेलारूस के स्टेट मिलिट्री एण्ड इंडस्ट्रीयल कमेटी के अध्यक्ष श्री एन.आई अजामाटोव

ने फरवरी, 2009 में 'एअरोइंडिया' प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए भारत का दौरा किया। इन उच्चस्तरीय दौरों से बेलारूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बेहतर गतिमात्रा बनाये रखने में मदद मिली।

सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-बेलारूस संयुक्त आयोग की मई 2009 में नई दिल्ली में दूसरी बैठक हुई। भारत-बेलारूस संयुक्त बिजनेस काउंसिल (जेबीसी) की छठी बैठक अक्तूबर 2009 में मिंस्क में आयोजित की गई।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बेलारूस के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध प्रगति पर थे। बेलारूस ने मई 2009 में मुंबई में एक केन्द्रीकृत व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की। भारतीय कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (भेल) को 55 मिलियन अमेरिकी डालर की ग्रोडनों-II पावर परियोजना के लिए ठेका मिला। यह बेलारूस में किसी भारतीय कंपनी को दिया गया पहला ठेका था। परियोजना के लिए इस संविदा पर सितंबर, 2009 में विदेश मंत्री के मिंस्क दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार ने इस परियोजना को 60 मिलियन अमेरिकी डालर का एक ऋण श्रृंखला प्रदान की। भारत सरकार मिंस्क में हाई टेक्नोलाजी पार्क में एक डिजीटल लर्निंग सेन्टर की स्थापना कर रही है जिसके लिए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विदेश मंत्री के मिंस्क दौरे के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बेलारूसी व्यवसायियों/मीडिया के लोगों ने संबंधित इंडियन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के प्रायोजन पर जुलाई, 2009 में इंडिया इंटरनेशनल गार्मेंट्स फेयर, अक्तूबर, 2009 में भारतीय हस्तकला एवं उपहार मेला और अक्तूबर, 2009 में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय लैदर मेले में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

बेलारूस के साथ सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सहयोग भी सुदृढ़ हुआ। बेलारूस की एक अंग्रेजी साहित्यिक पत्रिका 'नीमैन' ने बेलारूसी अकादमीशियन प्रो. मिखाइल आई मिहैलोव के भारत के संबंध में लेख पर विशेष जोर देते हुए सितंबर, 2009 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के साथ एक विशेष अंक प्रकाशित किया। मिंस्क स्थित भारतीय राजदूतावास ने आईसीसीआर के विद्यार्थियों द्वारा संचालित शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य कक्षाओं का आयोजन जारी रखा। बेलारूसी नामितों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए आईसीसीआर सांस्कृतिक छात्रवृत्ति का लाभ मिलता रहा। भारत के फिल्म समारोह निदेशालय ने भी नवंबर, 2009 में मिंस्क अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 'लिस्टापैड ' में भाग लिया।

जार्जिया

वर्ष के दौरान जार्जिया के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। जार्जिया में भारत के राजदूत (जिनका आवास येरेवान में है) ने विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जार्जिया के प्राधिकारियों से सतत वार्ता जारी रखी। अगस्त, 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट और जार्जिया-रूस में तनाव के परिणामस्वरूप जार्जियाई अर्थव्यवस्था को धक्का लगने के बावजूद भारतीय निवेशकों का विश्वास नहीं डगमगाया; इस्पात, तेल एवं गैस क्षेत्रों में भारत द्वारा जार्जिया में उल्लेखनीय निवेश किए गए।

जार्जिया द्वारा 2010 में नई दिल्ली में अपना रेजिडेंट मिशन खोले जाने की संभावना है।

29-30 मार्च, 2010 के दौरान नई दिल्ली में विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित किया जाएगा। भारतीय पक्ष का नेतृत्व संयुक्त सचिव (यूरेशिया) द्वारा किया जाएगा जबकि जार्जियाई विदेशी कार्यालय में एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक रिम डिपार्टमेंट के निदेशक जार्जियाई पक्ष का नेतृत्व करेंगे।

कजाखस्तान

प्रधानमंत्री की येकातिनबर्ग में एससीओ शिखर सम्मेलन के अवसर पर 16 जून, 2009 को कजाखस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरवायेव के साथ बैठक हुई। इस बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध के स्वरूप पर संतोष व्यक्त किया और जनवरी में कजाख राष्ट्रपति के भारत के राजकीय दौरे के दौरान जारी संयुक्त घोषणा में लिए गए और दर्शाए गए निर्णयों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने यह निदेश दिया कि भारत और कजाखस्तान के विदेश मंत्री को निकट भविष्य में बैठक करनी चाहिए और द्विपक्षीय संबंध क्षेत्र की कार्ययोजना को अंतिम रूप देना चाहिए तथा दोनों पक्षों द्वारा इसे बहुत सक्रियतापूर्वक आगे बढ़ाये जाने की जरूरत है।

अस्ताना में 22 सितंबर, 2009 को कजाखस्तान के साथ विदेशी कार्यालय परामर्श किए गए। श्री एन. रवि, सचिव (पूर्व) ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और अपने कजाख समकक्ष के साथ परामर्श किए।

विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के संबंध में लंदन सम्मेलन के अवसर पर जनवरी, 2010 में लंदन में अपने कजाख समकक्ष श्री कनात सौदम्बायेव के साथ बैठक की।

किर्गिज गणराज्य

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग संबंधी अंतर-सरकारी आयोग की बैठक 2 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने की संभावना है। इस आयोग की सह-अध्यक्षता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यमंत्री (वाणिज्य एवं उद्योग) और किर्गिज गणराज्य के प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। 26 जून, 2009 को विशकेक में किर्गिज गणराज्य के साथ विदेशी कार्यालय परामर्श किए गए। अंतर-सरकारी आयोग की बैठक की समाप्ति के पश्चात एक संयुक्त प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए गए। श्री एन. रवि, सचिव (पूर्व) ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। किर्गिज शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री इब्रैमोव, इमरेक सुल्तानोविच, उप विदेश मंत्री ने किया।

तजाकिस्तान

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल 6-8 सितंबर, 2009 के दौरान तजाकिस्तान के राजकीय दौरे पर रहीं। यह मध्य एशिया क्षेत्र का किसी भारतीय राज्याध्यक्ष का प्रथम दौरा था। माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति रहमान से मुलाकात और उसके बाद शिष्टमंडल स्तर पर बातचीत शामिल है। तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपतिजी से मुलाकात की। उन्होंने ताजिक संसद के निचले सदन के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ भी बैठक की। राष्ट्रपति ने कुलयाब में सूफी संत सैयद हमादोनी के मकबरे का भी दौरा किया। जम्मू व कश्मीर में इस्लाम को लाने का श्रेय इसी संत को दिया जाता है और इस राज्य से लोग अक्सर जयारत करने आते हैं। इस राजकीय दौरे से भारत-तजाकिस्तान संयुक्त व्यापार मंच के उद्घाटन का अवसर प्राप्त हुआ जिसको राष्ट्रपतिजी ने राष्ट्रपति रहमान के साथ संयुक्त रूप से संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सम्मानीय अतिथि के रूप में तजाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी भाग लिया। यह प्रथम अवसर था जब किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया था। राष्ट्रपति ने हमारे राजदूत द्वारा भारतीय समुदाय के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भी भाग लिया। इस दौरे के दौरान उच्चतम राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों की पुनः पुष्टि करने एवं आपसी हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका मिला।

तुर्कमेनिस्तान

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा 18-19 सितंबर, 2009 के दौरान तुर्कमेनिस्तान में उच्च स्तरीय शिष्टमंडल द्वारा किए गए सरकारी दौरे के साथ गए जिसके दौरान विदेश मंत्री एवं उनके तुर्कमेन समकक्ष द्वारा दोनों विदेशी कार्यालयों के बीच सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री ने तुर्कमेन राष्ट्रपति श्री गुरबंगुली बर्डी मुहम्मेदेव से मुलाकात की और बैठक के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय हित एवक क्षेत्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

विदेश मंत्री एवं उनके तुर्कमेन उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री राशिद मेरेडोक के बीच सरकारी बातचीत के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और वीज़ा नीति में छूट के संबंध में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय करार शामिल थे। विदेश मंत्री ने भारत सरकार द्वारा अशगाबत में 'इंडिया-तुर्कमेनिस्तान सेन्टर फॉर इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी ' की स्थापना के लिए तुर्कमेन पक्ष को एक समझौता ज्ञापन भी सौंपा। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों एवं सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। तुर्कमेन पक्ष ने दोनों पक्षों की ओर से सांस्कृतिक मंडली द्वारा दौरे के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का पता लगाने की आवश्यकता पर भी जोर किया।

गैस और तेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल की तुर्कमेन उप प्रधान मंत्री, तेल एवं गैस क्षेत्र का प्रभारी के साथ भी विस्तृत चर्चा हुई। टीएपीआई (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन) परियोजना के बारे में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और उप प्रधान मंत्री, तेल एवं गैस प्रभारी के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई।

श्रीमती प्रनीत कौर, राज्य मंत्री (विदेश मंत्रालय) 8-9 फरवरी, 2010 के दौरान अशगाबत में आयोजित होने वाली अन्तर-सरकारी आयोग की बैठक के तीसरे सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगी। तुर्कमेन पक्ष की ओर से सह-अध्यक्षता श्री राशिद मेरेडोव, उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री करेंगे। बैठक की समाप्ति के पश्चात एक संयुक्त प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किये जाने है।

यूक्रेन

भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत प्रगाढ़ एवं सौहार्दपूर्ण रहे। दोनों ही देश विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बरकरार रखने में जुटे रहे।

भारत और यूक्रेन ने जीवन विस्तार और भारतीय वायु सेना के एएन-32 मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एअरक्राफ्ट के आधुनिकीकरण के लिए संविदा किया जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा मिला। इसके बाद यूक्रेन वायु सेना प्रमुख के आमंत्रण पर भारतीय वायु सेना प्रमुख के यूक्रेन का (31 अगस्त से 5 सितंबर) दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल की यूक्रेन के रक्षा एवं औद्योगिक नीति मंत्रियों के साथ सार्थक बैठकें हुईं और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के कई पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सैन्य हित के कुछ अन्य क्षेत्रों का दौरा किया।

व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में प्रगति कायम रही क्योंकि दोनों ही देशों ने व्यापार प्रोन्नति तंत्रों जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों एवं प्रदर्शनियों सहित ठोस प्रयास किए। इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल इंडिया द्वारा कीव में एक क्रेता-बिक्रेता बैठक की गई और दूसरी बैठक केमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा की गई भारतीय कंपनियों ने यूक्रेन में आयोजित अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे तकनीकी, कृषि-औद्योगिक, पर्यटन एवं खाद्य प्रसंस्करण को शामिल करते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया।

संस्कृति दूसरा क्षेत्र था जो द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक विकास का साक्षी रहा। मिशन के सहयोग से युक्रेन के सांस्कृतिक संगठनों द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, प्रख्यात बांसुरी वादक और तबलावादक पंडित विजय घाटे और यूक्रेन के कलाकारों द्वारा अपनी भारत यात्रा से प्रेरणा पाकर फोटो एवं पेंटिंग जैसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऑल यूक्रेनियन एसोसिएशन ऑफ इंडोलोजिस्ट्स द्वारा भारत विज्ञान के संबंध में गोलमेज बैठक आयोजित की गई।

भारत सरकार ने यूक्रेनियन सरकार द्वारा देश के कुछ भागों में इन्फ्लूएंजा महामारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में की गई अपील के जवाब में एक मिलियन अमेरिकी डालर की दवाई के रूप में मानवीय सहायता की घोषणा करते हुए यूक्रेन की ओर सहायता का हाथ बढ़ाया। यूक्रेन में संचालित, भारतीय फर्मास्यूटिकल कंपनियों ने महामारी का मुकाबला करने में मदद करने की दृष्टि से यूक्रेन को अलग से लगभग 600,000 अमरीकी डालर की दवाई दी। मानवीय सहायता दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रगाढ़ एवं सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार की बचनवद्धता की अभिव्यक्ति थी।

उज्बेकिस्तान

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 22-23 अक्तूबर, 2009 के दौरान उज्बेकिस्तान का सरकारी दौरा किया। विदेश मंत्री ने 23 अक्तूबर, 2009 को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री इस्लाम करीमोव से मुलाकात की। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अप्रैल, 2006 में ताशकंद के सफल दौरे के पश्चात द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर चर्चा की गई। यह संतोषपूर्वक यह देखा गया कि द्विपक्षीय संबंधों को गति देते हुए अंतर-सरकारी आयोग की दो बैठकें हो चुकी थी। हाइड्रोकार्बन एवं खनन सहित द्विपक्षीय सहयोग के सहमत क्षेत्रों में और गति प्रदान करने एवं स्वास्थ्य, आई टी एवं कृषि जैसे सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने का निर्णय लिया गया। यह नोट किया गया कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंध सशक्त ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक बुनियादों पर आधारित था और 1991 से द्विपक्षीय संबंध अनुनादी एवं पारस्परिक रूप से विकास हुआ।

विदेश मंत्री और श्री ब्लादिमीर नोरोव, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच वार्ता के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वीजा नीति में छूट शामिल है। दोनों मंत्रियों ने बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष प्रकट किया और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उज्बेकिस्तान ने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की अभ्यर्थिता का अपना समर्थन दोहराया। उज्बेक पक्ष ने द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की दृष्टि से नये विचारों पर चर्चा करने के अधिदेश सहित सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के साथ भारत-उज्बेकिस्तान गोलमेज स्थापित करने के भारतीय पक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किया। उज्बेक पक्ष ने उज्बेकिस्तान में एक मिलियन अमेरिकी डालर के चिकित्सा उपस्कर एवं आपूर्ति अस्पतालों को देने का स्वागत किया। विदेश मंत्री ने 2006 में ताशकंद में स्थापित जवाहर लाला नेहरू सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र को उन्नत बनाने के लिए अतिरिक्त विकास सहायता का प्रस्ताव दिया। विदेश मंत्री ने उज्बेकिस्तान में एक इंटरप्रेनियरशिप डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की हमारी बचनवद्धता दोहराई। विदेश मंत्री ने अलबेरूनी इंस्टीच्यूट ऑफ ऑरिएंटल स्टडीज में इंडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया।

दौरे के दौरान, विदेश मंत्री ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए जहां पर उन्होंने 1966 में अंतिम सांस ली थी।

भारत-रूस-चीन त्रिपक्षीय सहयोग

भारत-रूस-चीन के विदेश मंत्रियों की नौवीं त्रिपक्षीय बैठक 27 अक्तूबर, 2009 को बेंगलोर में आयोजित की गई। इस बैठक से जलवायु परिवर्तन, वैश्विक वित्तीय वास्तुकला, यूएन सुधार, अफगानिस्तान में विकास और शंघाई सहयोग सहित महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारतीय, रूसी और चीनी नेताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान का मौका मिला। विशेष क्षेत्रों जैसे आपदा न्यूनीकरण और राहत, कृषि में सहयोग और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में सहयोग में त्रिपक्षीय सहयोग पिछले दो वर्षों से दिया जा रहा है। नवंबर, 2009 में सानया में आपदा न्यूनीकरण संबंधी दूसरी विशेषज्ञ स्तरीय बैठक आयोजित की गई। तीन देशों के बिजनेस चैम्बर्स के बीच 17-19 सितंबर, 2009 के दौरान चांगचुन, चीन में दूसरा त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया गया। फर्मास्युटिकल्स, अवसंरचना, आई टी एवं ऊर्जा परिचर्चा के विषय थे।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

प्रधानमंत्री ने 16 जून, 2009 को येकातरिनवर्ग, रूस में एससीओ शिखर (हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल) बैठक में भाग लिया। भारत एससीओ में प्रेक्षक राज्य है और यह पहला अवसर था जब भारत ने एससीओ में प्रधान मंत्री के स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री ने एससीओ देशों के नेताओं की चुनिंदा बैठकों में भाग लिया और व्यापक तौर पर प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया।

14 अक्तूबर, 2009 को बीजिंग में एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्मेंट काउंसिल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व श्री मुरली देवड़ा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने किया। मंत्री ने प्रारंभिक सत्र में वक्तव्य दिया।

व्यापार, संस्कृति, परिवहन और आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक के आमंत्रण प्राप्त हुए और इसमें संबंधित राजदूतावास के संबंधित मंत्रियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एससीओ के तत्वाधान में रूसी महसंघ ने अफगानिस्तान के बारे में मई 2009 में एक बैठक की जिसमें प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री सतीन्द्र लाम्बा ने भाग लिया।

■■

5 खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

खाड़ी

भारत खाड़ी देशों के साथ अपने ऐतिहासिक तथा पारंपरिक सौहार्दपूर्ण संबंध और सहयोग बनाए हुए है । तेल एवं गैस के बढ़ते आयात तथा व्यापार एवं निवेश के निरंतर बढ़ रहे अवसरों के साथ-साथ 2008 में संबंधों को मज़बूत बनाने और नए क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए इन देशों के साथ सहयोग के कारगर उपाए किए गए थे। इस वर्ष के दौरान हमारे संबंधों में इस क्षेत्र के महत्व को दर्शाने वाली कई द्विपक्षीय उच्चस्तरीय यात्राएं हुई।

खाड़ी क्षेत्र भारत का एक मुख्य व्यापारिक साझेदार हैं। 2006-07 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 47 बिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ तथा 2007-08 में यह बढ़कर 76 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया। खाड़ी क्षेत्र कुल मिला कर हमारी कच्चे तेल की कुल 70% आवश्यकता पूरी करता है तथा हमारी ऊर्जा सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाता है। लगभग 4.5 मिलियन भारतीय खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तथा काम करते हैं। वे हमारी अर्थव्यवस्था के प्राणाधार हैं और वार्षिक रूप से 30 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक धनराशि प्रेषित करते हैं।

बहरीन

भारत तथा बहरीन के बीच द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक तथा मैत्रीपूर्ण बने रहे। बहरीन के कुल 1.04 मिलियन निवासियों में से भारतीय राष्ट्रिकों की कुल संख्या 3,13,000 है। बहरीन के नेता अनेक क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को समझते हैं और भारत के साथ निकटतम रणनीतिक गठजोड करने को प्रयासरत हैं। बहरीन उच्च रणनीतिक महत्व के साथ खाड़ी सहयोग परिषद (जी सी सी) का सदस्य है।

2009 में द्विपक्षीय यात्राएं जारी रहीं तथा इनमें जुलाई 2009 में प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री का दौरा तथा दिसम्बर में मनामा-वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भागीदारी इत्यादि शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री डा0 शशि थरूर के बहरीन के हाल ही (4-5 दिसम्बर, 2009) के दौरे, जो उनका खाड़ी सहयोग परिषद् (जीसीसी) का प्रथम सरकारी दौरा था, से द्विपक्षीय संबंधों को विशेष प्रोत्साहन मिला। उन्होंने अन्यों के साथ-साथ, बहरीन के प्रधान मंत्री शेख खलीफा बिन सलाम अल-खलीफा, विदेश मंत्री शेख खालिद बिन अहमद अल-खलीफा, डॉ0 निजार अल-बहराना, उद्योग मंत्री मिस्टर हसन अब्दुला फखरू, श्रम मंत्री डा. मजीद मुहसिन अल-अलवी और समाज विकास मंत्री डा0 फातिमा मुहम्मद अल-बलू से मुलाकात की और उनके साथ पारस्परिक हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ठोस बातचीत की।

ईरान

उच्चस्तरीय यात्राएं

16-17 नवम्बर, 2009 को ईरानी विदेश मंत्री मनोचर मुत्ताकी ने भारत में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह जून 2009 में ईरानी राष्ट्रपति अहमदीनेज़ाद के पुर्नर्निर्वाचन के बाद ईरान की ओर से भारत की प्रथम उच्चस्तरीय यात्रा थी। इस दौरे के दौरान मुत्तकी ने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से मिलने गए और विदेश मंत्री से मुलाकात की। विचार-विमर्श के दौरान पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद, आई पी आई गैस पाइप लाइन परियोजना पर जोर देते हुए ऊर्जा सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार, अफगानिस्तान को चाबाहारी पत्तन एवं रेलवे लिंक, उत्तर-दक्षिणी गलियारे और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थितियां जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल किया गया।

श्री शेफोल्लाह जश्नसाज़, ईरान के तेल उप मंत्री और अध्यक्ष राष्ट्रीय इरानी तेल कम्पनी (एन आई ओसी) ने 30 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 2009 तक भारत में आए इरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों से वार्ताएं की। ईरानी उप-न्याय मंत्री श्री अब्दुल अली मिरकोई ने न्यायिक क्षेत्र में सहयोग पर विचार करने के लिए 7-10 दिसम्बर, 2010 तक भारत का दौरा किया।

द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य

भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापारः भारत और ईरान के बीच व्यापार में वृद्धि जारी रही। वर्ष 2007-08 में द्विपक्षीय व्यापार 12833.48 अमरीकी डालर (भारत से निर्यात 1943.91 मिलियन अमरीकी डालर तथा भारत में आयात 10889.57 मिलियन अमरीकी डालर, से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 13146.9 मिलियन अमरीकी डालर (भारत से निर्यात 2253.06 मिलियन अमरीकी डालर तथा भारत में आयात 10893.84 मिलियन अमरीकी डालर) तक बढ़ गया, इसमें 30.04% की वृद्धि दर्ज की गई (स्रोतः डी जी सी आई एस, कोलकता)

भारत से व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों की यात्राएंः दो देशों के बीच अनेक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों के आवागमन से आर्थिक

एवं वाणिज्यिक संबंधों में विकास जारी रहा। भारत से ईरान को गए व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों में दक्षिणी एशिया गैस एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लि0 (24-27 मई 2009), भारतीय चाय बोर्ड (24-27 मई 2009), मसाला बोर्ड (24-27 मई 2009), बुरहारी निर्यात बिज़नेस काउंसिलिंग सेन्टर (बीबीसीसी), मुम्बई (29 मई-जून, 2009) आयॉल एंडनेचूरल गैस का (ओएनजीसी) विदेश लिमिटेड, भारतीय तेल निगम लिमिटिड तथा भारतीय तेल लि0 (24-29 जुलाई, 2009), चमड़ा निर्यात परिषद (9-10 अगस्त, 2009), भारतीय उद्योग संघ (5-8 अक्टूबर, 2009), इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रोनिक विनिर्माण संघ (28 अक्तूबर-1 नवम्बर, 2009), स्वचालित घटक विनिर्माण संघ (11-14 नवम्बर, 2009), तथा दक्षिणी एशिया गैस एन्टरप्राइजिज लि0 (29 नवम्बर-1 दिसम्बर 2009) को शामिल किया गया था।

भारत में व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल की यात्राएं: ईरान से आए व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों में राष्ट्रीय ईरानी तेल कम्पनी (10-13 अगस्त, 2009), ईरान खान एवं उत्खन्न उद्योग विकास और नवीकरण संगठन (27 सितम्बर-3 अक्तूबर 2009), ईरान केन्द्रीय बैंक (3-5 नवम्बर, 2009), श्री शेफोल्लाह जश्नसाज़ उप तेल मंत्री एवं प्रबन्ध निदेशक राष्ट्रीय ईरानी तेल कम्पनी (एनआई ओ सी) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ईरानी तेल कम्पनी (30 नवम्बर-3 दिसम्बर 2009) को शामिल किया गया था। इसके अलावा, डा0 मोहम्मद, नहावन्दीअन, अध्यक्ष ईरान चैम्बर ऑफ कामर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड माइस (आईसीसीआईएम) की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दसवीं भारत-ईरान संयुक्त व्यवसाय परिषद् की बैठक में भाग लेने तथा 29वें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी के लिए 8-15 नवम्बर, 2009 तक नई दिल्ली का दौरा किया।

विविध

आई डी एस ए और आई पी आई एस के बीच छठा गोल मेज सम्मेलनः रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) और राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान के बीच छठा गोल मेज सम्मेलन 12-13 जुलाई, 2009 को तेहरान में आयोजित किया गया। इस गोल मेज में भाग लेने के लिए आई डी एस ए के महानिदेशक डा0 एन.एस. सिसौदिया की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आई डी एस ए प्रतिनिधिमंडल ने तेहरान का दौरा किया। गोल मेज सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक मंदी, ऊर्जा, परिवहन और क्षेत्र में सुरक्षा एवं द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

भारतीय-शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं खेल प्रतिनिधिमंडलों की ईरान यात्राएं: शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्रों से भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने ईरान की यात्राएं भी की। इन यात्राओं में भारतीय खेल प्राधिकरण टीम (5-8 अक्तूबर, 2009), भारतीय बॉलीबाल टीम (23-28 मई, 2009), पश्चिम बंगाल से एक थियेटर ग्रुप (30 जुलाई-7 अगस्त, 2009) खगोल विज्ञान और खगोल-भौतिकी पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पीयाड के लिए एक भारतीय टीम (18-26 अक्तूबर, 2009) को शामिल किया गया।

भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण संगठन दल ने ईरान की यात्रा की: भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण संगठन दल के तीन पोतों नामतः आई एन एस तीर, आई एन एस कृष्णा तथा आई सी जी एस (एकीकृत तटरक्षक प्रणालियां) वीरा ने सद्भावना यात्रा के एक भाग के रूप में 4-7 अप्रैल, 2009 तक बन्दार अब्बास की यात्रा की। ये पोत सैन्य प्रशिक्षण पोत थे जो भारतीय नौसेना के कनिष्ठ अधिकारियों को और मित्र विदेशी देशों के अधिकारियों को जहाज पर प्रशिक्षण देते हैं। इस यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के सैन्य अधिकारियों ने ईरानी नौसेना के अपने प्रतिपक्षियों से संपर्क किया और खेलों तथा अन्य साहसिक गतिविधियों में भाग लिया।

विदेश सचिव श्रीमती निरूपमा राव ने डा. मोहम्मद अली फथौलही, एशिया और ओशिनिया के उप विदेश मंत्री के निमंत्रण पर 2-3 फरवरी, 2010 तक विदेश कार्यालय परामर्शों (एफ ओ सी) के लिए ईरान का दौरा किया। एशिया और ओशेनिया के तत्कालिक ईरानी उप विदेश मंत्री मोहम्मद मेहदी अखाउन्दजादेह ने 17 दिसम्बर, 2008 को नई दिल्ली का दौरा किया। एफ ओ सी के चालू दौर में सामान्य महत्व के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों को शामिल किए जाने की आशा है।

कुवैत

भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक व्यापार-संबंध, सांस्कृतिक साम्यता तथा भारतीय प्रवासियों की बडी संख्या में उपस्थिति इन दीर्घकाल से चले आ रहे संबंधों को बनाए रखे व संपोषित किए हुए है। भारत एक प्राकृतिक व्यवसायी-हिस्सेदार और उच्च ज्ञान के लिए गन्तव्य स्थल रहा है।

कुवैत के युवराज शेख नवाब अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह के निमंत्रण पर अप्रैल 2009 में भारत के उप-राष्ट्रपति श्री एम हामिद अन्सारी की कुवैत यात्रा मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रमाण चिन्ह के तौर पर दर्शायी गई। दौरे के दौरान उन्होंने शेख-सबाह अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह, कुवैत राज्य के 'अमीर ' युवराज से मुलाकात की। वर्तमान प्रधान मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री/रक्षा मंत्री शेख जबेर मुबारक अल-हमद-अल-सब्बाह, उप प्रधान मंत्री/ विदेश मंत्री शेख (डा.) मोहम्मद सबाह अल-सलेम-अल-सब्बाह, तेल मंत्री श्री शेख- अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद-अल-सबाह, वित्त मंत्री श्री मुस्तफा जस्सीम अल शमाली ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान शिक्षा आदान-प्रदान कार्यक्रम, 2009-2011, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग अनुबंध तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2009-2011 नाम के तीन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।

3 फरवरा-5 फरवरी, 2010 तक विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा कुवैत यात्रा करेंगे।

विशेष कुवैत कक्ष

वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग (यू एन सी सी) ने 8615 ऐसे भारतीय दावेदारों की सूची भिजवाई, जिनकी कोई खोज-खबर नहीं थी और जिनकी दावेदारी राशि यू एन सी सी द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि के भीतर अवितरित राशि के रूप में यू एन सी सी को लौटा दी गई थी। यू एन सी सी द्वारा सभी देशों को अपने उन राष्ट्रिकों को जिन्हें (जब पहले राशि भिजवाई थी) पहले भुगतान नहीं किया गया था, उन्हें यह अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। एक बार इस कार्रवाई के पूरा होने पर अवितरित राशि यू एन सी सी को लौटाई जानी थी तथा यू एन सी सी में यह अव्यपगत हो जाएगी, जिससे कि राशि को फिर से प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं होगा। भारतीय दावेदारों का पता लगाने का कार्य अक्तूबर, 2005 में शुरू हो गया। 8615 दावेदारों की सूची प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की गई थी और सह सुलभ कराने के लिए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर रखी गई थी। इसमें राज्य सरकारों की सहायता भी ली गई थी। भारतीय दावेदारों का पता लगाने का कार्य अक्तूबर 2006 में समाप्त हो गया क्योंकि यू एन सी सी ने 30 अक्तूबर, 2006 के बाद पता लगाए गए दावेदारों की किसी भी सूची को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। यू एन सी सी ने जनवरी 2007 से जुलाई, 2007 के मध्य राशि भेज दी थी, जो कि छः महीनों की अवधि के भीतर वितरित की जानी थी, जिसे बाद में घटाकर चार महीने कर दिया गया तथा अवितरित राशि यू एन सी सी द्वारा भारत को राशि अंतरित किए जाने के 6 माह के भीतर यू एन सी सी को वापिस की जानी थी। अवितरित राशि की अन्तिम किश्त जनवरी 2008 में वापिस कर दी गई थी। यू एन सी सी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे वापिस की गई अवितरित राशि को भेजने के लिए सरकार के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए दावेदार अथवा उनकी सरकार कोई भी औचित्य व तर्क प्रस्तुत करें। यू एन सी सी ने यह भी सलाह दी है कि सरकारें उन्हें कोई भी प्रतिवेदन भेजने बंद कर दें।

इस प्रभाग ने पहली अप्रैल-दिसम्बर 2009 तक संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति दावेदारों से पूछताछ संबंधी 11 आरटीआई मामलों के जवाब दिये हैं। इसके अलावा, तीन न्यायिक मामले लम्बित हैं। भारत सरकार की स्थिति यह है कि क्षतिपूर्ति यू एन सी सी द्वारा दी जा रही थी तथा 1990-91 खाड़ी युद्ध के कुवैत से वापिस लौटे व्यक्तियों को जिन्हें यू एन सी सी क्षतिपूर्ति दे रहा था और चाहे किसी भी कारणों से उन्हें यह क्षतिपूर्ति न मिली हो ऐसे मामलों में भारत सरकार इस क्षतिपूर्ति को देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ओमान

भारत के ओमान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध वर्ष 2009 में और दृढ़ हो गए जब अप्रैल, 2009 में जब गत वर्ष प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने ओमान की यात्रा की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा0 मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने अप्रैल 2009 को हुई दूसरे भारत-ओमान संयुक्त कार्यदल की बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की और ओमानी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता आर्थिक योजना के सुलतान सलाहकार मोहम्मद बिन जुबेर ने की। इस कार्यदल ने उन क्षेत्रों को अभिज्ञात किया जिनमें दोनों देश त्वरित प्रगति कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत-ओमान संयुक्त निवेश कोश में वृद्धि की गई जिसे 100 मिलियन अमरीकी डालर की मूल पूँजी से बढाकर 1.5 बिलियन किया गया। इसे आधारभूत संरचना में संयुक्त निवेश हेतु उपयोग किया जाना है। वर्ष 2008 के दौरान (तेल एवं तेल-इत्तर) द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.0 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया।

ओमान के तेल एवं गैस मंत्री डा. मोहम्मद हैमद अल-रूमही ने मई 2009 में भारत की यात्रा की, ओमान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री मकबूल अली सुल्तान की अध्यक्षता में एक नौ-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार और वाणिज्य में गुजरात और ओमान के मध्य भागीदारी बढाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए सितम्बर 2009 में गुजरात का दौरा किया। इस अवधि में तकनीकी और उच्चतर शिक्षा, रक्षा सहयोग, भारतीय नौसेना जल पोतों की ओमान यात्रा तथा अक्तूबर और नवम्बर, 2009 में द्विपक्षीय वायु गतिविधियां देखी गई। ओमान सुल्तान ने अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के एंटी-पाएरेसी प्रचालन को समर्थन जारी रखा।

डा. फारूख अब्दुल्ला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 18-22 जनवरी, 2010 तक ओमान की यात्रा की। श्री मुरली देवड़ा, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने 29-30 जनवरी, 2010 को ओमान का दौरा किया। डा0 शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री 5-7 फरवरी, 2010 तक ओमान की यात्रा करेंगे।

कतर

भारत के कतर से जनता से जनता के संबंधों व वाणिज्यिक गठबन्धन सहित मैत्रीपूर्ण संबंधों का लम्बा इतिहास है। इन संवर्द्धित संबंधों के लिए 450,000 का बृहद भारतीय समुदाय प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। नवम्बर 2008 में डा. मनमोहन सिंह की यात्रा ने इन द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से बढावा देने के लिए सामंजस्य स्थापित किया, जब यह भी सहमति हुए थी कि यात्राओं की प्रगति सुनिश्चित करने और आगामी कार्रवाई करने के लिए एक उच्चस्तरीय अनुवीक्षण प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। इसकी प्रथम बैठक फरवरी 2009 में नई दिल्ली में हुई और दूसरी बैठक नवम्बर, 2009 में दोहा में हुई। नवम्बर, 2009 में दोहा में हुई बैठक के दौरान 5 बिलियन अमरीकी डालर तक की धनराशि के भारत में कतर के निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत और कतर के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

श्री मुरली देवड़ा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने 16 दिसम्बर, 2009 को दोहा का संक्षिप्त दौरा किया। भारतीय

पक्ष ने कतर पक्ष के सामने हमारी द्रव प्राकृतिक गैस (एल एन जी) की तत्काल और मध्य कालीन आवश्यकताओं को रखा। इस दौरे में दोनों देशों के संबद्ध मंत्रियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क के महत्व को भी आंका गया।

सऊ दी अरब

भारत-सऊदी संबंध ऐतिहासिक हैं और जनवरी 2006 में शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की भारत की यात्रा से और भी मज़बूत हो गए हैं। द्विपक्षीय संबंध आर्थिक शक्तियों से भी प्रोत्साहित हुए जिनमें ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिकतम मुखर-तत्व रहे। इन संबंधों में लगभग 1.78 मिलियन निवासी भारतीय समुदाय की उपस्थिति से प्रगाढ़ता आई है। प्रगाढ़ द्विपक्षीय आर्थिक संबंध द्विपक्षीय व्यवसाय की सतत वृद्धि में परिलक्षित हुए हैं, जो वर्ष के दौरान अनेक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल की यात्राओं से 23 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। बादशाही में 560 परियोजनाओं में भारतीय निवेश 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक पहुंच गया है।

27-30 अक्तूबर, 2009 तक रियाद में भारत-सऊदी संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक हुई और इसमें द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण सप्तक पर विचार-विमर्श किया गया। भारतीय पक्ष की सह-अध्यक्षता श्री प्रणव मुखर्जी, वित्त मंत्री द्वारा की गई। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री ने 31 अक्तूबर, 2009 को शाह अब्दुल बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की।

वर्ष 2009 की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए रियाद में 'इंडिया पर्यटन रोड़ शो' में पर्यटन राज्य मंत्री सुल्तान अहमद की भागीदारी शामिल है। सऊदी पक्ष से यात्राओं में शाह अब्दुल्ला के विशेष दूत के रूप में अगस्त में सऊदी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अब्दुल्ला अहमद जैनल अलिरेजा की यात्रा शामिल थी। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा विदेश मंत्री, वित्त मंत्री एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रियों से भी बैठकें की।

भारतीय सैन्य पोतो, आई एन एस दिल्ली और आई एन एस आदित्य ने मई, 2009 में जद्दा में तीन दिन की सद्भावना यात्रा की और शाही सऊदी नौसेना के साथ लाल समुद्र में सैन्य गतिविधियों में भाग लिया।

2010 के फरवरी अंत/मार्च प्रारंभ में प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। दौरे की रूपरेखा विचाराधीन है।

संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई)

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य संबंध पारंपरिक तौर पर घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं। भारत यू ए ई के लिए एक प्राकृतिक व्यावसायिक हिस्सेदार और उच्चतर शिक्षा के लिए गंतव्य स्थान है। बृहद प्रवासी भारतीय समुदाय यू ए ई में रहता है और विभिन्न आर्थिक उत्पादक गतिविधियों में लगा हुआ है। यू ए ई अधिकारियों द्वारा किए गए अध्ययनों के अद्यतन आंकडों के अनुसार यू ए ई में भारतीय समुदाय का आकार 1.7 मिलियन आंका गया है। 2008-09 में यू ए ई भारत का बृहदतम गैर-तेल वाणिज्य व्यावसायिक हिस्सेदार बन गया है, जो खाडी क्षेत्र के अरब राज्यों की सहयोग परिषद् (सी सी ए एस जी जिसे खाडी सहयोग परिषद् जी सी सी के नाम से भी जाना जाता है), के साथ भारत के कुल व्यापार का लगभग आधा के बराबर होता है। भारत यू ए ई निर्यातों का बृहदतम निर्यात गंतव्य है। 44 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक द्विपक्षीय व्यापार के साथ यू ए ई भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक हिस्सेदार के रूप में उभरा है। इस अवधि के दौरान भारत और यू ए ई ने 'सुरक्षा सहयोग करार ' पर विचार-विमर्श किया, उसे अंतिम रूप दिया और लागू किया है।

इस अवधि के दौरान अनेक यात्राएं हुईं जिनमें अक्तूबर में विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर का यू ए ई दौरा शामिल है। उन्होंने दुबई के शहजादे (युवराज), मंत्रीमंडलीय कार्य मंत्री से अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक सहयोग और निवेश बढाने हेतु वार्ता की। भारतीय सैन्य जलपोतों तीर, कृष्णा और आई सी जी एस वीरा ने मार्च 2009 में आबू धाबी की यात्रा की। यू ए ई पक्ष से विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान ने जून में भारत की यात्रा की और उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की।

18-22 जनवरी, 2010 को डा. फारूख अब्दुल्ला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यू ए ई की यात्रा करेंगे। 28 फरवरी-2 मार्च, 2010 के दौरान बौद्धिक संपदा अधिनियम कापी राइट विचार-गोष्ठी तथा आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के लिए डा0 शशि थरूर, विदेश राज्य मंत्री की आबू दाबी (यू ए ई) की यात्रा करने की संभावना है। शेख लुबना अल कासिमी विदेश व्यापार मंत्री यू ए ई 7-12 फरवरी, 2010 तक भारत की यात्रा करेंगे।

यमन

विदेश राज्य मंत्री डा- शशि थरूर ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर परिधि संगठन (आई ओ आर - ए आर सी) में सम्मेलन की अगुवाई करने के लिए जून 2009 में साना की यात्रा की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने यमन के राष्ट्रपति से मुलाकात की तथा हमारे राष्ट्रपति की ओर से यमन के राष्ट्रपति को एक पत्र दिया। राज्य मंत्री ने यमन के विदेश मंत्री और तेल एवं खनिज मंत्री के साथ भी बैठकें कीं।

जनवरी 2009 में एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (ए एस एस ओ सी एच ए एम) के निमंत्रण पर साना के चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के एक 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और अपने समकक्षों के साथ बैठकें की। अब भारतीय कम्पनियां उन्हें गत वर्ष आवंटित किए गए तेल ब्लाकों की खोज प्रक्रिया में लग गई हैं।

इराक

भारत तथा इराक के बीच सहनशील, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध हैं, जो 8 अप्रैल, 2003 को भारत की संसद

में पारित संकल्प द्वारा निर्देशित हैं, जिनके द्वारा भारत इराकी जनता की प्रभुसत्ता को शीघ्र बहाल करने तथा इराकी जनता के लिए उनके द्वारा मुक्त रूप से अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने तथा अपने राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के अधिकार के पक्ष में है। क्षेत्र के स्थायित्व के लिए भारत सदा इराक की शांति और स्थायित्व के पक्ष में है तथा इराक की संपूर्ण प्रभुसत्ता और इराकी जनता के लिए राजनीतिक भविष्य को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने तथा उनके प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण रखने के उनके अधिकार के पक्ष में है। भारत ने इराक की राजनीतिक प्रक्रिया, संविधान के विकास, निर्वाचन पद्धति, जनगणना तथा मतदाता पंजीकरण के लिए अपनी सहायता पेश की थी।

नकद राशि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अपील के उत्तर में इराकी जनता के सहयोग के लिए भारत ने 20 मिलियन अमरीकी डालर का वचन दिया था। इराक में निवेशों, पुर्ननिर्माण तथा विकास के लिए इराक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण निधि सुविधा (आई आर एफ एफ आई) में भारत ने कुल 10 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। इस समय भारत इराक सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) के अंतर्गत प्रतिवर्ष इराक को कम से कम 100 स्लाट्स तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना (सी ई पी) और सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (सीजी एस एस) के तहत भारत में उच्चतर अध्ययन के लिए अपने छात्रों को नामित करने के लिए इराक को 50 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आई सी सी आर) छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है।

भारतीय तेल निगम लि. (आई ओ सी) अनुप्रवाह तेल क्षेत्र संबंधी विभिन्न विषयों पर इराकी तेल कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। भारत इराक के सरकारी कर्मचारियों को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के अंर्तगत इराक को प्रतिवर्ष कम से कम 100 स्लॉट प्रदान करता रहा है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा प्रायोजित 'सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना (सीईपी) ' तथा 'सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना (जी सी एस एस)' के अंर्तगत उच्चतर अध्ययन के लिए अपने विद्यार्थियों को नामित करने के लिए भारत इराक को प्रतिवर्ष 50 स्लॉट ऑफर करता रहा है।

भारत-खाडी सहयोग परिषद् (जी सी सी)

भारत-खाड़ी सहयोग परिषद् संबंध मैत्रीपूर्ण रहे और 2009 में और अधिक मजबूत हो गए। भारत जी सी सी वार्ता का पांचवां दौर सितम्बर, 2009 को न्यूयार्क में आयोजित हुआ, जिसमें परामर्शी पद्धति के संस्थानिकरण को और भी मजबूत किया गया। विदेश मंत्री श्री एस एम कृष्णा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। उन्होंने पारस्परिक सम्बद्धता के मुद्दों तथा भारत-जी सी सी संबंधों को प्रगाढ़ करने और बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

वर्ष के दौरान भारत-खाड़ी सहयोग परिषद् (जी सी सी) मुक्त व्यापार करार संधि वार्ता पद्धति प्रचलित थी और इन संधि वार्ताओं को तेज करने के लिए उपायों पर दोनों पक्षों ने विचार-विमर्श किया। भारत जी सी सी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न मुद्दों का निरीक्षण करने पर सहमत हो गया है। दोनों पक्ष फरवरी, 2010 में चौथा औद्योगिकी सम्मेलन कराने पर सहमत हो गए हैं।

हज

दिसम्बर 2009 में लगभग 16,5000 भारतीय तीर्थयात्रियों ने हज किया। भारतीय हज समिति के माध्यम से 120,121 तीथयात्रियों ने तथा शेष ने निजी पर्यटन प्रचालकों के माध्यम से सऊदी अरब की हज यात्रा की। श्री सैफूद्दीन सौज ने सऊदी अरब को जाने वाले भारतीय सद्भावना प्रतिनिधिमंडल की अगुआई की।

इंडो-अरब निवेश सभा

8-9 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में दूसरी इंडो-अरब निवेश सभा हो रही है, जिसमें लगभग 200 सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा अरब देशों से कुछ मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की आशा है। इस सभा का उद्देश्य भारत में भारत संवर्द्धन कथन के कार्यढांचे में निवेश संभावनाओं को मुखरित करना तथा विभिन्न परियोजनाओं में भागीदारी लागू करना है।

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

ऊर्जा, व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सहयोग को शामिल कर पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में सभी देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं।

अल्जीरिया

अक्तूबर 2009 में पावर ट्रांसमिशन लाइनों में तीन भारतीय कंपनियों को नई परियोजनाएं प्रदान की गई। 15 भारतीय कंपनियों ने भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन के तत्वाधान में 30 मई से 4 जून, 2009 तक हुए 42वें अल्जीरियाई अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया। पश्चिमी बेड़े के पोतों के समुद्रपार नियोजन के एक हिस्से के रूप में 17-20 मई, 2009 के दौरान आई एन एस ब्यास, अल्जीरियाई पत्तन पर ठहरा। अल्जीयर्स तथा अल्जीरिया के अनेक अन्य शहरों में मार्च, 2009 में आई सी सी आर की चित्रकला प्रदर्शनी 'नारी द्वारा नारी' आयोजित की गई। भारतीय लघुचित्र कलाकार श्री शाकिर अली ने अल्जीरिया सरकार के निमंत्रण पर 14 अक्तूबर, 2009 को अल्जीयर्स में हुए अंतर्राष्ट्रीय चित्रावली एवं लघु उत्सव में भाग लिया। भारतीय लोक नृत्य की एक 12 सदस्सीय मंडली 'मीरा कला मन्दिर' ने 18-20 दिसम्बर, 2009 को तिमिमाउन, अल्जीयर्स में हुए चौथे मरूभूमि लोकोत्सव में भाग लिया।

जिबुती

आई एन एस बेतवा, आई एन एस ब्यास, आई एन एस गोदावरी, आई एन एस मुम्बई तथा आई एन एस त्रिशूल ने मार्च से

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 21 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की अगुवाई वाले हज सद्भावना प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधान मंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चह्वाण भी उपस्थित।

अक्तूबर 2009 के दौरान जिबुती पत्तन पर सोमालिया के तट पर जलदस्युता विरोधी गश्त लगाई।

मिस्र

14-16 जुलाई, 2009 को 15वें गुटनिरपेक्ष अंदोलन (एन ए एम) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शर्म-अल-शेख के दौरे के दौरान प्रधान मंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हुसने मुबारक से मुलाकात की। शिखर सम्मेलन से पहले 13-14 जुलाई को एन ए एम मंत्रालयी बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने भाग लिया। विदेश मंत्री ने मिस्र के विदेश मंत्री श्री अहमद अब्दुल गेयट से एक द्विपक्षीय बैठक भी की। शर्म-अल- शेख में 29-30 जून, 2009 को अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (आई आर ई एन ए) के तैयारी आयोग के दूसरे सत्र में भाग लेने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डा. फारूख अब्दुल्ला ने मिस्र की यात्रा की इस दौरे के दौरान उन्होंने मिस्र के बिजली एवं ऊर्जा मंत्री हसन अहमद यूनिस से सौर एवं पवन ऊर्जा में सहयोग पर विचार-विमर्श किया। डा. अब्दुला ने मिस्र के प्रमुख शेख और प्रमुख मुफ्ती से भी मुलाकात की।

मिस्र के व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री रचिद मोहम्मद रचिद ने विश्व व्यापार संगठन बातचीत के दोहा दौर पर अनौपचारिक मंत्रालयी बैठक में उपस्थित होने के लिए 2-4 सितम्बर, 2009 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री डा0 आनन्द शर्मा से मुलाकात की और द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में सुधार के उपायों पर विचार-विमर्श किया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने एक 'विकास आयामों का समेकन' पर अनौपचारिक अफ्रीकन डब्ल्यूटीओ व्यापार मंत्रालयी गहन चर्चा सत्र में भाग लेने के लिए 28-30 अक्तूबर, 2009 तक मिस्र की यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री डा- अहमद नाजिर तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री रचिद मोहम्मद रचिद से द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरे के दौरान मिस्र के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय तथा भारत के लघु, सूक्ष्य एवं मध्यम उधम (एम एस एम ई) मंत्रालय के मध्य सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्ययोजना (जे ए पी) पर हस्ताक्षर किए गए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की कैरो यात्रा के साथ शामिल होने के लिए अक्तूबर, 2009 में मिस्र के विभिन्न व्यापार संघों से विचार-विमर्श हेतु 27-31 अक्तूबर तक भारतीय व्यापार परिसंघ (सी आई आई) व्यवसायी प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र का दौरा किया। मिस्र के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा इस अवसर पर एक संयुक्त व्यवसाय मंच आयोजित किया गया। चमड़ा स्रोत मिशन पर 28-31 अक्तूबर, 2009 तक चमड़ा निर्यात् परिषद् ने भी मिस्र का दौरा किया।

मिस्र के बिजली एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. हसन यूनिस ने 16-19 नवम्बर, 2009 तक भारत की यात्रा की और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डा0 फारूख अब्दुल्ला और विद्युत राज्यमंत्री श्री भरत सिंह सोलंकी से द्विपक्षीय बैठकें की। डॉ. यूनिस ने विद्युत क्षेत्र में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ व्यवसायी बैठक, व्यावसायियों/निवेशेकों के साथ एक अलग बैठक की तथा देश में सौर एवं पवन ऊर्जा विनिर्माणी इकाइयों की यात्रा की।

कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विचार-विमर्श करने के लिए दो राज्य सरकार प्रतिनिधिमंडलों ने जिनमें एक ने (18-19 नवम्बर, 2009) पंजाब मुख्य मंत्री के नेतृत्व में तथा दूसरे ने (25-27 सितम्बर, 2009) केरल उद्योग मंत्री के नेतृत्व में मिस्र का दौरा किया। दो मिस्र कर्मचारियों ने सितम्बर 2009 में हैदराबाद फॉरमैक्सिल द्वारा आयोजित इंडो-अफ्रीका औषधीय व्यवसाय बैठक में भाग लिया। सितम्बर 2009 में कॉपैक्सिल क्रेता-विक्रेता बैठक में भी मिस्र के दो भागीदार थे।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान ने 10-13 जनवरी, 2010 तक मिस्र का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने प्रशासनिक विकास राज्य मंत्री डा. अहमद दरविश और मिस्र के उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री डा. हैनी महफूज हेलल से मुलाकात की। 15-18 जनवरी, 2010 को संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री श्री पवन कुमार बंसल के नेतृत्व में सांसदों के एक सद्भावना प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र का दौरा किया। दौरे में प्रतिनिधिमंडल ने लोक सभा के स्पीकर डा. अहमद फती सोरूर तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. मौफिद मोहम्मद सेहाब से बैठकें की।

10-20 नवम्बर, 2009 तक कैरो अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव (सी आई एफ एफ), 2009 में भारत को माननीय अतिथि का निमंत्रण मिला। इस फिल्म उत्सव में निदेशक अदूर गोपाल कृष्णन (अंतर्राष्ट्रीय अभिनिर्माण अध्यक्ष) सहित अनेक प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों ने भाग लिया। सी आई एफ एफ 2009 में 23 भारतीय फिल्में दिखाई गईं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा प्रायोजित सुश्री इशिरा पारिख के नेतृत्व में एक कलादल 'अनार्त ' ने उत्सव में शुरूआती सत्र में अपना प्रस्तुतीकरण दिया। 5-12 सितम्बर, 2009, को आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित पंथी ग्रुप और डैर्स्ट सिम्फॉनी ग्रुप ने मिस्र का दौरा किया।

एयरचीफ मार्शल एफ एच मेजर वायु सेना प्रमुख और लेफ्नेंनट जनरल डी एस बर्तवाल, महानिदेशक मिलट्री सर्तकता ने क्रमशः 26-29 अप्रैल, 2009 और 15-18 मई, 2009 तक मिस्र का दौरा किया।

इजराइल

भारत इजराइल मंच की दूसरी बैठक 8-10 सितम्बर, 2009 को तेल अवीव में हुई। इस मंच में एक 19 सदस्सीय सी आई आई प्रतिनिधिमंडल तथा 34 इजराइली व्यवसायियों, शिक्षाविदों तथा अधिकारियों ने भाग लिया। इजराइल बैंक के गर्वनर तथा आधारभूत संरचना और वित्त के इजराइली मंत्रियों ने भी भागीदारों को संबोधित किया। इस मंच ने आधारभूत संरचना, भूसंपदा, निवेश और वित्तीय संसाधनों, प्रौद्योगिकी, उद्योग तथा कृषि, नवीकरणीय

ऊर्जा और जल प्रौद्योगिकी में भारत और इजराइल के मध्य सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।

जनरल दीपक कपूर अध्यक्ष, स्टाफ समिति के प्रमुख और थलसेना स्टाफ के प्रमुख ने 8-11 नवम्बर, 2009 को इजराइल का दौरा किया। 17-19 नवम्बर, 2009 तक तेल अवीव में जल प्रौद्योगिकियों पर हुए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी 'डब्ल्यू ए टी ई सी 2009 ' के भारतीय भागीदारों में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्य मंत्री शामिल थे। रक्षा स्टाफ के प्रमुख लेफ्टीलेंट जनरल गाबी अशकेनाजी ने 8-10 दिसम्बर, 2009 तक भारत का दौरा किया। इजराइली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष डा. अजी अर्द ने 4 जनवरी, 2010 को भारत का दौरा किया। इजराइली उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्री श्री बंजामिन बेन एलीजर ने 8-14 जनवरी, 2010 तक भारत का दौरा किया और उन्होंने विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री आनन्द शर्मा, कृषि खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता कार्य मंत्री श्री शरद पवार और योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया से मुलाकात की। इजराइली नौसेना स्टाफ के प्रमुख वाइस एडमिरल एलिजर मरूम ने 18-22 जनवरी, 2010 तक भारत का दौरा किया।

आई सी सी आर प्रायोजित एक कार्नेटिक वोकल ग्रुप ने 15-20 नवम्बर, 2009 तक इजराइल की यात्रा की और वहां अवध सांस्कृतिक समारोह, 2009 में भाग लिया। श्रीमती राजेश्वरी बेहरा के नेतृत्व में तथा आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित एक ओडिसी नृत्य दल ने 24-28 नवम्बर 2009, तक इजराइल में अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कीं।

जॉर्डन

इंजीनियरिंग निर्यात् संवर्द्धन परिषद् के तत्वाधान में 14 भारतीय कंपनियों के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 4-07 मई 2009 तक हुई छठी पुर्न-निर्मित इराक प्रदर्शनी में भाग लिया। ए फेडेरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री (फिक्की) के एक प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2009 में जॉर्डन की यात्रा की और जार्डन के व्यापार चैम्बर्स के साथ एक-एक करके बैठकें कीं।

4 अक्तूबर 2009 को अम्मान में जॉर्डन फास्फेट माइन्स कंपनी (जे पी एम सी) और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआप्रेटिव लि. (इफ्को) में एक संयुक्त उद्यम परियोजना का उद्घाटन किया गया।

आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित एक सितार ग्रुप और एक भारतीय मंडली ने जुलाई 2009 में जॉर्डन उत्सव में भाग लिया। आई सी सी आर द्वारा आयोजित ओडिसी नृत्यांगना श्रीमती राजेश्वरी ने 30 नवम्बर, 2009 को अम्मान में अपना प्रस्तुतिकरण दिया।

लेबनान

भारत ने 10 नवम्बर, 2009 को लेबनान में गठित नई सरकार के गठन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा द्वारा क्रमशः लेबनान के प्रधानमंत्री श्री साद रफीक हरीरी और विदेश कार्य मंत्री एवं लेबनान के प्रवासी मामलों के मंत्री श्री अली अल चामी को बधाई संदेश भिजवाए गए। अप्रैल 2009 में कृषि और प्रासंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात् प्राधिकरण (ए पी डा) द्वारा कृषि मंत्रालय से एक चार सदस्सीय लेबनान प्रतिधिनिमंडल की मेजबानी की गई।

लीबिया

1 सितम्बर, 2009 को त्रिपोली, लीबिया में हुए ग्रेट अल-फतेह रेवोल्यूशन की 40वीं वर्षगांठ मनाने पर श्री के. रहमन खान, उपाध्यक्ष राज्य सभा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 2-12 अप्रैल, 2009 तक त्रिपोली में हुए वार्षिक त्रिपोली अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया। 7-10 जून, 2009 तक आई एन एस आदित्य, त्रिपोली पत्तन लीबिया पर ठहरा।

12-14 नवम्बर, 2009 को त्रिपोली में हुए एफ्रो-एशियन ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) की कार्यकारिणी समिति के 59वें सत्र की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्रालय की सचिव डा. रीता शर्मा द्वारा की गई। आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित एक बारह-सदस्यीय कत्थक नृत्यमंडली 'अनार्त' ने 16-22 नवम्बर, 2009 तक त्रिपोली, सिर्टे और बेंगाजी में प्रस्तुतीकरण किया।

मोरक्को

22-27 अप्रैल, 2009 तक भारतीय कंपनियों ने मेकंस में हुए अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले में भाग लिया। मई 2009 में संगीतकारों और कुचीपुड़ी नर्तकों के एक दल ने धार्मिक संगीत के फेज अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

इंजीनियरींग निर्यात् संवर्द्धन परिषद् (ई ई पी सी) ने 30 सितम्बर-3 अक्तूबर 2009 तक कासाबलांका में हुई सब-कांट्रेक्टिंग एंड पार्टनरशिप पर (एस आई एस टी ई पी) इंजीनियरी प्रदर्शनी की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया।

टायर और ट्यूबों, संगमरमर और ग्रेनाइट, रसायन और स्टेशनी मदों के निर्यात् हेतु एक सी ए पी ई एक्स आई एल (भारत से रसायन और सह-उत्पादों के निर्यात् संर्वद्धन हेतु अलाभकारी संगठन) प्रतिनिधिमंडल ने 6-08 नवम्बर, 2009 को कासाबलांका में हुई एक क्रेता-विक्रेता बैठक में भाग लिया।

फिलीस्तीन

भारत ने फिलीस्तीन जनता को उनकी अपनी जन्म भूमि के लिए उनके वैध अधिकारों हेतु अपना निश्चित समर्थन जारी रखा। नई दिल्ली में फिलीस्तीनी राज दूतावास की चांसरी एवं आवासीय परिसर का निर्माण, जो भारत सरकार और भारतीयों की ओर से एक उपहार है, लगभग पूरा होने को है। निकट पूर्व में फिलीस्तीनी विस्थापितों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत अभिकरण (यू एन आर डब्ल्यू ए) को भारत का वार्षिक अंशदान 20,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया।

सोमालिया

इस अवधि के दौरान सोमाली तटों पर जलदस्युता ने भारतीय ध्वज वाहक जहाजों तथा भारतीय व्यापारी नाविको को अक्रांत करना जारी रखा। अदीस अबाबा में 27-30 जनवरी, 2010 तक हुए अफ्रीकी संघ सम्मेलन के अंत में डा0 शशि थरूर, विदेश राज्य मंत्री ने सोमालिया के विदेश मंत्री से बातचीत की।

सूडान

सूडान के कृषि एवं वन प्रान्त मंत्री डा. अब्दुल हलीम इस्माइल अल-मुत्तफी ने 13-17 जुलाई, 2009 तक भारत का दौरा किया। वे कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामलों तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद पवार से मिले। अगस्त, 2009 में डा. ओसामा मोहम्मद, सूडान के राष्ट्रीय समन्वयक और इंजी. महमूद दोलिव मोहम्मद अलामिन ने टेलीकॉम्यूनिकेशंस कंसलटैंट्स इंडिया लि0 (टी सी आई एल) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पैन अफरीकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्ट पर एक द्विदिवसीय वर्कशाप में भाग लिया। अक्तूबर 2009 में भारत की चमड़ा निर्यात् परिषद् से एक चमड़ा स्रोत प्रतिनिधिमंडल ने सूडान का दौरा किया।

श्री संजय किरलोस्कर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, किरलोस्कर ब्रादर्स लि. के नेतृत्व में भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल के 17 सदस्सीय परिसंघ ने व्यवसाय एवं परियोजना भागीदारी संभावनाओं का पता लगाने के लिए, नवम्बर 2009 में सूडान का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के वरिष्ठ सहायक और कृषि तथा वन, पर्यटन एवं वन्यजीव, सिंचाई एवं जलसंसाधनों, स्वास्थ्य, विदेश व्यापार, ऊर्जा एवं खनन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विदेश मामले, वित्त एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मंत्रियों से मुलाकात की। सी आई आई ने उद्योग संघ के सूडानी चैम्बर्स के साथ सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ऊर्जा एवं खनन राज्य मंत्री सुश्री एंजलिना जैनी टैनी ने 7-8 दिसम्बर, 2009 तक नई दिल्ली में दूसरे भारत-अफ्रीका हाइड्रोकार्बन्स सम्मेलन में सूडानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने 24-25 जनवरी, 2010 के दौरान सूडान का दौरा किया। टाटा मोटर्स, मुम्बई के निमंत्रण पर खारतूम, सूडान के गर्वनर श्री अबदेल रहमान अल खिदिर ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 16-25 जनवरी, 2010 तक दिल्ली और मुम्बई की यात्रा की। एक तीन सदस्सीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सूडान गणराज्य के कृषि एवं वन मंत्री डॉ0 अब्दुल हलीम इस्माइल अल मुत्तफी ने 11-15 जनवरी, 2010 तक भारत की यात्रा की।

सीरिया

श्री सुधीर भार्गव, संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग के नेतृत्व में एक आठ सदस्सीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-18 मई, 2009 तक सीरिया की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान सीरियाई फॉसफेट्स क्षेत्र के विकास हेतु व्यवहार्यता चयन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सीरियाई फॉसफेट्स क्षेत्र के विकास हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में आंकड़ा एकत्र करने तथा सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए धातुकर्मीय एवं इंजीरियरी परामर्शदाताओं (एम ई सी ओ एन), भारतीय रेल प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सेवाएं (आर आई टी ई एस) तथा भारतीय परियोजना एवं विकास लि. (पी डी आई एल) के कर्मचारियों को शामिल कर एक 21-सदस्सीय प्रतिनिधिमंडल ने 6-15 नवम्बर, 2009 तक सीरिया की यात्रा की।

2,200 मेगावाल्ट टिशरीन विद्युत संयंत्र विस्तार परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए भारत सरकार ने जो 240 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सीमा ऑफर की थी, उसकी प्रथम किस्त के तौर पर सीरिया के साथ 100 अमरीकी डालर की ऋण सीमा के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करने के लिए बैंक आफ इंडिया के आयात और निर्यात् महाप्रबंधक (ई एक्स आई एम) ने 6-7 अक्तूबर, 2009 तक सीरिया का दौरा किया।

भारत हैवी इलैक्ट्रिक्लस लि0 और भारतीय चाय बोर्ड तथा पांच कंपनियों को शामिल कर एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 14-22 जुलाई, 2009 तक दमिस्कस अंतर्राष्ट्रीय मेला, 2009 में भाग लिया। सीरियाई वाणिज्य चैम्बर्स परिसंघ द्वारा मेजबानी किए गए भारत सीरिया संयुक्त व्यापार बैठक के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ के एक 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 18-19 जुलाई, 2009 तक सीरिया की यात्रा की। सीरिया ने 14-27 नवम्बर, 2009 तक नई दिल्ली में हुए 29वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया। एक सीरियाई व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 23-25 अक्तूबर, 2009 तक हुए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले में भाग लिया।

सुश्री बोनिया शब्बान, सीरियाई प्रेजीडेंसी की के राजनीतिक और मीडिया सलाहकार ने 6-9 जनवरी, 2010 तक भारत की यात्रा की और विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा तथा मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की तथा विदेश राज्यमंत्री डाक्टर शशि थरूर से बैठक की।

डा. आनन्द शंकर के नेतृत्व में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (आई सी सी आर) द्वारा प्रायोजित एक 12-सदस्यीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य मंडली ने 1-7 अगस्त, 2009 को सीरिया की यात्रा की। श्री दाहने खान लांगा के नेतृत्व में आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित एक 12-सदस्सीय राजस्थानी लोक नृत्यमंडली ने बोसरा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव, 2009 में भाग लेने के लिए 6-13 अगस्त, 2009 तक सीरिया का दौरा किया। एक आई सी सी आर द्वारा प्रायोजित तथा श्री अदिप कुमार घोख के नेतृत्व में एक सितार मंडली ने सीरिया सिल्क रोड-उत्सव, 2009 में भाग लेने के लिए 8-18 अक्तूबर, 2009 तक सीरिया का दौरा किया।

साहित्य अकादमी और अरब लेखक संघ के बीच 2003 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग करार के नवीकरण हेतु साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री सुनील गंगोपाध्याय के नेतृत्व में एक

तीन-सदस्यीय साहित्य अकादमी प्रतिनिधिमंडल ने 06 से 13 नवम्बर, 2009 तक सीरिया का दौरा किया।

ट्यूनीशिया

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर संयुक्त कार्यदल (जे डब्ल्यू जी) की पहली बैठक 16-17 अप्रैल, 2009 को ट्यूनीशिया में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री आर चन्द्रशेखर, विशेष सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तथा ट्यूनीशियन पक्ष का नेतृत्व श्रीमती लामिया सैफई सगीर राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी सचिव ने किया। संयुक्त कार्यदल की बैठक का उद्घाटन संचार प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अल हेज ग्ले द्वारा किया गया। दोनों पक्षों ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों विशेषतः इंटरनेट सुरक्षा, प्रशिक्षण, मानकीकरण तथा तकनीकी सहायता के क्षेत्रों को अभिज्ञात किया। ट्यूनीशिया के अल गजला प्रौद्योगिकीय पार्क तथा भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकीय पार्क (एस टी पी) के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत और ट्यूनीशिया के मध्य सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों (एस एम ई) के बीच दूसरी बैठक 30 सितम्बर-1 अक्तूबर 2009 तक ट्यूनीशिया में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री दिनेश राय, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने किया और अपने साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डा. एच पी कुमार को भी शामिल किया। ट्यूनीशिया पक्ष का नेतृत्व श्री सदोक बेजा, निदेशक उद्योग, ऊर्जा और एस एम ई मंत्रालय द्वारा किया गया।

इस अवधि के दौरान 2.5 बिलियन अमरीकी डालर के सरा ऑरटेन उर्वरक काम्पलेक्स के व्यवहार्यता अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फटिलाइजर्स (आर सी एफ) द्वारा संचालित एक संघ से एक छः सदस्सीय उर्वरक प्रतिनिधिमंडल सहित भारत से अनेक व्यवसायी प्रतिनिधिमंडलों ने ट्यूनीशिया का दौरा किया।

सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र निर्यात् संवर्द्धन परिषद् (एस आर टी ई पी सी) के विनिर्माताओं, डीलर्स और निर्यातकों ने 4-5 फरवरी, 2010 को ट्यूनीशिया में भारतीय कपडों, तैयार सामग्री, यार्न (धागे) इत्यादि की एक प्रदर्शनी लगाई। जुलाई में हुए कार्थेज के 45वें अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में एक भारतीय नृत्य मंडली 'बैलेट बॉलीबुड' ने प्रस्तुतीकरण किया तथा रमजान के दौरान आयोजित एक धार्मिक संगीत के पांचवें उत्सव में एक भारतीय संगीत समूह ने भाग लिया।

25-27 सितम्बर, 2009 तक हैदराबाद में भारत-अफ्रीका औषधीय व्यापार बैठक में भाग लेने के लिए एक तीन सदस्सीय ट्यूनीशियन औषधीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। एक चार सदस्सीय ट्यूनीशियन आई टी प्रतिनिधिमंडल ने 25-30 अक्तूबर, 2009 तक बैंगलोर में हुए साफ्टवेयर सेवा कम्पनियों के राष्ट्रीय संघ (नैसकॉम) उत्पाद सभा में भाग लिया।

ट्यूनिशिया के पैट्रोल और गैस मंत्रालय से एक दो-सदस्सीय प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान आर्थिक संकट, तेल और गैस उद्योग तथा भारत के पैट्रोलियम और गैस कामगार संघ द्वारा गठित ट्रेड यूनियन की भूमिका पर हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए 10-14 दिसम्बर, 2009 तक मुम्बई का दौरा किया। लायंस क्लब, ट्यूनीशिया के अंतर्राष्ट्रीय संघ से एक छः सदस्सीय प्रतिनिधिमंडल ने 37वें भारत, दक्षिण एशिया और मध्यपूर्व मंच (आई एस एस एम ई) में भागीदारी के लिए 3-13 दिसम्बर, 2009 तक हैदराबाद का दौरा किया।

अरब राज्य लीग

विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने अरब राज्य लीग के महासचिव श्री अमरे मोसा से सितम्बर, 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू एन जी ए) के दौरान (अतिरिक्त समय में) मुलाकात की।

2 अक्तूबर, 2009 को अहिंसा पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस को सफल बनाने के लिए काहिरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और अरब राज्य लीग के महासचिव श्री अमरे मोंसा द्वारा बीज-व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी पर एफ फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई।

■■

6 अफ्रीका (सहारा से दक्षिण)

दक्षिण और पूर्व अफ्रीका

भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन-अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष के दौरान भारत-अफ्रीका मंच सम्मेलन पर अनुवर्ती कार्रवाई जारी रही। दिसम्बर, 2009 में आदीस अबाबा में औपचारिक बैठकों सहित एयू के साथ विचार-विमर्श हुए। भारत ने जुलाई 2009 में सिरते में आयोजित एयू सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था।

वर्ष के दौरान भारत ने इस क्षेत्र से निम्नलिखित उच्चस्तरीय यात्राओं की मेजबानी कीः

- नामीबिया के राष्ट्रपति श्री हिफीकेपुमिया ने 30 अगस्त-3 सितम्बर 2009 तक भारत का सफल राजकीय दौरा किया।
- तंजानिया के प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2009 में भारत की यात्रा की।

भारत की ओर से उपराष्ट्रपति ने मई, 2009 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में डा. जैकब जुमा के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

वर्ष 2009 के दौरान की गई अन्य महत्वपूर्ण भारत यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

- बोत्सावाना के रक्षा, न्याय व सुरक्षा मंत्री (फरवरी)
- युगाण्डा के प्रेसीडेंसी प्रभारी मंत्री, उपमहान्यायवादी/न्याय व सांविधानिक कार्य राज्य मंत्री तथा वित्त राज्य मंत्री (मई)
- युगाण्डा के आंतरिक कार्य राज्य मंत्री (जून)
- लिसाथो राजशासी के संचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री (जून)
- इथोपिया के परिवहन व दूरसंचार राज्य मंत्री (जुलाई)
- युगांडा के शहरी विकास राज्य मंत्री (जुलाई)
- युगांडा के संचार व परिवहन राज्य मंत्री (जुलाई)
- इथोपिया के दक्षिण राष्ट्रों की राष्ट्रीयता परिषद तथा इथोपिया के जनवादी क्षेत्रीय व राष्ट्रीयता के अध्यक्ष (अगस्त)
- इथोपिया के ओरामिया क्षेत्र के राष्ट्रपति (अगस्त)
- मॉरीशस के सूचना व संचार प्रौद्योगिकी मंत्री (अगस्त)
- केन्या के स्वास्थ्य मंत्री (सितम्बर)
- जिम्बाब्वे के वाणिज्य व उद्योग मंत्री (सितम्बर)
- मॉरीशस के विदेश कार्य, क्षेत्रीय अखंडता व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (सितम्बर)
- तंजानिया के उद्योग, व्यापार व विपणन मंत्री (सितम्बर)
- दक्षिण अफ्रीका के व्यापार व उद्योग मंत्री (सितम्बर)
- नामिबिया के रक्षा व सुरक्षा मंत्री (अक्तूबर)
- मॉरीशस के पर्यावरण व राष्ट्रीय विकास एकक मंत्री (अक्तूबर)
- युगाण्डा के कृषि राज्य मंत्री (अक्तूबर)
- युगाण्डा के मात्स्यिकी के प्रभारी कृषि राज्य मंत्री (अक्तूबर)
- मॉरीशस के उपराष्ट्रपति-गैर सरकारी यात्रा पर (अक्तूबर-नवम्बर)
- दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध व सहयोग मंत्री (नवम्बर)
- मॉरीशस के राष्ट्रपति-गैर सरकारी यात्रा पर (नवम्बर-दिसम्बर)
- रवाण्डा के वित्त व आर्थिक नियोजन मंत्री (जनवरी 2010)
- मॉरीशस के लोक अवसंरचना, भूतल परिवहन व नौवहन मंत्री तथा शिक्षा, संस्कृति व मानव संसाधन विकास मंत्री (जनवरी 2010)
- मॉरीशस के उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री (जनवरी 2010)
- मॉरीशस के विदेश कार्य, क्षेत्रीय अखंडता व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (जनवरी 2010)
- दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री श्री प्रवीन गोर्धन (जनवरी 2010)

- दक्षिण अफ्रीका के जल व पर्यावरण कार्य मंत्री सुश्री बुईलवा सोनलिका (जनवरी, 2010)

भारत की ओर से महत्वपूर्ण यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- लोक सभा के उपाध्यक्ष, श्री चरनजीत सिंह अटवाल के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मॉरीशस व दक्षिण अफ्रीका यात्रा (अप्रैल)
- हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष, श्री तुलसीराम की मॉरीशस यात्रा (जून)
- वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा की दक्षिण अफ्रीका यात्रा (अगस्त)
- कोयला, सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के (प्रभारी) राज्य मंत्री, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल की डरबन यात्रा (अगस्त)
- केरल के उद्योग मंत्री श्री इलामारन करीम ने जोहंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की (सितम्बर)
- स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री दिनेश त्रिवेदी की आदीस अबाबा, इथोपिया यात्रा (अक्तूबर)
- लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार की अरुसा (तंजानिया) यात्रा (28 सितम्बर-6 अक्तूबर)
- विज्ञान व प्रौद्योगिकी, संसदीय कार्य, पृथ्वी विज्ञान तथा कार्मिक व प्रशिक्षण (प्रभारी) राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण की डरबन, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा (अक्तूबर)
- विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर की मॉरीशस यात्रा (नवम्बर)
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, श्री रमनसिंह के साथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ भारतीय वाणिज्य चैम्बर्स के व्यापार प्रतिनिधिमंडल की जोहंसबर्ग व केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका यात्रा (नवम्बर)
- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री की तंजानिया व केन्या यात्रा (जनवरी 2010)
- लोकसभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार की मॉरीशस यात्रा (जनवरी 2010)
- पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा की युगाण्डा यात्रा (जनवरी 2010)
- विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने आदीस अबाबा की यात्रा की तथा एयू सम्मेलन में भाग लिया (जनवरी 2010)
- विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर की मापूतो, मोजाम्बिक यात्रा (जनवरी 2010)

बोत्सवाना

भारत व बोत्सवाना के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। बोत्सवाना के रक्षा, न्याय व सुरक्षा मंत्री बिग्रेडियर (सेवानिवृत्त) डिकगाकगामातसु एनडेसू सिरेटासे ने 11-14 फरवरी 2009 को बैंगलूर में आयोजित सातवें इंटरनेशनल एयरोस्पेस एक्सपोजिशन-एयरो इंडिया-2009 में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।

8 मार्च, 2009 को उच्चायुक्त श्री विष्णु एन हाडे ने बोत्सवाना के शिक्षा व निपुणता विकास मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 731 कम्प्यूटर, यूपीएस व प्रिंटर सौंपे। यह दान बोत्सावाना के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फेस्टस मोगाए की राजकीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 2006 में दी गई वचनबद्धता के रूप में था।

हिंदुस्तान कम्प्यूटर्स लि. (एचसीएल) इनफोसिस्टम्स के एक विशेषज्ञ को बोत्सवाना के शिक्षा व निपुणता विकास मंत्रालय में कर्मचारियों की सहायता व प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

मेजर जनरल चंद्र प्रकाश, वीएसएम, अपर महानिदेशक, स्टाफ डयूटी, रक्षा मंत्रालय (सेना) ने इंटर एंजेसी टास्क टीम (आईएटीटी)/ आईएएसटीटी तथा बोत्सवाना डिफेंस फोर्स एंड सप्लाई ऑफ सिविल डिफेंस इक्विपमेंट के बीच करार के नवीकरण सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 31 मई-1 जून, 2009 को बोत्सवाना की यात्रा की।

वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव श्री पीके चौधरी तथा हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचडीसीपीएल) की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती अल्का त्यागी ने 24-26 जून, 2009 तक बोत्सवाना की यात्रा की तथा व्यापार व उद्योग मंत्री एवं अन्य कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श किया ताकि डेवस्वाना, जो बोत्सवाना सरकार व डी बियर्स के बीच संयुक्त उद्यम है, से कच्चे हीरे खरीदने की संभावना का पता लगाया जा सके।

भारत की भेषज निर्यात संवर्धन परिषद के नेतृत्व में एक 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 26-29 जुलाई, 2009 तक गाबोरोन की यात्रा की तथा 27 जुलाई, 2009 को वार्तासम्मत/क्रेता-विक्रेता भेंट आयोजित की। प्रतिनिधिमंडल ने सहायक स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की तथा स्वास्थ्य व भेषज कंपनियों के मंत्रालय, ड्रग रेगुलेटरी युनिट में कर्मचारियों के साथ बैठक की।

बोत्सवाना के व्यापार व उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 4-14 अगस्त, 2009 को 'बोत्सवाना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कार्यपालक विकास कार्यक्रम' पर एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में सरकारी कर्मचारियों, जनता व गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्री राजीव डोगरा, राजदूत (सेवानिवृत्त) ने बोत्सवाना के विदेश कार्य व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के पुनर्गठन के संबंध में 25 अक्तूबर-5 दिसम्बर, 2009 तक छः सप्ताह के लिए बोत्सवाना की यात्रा की। यह यात्रा बहुत ही सफल थी तथा स्थानीय प्राधिकारियों ने इसकी सराहना की थी।

उपराष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी के साथ श्रीमती सलमा अंसारी ने 9-11 जनवरी, 2010 तक बोत्सवाना की यात्रा की। उनके साथ श्रम व रोजगार राज्य मंत्री, श्री हरीश रावत, संसद के तीन सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी व मीडिया भी था। उपराष्ट्रपति ने अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अलावा बोत्सवाना के राष्ट्रपति व उपराष्टपति के साथ विचार-विमर्श किया। उपराष्ट्रपति के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ का 30-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था, जिसने बोत्सवाना के निर्यात विकास व निवेश प्राधिकरण (बीईडीआईए) के साथ विचार-विमर्श किया तथा विभिन्न व्यापारियों के साथ अलग-अलग बैठक की।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए थेः

1. कृषि व संबंधित क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
2. शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

इस यात्रा का स्थानीय मीडिया में व्यापक प्रचार हुआ था, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग प्रदर्शित हुआ था। यात्रा के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था तथा दोनों सरकारों की सुविधानुसार निकट भविष्य में यह यात्रा होने की संभावना है।

सचिव (रक्षा, न्याय व सुरक्षा) के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल तथा कमांडर वीडीएफ द्वारा 15-18 फरवरी, 2010 तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले रक्षा एक्स्पो में भाग लिए जाने की संभावना है।

बोत्सवाना सरकार बोत्सावाना में क्षेत्रीय निर्वाचक सभा आयोजित करने का अनुरोध करती रही है तथा उन्होंने हाल ही में स्मरण कराया है कि उसे निकट भविष्य में आयोजित किया जाना चाहिए। आगामी महीनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा।

बुरुंडी

वर्ष 2009 में भारत बुरुंडी संबंध नए चरण में प्रवेश कर गए थे, जब बुरुंडी ने अगस्त में नई दिल्ली में अपना आवासीय मिशन खोला था। इस समय मिशन के अध्यक्ष चार्ज डी अफेयर्स हैं तथा शीघ्र ही एक राजदूत द्वारा इसका अध्यक्ष बनने की संभावना है।

कोमोरोस

भारत व कोमोरोस में सदैव सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। 4 जून, 1976 से ही मेडागास्कर के साथ समवर्ती मान्यता सहित कोमोरोस में भारत की राजनयिक मौजूदगी है।

कोमोरियन लोगों को प्लम्बिंग, वैल्डिंग, उपस्कर व विद्युत, सिविल कार्य, आईटी, जल विज्ञान, सिविल इंजीनियरी, दूर-संचार, विश्लेषण प्रोग्रामिंग, निर्माण व लोक कार्य, जियोमीटर टोपोग्राफी में निपुणता प्रदान करने के लिए मोरोनी में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं। भारत सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का कार्यस्थल पहले ही चुन लिया है तथा निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है, इस परियोजना पर 1 मिलियन अमरीकी डालर की लागत आएगी, जिसे अफ्रीका के सहायता बजट में से पूरा किया जाएगा।

इरिट्रिया

एक भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस ब्रह्मपुत्र ने 21-24 मई, 2009 तक मसावा के इरिट्रियाई बंदरगाह पर सौहार्दपूर्ण यात्रा की। विदेश मंत्री ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 2009 के पत्र के माध्यम से अपने इरिट्रियाई समकक्ष को भारत सरकार के इस निर्णय से अवगत कराया था कि कृषि व शैक्षणिक उपस्करों की खरीद की वित्त व्यवस्था के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान किया जाएगा। एक्जिम बैंक मुम्बई श्रृंखलाबद्ध ऋण के लिए कार्यान्वयन अभिकरण होगा। वर्तमान वर्ष के दौरान इरिट्रिया को भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग प्रशिक्षण के 5 स्लॉट प्रदान किए गए थे।

इथिओपिया

भारत तथा इथिओपिया के मध्य द्विपक्षीय संबंध अधिक से अधिक मजबूत होते रहे। भारत इथिओपिया को लोकतांत्रिक व बहुलवादी ढांचे के रूप में विकसित करने के लिए आदर्श भूमिका निभाता रहा है। इथिओपिया ने भारत के साथ संबंधों को संस्थाकरण करने तथा इसकी रणनीतिक सहभागिता स्थापित करने का प्रयास किया है।

श्री गेताशु मेंजिस्टि, परिवहन व संचार राज्य मंत्री ने टाटा मोटर संयंत्र का दौरा करने के लिए 24-30 जुलाई, 2009 तक भारत की यात्रा की थी।

ओरोमा क्षेत्र के अध्यक्ष ने 1-5 अगस्त, 2009 तक भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कलकत्ता में इथिओपिया के मानार्थ कोंसलावास के उद्घाटन समारोह में भाग लिया तथा दिल्ली में भारतीय व्यापारियों के साथ बैठक भी की थी।

दक्षिण राज्य, राष्ट्रीय व जनवादी क्षेत्रीय राज्य (एसएनएनपीआरएस) के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्देशन यात्रा के रूप में 16-24 अगस्त, 2009 तक भारत की यात्रा की थी तथा प्रतिनिधिमंडल ने 17-19 अगस्त, 2009 तक नई दिल्ली में संसदीय अध्ययन व प्रशिक्षण कार्यालय के साथ बैठक 20-21 अगस्त, 2009 को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा से मुलाकात की।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री हिफिकपुण्ये पोहाम्बा 31 अगस्त, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस सम्मेलन में।

उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का 9 जनवरी, 2010 को बोत्सवाना में गाबारोन सर सेरेस्ते खामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके आगमन पर बोत्सवाना के उप राष्ट्रपति श्री मोमपति मेराफी द्वारा स्वागत।

इथिओपिया संसद के सदस्य व क्षमता निर्माण पर संसदीय समिति के अध्यक्ष तथा साथ ही इथिओपिया भारत संसदीय समूह के अध्यक्ष श्री तेकेले तेसीमी ने 23-31 अगस्त, 2009 तक भारत की यात्रा की।

संसद के दो सदस्यों तथा लोक सभा व राज्य सभा के महासचिव तथा राज्य सभा व लोक सभा के वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त 10-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 4-10 अप्रैल, 2009 तक 'संकट काल में शांति निर्माण, लोकतंत्र व विकास' नामक शीर्षक पर आदीस अबाबा में आयोजित 120 वीं अंतर संसदीय केंद्रीय संघ सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था। अदीस अबाबा में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अध्यक्ष, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति से मुलाकात की।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 'जनसंख्या व विकास कार्यक्रम संबंधी कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन, 2009 तथा जन्म स्वास्थ्य पर उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 25-29 अक्तूबर, 2009 को अदीस अबाबा की यात्रा की। संसद के दो सदस्यों ने आईसीपीडी कार्यक्रम संबंधी कार्रवाई में भी भाग लिया।

भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 9- सदस्यीय भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल इथिओपिया पहुंचा। दल का नेतृत्व एक कर्नल ने किया तथा इसमें एक लैफ्टिनेंट कर्नल, तीन मेजर तथा चार नान-कमीशंड ऑफिसर्स शामिल हैं तथा इथिओपियाई सरकार के निमंत्रण पर वे 3 वर्ष के लिए वहां रहेंगे।

दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार सतत रूप से बढ़ता रहा है तथा मुख्य रूप से भारत के पक्ष में है। इथिओपिया के सीमाशुल्क प्राधिकरण के अनुसार 2008-09 के दौरान इथिओपिया को किए गए भारतीय निर्यात का मूल्य 450 मिलियन अमरीकी डालर था, जबकि आयातों का मूल्य 12 मिलियन अमरीकी डालर था। वर्ष 2009 में इथिओपिया में भारतीय निवेश 4.15 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया था तथा अब भारत इथिओपिया में अकेला सबसे बड़ा निवेशक है।

एक भारतीय कंपनी मै. अनमोल प्रोडक्ट इथिओपिया प्राइवेट लि. ने 2 अगस्त, 2009 को अदीस अबाबा से लगभग 80 किमी दूर गिंची में अपनी पेपर पल्प फैक्ट्री का उद्घाटन किया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंद्ध परिषद द्वारा प्रत्यायोजित तथा श्री अभिजीत पोहानकार के नेतृत्व में एक 6-सदस्यीय समेकित संगीत समूह ने 16-22, अक्तूबर 2009 तक इथिओपिया की यात्रा की। इस समूह ने अदीस अबाबा तथा दिरे दावा में प्रस्तुतिकरण किए।

विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने अफ्रीकी संघ सम्मेलन के लिए इथिओपिया की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री ने इथिओपिया के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की।

केन्या

भारत की ओर से अधिकारी स्तरीय यात्राओं में केन्या के अंतरिम स्वतंत्र चुनाव आयोग तथा अंतरिम स्वतंत्र सीमा समीक्षा आयोग (आईआईबीआरसी) के लिए इंडक्शन कार्यशाला में भाग लेने के लिए 6-9 जुलाई, 2009 तक चुनाव आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी की यात्रा शामिल है। भारतीय चुनाव आयोग के अपर सचिव डॉ. मृत्युजंय सारंगी ने राष्ट्रीय चुनाव सुधार सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11-15 अगस्त, 2009 तक नैरोबी की यात्रा की तथा मूल्यांकन निदेशालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्या राजस्व प्राधिकरण के सॉफ्टवेयर समुन्नयन के लिए 23 अप्रैल-1 मई 2009 तक यात्रा की।

केन्या के स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक 16-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत अफ्रीका फार्मा बैठक में भाग लेने के लिए 14-16 सितम्बर, 2009 तक हैदराबाद की यात्रा की तथा एक 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएपीईएक्ससीआईएल इंडिया द्वारा आयोजित समकक्षीय क्रेता-विक्रेता बैठक में भाग लेने के लिए 27 सितम्बर को गोवा की यात्रा की।

केन्या गणराज्य के चिकित्सा सेवा मंत्री श्री पीटर अनयंग नियोंगो ने हैदरावाद में भारतीय भेषज निर्माता संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 24-28 सितम्बर, 2009 तक भारत की यात्रा की थी।

केन्या के स्वतंत्र अंतरिम चुनाव आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक 6 - सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 22-26 अक्तूबर, 2009 तक भारत की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र विधानसभा की मतगणना का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र की यात्रा की तथा इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी लेने के लिए भारत इलैक्ट्रोनिक लि. (बीईएल) बैंगलूर की यात्रा की। लोक सेवा मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल ने भी भारत में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण का अध्ययन करने के लिए 29 जून-10 जुलाई 2009 तक भारत की यात्रा की थी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम व केन्या के औद्योगिक इस्टेट के मध्य 12 मई, 2009 को पारस्परिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री दिनेश राय, सचिव, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने तथा केन्या के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व औद्योगिकीकरण मंत्री श्री हेनरी कारगे ने किया था।

वर्ष 2008 में द्विपक्षीय व्यापार में सतत वृद्धि हुई है, जिसका मूल्य 1200 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक था तथा भारत के निर्यातों की राशि 1094 मिलियन अमरीकी डालर थी। भारत से केन्या को किए गए निर्यातों की मुख्य मदों में औषध व

भेषज, रसायन व मशीनरी इत्यादि शामिल हैं। भारत द्वारा आयतित मुख्य मदों में काजू, चमड़ा व चमड़ा उत्पाद तथा रद्दी धातु शामिल हैं।

मैसर्स एस्सार एनर्जी ओवरसीज कंपनी ने 31 जुलाई, 2009 की स्थिति के अनुसार केन्या पैट्रोलियम रिफाइनरी में 50 प्रतिशत स्वामित्व का अधिग्रहण किया है तथा प्रधानमंत्री श्री रेला ओडिंगा, वित्त मंत्री श्री युहुरु केन्याता तथा एस्सार समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रशांत रूइया की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

केपैक्सिल ने 3 अगस्त, 2009 को क्रेता-विक्रेता भेंट आयोजित की, जिसका उद्घाटन सहायक व्यापार मंत्री ने किया था तथा इसमें बड़ी संख्या में उद्योगपतियों/व्यापारियों ने भाग लिया था। इलैक्ट्रोनिक व कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद ने 30 नवम्बर, 2009 को बीएसएम आयोजित किया।

प्रतिनिधिमंडल स्तरीय यात्राओं में 5-9 अक्तूबर, 2009 तक भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) की यात्रा, एनएबीएआरडी द्वारा एनएबीसीओएसएस परामर्शदायी सेवाओं का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (एनओबीएआरडडी) के एक सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की 2 अक्तूबर से यात्रा तथा केन्या राजस्व प्राधिकरण के साथ कर रजिस्टर कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए 9-15 नवम्बर, 2009 तक कर्नाटक सरकार से 5-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा शामिल है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) से 18- सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 5-6 अगस्त, 2009 को केन्या की यात्रा की तथा स्वास्थ्य मंत्री, सहायक ऊर्जा मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए स्थाई सचिव तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की।

लिसोथो

मार्च 2009 में नई दिल्ली में आयोजित द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की सचिव स्तर की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिसाथो के साथ संबंधों में और विस्तार व विविधिकरण हुआ है। मासेरू में एक व्यावसायिक केंद्र की स्थापना के लिए 4.7 मिलियन अमरीकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण की घोषणा के साथ ही भारत का विकास सहयोग जारी रहा। मासेरू में आधुनिक शिक्षा व सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक सम्पूर्ण भारत-लिसाथो केंद्र स्थापित करने के लिए 1.79 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में दिसम्बर, 2009 में नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

लिसाथो सरकार के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल 2011 तक लिसाथो के रक्षा बलों को अपना समर्थन जारी रखेगा। आईटीईसी के अतर्गत प्रदान किए गए सभी 30 प्रशिक्षण स्थानों का लिसाथो द्वारा उपयोग, लिसाथो में महत्वपूर्ण संस्थानों को पुस्तकों के उपहार के साथ-साथ 1000 फुटबॉल तथा फुटबॉल नेट का दान चालू द्विपक्षीय विकास सहयोग के अन्य पहलू थे। लिसाथो ने अल्प विकसित देशों के लिए भारत सरकार की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभ उठाने के अपने आशय की पुष्टि की है, जिसमें सहभागी देशों की शुल्क मुक्त व वरीयता प्राप्त बाजार तक पहुंच का प्रावधान है।

मेडागास्कर

मेडागास्कर के साथ भारत के चिरस्थायी व सौहार्दपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक व सभ्यतापरक संबंधों को भारतीय मूल के 20000 लोगों द्वारा और मजबूत किया जा रहा है, जो कि मेडागास्कर के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वर्ष 2009 में भारत ने मेडागास्कर की कृषि संबंधी परियोजनाओं के लिए 25 मिलियन अमरीकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण अनुमोदित किया था, ताकि इसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चावलों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

मेडागास्कर सरकार ने देश में पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क स्थापित करने के लिए अप्रैल 2009 में भारतीय दूरसंचार परामर्शदायी लि. (टीसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। टीसीआईएल ने पहले ही उपस्कर भेज दिए हैं तथा मेडागास्कर निकट भविष्य में भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों तथा उच्च विशेषज्ञता प्राप्त अस्पतालों से दूर-शिक्षा व दूर-चिकित्सा का लाभ उठाना शुरू कर देगा।

मेडागास्कर सरकार ने अल्प विकसित देशों के लिए भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना प्रस्ताव का लाभ उठाने का आशय व्यक्त किया है तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

खनन, अवस्थापना, कृषि, विद्युत, ऊर्जा, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में मेडागास्कर की बड़ी क्षमता को ध्यान में रखते हुए टाटा, रिलायंस, बिरला, एस्सार इत्यादि सहित कई प्रमुख कंपनियों ने देश में विभिन्न निवेश अवसरों के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। इसके परिणामस्वरूप, भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र से व्यापारी मेडागास्कर की यात्रा करते रहे हैं तथा सरकारी व गैर-सरकारी अधिकारियों से बातचीत करते रहे हैं।

हाल ही में मेडागास्कर सरकार ने देश में कृषि के विकास के लिए भारतीय कंपनी वरूण ग्लोबल एसएआरएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शुरू में कंपनी को चावल, मक्का व मसूर की खेती के लिए 3400 एकड़ कृषि योग्य भूमि दी गई है। यह भूमि 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई है तथा तत्पश्चात इसे 99 वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है। कंपनी ने उत्तरी मेडागास्कर में डियगे सारेज में अपनी परीक्षणार्थ परियोजना शुरू करने के लिए भारत से ट्रैक्टर व निपुण कर्मचारी मंगवाए हैं।

मालावी

भारत और मालावी के संबंध मैत्रीपूर्ण व सौहार्दपूर्ण बने रहे। मालावी ने 19 मई, 2009 को राष्ट्रपति व संसद के चुनाव

सफलतापूर्वक आयोजित किए थे। पदस्थ राष्ट्रपति श्री बिंगु वा मुथारिका ने राष्ट्रपति के चुनावों में निर्णायक विजय प्राप्त की तथा उनकी पार्टी ने संसदीय चुनावों में भी बहुमत हासिल किया। द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 30 प्रतिशत की सतत दर पर वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में मालावी को भारतीय निर्यातों में 29.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा विगत वर्ष की तुलना में मालावी से भारत के आयातों में 35.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा मालावी को प्रदान किए गए 30 मिलियन अमरीकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण का उपयोग सिंचाई, तम्बाकू, थ्रैशिंग तथा एक गांव एक परियोजना की वित्त व्यवस्था करने के लिए किया गया है। टेलिकम्यूनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लि. (टीसीआईएल) ने पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत दूर-शिक्षा, दूर-चिकित्सा व टेलिकांफ्रेंसिंग के लिए मार्च, 2009 में मालावी में सुविधाएं स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया है। श्री बिंगु वा मुथारिका, जिन्होंने भारत में अध्ययन किया था, ने विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ और सहयोग विकसित करने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की। वर्ष 2009-10 के दौरान मालावी को भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 40 स्थान आबंटित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश स्थानों का उपयोग किया जा चुका है।

उपराष्ट्रपति श्री एम.हामिद अंसारी ने अपनी पत्नी श्रीमती सलमा अंसारी के साथ 7-9 जनवरी, 2010 तक मालावी की सरकारी यात्रा की थी। उनके साथ श्रम व रोजगार राज्य मंत्री श्री हरीश रावत, संसद के 3 सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी व मीडिया था। उपराष्ट्रपति के प्रतिनिधिमंडल के साथ अलग से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी था। मालावी ने 2008 में प्रदत्त 30 मिलियन अमरीकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण का उपयोग कर लिया है। उपराष्ट्रपति ने मालावी की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान करने की घोषणा की थी। उन्होंने हाल ही में मालावी के कुछ भागों में आए भूकंप के दौरान राहत के रूप में 1 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा की।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए थेः

1. कृषि व संबंधित क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
2. मालावी के विदेश मंत्रालय व भारत के विदेश मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श के लिए प्रोतोकॉल।
3. मालावी में लघु उद्यमों के विकास के लिए पारस्परिक सहयोग के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा मालावी की एक गांव एक उत्पाद।

मॉरीशस

भारत तथा मॉरीशस के मध्य संबंध ऐतिहासिक व चिरस्थायी हैं। वर्ष के दौरान भारत ने मॉरीशस के साथ अपने बहुआयामी संबंध जारी रखे थे। सांस्कृतिक संबंधों के अलावा राजनैतिक, आर्थिक, रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्र में संबंध निरंतर जारी रहे। नवम्बर 2009 में पोर्ट ऑफ स्पेन में राष्ट्रमंडल की सरकारों की बैठक (सीएचओजीएम), 2009 के अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। मॉरीशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। भारत मॉरीशस के लिए सबसे बड़ा आयात स्रोत है। मॉरीशस के साथ भारत के रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग, नौसैनिक जहाजों की सौहार्दपूर्ण यात्रा व जलविज्ञान संबंधी कार्यकलापों के लिए यात्रा के माध्यम से पुनः संवर्धित हुए हैं। आधुनिक हल्का हैलिकॉप्टर ध्रुव 3 नवम्बर, 2009 को मॉरीशस को सौंपा गया था। तटीय निगरानी रेडार प्रणाली की स्थापना व आपूर्ति के लिए करार पर नवम्बर, 2009 में हस्तांतर किए गए थे। मॉरीशस के विद्यार्थियों ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाना जारी रखा। मॉरीशस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संवर्धित सहयोग के लिए भी भारत से अपेक्षा रखता है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, श्री तुलसी राम के साथ हिमाचल विधान सभा के सचिव, श्री गोवर्धन सिंह ने मॉरीशस की राष्ट्रीय सभा की प्रक्रिया व कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए 21-25 जून, 2009 तक मॉरीशस की यात्रा की। यह यात्रा राष्टमंडल संसदीय संघ के अध्ययन दौरे का एक हिस्सा है। हिमाचल के प्रतिनिधिमंडल ने मॉरीशस की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष से मुलाकात की।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोराट को प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मॉरीशस ने 1 अगस्त, 2009 को डॉक्टर ओनरीज कॉज इन साइंस (अर्थशास्त्र) की उपाधि प्रदान की थी।

मॉरीशस के सूचना व संचार प्रौद्योगिकी मंत्री श्री मोहम्मद अशरफ अली दलूल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 12-14 अगस्त, 2009 तक हैदराबाद की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान 13 अगस्त, 2009 आंध्र प्रदेश के ई-प्राप्ति मंच पर आदान-प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मॉरीशस के विदेश कार्य, क्षेत्रीय अखंडता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री डॉ. अर्विन बुलेल ने 3-4 सितंबर, 2009 को नई दिल्ली में विश्व व्यापार संगठन की अनौपचारिक मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।

मॉरीशस के उपराष्ट्रपति री अंगीडी वीरिया छेतियार ने 20 अक्तूबर-3 नवम्बर 2009 तक भारत की गैर सरकारी यात्रा की।

मॉरीशस के पर्यावरण व राष्ट्रीय विकास एकक मंत्री श्री लॉरमस बुंधू ने 22-23 अक्तूबर, 2009 को नई दिल्ली में 'जलवायु

परिवर्तनः प्रौद्योगिकी विकास व हस्तांतरण' सम्मेलन में भाग लिया।

भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री के. मोहनदास ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2010 के संबंध में 27-28 अक्तूबर, 2009 को मॉरीशस की यात्रा की।

विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने भारत से बंधुआ श्रमिकों के मॉरीशस आगमन की 175 वीं वर्षगांठ के स्मारक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 1-3 नवम्बर, 2009 तक मॉरीशस की यात्रा की थी। डॉ. शशि थरूर ने मॉरीशस गणराज्य के राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ तथा मॉरीशस गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 3 अक्तूबर, 2009 को हल्का आधुनिक हैलीकॉप्टर 'ध्रुव' प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम को सौंपा। भारत से मॉरीशस को तटीय निगरानी रेडार प्रणाली की आपूर्ति के लिए 3 नवम्बर, 2009 को भारत-मॉरीशस अंतर मंत्रालयी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। डॉ. थरूर ने 'भारत-अफ्रीकाः व्यापार में सहभागी' शीर्षक पर मॉरीशस विश्वविद्यालय को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर-रिम संघ (आईओआर-एआरसी) का दौरा किया।

मॉरीशस के राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने 29 नवम्बर-18 दिसम्बर, 2009 तक भारत का गैर-सरकारी दौरा किया।

भारतीय नौसैनिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस निर्देशक ने 10 मार्च-17 अप्रैल, 2009 तक मॉरीशस की समुद्री सीमा में जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। पोर्ट लुइस हार्बर, पोर्ट माथुरिन, अगोल्गा तथा साया दी माल्हा बैंक के सर्वेक्षण पत्र के साथ एसटी ब्रांडन द्वीप के मध्य भाग की फेयर शीट तथा डिजीटल आँकड़े मॉरीशस के भूमि व आवास मंत्री डॉ. आबू तवालिव कासेनली को सौंपे थे। भारतीय नौसेना के नौसैनिक जहाज आईएनएसवी महादेवी ने 30 मई-9 जून, 2009 तक लंबी दूरी की यात्रा पर मॉरीशस की यात्रा की। यह यात्रा भारतीय नौसेना की पहली एकमात्र 'सागर परिक्रमा' परिक्रमा के लिए प्रशिक्षण की तैयारी के रूप में की गई थी। भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस शारदूल तथा भारतीय तटरक्षक जहाज आईएनसीजी वरूण ने 17-21 अक्तूबर, 2009 तक मॉरीशस की यात्रा की। आगंतुक जहाज ने मॉरीशस के राष्ट्रीय तटरक्षकों को अन्य बातों के साथ साथ अग्निशमन, क्षति नियंत्रण, खोज व राहत कार्य तथा दस्यु विरोधी कार्यकलापों सहित शीर्षकों पर बंदरगाह पर प्रशिक्षण दिया। एनसीजी के कमांडो दल ने जहाज पर सवार समुद्री कमांडो दल के साथ बातचीत की।

प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने 19 अगस्त, 2009 को अपोलो अस्पताल समूह के संयुक्त उद्यम अपोलो ब्रामवैल अस्पताल का सरकारी रूप से उद्घाटन किया।

टेलिकम्यूनिकेशन कंसल्टेंटस इंडिया लि. (टीसीआईएल) ने मॉरीशस में दूर-शिक्षा, दूर-चिकित्सा तथा पैन-अफ्रीका ई-नेटवर्क परियोजना के वीवीआईपी नॉड सहित सभी तीनों नॉडो से संबंधित कार्य पूरा किया।

मॉरीशस को पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के वर्तमान दूर चिकित्सा केन्द्र के अलावा पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल की मेजबानी के लिए चुना गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए वाणिज्यिक आसूचना सांख्यिकी महानिदेशालय के अंनतिम आंकड़ों के अनुसार भारत से मॉरीशस निर्यात की राशि 956.25 मिलियन अमरीकी डालर (4398.13 करोड़ रुपए) थी तथा मॉरीशस से भारत आयात की राशि 13.93 मिलियन अमरीकी डालर (64.05 करोड़ रुपए) थी।

औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग के अनुसार अप्रैल, 2000 से अगस्त, 2009 की अवधि के दौरान मॉरीशस से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह की राशि 43.14 बिलियन अमरीकी डालर थी, जो कि इस अवधि के दौरान भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 44 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान मॉरीशस से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि 11.2 बिलियन अमरीकी डालर थी। मॉरीशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक मात्र सबसे बड़ा स्रोत रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मॉरीशस में भारत के बर्हिगामी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (स्वीकृत प्रस्ताव) की राशि 2049 मिलियन अमरीकी डालर थी, जोकि वित्तीय वर्ष 2008-09 में बहिर्गामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 10 प्रतिशत है। भारत से बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश के लिए देशों की सूची में मॉरीशस का छठा स्थान है।

विदेशी कार्य, क्षेत्रीय अखंडता व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री डॉ. अर्विन बालेल ने 9 जुलाई, 2009 को सरकार तथा मॉरीशस गणराज्य की जनता की ओर से प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में और अंशदान के रूप में 5,000 अमरीकी डालर (मात्र पांच हजार अमरीकी डालर- दो करोड़ तैंतालीस लाख सात हजार नौ सौ छयालीस भारतीय रूपए) का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। यह बिहार में 2008 में विनाशकारी बाढ़ के लिए था।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक दलों को मॉरीशस भेजना जारी रहा।

नौवहन चार्ट की बिक्री पर भारत-मॉरीशस प्रोतोकॉल पर 2 अप्रैल, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।

उपग्रहों व प्रमोचन वाहन के लिए टैलीमेट्री, ट्रैकिंग तथा टैलीकमांड स्टेशन की स्थापना तथा अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान व प्रयोज्यता के क्षेत्र में सहयोग पर भारत-मॉरीशस अंतर-सरकारी करार पर 29 जुलाई, 2009 को पोर्ट लुइस में हस्ताक्षर किए गए थे। कृषि एवं सहयोग विभाग, भारत के कृषि मंत्रालय तथा मॉरीशस के कृषि उद्योग, खाद्य उत्पादन व सुरक्षा मंत्रालय के बाद 13 अक्तूबर, 2009 को वनस्पति सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने मॉरीशस की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष के निमंत्रण पर 17-22 जनवरी, 2010 तक

मॉरीशस की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तथा मॉरीशस की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष व मॉरीशस के विदेश मंत्री के साथ-साथ विपक्ष के नेता के साथ बैठक की।

मॉरीशस लोक अवस्थापना, भूतल परिवहन व नौवहन मंत्री श्री अनिल कुमार बाचो तथा मॉरीशस शिक्षा, संस्कृति व मानव संसाधन मंत्री श्री बसंत कुमार बुनवारी ने 6-8 जनवरी, 2010 तक प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की थी।

मॉरीशस के उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री डॉ. आर सियानेन ने 18-21 जनवरी, 2010 तक निवेश मिशन पर भारत की यात्रा की थी। उन्होंने वित्त मंत्री व योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मुलाकात की थी।

मॉरीशस के विदेश कार्य, क्षेत्रीय अखंडता व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री डॉ. अर्विन बुलेल ने 21-23 जनवरी, 2010 तक सीआईआई के भारत-अफ्रीका व्यापार कन्क्लेव में भाग लेने के लिए चेन्नई की यात्रा की थी।

मोजाम्बिक

मोजाम्बिक के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण व परस्पर उपयोगी बने रहे। 19 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत-मोजाम्बिक संयुक्त आयोग बैठक तथा 30 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित कोयला समूह से संबंधित दूसरी भारत- मोजाम्बिक संयुक्त कार्य समूह की बैठक से द्विपक्षीय सहयोग और सुदृढ़ हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय कोयला उद्यम (भारतीय इस्पात प्राधिकरण, कोल इंडिया लि., आरआईएनएल एनएमडीसी और एनटीपीसी का परिसंघ) के छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 23-25 अप्रैल, 2009 तक मापूतो की यात्रा की। इस दल ने मोआतिज टीटे प्रांत व बियरा बंदरगाह में कोयला खनन स्थलों का दौरा भी किया। प्रतिनिधिमंडल ने खनिज संसाधन उपमंत्री से भी मुलाकात की।

मोजाम्बिक के राष्ट्रपति अरमांडो गुएबुजा ने 10 जून, 2009 को गाजा प्रांत में 33 केवी विद्युत केंद्र शुरू करके ग्राम विद्युतीकरण परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। ओवरसीज इफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि. ने भारत द्वारा मोजाम्बिक को प्रदान किए गए 20 मिलियन अमरीकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण के भाग के रूप में इस केंद्र की स्थापना की थी।

फार्मेक्सिल के तत्वाधान में भारतीय औषध निर्माता व निर्यातकों के 30-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 29 जुलाई-1 अगस्त, 2009 तक मापुतो की यात्रा की थी। उनके प्रवास के दौरान 30 जुलाई, 2009 को एक क्रेता-विक्रेता वैठक आयोजित की गई। उन्होंने मोजाम्बिक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से विचार-विमर्श किया तथा मोजाम्बिक को भारतीय औषधियों के निर्यात से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

कोल इंडिया लि. ने खनन रियायत के संबंध में मोजाम्बिक सरकार से भावी लाइसेंस, जो कि उन्होंने टीटी प्रांत में मोजाम्बिक में 2 कोयला खनन खंडों के लिए प्राप्त किया है, प्रदान करने संबंधी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कोल इंडिया अफ्रीकन विभाग नामक अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी भी स्थापित की है।

भारत ने मोजाम्बिक के नामपुला, जाम्बिजिया, इनहाम्बेन तथा गाजा प्रांत में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 30 मिलियन अमरीकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान किया है तथा इस संबंध में ऋण करार पर अप्रैल, 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।

भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के अंतर्गत 2009-10 में मोजाम्बिक के लिए 30 प्रशिक्षण स्थान स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा आईसीसीआर की सामान्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 15 छात्रवृत्तियां तथा अन्य 12 आयुष छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई थी।

भारत व मोजाम्बिक के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन व सुरक्षा करार अक्तूबर, 2009 में प्रभावी हुआ था। इस करार में ऐसे निवेश को पारस्परिक सुरक्षा व प्रोत्साहन देकर दोनों देशों में अधिक से अधिक निवेश अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल स्थिति सृजित करने की अभिकल्पना की गई है। वर्ष 2008 में भारत व मोजाम्बिक के बीच द्विपक्षीय व्यापार 172.775 मिलियन अमरीकी डालर था, जोकि 2007 में 152.575 अमरीकी डालर से 14 प्रतिशत अधिक था। भारत से मोजाम्बिक के आयात वर्ष 2007 में 135.858 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 144.374 मिलियन अमरीकी डालर हो गए थे तथा भारत को इसके आयात वर्ष 2007 में 16.71 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2008 में 28.40 अमरीकी डालर हो गए थे।

नेशनल हाइड्रोकार्बन्स कंपनी, मोजाम्बिक के प्रबंधक (प्रचालन) श्री पोलिनो ग्रेगारयो ने 7-8 दिसम्बर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे भारत-अफ्रीका हाइड्रोकार्बन्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी।

विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर के साथ संयुक्त सचिव (पूर्व व दक्षिण एशिया) श्री गुरजीत सिंह ने 13-14 जनवरी, 2010 को राष्ट्रपति गुएबुजा की दूसरी कार्यावधि के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए मापुतो की यात्रा की थी। अपने मापुतो प्रवास के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति गुएबुजा से मुलाकात की तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी, आंतरिक व विदेश कार्य मंत्री से बैठक की थी।

नामीबिया

भारत-नामीबिया द्विपक्षीय संबंध 2009 में और सुदृढ़ व मजबूत हुए। नामीबिया ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता व 2011-12 में अस्थाई सदस्यता के लिए अपना समर्थन जारी रखा था।

नामीबिया के राष्ट्रपति श्री हिफिके पोहाम्बा ने 30 अगस्त-3 सितम्बर, 2009 तक भारत की सफलतापूर्वक राजकीय यात्रा

की। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल था, जिसमें व्यापार व उद्योग, विदेश, जल व वन, खान व ऊर्जा व रक्षा से संबंधित 5 मंत्री तथा राष्ट्रीय योजना आयोग के महानिदेशक, वरिष्ठ अधिकारी व एक सशक्त व्यापारी समूह शामिल था। इस यात्रा के दौरान 5 समझौता ज्ञापनों/करारों अर्थात (1) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग से संबंधित करार, (2) रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, (3) भू-विज्ञान व खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, (4) पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क पर समझौता ज्ञापन, और (5) राजनयिक व सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा माफी रियायत पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस यात्रा के दौरान भारत सरकार ने कई घोषणाएं कीः (1) अगामी 5 वर्षों के दौरान भारत से उत्पादों की आपूर्ति व परियोजनाओं में उपयोग किए जाने के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण, (2) आगामी 5 वर्षों के दौरान शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान सहायता, (3) उनाम (उत्तरी परिसर) में खनन इंजीनियरी संकाय की स्थापना के लिए 12 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक का अनुदान, (4) भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग के अंतर्गत स्थानों की संख्या 55 से बढ़ाकर 110 तथा स्नातक, स्नातकोत्तर व डाक्ट्रेट कार्यक्रमों के छात्रवृत्ति की संख्या 7 से बढ़ाकर 15 कर दी गई।

नामीबिया के रक्षा व सुरक्षा मंत्री डॉ. निल्के लेआम्बो ने 16-19 अक्तूबर, 2009 तक भारत की यात्रा की थी। डॉ. लेआम्बो ने गृहमंत्री पी. चिदम्बरम से मुलाकात की तथा दिल्ली, मसूरी व चंडीगढ़ स्थित संस्थानों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान नामीबिया के मंत्री ने व्यापक विचार-विमर्श किया तथा नामीबिया की पुलिस व सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भारत की सहायता के लिए अनुरोध किया।

सचिव (खान) श्रीमती सान्ता शीला नायर के नेतृत्व में एक 6-सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 26 अक्तूबर-1 नवम्बर, 2009 तक भूविज्ञान व खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त कार्यसमूह की बैठक में भाग लेने के लिए नामीबिया की सफलतापूर्वक यात्रा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति पोहावाना, संस्थापक राष्ट्रपति डॉ. साम नजुमा और खान व ऊर्जा मंत्री श्री एरक्की एनघीमितिना से मुलाकात की तथा ओकुरुसु और स्वाकोपमुंड में खानों का दौरा किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त उद्यम निगम के लिए नामीबिया के कई भावी लाइसेंस धारकों से भी मुलाकात की।

नामीबिया के चुनाव आयोग से 21-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 4 संसद सदस्य, कई राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा चुनाव आयोग के अधिकारी शामिल थे, ने भारत में आम चुनाव के दौरान इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के उपयोग के बारे में सीखने के लिए 15 अप्रैल, 2009 को बैंगलूर की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने बैंगलूरु में चुनाव प्रक्रिया का जायजा लिया तथा इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के निर्माण की जानकारी लेने के लिए भारत इलैक्ट्रोनिक लि0 (बीईएल) ष्ट्च संयंत्र का दौरा किया।

भारत ने नामीबिया में बाढ़ राहत के लिए अप्रैल, 2009 में 1 करोड़ रुपए की राशि दान की। भारत के समय पर संकेत व योगदान का सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा नामीबिया में काफी सौहार्द उत्पन्न हुआ।

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रामेन्द्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) से एक 7-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 8-12 सितम्बर, 2009 को नामीबिया की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने रॉसिंग दक्षिण में यूरेनियम खान स्वाकोपमुंड का दौरा किया तथा नामीबिया की कई पार्टियों से विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान खान व ऊर्जा मंत्री श्री एरक्की एनघीमितिया तथा व्यापार व उद्योग मंत्री डॉ. हेग जीनगोब से मुलाकात की।

डायमंड इंडिया लि. के अध्यक्ष श्री पीएस पाण्ड्या की अध्यक्षता में इसके 4-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नामीबिया की यात्रा की तथा नामीबिया से कच्चे हीरे प्राप्त करने के लिए नामीबिया डायमंड ट्रेडिंग कंपनी (एनडीटीसी) से विचार-विमर्श किया। डीआईएल 25 जून, 2009 को एनडीटीसी से हीरों की प्रत्यक्ष खरीद करने में सफल रही। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय पार्टी ने सीधे ही नामीबिया से हीरों की खरीद की है।

युवा, राष्ट्रीय सेवा, खेल व संस्कृति मंत्री श्री विलियम केंजार तथा भारत के उच्चायुक्त श्री सेबांग तोपदेन ने 7 अक्तूबर, 2009 को भारत सरकार की अनुदान सहायता के अंतर्गत स्थापित आईटी कियोस्क (हाल-इन-द-बॉल परियोजना) का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया।

नामीबिया के रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव ने 1 अप्रैल, 2009 को बिंडराक में हिदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. द्वारा नामीबिया रक्षा मंत्रालय को 2 चेतक व 1 चीता हैलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए। संविदा का कुल मूल्य 9.515 मिलियन अमरीकी डालर था।

भारत-अफ्रीका विदेश सम्मेलन, 2008 में लिए गए निर्णयों के भाग के रूप में भारत विदेश व्यापार संस्थान ने नामीबिया के व्यापार व उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 21 सितम्बर-2 अक्तूबर, 2009 तक बिंडहाक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 2-दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया था।

नामीबिया वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल मार्टिन पिनेहास के नेतृत्व में 2-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 5-10 दिसम्बर, 2009 तक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) बैंगलूर का दौरा किया तथा नामीबिया रक्षा बलों द्वारा खरीदे जा रहे 3 हैलीकॉप्टरों के संबंध में तकनीकी विचार-विमर्श किया। एचएएल द्वारा नामीबिया के रक्षा मंत्रालय को 2 चेतक व 1 चीता हैलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए संविदा पर 1 अप्रैल, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।

नामीबिया राष्ट्रीय सभा की सांविधानिक व विधि कार्य संबंधी स्थायी समिति के 6-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय अध्ययन व प्रशिक्षण ब्यूरो, लोकसभा सचिवालय के साथ अध्ययन दौरे के लिए 14-18 दिसम्बर, 2009 तक नई दिल्ली की यात्रा की।

राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के अध्यक्ष डॉ. थियो बेन गुरिरेब तथा राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष श्री एसर कापेरे ने 4-8 जनवरी 2010 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों व पीठासीन अधिकारियों के 20वें सम्मेलन में भाग लिया।

राष्ट्रपति पोहाम्बा की भारत की सरकारी यात्रा के दौरान 31 अगस्त, 2009 को हस्ताक्षरित पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की प्रारम्भिक प्रक्रिया चल रही है। टेलिकम्यूनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लि. (टीसीआईएल) से एक दल द्वारा नामीबिया पक्ष के साथ कार्यान्वयन कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए जनवरी-फरवरी, 2010 में नामीबिया यात्रा करने की संभावना है।

रवाण्डा

रवाण्डा के साथ भारत के संबंध 2009 में और मजबूत हुए थे।

बीएचईएल द्वारा न्याबारोगों नदी पर कार्यान्वित की जा रही 27.5 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण की दूसरी किस्त अनुमोदित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वाणिज्यिक आसूचना व सांख्यिकी महानिदेशालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत से रवाण्डा निर्यात की राशि लगभग 29.31 मिलियन अमरीकी डालर (126.83 प्रतिशत वृद्धि) तथा रवाण्डा से भारत आयात की राशि 2.35 मिलियन अमरीकी डालर (253.55 प्रतिशत वृद्धि) थी।

रवाण्डा के वित्त व आर्थिक नियोजन मंत्री श्री जॉन खांगोम्बवा ने रवाण्डा को प्रदान किए गए 60 मिलियन अमरीकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण के संबंध में एग्जिम बैंक के साथ श्रृंखलाबद्ध करार पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से 14-16 जनवरी, 2010 तक नई दिल्ली की यात्रा की थी।

सेशल्स

वर्ष 2009-10 के दौरान भारत तथा सेशल्स के मध्य व्यापक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी।

श्री नलिन सूरी, सचिव (पश्चिम) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा 12-13 मई, 2009 को सेशल्स की यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने सेशल्स के राष्ट्रपति श्री जेम्स माइकल तथा उपराष्ट्रपति श्री जोजेफ बेलमंट से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री श्री पैट्रिक पिल्लै तथा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन व परिवहन मंत्री श्री जोएल मार्गन के साथ बैठक की।

रियर एडमिरल वीएस चौधरी के नेतृत्व में नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल ने सितम्बर, 2009 में सेशल्स की यात्रा की। भारत सेशल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास/प्रशिक्षण दल नवम्बर, 2009 में सेशल्स में आयोजित किया गया। सेशल्स रक्षा बलों के प्रमुख बिग्रेडियर लेपाल्ड पापेल ने 26 जुलाई-1 अगस्त, 2009 तक भारत की यात्रा की। भारतीय नौसैनिक जहाज निर्देशक (अप्रैल, 2009), आईएनएस मतंग (मई, 2009), आईएनएस त्रिशूल (जून, 2009), आईएनएस शारदूल व भारतीय तटरक्षक जहाज, आईसीजीएस वरूण (अक्तूबर, 2009) तथा आईएनएस सावित्री (नवम्बर, 2009) ने सौहार्द यात्रा के रूप में व दस्युता विरोधी अभियान के लिए सेशल्स की यात्रा की। भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी ने 18 जून, 2009 को सेशल्स की राष्ट्रीय दिवस परेड में भाग लिया। सेशल्स सरकार के 19 सिविल व 10 रक्षा कार्मिकों ने इस वर्ष भारत सरकार के भारतीय तकनीकी व आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंध भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता रहे हैं तथा दोनों देशों में राष्ट्रीय चुनावों के बाद गठित नई सरकारों ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक सहभागिता के महत्व की सशक्त रूप से पुनः पुष्टि की है। पूरे वर्ष के दौरान मंत्रालयी स्तरीय आदान-प्रदान, वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राएं तथा द्विपक्षीय तंत्रों की बैठकें चलती रही। जलवायु परिवर्तन, विश्वस्तरीय वित्तीय स्थिति, यूएन व्यवस्था में सुधार तथा विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर जैसे बहुपक्षीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग घनिष्ठ व प्रभावशाली रहा।

उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने मई, 2009 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में डॉ. जैकब जुमा के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मंत्री स्तरीय यात्राओं में वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा के साथ सरकारी व व्यापार प्रतिनिधिमंडल की 21-24 अगस्त, 2009 तक दक्षिण अफ्रीका यात्रा शामिल थी, जिसके दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डॉ. जैकब जुमा, उपराष्ट्रपति श्री केगलेमा मोटलांथी तथा अपने समकक्ष व्यापार व उद्योग मंत्री रॉब डेविस सहित अफ्रीकी ओर से कई मुख्य मंत्रियों के साथ मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने व्यापारी नेताओं के साथ भी बातचीत की। दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध व सहयोग मंत्री सुश्री मायते एन कोआना-माशाबने ने नवम्बर, 2009 में भारत की यात्रा की। उन्होंने 13 नवम्बर, 2009 को विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा के साथ व्यापक स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत की। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने अगस्त में ब्रासीला में आईबीएसए मंत्रालयी बैठक के अवसर पर तथा सितम्बर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के दौरान अपने दक्षिण अफ्रीकी समकक्ष के साथ भी मुलाकात की।

दक्षिण अफ्रीका के लिए अन्य मंत्रालयी बैठकों में कोयला सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के महालानोबिस पुरस्कार

प्रदान करने के लिए अगस्त में डरबन यात्रा भी शामिल है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी, संसदीय कार्य, पृथ्वी विज्ञान तथा कार्मिक व प्रशिक्षण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पृथ्वीराज चव्हान ने अक्तूबर, 2009 में विश्व विज्ञान एकेडमी के तीसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए डरबन की यात्रा की। इस सम्मेलन के अवसर पर आईबीसीए विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सरकारी व व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जोहानसबर्ग व केपटाउन की यात्रा की। केरल के उद्योग मंत्री श्री इलामराम करीम ने दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों व केरल के बीच व्यापार संवर्धित करने की सहायता का पता लगाने के लिए सितम्बर, 2009 में जोहानसबर्ग की यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका की ओर से व्यापार व उद्योग मंत्री श्री रॉव डेविस ने विश्व व्यापार संगठन की अनौपचारिक मंत्रालयी बैठक के लिए सितम्बर, 2009 में भारत की यात्रा की।

वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय यात्राओं में जोहानसबर्ग व केपटाउन मेगा टेक्सटाइल शो के लिए मार्च, 2009 में सचिव, कपड़ा मंत्रालय, की यात्रा, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ की तैयारियों के संबंध में अक्तूबर, 2009 में सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, की डरबन व जोहानसबर्ग यात्रा तथा सितम्बर व अक्तूबर, 2009 में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग से वरिष्ठ अधिकारियों की यात्रा शामिल है। अन्य यात्राओं में उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की आम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए सितम्बर, 2009 में केपटाउन की यात्रा शामिल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री विनोद रॉय ने सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कार्यपालक समिति की बैठक के लिए नवम्बर, 2009 में केपटाउन की यात्रा की।

एडमिरल सुरीश मेहता, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) तथा नौसेना अध्यक्ष (सीएनएस) ने दक्षिण अफ्रीकी नौसेना अध्यक्ष के निमंत्रण पर जून, 2009 में दक्षिण अफ्रीका का 4 दिवसीय दौरा किया। उन्होंने सेवा स्तरीय संपर्क के अलावा कार्यकारी रक्षा सचिव से भी मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान प्रचालनात्मक संपर्क, प्रशिक्षण में पारस्परिक सहयोग, सूचना का आदन-प्रदान तथा आईओएनएस पहल (जिसका भारत इस समय अध्यक्ष है) से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। रक्षा सहयोग से संबंधित अन्य यात्राओं में वाइस एडमिरल आरपी सूथन, नौसेना के उपाध्यक्ष की मई, 2009 की यात्रा शामिल है, जो दक्षिण अफ्रीका में बीसीसीआई के निदेशक मंडल की यात्रा के भाग के रूप में थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों देशों की नौसेनाओं के विकास व दीर्घावधिक नियोजन के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी नौसेना अध्यक्ष से भी मुलाकात की। भारतीय नौ सेना के कार्मिक अध्यक्ष वाइस एडमिरल डी.के. दिवान ने दोनों नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण संबंधी पहल पर चर्चा करने के लिए अप्रैल, 2009 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की।

द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत बने रहे, परंतु 2009 में विश्वव्यापी वित्तीय संकट तथा दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाने के कारण द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुआ। 2007 में व्यापार 6.27 अमरीकी डालर था, जो कि 3 प्रतिशत घटकर 2008-09 में 6.10 मिलियन अमरीकी डालर हो गया, जिसमें भारत के आयातों की राशि 4.55 बिलियन अमरीकी डालर तथा दक्षिण अफ्रीका को हमारे निर्यातों का मूल्य 1.55 बिलियन अमरीकी डालर था। दक्षिण अफ्रीकी व्यापार समारोह में भारत की सहभागिता जारी रही। सीआईआई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल, 2009 जोहानसबर्ग में आयोजित 11वीं वार्षिक विद्युत एवं बिजली कांग्रेस, 2009 में भाग लिया। आईटीपीओ के नेतृत्व में 30-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2009, में जोहानसबर्ग में सेटेक्स तथा अफ्रीका बिग सेवन प्रदर्शनी में भाग लिया। 'भारत के साथ व्यापार' का दूसरा सम्मेलन जुलाई, 2009 में जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया था। इस वर्ष के संस्करण की मुख्य विशेषता फार्मास्युटिकल्स उद्योग पर विशेष सत्र था तथा फार्मेक्सिल से 20 मध्यम आकार की कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्मेलन के दौरान अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। महाराष्ट्र इस सम्मेलन का सहभागी राज्य था तथा इसे प्रदर्शित करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। रसायन व संबंधित उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अगस्त, 2009 में जोहानसबर्ग में डेकोरेकस प्रदर्शनी में भाग लिया। जनवरी, 2010 में मुम्बई में आयोजित किए जाने वाले 'इलैक्ट्रामा 2010' का प्रचार करने के लिए भारतीय इलैक्ट्रिक व इलैक्ट्रानिक विनिर्माता संघ के प्रतिनिधिमंडल के लिए नवम्बर, 2009 में जोहानसबर्ग में एक रोड शो आयोजित किया गया था। राइटस के महाप्रबंधक ने नवम्बर, 2009 में नई आर्थिक सहभागिता व विकास परिवहन सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। खेल वस्तु निर्यात संवर्धन परिषद के नेतृत्व में भारत खेल वस्तु निर्माताओं के 10-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नवम्बर-दिसम्बर, 2009 में सोकरेक्स प्रदर्शनी के लिए जोहानसबर्ग की यात्रा की।

जोहानसबर्ग में विटवाटरस्रेंड विश्वविद्यालय में 2008 में अफ्रीका में भारतीय अध्ययन केंद्र शुरू होने से शैक्षणिक सहयोग और मजबूत हुआ, जोकि अक्तूबर, 2009 में सीआईएसए के अध्यक्ष के रूप में एक विख्यात भारतीय इतिहासकार की नियुक्ति से और आगे बढ़ा। गॉर्डन व्यापार विज्ञान संस्थान के मध्यम/वरिष्ठ स्तरीय प्रबंध कार्यपालकों के मिड कैरियर प्रशिक्षण के लिए विश्वस्तरीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम (जीईडीपी) से 65 कार्यपालकों के एक समूह ने सितम्बर, 2009 में भारत की यात्रा की थी। 100-सदस्यीय रेल प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका की सरकारी परिवहन कंपनी ट्रांसनेट के साथ संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फरवरी से मई, 2009 में जोहानसबर्ग की यात्रा की।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रत्यायोजित भरत नाटयम्, संगीत व भंगड़ा मंडली सहित कई संस्कृति मंडलियों ने दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न नगरों की यात्रा की। 'साझा इतिहास' का

तीसरा संस्करण सितम्बर-अक्तूबर, 2009 में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नृत्य, संगीत, कला, व्यंजन व साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री श्री प्रवीन गोरधन ने 6-9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान के लिए भारत की यात्रा की थी। दक्षिण अफ्रीका के जल व पर्यावरण कार्य मंत्री सुश्री बुएलवा सोनजिका ने 23-25 जनवरी, 2010 तक बेसिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

खान मंत्रालय के विशेष सचिव श्री विजय कुमार ने 31 जनवरी-5 फरवरी, 2010 तक केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में माईनिंग इनडाबा में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

स्वाजीलैंड

स्वाजीलैंड अफ्रीकी संघ (एयू) व दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) का एक सक्रिय सदस्य है। भारत ने 1971 में स्वाजीलैंड के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। स्वाजीलैंड के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण व मैत्रीपूर्ण रहे। भारत सरकार ने सितम्बर, 2009 में स्वाजीलैंड में विज्ञान व प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए 10 मिलियन अफ्रीकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण स्वीकृत किया था। वर्ष 2009-10 में स्वाजीलैंड के लिए आईटीईसी के अंतर्गत 17 प्रशिक्षण स्थान स्वीकृत किए गए थे। आईसीसीआर जीसीएसएस योजना के अंतर्गत स्वाजीलैंड को 2 छात्रवृत्तियां भी प्रस्तावित की गई थी।

वर्ष 2007-08 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार की राशि 47.52 मिलियन अमरीकी डालर थी, जबकि गत वर्ष में यह राशि 61.57 मिलियन अमरीकी डालर थी। भारतीय निर्यातों का मूल्य 10.35 मिलियन अमरीकी डालर तथा आयातों का मूल्य 37.17 मिलियन अमरीकी डालर था।

तंजानिया

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तंजानिया के साथ भारत के पारम्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण व मैत्रीपूर्ण संबंधों में विस्तार होता रहा।

भारत सरकार द्वारा दार-ए-सलाम विश्वविद्यालय व दार-ए-सलाम प्रौद्योगिकी संस्थान में पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के कार्यान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने से सूचना प्रौद्योगिकी व संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों में भी विस्तार हुआ।

आर्थिक क्षेत्र में तंजानिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार व निवेश नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, क्योंकि वर्ष 2008 में तंजानिया के साथ भारत का व्यापार 1.03 अमरीकी डालर था, जो कि तंजानिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार सहभागी था तथा निवेश के रूप में 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक राशि के कारण भारत तंजानिया में सबसे बड़ा निवेशक था।

तंजानिया द्वारा जुलाई, 2009 में 'किलिमो क्वांजा-कृषि प्रथम' घोषणा के बाद तंजानिया के प्रधानमंत्री श्री मिजिगों क्वांजा पीटर पिंडा ने सितम्बर, 2009 में भारत की यात्रा की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तंजानिया के कृषि व खाद्य सुरक्षा मंत्री व कृषि, पशुधन व पर्यावरण के लिए जांजीबार मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री पिंडा ने भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम हामिद अंसारी से मुलाकात तथा विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा के साथ बैठक की। यह यात्रा मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा व कृषि विकास पर केंद्रित थी। जिसका विशेष उद्देश्य भारत के साथ सहयोग को मजबूत बनाना तथा इसके अनुभवों से सीखना था।

तंजानिया के उद्योग, व्यापार व विपणन मंत्री डॉ. मैरी नागु ने हमारे वाणिज्यिक व उद्योग मंत्री के निमंत्रण पर 2-4 सितम्बर, 2009 तक नई दिल्ली में विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दोहा दौर पर अनौपचारिक मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। चूंकि, तंजानिया विश्व व्यापार संगठन के मामले में अल्प विकसित देशों की वार्ता के लिए प्रवक्ता है, इसलिए तंजानिया के मंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण थी।

भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने 55वें राष्ट्रीयमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए संसदीय व राज्य विधान सभा के अध्यक्षों के एक दल का नेतृत्व करते हुए 28 सितम्बर-6 अक्तूबर, 2009 तक अरुषा तंजानिया की यात्रा की थी।

संस्कृति, स्वास्थ्य देखरेख व उच्च अध्ययनों सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में भी विस्तार हुआ है। भारत आधुनिक चिकित्सा उपचार के लिए मुख्य गंतव्य स्थल के रूप में उभरा है। चूंकि, स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र में सहयोग एक तीव्र विकासशील क्षेत्र बन गया है, इसलिए अपोलो अस्पताल से एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सुविधाओं का आंकलन करने, बाह्य रोगियों की समीक्षा करने, स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण मंत्रालय के साथ आदान-प्रदान व विचार-विमर्श करने के लिए जुलाई, 2009 में दार-ए-सलाम की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान तंजानिया के स्वास्थ्य मंत्रालय व प्रतिनिधिमंडल ने दार-ए-सलाम में उच्च विशेषज्ञता वाला अस्पताल स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पर और विचार-विमर्श किया। तंजानिया योजना आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रबंधन व नियोजन में योजना आयोग की भूमिका व कार्य परिचालन में भारतीय अनुभवों से सीखने के लिए मई, 2009 में भारत की यात्रा की। तंजानिया के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक श्री एलएसएल उत्तोह ने भारतीय प्रणाली का अध्ययन करने तथा दोनों संस्थानों के बीच कार्यकारी संबंध मजबूत बनाने के लिए अक्तूबर, 2009 में भारत की यात्रा की थी।

तंजानिया अफ्रीका में शैक्षणिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम तथा आईटीईसी का सबसे बड़ा लाभार्थी बना रहा। उपरोक्त 2 कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्यायोजन के अलावा भारत तंजानिया के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से समान शिक्षा माध्यम व लागत के कारण से उच्चतर शिक्षा जारी रखने का एक अधिमान्यता प्राप्त गंतव्य स्थल है।

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने तंजानिया व्यापार मेला, 2009 में भाग लेने के लिए तंजानिया की यात्रा की। लगभग 7 भारतीय कंपनियों ने 2-4 दिसम्बर, 2009 तक प्रदर्शनी में अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही इलैक्ट्रोनिक व कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के 12 कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल ने 3 दिसम्बर, 2009 को तंजानिया की यात्रा की थी तथा क्रेता-विक्रेता भेंट आयोजित की थी। क्रेता-विक्रेता भेंट के दौरान तंजानिया की लगभग 35 भावी कंपनियों ने भाग लिया। इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने संचार तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्थायी सचिव से भी मुलाकात की तथा कर्मचारियों के समक्ष ई-प्रशासन, ई-प्राप्ति तथा भारत में विकसित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क पर प्रस्तुतिकरण दिया गया।

सांस्कृतिक क्षेत्र में आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित चार सदस्यीय भरतनाट्यम नृत्य मंडली ने अप्रैल, 2009 में तंजानिया की यात्रा की। इस नृत्य मंडली ने दार-ए-सलाम तथा जंजीबार, दोनों में प्रस्तुतियां कीं।

युगाण्डा

युगाण्डा के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण बने रहे। वर्ष के दौरान युगाण्डा से भारत में कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई। इन यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रेसीडेंसी प्रभारी मंत्री डॉ. बीटराइस वाबुदेया, उपमहान्यायवादी/ न्याय व सांविधानिक कार्य राज्य मंत्री, श्री प्रेडी रूहिंदी ने कैडिला के साथ विचार-विमर्श करने के लिए 30-31 मई, 2009 को अहमदाबाद की यात्रा की थी। प्रतिनिधिमंडल ने 2-3 जून, 2009 को सिपला के साथ विचार-विमर्श करने के लिए गोआ की यात्रा भी की थी।

आंतरिक कार्य राज्य मंत्री श्री मतिया कासिजा ने जून, 2009 में भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन के साथ मुलाकात की।

शहरी विकास राज्यमंत्री श्री अरबन तिबामान्या ने 12-18 जुलाई, 2009 तक भारत की यात्रा की थी। उन्होंने 14 जुलाई, 2009 को शहरी विकास राज्य मंत्री श्री सौगात राय तथा 15 जुलाई, 2009 को रेल राज्य मंत्री श्री ई. अहमद से मुलाकात की। युगाण्डा के राज्य मंत्री ने 15 जुलाई, 2009 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी तथा वित्त मंत्री से भी मुलाकात की।

युगाण्डा गणराज्य के कृषि राज्य मंत्री श्री खामीरामा के ब्राइट ने 5-9 अक्तूबर, 2009 तक भारत की यात्रा की थी। उन्होंने 8 अक्तूबर, 2009 को कृषि, उपभोक्ता कार्य, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री प्रो. केवी थामस से मुलाकात की तथा कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा इसकी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दोनों देशों के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मात्स्यिकी के प्रभारी कृषि राज्य मंत्री श्री प्रेड मुकीसा ने युगाण्डा में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयोगी तकनीकों का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय दौरे के रूप में 21-28 अक्तूबर, 2009 तक भारत की यात्रा की।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय के अंनतिम आंकड़ों के अनुसार भारत से युगाण्डा निर्यातों की राशि लगभग 217.90 मिलियन अमरीकी डालर (41.75 प्रतिशत वृद्धि) थी तथा युगाण्डा से भारत आयात की राशि 19.14 मिलियन अमरीकी डालर (26.56 प्रतिशत वृद्धि) थी।

एसोचैम से एक दो- सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने युगाण्डा सरकार के कृषि, पशुपालन तथा मात्स्यिकी मंत्री के निमंत्रण पर 23 अगस्त, 2009 से एक सप्ताह के लिए युगाण्डा की यात्रा की थी।

युगाण्डा के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संगठन (नारो), एनटैबी से छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-29 मई, 2009 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों का दौरा किया।

केपेक्सिल ने 28-29 सितम्बर, 2009 को प्रतिदेयता के रूप में क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की, जो दक्षिण एशिया प्रिंट कांग्रेस के अवसर पर आयोजित की गई थी। युगाण्डा के चार निर्यातकों ने गोआ में क्रेता-विक्रेता भेंट में भाग लिया तथा केपेक्सिल ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को वायुयान का किराया प्रदान किया।

पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने तेल के गवेषण व उत्पादन के क्षेत्र में युगाण्डा के साथ सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए 27-28 जनवरी, 2010 को युगाण्डा की यात्रा की थी।

जाम्बिया

मैत्री, पारस्परिक सूझ-बूझ तथा सहयोग के सिद्धांत भारत-जाम्बिया संबंधों की विशेषताएं हैं। राष्ट्रपति रुपिआ बांदा ने मुम्बई आतंकवादी हमलों पर भारत के साथ सहानुभूति व्यक्त की। जाम्बिया के खान मंत्री श्री मेक्सवेल म्वाले, जोकि 15 अगस्त, 2009 को राजदूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में जाम्बिया का समर्थन व्यक्त किया।

द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 40 प्रतिशत की सतत वृद्धि हुई थी। 2006-07 की अपेक्षा 2007-08 में जाम्बिया को भारत के निर्यातों में 29.08 प्रतिशत तथा जाम्बिया से भारत के आयातों में 35.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउसिंल ऑफ इंडिया (फार्माक्सिल) के 25-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 3-6 अगस्त, 2009 तक जाम्बिया की यात्रा की थी। 4 अगस्त, 2009 को एक क्रेता-विक्रेता भेंट आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन जाम्बिया के उपवाणिज्य व्यापार

व उद्योग मंत्री, श्री रिचर्ड तायमा द्वारा किया गया। जाम्बिया के भेषज विनियंत्रण, महानिदेशक सुश्री इस्नत म्वाये, फार्मा नोवा जाम्बिया लिमिटेड के महानिदेशक श्री राकेश एन. शाह तथा एलायंस फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड जाम्बिया के प्रबंध निदेशक श्री एम कृष्णा स्वामी ने 25-27 सितम्बर, 2009 तक हैदराबाद में आयोजित भारत-अफ्रीका भेषज व्यापार बैठक में भाग लिया।

टेलीक्म्यूनिकेशेन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमटेड (टीसीआईएल) ने जाम्बिया में भारत के पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत दूर-शिक्षा, दूर-चिकित्सा व राज्य अध्यक्षों के लिए टेली कांफ्रेंसिंग की सुविधाएं स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया है। आईटीईसी नागरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जाम्बिया को 75 स्थान आवंटित किए गए हैं। जाम्बिया ने इनमें से अधिकांश स्थानों का उपयोग कर लिया है।

लैफ्टिनेंट जनरल एसपीएस ढिल्लों, डीसीओएएस (आईएसएंडटी) ने 18-21 मार्च, 2009 तक जाम्बिया की यात्रा की तथा जाम्बिया के कार्यवाहक रक्षामंत्री डिप्टी आर्मी कमांडर, डिप्टी एयर कमांडर तथा रक्षा सेवा कमान व स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट से मुलाकात की। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) के 19-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-15 मई, 2009 तक जाम्बिया की यात्रा की थी। उन्होंने अन्य अधिकारियों सहित जाम्बिया के उप-रक्षा मंत्री तथा जाम्बिया के सेनाध्यक्ष व जाम्बिया के वायुसेनाध्यक्ष से मुलाकात की। यह एनडीसी दल की प्रथम जाम्बिया यात्रा थी। अपर महानिदेशक (स्टाफ ड्यूटी) मेजर जनरल चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में एक दो-सदस्यीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने 3-6 जून, 2009 तक लुसाका में डीएससीएसई से संबद्ध भारतीय सैन्य परामर्शी दल के कार्य के संबंध में जाम्बिया की यात्रा की।

उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सलमा अंसारी ने 5-7 जनवरी, 2010 तक जाम्बिया की सरकारी यात्रा की। उनके साथ श्रम व रोजगार राज्य मंत्री श्री हरीश रावत, संसद के 3 सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी व मीडिया भी था। उपराष्ट्रपति के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने अलग से यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने जाम्बिया में विकास परियोजनाओं के लिए 75 मिलियन अमरीकी डालर के नए श्रृंखलाबद्ध ऋण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा की। जाम्बिया की इतेजही तैजही जल विद्युत परियोजना जिसमें टाटा व जैसको संयुक्त उद्यम सहभागी हैं, के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान करने के लिए भारत के एक्जिम बैंक व जाम्बिया के वित्त व राष्ट्रीय नियोजन मंत्रालय के बीच ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

जिम्बाब्वे

सत्ताधारी जानु-पीएफ तथा लोकतांत्रिक परिवर्तन आंदोलन के दो दलों के बीच फरवरी, 2009 में स्थापित कमजोर गठबंधन से संबंधित समस्याओं के कारण जिम्बाब्वे की स्थिति अस्थिर बनी रही। राष्ट्रपति रोबर्ट मुगावे जोकि 1980 में इसकी स्वतंत्रता से ही देश पर शासन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री मोरगन स्वाननगीराई के साथ सत्ता में शामिल होने के अनिच्छुक हैं।

चूंकि, यूरोपीय संघ ने सितम्बर, 2009 में जिम्बाब्वे के राजनैतिक दलों के सभी नेताओं से मुलाकात करने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जोकि 2002 के बाद प्रथम है; भेजा था, इसलिए जिम्बाब्वे के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संबंध पुनर्स्थापित होने के संकेत हैं।

जिम्बाब्वे के साथ भारत के संबंध निकट और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्बाब्वे को सहायता, क्षमता निर्माण के लिए जिम्बाब्वे को भारतीय सहायता की नियमित विशेषता रही है। आईटीईसी सफल है तथा जिम्बाब्वे में अत्यधिक वांछित कार्यक्रम है। 1985 में जिम्बाब्वे के 3 व्यक्तियों से शुरू लगभग 400 व्यक्तियों को आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में अल्पावधिक नागरिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। 2009 के दौरान उपयोग किए गए स्थानों की संख्या बढ़कर 100 हो गई थी।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय दूतावास ने वेस्टरीज हाईस्कूल तथा हिंदू सोसायटी ऑफ हरारे के साथ मिलकर 2 अक्तूबर, 2009 को गांधी पद यात्रा तथा चित्रकला प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री प्रो. डब्ल्यू एनक्यूबे ने वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा के निमंत्रण पर विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दोहा दौर में अनौपचारिक मंत्रालयी बैठक में भाग लेने के लिए 3-4 सितम्बर, 2009 को भारत की यात्रा की थी। सीआईआई के 13-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिम्बाब्वे में व्यापार/निवेश अवसरों का पता लगाने के लिए 23 से 25 जून, 2009 तक हरारे की यात्रा की थी।

हरारे प्रौद्योगिकी संस्थान में अवस्थित भारत- जिम्बाब्वे प्रौद्योगिकी केंद्र में टूल एंड डाई वर्कशाप में मशीनों के स्थापन तथा चितुंगवीजा तथा बुलावायो में लघु उद्यम विकास निगम (एसईडीसीओ) में सामान्य सुविधाओं से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है तथा भारतीय विशेषज्ञ, तकनीशियनों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

भारत ने 1-6 मई, 2009 तक हरारे में आयोजित वार्षिक हरारे अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में भाग लेना जारी रखा। भारत ने 24 अगस्त-2 सितम्बर, 2009 तक हरारे में आयोजित जिम्बाब्वे के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी भाग लिया। 30 नवम्बर से 8 दिसम्बर, 2009 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला छवि फिल्म महोत्सव में एक भारतीय फिल्म 'विलापेगंलकापुरम' (दीवार के पार) प्रदर्शित की गई थी।

भारत ने हरारे में स्थित अफ्रीका क्षमता निर्माण फाउंडेशन (एसीबीएफ) की बैठकों में भाग लेना व विचार-विमर्श करना

जारी रखा, जोकि अफ्रीका में सतत विकास व गरीबी उन्मूलन के लिए मुख्य संस्थान है। भारत एसीबीएफ का पूर्णकालिक सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश है।

अफ्रीकी संघ

अफ्रीकी संघ के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का चौथा सत्र 'अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंचः मातृत्व, नवजात शिशु व बच्चा स्वास्थ्य में सुधार' के शीर्षक पर 7-8 मई, 2009 को अदीस अबाबा में आयोजित किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों की बैठक 4-6 मई, 2009 को हुई थी। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री राजीव खैर ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया तथा इस प्रतिनिधिमंडल के साथ फार्मेक्सिल के कार्यकारी निदेशक, रेनबैक्सी जैसी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सदस्य तथा अरबिंदो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड व डाक्टर रेड्डी की प्रयोगशाला के सदस्य भी थे। इस प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य कुछ अफ्रीकी देशों के मन से यह डर निकालना था कि भारत द्वारा उत्पादित तथा कई देशों को प्रेषित सजातीय दवाइयां घटिया स्तर की तथा नकली थी। अपने प्रवास के दौरान इस प्रतिनिधिमंडल ने केन्या, युगांडा, जाम्बिया, सूडान, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया तथा क्लिंटन फाउंडेशन, पीएसआई इथोपिया, एससीएमएस, जैसे कई गैर-सरकारी संगठनों के आगंतुक प्रतिनिधिमंडलों से विचार-विमर्श किया तथा उन्हें यह स्पष्ट किया कि सजातीय दवाइयों पर पेटेंटेड दवाइयों का उपयोग कैसे किया जाता है।

पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क संचालन समिति की छठी बैठक 7-8 मई, 2009 को अदीस अबाबा में आयोजित की गई थी। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के राजदूत, जोकि अफ्रीकी यूनियन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी हैं, तथा अवस्थापना संबंधी कार्यों के लिए अफ्रीकी संघ के आयुक्त डॉ. इलहाम एम.ए. इब्राहीम ने की थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. औसुफ सईद, संयुक्त सचिव (पश्चिम अफ्रीका) ने किया था, जिनके साथ टीसीआईएल, इग्नू, एमिटी विश्वविद्यालय तथा अपोलो अस्पताल के प्रतिनिधि भी थे। 20 से अधिक सदस्य देशों से प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

अफ्रीकी यूनियन तथा आर्थिक अफ्रीकी आयोग के स्थायी प्रतिनिधित्व वाले तथा अंतर सरकारी विकास प्राधिकरण (आईजीएडी) में भागीदार का दर्जा रखने वाले मिशन ने विभिन्न शीर्ष बैठकों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ आदान-प्रदान सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। अप्रैल, 2008 में सर्वप्रथम अफ्रीकी-भारत मंच सम्मेलन की भारत द्वारा मेजबानी के बाद अफ्रीकी संघ के साथ भारत के संपर्कों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 के दौरान आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत ईसीए को 15 स्लॉट तथा अफ्रीकी संघ को 15 स्लॉट प्रदान किए गए थे।

अप्रैल, 2008 में अंतर अभिकरणीय किशोर महिला उपसमिति (आईएएफएस) की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में श्री गुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव, (पूर्व व दक्षिण अफ्रीका) ने 4 दिसम्बर, 2009 को अदीस अबाबा की यात्रा की तथा संयुक्त कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श किया। अफ्रीकी संघ से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा अगले वर्ष के प्रारंभ में भारत की यात्रा किए जाने की संभावना है, ताकि संयुक्त कार्य योजना को घोषित किया जा सके।

विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने अदीस अबाबा में चल रहे अफ्रीकी संघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए 27-30 जनवरी, 2010 तक अदीस अबाबा की यात्रा की। उन्होंने एक पर्यवेक्षक के रूप में मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।

इथोपिया के प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करने के अलावा राज्य मंत्री ने अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष श्री जिनपिंग से विचार-विमर्श किया। राज्य मंत्री ने अफ्रीकी संघ के चिकित्सालय में पेन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना के एक दूर-चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। भारत-अफ्रीकी मंच सम्मेलन, 2008 के निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अफ्रीकी संघ के साथ संयुक्त कार्य योजना पर विचार-विमर्श किया गया था।

राज्य मंत्री ने अफ्रीकी संघ सम्मेलन के अवसर पर 15 अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की तथा द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

पूर्व व दक्षिण अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा)

भारत कोमेसा का एक सहकारी साझेदार है। जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त, जोकि लुसाका स्थित कोलेसा सचिवालय में भारत के विशेष प्रतिनिधि हैं, ने 7-8 जून, 2009 को जिम्बाव्वे में विक्टोरिया फालटाउन में आयोजित 13 वें कोमेसा सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने कोमेसा में एक ऊर्जा विशेषज्ञ भी प्रतिनियुक्त किया है, जिसने जून, 2009 में एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति पूरी कर ली है तथा कोमेसा एकीकृत ऊर्जा नियोजन रणनीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, पीटीए बैंक को श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान करता रहा है, जिसे कोमेसा देशों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक 60 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि प्रदान की है।

भारत-कोमेसा व्यापार 2007 में 5.31 बिलियन से बढ़कर 2008 में 8.9 बिलियन हो गया था, जिसमें 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भारत-अफ्रीकी परियोजना साझेदारी कॉनक्लेव के दौरान कोमेसा व्यापार परिषद (सीबीसी) ने 23 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आर्थिक वाणिज्य व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीबीसी व भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच सहयोग के लिए ढांचा प्रदान करता है।

पश्चिम अफ्रीका

बेनिन

डॉ. शशि थरूर, विदेश राज्य मंत्री ने 22-23 अक्तूबर, 2009 को कोटोनू में भारत बेनिन संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वर्ष 2009-12 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए थे।

केप वेर्डे

केप वेर्डे गणराज्य के विदेश कार्य, सहयोग व समुदाय मंत्री डॉ. जॉज ब्रिटो ने 18-21 नवंबर, 2009 तक भारत की यात्रा की थी। सरकारी स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का और विस्तार करने और इन्हें मजबूत बनाने के तौर-तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेशी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। केप वेर्डे ने वर्ष 2011-12 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के उम्मीदवार का समर्थन करने का वचन दिया। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताएं पूरा करने के लिए 10 मिलियन रुपए के अनुदान के अलावा प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। केप वेर्डे में एक सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की प्रस्ताव भी है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

विदेश कार्य मंत्री श्री एलैक्सीस थाम्बवे म्वाम्बा ने 27-30 अक्तूबर, 2009 तक भारत की यात्रा की थी। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा के साथ सरकारी स्तर पर वार्ता आयोजित की गई थी, जिसके दौरान विद्युत व रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 263 मिलियन अमरीकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण की घोषणा की गई थी। भारत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में होल-इन-द वॉल परियोजना के अंतर्गत एक सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र तथा तीन कार्यकारी केंद्र स्थापित करने तथा कांगोलाई महिलाओं को बेयरफूट महाविद्यालय, राजस्थान में सौर विद्युतीकरण तथा जल संचयन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा है।

कांगो गणराज्य

भारत ने कांगो गणराज्य को 9.4 मिलियन रुपए की दवाओं की एक खेप दान की।

घाना

डॉ. शशि थरूर, विदेश राज्य मंत्री ने 19 सितंबर, 2009 को अकरा में अल्प प्रवास किया, जिसके दौरान उन्होंने राष्ट्रपति श्री जोन इवांस अट्टा मिल्स से मुलाकात की थी।

लाइबेरिया

विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने 16-19 सितंबर, 2009 तक लाइबेरिया की यात्रा की थी। उन्होंने राष्ट्रपति श्रीमती रालन जोनसन सरलीफ से मुलाकात की तथा कार्यवाहक विदेश मंत्री श्री बिलियन वी.एस. बुल के साथ व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श के लिए एक प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्रों, 25 भारत निर्मित बसों; एक सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र; हॉल-इन-द वॉल कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना के अंतर्गत दो पाठ्य केंद्र व लाइबेरियाई राजनयिक व पुलिस कार्मिक के लिए क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण में तत्काल आवश्कताओं को पूरा करने के लिए 2 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान के रूप में लाइबेरिया को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। भारत से 125 सदस्यों की महिला पुलिस इकाई संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना दल का भाग है, जिसकी तैनाती इस समय लाइबेरियाई राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है।

माली

भारत ने बामाको, माली में अपना आवासीय मिशन खोला। विदेश कार्य व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री श्री मोक्टर क्वोन ने 8-13 अक्तूबर, 2009 तक भारत की यात्रा की थी। राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तकनीकी व सांस्कृतिक सहयोग पर करार तथा (I) माली व कोट, डी,अवायर के बीच विद्युत अंतर-संपर्क परियोजना के लिए 36 मिलियन अमरीकी डालर (II) कृषि के क्षेत्र में 15 मिलियन अमरीकी डालर के लिए श्रृंखलाबद्ध ऋण को लागू करने के लिए एक्सिम बैंक के साथ समझौता-ज्ञापन व विदेशी मामलों पर विचार-विमर्श से संबंधित प्रोतोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

नाइजर

भारत ने नियामे में अपना आवासीय मिशन खोला है।

सेनेगल

20 अक्तूबर, 2009 को डकार में विदेश मामलों से संबंधित विचार-विमर्श किया गया था।

साओ टोमे तथा प्रिंसाइप

विदेश कार्य, सहयोग व समुदाय मंत्री डॉ. कालौस अल्बर्टो पायर्स टेनी ने 1 दिसंबर को नई दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर के साथ सरकारी स्तर पर वार्ता की। भारत ने लघु व मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए प्रौद्योगिकी उद्यम व उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान तथा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में तत्काल आवश्यकताओं से पूरा करने के लिए 10 मिलियन रुपए के अन्य अनुदान की घोषणा की। भारत ने कृषि, क्षमता निर्माण व अवस्थापना के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाओं

के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण पर अनुकूल रूप से विचार किया। जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र के विस्तारित सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए तथा 2011-12 की अवधि के दौरान गैर- स्थायी सदस्य के लिए भी भारत के लिए साओ टोमे तथा प्रिंसाइप की सरकार के समर्थन का उल्लेख किया गया है। विदेश मामलो से संबंधित विचार-विमर्श पर प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर किए गए थे। साओ टोमे तथा प्रिंसाइप 47 वें देश के रूप में पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना में शामिल हुए थे।

टोगो

भारत सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए दवाइयों की एक खेप भेजी थी।

भारत अफ्रीकी परियोजना साझेदारी 2010 पर सीआईआई-एक्सिम बैंक कॉनक्लेव 14-16 मार्च, 2009 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय व अफ्रीकी आधिकारियों व व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था।

■■

7 यूरोप

मध्य यूरोप

आस्ट्रिया

भारत और आस्ट्रिया दोनों के लिए यह वर्ष विशेष महत्व का रहा, क्योंकि यह वर्ष भारत और आस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 60वां वर्ष था। उच्च स्तरीय यात्राओं, व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों एवं सांस्कृतिक मंडलियों के आदान-प्रदान से हमारे द्विपक्षीय संबंध और सुदृढ़ हुए।

लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 14-17 सितंबर, 2009 तक आस्ट्रिया का दौरा किया। अध्यक्ष महोदया ने संघीय राष्ट्रपति डॉ. हेन्ज फिशर, नेशनल कौंसिल की अध्यक्ष मैग बारबारा प्रामर तथा यूरोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री डॉ. मिशेल स्पिंडेलेजर के साथ मुलाकात की। आस्ट्रियाई संसद की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों के साथ भी एक बैठक का आयोजन किया गया। आस्ट्रियाई संसद ने भी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष महोदया के लिए एक विशेष 'लोकतंत्र कार्यशाला' का आयोजन किया।

भारत-आस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक का आयोजन 12-13 अक्तूबर, 2009 तक वियना में किया गया। राष्ट्रीय रक्षा कालेज के एक 19-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 17-22 मई, 2009 तक आस्ट्रिया का दौरा किया।

जून-जुलाई 2009 में 'स्जेन साल्जबर्ग' ने भारतीय राजदूतावास तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से साल्जबर्ग में भारतीय शास्त्रीय गायन कार्यक्रमों का आयोजन किया। यह महोत्सव भारत-आस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों का एक भाग था। 'इस्सेल संग्रहालय' वियना के सहयोग से भारतीय मिशन द्वारा 'भारत चलो' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय कलाकारों की लगभग 100 कृतियों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 1 सितंबर, 2009 को आस्ट्रिया के संघीय राष्ट्रपति डॉ. हेन्ज फिशर ने किया। यह प्रदर्शनी तीन माह तक चली।

भारतीय राजदूतावास ने पर्यटन, फिल्म महोत्सवों से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय समिति (सीआईएफएफटी), वियना द्वारा अतुल्य भारत टीवी विज्ञापनों को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार दिए जाने के अवसर पर 13 नवंबर, 2009 को वियना में 'अतुल्य भारत संध्या' का आयोजन किया। पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा ने इस समारोह में भाग लिया।

आस्ट्रिया के उप प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जोसफ प्रोल और वाणिज्य मंत्री श्री रेनहोल्ड मिट्टरलेहनर ने एक उच्चस्तरीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 17-19 फरवरी, 2010 तक भारत की यात्रा की। आस्ट्रिया के इन दोनों मंत्रियों ने भारत में अपने समकक्षों से मुलाकात की तथा उप प्रधान मंत्री ने उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा के साथ मुलाकात की। वर्ष 2005 में आस्ट्रियाई राष्ट्रपति तथा 2007 में आस्ट्रियाई विदेश मंत्री की यात्राओं के पश्चात यह आस्ट्रिया से होने वाली पहली उच्चस्तरीय यात्रा थी।

बोस्निया और हर्जेगोविना

भारत तथा बोस्निया के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। बोस्निया एवं हर्जेगोविना सरकार के न्याय मंत्री श्री बरीसा कोलाक ने 28-29 अक्तूबर, 2009 तक भारत का दौरा किया और उन्होंने पारस्परिक विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सजायाफ्ता कैदियों के हस्तांतरण से संबद्ध करार तथा प्रत्यर्पण संधि को अंतिम रूप दिए जाने पर भी चर्चा हुई। हवाई सेवा करार के मसौदे को भी अंतिम रूप दिया गया है और इस पर वर्ष 2010 में हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

बल्गारिया

भारत और बल्गारिया के बीच पारम्परिक रूप से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध इस वर्ष और भी पुष्पित-पल्लवित हुए। बल्गारिया के उप प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री श्री इवाइलो काल्फिन ने 28 फरवरा-3 मार्च, 2009 तक भारत की राजकीय यात्रा की। उन्होंने उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी तथा विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के साथ मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान राजनयिक एवं सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा व्यवस्था समाप्त किए जाने से संबद्ध एक करार तथा वर्ष 2009-11 के लिए शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति क्षेत्रों में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत के रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव श्री आर. के. माथुर के नेतृत्व में 3-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-बल्गारिया रक्षा सहयोग से संबद्ध संयुक्त समिति के 14वें सत्र में भाग लेने के लिए 6-9 मई, 2009 तक बल्गारिया का दौरा किया। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. टी. रामासामी ने भारत-बल्गारिया संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति के छठे सत्र में भाग लेने के लिए 13-16 मई, 2009 तक बल्गारिया के

लिए एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस यात्रा के दौरान 2009-2011 अवधि के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय पक्ष ने रुचि रखने वाले बल्गेरियाई शोध छात्रों के लिए 10 पीएचडी छात्रवृत्तियों का भी प्रस्ताव किया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित 13-सदस्यीय हिमाचल लोक नृत्य मंडली ने 24-31 अगस्त, 2009 तक बल्गारिया का दौरा किया और इसने बोर्गास में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय लोक साहित्य महोत्सव में भाग लेने के साथ-साथ वारना और सोफिया में अपने कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय भारत-विद्या सम्मेलन का आयोजन सोफिया में 25-26 सितंबर, 2009 को किया गया जिसमें भारत, बल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, एस्तोनिया और क्रोएशिया के भारत विज्ञानियों ने भाग लिया। बल्गारिया की राष्ट्रीय असेम्बली के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19-22 नवंबर, 2009 तक नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सांसद संघ के सातवें महाधिवेशन में भाग लिया।

क्रोएशिया

इवो सनादेर द्वारा 1 जुलाई, 2009 को त्यागपत्र दिए जाने के उपरान्त क्रोएशियाई लोकतांत्रिक संघ (एचडीजेड) की सुश्री जादरंका कोशोर को 5 जुलाई, 2009 को क्रोएशिया के प्रधान मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबद्ध भारत-क्रोएशियाई संयुक्त समिति के नौंवे सत्र का आयोजन 5-6 मार्च, 2009 तक क्रोएशिया में किया गया। वर्ष 2008 में 147 मिलियन अमरीकी डालर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ अर्थात वर्ष 2007 की तुलना में 27ऽ की वृद्धि दर्ज की गई। भारत से 137 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तथा महात्मा गांधी की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 अक्तूबर, 2009 को क्रोएशियाई संसद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित 10-सदस्यीय कत्थक नृत्य मंडली ने 9-13 मार्च, 2009 तक जग्रेब का दौरा किया। स्पंदन सांस्कृतिक न्यास, अहमदाबाद के 23-सदस्यीय लोक नृत्य समूह ने 2-11 जुलाई, 2009 तक कार्लोवेक में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय लोक साहित्य महोत्सवों में भाग लिया।

साइप्रस

भारत और साइप्रस के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत ने निरंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक संकल्पों के अनुसरण में साइप्रस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान किए जाने के प्रति अपना अक्षुण्ण समर्थन दिया है। भारत साइप्रस की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है तथा अप्रैल, 2004 में आयोजित जनमत संग्रह में साइप्रस की जनता द्वारा किए गए लोकतांत्रिक मतदान का स्वागत करता है। साइप्रस ने भी भारत के हितों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत को समर्थन प्रदान किया है।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी पुरंदेश्वरी तथा अन्य उच्चाधिकारियों और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों एवं मीडियाकर्मियों के साथ साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति श्री देमेत्रिस क्रिस्टोफियास के निमंत्रण पर 29-31 अक्तूबर, 2009 तक साइप्रस का राजकीय दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रपति देमेत्रिस क्रिस्टोफियास, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मैरियोस गैरोइयान तथा साइप्रस के मुख्य पादरी क्रिसोस तोमोस-II के साथ मुलाकात की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों के समग्र पहलुओं पर बातचीत की गई। भारत ने साइप्रस की संप्रभुता, एकता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना दीर्घकालीन समर्थन व्यक्त किया, जबकि साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन किया। राष्ट्रपति श्रीमती पाटील ने इंडिया बिजनेस फोरम में बीज व्याख्यान भी दिया, जिसमें अन्य के साथ-साथ, साइप्रस के न्याय मंत्री लोकास लुका तथा साइप्रस वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघों के प्रतिनिधियों, साइप्रस-भारत व्यावसायिक संघ के प्रतिनिधियों तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ परिसंघ और एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया (एसोचैम) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

वित्त राज्य मंत्री श्री नमोनारायण मीना ने लीमासोल में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए 30 सितंबर से, 2 अक्तूबर, 2009 तक साइप्रस का दौरा किया।

चेक गणराज्य

विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने भारत-यूरोपीय संघ मंत्रिस्तरीय त्रोइका में भाग लेने के लिए 28-30 जून, 2009 तक प्राग का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने चेक गणराज्य के राष्ट्रपति श्री वाक्लाव क्लाउस, प्रधान मंत्री श्री जैन सिसर तथा उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री जैन कोहाउट के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

सचिव (उच्च शिक्षा) श्री आर.बी. अग्रवाल के नेतृत्व में अध्यक्ष (विश्व विद्यालय अनुदान आयोग) तथा निदेशक (आईआईटी मुम्बई) के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने 26-28 अप्रैल, 2009 तक चेक गणराज्य का दौरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए तथा दोनों पक्षों ने शिक्षा पर एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। इस यात्रा की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा उप मंत्री के नेतृत्व में चेक गणराज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक में भाग लेने के लिए 7-11 दिसंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक श्री राजीव कुमार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए 21-22 मई, 2009 तक चेक गणराज्य का दौरा किया।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक प्रोफेसर एस.के. ब्रह्मचारी के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चेक विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष के निमंत्रण पर 17-18 सितंबर, 2009 तक चेक गणराज्य का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष श्री माधवन नायर ने अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21-24 अक्तूबर, 2009 तक चेक गणराज्य का दौरा किया। अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े चेक गणराज्य के संस्थानों एवं कंपनियों द्वारा बैठकों का आयोजन किया गया।

भारत-चेक गणराज्य संयुक्त रक्षा समिति की तीसरी बैठक का आयोजन 2 अप्रैल, 2009 को प्राग में किया गया। इस बैठक के दौरान रक्षा क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की गई और भावी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। सेना मुख्यालय के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रनो में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 5-7 मई, 2009 तक चेक गणराज्य का दौरा किया।

चेक गणराज्य के शिक्षा, युवा एवं खेल मामलों के उप मंत्री श्री व्लास्तीमिल रोजिका के नेतृत्व में चेक गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल ने 7-11 दिसंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान शिक्षा से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दल की पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। चेक गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली, मुम्बई और बंगलौर के शैक्षिक संस्थाओं का दौरा भी किया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य नियंत्रक डॉ. प्रहलाद के नेतृत्व में 13-17 दिसंबर, 2009 तक चेक गणराज्य का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री श्री एरिक गेउस के साथ मुलाकात की। उन्होंने चेक तकनीकी विश्वविद्यालय, ब्रनो तकनीकी विश्वविद्यालय, भौतिकी संस्थान तथा चेक गणराज्य की कंपनियों के साथ चर्चा की।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री दिनेश राय ने 11-13 जनवरी, 2010 तक चेक गणराज्य का दौरा किया। सचिव, एमएसएमई के साथ सीआईआई का एक प्रतिनिधिमंडल भी गया था। उन्होंने चेक गणराज्य के उद्योग एवं व्यापार उप मंत्री श्री मिलान होबोरका के साथ बैठक की। उन्होंने चेक वाणिज्य परिसंघ, चेक तकनीकी विश्वविद्यालय तथा चेक इन्वेस्ट के साथ भी चर्चा की।

डेनमार्क

भारत और डेनमार्क ने इस वर्ष अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना जारी रखा। डेनमार्क के प्रधान मंत्री लार्स लोके राससुमेसन ने कोप-15 के मेजबान के रूप में 11 सितंबर, 2009 को भारत का एक दिवसीय कार्यकारी दौरा किया और उन्होंने प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन (कोप-15) से जुड़े मुद्दों तथा क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों इत्यादि पर चर्चा की। प्रधान मंत्री ने डेनमार्क को बताया कि भारत कोप-15 के दौरान किसी संतुलित और प्रभावी सहमति पर पहुंचने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। इस यात्रा के दौरान पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डेनमार्क के प्रधान मंत्री ने सीआईआई द्वारा हरित प्रौद्योगिकी पर आयोजित एक व्यावसायिक सेमिनार को संबोधित किया। प्रधान मंत्री ने जलवायु परिवर्तन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (यूएफसीसीसी) के पक्षकारों के सम्मेलन (कोप-15) में भाग लेने के लिए 17-18 दिसंबर, 2009 तक कोपेनहेगन का दौरा किया।

कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (कोप-15) से पूर्व श्री जयराम रमेश, पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री ने 9-11 अक्तूबर, 2009 तक कोपेनहेगन का दौरा किया और 'क्योतो से कोपेनहेगनः वैश्विक तापन का मुकाबला एवं ऊर्जा सुरक्षा की प्राप्ति' विषय पर आयोजित विश्व के संपादकों के सम्मेलन को संबोधित किया। दोनों पक्षों ने नदियों की सफाई तथा कचरे को प्रसंस्कृत करके विद्युत उत्पादन करने में सहयोग किए जाने की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की। डेनमार्क की जलवायु और ऊर्जा मंत्री श्रीमती कौनीदेडेग्राड ने नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर उच्चस्तरीय सम्मेलन, 'प्रौद्योगिकी विकास एवं अंतरण' विषय पर आयोजित सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए 22-23 अक्तूबर, 2009 तक भारत का दौरा किया।

भारत के प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि ने 28-29 सितंबर, 2009 तक डेनमार्क का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान कार्मिकों की आवाजाही भागीदारी पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया, जिसका उद्देश्य डेनमार्क द्वारा भारतीय कुशल कार्मिकों की भर्ती करने के लिए रूपरेखा तैयार करना है। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा करार के पाठ को भी अंतिम रूप दे दिया है।

भारत और डेनमार्क के बीच विधि कार्यालय परामर्शों के छठे दौर का आयोजन नई दिल्ली में 18 मई, 2009 को हुआ। इस बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रीय रक्षा कालेज (एनडीसी) के 19-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन दौरे के भाग के रूप में 10 से 16 मई, 2009 तक कोपेनहेगन का दौरा किया। भारत और डेनमार्क के बीच वर्ष 2008 में पण्यों का द्विपक्षीय व्यापार 1249.7 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ। वर्ष 2008 में दोनों देशों के बीच 1454.1 मिलियन अमरीकी डालर का सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार किया गया।

एस्तोनिया

एस्तोनिया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे। एस्तोनिया ने पहली बार भारत के लिए राजदूत की नियुक्ति की, जो टालिन में आवासी होंगे। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत एस्तोनिया को 20 स्लॉट का प्रस्ताव किया गया जिसका उपयोग भी किया गया। एस्तोनिया

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और डेनमार्क के प्रधान मंत्री श्री लार्स लोक राममुस्सेन 11 सितंबर, 2009 को नई दिल्ली में भारत और डेनमार्क के बीच करारों पर हस्ताक्षर के अवसर पर।

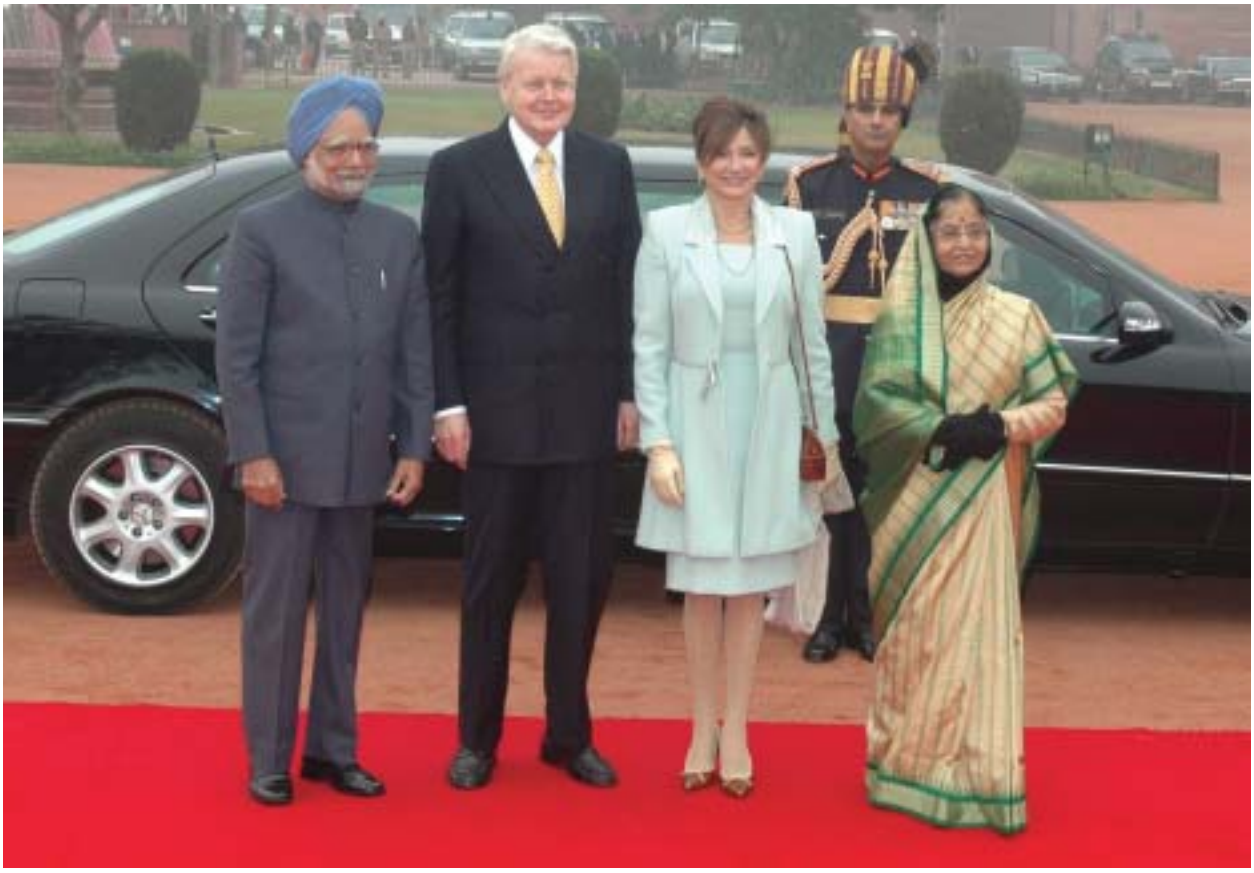

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 14 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आइसलैंड के राष्ट्रपति डॉ. ओलफुर रगनार ग्रिमसन के समारोहपूर्वक स्वागत के अवसर पर।

और भारत के बीच वर्ष 2008 में 49 मिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।

फिनलैंड

भारत और फिनलैंड के बीच होने वाले उच्चस्तरीय आदान-प्रदानों में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री श्री मौरी हेस्कारिन ने नवंबर, 2009 में सरकार एवं व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में 130 सदस्य शामिल थे। यह फिनलैंड से भारत आने वाला सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल था। व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल फिनलैंड की कंपनी ने सीआईआई द्वारा आयोजित 15वें प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन एवं प्रौद्योगिकी मंच में भाग लिया। इसके लिए फिनलैंड एक भागीदार राष्ट्र भी था। द्विपक्षीय व्यावसायिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा इसके साथ ही फिनलैंड से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। फिनलैंड और भारत के बीच वर्ष 2008 में 739 मिलियन यूरो का व्यापार हुआ।

फरवरी, 2009 में रक्षा से संबद्ध फिनलैंड की संसदीय समिति के आठ सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय भेषज एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) के निदेशक ने अप्रैल, 2009 में फिनलैंड का दौरा किया। हेलसिंकी विश्वविद्यालय तथा टेकन्लाजियन केहितानीस्केस्कस (टेकेस) में बैठकें कीं। भारत फिनलैंड के इन संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संपन्न करने के संबंध में बातचीत कर रहा है, जिसका उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं निष्पादित करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मई, 2009 में फिनलैंड का दौरा किया, जहां उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों के साथ संपर्क किया। फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय हवाई सेवा करार को नवीकृत किया गया है। द्विपक्षीय संयुक्त आयोग के 16वें सत्र का आयोजन अक्तूबर, 2009 में हेलसिंकी में किया गया।

फिनलैंड की संचार मंत्री सुश्री सुवीलिंडेन ने एक आधिकारिक एवं व्यावसायिक शिष्टमंडल के साथ 17-13 जनवरी, 2010 तक भारत का दौरा किया तथा आंकड़ों की सुरक्षा से संबद्ध एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आगामी कार्यक्रमः टेरी द्वारा आयोजित दिल्ली सतत विकास बैठक में भाग लेने के लिए फिनलैंड के प्रधान मंत्री श्री मैती वानहानेन फरवरी, 2010 में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। सड़क परिवहन क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री वर्ष के आरंभ में फिनलैंड की यात्रा पर जाने वाले हैं। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग करार में संशोधन किए जाने के संबंध में वार्ताएं की गई हैं और वाणिज्य मंत्री की फिनलैंड यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। इन यात्राओं से हमारे बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ बनाने में योगदान मिलेगा।

यूनान

यूनान में पूर्व के प्रमुख द्विपक्षीय दल पैन हेलनिक सोशलिस्ट (पासोक) पार्टी के नेता श्री जार्ज पपान्द्रु के नेतृत्व में एक नई सरकार ने अक्तूबर, 2009 में आयोजित उपचुनावों के बाद सत्ता संभाली है।

आईएनएस दिल्ली और आईएनएस व्यास नामक भारतीय नौसैनिक पोतों ने 18-21 जुलाई, 2009 तक यूनान के सबसे बड़े बंदरगाह पिरायस बंदरगाह का दौरा किया। इन नौसैनिक पोतों की यात्रा के दौरान ही वेस्टर्न फ्लीट के फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ एडमिरल एस. भसीन ने भी यूनान का दौरान किया और उन्होंने यूनान के रक्षा अधिकारियों के साथ उपयोगी चर्चाएं कीं। हेलनिक नौसेना के साथ 21 जुलाई, 2009 को नौसैनिक अभ्यास संपन्न किया गया। इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) ने पिरामस, एथेंस में अपना कार्यालय खोला। एशिया महाद्वीप के बाहर यह आईआरएस का पहला कार्यालय तथा यूनान में स्थापित पहली भारतीय कंपनी है।

भारत ने यूनान के सबसे प्रतिष्ठित व्यापार मेले थेसालोनेकी अंतर्राष्ट्रीय मेले में 'सम्मानित राष्ट्र' के रूप में भाग लिया। इस मेले में सरकार के छः विभागों/ निकायों तथा 66 कंपनियों ने भाग लिया। यहां भारतीय फिल्म एवं खाद्य महोत्सवों का भी आयोजन किया गया।

भारत से की गई यूनान की विभिन्न द्विपक्षीय यात्राओं में निम्नलिखित की यात्राएं शामिल हैः न्यायमूर्ति श्री जी.एन. रे, अध्यक्ष प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश; डॉ. सुभाष पाणि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत व्यापार संवर्धन संगठन; श्री के.बी.एल मित्तल, सचिव (रेलवे); तथा श्री एस.एम. आचार्य, सचिव (ईएसडब्ल्यू) रक्षा मंत्रालय।

आगामी कार्यक्रमः यूनान के प्रधान मंत्री श्री जार्ज पपान्द्रु दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4-7 फरवरी, 2010 तक भारत का दौरा करेंगे। वे दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और प्रधान मंत्री तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा से विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

हंगरी

हंगरी के साथ भारत के संबंध अत्यंत ही घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण तथा बहुफलकीय हैं। हंगरी के विदेश मंत्री डॉ. पीटर ब्लेडस ने 17-21 जनवरी, 2010 तक भारत का सरकारी दौरा किया और उन्होंने 19 जनवरी, 2010 को विदेश मंत्री के साथ विस्तृत वार्ता की। दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ बनाने तथा निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, भेषज, आटोमोबाइल पुर्जों, ऊर्जा, रक्षा एवं सुरक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कृषि क्षेत्रों तथा खेल सहित कौंसली एवं सांस्कृतिक मामलों पर

विशेष बल दिया। असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी चर्चा हुई। हंगरी के विदेश मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के साथ भी मुलाकात की। हंगरी के विदेश मंत्री ने 19-21 जनवरी, 2010 तक मुम्बई का दौरा किया। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ मुलाकात की। वर्तमान वर्ष के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संवर्धित सहयोग हुआ है। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दो मिलियन यूरो की धनराशि के साथ भारत-हंगरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कोष परिचालित हो गया है तथा शीघ्र ही वित्तपोषण के लिए द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का चयन किया जाएगा। सितंबर और नवंबर, 2009 में भारत तथा हंगरी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर दो संयुक्त कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

आगामी कार्यक्रमः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए फरवरी, 2010 में बुडापेस्ट जाने वाले हैं। वहां संयुक्त व्यावसायिक परिषद की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर भी इस वर्ष की पहली तिमाही में हंगरी की यात्रा पर जा सकती हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर को बुडापेस्ट में भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करना है।

आइसलैंड

आइसलैंड के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण हैं। आइसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र निकायों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चुनाव में भारत की उम्मीदवारी को बहुमूल्य समर्थन देना जारी रखा। आइसलैंड के साथ व्यापार और निवेश संबंध व्यापक तथा विविधतापूर्ण हुए हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों तथा भारत के बीच मुक्त व्यापार करार के संबंध में आइसलैंड के प्रस्ताव पर बातचीत जारी रही और इसकी चौथी बैठक का आयोजन सितंबर, 2009 में किया गया।

आइसलैंड के राष्ट्रपति डॉ. ओलाफुर रैगनर ग्रिम्सन तथा प्रथम महिला श्रीमती डोरिट मौसइफ ने 20-सदस्यीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 11-17 जनवरी, 2010 तक भारत का राजकीय दौरा किया। राष्ट्रपति ग्रिम्सन ने भारत की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा के साथ बैठकें कीं। अपनी बैठकों में प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ग्रिम्सन ने भूतापीय विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन तथा पुनर्चक्रण एवं हिमनद संबंधी अध्ययनों, भूकम्प पूर्वानुमान तथा आइसलैंड के तटवर्ती इलाकों में भारतीय कंपनियों द्वारा तेल का पता लगाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग सहित द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्हें राष्ट्रपति महोदया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ के लिए वर्ष 2007 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आइसलैंड के राष्ट्रपति ने नवीकरणीय ऊर्जा पर एक कार्यशाला में भी भाग लिया। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रपति ग्रिम्सन ने मुम्बई और बंगलौर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्यपालों के साथ मुलाकात की तथा भारतीय व्यावसाइयों के साथ बैठकें कीं।

भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर, 2009 में भारत और आइसलैंड के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन सेमिनार का आयोजन किया। इसके उपरान्त पर्यटन क्षेत्र से आइसलैंड का एक प्रतिनिधिमंडल फरवरी, 2010 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एसएटीटीई विश्व प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। पहली बार तमिल और तेलगू भाषा में दो क्षेत्रीय भारतीय फिल्मों का आंशिक फिल्मांकन आइसलैंड में किया गया।

लातविया

भारत और लातविया के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण हैं तथा इनका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। वर्ष 2008-09 में भारत-लातविया द्विपक्षीय व्यापार 100.63 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ, जबकि वर्ष 2007-08 में यह आंकड़ा 71.05 अमरीकी डालर का था अर्थात 41.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। लातविया के राजनयिक दिल्ली स्थित विदेश सेवा संस्थान में विदेश सेवा संस्थान द्वारा संचालित विदेशी राजनयिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग लेते रहे हैं। लातविया के राष्ट्रिकों ने भारत में हिन्दी पाठ्यक्रमों से भी लाभ लिया है।

लिथुवानिया

भारत और लिथुवानिया के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लिथुवानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति सुश्री दालिया ग्रेबाउस्केते ने 12 जुलाई, 2009 को लिथुवानिया की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। लिथुवानिया के विदेश मंत्री श्री भिगाउडस उसाकस ने वहां के अर्थव्यवस्था मंत्री श्री डाइनुवस क्रेविस के साथ 2-5 दिसंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के साथ बैठकें कीं। उन्होंने मुम्बई का भी दौरा किया और मुम्बई में लिथुवानिया का मानद कोंसलावास खोलने के अवसर पर आयोजित समारोह में श्री उसाकस ने एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुम्बई में आयोजित लिथुवानिया-भारत व्यावसायिक मंच में भाग लिया। भारत और लिथुवानिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2008 में 32.23 मिलियन यूरो से बढ़कर 292.69 मिलियन यूरो हो गया, जो विशेष रूप से भारत में भेजी गई उर्वरकों की एक बड़ी खेप के परिणामस्वरूप हुआ।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बीआईटीटीए) पर बातचीत आरंभ की है तथा वार्ता का पहला दौर 18-19 मई, 2009 को विलिनियस में आयोजित किया गया।

मेसेडोनिया

समीक्षाधीन अवधि के दौरान मेसेडोनिया सरकार ने कोलकाता में एक मानद कोंसल की नियुक्ति की है, जिसका कोंसली क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य पर होगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित 13-सदस्यीय हिमाचल लोक नृत्य मंडली ने 1-4 सितंबर, 2009 तक मेसेडोनिया का दौरा किया और स्कोपजे तथा वलानदोगो में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

माल्टा

भारत-माल्टा संबंध हमेशा से से सौहार्दपूर्ण एवं चिरकालिक रहे हैं। माल्टा और भारत के हित समुद्री कानून पर माल्टा की पहल तथा पर्यावरण संबंधी चिन्ताओं से संबंधित रहे हैं। माल्टा के उप प्रधान मंत्री डॉ. टोनियो बोर्ग ने 6-11 जनवरी, 2010 तक भारत का आधिकारिक दौरा किया। दिल्ली के अतिरिक्त उन्होंने चेन्नै और आगरा का भी दौरा किया। चेन्नै में माल्टा के उप प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के राज्यपाल की उपस्थिति में माल्टा के मानद कोंसलावास का उद्घाटन किया और दिल्ली में उन्होंने माल्टा के उच्चायोग का उद्घाटन किया जिसकी स्थापना जुलाई, 2007 में हुई थी। माल्टा के उप प्रधान मंत्री ने श्रीमती प्रेनीत कौर के साथ द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होनें विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। माल्टा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दोहरे कराधान के परिहार से संबद्ध करार पर वार्ताओं के दूसरे दौर के लिए फरवरी, 2009 में नई दिल्ली का दौरा किया। व्यापार एवं निवेश संवर्धन प्रतिनिधिमंडल ने 21-29 नवंबर, 2009 तक मुम्बई और नई दिल्ली का दौरा किया। दोनों देशों के बीच कार्यकलाप के मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं एवं नौवहन।

हालांकि, वर्ष 2007-08 के दौरान भारत और माल्टा के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी आई है। परन्तु, वर्ष 2008-09 के दौरान दिसंबर-अप्रैल तिमाही में निर्यातों में कुछ प्रगति हुई और 60.22 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया।

मोंटेनेग्रो

मोंटेनेग्रो के साथ भारत के संबंध समाजवादी युगोस्लाविया (युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य) के दिनों से ही घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। जून, 2006 तक मोंटेनेग्रो इसका एक घटक था। मोंटेनेग्रो में भारत के लिए पर्याप्त सद्भावना और मैत्री की भावना है। मोंटेनेग्रो ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने का भी संकेत दिया है। भारत मोंटेनेग्रो विदेश कार्यलय परामर्श का पहला दौर 21 जुलाई, 2010 को मोंटेनेग्रो में आयोजित किया गया।

मोंटेनेग्रो में योग्य एवं अनुभवी मानव शक्ति की कमी से जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए इसे भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत एक भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया है। अप्रैल, 2009 से मार्च, 2009 की अवधि के लिए आईटेक के अंतर्गत मोंटेनेग्रो को 5 सीटें आबंटित की गईं।

नार्वे

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच मंत्रियों एवं अधिकारियों के स्तर पर व्यापक कार्यकलाप किए गए। संसदीय मामले एवं जल संसाधन मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने 18-19 अगस्त, 2009 तक ओस्लो का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत में नार्वेयन भू-तकनीकी संस्थान के कार्यों एवं भावी योजनाओं के संबंध में एक वार्ता सत्र में भाग लिया तथा ओस्लो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन एवं पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा ने 27 अगस्त, 2009 को शहरी गरीब कोष इंटरनेशनल के शासी मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए नार्वे का दौरा किया। उन्होंने भारत को पर्यटन के एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए इंडिया पर्यटन रोड शो का भी उद्घाटन किया।

नार्वे के पर्यावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री श्री एरिक सोल्हेम ने 'जलवायु परिवर्तन पर उच्चस्तरीय सम्मेलनः प्रौद्योगिकी विकास एवं अंतरण' में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्तूबर, 2009 तक नई दिल्ली का दौरा किया। उक्त यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन तथा क्योतो प्रोतोकोल की स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित क्षेत्रों में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पूर्वोत्तर राज्यों के विद्युत मंत्रियों, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र एवं विद्युत व्यापार निगम के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन दौरे के लिए 4-14 जून, 2009 तक नार्वे की यात्रा की तथा वहां नार्वे के विद्युत क्षेत्र के अधिकारियों एवं कंपनियों के साथ बातचीत की।

भारत-नार्वे विदेश कार्यालय परामर्शों के पांचवे दौर का आयोजन 16 जून, 2009 को नई दिल्ली में किया गया। 14-15 मई, 2009 तक ओस्लो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दल की दूसरी बैठक के दौरान भारत और नार्वे के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक 13-14 अगस्त, 2009 तक ओस्लो में हुई। भारत और नार्वे ने द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा सेवा करार के पाठ को भी अंतिम रूप दिया।

आगामी कार्यक्रमः नार्वे के प्रधान मंत्री श्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग टाटा पर्यावरण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही दिल्ली सतत विकास शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 4-7 फरवरी, 2010 तक भारत के दौरे पर आ रहे हैं। नार्वे के विदेश मंत्री भारत-नार्वे संयुक्त आयोग की बैठक के चौथे दौर में भाग लेने के लिए 2 मार्च, 2010 को भारत यात्रा पर आने वाले हैं। हमारे विदेश मंत्री के साथ वे भी इस आयोग के सह-अध्यक्ष हैं।

पोलैंड

भारत और पोलैंड के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित यात्राएं होती रही हैं और हमारे संबंधों का निरन्तर विस्तार होता रहा है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने राज्य मंत्री डॉ. अश्विनी कुमार, तीन सांसदों तथा एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ 23-26 अप्रैल, 2009 तक पोलैंड की राजकीय यात्रा की। राष्ट्रपति महोदया ने पोलैंड के राष्ट्रपति श्री लेच कासजिन्स्की, प्रधान मंत्री श्री डोनाल्ड टस्क तथा संसद के अध्यक्ष श्री ब्रोनिसलाव कोमोरोवस्की के साथ चर्चाएं कीं।

राष्ट्रपति जी ने वहां भारतीय समुदाय तथा भारत-पोलैंड आर्थिक मंच को संबोधित किया। कराको में राष्ट्रपति जी ने जैगीलोनियन विश्वविद्यालय के रेक्टर और मोलोपोल्सकी प्रांत के गवर्नर से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान पर्यटन तथा स्वास्थ्य और दवाओं के क्षेत्र में दो करार संपन्न किए गए।

पोलैंड के विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री जैसेक नाज्दर ने द्विपक्षीय चर्चाओं के लिए 7-9 अक्तूबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने पोलैंड के राष्ट्रीय बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए 9-12 नवंबर, 2009 तक पोलैंड का दौरा किया।

द्विपक्षीय व्यापार में अच्छी वृद्धि हो रही है और वर्ष 2008 में यह आंकड़ा 1275 मिलियन अमरीकी डालर का था। पोलैंड यूरोपीय संघ में विद्यमान मंदी की प्रवृत्तियों से बचने में कामयाब रहा और वर्ष 2009 में इसकी अर्थव्यवस्था की विकास दर 1.4 प्रतिशत रहने की संभावना है।

रोमानिया

रोमानिया और भारत ने साझे हित के मामलों पर द्विपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करना जारी रखा। रोमानियाई राष्ट्रिकों के लिए संगीत, नृत्य तथा हिन्दी शिक्षण जैसे क्षेत्रों में छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना जारी रहा। रोमानिया के अनेक नागरिकों ने आईटेक प्रशिक्षण का लाभ लिया। भारत सरकार तथा रोमानिया सरकार के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण से संबद्ध करार का प्रोतोकोल अक्तूबर 2009 में प्रवृत्त हुआ।

26 जून, 2009 को नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श किए गए। रोमानियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में वैश्विक मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री दोरू-रोमुलुस कोस्तिया ने किया, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नलिन सूरी ने किया।

सर्बिया

भारत और सर्बिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। सर्बिया बाल्कन क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण ताकत है और यह भारत को एक प्रमुख उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। 20 जुलाई, 2009 को बेलग्रेड में आयोजित भारत-सर्बिया विदेश कार्यालय परामर्शों के पांचवे दौर में विशेषकर आर्थिक सहयोग सहित अन्य सभी क्षेत्रों में मैत्री की भावनाओं को अभिव्यक्त किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की अनिवार्यता में छूट दिए जाने से संबद्ध सितंबर, 2007 में संपन्न करार 17 जुलाई, 2009 से लागू हो गया। भारत के आईटेक कार्यक्रमों में एक भागीदार देश के रूप में सर्बिया को शामिल किए जाने के उपरांत इस वर्ष अप्रैल 2009 से मार्च, 2010 तक चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सर्बिया गणराज्य को पांच सीटें आबंटित की गईं। सर्बिया ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की सूचना दी।

स्लोवाकिया

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव श्री दिनेश राय ने स्लोवाकिया की राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास एजेंसी द्वारा आयोजित 'भारत के साथ व्यापार करने के संदर्शः भारतीय बाजार में प्रवेश हेतु स्लोवाक व्यावसाइयों को समर्थन' विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-25 जून, 2009 तक ब्रातिस्लावा का दौरा किया। एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों, जो उक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए सचिव महोदय के साथ गए थे, ने स्लोवाकियाई व्यावसाइयों के साथ अलग से बैठकें कीं। स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के साथ मिलकर उन्होंने भारत और स्लोवाकिया के बीच आर्थिक सहयोग संवर्धित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए स्लोवाकिया के अर्थव्यवस्था मंत्री श्री लुबोमिर जोहनातेक के साथ मुलाकात की। भारत और स्लोवाकिया के बीच वर्ष 2008 में 244 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ, जबकि वर्ष 2007 में यह आंकड़ा 228.5 मिलियन अमरीकी डालर का था।

स्लोवानिया

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर ने ब्लेड स्ट्रैटजिक मंच में भाग लेने के लिए 30 अगस्त-1 सितंबर, 2009 तक जुब्लजाना का दौरा किया। इस मंच की बैठकों के दौरान ही विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर ने स्लोवानिया के राष्ट्रपति डॉ. दानिलो तुएर्क तथा विदेश मंत्री श्री सैमुअल जबोगर के साथ मुलाकात की। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर की यात्रा के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा जुब्लजाना कला विश्वविद्यालय के संकाय के बीच जुब्लजाना विश्वविद्यालय में हिन्दी पीठ की स्थापना से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा मनोनीत डॉ. अरुण कुमार मिश्रा ने 16 नवंबर, 2009 से जुब्लजाना कला विश्वविद्यालय के संकाय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।

श्री जोजेफ जेरोवसेक के नेतृत्व में एक स्लोवेनियाई मैत्री दल ने 23-27 नवंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। स्लोवेनियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सूचित किया कि स्लोवेन्ज गार्डेक नगर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'सिटी ऑफ पीस' के रूप में घोषित किया गया है। नगर के महापौर श्री मतजाज जोनोस्कार भी इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

भारत में स्लोवानिया के प्रथम राजदूत ने सितंबर, 2009 के मध्य में नई दिल्ली स्थित स्लोवेनियाई राजदूतावास में अपना कार्यभार ग्रहण किया। भारत और स्लोवानिया के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबद्ध संयुक्त समिति के 7वें सत्र का आयोजन 29 सितंबर, 2009 को जुब्लजाना में किया गया।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने 9-16 सितंबर, 2009 तक सेल्जे में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय

व्यापार मेले में 14 कंपनियों की भागीदारी का समन्वय किया। स्लोवाकिया में हमारे राजदूतावास ने 2 अक्तूबर, 2009 से जुब्लजाना में महात्मा गांधी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। लोक उद्यम विभाग के सचिव श्री आर. बंदोपाध्याय ने जून, 2009 में जुब्लजाना में अंतर्राष्ट्रीय उद्यम संवर्धन केंद्र की शासी परिषद की 49वीं बैठक में भाग लिया।

आगामी कार्यक्रमः स्लोवानिया के राष्ट्रपति डॉ. दानिलो तुएर्क टाटा पर्यावरण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही दिल्ली सतत विकास शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 4-6 फरवरी, 2010 तक भारत के दौरे पर आ रहे हैं। भारतीय विश्व कार्य परिषद में वे पश्चिमी बाल्कन पर व्याख्यान भी देंगे।

स्वीडन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय यात्राओं का आदान-प्रदान जारी रहा। स्वीडन के प्रधान मंत्री फ्रेडरिक रेन्फेल्ट ने विदेश मंत्री कार्ल बिल्ट, व्यापार मंत्री इवा बोर्लिंग तथा एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठकों तथा भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठकों में भाग लेने के लिए 5-6 नवंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। दोनों पक्षों ने प्रतिरक्षा एवं पर्यावरण क्षेत्र में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच संलयन अनुसंधान क्षेत्र में एक करार भी संपन्न किया गया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने अधिकारियों एवं व्यावसायिकों के 18-सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल के साथ 15-16 सितंबर, 2009 तक स्वीडन का दौरा किया और स्वीडन के व्यापार मंत्री डॉ. इवा बोर्लिंग के साथ बैठक की। आर्थिक, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक सहयोग के लिए भारत-स्वीडन संयुक्त आयोग की कार्य योजना पर भी दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने स्टाकहोम में आयोजित विश्व जल सप्ताह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत के डॉ. बिंदेश्वरी पाठक को स्टाकहोम जल पुरस्कार से नवाजा गया।

यूरोपीय संघ के इरैस्मस मुंडुस छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में भारतीय छात्रों और डाक्टरेट शोधकर्ताओं ने स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय एवं कैरोलिंस्का संस्थान में अपना नामांकन कराया। भारतीय दूतावास ने लुंड विश्वविद्यालय को महात्मा गांधी पर 120 पुस्तकों का एक सेट दान स्वरूप दिया तथा गांधी जयन्ती पर स्टाकहोम इंटरनेशनल स्कूल में भारतीय दूतावास के सहयोग से 'आज के विश्व में महात्मा गांधी के आदर्शों की प्रासंगिकता' विषय पर आयोजित सेमिनार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया।

वर्ष 2008-09 में भारत-स्वीडन द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है और यह 2.6 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया, जबकि वर्ष 2007-08 में 2.3 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार हुआ था अर्थात 15.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

31 जनवरी-5 फरवरी, 2010 तक नई दिल्ली में भारत-स्वीडन स्वास्थ्य सप्ताह का आयोजन किया गया। इस संबंध में स्वीडन की बुजुर्ग देखभाल एवं लोक स्वास्थ्य मंत्री सुश्री मारिया लार्सन ने एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का आधिकारिक दौरा किया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2009 में संपन्न स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं कैरोलिंस्का संस्थान के बीच अगस्त, 2009 में संपन्न समझौत ज्ञापन के अनुसरण में किया गया।

स्वीडन के उदार दल की संसद सदस्य तथा संविधान से संबद्ध स्थाई समिति की सदस्य सुश्री मार्ग्रेटा शेडेरफेल्ट ने 22-27 फरवरी, 2010 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय से संबद्ध भारतीय स्थाई समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों तथा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की।

स्विट्जरलैंड

इस वर्ष के दौरान हुई यात्राओं से हमारे बीच विद्यमान द्विपक्षीय संबंध पुष्पित-पल्लवित हुए। युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. एम.एस. गिल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 8-17 अगस्त, 2009 तक स्विट्जरलैंड का दौरा किया। स्विट्जरलैंड के खेल संघीय कोंसलर के साथ हुई बैठक में उन्होंने पर्वतारोहण कार्यक्रमों में सहयोग, खेलों में नशीली दवाओं पर नियंत्रण, कोचिंग तथा अनुदेशकों को प्रशिक्षित किए जाने के संबंध में व्यापक चर्चा की। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 11-12 अगस्त, 2009 तक स्विट्जरलैंड का दौरा किया और सीआईआई, आईसीआईसीआई, जेएम फायनेंशियल तथा स्विस-भारत उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'बिल्डिंग इंडियाः रोड इंफ्रास्ट्रक्चर' नामक रोड शो में भाग लिया। मंत्री महोदय ने सीआईआई-डब्ल्यूईएफ द्वारा आयोजित भारत राजमार्ग अवसंरचना गोलमेज बैठक को भी संबोधित किया।

कपड़ा मंत्री श्री दयानिधि मारन के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25 से 28 अक्तूबर, 2009 तक स्विट्जरलैंड का दौरा किया। मंत्री महोदय ने ज्यूरिख स्थित वस्त्र औद्योगिक इकाई का दौरा किया। उन्होंने 'वस्त्र एवं अपारेल कोष में सहकारी व्यावसायिक अवसर' विषय पर एक सम्मेलन को भी संबोधित किया। स्विस परिसंघ की आर्थिक मामलों की संघीय कोंसलर श्रीमती डोरिस लूथर्ड के नेतृत्व में चार सदस्यीय शिष्टमंडल 3-4 सितंबर, 2009 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने आया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध भारत-स्विस कार्यकारी दल की पहली बैठक में भाग लेने के लिए

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 5 नवंबर, 2009 को
नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में स्वीडन के प्रधान मंत्री श्री फ्रेडरिक रीनफील्ड के साथ।

फ्रांस के राष्ट्रपति श्री निकोलस सरकोजी 14 जुलाई, 2009 को पेरिस स्थित होटल मैरिग्नी में
वर्किंग लंच के लिए प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का स्वागत करते हुए।

29 अप्रैल से 2 मई, 2009 तक स्विट्जरलैंड का दौरा किया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष श्री सी.वी. भावे के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 26-27 जून, 2009 तक के लिए बैसल का दौरा किया जहां इस प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड की पूर्ण बैठक में भाग लिया।

विदेश कार्यालय परामर्शों का छठा दौर 4 दिसंबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की गई। वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नए व्यापक प्रोतोकोल पर बातचीत करने के लिए 9-13 नवंबर, 2009 तक स्विट्जरलैंड का दौरा किया। यह प्रोतोकोल नवंबर, 1994 में संपन्न भारत- स्विट्जरलैंड दोहरे कराधान के परिहार पर करार से संबद्ध वर्तमान करार का स्थान लेगा।

3 सितंबर, 2009 को भारत और स्विट्जरलैंड ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए। भारत-ईएफटीए व्यापार एवं निवेश करार पर वार्ताओं के चौथे दौर का आयोजन 22 से 23 सितंबर, 2009 तक नई दिल्ली में किया गया।

टर्की

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने 8 सितंबर, 2009 को आयोजित आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से संबद्ध संयुक्त समिति के 9वें सत्र में भाग लेने के लिए 7 से 8 सितंबर, 2009 तक अंकारा का दौरा किया। अपनी इस यात्रा के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने टर्की के विदेश व्यापार राज्य मंत्री जफर कायलायान, टर्की के व्यापार और उद्योग मंत्री निहत इरगुन तथा जेसीईटीसी के सह अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री मेहमेत ऐदीन के साथ मुलाकात की। भारत-टर्की संयुक्त व्यावसायिक परिषद की बैठक का आयोजन 9 सितंबर, 2009 को इस्तांबुल में किया गया।

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 2-7 अक्तूबर, 2009 तक इस्तांबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लिया। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने टर्की के उप प्रधान मंत्री एवं अर्थव्यवस्था मंत्री श्री अली बबाकन से 7 अक्तूबर, 2009 को मुलाकात की तथा द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों एवं वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट जैसे विविध मुद्दों पर चर्चा की।

इन यात्राओं के अतिरिक्त नागर विमानन राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल ने सबीहा गोकसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए 30-31 अक्तूबर, 2009 तक तुर्की का दौरा किया। कपड़ा मंत्री श्री दयानिधि मारन ने 1-4 नवंबर, 2009 तक इस्तांबुल का दौरा किया और निवेश आकर्षित करने तथा व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए 3 नवंबर, 2009 को एक वस्त्र रोड शो में भाग लिया।

कैलेंडर वर्ष 2008 में द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा 3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया, जिसमें 2.45 बिलियन भारत द्वारा टर्की को किया जाने वाला निर्यात है। दोनों पक्ष इस आंकड़े को बढ़ाकर वर्ष 2011 तक 5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचाना चाहते हैं। 23 सितंबर, 2009 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पीएसएलवी सी-14 राकेट ने टर्की के पहले नैनो सैटलाइट इतुपसेट-1 को छोड़ा, जिसकी डिजाइन एवं निर्माण इस्तांबुल तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। इसके उपरांत हमारा द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग एक नए दौर में पहुंच गया है।

सचिव स्तरीय विदेश कार्यालय परामर्शों का 7वां दौर 9 अप्रैल, 2009 को आयोजित किया गया और संयुक्त सचिव/ महानिदेशक स्तर पर इससे संबंधित सत्र अंकारा में 16 दिसंबर, 2009 को आयोजित हुआ।

आगामी कार्यक्रमः टर्की के राष्ट्रपति अब्दुल्ला गुल 7-11 फरवरी, 2010 तक भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ एक बड़ा व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, जो नई दिल्ली और मुम्बई में बैठकें करेगा।

पश्चिमी यूरोप

बेल्जियम

भारत और बेल्जियम के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं तथा व्यापार एवं व्यवसाय इन संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है। बेल्जियम वर्ष 2008-09 के दौरान विश्व स्तर पर भारत का नौवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा।

19 नवंबर, 2009 को बेल्जियम के प्रधान मंत्री श्री हरमन वान रोमपुवे को यूरोपीय संघ के नेताओं द्वारा लिस्बन संधि के अंतर्गत यूरोपीय परिषद का पहला अध्यक्ष चुना गया। एक नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई और पिछली सरकार में विदेश मंत्री एवेस लेतेरमे को 25 नवंबर, 2009 को बेल्जियम के सम्राट द्वारा बेल्जियम का नया प्रधान मंत्री बनाया गया। नए मंत्रिमंडल में पिछले मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को शामिल किया गया है और उन्हें वही विभाग आवंटित किए गए हैं, जो उन्हें वान वान रोमपुवे की सरकार में प्राप्त थे। सिर्फ दो परिवर्तन किए गए, जिसके तहत स्टीवन वानाकेरे ने बेल्जियम के विदेश मंत्री के रूप में इवेस लेतेरमे की जगह ली तथा सुश्री इंगे वगैविट ने प्रचार व्यवसाय मंत्री के रूप में श्री वानकेरे की जगह ली। श्री लेतेरमे दूसरी बार बेल्जियम के प्रधान मंत्री बने हैं।

भारत-बेल्जियम सामाजिक सुरक्षा करार, जो किसी यूरोपीय देश के साथ संपन्न किया जाने वाला इस प्रकार का पहला करार है, 1 सितंबर, 2009 से प्रभावी हो गया।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि ने 30 सितंबर-3 अक्तूबर, 2009 तक बेल्जियम का दौरा किया। उन्होंने बेल्जियम के तत्कालीन विदेश मंत्री तथा वर्तमान प्रधान मंत्री एवेस लेतेरमे के साथ 30 सितंबर को ब्रसेल्स में इंडिया कालिंग कांफ्रेंस, 2009 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बेल्जियम के अपने समकक्ष उप प्रधान मंत्री तथा सामाजिक मामले एवं स्वास्थ्य मंत्री सुश्री लौराते आनकेलिक के साथ मुलाकात की।

भारत तथा बेल्जियम लक्जमबर्ग आर्थिक संघ के बीच आर्थिक संयुक्त परामर्शी बैठक के 11वें दौर का आयोजन 8 वर्षों के अंतराल के बाद 4-5 मई, 2009 तक ब्रसेल्स में किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव जी.के. पिल्लई तथा बेल्जियम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजदूत जेन वान डेसल, बेल्जियम के विदेश मंत्रालय के द्विपक्षीय संबंधों से संबद्ध महानिदेशक ने किया। लक्जमबर्ग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लक्जमबर्ग के विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के महानिदेशक द्वारा किया गया। दोनों पक्षों ने जारी सहयोग की समीक्षा की तथा परिवहन, लौह एवं इस्पात, हीरा व्यापार, पर्यटन, जैव प्रौद्योगिकी एवं भेषज, आईसीटी एयरोनाटिक्स, निवेश एवं व्यापार पहुंच, वित्तीय क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा की। भारत और बेल्जियम ने 12 बिलियन यूरो का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे वर्ष 2012 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। वर्ष 2008 में ही यह आंकड़ा 8.8 मिलियन यूरो तक पहुंच गया है।

अन्य यात्राओं में नौवहन मंत्रालय से संयुक्त सचिव 'बंदरगाह' श्री राकेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक 3-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नौवहन एवं बंदरगाहों से संबद्ध समझौता ज्ञापन के तहत कार्यकारी समूह की बैठक में भाग लेने के लिए 5-9 अक्तूबर, 2009 तक बेल्जियम का दौरा किया तथा यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने हेतु फ्लांडर्स सरकार के साथ बंदरगाहों एवं नौवहन के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए वर्ष 2010-2012 अवधि के लिए एक नए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

बेल्जियम अधिराज्य के युवराज एक आर्थिक मिशन के प्रमुख के रूप में 20-27 मार्च, 2010 तक के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। यह पिछले 15 वर्षों के दौरान इस प्रकार का चौथा मिशन होगा। उनके साथ एक बड़े व्यावसायिक एवं सरकारी प्रतिनिधिमंडल के भी आने की संभावना है। भारत के उप राष्ट्रपति आधिकारिक मेजबान होंगे। बेल्जियम के युवराज मुम्बई, पुणे और बेंगलुरु भी जाएंगे। मार्च, 2010 में होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य भारत और बेल्जयिम के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाना है।

फ्रांस

भारत-फ्रांस के बीच पारम्परिक रूप से घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। वर्ष 1998 में सामरिक भागीदारी की स्थापना के बाद से राज्याध्यक्ष/ शासनाध्यक्ष के स्तर पर तथा रक्षा प्रमुख की यात्राओं तथा ऊर्जा एवं अंतरिक्ष जैसे सामरिक क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर बढ़ते व्यावसायिक आदान-प्रदान के जरिए सभी क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों का संवर्धन हुआ है। फ्रांस पहला राष्ट्र था जिसके साथ भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा छूट दिए जाने के उपरान्त परमाणु ऊर्जा करार संपन्न किया। इस करार से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में इस करार के जरिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पूर्ण असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पहल करने की अनुमति दे दी गई। आज सभी महत्पूर्ण क्षेत्रों में हमारे संबंधों में लगातार मजबूती आ रही है और राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के साथ-साथ रक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा जैसे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक सहयोग किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 13-14 जुलाई, 2009 तक फ्रांस का दौरा किया था। वे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस 'बास्टिल दिवस परेड' के अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। भारतीय सशस्त्र बलों के 400 सैनिकों ने इस परेड में भाग लिया और मार्च पास्ट का नेतृत्व किया। ऐसा पहली बार हुआ, जब भारतीय सैनिकों ने किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित होने वाले समारोहों में भाग लिया। राष्ट्रपति सरकोजी ने प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सम्मान में दोहपर के भोज का आयोजन किया, जिसके पश्चात प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति जी ने एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोहों में आमंत्रितों की विशाल सभा को संबोधित किया। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति सरकोजी और उनकी पत्नी को भारत आने का न्यौता दिया।

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति सरकोजी की ट्रिनीडाड एवं टोबैगो में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान भी 27 नवंबर, 2009 को दोपहर के भोज के दौरान बैठक हुई, जिसमें उन्होनें जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की तथा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

भारत-फ्रांस रणनीतिक संवाद के 20वें दौर का आयोजन 17 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में किया गया। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री के.एम. नारायणन तथा राष्ट्रपति सरकोजी के राजनयिक सलाहकार जीन डेविड लेविटे ने भाग लिया। द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन 5 फरवरी, 2009 को पेरिस में किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन ने किया जबकि फ्रांसीसी पक्ष का नेतृत्व महासचिव गेरार्ड इरेरा ने किया। भारत-फ्रांस रणनीतिक संवाद के 21वें दौर का आयोजन 18 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में किया गया। इस संवाद में भी भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा फ्रांस की ओर से राष्ट्रपति सरकोजी के राजनयिक सलाहकार श्री जीन डेविड लेटिवे ने भाग लिया।

पिछले बारह महीनों (सितंबर, 2008 से अक्तूबर, 2009) के दौरान भारत-फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार घटकर 5.69 बिलियन यूरो (8.08 बिलियन अमरीकी डालर) रह गया है, जो वैश्विक आर्थिक संकट के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को परिलक्षित करता है, क्योंकि एक वर्ष पूर्व (सितंबर, 2007 से अक्तूबर, 2008) के पिछले समान बारह महीनों के दौरान हमारा द्विपक्षीय व्यापार 6.96 बिलियन यूरो (10.39 बिलियन अमरीकी डालर) था अर्थात 18.24 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। 409.6 मिलियन यूरो के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। नवगठित भारत-फ्रांस मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच की आरंभिक

बैठक 26 जून, 2009 को पेरिस में हुई और इस मंच की पहली बैठक का आयोजन 28-29 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में किया गया।

फ्रांस की विदेश व्यापार मंत्री सुश्री एने मैरी इदरेक ने 26-29 अक्तूबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग पर विशेष बल दिया गया। अपनी यात्रा के दौरान सुश्री इदरेक ने अन्य लोगों के साथ-साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री सुबोध कांत सहाय, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया तथा शहरी विकास मंत्री श्री जयपाल रेड्डी के साथ मुलाकात की।

आर्थिक एवं तकनीकी मुद्दों से संबद्ध भारत-फ्रांस संवाद का गठन संयुक्त कार्यकारी संघों के जरिए निर्धारित तरीके से किया गया है। इस वर्ष के दौरान संयुक्त कार्यकारी दल ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूर संचार, शहरी विकास एवं नगर परिवहन, कृषि, सड़क एवं पर्यावरण इत्यादि पर बैठकें कीं। 10-11 फरवरी, 2009 तक पेरिस में हवाई सेवाओं पर द्विपक्षीय बातचीत का आयोजन किया गया और इस अवसर पर द्विपक्षीय हवाई सेवा से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया।

फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग हमारे समग्र द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रक्षा सहयोग से संबद्ध उच्चस्तरीय समिति के 12वें सत्र का आयोजन 30 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में किया गया जिसमें सामरिक संदर्शों, अनुसंधान एवं विकास में सहयोग तथा खरीद जैसे मुद्दों के संबंध में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। इससे पूर्व भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग वार्ता की रूपरेखा के अंतर्गत अनेक बैठकों का आयोजन किया गया, नामतः भारत-फ्रांस अनुसंधान मंच (आईएफआरएफ) की बैठक 5-7 अक्तूबर, 2009 तक भारत में हुई; थल सेना/ नौसेना/ वायु सेना से संबंधित वार्ताओं का आयोजन 25-27 नवंबर, 2009 तक नई दिल्ली में किया गया; सैन्य उप-समूह (एमएसजी) की बैठक का आयोजन 30 नवंबर, 2009 को भारत में हुआ; तथा रक्षा उद्योग, खरीद, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध भारत-फ्रांस उप-समिति की बैठक 30 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में हुई। फ्रांस के रक्षा मंत्री हर्बे मोरिन ने 3-4 दिसंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया और उन्होंने हमारे रक्षा मंत्री के साथ चर्चाएं कीं। भारत-फ्रांस नौसेना अभ्यास, वरुण 2009 का आयोजन पहली बार अटलांटिक महासागर में 27 जून - 4 जुलाई, 2009 तक फ्रांस के ब्रिटानी तट पर किया गया। भारतीय पक्ष से आईएनएस दिल्ली, ब्रह्मपुत्र, ब्यास तथा टैंकर आईएनएस आदित्य ने इस अभ्यास में भाग लिया। वर्ष 2010 में भारत-फ्रांस वायु सेना अभ्यास गरुड़-4 का आयोजन किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

फ्रांस और भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोगों के क्षेत्र में भी अपने आपको महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखते हैं। एरियन स्पेस भारतीय उपग्रहों (इनसेट) के लिए प्रक्षेपण सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा है, जबकि भारत के पीएसएलवी का उपयोग यूरोपीय ग्राहकों के लिए उपग्रहों का प्रक्षेपण करने में किया गया है। इसरो तथा फ्रांस के इसके समकक्ष सीएनईएस के बीच द्विपक्षीय तकनीकी बैठक का आयोजन जुलाई, 2009 में बंगलौर में किया गया। इसरो तथा सीएनईएस मेघ ट्रापिक्स नामक वैज्ञानिक उपग्रह कार्यक्रम पर सहभागी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसका प्रक्षेपण इसरो के पीएसएलवी प्रक्षेपक पर वर्ष 2010 के मध्य में किया जाना निर्धारित है। इसरो द्वारा अभिकल्पित एवं निर्मित एक अन्य उपग्रह 'सरल' (आर्गोस तथा अल्तिका के लिए उपग्रह) को 2009-10 की अवधि के दौरान प्रक्षेपित किए जाने की आशा है, जिसमें सीएनईएस का सक्रिय सहयोग होगा। आशा की जाती है कि इन दोनों उपग्रहों से जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैश्विक चिन्ताओं के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। इसरो तथा सीएनईएस के बीच संयुक्त कार्यकारी दल की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

जनवरी, 2008 में राष्ट्रपति सरकोजी की भारत यात्रा तथा सितंबर, 2008 में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान जारी भारत-फ्रांस संयुक्त वक्तव्यों में की गई वचनबद्धताओं के अनुसरण में इस वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ बनाया गया।

भारत-फ्रांस शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (आईएफईईपी) (पेरिस, मार्च 2009) से संबद्ध संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक में निम्नलिखित के जरिए शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा युवाओं के बीच सहयोग को और गहन बनाने पर सहमति हुईः (I) भारत-फ्रांस विश्वविद्यालय कंसोर्टियम (सीआईएफयू) को सुदृढ़ बनाना, (II) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना ('मैसन डिस साइंसेस डि आई होमे'/ यूजीसी/ आईसीएसएसआर रूपरेखा के तहत), उदार वीजा व्यवस्था के जरिए भारत-फ्रांस साइबर विश्वविद्यालय एवं छात्रों/ विद्वानों/ शोधकर्ताओं की आवाजाही में वृद्धि, तथा (III) राजस्थान में एक नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना में फ्रांस का सहयोग। संस्थागत आधार पर अब भारत और फ्रांस के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के बीच संपन्न समझौता ज्ञापनों की संख्या 300 से अधिक हो गई है। फिलहाल फ्रांस में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 1700 है।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं, प्रकाशनों, सेमिनारों तथा वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान हेतु स्थापित सीईएफआईपीआरए रूपरेखा के अंतर्गत सहयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। चिकित्सा अनुसंधान, नए टीकों के विकास तथा भारत में आधुनिक चिकित्सा प्रयोगशालाओं की स्थापना के संबंध में भी आईसीएमआर तथा आईएनएसईआरएम के बीच ठोस सहयोग किया जा रहा है।

अक्तूबर, 2009 में फ्रांस में आयोजित वार्षिक संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में कमिशरेट ए इनर्जी एटामिक तथा भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच संपन्न सहयोग करार की समीक्षा

की गई। इस अवसर पर परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष और सीईए द्वारा एक संशोधन करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा विभाग जूल्स होरोविज रिएक्टर के निर्माण तथा प्रचालन से संबद्ध कंसोर्टियम में भाग ले सकेगा। सीनेट द्वारा 16 अक्तूबर, 2009 को असैनिक परमाणु सहयोग से संबद्ध अंतर्सरकारी करार को सर्वसम्मति से पारित किए जाने के उपरान्त राष्ट्रीय असेंबली ने भी 24 नवंबर, 2009 को इस करार का अनुसमर्थन कर दिया।

सीनेट द्वारा 16 अक्तूबर, 2009 को असैनिक परमाणु सहयोग से संबद्ध करार को सर्वसम्मति से पारित किए जाने के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय असेम्बली ने 24 नवंबर, 2009 को इस करार का अनुसमर्थन कर दिया। 14 जनवरी, 2010 को अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया जिसके उपरांत यह करार लागू हो गया है।

वर्ष 2009 के दौरान सांस्कृतिक संबंधों का पर्याप्त संवर्धन हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आचार्य अमजद अली खान तथा पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा पेरिस के प्रतिष्ठित स्थानों में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने तथा दृश्य कला की 82 प्रदर्शनियों (फोटो एवं चित्रकला) का आयोजन किए जाने सहित 70 से अधिक महत्वपूर्ण मंचीय कलाओं का प्रदर्शन किया गया। भारतीय सिनेमा ने मूसी गुनेत 'इंडियन समर' में आयोजित वार्षिक फिल्म महोत्सव सहित 17 बड़े फिल्म महोत्सवों में भाग लिया। इनमें इस वर्ष मराठी और मलयाली फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। केन फिल्म महोत्सव में युवा एवं नए भारतीय निर्देशकों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यधारा के सिनेमा पर आधारित चार कार्यक्रमों ने पेरिस तथा फ्रांस के अन्य शहरों में सभी आयु वर्गों के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जनवरी, 2009 में आयोजित 'सैलोन डू सिनेमा' में भारत एक भागीदार राष्ट्र था। अभी व्यापार मेलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मिलाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। फ्रांस में भारत ने पांच व्यापार एवं सांस्कृतिक मेलों में भाग लिया जिनमें माउंट पीलियर मेला इत्यादि शामिल था, जहां इस वर्ष भारत ने सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से 8 सांस्कृतिक महोत्सवों का भी आयोजन किया गया।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ. कर्ण सिंह ने सितंबर में पेरिस का दौरा किया और वहां उन्होंने फ्रांस के संस्कृति मंत्री फ्रेड्रिक मितरा तथा कल्चर फ्रांस के अध्यक्ष के साथ बैठकें कीं। उनके बीच हुई चर्चाओं में वर्ष 2010 के आरंभ में फ्रांस द्वारा 'बोनजोर इंडिया' तथा वर्ष 2010-2011 में फ्रांस में 'नमस्ते फ्रांस' नामक भारतीय महोत्सवों को शामिल किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और फ्रांस के विदेश मंत्रालय के बीच 17 नवंबर, 2009 को इस विषय पर एक समझौता ज्ञापन संपन किया गया।

कपड़ा मंत्री श्री दयानिधि मारन 31 जनवरी से 3 फरवरी 2010 तक भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सुबोधकांत सहाय भी फ्रांस की विदेश व्यापार मंत्री सुश्री ऐने मैरी इदरेक के आमंत्रण पर 3-5 फरवरी, 2010 तक फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्री 'इंडिया केम-2010' को बढ़ावा देने के लिए 11 से 12 फरवरी, 2010 तक फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे।

वर्ष 2010 की पहली तिमाही के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की योजना है। भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव 'नमस्ते फ्रांस' का शुभारंभ मार्च, 2010 में क्वाई ब्रान्ली संग्रहालय में 'अदर मास्टर्स आफ इंडिया' नामक स्वदेशी कला पर एक प्रदर्शनी के उद्घाटन से किया जाएगा। 'दी लास्ट महाराजाज' नामक भारत की एक वस्त्र प्रदर्शनी, जिसमें हुतीसिंग कलेक्शन को भी शामिल किया जाएगा, का आयोजन फरवरी, 2010 में फ्रांस के येवेरा सेंट लारेंस प्रतिष्ठान में किया जाएगा। इस अवधि के दौरान अनेक मंचीय कलाओं, फिल्म महोत्सवों इत्यादि का भी आयोजन किया जा रहा है।

जर्मनी

जर्मनी यूरोपीय संघ के भीतर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार तथा विश्व व्यापार प्रौद्योगिकी सहयोग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और एक महत्वपूर्ण निवेशक है। वर्ष 2009 विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह चुनाव का वर्ष था। भारत में अप्रैल, 2009 में लोक सभा चुनावों का आयोजन किया गया, जबकि यूरोपीय संसदीय चुनावों, संघीय राष्ट्रपति के चुनाव, अनेक संघीय राज्यों में चुनावों का अंततः सितंबर, 2009 में आयोजित बुन्ड्सटैग चुनावों के आयोजन के साथ जर्मनी में राजनीतिक गहमागहमी जारी रही। बुन्ड्सटैग के चुनावों में चांसलर मार्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी तथा बवारिया की इसकी सहायक पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल रही। फ्री डेमोक्रेटिक (लिबरल) पार्टी इस गठबंधन का एक नया भागीदार है। दो महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों, सीडीयू और सोशल डेमोक्रेटिक के उत्कृष्ठ गठबंधन का समय समाप्त हो गया, जब जर्मनी ने सीडीयू - एसटीपी की विकासोन्मुख कार्यसूची के पक्ष में अपना मतदान किया। सुश्री एंजिले मार्केल ने 28 अक्तूबर, 2009 को चांसलर का पदभार गहण किया, जबकि एफडीपी के श्री गुइडो वेस्टरवेल्ले ने 16-सदस्यीय मंत्रिमंडल में वाइस चांसलर एवं विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण किया। चुनावी वर्ष होने के बावजूद महत्वपूर्ण यात्राओं के संदर्भ में द्विपक्षीय आदान-प्रदान जारी रहा जैसा कि पिछले वर्ष के दौरान भी हुआ था। द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संपर्कों का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भागीदारियों को व्यापक बनाया गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण यात्राएं संपन्न की गईं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार आर. चिदंबरम के नेतत्व में भारतीय वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 25-28 मई, 2009 तक आयोजित दूसरे भारत-जर्मन सीएआर फ्रांउनहोफर सिम्पोसियम में भाग लेने के लिए जर्मनी का दौरा किया। अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष/अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॅ. जी माधवन नायर ने कोंसलर (अंतरिक्ष), भारतीय दूतावास

पेरिस, डॉ. राधिका रामचन्दन के साथ 27-28 मई, 2009 तक जर्मन एयरोस्पेस केंद्र में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का दौरा किया। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान ने 27-28 जून, 2009 तक लिंडाऊ, बवारिया में अयोजित नोबल पुरस्कार विजेताओं के सम्मेलन में भाग लिया। श्री कपिल सिब्बल को लिंडाऊ प्रयासों में किए गए उनके अंशदान के आधार पर उन्हें लिंडाऊ परिषद की मानद सीनेट का सदस्य बनाकर सम्मान दिया गया। रसायन क्षेत्र के 43 भारतीय छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र से संबद्ध अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जर्मनी के बवारिया राज्य के हौफ में 28 जुलाई, 2009 को बवारिया-भारत व्यवसाय एवं विश्वविद्यालय सहयोग केंद्र का उद्घाटन शामिल था। अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी मामलों के निवर्तमान मंत्री डॉ. कार्ल थियोडोर फ्रेनहर वॉन गुटनबर्ग तथा राजदूत ने संयुक्त रूप से इस केंद्र का उद्घाटन किया।

बढते आर्थिक एवं व्यापारिक संबधों से दोनों देशों में पर्याप्त रुचि जगी है और वर्ष 2009 में अनेक उच्चस्तरीय यात्राएं की गईं। इन यात्राओं में लोवर सेक्सोनी के आर्थिक मंत्री डॉ. फिलिप रोसलर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल का दौरा भी शामिल है जिसने 25 अप्रैल से 2 मई, 2009 तक मुम्बई, पुणे, चेन्नै और कोलाकाता का दौरा किया। यूरोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बवारिया राज्य की मंत्री सुश्री एमिल मूलर के नेतृत्व में बवारिया के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने 22 से 26 जुलाई, 2009 तक कर्नाटक का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य बवारिया और कर्नाटक के बीच सहयोग को और सुदृढ़ बनाने (जून, 2009 में म्यूनिख में आयोजित वैश्विक भारत व्यावसायिक बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए) हेतु कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए ठोस परियोजनाओं की पहचान करना था।

भारतीय पक्ष से होने वाली यात्राओं में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा की यात्रा शामिल थी, जिन्होंने बवारिया राज्य द्वारा 28-30 जून, 2009 तक म्यूनिख में आयोजित प्रथम वैश्विक भारत व्यवसाय बैठक (जीआईबीएम) में भाग लेने के लिए वहां की यात्रा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के संबोधन/क्रियाकलापों में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया गयाः वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों को कम करने हेतु नीतिगत रूपरेखा एवं उपायों के संबंध में सरकार के विचार, सतत विश्व हितैषी परिवेश सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था में विकास की गति को बनाए रखना, दोहा दौर तथा वैश्विक वित्तीय नियामक रूपरेखा के प्रति दृष्टिकोण, भारत-यूरोपीय संघ और भारत-जर्मन आर्थिक संबंध इत्यादि। कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्री श्री डी.एन. बाचीगोडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 16-19 जून, 2009 तक जर्मनी (फ्रैंकफर्ट और बर्लिन) का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध बैठकों में भाग लेना तथा इस क्षेत्र में अवस्थित महत्वपूर्ण संस्थाओं का दौरा करना था। कर्नाटक के बृहत एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री मेरुगेस आर. निरानी ने जर्मन-भारत व्यावसायिक बैठक में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया। कर्नाटक के लिए अलग से एक कार्यक्रम नामतः 'स्पॉटलाइट ऑन कर्नाटक' का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उस राज्य की औद्योगिक क्षमताओं तथा निवेशक हितैषी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना था, जिससे कि वैश्विक फर्मों के निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। जीआईबीएम के दौरान ही एमिला मुलर तथा कर्नाटक के बृहत एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री मेरुगेस आर. निरानी ने कर्नाटक-बवारिया समझौता ज्ञापन द्वारा चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कुछ ठोस परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 30 मार्च, 2009 को एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए।

चुनावों के बाद भी द्विपक्षीय यात्राओं की गति जारी रही और बैडन-उट्टेमबर्ग राज्य के मिनिस्टर प्रेसिडेंट श्री गुंथर ओटिंजर ने 140-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 15-20 नवंबर, 2009 तक भारत (नई दिल्ली, पुणे, मुम्बई और बंगलौर) का दौरा किया। यह अब तक भारत आने वाला सबसे बड़ा जर्मन प्रतिनिधिमंडल था। प्रतिनिधिमंडल में राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री, राज्य संसद के सदस्य, प्रेस के सदस्य, कंपनियों के प्रतिनिधि, बैंकर, राज्य पर्यटन अधिकारी तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। राजनीतिक स्तर पर हुई उनकी बैठकों में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित तथा कर्नाटक के राज्यपाल श्री हंसराज भारद्वाज शामिल थे। मंत्री महोदय और उनके प्रतिनिधिमंडल में शामिल अनेक आर्थिक एवं वैज्ञानिक हस्तियों ने बैठकों में भाग लिया और भारत में कार्यरत जर्मनी की कंपनियों का दौरा किया।

विदेश और सुरक्षा नीति पर जर्मन चांसलर के सलाहकार डॉ. क्रिस्टोफ ह्यूसेन तथा भारतीय राष्ट्रीय सुरखा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन, भारत-जर्मन सामरिक संवाद के सह अध्यक्ष हैं, जिसकी बैठक 21 दिसंबर, 2009 को नई दिल्ली में हुई।

कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती पानाबका लक्ष्मी ने फ्रैंकफर्ट में आयोजित हेमटेक्सटाइल मेला, 2010 तथा हैनोवर में आयोजित डोमटेक्स मेला, 2010 में भाग लेने के लिए 15-20 जनवरी, 2010 तक जर्मनी का दौरा किया।

जर्मन संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. होर्स्ट कोहलर 1-6 फरवरी, 2010 तक भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी तथा पत्रकार शामिल होंगे। वे नई दिल्ली, पुणे और मुम्बई जाएंगे।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री दयानिधि मारन जर्मनी के प्रमुख वस्त्र निर्यातकों के साथ बैठक करने के लिए 3-4 फरवरी, 2010 तक फ्रैंकफर्ट का दौरा करेंगे।

रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री एम.के. अलगिरी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8-12 फरवरी, 2010 तक जर्मनी का दौरा करेंगे।

आयरलैंड

भारत-आयरलैंड संबंधों के विविध क्षेत्रों में निरन्तर विकास होता रहा। खासकर आर्थिक एवं व्यावसायिक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी

तथ शिक्षा क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विशेष संवर्धन हुआ। आयरलैंड में स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीयों की बढ़ती संख्या तथा आयरलैंड में उच्च शिक्षा हेतु जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में हुई पर्याप्त वृद्धि और सामानों एवं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में निरन्तर हो रही वृद्धि से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कार्यकलापों को बढ़ावा मिला।

डॉ. टी. रामासामी, सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) ने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से संबद्ध द्विपक्षीय करार के अंतर्गत आयोजित संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए मई, 2009 में आयरलैंड का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने आयरलैंड के विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध एक करार पर हस्ताक्षर किए।

जून, 2009 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आयरलैंड की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान मिला। यात्रा के दौरान उन्होंने आयरलैंड की राष्ट्रपति मैरी मैकलीस के साथ मुलाकात की। आयरलैंड के विदेश मंत्री माइकल मार्टिन ने उनके सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। डॉ. कलाम ने ट्रिनिटी कालेज, डबलिन में बुद्धिजीवियों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने वर्ष 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने संबंधी अपने विजन का उल्लेख किया और साथ ही दोनों देशों के बीच साझे हित के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित किया।

भारत और आयरलैंड के बीच विदेश कार्यालय परामार्शों के पांचवे दौर का आयोजन सितंबर, 2009 में नई दिल्ली में किया गया, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के रोडमैप की पहचान की गई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 'भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता' विषय पर डबलिन के ट्रिनिटी कालेज में सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए अक्तूबर, 2009 में आयरलैंड का दौरा किया।

इटली

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ला-अकिला में आयोजित जी-8/जी-5 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7-11 जुलाई, 2009 तक इटली का दौरा किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने इटली के प्रधान मंत्री श्री सिल्वियो वर्लुसकोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई तथा आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई।

इससे पूर्व विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के स्थिरीकरण पर आयोजित जी-8 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 25-27 जून, 2009 तक इटली का दौरा किया था। विदेश मंत्री ने इस बैठक के दौरान इटली के विदेश मंत्री श्री फ्रैंको फरातीनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

जी-8/जी-5 कार्यकलापों के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने 12-14 सितंबर, 2009 तक रोम में आयोजित जी-8/जी-5 सभापतियों के सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इटली के चैम्बर आफ डेपुटीज के सभापति श्री जीआनफ्रांको फिनी के साथ द्विपक्षीय चर्चाएं कीं।

इटली के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वी. कैम्पोरिन ने 23-26 सितंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया।

अन्य यात्राओं में निम्नलिखित शामिल हैः श्री शरद पवार, कृषि मंत्री (15-18 नवंबर, 2009); श्री दयानिधि मारन, कपड़ा मंत्री (28-31 अक्तूबर, 2009);डॉ. अभिजीत सेन, सदस्य योजना आयोग (18-20 अप्रैल, 2009); श्रम सचिव (29-31 मार्च, 2009); कृषि सचिव (18-20 अप्रैल, 2009); पर्यावरण सचिव (22-24 अप्रैल, 2009); आर्थिक संबंध सचिव (23-24 अप्रैल, 2009); पेट्रोलियम सचिव (24-25 मई, 2009); विदेश सचिव (26-26 जून, 2009)।

इटली के आर्थिक विकास मंत्री श्री क्लाउडियो अस्काजोला ने उप मंत्री एडोल्फो उरसो के साथ भारत के लिए एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल में इटली के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा इटली के 120 व्यावसाइयों का एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। यह यात्रा 14-16 दिसंबर, 2009 तक हुई। आर्थिक सहयोग से संबद्ध भारत-इटली संयुक्त आयोग के 18वें सत्र का आयोजन 14 दिसंबर, 2009 को नई दिल्ली में इसी यात्रा के दौरान किया गया। बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा तथा इटली के मंत्री श्री अस्काजोला ने की तथा इटली के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली और मुम्बई में फिक्की के समन्वय से परस्पर व्यावसायिक वार्तालाप भी हुआ।

लक्ज्मबर्ग

भारत और लक्ज्मबर्ग ने 29-30 सितंबर, 2009 तक भारत के प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि की लक्ज्मबर्ग यात्रा के दौरान 30 सितंबर, 2009 को सामाजिक सुरक्षा करार के क्रियान्वयन हेतु सामाजिक सुरक्षा (एसएसए) तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबद्ध एक करार पर हस्ताक्षर किए।

भारत, बेल्जियम, लक्ज्मबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के बीच विद्यमान आर्थिक संयुक्त आयोग के 11वें दौर का आयोजन 8 वर्षों के अंतराल के बाद 4-5 मई, 2009 तक ब्रसेल्स में किया गया।

लक्ज्मबर्ग भारत में 26वां तथा यूरोपीय संघ के भीतर 11वां सबसे बड़ा निवेशक है।

आर्थिक मामलों से संबद्ध डच संसदीय स्थाई समिति के एक छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन के निमंत्रण पर 22-24 दिसंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने पुणे, बंगलौर और मुम्बई का भी दौरा किया।

लक्जमबर्ग के अर्थव्यवस्था एवं विदेश व्यापार मंत्री जिनोट क्रेके के नेतृत्व में एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल ने 9-14 जनवरी, 2009 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई का भी दौरा किया और व्यावसाइयों के साथ बातचीत की। इसके अतिरिक्त, उनकी अनेक आधिकारिक बैठकें भी हुईं। वर्ष 2004 में इस पद पर नियुक्ति के बाद उनकी भारत की यह चौथी यात्रा थी और साथ ही यह अप्रैल, 2007 के बाद लक्जमबर्ग से होने वाली पहली मंत्रिस्तरीय यात्रा थी। पूर्व की अनेक यात्राएं, जिनमें उन्होंने इसी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया था, वर्ष, 2005 (28 मार्च-2 अप्रैल), 2006 (28-29 मार्च) तथा 2007 (23-26 अप्रैल) को हुई थीं।

नीदरलैंड

इस वर्ष के दौरान भारत और नीदरलैंड संबंध सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे। हमारे बहुफलकीय संबंधों में चौतरफा विकास हुआ तथा दोनों पक्षों से उच्चस्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान किया गया। व्यापार और निवेश सहयोग भारत-नीदरलैंड संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद इसमें संतोषजनक प्रगति दर्ज की गई। दोतरफा व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो रही है और वर्ष 2008 में 3.86 बिलियन यूरो का व्यापार किया गया। नीदरलैंड द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा तथा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोनों के लिहाज से भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक है। यह बात महत्वपूर्ण है कि व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में है।

इस वर्ष की विशेष बात प्रवासी भारतीय दिवस-यूरोप रही, जिसका आयोजन 19 सितंबर, 2009 को हेग में किया गया। भारत सरकार द्वारा विदेश में मनाए जाने वाले प्रवासी दिवसों की कड़ी में यह इस प्रकार का तीसरा कार्यक्रम था। नीदरलैंड में पर्याप्त संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और उनकी अनुमानित संख्या 2,00,000 है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि ने इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए नीदरलैंड का दौरा किया। डच पक्ष का नेतृत्व पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. रुडलबर्स, सामाजिक एवं रोजगार मंत्री श्री पीट हेने होनर तथा हेग के महापौर श्री जे. वैन आर्टसेन द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप यूरोप में भारतीय मूल के प्रमुख सदस्य एक साझे मंच पर आने में सफल हुए तथा भारत-यूरोपीय संघ को संवर्धित करने में भारतीय मूल के लोगों की भूमिका पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संस्कृति, विरासत एवं परम्परा के समक्ष उत्पन्न अवसरों एवं चुनौतियों तथा उनके लिए भारत में उपलब्ध व्यापार एवं निवेश अवसरों पर भी विचार-विमर्श किए गए।

नीदरलैंड के सामाजिक एवं रोजगार मंत्री श्री पीट हैंडोनर ने 22-24 अक्तूबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत तथा नीदरलैंड के बीच सामाजिक सुरक्षा लाभों का आदान-प्रदान किया जाना सुविधाजनक हो सकेगा और दोनों देशों के बीच कुशल मानव संसाधनों की आवाजाही को प्रोत्साहन मिलेगा। हैंडोनर ने श्रम मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की तथा श्रम से जुड़े मुद्दों पर द्विपक्षीय तौर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाए जाने पर चर्चा की।

अन्य यात्राओं में शामिल थीं, अफगानिस्तान पर प्रधान मंत्री के विशेष दूत राजदूत एस.के.लाम्बा की यात्रा, जिन्होंने 31 मार्च, 2009 को अफगानिस्तान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 16-17 जून, 2009 तक हेग में आयोजित परमाणु आतंकवाद की रोकथाम से संबद्ध वैश्विक बहस की 5वीं बैठक में भी भाग लिया।

कोंसली सहयोग क्षेत्र में एक उल्लेखनीय घटनाक्रम यह रहा है कि नीदरलैंड ने निजी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संबद्ध हेग अभिसमय के अंतर्गत विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के वैधीकरण की अपेक्षा को समाप्त करने वाले हेग अभिसमय में भारत को शामिल किए जाने से अपनी आपत्ति को वापस ले लिया है। इस अधिमिलन से जन्म एवं विवाह प्रमाणपत्र जैसे भारतीय दस्तावेजों के वैधीकरण की अनिवार्यता समाप्त हो गई है, जिससे कि इनका उपयोग नीदरलैंड के साथ-साथ हेग अभिसमय में शामिल अन्य सभी देशों में किया जा सकता है।

डच प्रधान मंत्री के विदेश नीति एवं सुरक्षा सलाहकार श्री कैरल वान उस्टरोम ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन के निमंत्रण पर 22-24 दिसंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया।

आर्थिक मामलों से संबद्ध डच संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्ष सुश्री ए.जे. टिमर के नेतत्व में एक छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 2-9 जनवरी, 2010 तक भारत का दौरा किया।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन और पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा के 24-26 फरवरी, 2010 तक रॉटरडम नगर में आयोजित होने वाले गरीबी के विरुद्ध शहरों के वैश्विक संघ (डब्ल्यूएसीएपी) के 7वें मंच के लिए महापौर एवं निगम आयुक्तों के प्रतिनिधिमंडल के साथ नीदरलैंड जाने की आशा है।

साझा बाजार कोष

भारत ने इस वर्ष के दौरान एम्सटर्डम स्थित साझा बाजार कोष के मुख्यालय में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने अपनी वचनबद्धता के अनुरूप साझा बाजार कोष से संबंधित अपने सभी दायित्वों को पूरा करना जारी रखा। भारत ने 15-16 दिसंबर, 209 तक हेग में आयोजित साझा बाजार व्यापार की शासी परिषद की 21वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री दिनेश शर्मा को साझा बाजार कोष के सदस्य राज्यों, जिसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा सर्बिया शामिल हैं, द्वारा वर्ष 2010 से आरंभ होकर दो वर्ष के लिए 21वीं सदी की कांस्टीटुएंसी का कार्यकारी निदेशक चुना गया। भारत ने 14 दिसंबर, 2009 को हेग स्थित विश्व मंच

में आयोजित साझा बाजार कोष की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज के बाजारों की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया।

पुर्तगाल

वर्ष 2009-10 के दौरान पुर्तगाल के साथ हमारे पारम्परिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा गया। विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने लोकतंत्रों के समुदाय के 5वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया और लिस्बन में 11 जुलाई, 2009 को पुर्तगाल के विदेश मंत्री लुई अमाडो की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया।

इस वर्ष रक्षा क्षेत्र में सक्रिय सहयोग किया गया। मेजर जनरल अभिजीत गुहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय डिफेंस कालेज के 16-सदस्यीय समूह ने 17-22 मई, 2009 तक पुर्तगाल का दौरा किया। इसके साथ रियर एडमिरल एसपीएस चीमा, एवीएस, एनएम के कमान में भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के दो युद्धपोतों-आईएनएस दिल्ली तथा आईएनएस ब्यास ने 8-11 जुलाई, 2009 तक पुर्तगाल का दौरा किया।

सदस्य सचिव (वित्त) श्री आर. अशोक के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 21-24 अप्रैल, 2009 तक लिस्बन में आयोजित आईटीयू से संबद्ध नीतिगत मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंच की बैठक के लिए पुर्तगाल का दौरा किया। अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे संसद सदस्य (राज्य सभा) डॉ. के. कस्तूरीरंगन जो 'अंडरस्टैंडिंग एंड गवर्निंग रिस्क ऑफ प्लेनेटरी स्केल जियो इंजीनियरिंग' विषय पर बीज व्याखाता थे और टेरी के डॉ. राजेन्द्र पचौरी जो 'जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास की चुनौती' विषय पर बीज व्याख्याता थे।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा भेजे गए कलाकारों में वायलिन वादक डॉ. एल. सुब्रमण्यम तथा शहनाई वादक पंडित अशोक चौरसिया शामिल थे, जिन्होंने पुर्तगाल के संगीत प्रेमियों, भारतीय समुदाय के लोगों तथा अन्य की उपस्थिति में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

स्पेन

वर्ष 2009-10 भारत और स्पेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने स्पेन के सम्राट के निमंत्रण पर 20-23 अप्रैल, 2009 तक स्पेन का भारत से होने वाला पहला राजकीय दौरा किया। सम्राट से मुलाकात करने के अतिरिक्त उन्होंने प्रधान मंत्री जापाटेरो के साथ विस्तृत चर्चाएं कीं। अवसंरचना, कृषि, पर्यटन, लैटिन अमरीका में सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, एसएमई तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं सहयोग जैसे सात ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें द्विपक्षीय सहयोग को संवर्धित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने अगले पांच वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को बढ़ाकर दोगुना करने का भी प्रस्ताव किया। उनकी यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गएः

1. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापन
2. पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
3. नवीकरणीय ऊर्जा से संबद्ध समझौता ज्ञापन

इस राजकीय यात्रा के उपरांत स्पेन के युवराज प्रिंस फिलिप ऑफ आस्ट्रियाज ने भारत के उपराष्ट्रपति के आमंत्रण पर 10-12 नवंबर, 2009 तक भारत में अपना सर्वप्रथम सरकारी दौरा किया। उनके साथ प्रिंसेस लेटेजिया भी आई थीं। नई दिल्ली में प्रिंस ने उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष की नेता तथा विदेश मंत्री के साथ बैठकें कीं। राष्ट्रपति महोदया ने युवराज एवं प्रिंसेस के सम्मान में दोपहर के भोज का व्यक्तिगत तौर पर आयोजन किया। युवराज ने नई दिल्ली में स्पेन के विख्यात लेखक निगूएल डि सर्वेन्टीज के नाम पर नई दिल्ली में सर्वेन्टीज संस्थान तथा मुम्बई में एक निवेश सेमिनार का उद्घाटन किया।

कृषि, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस ने विगो (गैलीशिया) में आयोजित मात्स्यिकी मंत्रियों के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा विश्व मात्स्यिकी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 13-17 सितंबर, 2009 तक स्पेन का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पर्यावरण, ग्रामीण तथा समुद्री मामलों के मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं और उन्होंने सेंटियागो दि कम्पुस्टेला के महापौर के साथ मुलाकात की।

विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने बार्सीलोना के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र द्वारा '21वीं सदी में युद्ध और शांति' विषय पर आयोजित किए जाने वाले सेमिनार में भाग लेने के लिए 15-17 जनवरी, 2010 तक बार्सीलोना का दौरा किया।

पर्यटन तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्री कुमारी शैलजा ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (मुख्यालय मैड्रिड में) के 5वें रीडरशिप मंच तथा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, 2010 में भाग लेने के लिए 18-22 जनवरी, 2010 तक मैड्रिड का दौरा किया।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ए. राजा 15-17 फरवरी, 2010 तक बार्सीलोना में आयोजित किए जाने वाले जीएसएमए मोबाइल विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए स्पेन की यात्रा करने वाले हैं।

युनाइटेड किंगडम

इस वर्ष की मुख्य बात 27-29 अक्तूबर, 2009 तक राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील की युनाइटेड किंगडम की राजकीय यात्रा रही, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा युनाइटेड किंगडम की ऐसी तीसरी यात्रा तथा वर्ष 2004 में भारत और युनाइटेड किंगडम के बीच रणनीतिक भागीदारी की स्थापना किए जाने के बाद पहली राजकीय यात्रा थी। राष्ट्रपति जी ने ब्रिटेन की महारानी तथा शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने प्रधान मंत्री गोर्डन ब्राउन, कंजरवेटिव पार्टी के नेता डेविड कोमरोन तथा लिबरल पार्टी के नेता निक क्लेग से

मुलाकात की। एक समारोह में राष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ किए जाने के प्रतीक के रूप में महारानी से 'बैटन' प्राप्त किया। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जी ने युनाइटेड किंगडम में भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें कीं।

प्रधान मंत्री ने लंदन में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में एक अप्रैल, 2009 को युनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री गोर्डन ब्राउन के साथ मुलाकात की। उन्होंने 8 जुलाई, 2009 को इटली के ला अकिला में आयोजित जी-8 शिखर सम्मेलन के दौरान तथा 25 सितंबर, 2009 को जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान भी श्री गोर्डन ब्राउन से मुलाकात की। उन्होंने नवंबर, 2009 में पोर्ट आफ स्पेन में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान भी युनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री गोर्डन ब्राउन से मुलाकात की।

भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा तथा युनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव डेविड मिलिबैंड की बैठक 25 जून, 2009 को त्रिस्ते में हुई।

इसके अतिरिक्त, अनेक मंत्रिस्तरीय आदान-प्रदान भी हुए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने 21-24 मई, 2009 तक युनाइटेड किंगडम का दौरा किया। उदीयमान बाजार शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 17-18 सितंबर, 2009 तक उन्होंने पुनः वहां की यात्रा की। वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने जी-20 वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भाग लेने के लिए 4-5 सितंबर, 2009 तक लंदन के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने 6-7 नवंबर, 2009 तक स्काटलैंड में आयोजित एक बैठक में भाग लिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने'भारत निर्माण - सड़क अवसंरचना शिखर बैठक' शीर्षक से आयोजित एक रोड शो में भाग लेने के लिए 1-2 सितंबर, 2009 तक लंदन का दौरा किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने एक अन्य रोड शो में भाग लेने के लिए 8-9 सितंबर, 2009 तक लंदन का दौरा किया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने 4 फरवरी, 2010 को लंदन में आयोजित संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको) के छठे सत्र में भाग लेने के लिए लंदन का दौरा किया।

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने यूके-भारत शिखर मंच की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए 13-15 फरवरी, 2010 तक युनाइटेड किंगडम का दौरा किया।

व्यवसाय, नवाचार तथा कौशलों से संबद्ध फर्स्ट सेक्रेटरी आफ स्टेट तथा सेक्रेटरी आफ स्टेट लार्ड मंडेल्सन ने 18-23 दिसंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। दिल्ली के अतिरिक्ल लार्ड मंडेल्सन ने बेंगलुरु का भी दौरा किया।

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल पी.वी. नायक ब्रिटेन के अपने समकक्ष के निमंत्रण पर 14-19 मार्च, 2010 तक युनाइटेड किंगडम का दौरा करेंगे।

एयर मार्शल एस.सी. मुकुल एवीएसम, वीएम, वीएसएम चीफ आफ इंटीग्रेटेड स्टाफ 26-28 फरवरी, 2010 तक युनाइटेड किंगडम की यात्रा पर जाने वाले हैं।

भारत-यूके गोलमेज बैठक का आयोजन 26-28 फरवरी, 2010 तक डिजनी पार्क युनाइटेड किंगडम में किया जाएगा।

भारत के मुख्य न्यायधीश डॉ. के.जी. बालकृष्णन ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 'न्यायिक सुधारों के लिए न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में भाग लेने के लिए 13-15 जून, 2009 तक लंदन का दौरा किया। कानून एवं न्याय मंत्री श्री वीरप्पा मोइली ने इंग्लैंड तथा वेल्स में विधि वर्ष के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए 29 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2009 तक लंदन का दौरा किया।

कार्यकारी संचालन समूह (थल सेना) की बैठकों का आयोजन नई दिल्ली में 14 से 16 सितंबर, 2009 तक किया गया। भारत-यूके सैन्य उप-समूह की बैठक का आयोजन 14 से 16 अक्तूबर, 2009 तक नई दिल्ली में किया गया।

युनाइटेड किंगडम पक्ष की ओर से न्याय मंत्रालय में संसदीय अंडर सेक्रेटरी लार्ड बाच ने 23-28 अगस्त, 2009 तक भारत का दौरा किया। अंतर्राष्ट्रीय विकास मामलों के सेक्रेटरी आफ स्टेट एडवर्ड मिलीबैंड ने 1-2 सितंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। व्यवसाय, नवाचार एवं कौशल तथा विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय में मिनिस्टर आफ स्टेट लार्ड मार्विन डेविस ने 14-18 सितंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। जलवायु परिवर्तन मामलों के राज्य मंत्री लार्ड हंट ने 22-23 अक्तूबर, 2009 तक भारत का दौरा किया।

कंजरवेटिव फ्रेंड आफ इंडिया (सीएसआईएन) के अध्यक्ष शैलेश बारा के नेतृत्व में संसद सदस्यों के एक 6-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 27 जुलाई से 2 अगस्त 2009 तक भारत का दौरा किया। लार्ड अल्देरडाइस के नेतृत्व में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 27 सितंबर से 3 अक्तूबर, 2009 तक भारत का दौरा किया।

द्विपक्षीय व्यापार में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। सामानों एवं सेवाओं का कुल व्यापार लगभग 12 बिलियन पाउंड का हुआ। युनाइटेड किंगडम द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यातों में वर्ष 2008 में लगभग 30 प्रतिशत अर्थात 5.9 बिलियन की वृद्धि हुई, जबकि 2008 में आयात में 17 प्रतिशत अर्थात 6.2 बिलियन पाउंड की वृद्धि दर्ज की गई (युनाइटेड किंगडम के आंकड़े)। भारत द्वारा निवेश किए जाने के लिए युनाइटेड किंगडम अब तक सबसे अधिमानी राष्ट्र है और अगस्त, 2008 तक 6 बिलियन मूल्य के निवेश किए गए हैं। युनाइटेड किंगडम भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युनाइटेड किंगडम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह आकर्षित हुआ है, वे हैं विद्युत, तेल एवं गैस, दूरसंचार तथा सेवा उद्योग।

भारत के केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और युनाइटेड किंगडम के एचएमआरसी के बीच सीमा शुल्क अपराधों

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 25 सितंबर, 2009 को पिट्सबर्ग, अमेरिका में आयोजित जी-20 शिखर बैठक के दौरान ब्रिटिश के प्रधान मंत्री श्री गोर्डन ब्राउन से मुलाकात की।

की रोकथाम करने तथा इन मामलों की जांच में सहयोग को सुविधाजनक बनाए जाने से संबद्ध समझौता ज्ञापन पर 9 नवंबर, 2009 को लंदन में हस्ताक्षर किए गए।

यूरोपीय संघ

भारत तथा यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदार हैं, जिनका संबंध साझे मूल्यों तथा लोकतंत्र, विधिसम्मत शासन, मानवाधिकारों एवं मौलिक आजादी के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सर्वोच्च स्तरों सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित कार्यकलाप किए जाते रहे हैं। वर्ष 2005 में पारित तथा 2008 में पुनरीक्षित भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्रवाई योजना में भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच विद्यमान संबंधों के समग्र पहलुओं को शामिल किया गया है।

विश्व में सबसे बड़े आर्थिक ब्लॉक के रूप में यूरोपीय संघ की ताकत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा एवं पर्यावरण क्षेत्रों से संबद्ध प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उनकी प्रगति के संदर्भ में यूरोपीय संघ के साथ भारत का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। चूंकि, यूरोपीय संघ कार्यकलापों के अधिकाधिक क्षेत्रों में निरन्तर ताकतवर और प्रभावशाली होता जा रहा है। इसलिए, आशा की जा सकती है कि भारत के साथ इसके सहयोग के दायरे में वृद्धि होगी।

यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राज्यों द्वारा लिस्बन संधि का सफलतापूर्वक अनुसमर्थन किए जाने के उपरान्त 19 नवंबर, 2009 को यूरोपीय परिषद ने श्री हरमन वान रोम्पये को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया और सुश्री कैथरिन स्टॉन को विदेश मामलों एवं सुरक्षा नीति से संबद्ध संघ के उच्च प्रतिनिधि एवं विदेश संबंध के प्रभारी यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ 1 दिसंबर, 2009 को लागू संधि से यूरोपीय संघ की संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार आने की संभावना है। इससे यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच विदेश नीति का बेहतर समन्वय करने में सहायता भी मिलेगी।

भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक

10वें भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक का आयोजन 6 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व बारी के आधार पर स्वीडन के प्रधान मंत्री श्री फ्रेडरिक रेनफेल्ट और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जोस मैनुअल दुराओ बरासो ने किया। इस शिखर बैठक में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों की समीक्षा की गई और भारत तथा यूरोपीय संघ के विभिन्न घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। शिखर बैठक में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख निकायों की प्रतिनिधिक क्षमता, पारदर्शिता तथा प्रभाविता में संवर्धन करने के उद्देश्य से इसमें सुधार लाए जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया; आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने का संकल्प व्यक्त किया गया; ऊर्जा सुरक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करते हुए परमाणु संलयन ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत-यूरोपीय संघ करार संपन्न किए जाने को नोट किया गया और व्यापक व्यापार एवं निवेश करार तथा समुद्री परिवहन करार को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न किए जाने की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई।

यूरोपीय संसद

सितंबर, 2009 में आयोजित अपने पूर्ण सत्र में यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संसद में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किए जाने का अनुमोदन किया था और 30 सितंबर, 2009 को औपचारिक रूप से इसका गठन कर दिया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में 20 सदस्य तथा 20 एवजी है। ब्रिटिश एमईपी श्री ग्राहम वाटसन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

भारत-यूरोपीय संघ त्रोइका एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

भारत-यूरोपीय त्रोइका की 20वीं बैठक का आयोजन 30 जून, 2009 को प्राग में किया गया। भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यूरोपीय संघ पक्ष का नेतृत्व विदेश मामलों से संबद्ध यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से चेक गणराज्य के विदेश मंत्री श्री जेन कोहाउट ने किया। विदेश मामलों से संबद्ध यूरोपीय आयुक्त श्रीमती बेनिता फेरेरो वाल्डनर ने किया। भारत-यूरोपीय संघ संबंध, क्षेत्रीय मुद्दों तथा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वैश्विक वित्तीय संकट, अप्रसार एवं ऊर्जा सुरक्षा सहित विविध वैश्विक मुद्दों पर भी त्रोइका बैठक में चर्चा की गई।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का एक नियमित मंच विद्यमान है। इस वर्ष दो बैठकों का आयोजन किया गया। पहली बैठक 15 जून, 2009 को नई दिल्ली में हुई और दूसरी बैठक 28 सितंबर, 2009 को ब्रसेल्स में हुई।

संयुक्त कार्यकारी दल की बैठकें

कोंसली मुद्दों से संबद्ध भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्यकारी दल की 13वीं बैठक का आयोजन 25 मई, 2009 को नई दिल्ली में किया गया। भारतीय पक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों में शामिल थे- वास्तविक यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना, अत्यधिक कागजी कार्रवाई में कमी लाना, वर्क परमिट, भारतीय वाणिज्यिक यात्रियों के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली, समय पर मिलने वाला कोंसली संपर्क तथा सेंजन देशों के जरिए पारगमन करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को परेशान किए जाने की समस्या को दूर करना। यूरोपीय संघ पक्ष ने निम्नलिखित मुद्दों को उठाया - विलंब से दिए जाने वाले कोंसली संपर्क, न्यायालयों द्वारा रिहा किए गए अथवा मुक्त किए गए यूरोपीय संघ के राष्ट्रिकों के लिए अस्थाई पहचान पत्र दिए जाने की संभावना, विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा संपत्तियों की खरीद से संबंधित नियमों को स्पष्ट बनाया जाना, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबद्ध हेग अभिसमय पर प्रगति, यूरोपीय संघ के राष्ट्रिकों के लिए

पर्वतारोहण बचाव कार्यवाहियों के संबंध में भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया जाना, यूरोपीय संघ के कैदियों को फोन करने और फोन सुनने की अनुमति प्रदान किया जाना तथा मुम्बई आतंकी हमले जैसी आपात स्थितियों में यूरोपीय संघ के राष्ट्रिकों को शीघ्र बाहर निकालना सुनिश्चित करना।

आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक का आयोजन 11 जून, 2009 को किया गया। इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई - लश्कर-ए-तैयबा, अल कायदा और तालिबान पर विशेष बल देते हुए भारत के पड़ोस में आतंकी संगठनों से जुड़े मुद्दे, आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध लड़ाई, तीसरे देशों को तकनीकी सहायता, कट्टरवाद की रोकथाम, संयुक्त राष्ट्र में सहयोग (सीसीआईटी, वैश्विक आतंकवाद विरोधी नीति) तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित नए घटनाक्रमों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान।

भारतीय विश्व कार्य परिषद तथा यूरोपीय संघ सुरक्षा अध्ययन संस्थान द्वारा 8 से 9 अक्तूबर, 2009 तक नई दिल्ली में प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त रूप से भारत-यूरोपीय संघ मंच की बैठक का आयोजन किया गया।

ऊर्जा पैनल

भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की बैठक 6 अक्तूबर, 2009 को ब्रसेल्स में हुई। बैठक का समापन इस निर्णय के साथ हुआ कि दोनों पक्ष सहयोग के तीन क्षेत्रों, नामतः ऊर्जा प्रभाविता, कोयला/स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर विशेष बल देंगे।

व्यापार और निवेश

यूरोपीय संघ अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वर्ष 2008 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 60.92 बिलियन यूरो हो गया। यूरोपीय संघ को 29.39 बिलियन यूरो मूल्य का निर्यात किया गया, जबकि यूरोपीय संघ से भारत में 31.53 बिलियन यूरो का आयात हुआ। वर्ष 2008 में विविध सेवा क्षेत्रों में यूरोपीय संघ को किया जाने वाला कुल भारतीय निर्यात 7.94 बिलियन यूरो का था, जबकि यूरोपीय संघ से भारत में किया जाने वाला कुल आयात 8.56 बिलियन यूरो का रहा। वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में भारत द्वारा यूरोपीय संघ को 12.9 बिलियन यूरो मूल्य का निर्यात किया गया, जबकि भारत द्वारा 12.7 बिलियन यूरो मूल्य का आयात किया गया।

यूरोपीय संघ भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ से भारत में किए जाने वाले कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह 4.019 बिलियन यूरो था, जबकि वर्ष 2008 में घटकर यह 3.27 बिलियन यूरो हो गया। भारत यूरोपीय संघ में एक महत्वपूर्ण निवेशक बनकर उभरा। वर्ष 2007 में भारत से किया जाने वाला कुल निवेश 1.003 बिलियन यूरो था, जो वर्ष 2008 में बढ़कर 3.69 बिलियन यूरो हो गया।

महत्वपूर्ण यात्राएं

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई महत्वपूर्ण यात्राओं में शामिल हैं - मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की यात्रा, जिन्होंने यूरोपीय आयोग के साथ विचार-विमर्श करने तथा भारत एवं यूरोपीय आयोग के बीच बहुभाषावाद से संबद्ध संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए 6-8 मार्च, 2009 तक ब्रसेल्स का दौरा किया तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री जितिन प्रसाद की यात्रा, जिन्होंने विदेश मामलों से संबद्ध यूरोपीय आयोग के आयुक्तों के आमंत्रण पर तथा ऊर्जा सुरक्षा पर आयोजित एएसईएम मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 18 जून, 2009 को ब्रसेल्स का दौरा किया।

यूरोपीय संघ की वाणिज्य आयुक्त कैथरीन एस्टोन और कृषि आयुक्त मरियम फिशर बोयल ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 3 सितंबर, 2009 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया।

प्रतिस्पर्धा आयुक्त नीलिये क्रोएस ने सीआईआई द्वारा नई दिल्ली में 'प्रतिस्पर्धा, लोक नीति एवं आम आदमी' विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए 15-18 नवंबर, 2009 को भारत तक यात्रा की।

■■

8 अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए)

भारत और अमरीका दोनों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हित एक समान होते हुए दिखे। इस वर्ष पहली प्राथमिकता वैश्विक, आर्थिक एवं वित्तीय संकट से उबरने की दिशा में कार्य करने की थी। भारत और अमरीका ने शिखर सम्मेलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए आयोजित किया गया था।

प्रधान मंत्री ने लंदन में 2 अप्रैल, 2009 को आयेजित जी-20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और भारत-अमरीकी वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अनेक सकारात्मक और रचनात्मक उपायों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मामलों समेत सभी मुक्त समाजों के लिए भारत के पड़ोस से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद का खतरा और इससे निपटने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर चर्चा की। इस संबंध में दोनों नेताओं के विचार और दृष्टिकोण काफी हद तक मिलते-जुलते थे। राष्ट्रपति ओबामा ने प्रधान मंत्री श्री सिंह को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए नई समग्र अमरीकी कार्यनीति के बारे बताया। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति ओबामा द्वारा समस्याओं को और स्पष्ट रूप से रखने तथा लक्ष्यों को इंगित करने के लिए उनका स्वागत किया और कहा कि भारत हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा और अपने आसपास के प्रदेशों में भी शांति एवं स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करेगा। साथ ही, उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मामलों और उस विधि पर बातचीत की, जिसके जरिए भारत और अमरीका इन मामलों पर मिलकर काम कर सकते हैं तथा दोनों देशों ने जी-20, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के सुदृढ़ीकरण और सुधार तथा दोहा में होने वाले विश्व व्यापार संगठन वार्ता के शीघ्र तथा संतुलित परिणाम, जिसमें विकास संबंधी पहलुओं पर विशेष ध्यान था, के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

अमरीकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा

अमरीका की विदेश मंत्री सुश्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा के आमंत्रण पर 17-21 जुलाई, 2009 के दौरान भारत की यात्रा की और उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और (1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं खोज (2) रणनीतिक सहयोग (3) ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन (4) शिक्षा एवं विकास, और (5) अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं कृषि तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन और सामरिक सुरक्षा के क्षेत्र और सहयोग में और अधिक वृद्धि के लिए भारत-अमरीकी द्विपक्षीय सहयोग हेतु नई कार्यसूची की घोषणा की। उन्होंने आतंकवाद की चुनौती, परमाणु प्रसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा आपसी हित के मामले जैसे निरस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संबंधी सुधार, वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा आदि पर भी चर्चा की। अमरीकी विदेश मंत्री ने प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की।

उक्त मुलाकात के दौरान दो समझौते, यथा प्रौद्योगिकी रक्षोपाय समझौता (अंतरिक्ष) और भारत-अमरीका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अक्षय निधि एवं बोर्ड समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौता में एक भारत-अमरीकी बोर्ड की स्थापना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, अन्वेषण, उद्यम एवं वाणिज्य संबंधी गतिविधियों के लिए एक कोष बनाने का प्रावधान किया गया। प्रौद्योगिकी रक्षोपाय समझौता भारत द्वारा तीसरे देश के अमरीका-निर्मित असैन्य या गैर-वाणिज्यिक उपग्रह या अमरीकी सामानों से निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। दोनों सरकारों ने अपने रक्षा उपस्कर संबंधी प्रस्ताव-पत्र एवं स्वीकृति में अंतिम उपयोग निगरानी पर समझौते की घोषणा की। यात्रा के दौरान भारत-अमरीका संबंधों के महत्व तथा इन दोनों देशों द्वारा जिन वैश्विक एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर कार्रवाई की जाएगी, उसे दर्शाते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

इससे पहले अमरीका के राजनीतिक मामलों के अवर सचिव श्री विलियम जे. बर्न्स ने 10-13 जून, 2009 के बीच भारत की प्रारंभिक यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने विदेश सचिव श्री शिवशंकर मेनन के साथ जुलाई, 2009 में घोषित उपर्युक्त द्विपक्षीय कार्यसूची पर सहयोग के लिए वार्ता की थी। अवर सचिव श्री बर्न्स ने प्रधान मंत्री से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति ओबामा द्वारा संबोधित पत्र सौंपा, जिसमें श्री ओबामा ने उन्हें चुनाव जीतने पर बधाई दी थी और वाशिंगटन आने का अपना निमंत्रण तथा द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।

अन्य उच्चस्तरीय विचार-विमर्श

अमरीका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल जेम्स जोन्स ने 25-26 जून, 2009 के बीच भारत की यात्रा की। उन्होंने श्री एम.के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी से मुलाकात की।

गृह मंत्री

गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 8-10 सितंबर, 2009 के बीच अमरीका के साथ आतंकवाद-निरोध के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की 24 नवंबर, 2009 को व्हाइट हाउस, वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा से मुलाकात।

अमेरिकी विदेश मंत्री सुश्री हिलेरी क्लिंटन की 20 जुलाई, 2009 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात।

को मजबूत बनाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्राप्ति तथा आतंकवादी हमलों की जांच और निवारण पर सूचना और उत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान पर विशेष जोर देते हुए परस्पर सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अमरीका की यात्रा की। इससे पूर्व भारत की ओर से श्री विवेक काटजू, विशेष सचिव (राजनीतिक एवं आईओ), विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में आतंकवाद-निरोध पर भारत-अमरीकी संयुक्त कार्यकारी समूह ने 17 जून, 2009 को वाशिंगटन में अपनी 11वीं बैठक आयोजित की। बैठक में कार्यकारी समूह ने आतंकवाद-निरोध से संबंधित विभिन्न मुद्दों तथा वित्तीय कार्रवाई संबंधी कार्यबल में भारत की सदस्यता पर चर्चा की।

भारत के विदेश सचिव की अमरीका यात्रा

विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने 21 सितंबर, 2009 को वाशिंगटन में अपने अमरीकी समकक्ष श्री विलियम बर्न्स, राजनीतिक कार्य अवर सचिव, अमरीका से मुलाकात की। साथ ही उन्होनें सुश्री मारिया ओटेरो, लोकतंत्र एवं वैश्विक कार्य अवर सचिव, अमरीका से भी मुलाकात की और भारत-अमरीकी वैश्विक मामला मंच हेतु सहयोग के लिए अभिज्ञात कार्यसूची और मामलों पर विचार-विमर्श किया।

विदेश मंत्री

विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने अमरीकी विदेश मंत्री सुश्री हिलेरी क्लिंटन से 25 सितंबर, 2009 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पश्चात मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक बातचीत और परस्पर हित के अन्य मामलों में हुई प्रगति पर चर्चा की।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन ने 25-29 अक्तूबर, 2009 के बीच अमरीका की यात्रा की। उन्होंने अपने अमरीकी समकक्ष जनरल जेम्स जोन्स, रक्षा सचिव, सचिव होमलैन्ड सिक्योरिटी, डायरेक्टर एफबीआई और अनेक सीनेटरों तथा कांग्रेसमैन से मुलाकात की। एनएसए ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र का भी भ्रमण किया।

अमरीका के राजनीतिक कार्य के अवर सचिव

श्री विलियम बर्न्स, जो अमरीका के राजनीतिक कार्य के अवर सचिव हैं, ने नवंबर, 2009 में वाशिंगटन में अमरीकी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधान मंत्री की उच्चस्तरीय बैठक के लिए कार्यसूची और तैयारियों पर विचार-विमर्श करने के लिए 15-16 अक्तूबर, 2009 के बीच भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव के साथ मुलाकात की और मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया समेत रणनीतिक वार्ता में भाग लेने वाले कई मंत्रियों से मुलाकात की।

तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति

भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29-31 अक्तूबर, 2009 के बीच नई दिल्ली आए। साथ ही वे मुम्बई भी गए।

प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा

22-24 नवंबर, 2009 के बीच प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भारत में 20 जुलाई, 2009 को आए अमरीकी विदेश मंत्री द्वारा संप्रेषित अमरीकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर अमरीका गए। यह पहला ऐसा मौका था, जिसे स्वयं अमरीकी राष्ट्रपति ने आयोजित किया था। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने एक अमरीकी पहल करते हुए सर्वसम्मति से भारत-अमरीकी संबंधों के प्रगाढ़ होने पर एक संकल्प स्वीकृत किया और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अमरीका यात्रा का स्वागत किया।

इस अवसर पर प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत-अमरीकी साझेदारी के एक नए चरण की शुरुआत की और इसे 'वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' बताया। दोनों ही देशों ने इस बात की पुष्टि की कि भारत और अमरीका के समान लक्ष्य और पूरक बल से 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस आधार मिलेगा और परस्पर लाभ, एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अमरीका-भारत की वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने और एक बेहतर विश्व बनाने में महत्वपूर्ण योगदन देने का संकल्प किया।

भारत के प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति ने ऐसे वैश्विक संस्थानों को स्थापित करने की नितांत आवश्यकता पर जोर दिया 'जो समावेशी हों और वर्तमान एवं भावी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हों तथा संयुक्त राष्ट्र इसकी सुरक्षा परिषद सहित में वास्तविक सुधार इस प्रकार लाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की, जो 21वीं सदी की वर्तमान सच्चाइयों को प्रतिबिंबित करे' और इस प्रकार 'नई सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रतिनिधि, विश्वसनीय और कारगर मंच के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करने की इसकी क्षमता में वृद्धि करे।' उनकी चर्चा में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक 'खुली एवं समावेशी संरचना' की आवश्यकता भी शामिल थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समाधान के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में जी-20 के उद्भव का स्वागत किया । दोनों नेताओं ने जी-20, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संरचना को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ एवं कार्यक्षम ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर हुए समझौते का स्वागत किया, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर भी विचार-विमर्श किया तथा इन क्षेत्रों में नई पहल और अगले द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की। उन्होंने दोनों सरकारों के लिए आपसी हित वाले वैश्विक मामलों तथा तात्कालिक चिन्ता वाले क्षेत्रीय मामलों - खासकर भारत के पड़ोस से उपजने वाले आतंकवाद के खतरे पर बातचीत की। उन्होंने 26 नवंबर, 2008 के आतंकी हमले के दोषियों को सजा दिलाने तथा इन आतंकवादियों को शरण देने वाले सुरक्षित स्थानों और इनकी गतिविधियों को खत्म करने की नितांत आवश्यकता पर बल दिया।

वैश्विक परमाणु अप्रसार और सार्वभौमिक, निष्पक्ष तथा पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए आधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी वाले इन दोनों देशों के नेताओं ने एक ऐसा विश्व बनाने पर दृढ़ता दिखाई, जो परमाणु हथियारों से मुक्त हो और इस पर साथ-साथ काम करने की शपथ ली। उन्होंने एक दूसरे से नियमित रूप से परामर्श करने तथा बहुपक्षीय, निष्पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जांच योग्य फिसाइल सामग्री के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में निष्पन्न संधि के अनुसार शीघ्र वार्ता करने की इच्छा प्रकट की।

रक्षा के क्षेत्र में दोनों सरकारों ने मौजूदा वार्ता के जरिए परिस्पर लाभदायक रक्षा सहयोग, सेवा-स्तरीय आदान-प्रदान, रक्षा अभ्यास तथा व्यापार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सहयोग और इन कार्यों को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था में तेजी लाने की प्रक्रिया को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक हरित साझेदारी निष्पन्न करने पर सहमति हुई। यात्रा के दौरान भारत के सौर और पवन ऊर्जा अनुसंधान केंद्रों के साथ सहयोग के लिए अमरीका की राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशालाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए गए।

साथ ही कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन के जरिए भारत-अमरीकी कृषि सहयोग बढ़ाने तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विकास हेतु बाहरी अंतरिक्ष से संबद्ध वैज्ञानिक क्षमता अनुप्रयोग तथा कृषि क्षेत्र सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई।

दोनों सरकारें किसी द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत हैं और भारत-अमरीका आर्थिक संबंधों की नई दिशाओं की पहचान के लिए भारत-अमरीका सीईओ फोरम की बैठक बुलाई गई है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और यू.एस. पेटेंट एवं ट्रेड मार्क कार्यालय के बीच एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय (टीकेडीएल) पहुँच करार पर हस्ताक्षर किए गए।

क्षमता अभिवृद्धि, मानव संसाधन विकास और आईपीआर के महत्व के संबंध में सार्वजनिक तौर पर जागरुकता पैदा करने के लिए व्यापक स्तर पर आईपीआर से संबंधित मुद्दों पर समेकित रूप से द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए।

यू.एस. के वाणिज्य विभाग के तहत 'अमरीका में निवेश' और औधोगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के एक संयुक्त उद्यम 'भारत में निवेश' व भारत की विभिन्न राज्य सरकारों और फिक्की (एफआईसीसीआई) के बीच यू.एस. और भारत में द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

शिक्षा के क्षेत्र में दोनों सरकारों ने '21वीं शताब्दी ज्ञान पहल' शीर्षक के अन्तर्गत एक योजना शुरू की है। इसके तहत कुल 10 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किए जाने की योजना है। यह राशि अमरीका और भारतीय विश्व विद्यालयों के बीच विश्वविद्यालयीय संपर्क बढ़ाने और जूनियर फैकल्टी के विकास के लिए आबंटित की जाएगी। इसके तहत सामुदायिक कॉलेजों पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जाएगा। उन्होंने फुलब्राइट-नेहरू छात्रवृति कार्यक्रम को विस्तार करने की घोषणा की।

रोग नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए अमरीकी केन्द्रों की भागीदारी से भारत में एक क्षेत्रीय वैश्विक रोग अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अन्य दौरे

भारत सरकार से विचार-विमर्श करने और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति के बारे में हमारा मूल्यांकन एवं मत जानने के लिए अमरीकी राजदूत रिचर्ड हालब्रुक, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के लिए अमरीका के विशेष राजदूत ने 18 जनवरी, 2010 को दौरा किया। वह विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन से मिले और उन्होंने विदेश मंत्री श्री एस.एम.कृष्णा और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से भेंट की।

अमरीका के रक्षा सचिव डॉ. रोबर्ट गेट्स ने 19-20 जनवरी, 2010 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किया और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया। यह दौरा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करने के अवसर पर किया गया।

कांग्रेसी/ संसदीय दौरे

फरवरी, 2009 में अमरीकी नागरिक अधिकारों का नेतृत्व करने वाले प्रणेता डॉ. मार्टिन लूथर किंग के निकट अनुयायी एवं कांग्रेसी जॉन लेविस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ अमरीकी कांग्रेसी और मार्टिन लूथर किंग तृतीय, जो कि माननीय डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बेटे हैं और बहुत से अन्य अमरीकी कांग्रेसी जैसे प्रतिनिधि स्पेंसर बाचस, प्रतिनिधि जिम मैकडॉरमौट, प्रतिनिधि अलग्रीन, प्रतिनिधि लोरेटा सैंचेज, प्रतिनिधि शीला जैक्सन-ली और अन्य कांग्रेसी स्टॉफ तथा अधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई भारत के राष्ट्रपति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने की, क्योंकि अमरीका के पूज्यनीय नागरिक अधिकार प्रणेता डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भारत यात्रा को उस समय अस्वीकार कर दिया गया था, जब वे सन 1959 में महात्मा गाँधी के पैतृक सम्पति का जायजा लेने के लिए धार्मिक यात्रा पर आये थे।

प्रतिनिधि होवार्ट बर्मन के नेतृत्व में एक अमरीकी कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल ने 15-20 अप्रैल, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधि गैरी एकरमैन, प्रतिनिधि शीला जैकशन ली, प्रतिनिधि डेन लूंगरैन, प्रतिनिधि जिम कोष्टा और प्रतिनिधि जिम मौरन शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान मंत्री के साथ बैठक की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के.

नारायणन तथा विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव के साथ मुलाकात की।

अमरीकी सांसद (सीनेटर) जूड ग्रेग के नेतृत्व में अमरीकी सीनेट के एक प्रतिनिधि मंडल ने 31 दिसम्बर, 2009-4 जनवरी, 2010 तक भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में सीनेटर ईवान बइयाह, सीनेटर आरलैन स्पेक्टर, सीनेटर माइकल एनजी, सीनेटर एमई क्लोबूचर और सीनेटर जॉन कार्नाईन शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान मंत्री के साथ बैठक की और भारत अमरीकी संबंधों पर विचार-विमर्श किया।

भारत और अमरीकी संबंधों पर चर्चा के लिए सीनेटर जैफ मरकली, फ्रैंक लॉटेनबर्ग और कांग्रेसी बैरन हिल सहित सीनेटर क्लेरी मैकास्किल की अध्यक्षता में अमरीकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 16 फरवरी, 2010 को भारत का दौरा करेगा।

असैनिक परमाणु सहयोग

10 अक्तूबर, 2008 को दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित असैनिक परमाणु सहयोग करार के अनुसार करार को कार्यान्वित करने के लिए बहुत से कदम उठाये गए। वियना में 21-22 जुलाई, 2009 में 8-9 अक्तूबर, 2009 और इसके पश्चात वाशिंगटन; 6-7 नवंबर, 2009 और 21-22 नवंबर, 2009 के बीच आयोजित किए गए 123 करार के अनुच्छेद 6 (3) के अनुसार भारत और अमरीका पुनः प्रसंस्करण की प्रक्रियाओं और करारों पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का दूसरा दौर 15-19 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है।

भारत और अमरीका के बीच ऊर्जा संबंधी द्विपक्षीय वार्ता के अन्तर्गत गठित किए गए 5 कार्यकारी समूहों में से एक कार्यकारी समूह भारत अमरीका असैनिक परमाणु कार्यकारी, समूह की दूसरी बैठक 28-30 अप्रैल, 2009 को इडाहो नेशनल लैबोरेटरी, इडाहो संयुक्त राज्य अमरीका में आयोजित की गई। दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा एवं रियक्टरों के क्षेत्र में सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की और अपनी अगली बैठक में इस सहयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करने पर आम सहमति व्यक्त की।

अमरीका-भारत व्यापार परिषद और परमाणु ऊर्जा संस्थान वाशिंगटन के नेतृत्व में एक 55-सदस्यीय असैनिक परमाणु ट्रेड मिशन ने 6-11 दिसम्बर, 2009 के दौरान दिल्ली और मुम्बई का दौरा किया। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग और विद्युत मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक की। प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय जनता, निजी क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों और फिक्की (एफआईसीसीआई) और सीआईआई के साथ भी विचार-विमर्श किया। श्री मार्क वैबर, सलाहकार, उद्योग ब्यूरो, अमरीकी वाणिज्य विभाग भी ट्रेड मिशन में शामिल थे।

भारत अमरीकी सिविल परमाणु कार्यकारी समूह ने अपनी तीसरी बैठक 3-5 फरवरी, 2010 के बीच मुम्बई में आयोजित की। बैठक का नेतृत्व परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक (रणनीतिक आयोजना समूह) डॉ. आर बी ग्रोवर और अमरीकी ऊर्जा विभाग में परमाणु ऊर्जा के सहायक सचिव डॉ. वारेन पेटे मिलर ने किया।

ऊर्जा संबंधी द्विपक्षीय वार्ता

अमरीकी ऊर्जा सचिव श्री स्टीवेन चू ने 12-16 नवंबर, 2009 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने 13 नवंबर, 2009 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ भारत अमरीकी ऊर्जा वार्ता संबंधी एक बैठक की सह-अध्यक्षता की। उन्होंने विद्युत मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री जयराम रमेश, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री के विशेष उप राजदूत श्री श्याम सरन के साथ मुलाकात की। दोनों सरकारों ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और एक स्वच्छ ऊर्जा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर आम सहमति व्यक्त की, जिसे बाद में प्रधान मंत्री के अमरीकी दौरे के दौरान अंतिम रूप दिया गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

जनवरी-अक्तूबर 2009 की अवधि में भारत और अमरीका के बीच माल का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 31.5 बिलियन अमरीकी डालर रहा। इस अवधि में भारत ने अमरीका को 17.6 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के माल का निर्यात किया और इसी अवधि में भारत ने अमरीका से 13.9 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के माल का आयात किया। भारत ने 2009 में अमरीका को 28.3 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं का निर्यात किया।

अमरीका भारत में अग्रणी विदेशी निवेशकर्ताओं में से एक है। अप्रैल, 2000 से अगस्त, 2009 की अवधि के दौरान अमरीका से भारत में कुल एफडीआई इक्विटी अंतः प्रवाह 7.44 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जो कि इस अवधि के दौरान भारत में कुल अंतः प्रवाह (इनफ्लॉ) के 8 प्रतिशत के बराबर है। वर्ष 2004 से 2008 के दौरान भारत से यू.एस.- संबद्ध निवेश में प्रतिवर्ष औसतन 48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2008 में भारतीय कम्पनियों ने एम एवं क्यू, इक्विटी भागीदारी एवं अन्य माध्यमों से अमरीकी बाजार में लगभग 8.5 अमरीकी डालर का निवेश किया।

अमरीकी भारत व्यापार परिषद की 34वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने 16-19 जून, 2009 के बीच वाशिंगटन का दौरा किया। उन्होने अमरीका के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि, राजदूत रॉन कर्क से मुलाकात की। इनके साथ उन्होंने इण्डो यू.एस. व्यापार संबंधों पर चर्चा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने अमरीका के वाणिज्य सचिव, श्री गैरी लॉक और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती हेलरी क्लिंटन के साथ भी अमरीकी भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित 'सिनर्जी समिट' के अवसर पर मुलाकात की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 13-15 अक्तूबर, 2009 के दौरान भी वैश्विक सेवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया।

द्विपक्षीय निवेश संधि पर भारत-अमरीका वार्ता का पहला दौर 11-12 अगस्त, 2009 के दौरान नई दिल्ली मे आयोजित किया गया।

सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्री श्री कमल नाथ ने 13-17 सितम्बर, 2009 के बीच अमरीका का दौरा किया। उन्होने यह दौरा भारत में सड़क क्षेत्र पर अमरीकी निवेश प्राप्त करने के संबंध में किया।

भारत अमरीकी आर्थिक द्विपक्षीय वार्ता की एक बैठक 20 अक्तूबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्री माइकल फ्रोमन, अमरीकी राष्ट्रपति के उप सहायक और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कार्यों के लिए अमरीका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जिनके साथ वे आर्थिक द्विपक्षीय वार्ता के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, के साथ भी मुलाकात की।

भारत अमरीकी व्यापार नीति संबंधी फोरम की एक बैठक 26 अक्तूबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा और अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि, राजदूत रॉन किर्क द्वारा संयुक्त रूप से की गई। कृषि, नवोन्मेशी पहल और सृजनात्मकता, निवेश, सेवाओं और टैरिफ तथा नॉन-टैरिफ संबंधी बाधाओं के संबंध में पांचों फोकस समूहों के बीच बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच एक सामाजिक सुरक्षा करार, एक द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। इसे दोनों पक्षों के हितों से जुड़ी मदों के लिए बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आगामी कदम के रूप में देखा गया।

अमरीकी उप व्यापार प्रतिनिधि, राजदूत डीमेट्रियोज मेरेंटिस ने भारत अमरीकी व्यापार नीति संबंधी फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए 11-13 अगस्त, 2009 और फिर 24-26 अक्तूबर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया।

श्री सैम समनर रीड, वाशिंगटन के विदेश सचिव के नेतृत्व में वाशिंगटन राज्य से एक व्यापार मिशन ने 11-21 सितम्बर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली, हैदराबाद एवं मुम्बई में औद्योगिक सदस्यों के साथ बातचीत की।

दूसरे भारत अमरीकी विमानन भागीदारी सम्मेलन का आयोजन 7-9 दिसम्बर, 2009 के दौरान वाशिंगटन डीसी में किया गया। नागर विमानन मंत्रालय के सचिव श्री माधवन नाम्बियार ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधि मंडल में महानिदेशक, नागर विमानन डॉ. नसीम जैदी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री वी.पी. अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। अमरीकी प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व परिवहन सचिव श्री रे लाहूड, प्रशासक, यू.एस. संघीय विमानन प्रशासक श्री रेंडोल्फ बेबीट, अमरीकी उप वाणिज्य सचिव श्री डेनेस हाईटावर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। भारत और अमरीका, दोनों देशों की 80 विमानन कम्पनियों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत अमरीकी नागर विमानन सहयोग को एक नई ऊर्जा प्रदान की और दोनों देशों में स्टेकहोल्डरों, नियामकों, सेवा प्रदाताओं और सरकारों के लिए नागर विमानन संबंधी सहयोग को मजबूत बनाने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म साबित हुआ।

नागर विमानन सुरक्षा पर संयुक्त कार्यकारी समूह की एक बैठक 20 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक समझौता ज्ञापन अमरीका से भारत आने वाले विमानों में यू.एस. द्वारा एयर मार्शलों की तैनाती और दूसरा एयरपोर्ट तकनीकी दौरों को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से सहयोग से संबंधित हैं।

रक्षा संबंध

भारत अमरीकी वरिष्ठ प्रौद्योगिकी और सुरक्षा समूह की पांचवी बैठक 11-12 मई, 2009 के दौरान वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमरीका में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव श्री एस.के. माथुर और रक्षा मामलों के उप अवर सचिव , अमरीकी रक्षा विभाग में रक्षा प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा प्रशासन के कार्यकारी निदेशक श्री जेम्स हर्ष द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस बैठक में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

एडमिरल टिमोथी कीटिंग, कमांडर यू.एस. पैसिफिक कमांड ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद और समुद्र तटीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार से चर्चा के लिए 13-15 मई, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और नौसेना प्रमुख के साथ मुलाकात की। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने 20-24 जुलाई, 2009 के दौरान अमरीका का दौरा किया।

भारत अमरीकी थलसैनिक संयुक्त अभ्यास - 'युद्ध अभ्यास' का आयोजन 12-29 अक्तूबर, 2009 के दौरान मध्य प्रदेश के बबीना में किया गया। इसी प्रकार का भारत अमरीकी संयुक्त अभ्यास - 'कोप इंडिया' (वायु सेना) का आयोजन आगरा में 15-25 अक्तूबर, 2009 के बीच किया गया।

भारत अमरीकी रक्षा खरीद और उत्पादन समूह की बैठक 3-4 नवंबर, 2009 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वाइस एडमिरल जेफरी विरेंगा और महानिदेशक (अधिग्रहण), रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से की। भारत अमरीकी रक्षा नीति समूह की एक बैठक भारतीय रक्षा सचिव और अमरीकी रक्षा विभाग के उप सचिव श्री विलियन लेन की संयुक्त अध्यक्षता में 5-6 नवंबर, 2009 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई।

यू.एस. पैसिफिक कमांड (पीएसीओएम) के कमांडर एडमिरल रॉबर्ट बिलाड ने 3-4 दिसम्बर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन और थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर के साथ मुलाकात की। उन्होने रक्षा सहयोग तथा क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी स्थिति से संबंधित मुद्दों पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत अमरीकी संयुक्त तकनीकी समूह की 12वीं बैठक 28-29 जनवरी, 2010 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के मुख्य नियंत्रक और उनके अमरीकी समकक्ष श्री अलफ्रेड वोकमैन, अमरीकी रक्षा विभाग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के निदेशक ने संयुक्त रूप से की।

वैश्विक मुद्दे

राजदूत रॉन कर्क, अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि ने भारत द्वारा आयोजित दोहा दौर की अनौपचारिक मंत्रिमंडलीय बैठक में भाग लेने के लिए 3-4 सितम्बर, 2009 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने पिट्सबर्ग में आयोजित जी-20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा के तौर पर भाग लेने के लिए 22-25 सितम्बर, 2009 के दौरान अमरीका का दौरा किया।

भारत अमरीकी वैश्विक मुद्दों संबंधी फोरम की 7वीं बैठक 5 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में आयाजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव और लोकतंत्र और वैश्विक कार्य, अमरीकी राज्य विभाग की सचिव मिस मेरिया ओटेरो द्वारा संयुक्त रूप से की गई। दोनों पक्षों के बीच जलवायु परिवर्तन, स्थायी विकास, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, लोकतंत्र, मानव अधिकार और आपदा प्रबंधन से संबंधित वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए सहयोग पर चर्चा की गई।

राजदूत मेलाने वेरवीर, वैश्विक स्तर पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए अमरीकी अप्रतिनियुक्ति राजदूत ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने हेतु 8-11 नवंबर, 2009 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती कृष्णा तीरथ के साथ मुलाकात की और महिला एवं बाल विकास के सचिव, श्री डी. के.सीकरी के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया। इस बैठक का आयोजन भारत अमरीकी महिला सशक्तिकरण संबंधी द्विपक्षीय वार्ता के लिए कार्यसूची तैयार करने हेतु भारत अमरीकी महिला सशक्तिकरण फोरम के गठन के उद्देश्य से किया गया।

निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार

शस्त्र नियंत्रण और अंतराष्ट्रीय सुरक्षा कार्यो के लिए राज्य की अमरीकी अवर सचिव मिस एलेन ताउस्चर ने 11-13 नवंबर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होने यह दौरा भारत सामरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया। इस बातचीत एवं बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव और अवर सचिव मिस एलेन ताउस्चर द्वारा संयुक्त रूप से की गई। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन के साथ बैठक की और प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरन से मुलाकात की। उन्होंने निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग के भारत के प्रस्तावों पर चर्चा की।

उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग

भारत अमरीकी सहयोग में उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है। इस दिशा में हमेशा ध्यान आकृष्ट किया गया है। वर्ष 2008 में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 5.56 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत ने वर्ष 2008 में अमरीका से 4.5 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का आयात किया और 1.06 बिलियन अमरीकी डालर के उत्पादों का अमरीका को निर्यात किया। अमरीका से आयात किए गए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में एयरोस्पेस (2.6 बिलियन अमरीकी डालर-60 प्रतिशत) और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार उत्पादों (1.03 बिलियन अमरीकी पिट्सबर्ग - 22 प्रतिशत) का योगदान है।

द्विपक्षीय उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह के अन्तर्गत गठित किए गए भारत अमरीकी जैव-प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान विषयक कार्यकारी समूह ने बीआईओ-2009 की तरह अटलांटा में 20 मई, 2009 को एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान की गई चर्चा में नियामक ढांचे को सामंजस्य पूर्ण बनाने के लिए क्षमता विस्तार और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग, बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) संबंधी मुद्दों जैसे डेटा संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान उजागर करने संबंधी शर्तों के साथ-साथ तर्कसंगत एवं उपयुक्त प्रजातियों तथा उनकी कृत्रिम प्रजातियों के बीच अंतर आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की अग्रणी दवा कम्पनियों और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़ी कम्पनियों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों ने अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निर्यात और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए अवसरों की तलाश की।

उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह के जैव-प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान विषयक कार्यकारी समूह की एक सार्वजनिक -निजी बैठक का आयोजन 27 जुलाई, 2009 को नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक के प्रतिभागियों में अमरीकी प्रतिनिधि मंडल में वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि, यू.एस. मेडिकल डिवाइस इन्डस्ट्री आर्गनाइजेशन (एडीवीएएमइडी) और अमरीकी जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के सदस्य तथा भारत की ओर से विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और फार्मास्युटिकल विभाग, फिक्की, सीआईआई और भारतीय उद्योग के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक के दौरान चिकित्सा संबंधी युक्तियों, फार्मास्युटिकल्स और जैव-प्रौद्योगिकी सहयोग पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया गया।

भारत अमरीकी उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह की 7वीं बैठक 15-16 मार्च, 2010 को वाशिंगटन में आयोजित की जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने 25-31 अक्तूबर, 2009 के दौरान न्यूयार्क और वाशिंगटन का दौरा किया। उन्होंने अमरीकी शिक्षा सचिव के साथ मुलाकात की और दोनों शहरों में स्थित अनेक विश्वविद्यालयों का दौरा किया। प्रधान मंत्री के वाशिंगटन दौरे के दौरान दोनों सरकारों ने

'ओबामा - सिंह 21वीं शताब्दी की ज्ञान पहल' की शुरूआत की। इसके लिए दोनों पक्षों से 5-5 मिलियन अमरीकी डालर के वित्त पोषण पर सहमति व्यक्त की गई। इसके तहत भारत और अमरीकी विश्व विद्यालयों के बीच सम्पर्क और जूनियर फैकल्टी विकास विनिमय को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने प्रत्येक सरकार द्वारा एक मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के साथ फुलब्राइट-नेहरू कार्यक्रम को स्थायी तौर पर विस्तार देने लिए भी आम सहमति व्यक्त की, ताकि संयुक्त रूप से चिह्नित किए गए प्राथमिकता के क्षेत्रों में अधिकाधिक विद्यार्थी और बौद्धिक विनिमय अनुदान उपलब्ध कराये जा सकें, जिसके तहत रणनीतिक द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत में फुलब्राईट छात्रवृति कार्यक्रम की 60वीं वर्षगांठ 2 फरवरी, 2010 मनाई गई। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए यू.एस. इंडिया एजूकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस समारोह में विदेश मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

पहली फरवरी 2010 को अमरीकी राज्य विभाग में सार्वजनिक कार्यों और सार्वजनिक लोकतंत्र की अवर सचिव मिस जुडिथ मैकाले ने नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के साथ भारत अमरीकी शिक्षा संबंधी द्विपक्षीय वार्ता प्रारंभ की। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय शिक्षा सहयोग को मजबूत करने और नवंबर, 2009 में शुरू की गई सिंह-ओबामा ज्ञान पहल को भारत और संयुक्त राज्य अमरीका दोनों देशों से 5-5 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित करने पर जोर दिया गया।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भागीदारी

भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी वृत्तिदान निधि एवं बोर्ड की स्थापना के लिए 20 जुलाई, 2009 को नई दिल्ली में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

8 दिसम्बर, 2009 को वाशिंगटन में भारत अमरीका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए एक प्राथमिक बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ.टी. रामास्वामी द्वारा किया गया।

भारत और अमरीका ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए अलग से एक द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय स्तर पर संयुक्त रूप से की गई। इसका आयोजन स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया।

मातृत्व और बाल स्वास्थ्य, शारीरिक संबंधों से फैलने वाली बीमारियों और एचआईवी/ एड्स की मानव विकास अनुसंधान और रोकथाम विषय पर भारत अमरीकी संयुक्त कार्यकारी समूह की एक बैठक 18-19 नवंबर, 2009 के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, संयुक्त राज्य अमरीका में आयोजित की गई। पर्यावरणीय और पेशेगत स्वास्थ्य पर भारत अमरीकी कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन 21 अगस्त-2 सितम्बर 2009 के बीच गोवा में किया गया।

स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिनीसोटा विश्वविद्यालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), नई दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर अक्तूबर, 2006 में हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत 26-28 अगस्त, 2009 के दौरान मधुमेह एवं कैंसर पर एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। मिनीसोटा विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि मंडल ने पहली अक्तूबर, 2009 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर आयोजित तीसरी संयुक्त शीर्ष समिति की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया।

भारत अमरीकी वाणिज्यिक अंतरिक्ष पहल पर द्विपक्षीय वार्ता एवं करार 27-28 अक्तूबर, 2009 के दौरान बेंगलूर में निष्पादित किया गया। सेवाओं और निवेश के लिए सहायक अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि, मिस क्रिस्टाइन विलिस ने अमरीका की ओर से वार्ता का नेतृत्व किया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डॉ. ए. भास्करनारायन, वैज्ञानिक सचिव, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आइएसआरओ) द्वारा किया गया।

कनाडा

दिसम्बर, 2008 में ओटावा में आयोजित विदेशी कार्यालय परामर्शों के अनुक्रम में वर्ष के दौरान भारत कनाडा कार्यसूची का तेजी से विस्तार किया गया। कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री स्टॉकवेल बी. डे. और कनेडियन विदेश मंत्री श्री लॉ रैनी केनन के सानिध्य में कनाडा के प्रधान मंत्री श्री स्टीफन हार्पर का नवंबर, 2009 में किया गया भारत दौरा पूरे वर्ष भर दोनों सरकारों के नेताओं के बीच सघन उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संबंधों की पराकाष्ठा थी, क्योंकि इसके दौरान विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में द्विपक्षीय बातचीत को बढावा दिया गया।

स्वच्छ ऊर्जा

अप्रैल, 2009 में 15-17 अप्रैल, 2009 के दौरान कनाडा भारत फाउंडेशन द्वारा टोरंटो में आयोजित कनाडा भारत ऊर्जा फोरम में भागीदारी के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने किया। योजना आयोग के अध्यक्ष ने ऑनटेरिया का प्रीमियर आयोजित किया और बहुत से संभ्रात संस्थानों के अनुरोध पर वहाँ जाकर उन्हें संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भारत की विकास रणनीति और यहाँ निवेश के लिए भावी संभवनाओं और वर्तमान अवसरों पर भी चर्चा की।

असैनिक परमाणु सहयोग

भारत और कनाडा दोनों देशों की सरकारों ने असैनिक परमाणु सहयोग पर एक अंतर-सरकारी करार को अंतिम रूप प्रदान करने में अपनी साझा स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श और बातचीत की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डॉ. बी.आर. ग्रोवर, निदेशक (रणनीतिक आयोजना समूह), परमाणु ऊर्जा विभाग ने किया और कनाडा की ओर से आए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री डॉन

सिन्क्लेयर, महानिदेशक, अंतराष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो, विदेशी कार्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, कनाडा द्वारा किया गया। 28 नवंबर, 2009 को दोनों पक्षों ने भारत और कनाडा के बीच असैनिक परमाणु सहयोग के लिए एक करार की विषय-वस्तु को अंतिम रूप प्रदान किया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

एनईएलपी-7 और सीबीएम-4 के आठवें दौर के भाग के रूप में एक रोड शो आयोजित करने के लिए श्री जितिन प्रसाद, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 22-25 अगस्त, 2009 के दौरान कालगेरी, कनाडा का दौरा किया।

व्यापार एवं अर्थव्यवस्था

श्री गेराल्ड कैडी, कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के संसदीय सचिव, ने 1-5 सितम्बर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। वे कोलकाता में कनाडियायी आंचलिक व्यापार कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित हुए। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन की अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लिया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमल नाथ, वित्त राज्य मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के साथ भी बैठक की।

ओंटोरियो संघ की व्यापार एवं निवेश मंत्री मिस सैन्द्रा पोपाटेलो ने 21 अगस्त से 3 सितम्बर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया। वह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, वाणिज्य सचिव और सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से मिली। मुम्बई में उन्होंने भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत की।

भारत - कनाडा द्विपक्षीय व्यापार

जनवरी से नवंबर, 2009 की अवधि के लिए द्विपक्षीय व्यापार संबंधी आकड़े निम्नानुसार हैं

(आकड़े बिलियन अमरीकी डालर में)

विवरण	जनवरी से नवंबर, 2008	जनवरी से नवंबर, 2009	परिवर्तन प्रतिशत
भारत का कुल निर्यात	1.9	1.6	-15.1
भारत का कुल आयात	2.05	1.7	-14.4
व्यापार	3.9	3.3	-14.7

(कनेडियायी सांख्यिकी)

श्री स्टाकवेल बी.डे., कनेडियायी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने अहमदाबाद में कनाडा के व्यापार कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए 25 सितम्बर, 2009 को अहमदाबाद का दौरा किया। 29-30 सितम्बर, 2009 के दौरान ओटावा में आयोजित किए गए छठवें भारत कनाडा व्यापार नीति संबंधी परामर्शों ने दोनों सरकारों को अपने द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को समीक्षा करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। वाणिज्य सचिव श्री राहुल खुलार ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जबकि कनेडियन प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वहां के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उप मंत्री श्री लुईस लेवेस्क्यू द्वारा किया गया।

19-23 अक्तूबर, 2009 के दौरान ओटावा और क्यूबेक शहरों में भारत और कनाडा के बीच कनाडा की फेडेरल सरकार और क्यूबेक की संघीय सरकार के साथ समाजिक सुरक्षा संबंधी करार के एक मसौदे के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय अग्रणी मंत्रालय था।

कृषि संबंधी सहयोग

4 जून, 2009 को पंजाब के कृषि मंत्री श्री सच्चा सिंह लंगाह और मेनीटोबा की उप प्रीमियर एवं कृषि मंत्री सुश्री रोषन वाउचुक ने पंजाब में एक खाद्यान विकास केन्द्र की स्थापना के लिए सहयोग पर कनाडा के मेनीटोबा प्रांत और पंजाब के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

15-23 जनवरी, 2010 के दौरान भारत में आये अटलांटिक कनाडा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कनाडा में नोवा स्कोटिया संघ से सीनेटर डोनाल्ड ओलिवर ने किया। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, भारत सरकार, उद्योग, रोजगार मंत्री, महाराष्ट्र सरकार और नौवहन, परिवहन संबंधी केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों से मुलाकात की।

रणनीतिक मुद्दे

रणनीतिक मुद्दों पर भारत-कनाडा द्विपक्षीय बातचीत 18 जून, 2009 को ओटावा में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव (पीओएल एवं आईओ) श्री विवेक काटजू द्वारा किया गया। सुश्री कोलिन सोड्र्स, कनाडा के विदेशी कार्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग में सहायक उप मंत्री उनके समकक्ष के तौर पर बातचीत में शामिल हुई। दोनों प्रतिनिधि मंडलों में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मौजूदा स्थिति, निरस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दों, शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों, आपदा प्रबंधन, साझा सरोकार वाले अन्य वैश्विक मुद्दों पर आपसी समझ बढ़ाने के लिए अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

जवाबी आतंकवाद संबंधी सहयोग

जवाबी आतंकवाद पर भारत-कनाडा संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक 19 जून, 2009 को ओटावा में आयोजित की गई।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कनाडा के प्रधान मंत्री श्री स्टीफेन हार्पर 17 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में भारत और कनाडा के बीच करार पर हस्ताक्षर के अवसर पर।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 14 अक्तूबर, 2009 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में अर्जेंटीना की राष्ट्रपति सुश्री क्रिस्टीना फर्नाण्डेज डे क्रिचनेर के समारोहपूर्ण स्वागत के अवसर पर।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री विवेक काटजू, विशेष सचिव (पीओएल एवं आईओ), विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। बैठक के दौरान वैश्विक चुनौती से संबंधित संकल्पनाओं, जारी आतंकवाद अन्वेषणों, जबाबी आतंकवाद, आतंकवाद के वित्त पोषण, नशीली दवाओं की तस्करी आदि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर चर्चा की गई। विशेष सचिव ने कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री स्टॉकवेल बी डे, जिन्होंने कनाडा की संसद में अफगानिस्तान समिति की अध्यक्षता की थी, के साथ भी बैठक की और अफगानिस्तान, जहां कनाडा के रक्षा कार्मिकों की तैनाती की गई है, में मौजूदा स्थिति के बारे में विचारों के आदान-प्रदान करने के उद्देश्य श्री ल्यूनार्ड एडवर्डस, उप विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात की।

रक्षा सहयोग

मेजर जेनरल एम.जी. मैकडोनाल्ड, कनाडा के रक्षा अन्वेषण प्रमुख ने भारत का दौरा किया और भारत में अपने समकक्ष के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया और 23 सितम्बर, 2009 को नई दिल्ली में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भी चर्चा की।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत-कनाडा संयुक्त समिति की तीसरी बैठक 8 जून, 2009 को ओटावा में आयोजित की गई। दोनों देशों ने 7 संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा की और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों ने अपनी अभिरुचि व्यक्त की। दोनों देश कनाडियन विश्वविद्यालयों की भागीदारी से 'नैनो प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता की सुनिश्चिति' के एक सार्थक नेटवर्क की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डॉ. टी रामास्वामी, सचिव,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया। डॉ. रामास्वामी ने कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री स्टॉकवेल बी. डे. और श्री गैरी गुडीयर, कनाडा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजमंत्री के साथ भी बैठक की।

पर्यावरण

पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-कनाडा करार के अन्तर्गत स्थापित किए गए भारत-कनाडा पर्यावरण फोरम की पहली बैठक 18-19 जून, 2009 को ओटावा में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए विशिष्ट प्रस्तावों के संबंध में एक कार्य योजना तैयार करने के मुद्दे पर चर्चा की।

कनाडा के प्रधान मंत्री श्री स्टीफन हार्पर का भारत दौरा

कनाडा के प्रधान मंत्री श्री स्टीफन हार्पर 15-18 नवंबर, 2009 के दौरान एक सरकारी दौरे पर भारत आए। उनके साथ कनाडा के विदेश मंत्री श्री लॉरेंस केनन एवं वहां के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री और कनाडा की संसद के वरिष्ठ सदस्य श्री स्टॉकवेल बी. डे. विदेशी कार्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, कनाडा के अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने भी भारत का दौरा किया। द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तन लाने अर्थात उनमें सुधार लाने की दृष्टि से यह दौरा महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके तहत एक उच्च स्तरीय रणनीतिक कार्यसूची तैयार करने के लिए दोनों सरकारों की प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई।

दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने एवं उन्हें व्यापक बनाने के साथ-साथ एक साझा वैश्विक कार्यसूची पर सहयोग के लिए किए जाने वाली पहलों के संबंध में सहमति व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्रीय संबंधी मुद्दों पर चर्चा की-इसके तहत अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता और जबाबी आतंकवाद की दिशा में अपेक्षाकृत बेहतर सहयोग प्रदान करने में अपने आपसी हितों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक स्तर पर गहन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों सरकारों ने युनाइटेड नेशन फ्रेम वर्क के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन शीघ्र आयोजित करने के लिए कार्य करने हेतु सहमति व्यक्त की।

इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए द्विपक्षीय आर्थिक करारों पर हस्ताक्षर कर सुविधाजनक व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। दोनों देशों के नेताओं ने यह आशा व्यक्त की कि प्रस्तावित द्विपक्षीय संस्थागत ढांचे को अंतिम रूप प्रदान किए जाने से आगामी पांच वर्षो में कनाडा के साथ द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान स्तर की तुलना में 15 से 20 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँचाया जा सकेगा। इसके लिए सुदृढ़ प्रयासों की आवश्यकता होगी।

वैश्विक स्तर पर आई आर्थिक मंदी के दौरान भारत और कनाडा, दोनों देशों की सफलता के मद्देनजर दोनों देशों की सरकारों ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक भरपाई के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमति व्यक्त की और 2010 में कनाडा में आयोजित किए जाने वाले जी-20 सम्मेलनों की अग्रिम तैयारी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास मजबूत करने पर दोनों देश राजी हुए। उन्होंने दिसम्बर, 2009 में आयोजित कोपेनहेगन बैठक के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर की बातचीत के संदर्भ में सृजनात्मक ढंग से आगे आने के महत्व पर भी चर्चा की।

भारत और कनाडा के प्रधान मंत्रियों की उपस्थिति में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता ज्ञापन दोनों देशों से विशेषज्ञ व्यक्तियों वाले एक संयुक्त अध्ययन दल के गठन से संबंधित था। यह दल दोनों देशों के बीच एक विस्तृत आर्थिक भागीदारी करार (सीइपीए) की संभाव्यता की जांच करेगा। दूसरा समझौता ज्ञापन ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग से संबंधित था, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन फ्यूल-सेल प्रौद्योगिकी, जैव ईंधन, वायु और सौर ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण तथा उसके अनंतिम उपयोग, ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास, बढ़ा हुआ चिरस्थायी अन्वेषण एवं उत्पादन, तेल और गैस की माइनिंग और ड्रिलिंग जैसे मुद्दे शामिल हैं।

कनाडा के प्रधान मंत्री हार्पर ने भारतीय प्रधान मंत्री के साथ बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। कनेडियन प्रधान मंत्री श्री स्टीफन हार्पर की अगुवाई भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल एवं उपराष्ट्रपति श्री मुहम्मद हामिद अंसारी द्वारा की गई। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा और नेता प्रतिपक्ष श्री एल.के. अडवाणी ने प्रधान मंत्री हार्पर के साथ बात की। कनेडियन प्रधान मंत्री ने यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। श्री हार्पर भारतीय उद्योग जगत एवं व्यापारिक समुदाय के नेताओं से भी मिले और निवेश, शिक्षा और अवसंरचना संबंधी विषयों पर गोलमेज सम्मेलनों में भी उन्होंने ने भाग लिया। श्री हार्पर ने मुम्बई और अमृतसर का भी दौरा किया।

दौरे के दौरान जारी किए गए एक संयुक्त वक्तव्य में द्विपक्षीय संबंधों के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ किए जाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया गया। इसके तहत एक द्विपक्षीय निवेश प्रोन्नति एवं संरक्षण करार, एक सामाजिक सुरक्षा करार और एक सिविल परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेषी पहलों के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई, जहां व्यक्ति से व्यक्ति तक सम्पर्क को बढ़ाया जा सकता है और दोनों देशों में उच्चतर शिक्षा की संस्थानों के बीच सहक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई और 2011में कनाडा के विभिन्न स्थानों में भारतीय समारोह के आयोजन सहित सांस्कृतिक क्षेत्र में विनिमय की सुविधा के बहुत से प्रयास शुरू किए गए।

दौरे के दौरान श्री लारेंस केनन, कनाडियायी विदेश मंत्री ने भारतीय रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटोनी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री एम.के. नारायणन और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। श्री स्टॉकवेल बी.डे., कनाडियन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री पृथ्वी राज चौहान के साथ भी मुलाकात की।

संस्कृति

संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. विजय एस मदान के नेतृत्व में 3-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 25-29 जनवरी, 2010 के दौरान ओटावा का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय कला दीर्घा, अक्तूबर 2010 में भारत में आयोजित होने वाली सहज ज्ञान कला प्रदर्शनी, 2011 में कनाडा में भारत के वर्ष विषयक प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों और सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन, जिस पर बातचीत जारी है, के संबंध में विचार-विमर्श किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डॉ. एस. नातेस, वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 20-26 जनवरी, 2010 के दौरान वेंकूवर का दौरा किया। यह प्रतिनिधि मंडल कनेडियायी विशेषज्ञों के साथ व्यापार से व्यापार भागीदारी सम्मेलन और जैव-प्रौद्योगिकी पर भागीदारी से संबंधित उत्तरी अमरीका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनमें शामिल हुआ।

अन्य उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

ओंटोरियो संघ के प्रीमियर श्री डाल्टन मैकग्यून्टी ने 6-11 दिसम्बर, 2009 के बीच भारत का दौरा किया। उन्होंने ने 75-सदस्यीय एक ऐसे मिशन का नेतृत्व किया जिसका मुख्य ध्यान स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर था। इस मिशन में प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी अग्रणी कनेडियन कम्पनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। नई दिल्ली में प्रीमियर मैकग्यून्टी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने 7 दिसम्बर, 2009 को आयोजित 'स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषी पहल एवं उनके अनुसरण के क्षेत्र में भागीदारी' विषयक सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रीमियर मैकग्यून्टी ने दिल्ली में यमूना नदी की सफाई/संरक्षण के लिए पारिस्थितिकीय दृष्टि से मित्रवत प्रौद्योगिकियों का प्रस्ताव दिया। उन्होंने परिवहन मंत्री, वाणिज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा दिल्ली एवं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने भारत में निगमित क्षेत्र के लोगों के साथ भी विचार-विमर्श किया और हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित वैश्विक व्यापार पर गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की।

भारत के चुनाव आयोग की स्थापना के हीरक जयन्ती समारोह में भाग लेने के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला के आमंत्रण पर कनाडा के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री मार्क मेरन्ड ने 25-27 जनवरी, 2010 के बीच भारत का दौरा किया।

कनाडा के लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष मिस मेरिया बेराडोज ने 27 जनवरी-6 फरवरी 2010 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशकों के साथ मुलाकात की।

श्री जीन चेरेस्ट, क्यूबेक संघ के प्रीमियर ने 31 जनवरी-7 फरवरी, 2010 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने 186-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस प्रतिनिधिमंडल में व्यापार जगत से जुड़े नेता, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक शामिल थे। यह प्रतिनिधि मंडल ऊर्जा, जल विद्युत, जैव-प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, आईसीटी, आर एण्ड डी, अवसंरचना, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत आया। श्री चेरेस्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्री, नागर विमानन मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, खान मंत्री और डीओएनईआर तथा दिल्ली, मुम्बई और बेंगलूर के मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों से मुलाकात की।

बैंक ऑफ कनाडा के गर्वनर श्री मार्क कार्ने 16 फरवरी, 2010 को भारत का दौरा करने वाले हैं।

कनाडा के उच्च न्यायालय के न्यायधीश मॉरेस जे फिस एवं मार्शल राथेस्टीन तथा विधिक अधिकारी विटोल्ड टिमोस्की के सानिध्य में कनाडा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश बेवरली मैक लेचलीन 22-26 फरवरी, 2010 के दौरान भारत का दौरा करेंगे। यह दौरा पहले से चल रहे इंडो-कनेडियन विधि विनिमय के एक भाग के रूप में किया जा रहा है, कनाडा का पिछला दौरा मई, 2008 में किया गया था।

22-26 फरवरी, 2010 के दौरान कनेडियन सैनिक बलों के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसपी) के लिए एक 20-सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के भारत आने की उम्मीद है।

भारत कनाडा विदेशी कार्यालय परामर्श का आयोजन 3 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री विवेक काटजू और कनाडा सरकार के विदेश विभाग में उप मंत्री श्री ल्यूनार्ड एडवर्डस इस परिचर्चा का नेतृत्व करेंगे और वे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की समीक्षा करेंगे।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया के 18-19 मार्च, 2010 के दौरान कनाडा में होने वाली जी-20 शेरपा बैठक में भाग लेने की उम्मीद है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री कमल नाथ का 22-26 मार्च, 2010 के दौरान कनाडा दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे का उद्देश्य पीपीपी मॉडल के अनुसार भारत में राजमार्ग क्षेत्र में मौजूदा अवसरों के लिए व्यापार एवं निवेशक समुदाय को संवेदनशील बनाना है।

लैटिन अमरीकी देश

अर्जेंटीना

भारत और अर्जेंटीना की अर्जेंटीना के राष्ट्रपति डॉ. (श्रीमती) क्रीस्टीना फर्नांडेज डी. कर्चनर के 14-15 अक्तूबर, 2009 को भारत के राजकीय दौरे के दौरान रणनीतिक भागीदारी की दिशा में सहयोग करने की इच्छा को दोहराया। उनके साथ काफी बड़ा प्रतिनिधि मंडल भारत दौरे पर आया। इस प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्री मिस जार्ज तइयाना, लापाम्पा, सेनजॉन संघ के गवर्नर के साथ-साथ व्यापार जगत के काफी लोग शामिल थे। 15 वर्षों में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का यह पहला दौरा था। संयोगवश उस दौरान भारत और अर्जेंटीना के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही थी। दौरे पर आये गणमान्य व्यक्तियों से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल स्तर पर बातचीत की और भारत के उपराष्ट्रपति, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की चेयरपर्सन और नेता प्रतिपक्ष ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। दौरे के दौरान जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में दोनों ओर से बहु चरणीय द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की गई। एस एण्ड टी, हाइड्रोकार्बन, खेलकूद, व्यापार प्रोन्नति एवं बाह्य अंतरिक्ष जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी नौ करारों/ समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग की दिशा में सहयोग के लिए एक करार किया गया। दोनों पक्षों ने बढ़ रही आर्थिक व्यस्तता और आर्थिक व्यापार जो 2003 में 694 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2008 में 1328 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया है, के संदर्भ में संतुष्टि व्यक्त की और दोनों देशों ने वर्ष 2012 तक 3 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। राष्ट्रपति क्रिस्टीना ने मुम्बई और दिल्ली में आयोजित व्यापारिक सेमिनारों में भाग लिया और भारतीय कारोबारियों से अर्जेंटीना में निवेश करने का अनुरोध किया।

भारतीय दूतावास द्वारा कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीज के सहयोग से 2 जुलाई, 2009 को ब्यूनर्स आयर्स में इंडो-लेक बिजनेस कनक्लेव का आयोजन किया गया जिसमें भारत, ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेंटीना से चेम्बर्स ऑफ कामर्स के प्रेसीडेन्ट के साथ-साथ ब्राजील, चिली और कोलम्बिया में भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उरूग्वे, कॉर्डोवा और ब्यूनर्स आयर्स में व्यापारिक सेमिनारों का भी आयोजन किया गया। अर्जेंटीना और पेरूग्वे और उरूग्वे में 5-15 नवंबर, 2009 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में हस्तकला प्रदर्शनी, भरतनाट्यम और डांडिया गुजराती लोक नृत्य प्रदर्शन, फिल्म महोत्सव, साहित्यिक प्रतिस्पर्धा, खाद्ययान महोत्सव, फोटो प्रदर्शनी के अलावा 'अतुल्य भारत' पर्यटन अभिवृद्वि संबंधी कार्यकलापों का आयोजन किया गया।

बोलिविया

3-4 सितम्बर, 2009 के दौरान दिल्ली में आयोजित व्यापार मंत्रियों की अनौपचारिक विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिमंडलीय बैठक में भाग लेने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा के आमंत्रण पर बोलिविया के बाह्य व्यापार एवं एकीकरण के लिए उप मंत्री श्री पेबलो गुजमेन लेगुआ ने भारत का दौरा किया। जिन्दल स्टील एवं पावर लिमिटेड ने बोलिविया में इएल रयूटन स्थित अपनी पट्टा खान से लौह अयस्क के निर्यात के लिए ढांचागत सुविधाओं को पूरा कर लिया है। इसके लिए उन्होंने 2.1 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक का अधिग्रहण किया है।

ब्राजील

31 अगस्त-1 सितम्बर 2009 के दौरान द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की चौथी बैठक और आईबीएसए (इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका) बातचीत फोरम की 6वीं मंत्रिमंडलीय बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा के ब्राजील दौरे में ब्राजील के साथ रणनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने ब्राजील के विदेश मंत्री सैल्सो एमोरिम के साथ संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में कृषि, ऊर्जा, व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं अंतरिक्ष

अनुसंधान सहित द्विपक्षीय हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने अपने-अपने द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक महत्व उजागर किए और इसके साथ ही बहुत से बहुपक्षीय मुद्दे पर भी आपसी परामर्श का महत्व स्पष्ट किया गया। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र में एक विस्तृत सुरक्षा परिषद में अपनी एक स्थायी सीट के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी के समर्थन के प्रति वचनबद्धता जाहिर की और स्थायी तथा अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद के विस्तार के महत्व पर अन्य देशों को संवेदनशील बनाने के लिए समर्पित प्रयास करने की शपथ ली। ब्राजील ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को ब्लॉक बीएमएस 17-आबंटित करने के लम्बित मुद्दे का समाधान करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। दोनों देशों ने ब्राजील, भारत और अन्य किसी देश में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अवसरों और कार्यकलापों में संयुक्त रूप से बोली लगाने, संयुक्त उद्यमों और सहयोग के माध्यम से अपनी पेट्रोलियम कम्पनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) ने ब्राजील स्थित पेट्रोलियम रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल्स, आयल एण्ड गैस प्रोसेसिंग (ऑनशोर), ऑयल एण्ड गैस प्रोसेसिंग (ऑफशोर) और पाइप लाइनों के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में अपनी गहन रुचि व्यक्त की है।

ब्राजील के विदेश मंत्री श्री सेल्सो एमोरिम ने वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा के आमंत्रण पर नई दिल्ली में विश्व व्यापार संगठन दोहा दौर पर एक अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए सितम्बर, 2009 में भारत का दौरा किया। भारत और ब्राजील के बीच वर्ष 2008-09 के दौरान 3.68 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार किया गया।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) श्री विवेक काटजू ने 28-29 जनवरी, 2010 के दौरान नई दिल्ली में ब्राजील के राजनीतिक कार्यों के अवर सचिव, विदेशी कार्य मंत्रालय ब्राजील श्री रोबर्टो जगुवारेबे के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका (आईबीएसए) और ब्राजील, भारत, रूस, चीन (बीआरआइसी) से संबंधित मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की।

चिली

भारत-चिली रक्षा सहयोग को 31 मई-5 जून, 2009 के बीच भारत के थल सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर के चिली दौरे के तहत और सशक्त बनाया गया। इससे पहले 11-15 मई, 2009 के दौरान राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के एक 18-सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने चिली का दौरा किया। इस दौरे के दौरान राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी) और एएनईपीई (एनडीसी का समकक्ष) के बीच आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए बातचीत की गई।

एम.एस.स्वामीनाथन फाउंडेशन (एम.एस.एस.आर.एफ) के अध्यक्ष एवं भारत में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने चिली के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर 23-29 अक्तूबर, 2009 के दौरान चिली का दौरा किया। उनके साथ इस फाउंडेशन के 7 सुप्रसिद्व वैज्ञानिक भी इस दौरे में शामिल हुए। एम.एस. एस.आर.एफ. और फंडेशियन पैरा लॉ इनोवेशियन एग्रेरिया के बीच एक भागीदारी अवसंरचना करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

कोलम्बिया

कोलम्बिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को इस वर्ष के दौरान सुदृढ़ किया गया, जब मंत्रिमंडलीय स्तर के दौरे कर दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श किया गया। विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने 18-19 जनवरी, 2010 में कोलम्बिया का दौरा किया और उन्होंने कोलम्बिया के राष्ट्रपति श्री अलवारो उरिबे, उप राष्ट्रपति श्री फ्रांसिस्को सेंटोज और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री एडगर जोमेज रोमन के साथ बैठक की। उन्होंने विदेश मंत्री बरमुडेज के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और क्षेत्रीय विकास तथा बहुचरणीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। यह दौरा राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के अवसर पर किया गया। विदेश राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी और एसईएनए (व्यावसायिक एवं पेशागत प्रशिक्षण के लिए कोलम्बिया सरकार का एक निकाय) के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन कोलम्बियायी बीपीओ और कॉल सेंटरो की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा। इससे पहले कोलम्बिया के विदेश मंत्री श्री जेमी बर्मुडेज के साथ वहां के वाणिज्य, उद्योग एवं पर्यटन मंत्री लूईस ग्यूलर्मो प्लाटा और एक छोटे व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया। विदेश मंत्री ने उनके साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की, जहां दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा बहुचरणीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दौरे के दौरान बेम्बु अनुप्रयोग और द्विपक्षीय निवेश प्रोन्नति एवं संरक्षण करार (बीआईपीपीए) की दिशा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इससे पहले 2 अप्रैल, 2009 को नई दिल्ली में विदेशी कार्यालय स्तर पर द्विपक्षीय परामर्श एवं विचार-विमर्श किया गया। कोलम्बिया के विदेशी कार्यों के उप मंत्री, राजदूत क्लेमेंसिया फोरेरो यूक्रोस और श्री नलिन सूरी, सचिव (पश्चिम) ने क्रमशः कोलम्बियायी और भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता एवं नेतृत्व किया। उप मंत्री ने विदेश राज्य मंत्री श्री शशि थरूर के साथ भी बैठक की और द्विपक्षीय संबंधों पर विचार-विमर्श किया। कोलम्बिया के साथ रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की पहली बैठक 7-9 सितम्बर, 2009 के बीच बगोटा में आयोजित की गई। अपर सचिव श्री आर.एस. माथुर, रक्षा मंत्रालय और कोलम्बिया के उप मंत्री ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा उत्पादन एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए जोर दिया गया।

व्यापारिक अवसरों की तलाश के लिए वर्ष के दौरान बहुत से व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों ने कोलम्बिया का दौरा कियाः इस दौरान जून, 2009 में उच्च सशक्त प्रतिनिधि मंडल और भारत के मसाला बोर्ड का एक प्रतिनिधि मंडल जुलाई, 2009 में

कोलम्बिया गया। 6 अगस्त, 2009 को फिनेकल टीएम यूनीवर्सल बैंकिंग सोल्यूशन, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की एक सहायक कम्पनी ने बैंकोलोम्बिया, कोलम्बिया के सबसे बड़े बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। स्टेट ऑयल कम्पनी इकोपेट्रोल के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 8-11 सितम्बर, 2009 के दौरान भारत का दौरा किया।

भारत ने 1 से 9 अक्तूबर, 2009 तक आयोजित बगोटा के 26वें सिने महोत्सव में एक सम्मानित देश के रूप में भाग लिया। गांधी जयन्ती समारोह के अवसर पर 2 अक्तूबर, 2009 को 'मेंकिंग ऑफ महात्मा गांधी' सहित भारत के प्रसिद्व फिल्म निर्देशक श्री श्याम बेनेगल की 6 फिल्में प्रदर्शित की गई।

इक्वाडोर

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने मई, 2009 में इक्वाडोर के रक्षा मंत्री श्री जेवियर प्रोंस को इक्वाडोर द्वारा खरीदे गए 7 ध्रुव हेलीकॉप्टरों में से 5 हेलीकॉप्टर सौंपे। इक्वाडोर में भारतीय सहयोग से एक सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के लिए क्योटो में 11 अगस्त, 2009 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। 19 नवंबर, 2009 को इक्वाडोर में भारतीय महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें उप राष्ट्रपति श्री लेनिन मोरेनो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

मैक्सिको

वर्ष के दौरान मैक्सिको के साथ हमारी सुविधाजनक भागीदारी के क्रम में द्विपक्षीय बातचीत की गई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला ने मैक्सिको के मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुरोध पर 1-6 जुलाई, 2009 को मैक्सिको का दौरा किया, उन्होंने यह दौरा 5 जुलाई, 2009 को मैक्सिको में हुए मध्यावधि चुनावों के एक प्रेक्षक के रूप में किया।

मैक्सिको के साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.3 बिलियन अमरीकी डालर (मैक्सिको के पक्ष में 650 मिलियन अमरीकी डालर और 1738 मिलियन अमरीकी डालर) रहा। मैक्सिको के सबसे बड़े बैंक - बैंकोमर के एक 40-सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने 20 नवंबर-4 दिसम्बर 2009 तक भारत का दौरा किया। इंजीनियरींग निर्यात अभिवृद्धि परिषद के नेतृत्व में भारत के साथ इंजीनियरींग कम्पनियों ने 15-17 जुलाई, 2009 के दौरान मैक्सिको सिटी में आयोजित ऑटोमेकेनिका में भाग लिया। पुस्तक प्रकाशन एवं प्रिटिंग उद्योग से जुड़ी 10 भारतीय कम्पनियों ने गौदालाजारा में 29 नवंबर-3 दिसम्बर 2009 तक आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में भाग लिया। मैक्सिकन अपेरल इंडस्ट्री ऐसोसियेशन के समन्वय में कपड़ा उद्योग से जुड़े 6-सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 18-20 नवंबर, 2009 को भारत का दौरा किया।

आईसीसीआर ने मैक्सिको में 2010 में एक भारतीय संस्कृति केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। यह केन्द्र मैक्सिको के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनायेगा। भारत ने 5-8 नवंबर, 2009 तक एकापुल्को के तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव- 'ला नाओ' में पहली बार भाग लिया। इसमें आईसीसीआर के तरफ से मथुरा, गीतांजलि इंटरनेशनल फॉल्क टैंग (जीआईएफटी) का एक लोकनृत्य दल भी शामिल हुआ।

पेरूग्वे

भारतीय महोत्सव का पेरूग्वे में पहला आयोजन वर्ष 2009 में किया गया। इस अवसर पर खाद्यान महोत्सव, फिल्म महोत्सव और शास्त्रीय एवं लोक नृत्य शो का भी आयोजन किया गया।

पेरू

पेरू के साथ द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत के विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने 20-22 जनवरी, 2010 के बीच पेरू का दौरा किया। उन्होंने पेरू के विदेश मंत्री श्री जोश एण्टोनियो ग्रासिया बेलॉण्डे के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए विचार-विमर्श किया और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों के संबंध में विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के मंत्रियों ने वर्ष 2010-12 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक द्विपक्षीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इंडियन कॉउन्सिल ऑफ वर्ल्ड एफेयर्स तथा पेरू स्थित इसके समकक्ष संस्था सीईपीईआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर विदेश राज्य मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।उन्होंने लीमा के मेयर, श्री ल्यूस केस्टानेडा लोसियो और एन्डीन समुदाय के महासचिव श्री फ्रेडी एलर के साथ मुलाकात की। इनके साथ उन्होंने एन्डीन समुदाय के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने पेरू-इंडिया चेम्बर ऑफ कामर्स, इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों, विचारकों और शिक्षाविदों के साथ भी बातचीत की।

पेरू ने नई दिल्ली में विदेशी राजनयिकों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग पाठ्यक्रमों के लिए एक उम्मीदवार भेजा है। केमेक्सिल, जूट विनिर्माता विकास परिषद (जेएमबीसी) और टैक्सप्रोसिल से एक व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल ने इस अवधि के दौरान पेरू का दौरा किया और लीमा में बहुत सी क्रेता-बिक्रेता बैठकों का आयोजन किया गया।

उरूग्वे

उरूग्वे में भारतीय महोत्सव का पहली बार आयोजन वर्ष 2009 में आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के आईटीडीसी के 2 सैफों के साथ खाद्यान महोत्सव के साथ-साथ शास्त्रीय और लोकनृत्य का अयोजन किया गया। इसके अलावा, बॉलिवुड की 10 फिल्मों के साथ फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया।

वेनेजुएला

वर्ष 2008-09 में क्रूड ऑयल के व्यापक स्तर पर आयात के कारण वेनेजुएला एलएसी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। दोनों देशों के बीच का व्यापार लगभग 4 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया और भारत से निर्यात 179 मिलियन अमरीकी डालर का आकड़ा छू गया। राष्ट्रीय रक्षा

महाविद्यालय के एक 18-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 17-22 मई, 2009 के दौरान वेनेजुएला का दौरा किया। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित एक 9 सदस्यीय दल ने 23-28 मई, 2009 के दौरान भारत और वेनेजुएला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के आयोजन पर भाग लिया। इस अवसर पर मेरिडा में एक भारतीय महोत्सव का भी आयोजन किया गया जहां 'भारतः बहुपक्षीय बातचीत' और 'भारत और वैश्विक वित्तीय संकट' विषयों पर दो सेमिनारों का आयोजन किया गया। भारतीय महोत्सव के एक भाग के रूप में कश्मीर पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी, एक कला प्रदर्शनी, एक भारतीय फिल्म एवं वृत्तचित्र महोत्सव और एक खाद्यान महोत्सव का भी आयोजन किया गया।

मध्य अमरीका

बेलिज

भारत ने बेलिज के अनुरोध पर सितम्बर, 2009 में बेलिज पुलिस अकादमी का नवीकरण करने के लिए एक भारतीय पुलिस अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की।

कोस्टा रिका

कोस्टा रिका की क्षमता अभिवृद्धि में भागीदारी के लिए हमारे प्रयास के एक भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा कोस्टा रिका में एक सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के संबंध में 18 सितम्बर, 2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एल साल्वाडोर

एल साल्वाडोर ने 1 अप्रैल, 2009 से दोनों देशों के राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए भारत और एल साल्वाडोर के बीच हस्ताक्षरित वीजा मुक्त करार को कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। भारत सरकार ने भाई चारे की एक मिशाल के तौर पर एल साल्वाडोर को 2 लाख 50 हजार अमरीकी डालर का नकद डोनेशन दिया। यह डोनेशन नवंबर, 2009 में ह्यूरिकन 'ईदा' की शुरूआत के अवसर पर मानवीय सहायता के रूप में प्रदान किया गया।

ग्वाटेमाला

भारत ने ग्वाटेमाला में अपने मिशन की शुरूआत दिसम्बर, 2009 में की। इस मिशन की शुरूआत ग्वाटेमाला में बार-बार सूखा पड़ने और खाद्यान असुरक्षा के कारण ग्वाटेमाला सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए की गई एक अपील के तहत की गई। इस क्रम में भारत सरकार ने ग्वाटेमाला को नवंबर, 2009 में 2 लाख 50 हजार अमरीकी डालर का नकद डोनेशन दिया।

होन्डुरास

होन्डुरास ने भारत से ट्रक, संचार उपस्कर आदि अधिग्रहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए 30 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का भरपूर सदुपयोग किया।

निकारागुआ

विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में एनआईआईटी स्टॉफ की सहायता से 'एनआईआईटी-आईएनएटीईसी इंडिया-निकारागुआ आईटी सेंटर' में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में यह संस्थान दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है।

पनामा

पनामा सरकार ने 1 जुलाई, 2009 को नव-चयनित राष्ट्रपति रिकार्डो मर्टेनली द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात भारतीय नागरिकों के लिए वीजा रिजीम में छूट प्रदान की है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमरीका/ कनाडा/ यू.के./ आस्ट्रेलिया अथवा यूरोपिय संघ के किसी भी देश का वीजा, जिसका कम से कम एक बार प्रयोग अवश्य किया गया हो, रखने वाले भारतीय नागरिक पनामा में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें यह प्रवेश पनामा पहुँचने पर 30 दिनों के लिए जारी किए गए वैध पर्यटक कार्ड के आधार पर दिया जाएगा।

कैरिबियन

एंटीगुआ और बारबुडा

इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन फॉर माईग्रेशन (आईओएम) और यूएन अपील ट्रिब्यूनल के बाह्य ऑडिटर सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए इसने भारत की दावेदारी का समर्थन किया है।

क्यूबा

भारत के साथ क्यूबा के संबंधों में वर्ष 2009 में तेजी से सुधार हुआ एवं इस दौरान दोनों देशों की ओर से बहुत से कार्यकलाप आयोजित किए गए तथा उच्चस्तरीय दौरों के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान किया गया। श्री ई. अहमद, विदेश राज्य मंत्री ने 27-30 अप्रैल, 2009 तक हवाना में आयोजित एनएएम मंत्रिमंडलीय सीओबी बैठक में 10-सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने क्यूबा के विदेश मंत्री श्री ब्रुनो रॉडरिग पेरिल्ला से मुलाकात की और बहुत से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

क्यूबा सरकार के अनुरोध पर 'इंडिया क्यूबा नॉलेज सेंटर' को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। क्यूबा के साथ 8 जून, 2009 को 'को-आपरेशन कन्वेनशन इन द आईसीटी सेक्टर' विषयक एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। 20 नवंबर, 2009 को आईटीईसी दिवस समारोह, भारत और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ (1960-2010) के समारोह की शुरूआत की सरकारी घोषणा की गई। इन समारोहों के एक भाग के रूप में आईसीसीआर ने क्यूबा के एक ख्यातिप्राप्त पेंटर मिस जायदा डेल रियो के भारत दौरे को प्रायोजित किया।

भारत ने नवंबर, 2009 में क्यूबा को यहां से कृषि संबंधी मशीनों की खरीद के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला प्रदान की।

डोमिनिकन गणराज्य (रिपब्लिक)

डोमिनिकन गणराज्य के साथ सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध लगातार व्यापक एवं प्रगाढ़ हो रहे हैं। इन संबंधों को डोमिनिकन

गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. लियोनेल फर्नांडेज के आमंत्रण पर 23-25 जनवरी, 2010 के दौरान विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर की डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा से नई दिशा प्राप्त हुई। विदेश राज्य मंत्री ने वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने, क्षेत्रीय विकास और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। वह विदेश मंत्री श्री कार्लोस मोरालेस ट्रांकोसो और विदेशी व्यापार तथा पर्यटन मंत्री श्री एडी मार्टिनज से भी मिले। इस दौरे के दौरान डोमिनिकन गणराज्य में एक सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

गुयाना

मई, 2009 में गुयाना में भारतीय प्रवेश दिवस की 171वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आईसीसीआर के एक समेकित नृत्य एवं संगीत दल ने गुयाना का दौरा किया। इस दौरान गुयाना में जल निकास और सिंचाई परियोजनाओं के लिए हैवी ड्यूटी कृषि पम्पों की खरीद हेतु 4 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला प्रदान करने के लिए एक करार को अंतिम रूप दिया गया।

हैती

भारत ने 12 जनवरी, 2010 को हैती में भूकम्प से फैली तबाही के लिए आपातकालीन राहत के रूप में 5 मिलियन अमरीकी डालर का नकद योगदान दिया है। हैती के लोगों और सरकार को हमारी संवेदना प्रेषित करने के लिए 26 जनवरी, 2010 को विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने व्यक्तिगत रूप से हैती का दौरा किया। यह किसी भारतीय मंत्री द्वारा हैती का किया गया पहला दौरा है और इस दौरान वे हैती के राष्ट्रपति श्री रैने प्रीवेल से भी मिले। भारत में सृजित पहली पुलिस यूनिट (एफपीयू) कंटिंजेंट, जो हैती में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सहयोग के तौर पर संयुक्त राष्ट्र स्टेबलाइजेशन मिशन इन हैती (एमआईएनयूएसटीएएच) में शामिल हुई, ने 17 अक्तूबर 2009 को सफलता पूर्वक अपनी सेवा का एक वर्ष पूरा किया है। इस कंटिंजेंट ने हैतियन नेशनल पुलिस (एचएनपी) और संयुक्त राष्ट्र पुलिस (यूएनपीओएल) को अपने दैनिक कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष ऑपरेशनों के दौरान सक्रिय सहयोग प्रदान किया। मिशन अधिदेश को आगे बढ़ाने में आईएफपीयू के योगदान की एमआईएनयूएसटीएएच प्राधिकारियों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। इसी प्रकार की दूसरी कंटिंजेंट 17 अक्तूबर, 2009 को हीं हैती के पोर्ट-आफ-प्रिंस में पहुँची है।

जमैका

आईटीईसी कार्यक्रम के तहत भारतीय सहायता से किंग्सटन में स्थापित किए गए आईसीटी केन्द्र ने फरवरी, 2009 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

सूरीनाम

इस वर्ष भारत और सूरीनाम के बीच द्विपक्षीय संबंध पराकाष्ठा पर पहुँच गए। इस दौरान सूरीनाम में वाणिज्यिक ढांचों में निवेश को बढ़ावा दिया गया। एक भारतीय कम्पनी-3 एफ (फूड,फैट एण्ड फर्टिलाइजर) को इसकी ऑयल-पाम परियोजना के लिए सूरीनाम सरकार द्वारा 21000 हेक्टेयर भूमि देने का प्रस्ताव किया गया है। एक बार परियोजना के पूरी तरह से परिचालित हो जाने पर इसमें 200 मिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक का निवेश शामिल होगा और इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर 4000 से अधिक लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा।

भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई ऋण श्रृंखला के तहत सूरीनाम के रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13.407 मिलियन अमरीकी डालर की लागत पर 3 चेतक हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सूरीनाम के सार्वजनिक कार्य मंत्री श्री गणेश कान्धाई ने किर्लोस्कर बंधुओं द्वारा स्थापित किए जा रहे दूसरे चरण के पंपिंग स्टेशनों की स्थापना के संबंध में किर्लोस्कर बंधुओं के आमंत्रण पर 13-17 अप्रैल, 2009 को भारत का दौरा किया।

सेंट लूसिया

भारत ने सेंट लूसिया को एक अग्नि दुर्घटना में नष्ट हो गए सेंट जुडे हॉस्पिटल के पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख 50 हजार अमरीकी डालर का नकद डोनेशन दिया है।

त्रिनिदाद एवं टोबेगो

27-29 नवंबर, 2009 तक सीएचओजीएम सम्मेलन के लिए भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के त्रिनिदाद एवं टोबेगो दौरे के दौरान उन्होंने उस क्षेत्र के कई देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया।

फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबेगो के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सीआईआई ने पहली इंडिया-कैरिबियन कनक्लेव का आयोजन 23 जून, 2009 को किया। इसका उद्घाटन टी एण्ड टी ट्रेड एवं उद्योग मंत्री मेरियानो ब्राउन द्वारा किया गया। इस कनक्लेव में सूरीनाम, क्यूबा और एल सल्वाडोर ने भी भाग लिया। सीआईआई के एक दल ने भी 24-27 जून, 2009 तक आयोजित 10वें व्यापार एवं निवेश सम्मेलन (टीआईसी) में भाग लिया। भारतीय पर्यटन और यात्रा विषयक एक सेमिनार का उद्घाटन टी एण्ड टी पर्यटन मंत्री श्री रॉस द्वारा किया गया। भारत-टी एण्ड टी चेम्बर ऑफ इंडस्ट्री एवं कॉमर्स की स्थापना न केवल भारत और टी एण्ड टी में व्यापार और निवेश के लिए की गई बल्कि यह फोरम अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार एवं निवेश की संभवनाएं तलाश करेगा।

भारत और त्रिनिदाद एवं टोबेगो के स्वतंत्रता दिवस जो क्रमशः 15 और 31 अगस्त को होते हैं, को मनाये जाने के उपलक्ष्य में 7-31 अगस्त, 2009 के बीच एक भारतीय महोत्सव का आयोजन भी किया गया। आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित एक सांस्कृतिक दल ने भारतीय प्रवेश दिवस समारोह में भाग लेने के लिए 26 मई-1 जून, 2009 तक त्रिनिदाद एवं टोबेगो का दौरा किया।

■■

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 9

यूएनपी

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 64वां सत्र

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने 20-27 सितंबर, 2009 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र की आम बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 26 सितंबर, 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते समय विदेश मंत्री ने इस समय की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के सामने मौजूद चुनौतियों का कारगर ढंग से सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक अभिशासन संरचनाओं के सुधार एवं पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का सही मायने में सहभागितापूर्ण एवं वैश्विक प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे द्वीपीय राष्ट्रों एवं अफ्रीका समेत विकासशील देशों की आवाज मुख्य रूप से प्रासंगिक है। विशेष रूप से, विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका सुदृढ़ करने तथा वैश्विक विचार-विमर्श में इसकी भूमिका बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) को विकास के लिए एक मजबूत निकाय में परिवर्तित करने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सुधार करने एवं इसकी स्थायी एवं अस्थाई सदस्यता का विस्तार करके इसे और प्रतिनिधिमूलक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आर्थिक एवं वित्तीय संकट की बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रत्युत्तर न केवल अर्थव्यवस्थाओं को उत्प्रेरित करने वाले उपायों तक सीमित होना चाहिए, अपितु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इसमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अभिशासन प्रणाली, जो संकट से निपटने में विफल रही, के पुनर्गठन के तरीके शामिल होने चाहिए। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आर्थिक उथल-पुथल के कारण गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता एवं रोगों के उन्मूलन में मेहनत से प्राप्त उपलब्धियां मिट्टी में मिल रही हैं तथा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य है कि संयुक्त राष्ट्र इन चुनौतियों से निजात पाने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करे तथा संकट के किसी भी वैश्विक प्रत्युत्तर में विकासशील देशों को प्राथमिकता मिले।

वैश्विक आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने दोहा विकास दौर में वार्ताओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया तथा इन्हें शीघ्र बहाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत निष्पक्ष एवं साम्यपूर्ण नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का पुरजोर समर्थन करता है, जो विकासशील देशों की जायज मांगों को स्वीकार करती हैं एवं उन पर ध्यान देती है।

जलवायु परिवर्तन पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कोपेनहेगन सम्मेलन में एक ऐसे परिणाम के लिए काम करेगा, जो विकासशील देशों की विकास अनिवार्यताओं को स्वीकार करे तथा जिसकी जड़ें साझी किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियों एवं संबंधित सक्षमताओं के सिद्धांत पर आधारित हों। उन्होंने केवल 'उपशमन' पर ध्यान देने से आगे निकलने की आवश्यकता पर बल दिया तथा यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि ऐसे अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित हो, जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि वित्तीय, प्रौद्योगिकीय एवं क्षमता निर्माण संसाधनों के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता अवश्य की जाए ताकि वे अनुकूलन से संबंधित व्यापक चुनौतियों का सामना कर सकें तथा ऐसे विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है जो छोटे-छोटे द्वीपीय राष्ट्रों की तथा सबसे अधिक अरक्षित राष्ट्रों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत द्वारा 'जलवायु परिवर्तनः प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण' पर उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन (22-23 अक्तूबर, 2009) की मेजबानी महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री ने भारत द्वारा उठाए गए घरेलू कदमों का भी उल्लेख किया जैसे कि अलग आठ राष्ट्रीय मिशनों के साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसमें परिवर्धित ऊर्जा दक्षता एवं सौर ऊर्जा के लिए मिशन शामिल हैं, 2009 में वानिकी के लिए बजट को दो गुना करके 1.3 बिलियन करना, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रमुख अनुसंधान को सहायता देना एवं सुकर बनाना।

परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को भारत द्वारा प्रदान की गई सर्वोच्च प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए, विदेश मंत्री ने परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने पर नवीकृत वैश्विक बहस का स्वागत किया। उन्होंने परमाणु हथियारों का उत्पादन करने, विकास करने, जखीरा बनाने एवं प्रयोग करने पर प्रतिबंध के लिए एक निर्दिष्ट समय-सीमा के अंतर्गत उनके पूर्ण उन्मूलन का प्रावधान करने के लिए भारत के परमाणु हथियार अभिसमय संबंधी प्रस्ताव को दोहराया, जिसे पहली बार 1988 में राजीव गांधी कार्य योजना में अभिव्यक्त किया गया तथा सितंबर 2008

में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में प्रधान मंत्री द्वारा उल्लिखित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली कार्रवाई के साथ भारत के दीर्घावधिक संबंधों को याद करते हुए, विदेश मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि शांति बहाली संबंधी कार्रवाइयों के लिए मानदंड संबंधी आधार को सुदृढ़ करने और सैन्य बल प्रदान करने वाले प्रमुख देशों (टीसीसी) को अधिक महत्व देने से शांति बहाली का काम और कारगर ढंग से एवं

विदेश मंत्री ने सभी देशों से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूपरेखा को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अभिसमय (सीसीआईटी) के पाठ पर शीघ्र सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास करने का भी आह्वान किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अतिरिक्त समय में विदेश मंत्री ने 22 सितंबर, 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री बान की मून द्वारा आयोजित 'जलवायु परिवर्तन पर शिखर बैठक' में प्रधान मंत्री का प्रतिनिधित्व किया। गोलमेज में अपने हस्तक्षेप में विदेश मंत्री ने कहा कि कोपेनहेगन में सारवान एवं रचनात्मक परिणाम सुनिश्चित करने में भारत की काफी रुचि है तथा हम समाधान के अंग होंगे, भले ही हमने समस्या उत्पन्न नहीं की है। उन्होंने कहा कि परिणाम समता पर आधारित होना चाहिए तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के प्रावधानों एवं सिद्धांतों, विशेष रूप से साझी किन्तु विभेदीकृत जिम्मेदारियों के साथ-साथ ऐतिहासिक जिम्मेदारी का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस बात का सुनिश्चय भी किया जाना चाहिए कि विकासशील देश त्वरित विकास के पथ पर चलते रहें ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने एवं अनुकूलन के लिए उनके पास संसाधन हों। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश तथा जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरन ने भी जलवायु परिवर्तन पर आयोजित बैठक में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान अतिरिक्त समय में विदेश मंत्री ने न्यूयार्क में आयोजित विभिन्न उच्च स्तरीय बहुपक्षीय बैठकों में भाग लिया, नामतः समूह-15 (जी-15) की 14वीं शिखर बैठक (25 सितंबर), इब्सा (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) की मंत्रिस्तरीय बैठक (21 सितंबर), जी-5 की विदेश मंत्री बैठक (22 सितंबर), राष्ट्रमंडल विदेश मंत्री बैठक और राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय पर्यटन बैठक (24 सितंबर), ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत एवं चीन) मंत्रिस्तरीय बैठक (24 सितंबर), यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ पर बैठक (24 सितंबर), समूह-15 की मंत्रिस्तरीय बैठक (24 सितंबर), पांचवीं भारत-जीसीसी राजनीतिक वार्ता (25 सितंबर), जी-77 मंत्रिस्तरीय बैठक (25 सितंबर) और सार्क मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक (26 सितंबर)। इसके अलावा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सभ्यताओं के गठबंधन के मित्र समूह की बैठक (26 सितंबर) में तथा नए अथवा बहाल किए गए लोकतंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएनआरडी) की मंत्रिस्तरीय बैठक (29 सितंबर) में भी भाग लिया।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में भाग लिया तथा 19 अक्तूबर, 2009 को 'शांति एवं विकास के लिए खेलः खेल एवं ओलम्पिक आदर्श के माध्यम से शांतिपूर्ण एवं बेहतर विश्व का निर्माण' विषय पर वक्तव्य दिया।

विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में भाग लिया तथा 20 अक्तूबर, 2009 को 'अफ्रीका के विकास के लिए नई साझीदारीः कार्यान्वयन में प्रगति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहायता' विषय पर वक्तव्य दिया। डॉ. थरूर ने जनसंख्या एवं विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर भी 12 अक्तूबर, 2009 को एक वक्तव्य दिया।

18 संसद सदस्यों से युक्त भारत के एक गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर-नवंबर, 2009 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में भाग लिया तथा अनेक सामयिक विषयों पर भारत की स्थिति पर वक्तव्य दिया।

जून 2009 में आयोजित चुनावों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए 16 सदस्य राष्ट्रों में भारत भी एक था। सुरक्षा परिषद के 16 चुने गए सदस्य तथा पांच स्थायी सदस्य मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य समिति के सदस्य के रूप में काम करते हैं।

तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्तूबर, 2009 को डैग हम्मार्सजोल्ड पुस्तकालय, न्यूयार्क में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया, जिसके दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डॉ. अली अब्दुस्सलाम ट्रिकी और संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव डॉ. आशा-रोस मिगिरो द्वारा एक स्मारक डाक टिकट एवं स्मृति कार्ड जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन द्वारा जारी किया गया एक डालर का डाक टिकट महात्मा गांधी की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाता है, जिसे डॉ. फेरडी पैशिको ने डिजाइन किया था। स्मृति कार्ड चार नए डाक टिकटों के ब्लॉक को दर्शाता है तथा इस पर भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा एवं संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री बान की मून की ओर से संदेश हैं।

संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक मुद्दे

भारतीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में तथा इसकी समितियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, महासभा का सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, शांति बहाली, शांति निर्माण, केंद्रीय आपात कालीन प्रत्युत्तर निधि, मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन, सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की रक्षा, अफगानिस्तान में स्थिति, मध्य पूर्व में स्थिति, फिलीस्तीन का मुद्दा तथा नए अथवा बहाल किए गए लोकतंत्रों के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सरकारों के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा

सहायता आदि के मुद्दों पर वक्तव्य दिया। मुख्य राजनीतिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में हुई चर्चाओं में भारत की भागीदारी के मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं।

मध्य पूर्व

भारत 64वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र के साथ-साथ चौथी समिति में मध्य-पूर्व के मुद्दे पर विचार-विमर्श में शामिल रहा। फिलीस्तीन के मुद्दे पर भारत के वक्तव्यों ने चारपक्षीय रोडमैप तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 1397 एवं 1515 में यथा पृष्ठांकित इजराइल के साथ शांति को साथ-साथ, सुरक्षित एवं मान्यताप्राप्त सीमाओं के अंदर एक स्वतंत्र, संप्रभु, व्यवहार्य एवं एकीकृत फिलीस्तीन राष्ट्र में रहने के उनके अधिकार के साथ फिलीस्तीनी लोगों के अहरणीय अधिकारों के लिए अपना स्थाई, ऐतिहासिक एवं दृढ़ समर्थन दोहराया। आतंक एवं हिंसा के सभी कृत्यों के प्रति अपने पुरजोर विरोध को दोहराते हुए, भारत के वक्तव्यों ने उनके जायज लक्ष्यों को प्राप्त करने में तथा गरिमा एवं आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर केंद्रित उनके प्रयासों में फिलीस्तीनी लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया।

गाजा पट्टी में मानवीय सरोकारों को प्राथमिकता प्रदान करने पर बल देते हुए, भारत ने अधिकृत फिलीस्तीनी भूभाग में इजराइली बस्तियां बसाने का कार्य बंद करने तथा फिलीस्तीन के अंदर सामानों एवं व्यक्तियों की स्वतंत्र आवाजाही पर प्रतिबंध समाप्त करने का आह्वान किया। भारत ने दिसंबर, 2008 से जनवरी, 2009 के दौरान गाजा संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून एवं मानवाधिकार कानून के हुए उल्लंघनों की कठोर शब्दों में निन्दा की तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून एवं मानवाधिकार कानून के संगत लिखतों का सभी संबंधित पक्षों द्वारा बिना शर्त पालन करने का आह्वान किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी गाजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र तथ्यान्वेषी मिशन पर संकल्प के समर्थन में मतदान किया। साथ ही भारत ने गाजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र तथ्यान्वेषी मिशन द्वारा की गई कुछ सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भागीदारी तथा मिशन द्वारा अपनाई गई कुछ कार्यविधियां शामिल हैं।

भारत ने अधिकृत फिलीस्तीनी भूभाग में राहत कार्य करने के लिए 2009 के दौरान, जो इसकी स्थापना का 60वां वर्ष था, संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) में अपने योगदान में वृद्धि की। भारत ने गाजा के पुनर्गठन के लिए फिलीस्तीनी अर्थव्यवस्था की सहायता करने के लिए मार्च 2009 में शर्म-अल-शेख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद फिलीस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकारण को बजट सहायता के रूप में 10 मिलियन अमरीकी डालर की राशि भी प्रदान की।

फिलीस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में प्रधान मंत्री ने कहा कि टिकाऊ, व्यापक एवं उचित समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से शांति प्रक्रिया को तेज करने के लिए समवेत एवं चहुंमुखी कार्रवाई आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सुधार

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यथार्थ एवं व्यापक सुधार की दिशा में सक्रियता से प्रयास करता रहा, जिसमें इसकी स्थायी एवं अस्थायी सदस्यता की दोनों श्रेणियों में विस्तार तथा काम करने की विधियों में सुधार शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटना मार्च, 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनौपचारिक पूर्ण सत्र में अंतर्सरकारी वार्ताओं की शुरुआत थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में मार्च से सितंबर, 2009 के दौरान तीन दौर की वार्ता हुई। इन वार्ताओं के दौरान अधिकांश प्रतनिधिमंडलों ने स्थाई एवं अस्थाई दोनों श्रेणियों में विस्तार के लिए अपनी तरजीह का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया। अंतर्सरकारी वार्ताओं के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए सारांशों में इस पहलू को नोट किया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र के अंत में जी-4 देशों (ब्राजील, जर्मनी एवं जापान) तथा अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन एवं प्रशांत द्वीप के समान विचार वाले राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक ऐसा संकल्प अपनाए जाने के लिए सफलतापूर्वक काम किया, जो 63वें सत्र में हुई प्रगति के आधार पर 64वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में वार्ताओं की तत्काल बहाली का आह्वान करता है। चौथे दौर की वार्ता दिसंबर, 2009 में आयोजित की गई। तदनंतर, जी-4 देशों तथा दक्षिण अफ्रीका ने वार्ताओं के अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत करने के लिए 138 देशों को लामबंद किया जिसमें एक ऐसा पाठ प्रस्तुत करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया जिस पर वार्ता आगे बढ़ सके।

आतंकवाद

आतंकवाद की रोकथाम एवं दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सुदृढ़ीकरण संयुक्त राष्ट्र में भारत की भागीदारी की प्रमुख प्राथमिकता बनी रही। इस संदर्भ में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) के प्रारूप पर वार्ता को शीघ्र अंजाम पर पहुंचाने के लिए अन्य देशों के साथ अपनी भागीदारी जारी रखी। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने अक्तूबर, 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र के अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में व्यापक अभिसमय के महत्व पर बल दिया तथा प्रारूप सीसीआईटी को अविलंब अंतिम रूप देने एवं अपनाने के लिए सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया। भारत ने 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति के कार्यान्वयन तथा संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यान्वयन कार्यबल (सीटीआईटीएफ) के संस्थान करण के प्रति अपना समर्थन जारी रखा। भारत ने आतंकवाद से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखा। अल-कायदा

एवं तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति की निगरानी टीम के समन्वयक श्री रिचर्ड बेरेट ने आतंकवाद रोधी उपायों के कार्यान्वयन में सहयोग पर चर्चा करने के लिए सितंबर, 2009 में भारत का दौरा किया।

शांति रक्षा

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा पर नीतिगत बहस में सक्रियता से भाग लिया तथा 2009 के दौरान शांति रक्षा से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीन वक्तव्य दिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा कार्रवाई में नागरिकों की सुरक्षा पर बहस में भी वक्तव्य दिया। इसके अलावा, भारत में शांति रक्षा संबंधी कार्रवाइयों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यसमूह के साथ अपनी भागीदारी जारी रखी तथा शांति रक्षा के क्षेत्र में अन्य बहुपक्षीय पहलों में हिस्सा लिया।

भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा संबंधी कार्रवाइयों में योगदान देने वाले सबसे पुराने, सबसे बड़े एवं संघटक देशों में से एक है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र के 9 शांति रक्षा मिशनों में लगभग 8760 सैन्यबलों की तैनाती के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा सैन्यबल योगदानकर्ता देश था। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत की सबसे बड़ी उपस्थिति कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र में थी (4547), जिसके बाद सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (2677) का स्थान है। चुनौतीपूर्ण स्थितियों में संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात भारतीय सैनिकों एवं पुलिसकर्मियों द्वारा निरंतर रूप से अनुरक्षित निष्पादन के उच्च मानकों ने उन्हें पूरे विश्व में सम्मान दिलाया है।

संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष

ऐसी परियोजनाओं की सहायता के लिए 2005 में आरंभ किए गए संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में भारत ने प्रमुख भूमिका निभाना जारी रखा, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ एवं समेकित करती हैं तथा लोकतांत्रिक अभिशासन को संभव बनाती हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक तथा 20 मिलियन अमरीकी डालर के योगदान के साथ यूएनडीईएफ में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। अपने अस्तित्व में आने के समय से ही यूएनडीईएफ ने तीन चक्रों में लगभग 271 परियोजनाओं के लिए तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता की है। 2009 के दौरान यूएनडीईएफ के सलाहकार बोर्ड की दो बार बैठक अप्रैल एवं अक्तूबर में हुई। अक्तूबर, 2009 में बोर्ड की पिछली बैठक में नई परियोजनाओं के वित्तपोषण का चौथा चक्र शुरू करने की सिफारिश की गई। सलाहकार बोर्ड के साथ-साथ विशेषज्ञ समूह की बैठकों में भारत ने परियोजनाओं की कारगर निगरानी तथा निधियों के समुचित उपयोग एवं वितरण पर बल दिया है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर ने 1-3 दिसंबर, 2009 तक नैरोबी, कीनिया में दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 2 दिसंबर, 2009 को सम्मेलन को संबोधित करते समय उन्होंने द्विपक्षीय रूप में तथा साथ ही क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय समूहों की रूपरेखा में दक्षिण के सामूहिक हित को आगे बढ़ाने के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता एवं प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से दक्षिण-दक्षिण सहयोग का विस्तार करने तथा उत्तर से संसाधन लाकर त्रिकोणीय सहयोग बढ़ाने को संभव बनाने तथा दक्षिणी सक्षमताओं, विशेषज्ञता एवं अनुभव का लाभ उठाने का भी आग्रह किया।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन

गुट निरपेक्ष आंदोलन

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 15-16 जुलाई, 2009 को शर्म-अल-शेख, मिस्र में गुट निरपेक्ष आंदोलन (नाम) के 14वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस शिखर बैठक के दो विषय इस प्रकार थेः 'वर्तमान आर्थिक एवं वित्तीय संकट' तथा 'शांति एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता'। शिखर बैठक में अपने वक्तव्य में प्रधान मंत्री ने विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुधार संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में 'नाम' के महत्व को उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर गंभीर सरोकार व्यक्त करते हुए प्रधान मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) पर शीघ्र सहमति का आह्वान किया। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने 'नाम' शिखर बैठक से ठीक पहले 13-14 जुलाई, 2009 को आयोजित 'नाम' की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री ने 13 जुलाई, 2009 को आयोजित 'नाम' की फिलीस्तीन पर समिति की मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लिया।

तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री श्री ई. अहमद ने 'नाम' शिखर बैठक की तैयारी के लिए 29-30 अप्रैल, 2009 को हवाना, क्यूबा में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन समन्वय ब्यूरो की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 'नाम' की मंत्रिस्तरीय बैठक द्वारा अपनाए गए अंतिम दस्तावेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुम्बई में 26-29 नवंबर, 2008 तक घृणित आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निन्दा की गई तथा निन्दनीय हमले के षडयंत्रकारियों, आयोजकों, वित्तपोषकों एवं प्रायोजकों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया।

राष्ट्रमंडल

राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में सबसे बड़ा देश भारत इसकी गतिविधियों में योगदान देने वाले अग्रणी देशों में से एक तथा इसके बजट में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में पांचवां है। विकासशील राष्ट्रमंडल देशों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रमंडल तकनीकी सहयोग कोष (सीएफटीसी) के अंतर्गत यूके के बाद सबसे अधिक मात्रा में तकनीकी विशेषज्ञ प्रदान करता है तथा 2009-10 में इसने इस कोष में 1 मिलियन

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 16 जुलाई, 2009 को शर्म-अल-शेख, मिस्र में नाम के पंद्रहवें शिखर बैठक के दौरान प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए साथ में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की 16 जुलाई, 2009 को शर्म-अल-शेख, मिस्र में आयोजित पंद्रहवीं नाम शिखर बैठक के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति श्री होसनी मुबारक से मुलाकात।

अमरीकी डालर का योगदान दिया। भारत ने राष्ट्रमंडल देशों में डिजिटल अंतराल को पाटने के लिए माल्टा में चोगम-2005 में सृजित राष्ट्रमंडल संयोजकता विशेष स्वैच्छिक कोष में भी 1 मिलियन यूरो के योगदान की प्रतिबद्धता की।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 27-29 नवंबर, 2009 तक पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनीडाड और टोबैगो में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक (चोगम) में भाग लिया। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने 25-26 नवंबर, 2009 तक पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित चोगम पूर्व विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लिया। चोगम, 2009 का विषय थाः 'अधिक साम्यपूर्ण एवं स्थायी भविष्य के लिए साझेदारी'। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने चोगम, 2009 की प्रेसवार्ता को अंतिम रूप देने तथा जलवायु परिवर्तन समेत अन्य अकेले वक्तव्यों को अंतिम रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाई। चोगम, 2009 के दौरान प्रधान मंत्री ने राष्ट्रमंडल के लिए भारत द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त पहलों की घोषणा कीः

क) 2010 में आरंभ होने वाले विदेश सेवा संस्थान, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के लिए एक पूर्णतः वित्तपोषित राजनयिक प्रशिक्षण मॉड्यूल।

(ख) भारत राष्ट्रमंडल साझेदारी प्लेटफार्म पोर्टल (सीपी 3) के पहले चरण की लागत वहन करने की जिम्मेदारी लेगा।

(ग) राष्ट्रमंडल 2010 खेल के मेजबान के रूप में, भारत चार वर्ष के लिए राष्ट्रमंडल सचिवालय में खेल विकास सलाहकार के पद का खर्च वहन करेगा।

(घ) भारत के अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रमंडल देशों के लिए प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त 250 स्लाट्स।

(ङ) जिनेवा में नवगठित राष्ट्रमंडल लघु राष्ट्र संयुक्त कार्यालय के लिए प्रतिवर्ष 80,000 अमरीकी डालर का अंशदान।

(च) दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रमंडल मीडिया विकास कोष में भारत के अंशदान को दोगुना करके 1,20,000 अमरीकी डालर करना।

(छ) अनुभवों का आदान-प्रदान करने तथा एक दूसरे से सबक लेने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोगों का एक निकाय आयोजित करने संबंधी राष्ट्रमंडल महासचिव की पहल के लिए समर्थन।

भारत सरकार ने 2009 को आधुनिक राष्ट्रमंडल के सृजन की 60वीं वर्षगांठ के रूप में मनाने के लिए अनेक पहलों एवं परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें स्मारक डाक टिकट एवं पहले दिन के कार्यक्रम का प्रसारण जारी करना तथा 100 रुपये एवं 5 रुपये के स्मारक सिक्के जारी करना शामिल है।

सोमालिया के समुद्री तट पर समुद्री डकैती रोकने पर संपर्क समूह

भारत ने अदन की खाड़ी में तथा सोमालिया के समुद्री तट पर समुद्री डकैती से लड़ने के इच्छुक देशों एवं संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में जनवरी, 2009 में स्थापित सोमालिया तट से समुद्री डकैती समाप्त करने पर संपर्क समूह (सीजीपीसीएस) के विचार-विमर्शों में भाग लेना जारी रखा। भारत सीजीपीसीएस का संस्थापक सदस्य है, जिसमें प्रेक्षक के रूप में भाग लेने वाले दो समुद्र उद्योग समूहों अर्थात बिमको एवं इटरटान्को के साथ इस समय 45 देश एवं 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन (संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, नाटो, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, अरब राष्ट्र लीग, इंटरपोल एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन) शामिल हैं।

लोकतंत्रों का समुदाय

विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने 11-12 जुलाई, 2009 को लिस्बन में इस समूह के अध्यक्ष के रूप में पुर्तगाल की मेजबानी में आयोजित लोकतंत्रों के समुदाय (सीओडी) के 5वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में 'लोकतांत्रिक अभिशासन में वर्तमान वित्तीय एवं आर्थिक संकट के फलितार्थ, लोकतांत्रिक अभिशासन एवं विकास तथा लोकतंत्रों के समुदाय के लिए भावी चुनौतियां', पर तीन विषयपरक सत्र आयोजित किए गए। भारत सीओडी के संचालन समूह का सदस्य है, जो पूरे विश्व में अभिशासन के लोकतांत्रिक रूप के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक देशों का एक मंच है।

आर्थिक मुद्दे

विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने सितंबर, 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र की आम बहस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 26 सितंबर, 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते समय विदेश मंत्री ने इस बात पर गहन आत्म-विश्लेषण करने की आवश्यकता पर बल दिया कि क्या संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य वैश्विक अभिशासन संरचनाएं उन चुनौतियों को कारगर ढंग से पूरा करने के लिए सुनिर्मित हैं, जिनका वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि वैश्विक चुनौतियों को सही मायने में सहभागितापूर्ण एवं वैश्विक प्रत्युत्तर मिले, तो वैश्विक अभिशासन वास्तुशिल्प का सुधार एवं पुनर्गठन हमारे समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है तथा छोटे-छोटे द्वीपीय राष्ट्रों एवं अफ्रीका समेत विकासशील देशों की आवाज की प्रासंगिकता सबसे अधिक है।

विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान आर्थिक एवं वित्तीय संकट के आलोक में, गरीबी, भुखमरी, निरक्षरता एवं रोगों के निवारण में मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियां मिट्टी में मिलती जा रही हैं तथा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अनिवार्य

है कि इन चुनौतियों से संगत ढंग से निजात पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सहमति से कार्य करना चाहिए। भारत, जो जी-20 तथा अन्य प्रक्रियाओं में सक्रियता से शामिल है, ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि संकट के किसी भी वैश्विक प्रत्युत्तर में विकासशील देशों को प्राथमिकता अवश्य मिलनी चाहिए।

विदेश मंत्री ने दोहा विकास दौर में वार्ता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा कहा कि भारत पूरी तरह से निष्पक्ष एवं साम्यपूर्ण नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के पक्ष में है, जो विकासशील देशों की जायज मांगों को स्वीकार करता है तथा उस पर ध्यान देता है। उन्होंने वार्ता शीघ्र बहाल करने संबंधी भारत के प्रयासों, विशेष रूप से 3-4 सितंबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का भी स्मरण किया।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने 24-30 जून, 2009 के दौरान न्यूयार्क में 'विश्व वित्तीय एवं आर्थिक संकट तथा विकास पर इसका प्रभाव' पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारतीय प्रतनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने 25 जून, 2009 को पूर्ण सत्र को संबोधित किया। भारत ने सम्मेलन के दौरान आयोजित चार गोलमेज बैठकों में भी भाग लिया।

भारत ने न्यूयार्क में 6 अप्रैल, 2009 को आयोजित 'वैश्विक खाद्य संकट और खाद्य का अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अंतःक्रियात्मक विषयपरक वार्ता' और 18 जून, 2009 को 'ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत' पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अंतःक्रियात्मक विषयपरक वार्ता में भाग लिया।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में भाग लिया तथा 'शांति एवं विकास के लिए खेलः खेल एवं ओलंपिक आदर्श के माध्यम से शांतिपूर्ण एवं बेहतर विश्व का निर्माण' विषय पर वक्तव्य दिया।

विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में भाग लिया तथा 'अफ्रीका के विकास के लिए नई साझेदारीः कार्यान्वयन में प्रगति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहायता' विषय पर वक्तव्य दिया।

लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने 16-17 नवंबर, 2009 को न्यूयार्क में आयोजित संसद अध्यक्षों के तीसरे विश्व सम्मेलन की तैयारी समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया।

आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी)

6-30 जुलाई, 2009 तक जिनेवा में आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) का सारवान सत्र, 2009 आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर ने इस सत्र के मंत्री स्तरीय खण्ड में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ब्रेटन वुड्स संस्थाओं, विश्व व्यापार संगठन के साथ ईसीओएसओसी की वसंतकालीन उच्चस्तरीय बैठक तथा संयुक्त राष्ट्र व्यापार पर विकास सम्मेलन न्यूयार्क में 27 अप्रैल, 2009 को आयोजित किया गया। आर्थिक कार्य विभाग में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद विरमानी ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

पोषणक्षम विकास आयोग

भारत ने पोषणक्षम विकास आयोग के कार्य में सक्रियता से भाग लिया। यह एजेंडा 21 तथा जोहान्सबर्ग कार्यान्वयन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं संवर्धन की भूमिका के साथ स्थाई विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंदर उच्च स्तरीय आयोग है। राज्य मंत्री (वन एवं पर्यावरण) श्री नमोनारायण मीणा ने 4 से 15 मई, 2009 तक न्यूयार्क में आयोजित आयोग के 17वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह दो वर्षीय कार्यान्वयन चक्र का नीति सत्र था तथा कृषि, ग्रामीण, विकास, भूमि, सूखा, मरुस्थलीकरण एवं अफ्रीका जैसे विषयपरक क्लस्टर पर केंद्रित था।

संयुक्त राष्ट्र वन मंच

भारत ने 21 अप्रैल-1 मई 2009 तक न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन मंच के आठवें सत्र (यूएनएफएफ 8) में भाग लिया। भारत ने 30 अक्तूबर, 2009 को न्यूयार्क में आयोजित यूएनएफएफ 9 के विशेष सत्र में भाग लिया।

मानवीय मामले / आपदा जोखिम कटौती

भारत ने इस क्षेत्र में जिनेवा में आधारित दो मुख्य संगठनों, नामतः संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय (यूनोचा) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा कटौती रणनीति (यूएनआईएसडीआर) के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा। गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 16-19 जून, 2009 तक जिनेवा में यूएनआईएसडीआर द्वारा आयोजित वैश्विक आपदा जोखिम कटौती मंच के दूसरे सत्र में भाग लिया।

4-6 नवंबर, 2009 तक दूसरे भारतीय आपदा प्रबंधन कांग्रेस में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के निमंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव तथा आपदा जोखिम कटौती के लिए विशेष प्रतिनिधि सुश्री मार्गरेटा वाल्स्ट्रोम ने भारत का दौरा किया।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर)

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त श्री अंटोनियो ग्यूटेरेस ने 1-2 दिसंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। यह भारत की उनकी दूसरी यात्रा थी, उनकी पहली यात्रा 2006 में हुई थी तथा 2008 में जिनेवा में यूएनएचसीआर के मुख्यालय में औपचारिक द्विपक्षीय विचार-विमर्श के पहले दौर का आयोजन किया गया था। चर्चा सार्थक रही तथा इसने अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एजेंडा के लिए वर्तमान चुनौतियों पर विचारों के आदान-प्रदान के अलावा भारत के अनुभव एवं विशेषज्ञता को साझा करने का अवसर प्रस्तुत किया।

भारत ने यूएनएचसीआर कार्यक्रम की कार्यकारिणी समिति के 60वें सत्र में भाग लिया, जिसका आयोजन 28 सितंबर-2 अक्तूबर, 2009 तक जिनेवा में किया गया।

सामाजिक एवं मानवाधिकार के मुद्दे

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में विभिन्न एजेंडा मुद्दों पर बहस में सक्रियता से भाग लिया जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं : मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट, पार-अटलांटिक गुलामी प्रथा की 200वीं वर्षगांठ समारोह के लिए अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो-अप), नए या बहाल किए गए लोकतंत्रों को बढ़ावा देने एवं सुदृढ़ करने के लिए सरकारों के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा सहायता, स्वापक औषधि आयोग के 52वें सत्र के उच्च स्तरीय खण्ड के परिणाम। सामाजिक विकास, महिलाओं की तरक्की, बच्चों के अधिकार, नस्लवाद एवं नस्लीय भेदभाव का उन्मूलन, लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार, अपराध की रोकथाम तथा आपराधिक न्याय और सुंयक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की रिपोर्ट आदि से संबंधित मुद्दों पर भी हस्तक्षेप किए गए।

भारत ने महासभा की तीसरी समिति में आयोजित बहस में भी भाग लिया, जो सामाजिक, मानवीय मामलों एवं मानवाधिकार के मुद्दों की जांच करती है। समिति ने 27 विशेष कार्यविधि अधिदेश धारकों, मानवाधिकार संधि निकायों के अध्यक्षों तथा मानवाधिकार परिषदों के कार्य समूहों के अध्यक्षों के साथ अंतःक्रियात्मक वार्ता आयोजित की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अपने कार्यालय के कार्य एवं प्राथमिकताओं का भी संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया।

महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग

महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग (सीएसडब्ल्यू) ने 2-13 मार्च, 2009 तक अपने 53वें सत्र का आयोजन किया। भारत चार वर्ष के लिए 2009 से इस आयोग का सदस्य है। अन्यों के अलावा, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्ष प्राथमिकता वाला विषय था 'एचआईवी/एड्स के संदर्भ में देखभाल समेत महिलाओं एवं पुरुषों के बीच जिम्मेदारियों का समान बंटवारा'। सम्मत निष्कर्षों के अलावा, आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर अनेक संकल्पों को अपनाया जिनमें फिलीस्तीन की महिलाओं की स्थिति तथा उनके लिए सहायता, कन्या शिशु तथा एचआईवी/एड्स शामिल हैं।

विकलांग व्यक्ति अधिकार अभिसमय के सरकारी पक्षकारों की दूसरी बैठक

भारत ने 2-4 सितंबर, 2009 तक आयोजित विकलांग व्यक्ति अधिकार अभिसमय के सरकारी पक्षकारों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में अभिसमय का सरकारी पक्षकार बनने के लिए देशों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। अभिसमय के कार्यान्वयन पर, विशेष रूप से भौतिक सुगम्यता, तर्कसंगत समायोजन, न्याय एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया तक पहुंच के क्षेत्र में तथा साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इस अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए विधायी उपायों पर अंतःक्रियात्मक चर्चाएं आयोजित की गईं। इस समय अभिसमय के 66 सरकारी पक्षकार हैं।

संयुक्त राष्ट्र में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन द्वारा एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया गया तथा जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन द्वारा जारी किया गया एक डालर का डाक टिकट महात्मा गांधी के कलात्मक प्रदर्शन को दर्शाता है, जिसे डॉ. फेरडी पैचिको द्वारा डिजाइन किया गया है। निशानी कार्ड पर चार नए डाक टिकटों का एक ब्लाक दर्शाया गया है तथा इस पर भारत के विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री बान की मून की ओर से संक्षिप्त संदेश छपे हैं।

मानवाधिकार परिषद

2009 के दौरान मावाधिकार परिषद का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा तथा इसने अपने अस्तित्व के चौथे वर्ष तक संस्था निर्माण पैकेज में रेखांकित तंत्रों को सफलतापूर्वक मूर्त रूप दिया। तीन नियमित सत्रों के अलावा, परिषद ने चार विशेष सत्रों का भी आयोजन किया (दो अधिकृत फिलीस्तीनी भूभाग में स्थिति पर, एक श्रीलंका पर और एक मानवाधिकारों की प्राप्ति पर वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट के प्रभाव पर)। परिषद ने 48 देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करते हुए तीन सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) सत्रों का भी आयोजन किया। सलाहकार समिति, सामाजिक मंच, अल्पसंख्यक मुद्दा मंच तथा देशज लोक विशेषज्ञ मंच के सत्रों के अलावा, परिषद ने विकास के अधिकार पर तथा पूरक मानकों के विस्तार पर सत्रों के आयोजन के साथ-साथ बच्चों के अधिकार पर अभिसमय के वैकल्पिक प्रोतोकॉल पर भी सत्र का आयोजन किया। वर्ष के दौरान कार्य समूह के विभिन्न तैयारी एवं अनुवर्तन सत्रों के साथ, 20-24 अप्रैल, 2009 तक नस्लवाद पर डरबन समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मानवाधिकारों एवं मूल्यों के प्रति अपनी परंपरागत प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, पूरे विश्व में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी रक्षा करने में परिषद की प्रभावकारिता बढ़ाने के विचार से भारत ने सभी सत्रों में रचनात्मक एवं समावेशी ढंग से सक्रियता से भाग लिया। हमारा दृष्टिकोण हमारे इस दृढ़ विश्वास द्वारा निर्देशित था कि परिषद के उद्देश्यों को वार्ता एवं सहयोग के माध्यम से सबसे अच्छी तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रमुख पहलू इस प्रकार थे:

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त सुश्री नवनीतम पिल्लई ने 22-24 मार्च, 2009 तक भारत का दौरा किया जो

एक दशक में इस तरह का पहला दौरा है। उच्च स्तरीय चर्चाओं के फलस्वरूप देश में मानवाधिकार की स्थिति के बारे में विचारों का खुलकर आदान-प्रदान हुआ तथा खुली वार्ता हुई।

- 20-22 अप्रैल, 2009 तक आयोजित डरबन समीक्षा सम्मेलन के उच्च स्तरीय खण्ड में विशेष सचिव (राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन) द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया।
- अन्य बातों के साथ-साथ, तैयारी समिति ब्यूरो के सदस्य के रूप में भारत ने नस्लवाद पर डरबन समीक्षा सम्मेलन के लिए तैयारियों में सक्रियता से योगदान दिया।
- चीन, भूटान और वनातू की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के लिए त्रोइका पर भारत ने रैपोर्टियर के रूप में काम किया; तथा चीन एवं भूटान दोनों के लिए त्रोइका की अध्यक्षता की।
- भारत ने अक्तूबर, 2009 तक मानवाधिकार के मुद्दों पर एशियाई समूह के क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में काम किया।
- विषाक्त एवं खतरनाक उत्पादों एवं अपशिष्ट के संचलन एवं डंपिंग के प्रतिकूल प्रभावों पर विशेष रैपोर्टियर श्री ओकेचुकवाउ इबीआनू ने 11-21 जनवरी, 2010 तक भारत का दौरा किया।

अनेक प्रख्यात भारतीयों ने महत्वपूर्ण संधि मानीटरिंग निकायों तथा मानवाधिकार तंत्रों के विशिष्ट सदस्य के रूप में काम करना जारी रखा। इनमें शामिल हैंः श्री पी. एन. भगवती (सदस्य, मानवाधिकार समिति), श्री चंद्रशेखर दासगुप्ता (सदस्य, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आयोग), श्री दिलीप लाहिड़ी (सदस्य, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति), सुश्री इंदिरा जयसिंह (सदस्य, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति), श्री अर्जुन सेनगुप्ता (अध्यक्ष, विकास के अधिकार पर अंतर्सरकारी कार्य समूह)। श्री आनंद ग्रोवर ने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के सर्वोच्च प्राप्य मानक प्राप्त करने के हर किसी के अधिकार पर विशेष रैपोर्टियर के रूप में अपने अधिदेश का निर्वाह करना जारी रखा।

चुनाव

सफल प्रचार अभियान के बाद, भारत ने पेरिस में यूनेस्को में 16-25 जून, 2009 तक आईओसी महासभा के 25वें सत्र के दौरान आयोजित चुनावों में आईओसी की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव जीता।

सफल प्रचार अभियान के बाद, भारत ने 23 नवंबर-4 दिसंबर 2009 तक लंदन में आयोजित आईएमओ की सभा के 26वें सत्र के दौरान 'बी' श्रेणी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठनों (आईएमओ) की परिषद का चुनाव जीता।

सफल प्रचार अभियान के बाद, भारत को 2010-2012 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

जलवायु परिवर्तन वार्ता तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय (यूएनएफसीसीसी)

भारत ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता एवं चर्चा को सुकर बनाने की पहल की है, जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर नई दिल्ली में 22-23 अक्तूबर, 2009 को 'जलवायु परिवर्तनः प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण' पर एक उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन उपशमन के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के लिए एक रोडमैप तैयार करने तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत बहुपक्षीय वार्ता का समर्थन करने के लिए अनेक देशों की सरकारों, विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों तथा सभ्य समाज को एकजुट किया। सम्मेलन ने यूएनएफसीसीसी पर चल रही वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रदान की।

विदेश मंत्री ने 'जलवायु परिवर्तन पर शिखर बैठक' नामक जलवायु परिवर्तन पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की। यह शिखर बैठक 22 सितंबर, 2009 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त समय में आयोजित की गई जिसमें पूरे विश्व के नेता जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। इस शिखर बैठक का उद्देश्य यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं में विज्ञान के आधार पर महात्वाकांक्षी सम्मत परिणाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षित राजनीतिकि इच्छा एवं विजन तैयार करना था। यह वार्ता मंच नहीं था। बैठक के दौरान राज्य मंत्री (वन एवं पर्यावरण) तथा जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री के विशेष दूत श्री श्याम सरन द्वारा विदेश मंत्री की सहायता की गई।

कोपेनहेगन में 7-18 दिसंबर, 2009 तक जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पक्षकार सम्मेलन (कोप-15) की 15वीं बैठक में अधिकारियों, सांसदों, सभ्य समाज के सदस्यों एवं युवाओं से युक्त एक बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। कोप-15 के दौरान राज्य मंत्री (वन एवं पर्यावरण) तथा जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री के विशेष दूत ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया, जबकि सम्मेलन के उच्च स्तरीय खंड, जिसका आयोजन 16-18 दिसंबर, 2009 को किया गया तथा जिसमें तकरीबन 120 देशों के राष्ट्राध्यक्षों/ शासनाध्यक्षों ने भाग लिया, में 18 दिसंबर, 2009 को प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान विकसित एवं विकासशील देशों के बीच सतत रूप से जारी गंभीर विभाजन देखा गया। फलस्वरूप, कोप-15 बाली रोडमैप द्वारा यथा अधिदेशित एडब्ल्यूजी-एलसीए (दीर्घावधिक सहयोगात्मक कार्रवाई पर तदर्थ कार्य समह - बाली

कार्य योजना के अंतर्गत यूएनएफसीसीसी के परिवर्धित कार्यान्वयन से संबंधित) तथा एडब्ल्यूजी-केपी (क्योतो प्रोटोकाल के अंतर्गत अनुबंध-1 पक्षों के लिए और प्रतिबद्धताओं पर तदर्थ कार्य समूह - क्योतो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता चरण के लिए अनुबंध-1 पक्षकारों की उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता से संबंधित) के जुड़वां मार्ग पर वार्ताओं को अंजाम तक पहुंचाने में सफल नहीं रहा। तथापि, कोप-15 ने नवंबर-दिसंबर, 2010 में मेक्सिको में आयोजित होने वाले 16वें पक्षकार सम्मेलन (कोप-16) में सम्मत परिणाम पर पहुंचने के लिए बाली सम्मेलन में आरंभ की गई इस जुड़वां मार्ग वार्ता प्रक्रिया को जारी रखने का अधिदेश देने का निर्णय लिया।

कोप-15 में एक सामानांतर घटना में, 'अध्यक्ष के मित्र' प्रक्रिया में, जहां भारत भी प्रतिभागी था, जिसका आयोजन 25-30 देशों के बीच डेनिश मेजबानों द्वारा किया गया, 'कोपेनहेगन समझौता' को अंतिम रूप दिया गया, जो कोई कानूनन बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए बिना उपशमन, अनुकूलन, वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर बाली कार्य योजना के विभिन्न घटकों से संबंधित है। तथापि, पक्षकार सम्मेलन ने कोपेनहेगन समझौते को अंगीकार नहीं किया, जैसा कि शुरू में उम्मीद की गई थी तथा कुछ देशों की सतत आपत्तियों के कारण इसे केवल नोट किया। इस प्रकार यह समझौता न तो कानूनन बाध्यकारी है और न ही यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत किसी नई वार्ता प्रक्रिया के लिए अधिदेश है।

कोपेनहेगन में कोप-15 से पूर्व यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत एडब्ल्यूजी-एलसीए तथा एडब्ल्यूजी-केपी में जलवायु परिवर्तन वार्ता में आधिकारिक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। इनमें बोन में एडब्ल्यूजी-एलसीए एवं एडब्ल्यूजी-केपी की बैठकें (29 मार्च-8 अप्रैल, 2009 और 10-14 अगस्त, 2009), बैंकाक (28 सितंबर-9 अक्तूबर, 2009) और बार्सीलोना (2-6 नवंबर, 2009) की बैठकें शामिल हैं।

भारत ने कोपेनहेगन परिणाम तथा यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत भावी वार्ताओं की दिशा का जायजा लेने के लिए 24 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में चार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन - जिसे बेसिक समूह के नाम से भी जाना जाता है) के मंत्रि स्तरीय विचार-विमर्श की मेजबानी की।

इसके अलावा, भारत ने जलवायु परिवर्तन तथा संबंधित मुद्दों पर बल देते हुए अनेक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रियता से भाग लिया। प्रधान मंत्री ने जी-8ऊ5 शिखर बैठक (आठ सर्वाधिक औद्योगिक देशों - अमरीका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और रूस का समूह तथा पांच प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं - भारत, चीन, ब्राजील, मेक्सिकों एवं दक्षिण अफ्रीका के समूह के साथ उनकी आउटरीच अंतःक्रिया) के दौरान अतरिक्त समय में 9 जुलाई, 2009 को ला-अकिला (इटली) में आयोजित ऊर्जा एवं जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच (एमईएफ) की शिखर बैठक में भाग लिया जिसमें विश्व की 17 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास एवं नियोजन तेज करने के लिए 26-27 अक्तूबर, 2009 को संघाई में आयोजित स्वच्छ विकास एवं जलवायु (एपीपी) पर एशिया प्रशांत साझेदारी - जो सात एशिया प्रशांत देशों (आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, कनाडा, जापान, कोरिया गणराज्य एवं संयुक्त राज्य) की एक स्वैच्छिक साझेदारी है - में आधिकारिक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

आप्रवासन

जून, 2008 में अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन संगठन (आईओएम) का सदस्य बनने के समय से ही भारत ने प्रव्रजन के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी बढ़ाना जारी रखा है। आईओएम प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर भारत में पहले से ही अनेक परियोजनाओं को संपन्न कर रहा है, जिनका उद्देश्य विदेश में भारतीय कामगारों की स्थिति में सुधार लाना है।

भारत ने 2010 से 2012 की अवधि के लिए आईओएम के विदेशी लेखापरीक्षक के पद के लिए भारी बहुमत से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजीआई) के चयन में परिणत सफल चुनाव प्रचार का संचालन किया।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत के स्थाई प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 4-5 नवंबर, 2009 को एथेंस में आयोजित प्रव्रजन एवं विकास पर वैश्विक मंच (जीएफएमडी) की तीसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत 2009 में जीएफएमडी के संचालन समूह का सदस्य बना तथा जिनेवा में मित्र मंच एवं संचालन समूह की तैयारी बैठकों में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ **एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी)**

अपर सचिव, विदेश मंत्रालय ने अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग के 18वें सत्र में भाग लेने के लिए चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसका आयोजन वियना में 16-24 अप्रैल, 2009 तक किया गया।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)

यूनेस्को के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत इसके सभी मुख्य अधिदेशों में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा वार्ताकार, सूत्रधार एवं सर्वसम्मति निर्माता के रूप में अपनी भूमिका में विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अक्सर सेतु का काम करता है।

भारत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यूनेस्को के श्रेणी-1 संस्थान के रूप में नई दिल्ली, भारत में शांति एवं स्थाई विकास के लिए महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए भारत के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अपनाया जाना था। यह संस्थान एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला तथा विकासशील देशों में तीसरा संस्थान है।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 18 दिसंबर, 2009 को कोपेनहेगन में आयोजित पंद्रहवें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 27 नवंबर, 2009 को पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित चोगम, 2009 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के साथ।

भारत को कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया, जिसका भारत 1947 से लगातार सदस्य रहा है। हमारी जीत विशेष रूप से विकासशील देशों से संबंधित मुद्दों पर यूनेस्कों में हमारे उच्च प्रोफाइल, प्रमुख मुद्दों पर उत्तर एवं दक्षिण के बीच सेतु के रूप में भारत की भूमिका तथा हमारी लोकतांत्रिक, बहुवादी, बहुसांस्कृतिक एवं धर्मनिरपेक्ष साख के कारण थी। भारत सरकार द्वारा डॉ. कर्ण सिंह को कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया।

हमारे निमंत्रण पर यूनेस्को के निवर्तमान महानिदेशक श्री कोचिरो मत्सुरा ने 10-11 नवंबर, 2009 को भारत की पांचवी राजकीय यात्रा की। यह एक विशेष इशारा था क्योंकि 15 नवंबर, 2009 को पद भार छोड़ने से पूर्व यह उनकी आखिरी राजकीय यात्रा थी। नई महानिदेशक सुश्री इरीना बोकोवा ने भी 11-14 जनवरी, 2010 तक महानिदेशक के रूप में भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा करने के लिए भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।

अंतर्संसदीय संघ (आईपीयू)

19 से 21 अक्तूबर, 2009 तक जिनेवा में आईपीयू की 121वीं सभा आयोजित की गई। लोकसभा की माननीय अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार की अध्यक्षता में सांसदों के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

एजेंडा की प्रमुख मदों में शामिल थेः (1) आपातकालीन मद पर बहस, (2) संयुक्त राष्ट्र सुधार की प्रगति पर ब्रीफिंग एवं बहस जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर अद्यतन एवं चर्चा, (3) गुमशुदा व्यक्तियों की पुस्तिका जारी करना, (4) संयुक्त राष्ट्र विकास सहयोग मंच पर चर्चा तथा विदेशी सहायता पर यूपीयू संकल्प का कार्यान्वयन, (5) एड्स/ एचआईवी पर पैनल चर्चा - रोकथाम, उपचार एवं देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच।

लोक सभा सांसद श्री पी.सी. चाको के नेतृत्व में एक सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 28-30 सितंबर, 2009 तक विश्व व्यापार संगठन पर संसदीय सम्मेलन के 19वें सत्र में भाग लेने के लिए जिनेवा का दौरा किया। एजेंडा के मुख्य विषयों में शामिल थे - (1) बहुपक्षीय व्यापार वार्ता की वर्तमान स्थिति तथा दोहा दौर की निष्पत्ति के लिए संभावित परिदृश्य, (2) डब्ल्यूटीओ सार्वजनिक मंच, 2009 से संबंधित विचारों का आदान-प्रदान। विषय का शीर्षक था 'वैश्विक समस्याएं, वैश्विक समाधानः बेहतर वैश्विक अभिशासन की ओर।'

डॉ. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (सांसद) तथा श्रीमती जयंती नटराजन (सांसद) से युक्त एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं की स्थिति पर संसदीय समितियों तथा लैंगिक समानता से संबंधित अन्य समितियों के सदस्यों के चौथे सम्मेलन में भाग लेने के लिए 28-29 सितंबर, 2009 को जिनेवा का दौरा किया।

संयुक्त राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास आयोग (सीएसटीडी)

संयुक्त राष्ट्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास आयोग (सीएसटीडी) का 12वां वार्षिक सत्र 25-29 मई, 2009 तक जिनेवा में आयोजित किया गया। सत्र में एक मंत्रिस्तरीय खंड शामिल था तथा दो प्राथमिकता विषयों, 'समावेशी सूचना समाज के लिए विकासोन्मुख नीतियां' तथा 'शिक्षा एवं अनुसंधान में नवाचार एवं क्षमता निर्माण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरी' को ध्यान में रखते हुए सूचना समाज पर विश्व शिखर बैठक (डब्ल्यूएसआईएस) के परिणामों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया तथा भारत ने वैश्विक डिजिटल अंतराल को कम करने तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अभिनव नीतियों को एकीकृत करने के लिए तरीकों की पहचान पर चर्चाओं में सक्रियता से भाग लिया।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)

सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्व जलवायु सम्मेलन - 3 (डब्ल्यूसीसी-3) में भाग लिया, जिसका आयोजन 31 अगस्त से 4 सितंबर, 2009 तक जिनेवा में किया गया। एजेंडा की प्रमुख मदों में शामिल थे - (1) जलवायु सूचना के आर्थिक एवं सामाजिक लाभ, (2) जलवायु भविष्यवाणी विज्ञान को आगे बढ़ाना, (3) जलवायु अनुकूलन एवं कोपेनहेगन प्रक्रिया पर गोलमेज चर्चा, (4) जलवायु चरम, चेतावनी प्रणालियां एवं आपदा जोखिम को कम करना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

भारत ने 18-22 मई, 2009 तक आयोजित 62वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। भारत को 2009 से तीन वर्ष की अवधि के लिए डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया। भारत ने डब्ल्यूएचओ मंच में जन स्वास्थ्य सरोकारों पर ध्यान देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान देने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने, आवश्यक दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबद्ध मुद्दों (ट्रिप्स) की सुनम्यताओं के पूर्ण प्रयोग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल देना जारी रखा।

भारत ने एन्फ्लुएंजा महामारी तैयारी रूपरेखा (पीआईपीएफ) को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्सरकारी प्रक्रिया में भाग लेना जारी रखा। ए/एच1एन1 महामारी (स्वाइन फ्लू) के संदर्भ में, इस रूपरेखा का महत्व और बढ़ गया है। भारत ने इस बात पर बल देना जारी रखा कि रूपरेखा में लाभ के आदान-प्रदान तथा एन्फ्लुएंजा महामारी से संबंधित सामग्री तक पहुंच पर साम्यपूर्ण ढंग से ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि संपूर्ण प्रभावित आबादी को टीकों एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो। हम अल्कोहल के हानिकर प्रभावों को कम करने पर एक वैश्विक रणनीति तैयार करने के लिए चल रहे विचार-विमर्श में शामिल हैं तथा जन स्वास्थ्य सरोकारों के प्रिज्म के माध्यम से रणनीति तैयार

करने का आह्वान किया है। भारत तंबाकू नियंत्रण पर रूपरेखा अभिसमय (एफसीटीसी) की छत्रछाया में तंबाकू उत्पादों में अबाध व्यापार पर प्रोटोकाल के लिए चल रही अंतर्सरकारी वार्ताओं में भी भाग ले रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

भारत ने 3-19 जून, 2009 तक आयोजित आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 98वें सत्र में भाग लिया, जिसने चल रहे आर्थिक संकट के श्रम परिणामों से निपटने के लिए रोजगार केंद्रित नीति उपकरण के रूप में वैश्विक जॉब संधि का पृष्ठांकन किया। श्रम मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खर्गे ने 15-16 जून, 2009 को आईएलसी के उच्च-स्तरीय खंड के विचार-विमर्श में भाग लिया तथा भारत में श्रम उन्मुख सामाजिक नीतियों के बारे में बताया। भारत ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों तथा आर्थिक गतिविधि के सामाजिक भागों पर दिए जा रहे बल का उल्लेख किया। इस संदर्भ में, समाज के अरक्षित वर्गों की रक्षा के लिए सामाजिक संरक्षण एवं रोजगार लाभों, जिन्हें भारत में शुरू किया गया है, का आईएलओ में स्वागत किया गया। एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा नेट के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), असंगठित क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एनएसडीपी), एक स्वैच्छिक सामाजिक सुरक्षा नेट के रूप में नई पेंशन योजना (एनपीएस) ने आईएलओ संघटकों के अंदर महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपायों के रूप में पहचान हासिल की है।

सूचना समाज पर विश्व शिखर बैठक का अनुवर्तन (डब्ल्यूएसआईएस)

15-18 नवंबर, 2009 तक शर्म-अल-शेख (मिस्र) में इंटरनेट अभिशासन मंच की चौथी वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया जिसका विषय 'इंटरनेट अभिशासन - सबके लिए अवसर सृजित करना' था। इसमें पहुंच एवं विविधता, सुरक्षा, खुलापन एवं निजता, इंटरनेट अभिशासन तथा इंटरनेट संसाधनों का प्रबंधन जैसे मुद्दों की छानबीन की गई। बैठक में आर्थिक विकास एवं सामाजिक तरक्की को समर्थ बनाने वाले के रूप में इटरनेट की पहचान की गई, तथा डिजिटल अंतराल को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ)

आईएसओ तकनीकी प्रबंधन बोर्ड (टीएमबी) की 45वीं बैठक 9-11 जून, 2009 तक जिनेवा में आयोजित की गई। अपर महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बैठक में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ (आईटीयू)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ए. राजा ने 'आईटीयू दूरसंचार विश्व 2009' में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसका आयोजन जिनेवा में 5-9 अक्तूबर, 2009 तक किया गया।

सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अगले वर्ष हैदराबाद में आईटीयू सम्मेलन की मेजबानी से संबंधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के कार्य को अंतिम रूप देने के लिए जिनेवा का दौरा किया। इस समझौता ज्ञापन पर सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा आईटीयू के उपाध्यक्ष द्वारा 20 अक्तूबर, 2009 को हस्ताक्षर किए गए।

विधि एवं संधि प्रभाग

वर्ष 2009 के दौरान विधि एवं संधि प्रभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां नीचे दी गई हैः

निवेश करार

चालू वर्ष के दौरान, कोलंबिया के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बीआईपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा लीबिया, म्यांमार, मोजाम्बिक और बांग्लादेश के साथ बीआईपीए में संशोधन किए गए हैं। जॉर्डन और सर्बिया के साथ बीआईपीए के संबंध में संशोधन के लिखतों का दिल्ली में आदान-प्रदान हुआ है, ताकि करार प्रभावी हो सकें। कनाडा के साथ वार्ता पूरी हो गई है तथा हस्ताक्षर के लिए अंतिम पाठ तैयार है। संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अन्वेषणात्मक बातचीत पूरी हो गई है तथा ईरान, युगांडा, ट्यूनीशिया, नामीबिया, नेपाल, एस्तोनिया और स्लोवानिया के साथ वार्ता चल रही है।

मंत्रिमंडल हेतु टिप्पणियां

वर्ष के दौरान, कोलंबिया, लिथुआनिया एवं सिसली के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करार (बीआईपीए) के संबंध में प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पणियां परिचालित एवं अनुमोदित किए गए हैं। इसी तरह, भूटान के साथ वायु सेवा करार और बोस्निया एवं हर्जेगोविना के साथ वायु सेवा करार के संबंध में प्रारूप मंत्रिमंडल टिप्पणियां की जांच की गई है तथा मंत्रालय की सहमति से अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रभाग ने इक्वाडोर, स्वीडन, वियतनाम एवं यूके के साथ रक्षा सहयोग पर मंत्रिमंडल टिप्पणी तथा बहुमूल्य धातुओं की वस्तुओं के नियंत्रण एवं विपणन पर अभिसमय से सहमति के लिए प्रस्ताव के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, स्विट्जरलैंड के बीच एमओयू, भारत और स्विट्जरलैंड, डेनमार्क एवं लक्जमबर्ग के बीच सामाजिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल टिप्पणी की भी जांच की है तथा स्वीकृति प्रदान की है। प्रभाग ने डेनमार्क, नार्वे, फिनलैंड एवं आस्ट्रिया के साथ जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं से संबंधित मंत्रिमंडल टिप्पणियों की भी जांच की है।

वर्ष के दौरान, विधि एवं संधि प्रभाग ने भारत में एवं विदेशों में विभिन्न परियोजनाओं पर अनेक करार एवं निविदा दस्तावेजों की जांच की है; सेवा मामलों, विभिन्न पासपोर्ट एवं कोंसुलर मुद्दों वाले विभिन्न न्यायिक मामलों में अपनी राय दी है; और विदेश मंत्रालय को संबोधित अनेक आरटीआई अनुरोधों पर निविष्टयां दी है तथा कानूनी राय की पेशकश की है। प्रभाग ने हेग अंतर्राष्ट्रीय विधि अकादमी, स्थाई मध्यस्थता न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय निजी कानून एकीकरण संस्थान (यूएनआईडीआर ओआईटी), हेग निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मेलन (एचसीसीएच) तथा एशिया अफ्रीका विधि परामर्श संगठन (आल्को) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत के वार्षिक अंशदान के भुगतान को प्रॉसेस किया है।

सामाजिक सुरक्षा करार

इस प्रभाग ने जर्मनी, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, नार्वे, कनाडा, डेनमार्क, कोरिया, लक्जमबर्ग एवं हंगरी जैसे विभिन्न देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों की वार्ताओं में सक्रियता से भाग लिया है।

सार्क

इस प्रभाग ने भारत सरकार और सार्क वस्त्र एवं दस्तकारी संग्रहालय के बीच प्रारूप मुख्यालय करार का प्रस्ताव रखा है। मुख्यालय करार के अनुसरण में, संग्रहालय दिल्ली में क्रियाशील होगा तथा करार की कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर कतिपय सुविधाएं एवं प्रतिरक्षण भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, अक्तूबर, 2009 में काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालयों की तीसरी अंतर्सरकारी बैठक के दौरान, शैक्षिक योजना, व्यवसाय योजना एवं वित्तीय परिव्यय से संबंधित तौर-तरीकों पर चर्चा हुई है।

इस प्रभाग ने दक्षिण एशिया में महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार तथा बाल कल्याण संवर्धन से संबंधित सार्क अभिसमय को लागू करने के लिए क्षेत्रीय कार्यबल की तीसरी बैठक में भी भाग लिया।

प्रत्यर्पण तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहायता

विधि एवं संधि प्रभाग ने विदेशी राष्ट्रों के साथ आपराधिक एवं सिविल मामालों में परस्पर कानूनी सहायता पर प्रत्यर्पण संधि, करार संपन्न करने के लिए द्विपक्षीय वार्ताओं में भाग लिया है। मेक्सिको, तजाकिस्तान और पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर सफल वार्ता के बाद वर्ष 2009 में उनको लागू करने एवं प्रभावकारिता की कार्यविधि पूरी की गई। मोरक्को एवं इजराइल के साथ प्रत्यर्पण संधि पर वार्ता की गई है तथा अंतिम रूप दिया गया। सऊदी अरब एवं अजरबेजान के साथ प्रत्यर्पण संधि पर वार्ता शुरू की गई। इसके अलावा, विधि एवं संधि प्रभाग ने कोलंबिया एवं सर्बिया द्वारा प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधियों के प्रारूप पाठों की जांच की है।

विधि एवं संधि प्रभाग ने बांग्लादेश, इजराइल एवं अजरबेजान के साथ आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता से संबंधित संधियों पर वार्ता में भाग लिया है। फलस्वरूप, बांग्लादेश एवं अजरबेजान के साथ संधियों को अंतिम रूप दिया गया। इस प्रभाग ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण करार पर सऊदी अरब, इजराइल एवं ईरान के साथ वार्ताओं में भाग लिया है तथा इन सभी संधियों के पाठों को अंतिम रूप दिया गया।

विधि एवं संधि प्रभाग ने घरेलू एवं विदेशी क्षेत्राधिकारों से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रत्यर्पण अनुरोधों एवं अन्य अनुरोधों की जांच की है तथा उन पर कानूनी सलाह प्रदान की है।

पर्यावरणीय कानून

पिछले वर्ष के दौरान, विधि एवं संधि प्रभाग ने पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित अनेक करारों, वन्य जीव अनुसंधान संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों, समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा स्वच्छ विकास तंत्र की जांच की।

प्रभाग ने जैव सुरक्षा, आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित वार्ताओं में भाग लिया। जैव सुरक्षा के संबंध में, फरवरी, 2009 में जैव सुरक्षा पर कार्टेजीना प्रोतोकॉल (अनुच्छेद 27) के संदर्भ में दायित्व एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित 'अध्यक्षों के मित्र समूह' की पहली बैठक में प्रभाग का प्रतिनिधित्व किया गया। इस बैठक द्वारा तीन दस्तावेज अपनाए गए सीमापारीय संदर्भ में उत्पन्न जीवित परिष्कृत जीवों के परिवहन, संक्रमण, निपटान एवं प्रयोग से जैविक विविधता के संरक्षण एवं प्रयोग को क्षति से उत्पन्न देयता पर कानूनन बाध्यकारी 'प्रशासनिक दृष्टिकोण'; सिविल देयता पर कानूनन गैर बाध्यकारी सिद्धांत (हालांकि विकासशील देशों की ओर से भारी दबाव के कारण कुछ मुख्य घटकों को प्रशासनिक दृष्टिकोण में अंतःस्थापित किया गया); और पूरक वित्तपोषण तंत्र। फरवरी, 2010 में होने वाली दूसरी बैठक में इन लिखतों पर और चर्चा होनी है। जहां तक आनुवंशिक एवं जैविक संसाधनों से संबंधित पहुंच एवं लाभों की हिस्सेदारी का संबंध है, निम्नलिखित में प्रभाग का प्रतिनिधित्व किया गयाः जनवरी, 2009 में पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी (एबीएस) पर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार करने के लिए जैविक विविधता अभिसमय (सीबीडी) पर कोप-9 द्वारा स्थापित तकनीकी एवं कानूनी विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक; अप्रैल, 2009 में आयोजित पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी (एबीएस) पर तदर्थ खुले कार्यबल की सातवीं बैठक और 15 नवंबर, 2009 को आयोजित पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी (एबीएस) पर तदर्थ खुले कार्य समूह की आठवीं बैठक। इन बैठकों ने मांट्रियल अनुबंध उत्पन्न किया है जिसमें आनुवंशिक एवं जैविक संसाधनों की पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी पर बुनियादी वार्ता पाठ निहित है। इस अनुबंध में आनुवंशिक एवं जैविक संसाधनों की पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी पर मुख्य घटक निहित हैं।

नवंबर 2009 में बार्सीलोना में दो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में तथा दिसंबर, 2009 में कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के कोप-15 में भी प्रभाग का प्रतिनिधित्व किया गया। ये दो बैठकें तथा 2009 में पहले आयोजित बैठकें 'कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन समझौता' निष्पादित करने में सहायक थीं।

तंबाकू प्रोतोकॉल

तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार संबंधी प्रोटोकॉल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्ता बैठकों में प्रभाग का प्रतिनिधित्व किया गया। जिन बैठकों में भाग लिया गया, वे इस प्रकार हैः जून 2009 में आयोजित तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार संबंधी प्रोटोकॉल पर अंतर्सरकारी वार्ता निकाय (आईएनबी-2) का तीसरा सत्र; जिनेवा में अक्तूबर, 2009 में आयोजित तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार पर अंतर्सरकारी वार्ता निकाय (आईएनबी) के प्रारूपण समूह-2 की पहली बैठक; और नवंबर, 2009 में आयोजित तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार पर अंतर्सरकारी वार्ता निकाय (आईएनबी) के प्रारूपण समूह-2 की दूसरी बैठक। इस समय यह प्रोटोकॉल जिस रूप में है उस रूप में इसमें अंतिम रूप दिए गए अधिकांश घटकों के साथ एक वार्ता पाठ निहित है जिसमें तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार के लिए संपूर्ण कानूनी निदान/ प्रतिबंध एवं आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रण शामिल है।

जल संसाधन

प्रभाग ने मई-जून, 2009 में नई दिल्ली में आयोजित स्थाई सिंधु आयोग की बैठक में भाग लिया। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र जल विपथन के संबंध में अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने, हिस्सा लेने एवं निविष्टियां प्रदान करने में भी प्रभाग शामिल था। हमने गंगा नदी संधि तथा मणिपुर में तिपाईमुख बांध पर उठाए गए सरोकारों पर भी निविष्टियां/ टिप्पणियां प्रदान की। प्रभाग ने किशनगंगा जल विद्युत परियोजना के निर्माण पर पाकिस्तान द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों पर भी असंख्य टिप्पणियां प्रदान की।

अंटार्कटिका

बाल्टीमोर, यूएसए में अप्रैल, 2009 में आयोजित 32वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री समिति बैठक (एटीसीएम) के कानूनी एवं संस्थानिक समूह की बैठक में प्रभाग का प्रतिनिधित्व किया गया।

संयुक्त राष्ट्र तथा अंतराष्ट्रीय कानून

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन के लिए उपायः आतंकवाद पर तदर्थ समिति, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (सीसीआईटी) पर वार्ता कर रही है, की इस वर्ष की बैठक में कोई प्रगति नहीं हो सकी। यद्यपि, सूत्रधार द्वारा प्रस्तावित नए पाठ के लिए काफी समर्थन है, जिसमें इस अभिसमय एवं आईएचएल के बीच दण्डाभाव एवं रेखांकन के मुद्दे का समाधान ढूंढ़ने का प्रयास है, कुछ प्रतिनिधियों ने पाया कि नए घटक उनके सरोकारों को पूरी तरह प्रतबिंबित नहीं कर रहे हैं। चर्चा को सुकर बनाने के लिए इस सत्र में अध्यक्ष ने विभिन्न प्रस्तावों को एकल पाठ में समेकित किया जो कई वर्षों से परिचालन में रहे हैं।

आतंकवाद रोधी रणनीतिः भारत ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति का समर्थन करना जारी रखा तथा पिछले वर्ष इसकी द्विवार्षिक समीक्षा में सक्रियता से भाग लिया। भारत आतंकवाद रोधी कार्यान्वयन कार्यबल के संस्थानीकरण का स्वागत करता है जो 'एक के रूप में प्रदान करने' की संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करेगा तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के आतंकवाद रोधी प्रयासों में समग्र समन्वय एवं संगति का सुनिश्चय करेगा।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर तथा संगठन की भूमिका के सुदृढ़ीकरण पर विशेष शिखर सम्मेलनः अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता बढ़ाने के विचार से सदस्य देशों द्वारा लाए गए विशिष्ट प्रस्तावों तथा संयुक्त राष्ट्र के और प्रभावी कामकाज के लिए अन्य सुझावों पर विशेष समिति विचार करती है, जिनके लिए चार्टर में संशोधन करने की जरूरत नहीं हो सकती। 2009 में भी बैठक के दौरान मुख्य ध्यानाकर्षण 'संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की शुरुआत एवं कार्यान्वयन के लिए बुनियादी शर्तें एवं मानक' पर रूसी संघ कार्यकारी दस्तावेज पर बना रहा। रियो समूह ने 'संयुक्त राष्ट्र सुधार के कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श' नामक प्रस्तावित एजेंडा मद को वापस ले लिया। क्यूबा ने 1997 के सत्र में प्रस्तुत 'संगठन की भूमिका का सुदृढ़ीकरण तथा इसकी कारगरता बढ़ाना' नामक प्रस्ताव पर संशोधित कार्यकारी कागजात प्रस्तुत किए।

संयुक्त राष्ट्र में न्यायकरणः छठवीं समिति ने संयुक्त राष्ट्र के स्टाफ के लिए एक नई आंतरिक न्याय प्रणाली 'संयुक्त राष्ट्र में न्यायकरण' प्रकरण के कानूनी पहलुओं की जांच का कार्य जारी रखा तथा संयुक्त राष्ट्र विवाद अधिकरण तथा संयुक्त राष्ट्र अपील अधिकरण की प्रारूप संविधियों को अंतिम रूप दिया। महासभा ने मार्च 2009 में संयुक्त राष्ट्र विवाद अधिकरण में काम करने के लिए पांच तथा संयुक्त राष्ट्र अपील अधिकरण में काम करने के लिए सात जज नियुक्त किए। 2007 में सृजित ये निकाय आंतरिक शिकायतों एवं अनुशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने में विश्व निकाय प्रणाली की सहायता करते हैं। 1 जुलाई, 2009 की स्थिति के अनुसार, कार्य संबद्ध विवादों को निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में दो चरणीय न्यायिक प्रणाली है। तथापि, अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए, नई प्रणाली सुदृढ़ीकृत लोकपाल एवं मध्यस्थता सेवाओं के साथ विवादों के अनौपचारिक समाधान को भी बढ़ावा देगी।

महासागर और समुद्र का कानून

फिश स्टॉक करारः स्ट्रैडलिंग फिश स्टॉक तथा अत्यंत प्रवासी फिश स्टॉक के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित समुद्र के कानून

पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनएफएसए) के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए करार के पक्षकार देशों के अनौपचारिक परामर्श के आठवें दौर का आयोजन 16-19 मार्च, 2009 तक किया गया। इस वर्ष की बैठक का सारवान विषय 'सतत वार्तालाप' था, जो करार में व्यापक सहभागिता बढ़ाने पर केंद्रित था। सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने 2010 में बहाल होने वाले समीक्षा सम्मेलन में की जाने वाली समीक्षा के दायरे पर भी चर्चा की।

महासागरों एवं समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र खुली अनौपचारिक परामर्श प्रक्रियाः महासागरों एवं समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र खुली अनौपचारिक परामर्श प्रक्रिया की 10वीं बैठक का विषय था 'पहली नौ बैठकों में इसकी उपलब्धियों एवं कमियों की समीक्षा समेत परामर्श इस प्रक्रिया के परिणामों का कार्यान्वयन'।

प्रतिनिधियों ने 1999 में अस्तित्व में आने के समय से लेकर अब तक के आईसीपी के परिणामों के कार्यान्वयन पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके अलावा, उन्होंने इसकी उपलब्धियों एवं कमियों, अंतर-एजेंसी सहयोग एवं समन्वय की समीक्षा की तथा ऐसे मुद्दों की पहचान की जिन्हें महासागर एवं समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के भावी कार्य से लाभ प्राप्त हो सकता है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आईसीपी को समुद्र के कानून के संदर्भ में स्थायी विकास के मुद्दों से जुड़े विषयों पर चर्चा करनी चाहिए।

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के सरकारी पक्षकारों की बैठक

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के सरकारी पक्षकारों की 19वीं बैठक 13-20 जून, 2008 तक आयोजित की गई। तीन निकायों - समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण तथा महाद्वीपीय शेल्फ सीमा आयोग - के अध्यक्षों द्वारा व्यापक ब्यौरा पेश किया गया एवं अधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा एवं बजटीय मामलों पर रिपोर्टें प्रदान की गईं।

महाद्वीपीय शेल्फ सीमा आयोग के अध्यक्ष ने आयोग के बढ़े हुए कार्यभार को संभालने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों का उल्लेख किया तथा कहा कि इसे संयुक्त एवं आंशिक निवेदन समेत 51 निवेदन तथा प्रारंभिक सूचना के 43 सेट प्राप्त हुए हैं। निवेदनों की विशाल संख्या को देखते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि सदस्यों की वर्तमान संख्या एवं बैठकों की अनुसूची में आयोग 2030 तक ही वर्तमान सूची को पूरा करने में समर्थ हो पाएगा। (भारत का दावा 2027 में विचार के लिए आएगा)। इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि न्यूयार्क में और अधिक समय तक आयोग के सदस्यों का उपलब्ध होना आवश्यक है।

जहां तक समुद्र के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण तथा महाद्वीपीय शेल्फ सीमा आयोग में सीटों के आवंटन के मुद्दे का संबंध है, पश्चिम यूरोपीय तथा अन्य समूहों (डब्ल्यूईओजी) ने दोनों निकायों में से प्रत्येक में अपनी एक सीट छोड़ दी, जो अब फ्लोटिंग सीट होगी तथा एशिया, अफ्रीका एवं डब्ल्यूईओजी से उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, एशियाई - अफ्रीकी राष्ट्रों के बीच दोनों में से प्रत्येक निकाय के लिए एकांतरिक रूप में एशियाई - अफ्रीकी उम्मीदवार को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे का समर्थन करने के लिए आपसी सहमति हुई कि डब्ल्यूईओजी उम्मीदवार के चुने जाने की कोई संभावना न रहे।

विधि एवं संधि प्रभाग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के एजेंडा में समुद्र के कानून से संबंधित मुद्दों की जांच करता है। अपने 64वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने एजेंडा मदों 'महासागर एवं समुद्र का कानून' तथा 'स्ट्रैडलिंग फिश स्टॉक एवं अत्यंत प्रव्रजक फिश स्टॉक और संबंधित उपकरणों के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित 10 दिसंबर, 1982 के समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय तथा संबद्ध लिखतों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 1995 के करार के माध्यम से पोषण क्षम मत्स्यिकी' पर दो संकल्प 64/71 तथा 64/72 अपनाए गए हैं। यह प्रभाग ऐसे मुद्दों पर सलाह देने में सक्रियता से शामिल था, जो संकल्पों को अंतिम रूप देने के दौरान उठे थे।

विधि एवं संधि प्रभाग ने न्यूयार्क में 20-24 अप्रैल, 2009 तक आयोजित समुद्र विज्ञान अनुसंधान से संबंधित समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रारूप दिग्दिर्शका की समीक्षा करने एवं अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।

सोमालिया तट पर समुद्री डकैती रोकने पर संपर्क समूह

विधि एवं संधि प्रभाग ने सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती रोकने संबंधी संपर्क समूह के कानूनी मुद्दों पर कार्य समूह-2 में सक्रियता से भाग लिया है। इस कार्य समूह ने सौंपे गए कार्यों को संपन्न किया है, जैसे कि सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती से उत्पन्न कानूनी चुनौतियों पर सूचना का निरंतर आदान-प्रदान, संदिग्ध समुद्री डकैतों के अभियोजन के लिए अतिरिक्त तंत्र स्थापित करने की संभावना की जांच, कानूनी विशेषज्ञों से युक्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनी नेटवर्क की स्थापना, ऐसे कदमों की सूची से युक्त 'कानूनी उपकरण बॉक्स' का विकास, जिन्हें सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उठा सकते हैं कि वे संदिग्ध समुद्री डकैतों को दण्डित करने में समर्थ हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यास निधि के लिए अड़चनों की सूची तथा विचारार्थ विषय आदि। यह कार्य समूह अभियोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आधार के संकलन तथा साक्ष्य मानक 'शिप राइडर' करारों पर जेनरिक टेम्पलेट तैयार करने तथा संदिग्ध समुद्री लुटेरों एवं सशस्त्र डकैतों के हस्तांतरण की शर्तों पर समझौता ज्ञापन तैयार करने में भी शामिल था।

यूएनसीआईटीआरएएलः इस प्रभाग ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग के 42वें सत्र की बैठक में तथा यूएनसीआईटीआरएएल कार्य समूह 5 एवं 6, जो क्रमशः दिवालिया कानून एवं प्रतिभूति ब्याज से संबंधित कामकाज देखते हैं, की बैठकों में भी भाग लिया है। इस वर्ष आयोग ने सीमापारीय दीवालिया कार्यवाहियों में सहयोग, संचार एवं समन्वय पर यूएनसीआईटीआरएएल टिप्पणियों को अंगीकार किया है। सार्वजनिक प्रापण पर प्रारूप यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून तथा सुरक्षित लेनदेन पर यूएनसीआईटीआरएएल विधायी दिग्दर्शिका का अनुबंध अपने-अपने कार्य समूहों में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं तथा 2010 में अंगीकरण के लिए तैयार हो जाएंगे। यद्यपि, यूएनसीआईटीआरएएल की भारतीय सदस्यता 20 जून, 2010 को समाप्त हो जाएगी, भारत को 3 नवंबर, 2009 को आयोजित महासभा के चुनाव में 21 जून, 2010 से आरंभ होने वाली 6 वर्ष की अवधि के लिए यूएनसीआईटीआरएएल का सदस्य फिर से चुन लिया गया है।

यूनेस्को

इस प्रभाग ने उत्पत्ति के अपने देश में सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को की अंतर्सरकारी समिति के 15वें सत्र में भाग लिया है तथा पेरिस में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 35वें सत्र के दौरान आयोजित विधि समिति की बैठक में भी भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)

इस प्रभाग ने हेग अभिसमय, 1970 तथा मांट्रियल अभिसमय, 1971 में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने एवं अंतिम रूप देने के लिए मांट्रियल में 9-17 सितंबर, 2009 तक आयोजित आईसीएओ की विधि समिति की बैठक के 34वें सत्र में सक्रियता से भाग लिया है। ये संशोधन वस्तुतः आतंकवाद रोधी एवं प्रसार रोधी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे विभिन्न कार्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिन्हें सरकारों को अपने घरेलू कानूनों के अंतर्गत दण्डनीय बनाना होगा। इसमें शामिल हैंः सिविल एयरक्राफ्ट का हथियार के रूप में प्रयोग; जैविक, रासायनिक एवं परमाणु पदार्थों को गैर-कानूनी ढंग से फैलाने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट का प्रयोग; जैविक, रासायनिक एवं परमाणु पदार्थों का प्रयोग करते हुए नागरिक उड्डयन के विरुद्ध हमला; इनमें से किसी कार्य को अंजाम देने की धमकी; और ऐसे कृत्यों में योगदान देने वाले कार्य जिनमें उकसाना, भाग लेना, आयोजित करना, अंजाम देना आदि शामिल हैं, अभिसमय के अंतर्गत निषिद्ध अपराध के रूप में दण्डनीय होंगे।

2009 में अप्रैल-मई, 2009 के दौरान मांट्रियल में एक राजनयिक सम्मेलन बुलाया गया तथा प्रत्येक अभिसमय पर अंतिम प्रारूप को अनुमोदित करने के विचार से सम्मेलन ने गैर-कानूनी दखल (गैर-कानूनी दखल अभिसमय) के मामले में तीसरे पक्षों को एयरक्राफ्ट द्वारा उत्पन्न क्षति के लिए क्षतिपूर्ति पर प्रारूप अभिसमय तथा तृतीय पक्षों को एयरक्राफ्ट द्वारा उत्पन्न क्षति के लिए क्षतिपूर्ति पर प्रारूप अभिसमय (सामान्य जोखिम अभिसमय) को अपनाया। 33वें सत्र के दौरान अंतिम रूप दिए गए पाठों को 2010 में मांट्रियल में आयोजित होने वाले राजनयिक सम्मेलन में अपनाया जाएगा।

विधि एवं संधि प्रभाग ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अंगीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाले विभिन्न बहुपक्षीय सम्मेलनों में सक्रियता से भाग लिया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः गैर- कानूनी दखल (गैर-कानूनी दखल अभिसमय) के मामले में तीसरे पक्षों को एयरक्राफ्ट द्वारा उत्पन्न क्षति के लिए क्षतिपूर्ति पर अंतराष्ट्रीय अभिसमय; तृतीय पक्षों को एयरक्राफ्ट द्वारा उत्पन्न क्षति के लिए क्षतिपूर्ति पर अंतराष्ट्रीय अभिसमय (सामान्य जोखिम अभिसमय); जलयानों की सुरक्षित एवं पर्यावरणीय दृष्टि से स्वस्थ रिसाइकलिंग के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 2009 जिसे मई, 2009 में अपनाया गया।

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन

निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन ने हेग में 2-12 फरवरी, 2009 तक हेग अपोस्टल, सेवा, साक्ष्य एवं न्याय अभिसमयों तक पहुंच के व्यावहारिक प्रचालन पर विशेष आयोग की बैठक का आयोजन किया। विधि एवं संधि प्रभाग ने विशेष आयोग की बैठक में सक्रियता से भाग लिया।

भारत हेग सम्मेलन का सदस्य है तथा बैठक में जांच किए गए चार अभिसमयों में से तीन का पक्षकार है (न्याय अभिसमय तक पहुंच को छोड़कर)। अभिसमयों के प्रावधानों की जांच के अलावा, बैठक में इन अभिसमयों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं एवं कार्यविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में हुई वार्ताओं से विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के बारे में हमारी समझ बढ़ी और सरकारी पक्षकारों में इन अभिसमयों के प्रभावी कार्यान्वयन में इनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी मिली। विधि और संधि प्रभाग ने विशेष आयोग की बैठक में सक्रिय भागीदारी की।

प्रभाग द्वारा अनेक प्रतिरक्षा सहयोग करारों, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी करारों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी करारों की वर्ष के दौरान जांच की गयी। प्रभाग ने मादक औषधियों के निमंत्रण और मादक द्रवों की अवैध तस्करी की रोकथाम और साइक्रोट्रोपिक वस्तुओं तथा प्रिकर्सर रसायनों तथा संबंधित मामलों, आर्थिक, वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और दवाइयां, परंपरागत दवाइयां, पर्यटन, सिविल सेवा के क्षेत्र में सहयोग, कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन, विभिन्न देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए सहायता तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करारों/समझौता ज्ञापनों की विधीक्षा की गयी।

भारत ने वर्ष के दौरान कई देशों के साथ बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संधियों/करारों पर हस्ताक्षर/उनका अनुसमर्थन किया। विस्तृत सूची परिशिष्ट-X पर संलग्न है। वर्ष 2009 के दौरान जारी पूर्ण शक्तियों के लिखतों की सूची परिशिष्ट-XI पर और अनुसमर्थन के लिखतों की सूची परिशिष्ट-XII पर संलग्न है।

■■

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामले 10

प्रस्तावना

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के रूप में वैश्विक, निष्पक्ष एवं सत्यापनीय परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपने चिरकालिक और सतत समर्थन की पुष्टि करना जारी रखा। भारत को कुछ सकारात्मक संकेतों से प्रोत्साहन भी मिला। इससे इस बात का संकेत प्राप्त हुआ कि परमाणु निरस्त्रीकरण को पुनः अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है। इसमें अप्रैल, 2009 में प्राग में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का संबोधन तथा परमाणु हथियारों के भंडारों में और कमी लाने हेतु स्टार्ट-I के उत्तरवर्ती करार पर बातचीत करने के लिए अरमीका और रूस के बीच वार्ताएं शामिल हैं। भारत ने लगभग एक दशक के अवरोध के उपरान्त निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी) में विखंडनीय पदार्थ नियंत्रण संधि (एफएमसीटी) सहित अन्य संधियों पर कार्य योजना पारित किए जाने का समर्थन किया।

न्यूयार्क में आयोजित 64वें संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में भारत ने परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन, भण्डारण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इनका पूर्ण उन्मूलन किए जाने हेतु परमाणु शस्त्रों पर एक अभिसमय के अपने प्रस्ताव को दोहराया। यह प्रस्ताव वर्ष 1988 की राजीव गांधी कार्य योजना में अभिव्यक्त परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की चिरकालिक वचनबद्धता के अनुरूप है। भारत ने वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत एक कार्यकारी दस्तावेज सहित अन्य तरीकों से परमाणु निरस्त्रीकरण से संबद्ध अन्य प्रस्तावों का समर्थन किया, जिनमें निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार पर नई वैश्विक सहमति का निर्माण करने के लिए कतिपय तत्वों का समावेश किया गया है।

इस वर्ष के दौरान भारत ने निरस्त्रीकरण से संबद्ध विभिन्न बहुपक्षीय बैठकों में सकारात्मक भागीदारी की, जिनमें अन्य के साथ-साथ जैव हथियार अभिसमय (बीडब्ल्यूसी), रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी) तथा कतिपय पारम्परिक हथियारों से संबद्ध अभिसमय शामिल हैं। भारत ने आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों एवं एशियाई कार्यकलाप तथा विश्वासोत्पादक उपायों से संबद्ध अभिसमय में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। विभिन्न मुद्दों पर भारत के विचारों का प्रचार-प्रसार करने के लिए निरस्त्रीकरण क्षेत्र में विविध गैर-सरकारी संगठनों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखे गए। भारत ने उद्योग जगत एवं अन्य भागीदारों के सहयोग तथा यथोचित समन्वित प्रयासों से आउटरीच गतिविधियों सहित अन्य सभी कार्यकलापों के जरिए दोहरे उपयोग की मदों पर निर्यात नियंत्रण विनिमयों को कायम रखा एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन की प्रक्रिया भी जारी रखी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए)

महासभा की पहली समिति की बैठक के दौरान भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई और अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति कदम-दर-कदम प्रक्रिया के जरिए परमाणु शस्त्रों का पूर्ण उन्मूलन करने की संरचनात्मक वचनबद्धता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। भारत ने आगे के मार्गों के संबंध में बहस और सर्वसम्मति को बढ़ावा देने हेतु कुछ व्यावहारिक उपायों का भी सुझाव दिया। इन उपायों को पहले ही महासभा और निरस्त्रीकरण सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- नाभिकीय शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य के प्रति सभी नाभिकीय शस्त्र संपन्न देशों की वचनबद्धता की पुष्टि;
- सुरक्षा सिद्धांतों में नाभिकीय शस्त्रों की प्रमुखता में कमी;
- नाभिकीय हथियार की वैश्विक पहुंच और खतरे को ध्यान में रखते हुए अचानक होने वाले नाभिकीय युद्ध सहित नाभिकीय खतरों में कमी लाने के लिए नाभिकीय शस्त्र संपन्न राज्यों द्वारा कदमों का स्वीकरण, अनिच्छा से और अचानक होने वाले नाभिकीय हथियारों के उपयोग को रोकने के लिए नाभिकीय शस्त्रों को चौकसी की स्थिति से हटाना;
- नाभिकीय शस्त्रों के ''प्रथम उपयोग नहीं'' पर नाभिकीय शस्त्र संपन्न देशों के बीच वैश्विक सहमति पर बातचीत;
- नाभिकीय शस्त्र विहीन देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किए जाने के संबंध में परमाणु शस्त्र संपन्न देशों के बीच वैश्विक करार पर वार्ता;
- नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी पर पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित अभिसमय पर वार्ता;
- नाभिकीय शस्त्र अभिसमय पर वार्ता जिसके तहत नाभिकीय शस्त्रों के विकास, उत्पादन, भण्डारण और प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके, और निर्धारित समय-सीमा के भीतर नाभिकीय हथियारों का वैश्विक, भेदभाव रहित और सत्यापनीय उन्मूलन किया जा सके।

पिछले वर्षों की भांति ही भारत ने प्रथम समिति में तीन संकल्प प्रस्तुत किए, यथा 'आतंकवादियों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियार प्राप्त किए जाने पर रोक लगाने से संबंधित उपाय, 'परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध से संबद्ध अभिसमय' तथा परमाणु खतरे में कमी लाना'। 'आतंकवादियों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) प्राप्त किए जाने पर रोक लगाने से संबद्ध उपाय' से संबंधित भारत के प्रस्ताव, जिसे सर्वप्रथम वर्ष 2002 में लाया गया था, को पुनः सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, जिससे इस खतरे से निपटने की आवश्यकता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विद्यमान सर्वसम्मति का पता चलता है। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों से ऐसा उपाय करने का आह्वान किया गया जिनसे आतंकवादियों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों को प्राप्त करने से रोका जाए तथा इस बात पर बल दिया गया कि इस खतरे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रिया समावेशी, बहुपक्षीय एवं वैश्विक होनी चाहिए। इस वर्ष प्रस्ताव का सह प्रायोजन 71 देशों द्वारा किया गया। इससे इस बात का पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकल्प को कितना महत्वपूर्ण मानता है।

'परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध से संबद्ध अभिसय' से संबंध संकल्प में निरस्त्रीकरण सम्मेलन से ऐसी सर्वसम्मति पर पहुंचने हेतु वार्ता का शुभारंभ करने का आह्वान किया गया, जिसके फलस्वरूप किसी भी परिस्थिति में परमाणु शस्त्रों के उपयोग अथवा उपयोग की धमकी पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संपन्न किया जा सके। परमाणु खतरे में कमी से संबंधित भारत के संकल्प में परमाणु हथियारों के औचक प्रयोग के जोखिम में कमी लाने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा इन हथियारों को चौकसी की स्थिति से हटाने के महत्व पर बल दिया गया है। इस संकल्प में परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा करने तथा परमाणु हथियारों के औचक प्रयोग के जोखिम में कमी लाने संबंधी तात्कालिक उपाय करने का आह्वान किया गया है। उनमें परमाणु हथियारों को चौकसी की स्थिति तथा लक्ष्य से हटाने और परमाणु शस्त्र संपन्न देशों से सुझाए गए कदमों को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है। इन तीनों संकल्पों को राष्ट्रों के विशाल बहुमत से पारित किया गया। प्रथम समिति एवं आमसभा ने भी 'अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर भारत द्वारा प्रस्तावित निर्णय के प्रारूप को बिना मतदान के पारित कर दिया।

निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी)

निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सीडी) एक मात्र बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि वार्ता निकाय है। वर्ष 2009 के वार्षिक सत्र के दौरान निरस्त्रीकरण सम्मेलन में एक दशक से अधिक अवधि के गतिरोध के पश्चात किसी कार्य योजना पर सर्वसम्मति बनी। 29 मई, 2009 को निरस्त्रीकरण सम्मेलन में सर्वसम्मति से दस्तावेज सीडी/1864 को पारित कर दिया गया। इस दस्तावेज का शीर्षक '2009 सत्र के लिए कार्य योजना की स्थापना हेतु निर्णय' था। भारत ने इस कार्य योजना को पारित किए जाने का समर्थन किया। भारत ने यह भी कहा कि वह निरस्त्रीकरण सम्मेलन में संपन्न किए जाने वाले निष्पक्ष, बहुपक्षीय वार्ताओं पर आधारित एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापनीय विखंडनीय नियंत्रण संधि में शामिल होने के लिए तैयार है, बशर्ते कि इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखा जाए। तथापि, निरस्त्रीकरण सम्मेलन वर्ष 2009 में आयोजित वार्षिक सत्र के दौरान सीडी/1864 में सन्निहित निर्णयों के आधार पर ठोस कार्यों की शुरुआत करने में असफल रहा। भारत निरस्त्रीकरण सम्मेलन की कार्य योजना के भाग के रूप में विखंडनीय पदार्थ नियंत्रण संधि से संबंधित वार्ताओं में रचनात्मक भागीदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (यूएनडीसी)

वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग के तीन हफ्तों के सत्र का आयोजन 13 अप्रैल से 1 मई, 2009 तक न्यूयार्क में किया गया। अपने अधिदेश के अनुरूप यूएनडीसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सहायक निकाय के रूप में कार्य करता है तथा निरस्त्रीकरण से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है एवं अनुशंसाएं देता है। वर्ष 2009 में आयोजित सत्र यूएनडीसी के नए तीन वर्षीय चक्र की शुरुआत थी। इसमें नए चक्र के लिए तीन मदों की कार्यसूची को पारित किया गया। 'परमाणु निरस्त्रीकरण एवं परमाणु शस्त्रों के अप्रसार लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी अनुशंसाएं', 'चौथे निरस्त्रीकरण दशक के रूप में 2010 को घोषित किए जाने संबंधी प्रारूप के तत्व' तथा 'घोषणा के प्रारूप के तत्वों को स्वीकार किए जाने के उपरान्त परमाणु हथियारों के क्षेत्र में व्यावहारिक विश्वासोत्पादक उपाय (अधिमानतः वर्ष 2010 तक परन्तु 2011 के बाद नहीं)।' वर्ष 2009 में आयोजित सत्र के दौरान कार्यसूची की प्रथम दो मदों पर ठोस चर्चाएं की गईं। भारत ने यूएनडीसी के नए चक्र की कार्यसूची को नियमित रूप दिए जाने के संबंध में की जाने वाली वार्ताओं में सकारात्मक रूप से भाग लिया। बहुपक्षवाद के महत्व की पुष्टि करते हुए भारत ने यूएनडीसी के सदस्य देशों से वैश्विक और निष्पक्ष निरस्त्रीकरण की सकारात्मक भावनाओं के प्रति अपने प्रयासों को दोगुना करने का आह्वान किया।

जैविक हथियार अभिसमय (बीडब्ल्यूसी)

वर्ष 2006 में आयोजित छठे बीटीडब्ल्यूसी समीक्षा सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप बीटीडब्ल्यूसी के सरकारी पक्षकारों की बैठक 7-11 दिसंबर, 2009 तक और विशेषज्ञों की बैठक 24द्ध28 अगस्त, 2009 तक जनवरी में हुई। ये बैठकें कनाडा की अध्यक्षता में आयोजित की गईं और इनमें संक्रामक रोगों की निगरानी, जांच इत्यादि से जुड़े क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना पर चर्चा की गई।

भारत ने सरकारी पक्षकारों की बैठक में तथा विशेषज्ञों की बैठक में रचनात्मक भागीदारी की। सरकारी पक्षकारों की बैठक में भारत ने बीडब्ल्यूसी के अनुच्छेद-10 के संदर्भ में संक्रामक रोगों

की निगरानी, जांच एवं निदान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं क्षमता निर्माण से जुड़े अपने अनुभवों पर एक कार्यकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एच1एन1 के प्रसार का मुकाबला करने में अपने अनुभवों पर भी एक प्रस्तुति दी। भारत ने सरकारी पक्षकारों की बैठक के अंतिम दस्तावेज पर हुई वार्ताओं में अग्रणी भूमिका निभाई। इससे पूर्व विशेषज्ञों की बैठक में भारत ने बीटीडब्ल्यूसी के अनुच्छेद 10 के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा भारत में रोग निगरानी के संबंध में दो प्रस्तुतियां दीं।

रासायनिक हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)

भारत ने हेग में रासायनिक हथियारों पर नियंत्रण से संबद्ध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने अपनी वचनबद्धताओं के अनुरूप अभिसमय के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखा। रासायनिक हथियार अभिसमय के अंतर्गत की गई वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत की व्यापक सराहना की गई, जिसमें सीडब्ल्यूसी के दायित्वों के अनुरूप रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करना भी शामिल है।

भारत ने 30 नवंबर से 4 दिसंबर, 2009 तक हेग में आयोजित सीडब्ल्यूसी के सरकारी पक्षकारों के 14वें सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की। इसने 41-सदस्यीय कार्यकारी परिषद के 56वें, 57वें एवं 58वें सत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका यह वर्ष 1997 में इस संगठन की स्थापना के बाद से ही एक सक्रिय सदस्य रहा है। भारत ने इन बैठकों में अपनी तथा अन्य विकासशील देशों की हित-चिन्ता से जुड़े सभी मुद्दों को उठाया। भारत ने इस संगठन के विभिन्न सहायक निकायों में भी सक्रिय भागीदारी की जिनमें वैज्ञानिक सलाहकार तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों से संबद्ध परामर्शी निकाय शामिल हैं। अनुच्छेद-11 के तहत रसायन शास्त्र के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी वचनबद्धता के भाग के रूप में भारत ऐसा एक मात्र विकासशील देश है, जिसने विदेशी सहभागियों के लिए लगातार दूसरी बार सहयोजित कार्यक्रम की मेजबानी की। भारत ओपीसीडब्ल्यू केंद्रीय विश्लेषणात्मक डाटाबेस में एक महत्वपूर्ण प्रदाता के रूप में भी उभरा है। कार्यकारी परिषद की बैठकों के दौरान विशेष रूप से आयोजित बैठकों में भारत ने इनमें रुचि रखने वाले सरकारी पक्षकारों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों को रासायनिक उद्योग, सत्यापन तथा प्रशासनिक तथा वित्तीय मुद्दों के संबंध में भी जानकारी दी।

कतिपय परमाणु हथियारों से संबद्ध अभिसमय (सीसीडब्ल्यू)

भारत कतिपय पारंपरिक हथियारों, जिन्हें अत्यंत खतरनाक माना जा सकता है और जिनका अंधाधुंध प्रयोग हो सकता है, के उपयोग पर प्रतिबंध अथवा निषेध लगाने से संबद्ध अभिसमय का एक उच्च संविदाकारी पक्षकार है और इसने इसके सभी पांचों प्रोतोकोलों का अनुसमर्थन किया है, जिनमें बारूदी सुरंगों, छद्म बम और अन्य हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध अथवा निषेध पर संशोधित प्रोतोकोल-2 तथा युद्ध के विस्फोटक अवशेषों पर प्रोतोकोल-5 भी शामिल हैं। भारत ने अभिसमय के अनुच्छेद-1 में संशोधन का भी समर्थन किया है।

सीसीडब्ल्यू से संबद्ध अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकारों की वार्षिक बैठक का आयोजन 12-13 नवंबर, 2009 तक जिनेवा में किया गया। 2008 में सरकारी पक्षकारों की बैठक में सरकारी विशेषज्ञों के समूह (जीजीई) से एक ऐसे प्रस्ताव पर बातचीत करने का अनुरोध किया गया था, जिससे कि सैन्य और मानवीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए एकत्रित विस्फोटकों के मानवीय प्रभाव की समस्या पर तत्काल ध्यान दिया जा सके और उसकी रिपोर्ट 2009 की बैठक से पहले प्रस्तुत की जाए। 2009 में जीजीई की दो औपचारिक तथा तीन अनौपचारिक बैठकें कुल तीन हफ्तों के लिए हुईं। यह अपनी वार्ताएं संपन्न करने में असमर्थ रहा। वार्षिक बैठक में निर्णय लिया गया कि जीजीई अपनी वार्ताएं जारी रखेगा और इसे यथासंभव शीघ्र संपन्न करने के प्रयास करेगा और उच्च संविदाकारी पक्षकारों की अगली बैठक (2010) को सूचित करेगा। जीजीई को इस प्रयोजनार्थ 2010 में दो सप्ताह तक बैठक करने का अधिदेश दिया गया।

युद्ध के विस्फोटक अवशेषों पर सीसीडब्ल्यू के प्रोतोकोल-5, जो नवंबर, 2009 में लागू हुआ, की तीसरी बैठक जनवरी में 9-10 नवंबर, 2009 को आयोजित की गई। निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थाई प्रतिनिधि राजदूत हामिद अली राव को तीसरी वार्षिक बैठक का अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में इस प्रोतोकोल को सुदृढ़ बनाने तथा इसे क्रियान्वित किए जाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई और इस पर सहमति व्यक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में राष्ट्रीय रिपोर्टों के दिशानिर्देश तथा एक वेबसाइट बनाए जाने के संबंध में प्रगति हुई, जिससे कि प्रोतोकोल-5 के तहत इलेक्ट्रानिक तरीके से सूचना के आदान-प्रदान का एक मंच उपलब्ध हो सके। अमरीका, पाकिस्तान एवं कनाडा सहित 13 देश तीसरे सम्मेलन के पूर्व ही प्रोतोकोल-5 के सरकारी पक्षकार बन गए।

'बारूदी सुरंगों, छद्म बमों और अन्य विस्फोटकों के उपयोग, प्रतिबंध एवं निषेध से संबद्ध सीसीडब्ल्यू अभिसमय' के संशोधित प्रोतोकोल के सरकारी पक्षकारों की वार्षिक बैठक 11 नवंबर, 2009 को जिनेवा में हुई। इस बैठक में उन्नत विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई तथा वर्ष 2010 में आयोजित की जाने वाली विशेषज्ञों की बैठक में आईईडी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के व्यावहारिक उपायों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा जारी रखने का निर्णय लिया गया। भारत ने इस बात का उल्लेख किया कि उसने संशोधित प्रोतोकोल-2 के संबंध में अपने सभी दायित्वों को पूरा किया है और साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के संदर्भ में बारूदी सुरंगों के अंधाधुंध उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न मानवीय चिन्ताओं का समाधान करने हेतु

अनेक उपाय किए हैं। भारत ने आतंकवादियों एवं अराजक तत्वों द्वारा बार-बार आईईडी का उपयोग किए जाने तथा उन्हें आईईडी की आपूर्ति किए जाने से जुड़े सीमापार आयामों की समस्या को रेखांकित किया।

भारत बारूदी सुरंग मुक्त एक ऐसे विश्व के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के विजन को स्वीकार करता है और बारूदी सुरंगों के स्थान पर उपलब्ध वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए तैयार है। भारत ने 30 नवंबर-4 दिसंबर, 2009 तक कार्टाजेना में अभिसमय की दूसरी समीक्षा बैठक में एक पर्यवेक्षक की हैसियत से भाग लिया। इसी प्रकार, भारत ने 25-29 मई, 2009 तक भी इस अभिसमय की स्थाई समिति की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भागीदारी की। तथापि, भारत बारूदी सुरंगों के उपयोग, भंडारण, उत्पादन एवं अंतरण पर प्रतिबंध एवं उन्हें नष्ट किए जाने से संबद्ध अभिसमय अथवा ओटावा अभिसमय का पक्षकार नहीं है, क्योंकि भारत का मानना है कि यदि इन बारूदी सुरंगों का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक किया जाए, तो ये बेहतर और वैध रक्षा औजार साबित हो सकते हैं।

लघु शस्त्र एवं हल्के हथियार

लघु शस्त्रों एवं हल्के हथियारों के सभी पहलुओं पर प्रतिबंध लगाने, इनका मुकाबला करने और इनके गैर-कानूनी व्यापार का उन्मूलन करने से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र (यूएनपीओए) कार्य योजना, जिसे जुलाई, 2001 में पारित किया गया था, में इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक उपायों का प्रावधान किया गया है। भारत ने बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय आधार पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन किया है।

भारत शस्त्रों के निर्माण में पारदर्शिता से जुड़े लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध रहा और इसने परमाणु हथियारों के संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर पर वर्ष 2009 में आयोजित सरकारी विशेषज्ञों के समूह में भाग लिया। इस रजिस्टर के प्रचालन एवं आगे के घटनाक्रमों की समीक्षा जीजीई द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

भारत ने 15 मई, 2009 को असैनिक परमाणु संयंत्रों में सुरक्षोपाय के अनुप्रयोग हेतु आईएईए के साथ संपन्न करार के अतिरिक्त प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए।

भारत ने 14 से 18 सितंबर, 2008 तक आयोजित आईएईए के 53वें महाधिवेशन में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अनिल काकोदकर, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग ने किया। महाधिवेशन में परमाणु संरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षोपाय, परमाणु अनुप्रयोग एवं परमाणु ऊर्जा से जुड़े विषयों पर अनेक संकल्प पारित किए गए।

16 सितंबर, 2009 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के समक्ष भारत-आईएईए सुरक्षोपाय करार के पैरा-13 के उपबंधों के अनुसरण में चरणबद्ध तरीके से एवं स्वैच्छिक आधार पर अपने असैनिक परमाणु संयंत्रों को आईएईए रक्षोपायों के तहत लाए जाने के लिए घोषणा प्रस्तुत की। इसके अनुसरण में, भारत ने इन सुविधाओं को आईएईए के रक्षोपाओं के अधीन लाने के लिए 16 अक्तूबर, 2009 और 19 अक्तूबर, 2009 को अधिसूचनाएं प्रस्तुत कीं।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत और एनएसजी त्रोइका के बीच बैठकों के दो दौर हुए। पहली बैठक का आयोजन 11 मई, 2009 को नई दिल्ली में तथा दूसरी बैठक का आयोजन 17 सितंबर, 2009 को वियना में किया गया। ये बैठकें सितंबर, 2008 के एनएसजी के उस निर्णय के संदर्भ में की गईं, जिसके तहत इसके सभी सदस्यों को भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इन चर्चाओं में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में भावी सहयोग पर विचार-विनिमय को भी शामिल किया गया।

एशिया में कार्यकलाप एवं विश्वासोत्पादक उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए)

भारत ने सीआईसीए की बैठकों में अपनी सक्रिय एवं रचनात्मक भागीदारी जारी रखी। इसने जून, 2009 तथा जनवरी, 2010 में अलमाती में तथा अक्तूबर, 2009 में बीजिंग में आयोजित सीआईसीए विशेष कार्यकारी दल (एसडब्ल्यूजी)/ वरिष्ठ अधिकारी समिति (एसओसी) की बैठकों में भाग लिया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर आयोजित विशेषज्ञों की बैठकों में भी भागीदारी की। सीआईसीए प्रक्रिया में भारत की भागीदारी अभी भी इसके इस आशय के दृष्टिकोण से निर्देशित होती है कि एशियाई पहचान के अभिन्न अंग के रूप में इसकी विविधता एवं विषमता को देखते हुए सीआईसीए आपसी समझबूझ, विश्वास एवं संप्रभु समानता पर आधारित सहकारी एवं बहुलवादी सुरक्षा व्यवस्था के विकास में योगदान दे सकता है।

एशियाई क्षेत्रीय मंच (एआरएफ)

भारत ने 9-11 नवंबर, 2009 तक नई दिल्ली में विश्वासोत्पादक उपायों एवं निषेधात्मक राजनय से संबद्ध आसियान क्षेत्रीय मंच अंतर-सत्रीय समर्थन समूह (एआरएफ-आईएसजी) की बैठकों की मेजबानी की। इस बैठक का आयोजन जुलाई, 2009 में फुकेट, थाईलैंड में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच की 16वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में किया गया। आईएसजी की इस बैठक के लिए वियतनाम ने आसियान पक्ष की ओर से सह-अध्यक्षता की। यह दूसरा अवसर था जब भारत ने एआरएफ-आईएसजी की मेजबानी की। पहली बैठक का आयोजन वर्ष 2001 में किया गया था। भारत मार्च, 2010 में वियतनाम में आयोजित होने वाली एआरएफ-आईएसजी की अगली बैठक की सह-अध्यक्षता करेगा।

आईएसजी की सह-अध्यक्षता करने के भारत के निर्णय से इस बात का पता चलता है कि भारत एआरएफ में अपनी सदस्यता

को कितना महत्वपूर्ण मानता है। भारत का मानना है कि एशिया प्रशांत में वार्ता के एक प्रधान राजनैतिक एवं सुरक्षा मंच के रूप में अभी भी एआरएफ इस क्षेत्र की सुरक्षा संरचना की आधारशिला है। 1994 में गठन के बाद से ही आसियान क्षेत्रीय मंच ने अपने सदस्य देशों के बीच आस्था एवं विश्वास का निर्माण करने तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किए जाने के एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरा है। भारत ने भी आपदा राहत एवं अप्रसार तथा निरस्त्रीकरण से संबद्ध अंतर-सत्रीय बैठकों (आईएसएम) सहित आसियान क्षेत्रीय मंच के विभिन्न कार्यकलापों में भाग लिया।

सामरिक निर्यात नियंत्रण

भारत उन संवेदनशील सामानों एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण लगाता रहा है, जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग सामूहिक विनाश के हथियारों अथवा उनकी डिलिवरी प्रणाली के निर्माण के लिए किया जा सकता है। मंत्रालय ने सामूहिक विनाश के हथियारों एवं उनकी डिलिवरी प्रणाली अधिनियम, 2005 के अनुसरण में उद्योग जगत, संबंधित विभागों एवं अन्य सहभागियों के साथ विभिन्न आउटरीच कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया और उसमें भाग लिया।

अन्य मुद्दे

भारत-अमरीका सामरिक सुरक्षा संवाद का आयोजन 13 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में किया गया। भारतीय एवं अमरीकी प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व क्रमशः विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव एवं शस्त्र नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुश्री एलेन ताउसर ने किया। ये वार्ताएं नई वार्ता रूपरेखा पर जुलाई, 2009 में नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा और अमरीकी विदेश मंत्री श्रीमती हिलेरी क्लिंटन के बीच हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में हुईं। वार्ताओं में वैश्विक एवं क्षेत्रीय सामरिक मुद्दों के साथ-साथ निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार के संबंध में बहुपक्षीय मंचों पर हुए घटनाक्रमों को भी शामिल किया गया।

भारत ने 16-17 जून, 2009 तक हेग में आयोजित परमाणु आतंकवाद का मुकाबला करने से संबद्ध वैश्विक अभिसमय की पांचवीं पूर्ण बैठक में भाग लिया। भारत जून, 2008 में मैड्रिड में आयोजित बैठक में इस वैश्विक पहल में शामिल हुआ था।

■■

11 बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

वर्ष 2009 के दौरान भारत के बहुपक्षीय आर्थिक क्रियाकलापों में और अधिक व्यापकता आई। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे बहुपक्षीय मंचों में विचार-विमर्श के केन्द्रबिन्दु बने रहे। इस वर्ष के बहुपक्षीय क्रियाकलापों में मुख्य थे - जी-8 आउटरीच शिखर बैठक में प्रधान मंत्री की लगातार पांचवी बार भागीदारी, ब्राजील, रूस, भारत और चीन (ब्रिक) के नेताओं का रूस में प्रथम औपचारिक शिखर बैठक, भारत-आसियान शिखर बैठक और पूर्वी एशिया शिखर बैठक। बहुपक्षीय चर्चाओं में आने वाली बाधाओं को दूर करने और डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षीय प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए वार्त्ताकारों को स्पष्ट संकेत प्रदान करने हेतु व्यापक सर्वसम्मति विकसित करने के लिए सितम्बर, 2009 में डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का भारत द्वारा आयोजन वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।

वर्ष के दौरान एसीडी, एएसईएम, बिमस्टेक, एमजीसी, इब्सा, जी-15, आईओआर-एआरसी और अन्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूहों के साथ क्रियाकलाप और अधिक समेकित हुए। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने ब्रिक, जी-5 और इब्सा की मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जी-20 शिखर बैठक के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों पर दृष्टिकोणों को समन्वित करने के लिए ब्रिक वित्त मंत्रियों की बैठक हुई।

एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम)

भारत ने विभिन्न एएसईएम बैठकों और पहलों में सक्रियतापूर्वक भाग लेना जारी रखा। हनोई में 25-26 मई, 2009 को आयोजित एएसईएम विदेश मंत्रियों की नौंवी बैठक में विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्वी) श्री एन. रवि ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के अंत में जारी अध्यक्ष महोदय के वक्तव्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, आस्ट्रेलिया और रूस द्वारा एएसईएम में शामिल होने के लिए किए गए आवेदन का स्वागत किया गया और ब्रसेल्स में अक्तूबर, 2010 में आयोजित होने वाले एसईएम की आठवीं शिखर बैठक में इन दोनों देशों को शामिल कर सकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया। एएसईएम के अंतर्गत उत्तर-पूर्व और दक्षिण एशिया उप-समूह के समन्वयकर्त्ता के रूप में भारत ने एएसईएम के विस्तार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एशियाई सदस्यों के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए सितम्बर, 2009 में एएसईएम के एशियाई सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की।

ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन)

प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन (ब्रिक) के नेताओं की प्रथम औपचारिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए येकातेरिनबर्ग, रूस की 15-17 जून, 2009 तक यात्रा की। यह प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी।

नेताओं ने शिखर बैठक में, अन्य मुद्दों के साथ-साथ, वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट की स्थिति पर ध्यान केन्द्रित रखा। विकासशील देशों के हित के जी-20 निर्णयों का कार्यान्वयन करवाने और वैश्विक शासन पद्धति की मौजूदा प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए आर्थिक मामलों पर चतुर्पक्षीय ब्रिक ढाँचे के अंतर्गत सहयोग को गहन बनाने की आवश्यकता पर नेताओं ने बल दिया। शिखर बैठक में ब्रिक नेताओं का संयुक्त वक्तव्य और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर एक संयुक्त वक्तव्य पारित किया गया।

ब्रिक वित्त मंत्रियों ने पारस्परिक रुचि के मसलों पर दृष्टिकोण को समन्वित करने के लिए लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित जी-20 शिखर बैठक के पूर्व भी मुलाकात की। रूस द्वारा मई, 2009 के अंत में आयोजित ब्रिक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन ने भाग लिया। ब्रिक प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकारियों की पहली सितम्बर, 2009 को कजान, रूस में आयोजित बैठक में भी भारत ने भाग लिया।

न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 64वीं महासभा के दौरान ब्रिक विदेश मंत्रियों की 24 सितम्बर, 2009 को आयोजित बैठक में विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट, ब्रिक सांस्थानीकरण, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

जी-8 आउटरीच और जी-5 शिखर बैठक

प्रधानमंत्री ने 8-10 जुलाई, 2009 को इटली के शहर ला' आकिला में आयोजित जी-5 शिखर बैठक और जी-8 आउटरीच बैठक में भाग लिया। यह वर्ष 2005 के बाद से प्रधानमंत्री की लगातार पाचवीं जी-8 शिखर बैठक थी।

जी-5 नेताओं की बैठक की कार्यसूची में वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट-एमडीजी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए विकासशील देशों के लिए इसके प्रभाव, ग्रीनरिकवरी, दोहा दौर,

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 8 जुलाई, 2009 को ला' आकिला, इटली में जी-5 देशों के नेताओं के साथ।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 9 जुलाई, 2009 को
ला' आकिला, इटली में जी-8 शिखर बैठक से पहले जर्मन चांसलर सुश्री अंजेला मर्केई के साथ।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और जी-5 सहयोग के भावी संकेत शामिल थे। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भावी प्रगति को समावेशी होना चाहिए और सभी देशों को स्टैगफ्लेशन के विरुद्ध सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। जी-5 नेताओं ने बैठक के पश्चात एक राजनीतिक घोषणापत्र भी जारी किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोहा दौर पर जी-8 घोषणापत्र अपेक्षाकृत कमजोर है, जी-5 नेताओं ने इस मुद्दे पर अलग से एक वक्तव्य भी जारी किया।

जी-8/जी-5 देशों और मिस्र (मेजबान देश इटली द्वारा आमंत्रित) की शिखर बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट और विश्व शासन प्रणाली का मसला चर्चा का मुख्य केंद्रबिन्दु था। शिखर बैठक के पश्चात जी-8/जी-5 नेताओं ने एक संयुक्त घोषणापत्र 'विश्व कार्यसूची का संवर्धन ' जारी किया। ला' अकिला में जी-8/जी-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन की रूपरेखा के अंतर्गत आयोजित प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच (एमईएफ) की बैठकों में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। एमईएफ का 9 जुलाई, 2009 को आयोजित पहला सत्र दोहा दौर पर और दूसरा सत्र जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित था।

वर्ष 2009 के जी-8 प्रेसीडेंसी, इटली ने वर्ष 2009 के जी-8 शिखर बैठक के पश्चात विभिन्न मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए भारत और अन्य आउटरीच देशों को आमंत्रित किया। लोक सभा की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार ने सितंबर, 2009 में रोम में आयोजित जी-8 आउटरीच देशों के अध्यक्षों की पहली बैठक में भाग लिया। यह जी-8 और आउटरीच देशों के अध्यक्षों की पहली बैठक थी।

विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने अफगानिस्तान पर आयोजित जी-8 आउटरीच बैठक में भाग लिया। जी-8 आउटरीच देशों की मंत्रीस्तरीय अन्य बैठकों, जिनमें भारत ने भाग लिया, में श्रम मंत्रियों, कृषि मंत्रियों, पर्यावरण मंत्रियों और ऊर्जा मंत्रियों की बैठकें शामिल हैं। अस्थिरीकरण के कारक और सीमा-पार के खतरों पर जी-8 और आउटरीच मंत्रियों के अप्रैल, 2009 में रोम में आयोजित सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) ने भाग लिया।

जी-5 विदेश मंत्रियों की बैठक

परिवर्तनशील अंतर्राष्ट्रीय ज्यामिती, जी-20 के सांस्थानीकरण और जी-5 के बीच भावी समन्वय पर चर्चा करने के लिए न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र के दौरान 22 सितंबर, 2009 को जी-5 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

बिमस्टेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल)

बिमस्टेक विदेश मंत्रियों की 10-11 दिसंबर, 2009 को ने पीइ ताव, म्यांमा में आयोजित 12वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने किया। मंत्रिस्तरीय बैठक के पूर्व 10-11 दिसंबर, 2009 को वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक और 8-9 दिसंबर, 2009 को तैयारी संबंधी एक बैठक हुई। 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने बिमस्टेक की अध्यक्षता म्यांमा को सौंप दी।

यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा-पार संगठित अपराध और अवैध मादक दवाओं के व्यापार का मुकाबला करने में सहयोग करने संबंधी बिमस्टेक अभिसमय पर हस्ताक्षर का साक्षी रही। भारत सहयोग के इस क्षेत्र का प्रमुख देश है।

बिमस्टेक की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में सहयोग के 14वें क्षेत्र के रूप में जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया। सभी सदस्य देशों ने एशियाई विकास बैंक द्वारा संचालित बिमस्टेक परिवहन अवसंरचना और संभारतंत्रीय अध्ययन को स्वीकृति प्रदान की, जिससे बिमस्टेक में समग्र सहयोग का और अधिक विस्तार सुविधाजनक होगा।

डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

भारत ने सितंबर, 2009 में डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत बहुपक्षीय व्यापार वार्त्ता को निर्धारित ढंग से आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में दोहा वार्त्ता में सभी हितों और दृष्टिकोण से सभी समूहों को एक साथ लाया गया। सम्मेलन में दोहा दौर को वर्ष 2010 के अन्दर सम्पन्न करने की आवश्यकता की सर्वसम्मति से पुष्टि व्यक्त की गई। विकास को दोहा दौर के केन्द्र में रखने की सख्ती से पुष्टि की गई। सहभागियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि किसी भी मसले पर मतभेद रह सकते हैं, लेकिन संवाद को गहन बनाना इन मतभेदों को पाटने की दिशा में पहला कदम है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशक डॉ0 फ्रांसीस गुटी ने 9-14 नवंबर, 2009 तक भारत का दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, पर्यावरण एवं वनकी राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने उनका स्वागत किया। यह दौरा पॉचवें अंतर्राष्ट्रीय सृजनशीलता एवं आविष्कार मंच, पारंपरिक ज्ञान पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मनोरंजन क्षेत्र में एक गोलमेज बैठक के सिलसिले में था। इन कार्यक्रमों की मेजबानी फिक्की के सहयोग से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने की।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)

आसियान के साथ सुदृढ़ और बहु-आयामी संबंध भारत के मुख्य केंद्र बिन्दु में होना वर्ष 1990 के पूर्वार्द्ध से विश्व की राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य में आए महत्वपूर्ण बदलाव और आर्थिक उदारीकरण की दिशा में भारत द्वारा स्वयं आगे बढ़ने का परिणाम था। आर्थिक गुंजाइश के लिए भारत की खोज के परिणामस्वरूप

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 25 अक्तूबर, 2009 को हुआ हिन,
थाइलैंड में चौथी पूर्व एशियाई शिखर बैठक (ईएएस) में राष्ट्र/सरकार प्रमुखों के साथ।

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 24 अक्तूबर, 2009 को हुआ हिन, थाइलैंड में आयोजित सातवीं भारत-आसियान शिखर बैठक के पहले आसियान नेताओं के साथ समूह फोटो में

'पूर्वोन्मुख नीति ' का उदय हुआ। बृहत्तर एशिया प्रशांत क्षेत्र में आसियान की आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक महत्ता और व्यापार एवं निवेश में भारत का प्रमुख भागीदार बनाने की उसकी क्षमता हमारे नीति प्रतिमानों का महत्वपूर्ण तत्व हैं। म्यांमा को शामिल करने के लिए आसियान का निरंतर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना उसे हमारी भी भू-सीमाओं तक ले आया। अब यह भारत को 21वीं सदी के बाजार को आकार देने वाले एशिया-प्रशांत केंद्रित आर्थिक विरोधाभासों के साथ जोड़ने के लिए सेतु प्रदान करता है। आसियान स्वयं भारत के व्यावसायिक एवं तकनीकी क्षमताओं के साथ जुड़ना चाहता है। सी एल एम वी (कंबोडिया, लाओस, वियतनान, म्यांमा) के साथ हमारी पारंपरिक मैत्री ने भी आसियान एकीकरण की पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत को एक अमूल्यवान मित्र बनाता है।

भारत और आसियान अपने सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में एकमत रखते हैं। हम लोगों का क्षेत्र की शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कच्ची सामग्री, पण्य और ऊर्जा आपूर्ति के सरल प्रवाह हेतु हिन्द महासागर के समुद्री गलियारों की सुरक्षा शामिल है। वर्ष 1996 से भारत आसियान क्षेत्रीय मंच में सक्रिय भागीदार रहा है।

भारत की गहन वार्त्ता के छह वर्षों के पश्चात आसियान आर्थिक मंत्रियों और भारत की बैठक में बैंकाक में आसियान-भारत माल व्यापार करार पर 13 अगस्त, 2009 को हस्ताक्षर किये गए। इस करार से विनिर्दिष्ट स्तरों तक मालभाड़े में कटौती और क्षेत्र के 1.5 बिलियन लोगों से अधिक का बाजार सृजित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दिशा में अगला कदम भारत-आसियान एफटीए पूर्ण करने के लिए निकट भविष्य में सेवा में व्यापार और निवेश में व्यापार करारों पर वार्त्ता निष्पादित करना है।

वार्त्ता भागीदारों के साथ वार्षिक आसियान शिखर बैठक और पूर्वी एशिया शिखर बैठक अक्तूबर, 2009 में थाइलैंड में संपन्न हुई। भारत-आसियान शिखर बैठक और पूर्वी एशिया शिखर बैठक 24-25 अक्तूबर, 2009 को चाम हुवा हिन, थाइलैंड में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने बढ़ती भारत-आसियान सहभागिता को और मजबूत बनाने और पुनर्सक्रिय करने के लिए भारत-आसियान शिखर बैठक में कई नई पहलों की घोषणा की। पूर्वी एशिया शिखर बैठक में भारत ने आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, वित्त, ऊर्जा और वैश्विक महामारी के मुद्दों पर चर्चा में भाग लिया। नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का भारत का प्रस्ताव संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी होने के साथ मुख्य रूप से केंद्रबिन्दु में रहा।

हिन्द महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ (आईओआर - एआरसी)

भारत आईओआर - एआरसी का संस्थापक और महत्वपूर्ण सदस्य है। हिन्द महासागर परिधि 18 देशों की भाषाओं, संस्कृति और धर्मों की व्यापक विविधता के साथ एक विषम क्षेत्र है। आईओआर - एआरसी की मंत्रिपरिषद की नौंवी बैठक 25 जून, 2009 को साना, यमन में संपन्न हुई। विदेश राज्य मंत्री डॉ0 शशि थरूर ने इस मंत्रिपरिषद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मंत्रिपरिषद की बैठक के प्रमुख निष्कर्षों में क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतरण केन्द्र (आईएसएसटीटी), मत्स्यपालन सहायक यूनिट और समुद्री परिवहन परिषद की स्थापना करना शामिल है। भारत ने यमन से उपाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया और आईओआर - एआरसी का अगले दो वर्षों की अवधि तक अध्यक्ष बना। भारत अध्यक्ष का पद वर्ष 2011 में ग्रहण करेगा।

भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (इब्सा)

तीन भिन्न महाद्वीपों के तीन विकासशील लोकतांत्रिक देशों का मंच इब्सा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर समन्वय को सुदृढ़ करने, दक्षिण की सामूहिक आवाज को विस्तार देने के लिए दक्षिण सहयोग बढ़ाने और साझे अनुभव, संपूरकताओं और संसाधनों पर आधारित परस्पर लाभकारी त्रिपक्षीय सहयोग को व्यापक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र बन गया है।

छठी इब्सा मंत्रिस्तरीय बैठक ब्रासीलिया में सितम्बर, 2009 में आयोजित हुई। विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 14वीं फोकल प्वाएंट बैठक 15-16 जुलाई, 2009 को रियो-डि-जेनेरो में संपन्न हुई। वर्ष के दौरान कृषि, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण मानव अधिवास, सूचना सोसायटी, राजस्व प्रशासन, सामाजिक विकास, व्यापार, लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था, परिवहन जैसे क्षेत्रों में और इब्सा महिला मंच की तैयारी बैठक में कार्यदल की कई बैठकें आयोजित हुई।

गिनी बिसाऊ, हैती, बुरूण्डी, लाओस, केप वर्डे, कंबोडिया और फिलीस्तीन में गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यों को बढ़ाने के लिए गरीबी एवं भूख उन्मूलन इब्सा सुविधा कोष के तहत और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों के लिए इब्सा ने परियोजनाएं शुरू की है।

एशिया सहयोग वार्त्ता (एसीडी)

एशिया सहयोग वार्त्ता, आर्थिक वार्त्ता और सहयोगी परियोजनाओं पर केंद्रित 31 देशों का अनूठा पैन-एशियाई समूह है। एसीडी का लक्ष्य एशिया की क्षमताओं को समेकित कर और क्षेत्र तथा उसमें रहने वाले लोगों के परस्पर लाभ के लिए एशिया की विविधता से लाभ उठा कर एक संयुक्त, मजबूत, प्रतिस्पर्द्धात्मक और समृद्ध एशियाई समुदाय का निर्माण करना है।

एशिया सहयोग वार्त्ता की आठवीं मंत्रिस्तरीय बैठक 15 अक्तूबर, 2008 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित हुई। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक का विषय 'ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी एंड डेवलपेंट प्रास्पेक्ट्स ' था।

यह सहमति हुई कि विशेष बल पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन के क्षेत्रों में सहयोग पर दिया जाना चाहिए, जिसमें क्षेत्र में लोगों से

लोगों के बीच संवर्धित सहयोग सृजित करने की क्षमता है। एसीडी की स्थापना के दिन 18 जून को एसीडी दिवस के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया।

भारत 24 मार्च, 2010 को चतुर्थ एसीडी पर्यटन व्यापार मंच की बैठक और ट्रैक-।। प्रक्रिया के भाग के रूप में 11-12 फरवरी, 2010 को विचार केन्द्रों की पहली बैठक आयोजित करेगा।

■■

12 सार्क प्रभाग

अप्रैल, 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा स्वतः स्फूर्त प्रेरणा सार्क के घोषणा के कार्यान्वयन चरण के सतत और अनुत्क्रमणीय अंतरण के लिए अधिकांशतः उत्तरदायी है। अपनी घरेलू विकासात्मक चुनौतियों के हल के लिए सार्क की तरफ देखने वाले अन्य सदस्य देशों की बढ़ती आवश्यकताओं सहित असममिति और गैर-पारस्परिक तरीके से अपने दायित्वों को निभाने में भारत की प्रतिबद्धता द्वारा यह प्रक्रिया और सुदृढ़ हुई है।

हाल के समय में सार्क क्षेत्र सुरक्षा विषयों पर संवर्धित सहयोग का गवाह रहा है। सार्क मंत्रियों की परिषद (कोलम्बो, 27-28 फरवरी, 2009) के 31वें सत्र ने क्षेत्र में आतंकवाद की बढ़ती बुराई के निपटारे के लिए गहन सहयोग करने के लिए 'आतंकवाद के समापन के सहयोग के लिए सार्क मंत्रालयी घोषणा ' को अपनाया। घोषणा में उल्लेख है कि सदस्य देश सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधित भू-भाग का आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों अथवा आतंकवादी कृत्यों के आयोजन के लिए इस्तेमाल न हो। श्रीलंका आधारित सार्क आतंकवादी अपराध प्रबोधन डेस्क (एसटीओएमडी) तथा सार्क मादक द्रव्य अपराध प्रबोधन डेस्क (एसडीओएमडी) आतंकवादी और मादक द्रव्य संबंधी मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान को सक्षम बनायेंगे। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से डेस्कों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी तरह मुक्त/अवर्गीकृत सूचना के आदान-प्रदान हेतु भारत द्वारा सदस्य देशों के पुलिस प्राधिकरणों के बीच एक इंटरनेट आधारित नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में महिला और बच्चों के अवैध व्यापार-संबंधी सार्क अभिसमय के कार्यान्वयन तथा 28-29 मई, 2009 को आयोजित दक्षिण एशिया में बाल कल्याण के प्रोत्साहन को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यबल की तीसरी बैठक में महिला और बच्चों के अवैध व्यापार संबंधी मानक परिचालन प्रोतोकाल को अंतिम रूप प्रदान किया गया है।

सार्क में इस नई गतिशीलता की सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति सार्क विकास निधि (एसडीएफ) का पूर्व परिचालन रहा है, भूटान में इसके स्थायी परिसर की स्थापना 2010 तक हो जाएगी। भारत सार्क का एकमात्र सदस्य देश है, जिसने एसडीएफ में 189.9 मिलियन अमरीकी डालर की अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता अंतरित की है। महिला सशक्तिकरण तथा मातृत्व और बाल स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी परियोजना पर भारत की तकनीकी सहायता से एसडीएफ के तत्वाधान के अंतर्गत वर्तमान में दो क्षेत्रीय परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। बायो-मास कुकिंग स्टोवस तथा सौर्य ऊर्जा लालटेन उपलब्ध करवाने पर भारत द्वारा प्रस्तावित तीसरी परियोजना भी विचाराधीन है।

निकट भविष्य में नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम को छूने की आशा है। परियोजना कार्यालय की स्थापना, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 द्वारा इसकी अंतर्राष्ट्रीय विधायी रूप रेखा को अंतिम रूप प्रदान करना, संयुक्त राष्ट्र प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार अधिनियम, 1947 के अनुसार विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करना तथा 'क्षेत्रीय केन्द्रों के सिद्धांतों ' के अनुसार वित्त पोषण के साथ प्रतिष्ठित परियोजना पर कार्य चल रहा है। सहमति से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार एसएयू को स्थापित करने तथा इसको पूर्ण रूप से कार्यात्मक करने की कुल लागत 308.91 मिलियन अमरीकी डालर होगी। भारत परियोजना में 229.11 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान देगा, जिसमें 100 पूंजीगत लागत को वहन करना शामिल है। विश्वविद्यालय के 2015 तक पूरी तरह स्थापित होने की संभावना है।

नवंबर, 2005 में ढाका में आयोजित 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सम्पन्न वस्त्र और हस्तशिल्प परम्पराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वस्त्र और हस्तशिल्प का सार्क संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। अन्य सार्क क्षेत्रीय केन्द्रों की तर्ज पर संग्रहालय एक अन्तर सरकारी निकाय होगा तथा इसे दिल्ली हाट, पीतमपुरा में स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित सार्क संग्रहालय की विधायी और वित्तीय रूप रेखा को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए द्वितीय अन्तर सरकारी संचालन समिति की बैठक 29-30 सितंबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

अधिक भौतिक सम्बद्धता सृजित करने के विषय पर आगे कार्रवाई करते हुए कोलंबो (24-25 जुलाई, 2009) में आयोजित परिवहन मंत्रियों की दूसरी बैठक में समयबद्ध तरीके से मोटर वाहन और रेलवे (भारत द्वारा प्रस्तावित) पर दो मसौदा क्षेत्रीय करारों पर बातचीत करने के लिए विशेषज्ञ समूह की विशेष बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिससे कि उनको 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हेतु अंतिम रूप प्रदान किया जा सके। कोलम्बो-कोचीन मार्ग के जरिए भारत और श्रीलंका के बीच मालगाड़ी सेवा तथा नई दिल्ली-माले के बीच सीधी वायु सेवा के शीघ्र शुरू होने की सम्भावना है। अरवोरा-अगरतल्ला कोरिडोर को शीघ्र परिचालित करने के उद्देश्य से सदस्य देशों ने त्रिपक्षीय परामर्श आयोजित करने पर सहमति जतायी है।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार के अक्षरशः समग्र कार्यान्वयन के लिए प्रशंसनीय प्रगति हुई है। सदस्य देशों ने 1 जनवरी, 2008 से एलडीसी को जीरो ड्यूटी पहुंच प्रदान करने तथा एलडीसी के संबंध में इसकी नकरात्मक सूची को 744 से 480 तक एकतरफा कम करने के भारत के निर्णय की प्रशंसा की है, जोकि लक्षित तिथि से एक वर्ष पहले है। भारत अपनी संवेदनशील सूची को निरंतर संशोधित करता रहता है तथा एलडीसी हेतु 740 तथा गैर-एलडीसी हेतु 868 मदें इसकी परिधि से बाहर हैं। सेवा में व्यापार पर मसौदा करार भी बातचीत के अंतिम स्तर पर है। सार्क अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक मंदी के प्रभावों को नोट करते हुए कोलम्बो (27-28 फरवरी, 2009) में आयोजित मंत्रियों की सार्क परिषद के 31वें सत्र ने संकट से निपटने के लिए समन्वित क्षेत्रीय दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए 'वैश्विक आर्थिक मंदी पर सार्क मंत्रालयी वक्तव्य' को अपनाया। यह निर्णय लिया गया कि लघुकालिक द्रवता कठिनाइयों के हल के लिए क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यवस्था सृजित करने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। विकासशील अर्थव्यवस्थओं के हितों की रक्षा करने के लिए इसने वैश्विक पहल की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें बहुपक्षीय सहायता एजेंसियों तथा अन्य विकास साझेदारों को ऋण के पुनः भुगतान पर ऋण स्थगन शामिल होना चाहिए।

भारत ने दो महत्वपूर्ण सार्क बैठकों की मेजबानी भी की। सार्क पर्यावरण मंत्रियों की आठवीं बैठक 19-21 अक्तूबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। अप्रैल 2010 में 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को शीर्षक के रूप में पारित करने के भूटान सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए बैठक में जैव विविधता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर भारत द्वारा परिचालित अवधारणात्मक लेखों पर आधारित क्षेत्रीय परियोजनाओं का पता लगाने के लिए सदस्य देशों को निर्देश देते हुए पर्यावरण पर दिल्ली वक्तव्य जारी किया गया तथा भारत सरकार की सहायता से सार्क सदस्य देशों में अग्रिम तूफान चेतावनी प्रणाली हेतु 50 मौसम केन्द्रों की स्थापना पर चर्चा की गई, जिसकी शुरुआत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से की जाएगी। सदस्य देशों के विचारार्थ भारत द्वारा मसौदा क्षेत्रीय पर्यावरण संधि भी परिचालित की गई। कोपनहेगन शिखर सम्मेलन के सम्मुख यूएनएफसीसीसी सचिवालय को सार्क के सदस्य देशों की तरफ से प्रस्तुत 'जलवायु परिवर्तन पर सहयोगी स्थिति ' में सार्क की संवर्द्धित सहक्रिया को भी अभिव्यक्ति प्राप्त हुई।

सभी सदस्य देशों के सार्क मंत्रिमंडलीय सचिवों की 13-14 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में बैठक हुई तथा उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक में क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से उन क्षेत्रों पर सूचना और श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान-प्रदान किया गया, जहां सार्क में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार पहल की गई है। सदस्य देशों ने निष्पादन प्रबंधन तथा मूल्यांकन और सूचना प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठ प्रथाओं के आदान-प्रदान पर दो अवधारणात्मक लेखों के भारत द्वारा प्रस्तुतिकरण को प्रशंसा के साथ नोट किया तथा संवर्द्धित सहयोग के लिए इच्छा प्रकट की।

अन्य सार्क तंत्रों की बैठकों के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया जैसे एसएयू (दिल्ली, 7-9 जनवरी, 2010) की स्थापना संबंधी पांचवीं सार्क अन्तर सरकारी संचालन समिति की बैठक तथा पर्यावरण (दिल्ली, 18-19 जनवरी, 2010) पर मसौदा सार्क संधि पर बातचीत करने के लिए बैठक। 8-10 फरवरी, 2010 को काठमाण्डू में आयोजित होने वाले सेवाओं में व्यापार संबंधी मसौदा सार्क करार को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आगामी बैठक के दौरान अधिक व्यापार उदारीकरण प्राप्त किए जाने की सम्भावना है। 1-2 फरवरी, 2010 को काठमाण्डू में आयोजित होने वाली बैठक में मोटर वाहन और रेलवे संबंधी सार्क क्षेत्रीय करारों पर बातचीत करने के लिए प्रथम विशेषज्ञ समूह की बैठक में क्षेत्र में श्रेष्ठ परिवहन सम्बद्धता को परिचालित करने के लिए सदस्य देशों के संकल्प पर विचार किया जाएगा। क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के विषय को 3-5 फरवरी, 2010 को काठमाण्डू में आयोजित होने वाली एसडीएफ के शासी बोर्ड की सातवीं बैठक में उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सार्क गृह मंत्रियों की तीसरी बैठक तथा इसकी अनुवर्ती बैठकें 16-20 फरवरी, 2010 को इस्लामाबाद में आयोजित की जायेंगी तथा इसमें पुलिस सहयोग, मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार को समाप्त करने, आप्रवासन तथा अन्य सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा की जाएगी।

सार्क क्षेत्र में लोगों में आपस में गतिविधियों में क्रमिक वृद्धि हुई है। भारत ने नई दिल्ली में द्वितीय सार्क बैन्ड उत्सव, आगरा में सार्क साहित्य उत्सव तथा चंडीगढ़ में द्वितीय सार्क लोकगीत उत्सव की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इसके अतिरिक्त, भारत ने दूर चिकित्सा, दूर-शिक्षा, पर्यावरण सापेक्ष परियोजनाओं जैसे सौर ग्रामीण विद्युतीकरण, वर्षाजल संचयन, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, भारत केन्द्र के रूप में तथा सदस्य देश विकेन्द्र के रूप में, केन्द्र व विकेन्द्र दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए दलहन की शटल ब्रीडिंग के क्षेत्रों में परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है। परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है। सदस्य देशों के बीच बढ़ती आर्थिक अंतर निर्भरता के साथ सार्क निस्संदेह दक्षिण एशिया में संवर्धित आर्थिक सहयोग के महत्वपूर्ण संवाहक के रूप में रूपांतरित हो जाएगा।

■■

13 तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग तथा विकास भागीदारी

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आइटेक) कार्यक्रम और अफ्रीका कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता (स्केप), जो अनुभवों के आदान-प्रदान, प्रौद्योगिकी के अंतरण तथा क्षमता निर्माण पर केन्द्रित है, विकासशील विश्व के साथ भारत की विकास भागीदारी और सहयोग के महत्वपूर्ण घटक बने रहे। विभिन्न देशों में इन सहकारी क्रियाकलापों की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता की झलक आइटेक कार्यक्रम, जिसने विकासशील देशों में एक ब्रांड नाम प्राप्त कर लिया है, में सहभागियों की बढ़ती सहायता से मिलती है। वर्ष 1964 में छोटे स्तर से शुरू होकर विगत वर्षों में आइटेक का विस्तार हुआ है और यह आज सहयोग के विविध क्षेत्रों में अपने आपको प्रकट करते हुए भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम का एक मुख्य घटक और गतिशील हिस्सा बन गया है। यह मांगपरक और उत्तर-उन्मुखी है। वर्तमान में 158 आइटेक/स्केप सहभागी देश हैं। (परिशिष्ट-XIV में सूची संलग्न है)

आइटेक और स्केप असैनिक तथा रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत में सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारी संख्या में भागीदारों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। मौजूदा आइटेक वेबसाइट को पुनः अभिकल्पित और नए वेब पतेः itec.mea.gov.in पर सक्रिय किया गया है। अब यह और अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बन गया है और आइटेक सहभागियों की आवश्यकताओं के प्रति उसे आसान बनाने के लिए विशेष रूप से लक्ष्य किया गया है, ताकि वे पैनलबद्ध संस्थानों और अनुमोदित पाठ्यक्रमों से संबंधित विवरण प्राप्त कर सकें और फार्म इत्यादि डाउनलोड कर सकें। 158 आइटेक/स्केप सहभागी देशों की सहभागी सरकारों के साथ-साथ पाठ्यक्रम में रूचि रखने वाले उम्मीदवारों दोनों के लिए संदर्भ दस्तावेज के रूप में एक ब्रोशर-आइटेक/स्केप पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण संस्थानों के वार्षिक संकलन प्रकाशित किए गए। विदेश स्थित मिशनों में आयोजित वार्षिक 'आइटेक दिवस' समारोह के जरिए पूर्व विद्यार्थियों के नेटवर्क को प्रोत्साहित किया गया।

असैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2009-10 के दौरान 158 विकासशील देशों को उनके हित और लाभ के क्षेत्रों में लगभग 5000 असैनिक प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किए गए। असैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसके पैनल में 42 संस्थाएं हैं और इसके तहत कार्यरत व्यावसायिकों के लिए व्यापक आधार वाले एवं विभिन्न प्रकार के कौशलों एवं विषयों पर मुख्य रूप से 200 अल्पकालिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए। सबसे अधिक लोकप्रिय सूचना प्रौद्योगकी एवं भाषा विज्ञान (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम रहे। सरकारी अधिकारियों को वित्त एवं लेखा, लेखा परीक्षा, बैंकिंग, शिक्षा, आयोजना एवं प्रशासन, संसदीय अध्ययन, अपराध रिकार्ड इत्यादि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किए गए। अन्य ने वस्त्र, ग्रामीण विद्युतीकरण, उपकरण डिजाइन तथा नेत्र विज्ञान उपकरण जैसे तकनीकी/विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सेवाओं का सदुपयोग किया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, एसएमई और उद्यम विकास से जुड़े सामान्य पाठ्यक्रमों ने भी सहभागियों का ध्यान आकर्षित किया। (विदेश मंत्रालय के आइटेक एवं स्केप कार्यक्रमों के अंतर्गत असैनिक पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाली संस्थाओं की सूची परिशिष्ट-XV पर है।)

आइटेक कार्यक्रम अनिवार्य तौर पर द्विपक्षीयता पर आधारित है। तथापि, विगत कुछ वर्षों से आइटेक कार्यकलापों के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और इसके दायरे में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों को भी लाया गया है। इन संगठनों और समूहों में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान), जी-15, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिमस्टेक), मेकोंग गंगा सहयोग (एमजीसी), अफ्रीकी संघ (एयू), अफ्रो-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ), पैन अफ्रीकी संसद, कैरिबियन समुदाय (कैरिकॉम), राष्ट्रमंडल और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) शामिल हैं।

वर्ष 2008 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई और आइटेक भागीदार देशों से प्राप्त अनुरोधों के उत्तर में वर्ष के दौरान निम्नलिखित विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए गएः(i) श्रीलंकाई अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं अंग्रेजी प्रवीणता पाठ्यक्रम (ii) अफगानिस्तान के लिए 'ग्रामीण विकास, प्रबंधन और सुशासन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर विशेष पाठ्यक्रम (iii) अफ्रीका के लिए 'खनिज अन्वेषण' पर विशेष पाठ्यक्रम (iv) अफ्रीका के लिए 'सुदूर संवेषण तथा डिजीटल छवि प्रसंस्करण' पर विशेष पाठ्यक्रम (v) घाना के लिए ' मादक पदार्थ कुत्ता प्रशिक्षण' पर विशेष पाठ्यक्रम (vi) 6 सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग पर विशेष पाठ्यक्रम (vii) नामिबीया के लिए भूवैज्ञानिक जवार मॉडयूल के लिए आरियूंटेशन पाठ्यक्रम पर विशेष पाठ्यक्रम (viii) पैन-अफ्रीकी डाक संघ के सदस्यों के लिए 'डाकपालों तथा प्रबंधकों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम 'विषय पर विशेष पाठ्यक्रम (ix) 'वायु टरबाइन प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोग' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा (x) अफ्रीका के लिए 'भौगोलिक सूचना प्रणाली' पर विशेष पाठ्यक्रम।

रक्षा प्रशिक्षण

रक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ती रुचि का पता इस बात से चला कि रक्षा सेवा के तीनों विंगों, अर्थात् सेना, नौसेना और वायुसेना ने विभिन्न रक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में 797 अधिकारियों/ प्रशिक्षुओं को स्वीकार किया, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 757 थी। इन पाठ्यक्रमों का स्वरूप सामान्य और विशेषज्ञता था और इनमें सुरक्षा तथा सामरिक अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, आर्टिलरी, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, समुद्री जल विज्ञान, उग्रवाद का मुकाबला तथा जंगल युद्ध कला शामिल थे, साथ ही इसमें तीनों सेनाओं के युवा अधिकारियों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम शामिल थे। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज तथा रक्षा सेवा स्टॉफ कॉलेज, वेलिंगटन के लिए निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और विकसित देशों के अधिकारियों ने भी स्व-वित्तपोषण आधार पर उनमें भाग लिया। उत्तरोत्तर बढ़ते इस क्रियाकलाप से भारत में रक्षा प्रशिक्षण को विकासशील एवं विकसित देशों द्वारा दिए जाने वाले महत्व का पता चलता है। रक्षा सेवा स्टॉफ कॉलेज के लिए स्थानों के वितरण को अंतिम रूप दिया गया और इसकी सूचना संबंधित मिशनों को संप्रेषित की गयी।

विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध पर असैनिक एवं रक्षा क्षेत्र में 40 विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किए गए जो सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा परीक्षा, विधिक सुविज्ञता, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों, फार्माकालोजी, सांख्यिकी एवं जनसंख्या विज्ञान एवं लोक प्रशासन तथा वस्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सलाह देने और सुविज्ञता प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्त हैं। लाओस, लेसोथो, सेशल्स, जांबिया , इथोपिया तथा मंगोलिया जैसे देशों द्वारा प्रशिक्षण तथा सलाहकारी क्षमता में रक्षादलों की सेवाएं प्राप्त की गयीं।

अध्ययन दौरे

(1) इथोपिया के अनुरोध पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के दो विशेषज्ञों को इथोपियाई राजस्व तथा सीमा शुल्क प्राधिकरण (ई.सी.आर.ए.) का सीमा शुल्क डाटा बेस तैयार करने में मदद के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

(2) केन्या के अनुरोध पर, एक 3-सदस्यीय केनियाई प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया।

(3) इण्डोनेशियाई सरकार के अनुरोध पर, जल प्रबंधन के क्षेत्र में आईआईटी, रुड़की से एक विशेषज्ञ ने इण्डोनेशिया का दौरा किया।

परियोजना भागीदारी तथा परियोजना सहयोग

वर्ष 2009-10 में विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और लघु एवं मझौले उपक्रमों, सिविल विनिर्माण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक द्विपक्षीय परियोजनाएं चलाई गयीं। द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं में मुख्यतः आवश्यक भौतिक अवसंरचना की स्थापना तथा क्षमता निर्माण पर बल दिया गया, जिससे कि इन परियोजनाओं की दीर्घावधिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

क्रियान्वयनाधीन मुख्य परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैः

(1) लाओस में वैट फोऊ मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की है। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के एक दल ने परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना स्थल पर अपना शिविर डाल दिया है।

(2) लाओस में सूचना प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने की एक परियोजना ने काफी प्रगति की है और पूरा होने के कगार पर है।

(3) एसेह, इण्डोनेशिया में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए परियोजनाओं को एच.एम.टी (आई) को सौंपा गया है और परियोजना का कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

(4) एसेह, इण्डोनेशिया में एक प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किया गया। भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज से प्राप्त व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट को इण्डोनेशिया प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है।

(5) अल सल्वाडोर, होंडूरस तथा निकारागुआ में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित किया गया है। ये केन्द्र अपने पूरा होने के अंतिम चरण में है। ऐसा ही एक केन्द्र जमैका में स्थापित किया गया है और प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण कार्य शुरू हो गया है। इक्वेडोर, कोस्टारिका तथा बेनिन में आईटी केन्द्रों को स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य इन देशों में क्षमता निर्माण करना तथा आईटी अवसंरचना का संवर्धन करना है।

(6) जिम्बाब्वे में लघु व मझौले उपक्रमों (एस.एम.ई.) के क्षेत्र में एक परियोजना पूरा होने के अग्रिम चरण में है। जिम्बाब्वे के कार्मिकों के कार्य पर प्रशिक्षण का अंतिम चरण शुरू हो गया है।

व्यवहार्यता अध्ययन

एंटिगुआ और बरबुडा में मल व्यवस्था संयंत्र के लिए हैदराबाद जल आपूर्ति और मल व्यवस्था बोर्ड द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है और व्यवहार्यता अध्ययन की रिपोर्ट एंटिगुआ और बरबुडा सरकार को सौंपी गई।

अवसंरचना परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कई अन्य परामर्श सेवाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, विशेष रूप से

एक गहरे पानी के बंदरगाह के निर्माण के साथ-साथ स्पंज लौह एवं इस्पात उत्पादन के खनन से संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन दोनों ही गुयाना और मांटिनीग्रो के एक संचार नेटवर्क की स्थापना करना।

आपदा राहत के लिए सहायता

भारत ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित विभिन्न देशों के लिए तत्काल राहत सहायता प्रदान की। भूकंप, चक्रवातों और बाढ़ इत्यादि से प्रभावित लेबनान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, म्यांमा, बूर्किना फासो, अल-सलवाडोर, गुयाना तथा हैती जैसे देशों को मानवीय सहायता प्रदान की गयी। आग से क्षतिग्रस्त अस्पताल के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए सेंट लुसिया से प्राप्त अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है।

■■

निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन 14

श्रृंखलाबद्ध ऋण

राजनयिक रणनीति के भाग के रूप में भारत सरकार अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा एशिया में विकासशील देशों को रियायती श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान करती है। द्विपक्षीय सहयोग का संवर्धन करने के उद्देश्य से ये श्रृंखलाबद्ध ऋण सस्ते ऋण के रूप में हैं, जिससे ऋण प्राप्त करने वाले देश को ढांचागत विकास तथा क्षमता निर्माण परियोजनाएं शुरू करने में सहायता मिलती है।

भारत सरकार ने अब तक विभिन्न विकासशील देशों को 5.02 बिलियन अमेरिकी डालर के 123श्रृंखलाबद्ध ऋण प्रदान किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 22 जनवरी, 2010 तक 1.03 बिलियन अमेरिकी डालर के 25 श्रृंखलाबद्ध ऋण अनुमोदित किए गए हैं। इसमें श्रीलंका को रेलवे परियोजना के लिए 492 मिलियन अमेरिकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण, तिशरीन विद्युत परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए सीरिया को 100 मिलियन अमेरिकी डालर के श्रृंखलाबद्ध ऋण, ग्रोडनो-II विद्युत संयंत्र के पुनर्निर्माण के लिए बेलारूस को 60 मिलियन अमेरिकी डालर तथा सूचना प्रौद्योगिकी व लाईवस्टाक वैक्सीनेशन के लिए मंगोलिया को 20 मिलियन अमेरिकी डालर का श्रृंखलाबद्ध ऋण शामिल है। शेष राशि अंगोला, बेमिन, बुर्किनाफासो, केप वार्डे, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इरीट्रिया, आइवरी तट, लिसाथो, माली, मारीटेनिया, रवाण्डा, सेनेगल, सेशल्स, सियरा लियोन, स्वाजीलैंड, सुरीनाम, व तंजानिया जैसे अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी देशों को आबंटित की गई है। अनुमोदित परियोजनाओं में सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे, कृषि, जल आपूर्ति, विद्युत उपार्जन, औद्योगिक पार्क इत्यादि विस्तृत प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं।

श्रृंखलाबद्ध ऋणों से न केवल प्राप्तकर्ता देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा भारत के लिए पर्याप्त सौहार्द स्थापित करने में सहायता मिली है, बल्कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में हमारी बढ़ती आर्थिक शक्ति का अनुमान लगाने में भी सहायता मिली है तथा भारतीय कंपनियां वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए परियोजना संविदा व आदेश प्राप्त कर सकी हैं। कई बार इन आदेशों से भारतीय कंपनियों को पूर्णतया वाणिज्यिक आधार पर अतिरिक्त व्यापार अर्जित करने में सहायता मिली है।

जिन देशों के पास श्रृंखलाबद्ध ऋण के अंतर्गत सक्षम परियोजनाएं अभिज्ञात करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है, उनकी सहायता करने हेतु उन्हें परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

आईटीपी प्रभाग श्रृंखलाबद्ध ऋण का सक्षम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, एग्जिम बैंक तथा भारतीय मिशनों के साथ मिलकर कार्य करेगा। अधिक सक्षमता तथा पारदर्शिता शुरू करने के लिए श्रृंखलाबद्ध ऋण से संबंधित भारत सरकार की नीति की समीक्षा करने का प्रयास भी किया गया है।

निवेश व व्यापार संवर्धन

आईटीपी प्रभाग विदेश स्थित वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के कार्यपालन का विस्तृत अध्ययन करता है, ताकि उन्हें प्रभावशाली व भारतीय उद्योग व व्यापार की बढ़ती मांग के अनुकूल बनाया जा सके। यह नोट करते हुए कि वित्तीय संसाधन भारी कठिनाइयों को पैदा करते हैं, यह निर्णय लिया गया है कि उनके द्वारा संचालित द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा के आधार पर 2009-10 के दौरान भारतीय मिशनों को 9.09 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आबंटित की जाए। इस राशि का उपयोग वाणिज्यिक प्रकोष्ठों द्वारा बाजार सर्वेक्षणों सहित बाजार विस्तार कार्यकलापों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, क्रेता-बिक्रेता समारोहों इत्यादि को आयोजित करने के लिए किया जाता है। मिशनों से प्राप्त कई प्रवर्तनकारी प्रस्तावों को इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है।

आईटीपी प्रभाग ने नीतिगत निविष्टियां प्रदान करने के लिए वाणिज्य, वित्त, नागरिक उड्डयन, नौवहन मंत्रालयों तथा विदेशी निवेश व व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए आरबीआई, एग्जिम बैंक व एफआईसीसीआई, सीआईआई इत्यादि जैसे प्रमुख औद्योगिक संगठनों के साथ संपर्क जारी रखा है। इसने व्यापार संवर्धन निकायों व आगन्तुक प्रतिनिधिमंडलों के बाह्य अंतरापृष्ठ में उनकी सहायता की है। वर्ष के दौरान सजातीय औषधियों, उर्वरकों व रेलवे सुविधाओं से संबंधित व्यापार व निवेश मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाया गया था।

आईटीपी प्रभाग ने अपने व्यापार संवर्धन कार्यकलापों का समर्थन करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित चुनौती कोष के अंतर्गत मिशनों से प्राप्त प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य किया है। इसने तुर्की में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन वार्ता सम्मेलन में 17 देशों के साथ विचार-विमर्श सहित नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित द्विपक्षीय नागरिक उड्डयन वार्ता में भाग लिया है।

आईटीपी प्रभाग ने मार्च, 2009 में भारत-चीन 'संकट पश्चात विश्व में एशियाई शताब्दी के संचालक ' पर एक सम्मेलन

आयोजित करने में सीआईआई की सहायता की थी। यह फरवरी, 2010 में दूसरे भारत-अरब निवेश परियोजना कनक्लेव के आयोजन में भी एफआईसीसीआई को सहयोग देगा।

इस मंत्रालय की वेबसाईट www.indiainbusiness.nic.in जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश व व्यापार अवसरों के साथ-साथ महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकों पर अद्यतन आंकड़ों से संबंधित व्यापक सूचना प्रदान करती है, का बेहतर तरीके से समुन्नयन व पुनर्गठन किया गया है, ताकि इसे और उपभोक्ता अनुकूल बनाया जा सके। आईटीपी प्रभाग के वार्षिक प्रकाशन अर्थात 'इण्डिया डायनामिक बिजनेस पार्टनर' का अद्यतन संस्करण तैयार किया जा रहा है। यह विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों को भेजा जाएगा। सीडी रोम सहित यह प्रतियां संभावित निवेशकों को भारत में क्षेत्रवार व राज्यवार निवेश अवसरों का विवरण प्रदान करती हैं।

■■

ऊर्जा सुरक्षा

15

सितंबर, 2007 में विदेश मंत्रालय के आईटीपी प्रभाग में एक ऊर्जा सुरक्षा एकक का सर्वप्रथम गठन किया गया था। ऊर्जा आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऊर्जा सुरक्षा विषयों के बढ़ते संदर्भ के चलते 2009 में ऊर्जा सुरक्षा एकक का एक समग्र प्रभाग के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया।

इस नए विषय के प्रभाग ने यूएनजीए, जी-20, नाम, बीआरआईसी, एएसईएम, आईबीएसए, पूर्व एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, सीआईसीए, कॉमनवेल्थ आदि जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में ऊर्जा सुरक्षा मामलों पर भारत की स्थिति को सुस्पष्ट करने के लिए सूचना उपलब्ध करवाई। प्रभाग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत्रों पर प्रथम वैश्विक निकाय अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (इरेना) के साथ देश को जोड़ने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग ऊर्जा सक्षमता व सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता में भारत की सदस्यता के साथ निकट रूप से जुड़ा है तथा इसने विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता क्लब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ हमारे बढ़ते संपर्कों का मार्गदर्शन भी किया है।

ऊर्जा संबंधी मामलों पर मंत्रालय के नोडल प्रभाग के रूप में प्रभाग ने ऊर्जा क्षेत्र के मंत्रालयों के साथ निकट समन्वय स्थापित किया हुआ है तथा ऊर्जा संबंधी मामलों पर उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुविधाजनक बनाया है। दिसंबर, 2009 में द्वितीय भारत-अफ्रीकी हाइड्रोकार्बन्स सम्मेलन आयोजित करने में सहायता प्रदान की गई थी। प्रभाग ने ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनौपचारिक कार्य समूह के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के तेल व अवसंरचना संबंधी उद्यमों के साथ समन्वय स्थापित करना जारी रखा।

ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग गैर-सरकारी क्षेत्र सहित ऊर्जा सुरक्षा पर देश के सभी हितधारकों में शामिल हो गया है। जैव-डीजल, इथोनॉल इत्यादि पर गहमागहमीपूर्ण सत्र आयोजित करने के बाद ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियों को शामिल करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित मामलों पर निगमों, चैम्बरों व विचार केन्द्रों को परामर्श दिया गया था। ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित संगोष्ठियों की सह-अध्यक्षता की गई थी तथा ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित विषयों पर कागजात तैयार किए गए थे।

■■

16 नीति आयोजना और अनुसंधान

नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग की मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं - विदेश नीति और वैश्विक कार्यों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं और अध्ययनों को प्रक्रियागत करना, भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित विषयों को देखने वाले विचारकों, अनुसंधान निकायों, विश्वविद्यालयों आदि का डाटा बेस तैयार करना/उसको अद्यतन करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) तथा इसके सम्बद्ध और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान में विशेषज्ञता प्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों के साथ विचार विनियम करना तथा जब भी निर्देश हो मंत्री/राज्य मंत्री के लिए मसौदा तैयार करना। इसके अतिरिक्त, नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग, मंत्रिमंडल और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए महीने के महत्वपूर्ण घटनाक्रम का मासिक सार तैयार करता है और प्रेषित करता है। प्रभाग समयबद्ध तरीके से विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट संकलित, सम्पादित, मुद्रित तथा वितरित भी करता है। यह रिपोर्ट शेष विश्व के साथ भारत के संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर सरकार के दृष्टिकोण के सार संग्रह के रूप में है। प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इंडिया-2010 के 'भारत और विदेश' पाठ हेतु सामग्री को समन्वित और संकलित करता है।

इस अवधि के दौरान अगस्त, 2009 में मिशन प्रमुख सम्मेलन का आयोजन इस प्रभाग का एक मुख्य कार्यकलाप है, जिसमें लगभग 120 राजदूतों व उच्चायुक्तों ने भाग लिया था। मिशन प्रमुखों को उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा, वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा, प्रवासी भारतीय कार्यमंत्री श्री व्यालार रवि, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ0 मोंटेक सिंह आहलूवालिया, विदेश राज्य मंत्री डॉ0 शशि थरूर, विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रेनीत कौर, प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री श्याम शरन, राज्य सभा सदस्य व आईआईसी की अध्यक्षा श्रीमती कपिला वात्स्यायन तथा विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने सम्बोधित किया।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हित परियोजना (एन आई पी) का वित्त पोषण व मानीटरन पी पी एडं आर प्रभाग द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय हित परियोजना पहले ही पूरी कर ली गई है तथा महत्वपूर्ण मुद्दों, जिनका भारत के राष्ट्रीय हितों व विदेश नीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, पर लगभग 20 दस्तावेज तैयार किए गए हैं।

नीति नियोजन प्रभाग ने कोलकाता विश्वविद्यालय में विदेश नीति अध्ययन संस्थान की स्थापना का सह समन्वय व अनुवीक्षण किया है, जिसकी स्थापना विदेश मंत्रालय की वित्तीय सहायता से की गई थी। इसके कार्यक्रमों में एम फिल पाठ्यक्रम शुरू करना तथा पूर्व एशिया व दक्षिण एशियाई देशों पर केन्द्रित भारत की विदेश नीति संबंधी अनुसंधान/परियोजना शुरू करना शामिल है। नीति नियोजन व अनुसंधान प्रभाग को मंत्रालय के एम ई आर प्रभाग के साथ मिलकर आईओआर-एआरसी (क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत-हिन्द महासागर परिधि संघ) पर परियोजना दस्तावेज तैयार करने के लिए अधिदेश प्राप्त है।

इस अवधि के दौरान चीन व जापान के साथ विदेश नीति संबंधी विचार-विमर्श आयोजित किए गए थे। दोनों अवसरों पर संयुक्त सचिव पी पी एंड आर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

इस अवधि के दौरान नीति नियोजन व अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित सम्मेलनों, संगोष्ठियों व अध्ययनों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग, स्थिति कक्ष व सीमा कक्ष के कार्य की देखरेख भी करता है। उनके सभी प्रशासनिक मुद्दों और वास्तविक कार्यों की देखरेख इस प्रभाग द्वारा की जाती है। यह प्रभाग हमारे देश में आने वाले विदेशी प्रकाशनों में भारत की बाह्य सीमाओं के सीमाकंन की जांच करने के लिए उत्तरदायी था तथा इसने इस मामले से संबंधित मंत्रालयों को अपनी सलाह भी प्रदान की है। इसने कई सरकारी व उप-सरकारी कार्यालयों तथा अनुसंधान विद्वानों को भारत के सर्वेक्षण के साथ उनके सरकारी कार्य में उपयोगी मैप शीट की आपूर्ति भी समन्वित की है। यह प्रभाग अनुसंधान विद्वानों से मंत्रालय के पुराने रिकार्ड देखने के अनुरोध से संबंधित कार्य भी करता है।

सीमा कक्ष

पी पी एंड आर प्रभाग के भाग के रूप में स्थापित सीमा कक्ष के कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) भारतीय सर्वेक्षण के समन्वय से भारत की सीमाओं की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित भारत की बाह्य सीमाओं के सभी पहलुओं की जांच करना तथा प्रकाशन हेतु मैप शीटों की जांच करना।

(ख) क्षेत्रीय प्रभागों को सीमा संबंधी मामलों पर मानचित्र संबंधी सलाह और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना।

(ग) उपलब्ध मानचित्र संबंधी सामग्री/आधारिक मानचित्रों के एकत्रीकरण, मिलान और उनको डिजीटल बनाने में सहायता करना।

(घ) भारतीय सर्वेक्षण व राज्य सरकारों के साथ सीमा स्तंभों की मरम्मत/अनुरक्षण तथा भारतीय भूभाग (डाटा बेस आदि का अनुरक्षण) में किसी अतिक्रमण संबंधी रिपोर्टों सहित संयुक्त सीमा सर्वेक्षण कार्य के संबंध में सम्पर्क करना।

(ङ) समुद्री सीमा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई ई जैड) से संबंधित सूचना के एकत्रीकरण और उसको डिजीटल बनाने तथा महाद्वीपीय शैल्फ के रेखाचित्र बनाने में सहायता करना।

(च) विकास कार्यों के प्रयोजन के लिए विभिन्न सरकारी व उप-सरकारी संगठनों द्वारा अनुरोधित प्रतिबन्धित मानचित्रों की रक्षा मंत्रालय के सहयोग से जांच करना।

(छ) नौसैनिक जल विज्ञान कार्यालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ सम्पर्क करना।

(ज) भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में सभी मानचित्रों, दस्तावेजों और सूचना के संग्राहक के रूप में कार्य करना।

(झ) विदेश पत्र-पत्रिकाओं और मानचित्रों में प्रकाशित गलत मानचित्रों की जांच करना तथा इन मानचित्रों को ठीक करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

सीमा कक्ष ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय भू-भाग तथा समुद्री सीमा पर विभिन्न आंतरिक/अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया, जोकि निम्नलिखित हैं:

(क) भारत की बेसलाइन प्रणाली पर अंतर-मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।

(ख) भारत की बेसलाइन प्रणाली के लिए राजपत्र अधिसूचना के लिए निविष्टियाँ प्रदान की।

(ग) सर्वेक्षण व मानचित्रण प्रवृत्ति व प्रौद्योगिकी के संबंध में भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए व्याख्यान आयोजित करना तथा क्षेत्रीय कार्यों के लिए सीमा कक्ष व भारतीय सर्वेक्षण के दौरे आयोजित करना।

(घ) देहरादून में भारत-नेपाल सीमा पर तकनीकी स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय सीमा (जमीनी व समुद्री) के विभिन्न पहलुओं पर भू-भाग संबंधी सभी प्रभागों को मानचित्र संबंधी व तकनीकी निविष्टियां प्रदान की।

(च) उत्तरी प्रभाग के लिए भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट गंडक बॉध परियोजना की अवस्थिति को अधिप्रमाणित करना।

(छ) कृष्णा गोदावरी तट पर सर्वेक्षण व गवेषण कार्यकलापों पर सेवा कर लागू करने का आधार सुनिश्चित करने के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद आसूचना महानिदेशालय, अहमदाबाद आंचलिक इकाई को जवाब देने के लिए एफएसओ को संबद्ध निविष्टियां सहित टिप्पणियों प्रदान कीं।

(ज) गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित असम-नागालैण्ड सीमा बैठकों में भाग लिया तथा बी एस एम प्रभाग को संबंधित सूचना और मानचित्रों की आपूर्ति की।

(झ) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के भाग के रूप में भारत-भूटान सीमा वार्ता पर सरकारी स्तरीय बैठक में भाग लेना।

(ञ) पी पी एंड आर प्रभाग के माध्यम से भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संबंध में ओ एस एम और डी एस एम मानचित्रों का अधिप्रमाणन।

(त) भारत की बाह्य सीमा सहित सीमावर्ती इलाकों के मानचित्र हेतु डाटाबेस तैयार करना।

(थ) सीमावर्ती इलाकों के मानचित्र का अभिलेखीकरण करना व उनको डिजीटल बनाना।

(द) भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित स्थलाकृति संबंधी मानचित्रों का डिजीटल व हार्ड प्रति के रूप में अभिलेखीकरण।

स्थिति कक्ष

सामान्य

सामान्य स्थिति कक्ष मंत्रालय का बहु-आयामी, बहु-सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक परिसर है। 2007 में स्थापित इस कक्ष में अपेक्षित संचार सम्पर्क तथा डिस्प्ले पैनलों की व्यवस्था है, जोकि किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपेक्षित हैं। मंत्रालय के संकट प्रबंधन कक्ष के रूप में इसकी मुख्य भूमिका के अलावा इसका उपयोग सभी प्रभागों द्वारा टेलीफोन/वीडियो कांफ्रेसिंग आदि सहित प्रस्तुतिकरणों व सम्मेलनों जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रभावशाली ढंग से किया जाता है।

भूमिका

स्थिति कक्ष की भूमिका निम्नानुसार हैः-

(क) मिशन प्रमुखों के साथ सम्मेलन, प्रस्तुतिकरण, आवधिक ब्रीफिंग, वीडियो/टेलीफोन कांफ्रेसिंग तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा यथापेक्षित मानचित्रों तथा छवि पर विचार-विमर्श की सुविधा प्रदान करने के लिए बहुसुविधा सम्पन्न परिसर के रूप में कार्य करना।

(ख) संकट की स्थिति में संकट प्रबंधन कक्ष (नियंत्रण कक्ष) के रूप में कार्य करना।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्यकलाप

मिशनों में वीडियों कांफ्रेंसिंग सुविधा स्थापित करना। मंत्रालय में संचार के नए आयाम स्थापित करने के संबंध में विदेश सचिव की इच्छा के अनुरूप चुनिन्दा मिशनों में चरणबद्ध तरीके से वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा स्थापित की जा रही है। परियोजना के चरण-I के भाग के रूप में 2008 में छः मिशनों में सुविधा स्थापित की गई थी। इस समीक्षाधीन अवधि के दौरान परियोजना का चरण-II पूरा कर लिया गया था तथा चरण-III का कार्य पूरा किया जा चुका था। थिम्पू, वियना, काठमाण्डू तथा काबुल स्थित मिशनों में सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक निम्नलिखित मिशनों में यह सुविधा स्थापित की जा चुकी हैः

क्र.सं.	मिशन	स्थापित किए जाने का महीना
चरण-1		
1.	भारतीय राजदूतावास, पेरिस	जून, 2008
2.	भारतीय राजदूतावास, ब्रसेल्स	जून, 2008
3.	भारतीय उच्चायोग, लंदन	जून, 2008
4.	भारतीय उच्चायोग, ढाका	नवम्बर, 2008
5.	भारतीय उच्चायोग, कोलंबो	नवम्बर, 2008
6.	भारतीय राजदूतावास, बीजिंग	दिसम्बर, 2008
चरण-2		
7.	पी एम आई, यू.एन, न्यूयार्क	अप्रैल, 2009
8.	भारतीय राजदूतावास, वाशिंगटन	अप्रैल, 2009
9.	भारतीय राजदूतावास, मास्को	जून, 2009
चरण-3		
10.	भारतीय उच्चायोग, माले	जून, 2009
11.	पी एम आई, यू.एन, जिनेवा	जून, 2009
12.	सी जी आई, शंघाई	जून, 2009

■■

प्रोतोकोल

17

अप्रैल, 2009-मार्च, 2010 की अवधि के दौरान राज्य प्रमुख, उप राष्ट्रपति और सरकार प्रमुखों के स्तर के 95 दौरे (73 आने वाले और 22 जाने वाले) हुए थे। तीन देशों (बुंडी, जाम्बिया तथा जार्जिया) ने इस अवधि के दौरान निवासी मिशन खोला, जिससे नई दिल्ली में निवासी मिशनों की कुल संख्या 140 हो गई। वर्ष 2009 में मुंबई में इथोपिया और न्यूजीलैण्ड के लिए नये प्रधान कोंसलावास खोलने के लिए अनुमोदन दिए गए थे। 5 देशों को भारतीय मेट्रो शहरों में मानद वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। जनवरी, 2010 और फरवरी, 2010 माह में क्रमशः मुंबई में हंगरी के मानद कौंसुल और बेंगलुरु में आयरलैंड के मानद कौंसुल को मानद प्रधान कौंसुल में परिवर्तित किया गया। अप्रैल, 2009 से फरवरी, 2010 की अवधि में विदेशी मिशनों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 157 नए केन्द्रों का सृजन किया गया। भारत में निहित मुख्य हितों को दर्शाता है, अतिविशिष्ट व्यक्तियों का बड़ी संख्या में दौरे, नए मिशनों, कोंसलावासों और व्यापार कार्यालयों के खुलने के साथ-साथ राजनयिक मिशनों द्वारा असंख्य अतिरिक्त केन्द्रों का सृजन-विश्व के साथ भारत के सक्रिय तथा बहुमुखी संबंधों को प्रतिबिम्बित करता है ।

राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष या समकक्ष स्तर के राजकीय दौरे

क्रम सं.	सम्मानित अतिथि	तिथियां
	2009	
1.	नामीबिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री हिफिकेपुण्ये पोहामबा।	30 अगस्त-3 सितंबर
2.	मंगोलिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री साखीयागिन एलबेगदोर्ज।	13-16 सितंबर
3.	अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. क्रिस्टिना फर्नानडेजे	13-15 अक्तूबर
4.	भूटान के नरेश महामहिम श्री जीग्मे खेसर नामगयेल वांग्चूक	21-26 दिसंबर
	2010	
1.	बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना	10-14 जनवरी
2.	आईसलैंड के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ओलाफर रागनार।	11-17 जनवरी
3.	मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम दातोश्री मोहम्मद नाजीबटन अबुल रज्जाक।	19-23 जनवरी
4.	कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री ली यूण्ग बैक	24-27 जनवरी
5.	जर्मनी के राष्ट्रपति महामहिम श्री होर्सट कोल्हर	1-7 फरवरी
6.	तुर्की के राष्ट्रपति महामहिम श्री अब्दुल्लाह गुल	7-12 फरवरी
7.	नेपाल के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. राम बरन यादव	15-18 फरवरी
8.	रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री ब्लादिमीर पुतीन	12 मार्च

राज्य/सरकार/उप राष्ट्रपति तथा समकक्ष स्तर के सरकारी/कार्यकारी दौरे

	2009	
1.	भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम योनचेन जीगमी वाई. थीनले	21 जून-3 जुलाई
2.	नेपाल के प्रधानमंत्री महामहिम श्री माधव कुमार नेपाल	18-22 अगस्त

3.	डेनमार्क के प्रधानमंत्री महामहिम श्री लार्स लोक्के रसमुस्सेन	11-12 सितंबर
4.	वियतनाम के उप राष्ट्रपति मदाम म्यून थी डोन	30 सितंबर-4 अक्तूबर
5.	टोंगा के नरेश महामहिम नरेश जॉर्ज टूपोड	11 से 20 सितंबर
6.	डेनमार्क के प्रधानमंत्री महामहिम श्री लार्स लोक्के रसमुस्सेन	11-12 सितंबर
7.	तंजानिया संयुक्त गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मिजेण्गो के. पीण्डा	13-17 सितंबर
8.	स्वीडन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फ्रेडरीक रेनफेल्ड भारत यूरोप शिखर सम्मेलन	5-7 नवंबर
9.	यूरोपीय आयोग के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोसे मैनूल बरोसो-???? यूरोप शिखर सम्मेलन	6-8 नवंबर
10.	ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री महामहिम श्री केविन रुड	11-13 नवंबर
11.	स्पेन के युवराज, आस्ट्रिया के एच.आर.एच. प्रिंस फेलीप	10-12 नवंबर
12.	कनाडा के प्रधानमंत्री महामहिम श्री स्टीफेन हार्पर	15-18 नवंबर
13.	जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री यूकीमो हतोयामा	27-29 सितंबर

2010

1.	फिलीस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष महामहिम श्री मेहमूद अब्बास	11-12 फरवरी
2.	मालदीव के उप राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद वाहिद हसन	19-28 फरवरी
3.	बेल्जियम के युवराज एच.आर.एच प्रिंस फिलिप	22-26 मार्च

विदेश मंत्री और समकक्ष स्तर के सरकारी दौरे

2009

1.	संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री माननीय शेख अब्दुल्लाह बिन जायेद अल नहयान	11-12 जून
2.	कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री यू-म्यांग वान	22-24 जून
3.	राज्य सचिव, यूएसए महामहिम हिलेरी रोधाम क्लिंटन	17-21 जुलाई
4.	पापुआ न्यू गिनीया के विदेश मंत्री महामहिम सैम्यूल टी अबाल	23-29 जुलाई
5.	अफगानिस्तान के विदेश मंत्री महामहिम डॉ. रनगिन दादफर स्पाण्टा	25-29 जुलाई
6.	मालदीव के विदेश मंत्री महामहिम डॉ. अहमद शाहिद	27-30 जुलाई
7.	चीन के एसआर महामहिम श्री दाई बीनग्गूओ	6-9 अगस्त
8.	नेपाल के विदेश मंत्री महामहिम सुश्री सुजाता कोईराला	10-14 अगस्त
9.	बांग्लादेश के विदेश मंत्री महामहिम डॉ. दिपू मोनी	7-10 सितंबर
10.	ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री महामहिम श्री स्टीफेन स्मिथ	12-16 अक्तूबर
11.	कांगो के विदेश मंत्री महामहिम श्री एलिक्स थाम्बवे वाम्बा	27-30 अक्तूबर
12.	रूसी संघ सरकार के उपाध्यक्ष महामहिम श्री सर्जी सोबियानीन	8-12 नवंबर
13.	कोलम्बिया के विदेश मंत्री महामहिम श्री जेम बरमूदज मेरीजाल्दे	9-11 नवंबर
14.	दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री महामहिम श्रीमती मैते कोयना मशावने	12-16 नवंबर
15.	ईरान के विदेश मंत्री महामहिम मनोचहेर मोन्ताकी	16-17 नवंबर

16.	केप वर्डे के विदेश मंत्री महामहिम श्री जोसे ब्रीटो	18-22 नवंबर
17.	साओ तोमे तथा प्रीनसिपे के विदेश मंत्री महामहिम श्री कार्लोस टिनि	29 नवंबर से 2 दिसंबर
18.	लिथुआनिया के विदेश मंत्री महामहिम श्री व्यगौडास सैकास	2-5 सितंबर
19.	सिंगापुर के मेन्टर मंत्री महामहिम श्री ली कॉन यू	14-17 दिसंबर
20.	थाइलैंड के विदेश मंत्री महामहिम श्री कासित पिरोम्या	22-27 दिसंबर

2010

1.	माल्टा के उप विदेश मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. टोनिया बोर्ग	6-11 जनवरी
2.	हंगरी के विदेश मंत्री महामहिम डॉ. पीटर बल्ताज	17-21 जनवरी
3.	भूटान के विदेश मंत्री महामहिम योनयो म्येन शेरींग	27 जनवरी-1 फरवरी
4.	लाओ लोकतांत्रिक गणराज्य के विदेश मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. थॉग लौन सीसोलीथ	31 जनवरी-3 फरवरी
5.	बहरीन के विदेश मंत्री महामहिम शेख खालिद बिन अहमद अल-खलिफा	12 फरवरी
6.	रूस के उप प्रधानमंत्री महामहिम सरजी एस. सोबयानीन	15 फरवरी
7.	नार्वे के विदेश मंत्री महामहिम श्री जोनास गहर स्टोर	2 मार्च
8.	इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री महामहिम डॉ. एन. हसन वीराजूदा	24 मार्च

राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों/उप राष्ट्रपति व प्रथम महिला तथा समकक्ष स्तर/विदेश मंत्री के निजी/पारगम दौरे

2009

1.	थाइलैंड के युवराज एचआरएच महामहिम वजीरालैंग कोर्न	30 मई, मुंबई
2.	थाइलैंड के युवराज एचआरएच महामहिम वजीरालैंग कोर्न	30 जून, मुंबई
3.	ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री महामहिम श्री केवीन रूड	12 जुलाई, चेन्नई
4.	थाइलैंड के युवराज एचआरएच महामहिम वजीरालैंग कोर्न	15 अगस्त, मुंबई
5.	मॉरीशस के राष्ट्रपति महामहिम श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ	29 नवंबर-9 दिसंबर

2010

1.	सेशेल्स के राष्ट्रपति महामहिम श्री जेम्स एलिक्स मिशेल	8-11 जनवरी-चेन्नई
2.	भूटान की राजमाता महामहिम अशी डोर्जी वाण्गयू वाण्गचूक	18-25 जनवरी
3.	मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम श्री मोहम्मद नशीद	22-24 जनवरी, चेन्नई
4.	थाईलैंड के युवराज एचआरएच महामहिम वजिरालैगकोर्न	21 जनवरी, मुंबई
5.	डीएसडीएस के लिए स्लोवेनिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री डानीलो तुर्क	4-7 फरवरी
6.	डीएसडीएस के लिए किरीभाती गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री अनोटे टॉग	4-7 फरवरी
7.	डीएसडीएस के लिए भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जीगमी योसर थीनले	4-7 फरवरी
8.	डीएसडीएस के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मैत्ती वनहनेन	4-7 फरवरी
9.	डीएसडीएस के लिए मिस्र के हेलेनीक गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जॉर्ज पापानड्रियू	4-5 फरवरी
10.	डीएसडीएस के लिए नार्वे के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जेन्स स्टोलटेनभर्ग	4-7 फरवरी

11.	डीएसडीएस के लिए मॉरीशस के उप प्रधानमंत्री नवीकरण ऊर्जा तथा जन सुविधाएं मंत्री महामहिम डॉ. अहमद रशीद भीभीजॉन	4-7 फरवरी
12.	डीएसडीएस के लिए क्यूभेक के प्रधानमंत्री महामहिम जीन चारेस्ट	4-7 फरवरी

भारत के राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के विदेश दौरे

2009

1.	उप राष्ट्रपति का कुवैत दौरा	6-8 अप्रैल
2.	राष्ट्रपति का स्पेन और पोलैंड दौरा	20-27 अप्रैल
3.	उप राष्ट्रपति का दक्षिण अफ्रीका दौरा	8-10 मई
4.	प्रधानमंत्री का एससीओ और ब्रीक के लिए रूसी संघ दौरा	15-17 जून
5.	प्रधानमंत्री का जी-8 के लिए इटली दौरा	7-11 जुलाई
6.	प्रधानमंत्री का गुटनिरपेक्ष के लिए फ्रांस तथा मिस्र दौरा	13-17 जुलाई
7.	राष्ट्रपति का रूस और ताजिकिस्तान दौरा	2-8 सितंबर
8.	प्रधानमंत्री का जी-20 के लिए पिट्सबर्ग दौरा	23-27 सितंबर
9.	विदेश मंत्री का मास्को, रूस, ताशकंद तथा उजबेकिस्तान दौरा	20-24 अक्तूबर
10.	प्रधानमंत्री का थाईलैंड (7वां आशियान शिखर सम्मेलन) दौरा	23-25 अक्तूबर
11.	राष्ट्रपति का यू.के. तथा साइप्रस दौरा	26 अक्तूबर-1 नवंबर
12.	विदेश मंत्री का काबुल, अफगानिस्तान दौरा	18-19 नवंबर
13.	विदेश मंत्री का वाशिंगटन, यूएसए दौर	21-25 नवंबर
14.	प्रधानमंत्री का संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पोर्ट आफ स्पेन (सीएचओजीएम 26-28) दौरा	21-28 नवंबर
15.	विदेश मंत्री का पोर्ट आफ स्पेन, त्रिनिदाद व टोबैगो दौर	26-29 नवंबर
16.	विदेश मंत्री का नय पाई टाव, म्यांमा दौरा	10-11 दिसंबर
17.	प्रधानमंत्री का कोपेनहेगन (जलवायु शिखर सम्मेलन) दौरा	17-18 दिसंबर

2010

1.	उप राष्ट्रपति का जाम्बिया, मालावी, बोत्सवाना दौरा	5-12 जनवरी
2.	विदेश मंत्री का लंदन, यू.के. दौरा	26-31 जनवरी
3.	विदेश मंत्री का कुवैत दौरा	3-4 फरवरी
4.	प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा	27 फरवरी से 1 मार्च
5.	विदेश मंत्री का ईरान दौरा	30 मार्च

1.4.2009 से 31.3.2010 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष पत्र प्रस्तुत करने वाले विदेशी राजदूतों/उच्चायुक्तों की सूची

नाम	प्रत्यक्ष पत्रों की प्रस्तुती
मालदीव के उच्चायुक्त महामहिम श्री अबूल अजीज युसूफ	12 जून, 2009
जाम्बिया के उच्चायुक्त महामहिम श्री फेलीक्स बादजी	12 जून, 2009

सूडान के राजदूत महामहिम श्री अल खिदिर हारोन अहमद अब्दूलरजिया	12 जून, 2009
स्लोवाक गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री मारियन तोमासिक	15 जुलाई, 2009
सऊदी अरब के राजदूत महामहिम श्री फैजी हसन ट्राड	15 जुलाई, 2009
नाइजीरिया के उच्चायुक्त महामहिम श्री मोहम्मद घाली उमर	15 जुलाई, 2009
संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत महामहिम श्री तीमोथी जे. रोईमर	11 अगस्त, 2009
थाईलैंड के राजदूत महामहिम श्री क्रिट क्राईचिट्टी	11 अगस्त, 2009
बांग्लादेश के उच्चायुक्त महामहिम श्री अहमद तारिक करिम	11 अगस्त, 2009
पेरू के राजदूत महामहिम श्री जेवियर मैनूल पौलीनीच वलार्डे	24 सितंबर, 2009
ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त महामहिम श्री पिटर जोसेफ नूझूमूरी वारधीज	24 सितंबर, 2009
साईप्रस की उच्चायुक्त महामहिम सुश्री नफसीका चर. करोस्ती	24 सितंबर, 2009
फिनलैंड की राजदूत महामहिम सुश्री तरही हकाला	24 सितंबर, 2009
स्लोवेनिनया के राजदूत महामहिम श्री जनेज प्रिमोज	24 सितंबर, 2009
फिलीस्तीन के राजदूत महामहिम श्री अदली शबन हसन सादेक	24 सितंबर, 2009
कुवैत राज्य के राजदूत महामहिम श्री सामी मोहम्मद एसएम अल सूलैमान	24 सितंबर, 2009
पनामा के राजदूत महामहिम श्री जुलीओ दी ला गॉर्डिया अरोया	11 नवंबर, 2009
परागुए के राजदूत महामहिम श्री जेनायो विसेंट पाप्यालार्डो अयाला	11 नवंबर, 2009
सर्बिया के राजदूत महामहिम श्री जोबान मिरीलोविक	11 नवंबर, 2009
जर्मनी के राजदूत महामहिम श्री थामस मटूस्सेक	11 नवंबर, 2009
आईसलैंड के राजदूत महामहिम श्री गुडमूनडूर इरिकसन	11 नवंबर, 2009
मैक्सिको के राजदूत महामहिम श्री जैमे विरगिलियो नौलार्ट सैनचेज	20 नवंबर, 2009
मोजाम्बिक के उच्चायुक्त महामहिम श्री जोसे मारिया डी सिल्वा वीईरा मोराईस	20 नवंबर, 2009
अर्मेनिया के राजदूत महामहिम श्री अराहकोबयान	20 नवंबर, 2009
रूस के राजदूत महामहिम श्री एलेक्जेंडर मिखाइलोवीच कदाकिन	20 नवंबर, 2009
घाना के उच्चायुक्त महामहिम राबर्ट टैकी	20 नवंबर, 2009
मैसीडोनिया के राजदूत महामहिम श्री पीटर जोवानोवस्की	21 दिसंबर, 2009
नेपाल के राजदूत महामहिम श्री रुकमा शूमशेरे जेबी राना	21 दिसंबर, 2009
श्रीलंका के उच्चायुक्त महामहिम श्री प्रसाद कारियावासम	21 दिसंबर, 2009

1.04.2009 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान भारत छोड़ने वाले मिशन प्रमुखों की सूची

जर्मनी के राजदूत महामहिम श्री बर्नड मूतजेलबर्ग	28 अप्रैल, 2009
सर्बिया के राजदूत महामहिम श्री वूक जूगीक	1 मई, 2009
कुवैत राज्य के राजदूत महामहिम श्री खालफ अबास खालफ अल फौदरी	8 मई, 2009
बांग्लादेश के उच्चायुक्त महामहिम श्री लियाकत अली चौधरी	13 मई, 2009

स्लोवाक गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री ओसामा मुसा	1 जून, 2009
फिलीस्तीन राज्य के राजदूत महामहिम श्री एलेक्जेंडर इलासिक	8 जून, 2009
पेरू के राजदूत महामहिम श्री मैनूल अर्नेस्टो पीकासो नोटो	2 जुलाई, 2009
बोस्निया और हर्जेगोबिना के राजदूत महामहिम श्री केमल मफटीक	2 जुलाई, 2009
मोजाम्बिक उच्चायुक्त के महामहिम श्री कार्लोस अगोसतीनहो दो रोजारीओ	20 जुलाई, 2009
पनामा के राजदूत महामहिम श्री अल्बर्टो जे. पीनजोन एम.	30 जुलाई, 2009
रूसी संघ के राजदूत महामहिम श्री याशेसलव आई. टूबनीकोव	31 जुलाई, 2009
चेक गणराज्य के राजदूत महामहिम डॉ. हाइनेक क्मोनीसेक	5 अगस्त, 2009
ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त महामहिम श्री जॉन मैक कार्थी	10 अगस्त, 2009
अर्मेनिया के राजदूत महामहिम श्री अशोत कोचारियन	16 अगस्त, 2009
फिनलैंड के राजदूत महामहिम श्री अस्को नूम्मीनेन	19 अगस्त, 2009
साइप्रस के उच्चायुक्त महामहिम श्री एन्ड्रीयास जेनोनोस	31 अगस्त, 2009
ट्यूनिशीया के राजदूत महामहिम श्री रॉफ चैटी	1 सितंबर, 2009
कजाकिस्तान के राजदूत महामहिम श्री कैरात उमारोव	28 सितंबर, 2009
श्रीलंका के उच्चायुक्त महामहिम श्री सीआर जयसिंघे	30 सितंबर, 2009
अल-सल्वाडोर के राजदूत महामहिम श्रीमती पैट्रीसिया फिगोरा रोडरिगोज	1 अक्तूबर, 2009
अल्जिरिया के राजदूत महामहिम डॉ. नॉरेजजीन बरदार-दैदज	6 नवंबर, 2009
सीरिया अरब गणराज्य के महामहिम श्री फाहद सलीम	7 दिसंबर, 2009
अयोस्टोलीक ननसिमो अपोस्टोलीक दूतावास (होली सी के राजदूत) महामहिम आर्कबीशॉप पेडरो लोपेज क्वीनटाना	30 दिसंबर, 2009
अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के राजदूत महामहिम डॉ. सयैद मखदूम रहिन	15 जनवरी, 2010
फिलीपींस के राजदूत महामहिम फ्रॉन्सिस्को एल. बेनेडिक्टो	2 फरवरी, 2010

1.04.2009 से 31.01.2010 की अवधि के दौरान निम्नलिखित देशों ने नई दिल्ली में निवास मिशन खोला

1. बुरुण्डी
2. जाम्बिया
3. जार्जिया

वर्ष 2009 में अनुमोदित भारत में विदेशी देशों के व्यापार कार्यालयों/प्रधान कौंसलावासों/मानद कौंसलावासों की सूची

	2009 मे अनुमोदित व्यापार कार्यालय	
1.	मैक्सिको	मुंबई
2.	कनाडा	हैदराबाद, कोलकाता,अहमदाबाद
3.	ग्रीक	मुंबई
4.	इण्डोनेशिया	चेन्नई
5.	डेनमार्क	अहमदाबाद

वर्ष 2009 में अनुमोदित प्रधान कौंसलावास

1.	इथोपिया	मुंबई
2.	न्यूजीलैंड	मुंबई

वर्ष 2009 में अनुमोदित मानद कौंसलावास

1.	बेनीज	बेंगलूर
2.	डोमिनिकन गणराज्य	मुंबई
3.	अल सल्वाडोर	मुंबई
4.	इथोपिया	कोलकाता
5.	इक्वेडोर	ुंबई
6.	फिनलैंड	हैदराबाद
7.	गैबन	चेन्नई
8.	लाताविया	चेन्नई
9.	लिथुआविया	चेन्नई
10.	लक्जमबर्ग	मुंबई
11.	लाओ पी.डी.आर-	कोलकाता
12.	मैसीडोनिया	कोलकाता
13.	माल्टा	चेन्नई
14.	पारागुए	मुंबई, कोलकाता
15.	सामोआ राज्य	नई दिल्ली
16.	सेशल्स	कोलकाता, चेन्नई
17.	स्पेन	बेंगलूर
18.	सूरीनाम	मुंबई, कोलकाता
19.	मंगोलिया	बेंगालुरु

जनवरी, 2010 माह में मुंबई में हंगरी का मानद कौंसुल, मानद प्रधान कौंसुल में परिवर्तित हुआ।

फरवरी, 2010 माह में बेंगालुरु में आयरलैंड का मानद कौंसुल, मानद प्रधान कौंसुल में परिवर्तित हुआ।

अप्रैल 2009 से जनवरी**, 2010 की अवधि के दौरान भारत में विदेशी मिशनों/केन्द्रों में सृजित नए केन्द्रों का विस्तृत मासिक विवरण इस प्रकार है-**

मास	अनुमोदित नए केन्द्रों की संख्या
अप्रैल 2009	22
मई 2009	29
जून 2009	12

जुलाई 2009	13
अगस्त 2009	16
सितंबर 2009	14
नवंबर 2009	12
दिसंबर 2009	10
जनवरी 2010	4
फरवरी 2010 (22.2.2010 तक)	11
कुल	157

■■

कोंसली, पासपोर्ट और वीजा सेवाएं 18

पासपोर्ट कार्यालय

भारत में वर्तमान में 37 पासपोर्ट कार्यालय और 15 पासपोर्ट संग्रह केंद्र हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालय कंप्यूटरीकृत हैं और उनमें मशीन द्वारा मुद्रित तथा मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्ट जारी होते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नागर उड्डयन संगठन द्वारा विनिर्धारित दिशा-निदेशों के अनुसार है। पासपोर्ट आवेदनों को इलेक्ट्रानिकी विधि से स्कैन और स्टोर किया जाता है।

पासपोर्ट सेवाएं

विगत वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है। जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या में बढ़ोत्तरी को नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है:-

वर्ष	1979-80	1989-90	1999-2000	2009
जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या लाख में	8.51	15.58	25.80	50.28
%बढ़ोत्तरी	-	83%	66%	94%

37 पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा वर्ष 2008 में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या 53.10 लाख थी। तथापि, वर्ष 2009 के दौरान यह बढ़ोत्तरी स्थिर रही और इस दौरान 50.28 लाख पासपोर्ट जारी किए गए। सभी पासपोर्ट कार्यालयों से प्राप्त कुल राजस्व वर्ष 2009 में 610.10 करोड़ रुपए के लगभग था, जबकि वर्ष 2008 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति 617.23 करोड़ रुपए रही।

मंत्रालय जनता की सुविधा के लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और सरल तथा त्वरित बनाने के लिए अनेक कदम उठा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं-

(क) जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों तथा त्वरित डाक केंद्रों के माध्यम से विकेंद्रीकरण

पासपोर्ट जारी करने और उससे जुड़ी सेवाओं को आवेदकों की पहुंच के और नजदीक ले जाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ (डीपीसी) खोले गए हैं, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पासपोर्ट आवेदन प्राप्त किए जाते हैं तथा जांच और पुलिस सत्यापन के उपरांत उन्हें संबंधित पासपोर्ट कार्यालय को पासपोर्ट जारी किए जाने हेतु भेज दिया जाता है। फिलहाल 463 जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं। पासपोर्ट आवेदन 1096 त्वरित डाक केंद्रों के माध्यम से भी प्राप्त किए जाते हैं। वर्ष के दौरान चवाक्कड़ डाक घर, जिला त्रिसूर, केरल में एक और त्वरित डाक केंद्र स्थापित किया गया।

(ख) ऑनलाइन आवेदन

सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करने की व्यवस्था शुरू की गयी है। उपरोक्त जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों और त्वरित डाक केंद्रों को भी ऑनलाइन आवेदन फाइल करने और आंकड़े पासपोर्ट कार्यालयों को अनुमति दी गयी है, जिससे पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन सहज हुआ है।

(ग) अवसंरचना

वर्ष 2009 के दौरान, भुवनेश्वर स्थित पासपोर्ट कार्यालय के नवनिर्मित सरकारी भवन में स्थानांतरित किया गया। विशाखापट्टनम स्थित पासपोर्ट कार्यालय का भवन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है और कार्यालय को इसमें 2010 में स्थानांतरित किए जाने की आशा है। मुंबई स्थित नए कार्यालय का निर्माण कार्य 2010 के आरंभ में शुरू होने की आशा है।

(घ) पासपोर्टों का केंद्रीकृत मुद्रण

विदेश स्थित 140 गैर-कंप्यूटरीकृत मिशनों/पोस्टों के लिए मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2009 तक 170196 पासपोर्ट जारी किए, जो कि सीपीवी प्रभाग, नई दिल्ली में मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्टों की केंद्रीयकृत मुद्रण परियोजना के सफल कार्यान्वयन के बाद संभव हुआ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों का सम्मेलन

दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों से 16 क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों का एक सम्मेलन 10 अगस्त, 2009 को तिरुअनंतपुरम में आयोजित किया गया। उत्तरी, केंद्रीय और पूर्वी क्षेत्रों से 17 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का एक अन्य सम्मेलन 31 अक्तूबर, 2009 को कोलकाता में आयोजित किया गया। दोनों सम्मेलनों की अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर द्वारा की गयी थी।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

सभी पासपोर्ट कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के कदम उठाए गए हैं। आवेदकों की सहायता के लिए तथा शिकायतों का त्वरित निस्तारण हेतु सुविधा काउटंरों और सहायता डेस्कों की भी स्थापना की गयी है। एक लोक शिकायत निवारण तंत्र संयुक्त सचिव (सीपीवी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी की पूरी निगरानी में सीपीवी प्रभाग में भी स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी पासपोर्ट कार्यालय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की सीपीग्राम वेबसाइट के माध्यम से भी लोक शिकायतों का निस्तारण करते हैं।

पासपोर्ट अदालतें

पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट आवेदकों की शिकायतों के निस्तारण हेतु आवधिक रूप से पासपोर्ट अदालतें आयोजित की जाती हैं। ये अदालतें पुराने मामलों के निस्तारण में बहुत उपयोगी रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में एक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। प्रभाग द्वारा कुल 932 सूचना का अधिकार आवेदनों और 363 सूचना का अधिकार अपीलों को प्राप्त और निस्तारित किया गया।

वेबसाइट

1999 में स्थापित सीपीवी प्रभाग की वेबसाइट http//passport.gov.in को और अधिक प्रयोक्ता उपयोगी बनाने के लिए समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। इसमें पासपोर्ट, स्थिति पूछताछ पर विस्तृत जानकारी होती है और विभिन्न पासपोर्ट कार्यालय से जोड़ने की सुविधा तथा डाउनलोड कर सकने योग्य फार्म भी उपलब्ध हैं।

वीजा जारी किया जाना

विगत वर्षों में हमारे मिशनों और पोस्टों द्वारा वीजा दिए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है एवं उसे जारी करने की प्रक्रिया को भी कंप्यूटरीकृत किया गया है। अधिकांश मिशन और केंद्र या तो उसी दिन काउंटर पर ही या अधिक से अधिक 48 घंटे के भीतर वीजा जारी कर देते हैं।

वीजा-अधित्याग करार

भारत के 48 देशों के साथ वीजा-अधित्याग करार हुए हैं, जिसके तहत राजनयिक/सरकारी पासपोर्टधारकों को वीजा की अपेक्षा से छूट दी गयी है। चालू वर्ष के दौरान, नामीबिया के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट जारी किया जाना

सीपीवी प्रभाग द्वारा वर्ष 2009 में 2659 राजनयिक और 22594 सरकारी पासपोर्ट जारी किए गए, जबकि वर्ष 2008 में 2775 राजनयिक और 22,948 सरकारी पासपोर्ट जारी किए गए थे। सीपीवी प्रभाग द्वारा वर्ष 2009 में विदेशी राजनयिकों और सरकारी पासपोर्ट धारकों को 7173 वीजा जारी किए गए।

नई परियोजनाएं

मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट/वीजा जारी किए जाने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा उन्नत बनाने के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। ये परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

(1) ई-पासपोर्ट जारी करना

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने ई-पासपोर्ट जारी किए जाने की प्रक्रिया का 25 जून, 2009 को लोकार्पण किया, जिसे बायोमैट्रिक पासपोर्ट भी कहा जाता है। एक अग्रगामी परियोजना के हिस्से के रूप में अब सभी राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट ई-पासपोर्ट के रूप में जारी किए जाते हैं। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक द्वारा ई-पासपोर्ट बनाने के लिए आईसीएओ शिकायत इलेक्ट्रानिक संपर्क रहित इनलेज और उसकी संचालन प्रक्रिया की इलेक्टानिक संपर्क रहित इनलेज और उसकी संचालन प्रक्रिया की खरीद हेतु वैश्विक पीक्यूबी अनुप्रयोगों का मूल्यांकन 16 अक्तूबर, 2009 को शुरू किया गया। ई-पासपोर्टों के पूर्ण रोल-आउट के सितंबर 2010 तक तैयार होने की आशा है।

(2) पासपोर्ट सेवा परियोजना

सितंबर, 2007 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पासपोर्ट सेवा परियोजना शुरू की। परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट से जुड़ी सभी सेवाएं समय पर, पारदर्शी ढंग से, अधिक ग्राह्य तथा भरोसेमंद ढंग से उपलब्ध कराना है।

परियोजना के अंतर्गत पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना है, जिसके अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में अंतर्गस्त गैर-शासकीय कार्य जैसे आवेदन प्रपत्रों की शुरूआती जांच, शुल्क स्वीकार करना, दस्तावेजों की जांच-पड़ताल, फोटो लेना आदि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, सेवा प्रदाता द्वारा किए जाएंगे। संवेदनशील कार्य जैसे पासपोर्ट जारी करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से तीन दिन के भीतर पासपोर्ट जारी करने और जहां पुलिस सत्यापन वांछित है, वहां सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तीन दिनों के भीतर उसे जारी किए जाने का आशय है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर और चंडीगढ़ के अधीन सात अग्रगामी स्थलों पर परियोजना के शुरू होने की घोषणा सेवा प्रदाता द्वारा विकसित अनुप्रयोगों सॉफ्टवेयर की जांच से मंत्रालय के संतुष्ट हो जाने के बाद किए

जाने की आशा है। बाद में परियोजना को तीन चरणों में पूरे देश में लागू किया जाएगा।

(3) वीजा कार्य को बाहरी स्रोतों से करवाया जाना

विदेश स्थित पचपन भारतीय मिशनों/केंद्रों को वीजा आवेदन संग्रह कार्य को बाहरी स्रोतों से करवाने के लिए अधिकृत किया गया है। विदेश स्थित अट्ठारह (18) भारतीय मिशनों/केंद्रों ने वर्ष के दौरान बाहरी स्रोतों से यह कार्य करवाना शुरू कर दिया है। वीजा कार्य बाहरी स्रोतों से करवाने वाले विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों की कुल संख्या अब 48 (अड़तालीस) हो चुकी है।

(4) अपोस्टाइल कान्वेंशन परियोजना शुरू करना

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा 317078 निजी और शैक्षणिक दस्तावेजों तथा 227625 वाणिज्य दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त 124661 दस्तावेजों का एपोस्टाइल किया गया, ताकि उन्हें एपोस्टाइल कर चुके सदस्य देशों में उपयोग किया जा सके।

(5) प्रत्यार्पण मामले और विधिक सहायता

मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, वित्तीय जालसाजी और मादक पदार्थों की तस्करी सहित संगठित अपराध का मुकाबला करने के करार पर चर्चा के लिए विभिन्न देशों के साथ सक्रियता से कार्य कर रहा है। इन कोंसलीय करारों में प्रत्यर्पण संधियां आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता, सिविल और वाणिज्यिक मसलों में परस्पर विधिक सहायता और सजायाफ्ता कैदियों का अंतरण शामिल है।

कजाखस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 24 जनवरी, 2009 को दोनों देशों के बीच एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष के दौरान एक भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने प्रत्यर्पण, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि और सिविल तथा वाणिज्यिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि पर वार्ता के लिए मोरोक्को, अजरबेजान और इजराइल की यात्रा की। वियतनाम और बोस्निया तथा हरजेगोविना से भी सरकारी प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आए और उन्होंने भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि तथा अपराधिक मामलों में परस्पर सहायता संधि पर वार्ता की।

वर्ष के दौरान भारत से दो व्यक्तियों को ब्रिटेन तथा अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया तथा विदेशों से चार व्यक्तियों को भारत में प्रत्यर्पित किया गया। भारत सरकार ने विभिन्न देशों से चार (4) व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त किया है।

■■

19 प्रशासन और स्थापना

प्रशासन

विदेशों में 173 आवासी भारतीय मिशन एवं केंद्र हैं। समीक्षाधीन वर्ष में भारतीय दूतावास, बमाको तथा भारतीय दूतावास, नियामे नामक दो नए मिशन खोले गए। ग्वाटेमाला सिटी में एक अन्य मिशन शीघ्र ही खोला जाएगा।

मंत्रालय के प्रशासनिक तंत्र को कारगर बनाने की दृष्टि से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को और अधिक विकेंद्रित करने एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास निरंतर किए जाते हैं। गृह छुट्टी किराए से संबंधित नियमों को और उदार बनाया गया हैः तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए उसी मिशन में समायोजित अधिकारियों के लिए किरायों के एक अतिरिक्त सेट का प्रावधान किया गया है तथा एचएलएफ/ आपात यात्रा के तहत अनुमत हवाई अड्डों की सूची में पांच और स्टेशनों के नाम शामिल किए गए हैं। सर्दियों के मौसम में ऊष्मीकरण रियायतें प्राप्त करने वाले मिशनों की सूची को विस्तारित किया गया है। बाह्य-भारत छुट्टी से संबंधित नियमों को उदार बनाया गया है। छठे वेतन आयोग के आलोक में विभिन्न भत्तों को विनियमित करने वाले नियमों में संशोधन किए जाने के साथ ही विदेश स्थित भारतीय मिशनों/ केंद्रों में तैनात अधिकारियों के संबंध में संशोधित नियमों को न्यायसंगत तरीके से लागू करने के लिए मानदण्ड बनाए गए हैं। जिन मामलों में नियमों में छूट देना आवश्यक है, ऐसे मामलों में कार्रवाई की गई है और सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करके पात्र अधिकारियों को उनकी समस्याओं के प्रति मानवीय एवं कल्याणकारी दृष्टिकोण रखते हुए राहत प्रदान की गई है।

नई भर्तियों के लिए मांग समय से प्रस्तुत की गयी और सभी स्तरों पर मानव-शक्ति की तैनाती की आवधिक समीक्षा की गई। सभी मिशनों और केंद्रों में मानव-शक्ति की तैनाती की समीक्षा का व्यापक कार्य शुरू किया गया और यह अभी जारी है।

विभागीय प्रोन्नति समिति की नियमित बैठकों और संशोधित सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति योजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन के जरिए मंत्रालय में कार्यरत विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया गया।

मंत्रालय में अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल संख्या 3414 है। ब्यौरे परिशिष्ट- रू पर दिए गए हैं। ये कार्मिक भारत तथा विदेश स्थित 173 मिशनों/ केंद्रों में तैनात हैं। इसमें भारतीय विदेश सेवा (भाविसे) और भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' दुभाषिया संवर्ग, विधि एवं संधि संवर्ग तथा पुस्तकालय संवर्ग शामिल हैं, परन्तु इसमें समूह 'घ' और संवर्ग'बाह्य पद शामिल नहीं हैं।

1 अप्रैल-30 नवंबर, 2009 तक सीधी भर्ती, विभागीय प्रोन्नति और सीमित विभागीय परीक्षाओं के जरिए विभिन्न समूहों में मंत्रालय में की गई भर्ती, जिसमें आरक्षित रिक्तयों की भर्ती भी शामिल है, का ब्यौरा परिशिष्ट-।। पर है।

महिला/पुरु ष संबंधी मुद्दे

महिला/पुरुष समानता मंत्रालय की समग्र नीति का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। इसके अनुसरण में महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देकर समान अवसर प्रदान किया जाता है। मंत्रालय में निदेशक तथा इसके ऊपर रैंक के 52 अधिकारी हैं (23 मुख्यालय में तथा 29 विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में हैं) विदेश में तैनात 29 महिला अधिकारियों में से 17 मिशन प्रमुख/ केंद्र प्रमुख हैं।

विकलांग

विकलांग कार्मिकों के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करना और अपने कार्मिकों में उन्हें यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने विकलांगों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की है, जिनमें भारतीय विदेश सेवा के पद भी शामिल हैं।

स्थापना प्रभाग

स्थापना प्रभाग के कार्य में मुख्यतः परिसंपत्तियों को किराए पर लेने एवं उनके अनुरक्षण, विदेश भत्ते तथा प्रातिनिधिक अनुदान के निर्धारण, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर एवं सरकारी वाहनों की खरीद, आपूर्ति एवं अनुरक्षण, कलात्मक वस्तुओं की आपूर्ति, विदेश मंत्रालय के आवासीय परिसरों एवं हॉस्टलों के प्रबंधन एवं अनुरक्षण, तोशाखाना का रखरखाव एवं स्टेशनरी की खरीद एवं आपूर्ति शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मुद्दों को प्रशासित करने वाले नियमों, विनियमों एवं प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के प्रयास जारी रहे, ताकि उन्हें और भी सरल तथा पारदर्शी बनाया जा सके।

सूचीकरण योजना के अंतर्गत विदेश भत्ते की वार्षिक समीक्षा विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की एक संयुक्त टीम द्वारा की गई। पहली बार विभिन्न द्विपक्षीय एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए विदेशों में प्रतिनियुक्त गैर-प्रातिनिधिक अधिकारियों के लिए विदेश प्रतिपूरक भत्ते की शुरुआत की गई। संपत्ति दल ने मेलबोर्न और पोर्ट मोर्सबी का दौरा किया, जिसका उद्देश्य इन मिशनों को

बृहत्तर एवं बेहतर स्थानों में स्थानांतरित करते हुए इनकी स्थितियों में सुधार लाना था।

भारतीय मिशनों के निरीक्षण के भाग के रूप में निरीक्षकों की एक उच्चस्तरीय टीम द्वारा लिस्बन, जार्जटाउन, कराकास एवं बगोटा स्थित मिशनों का निरीक्षण किया गया। इनकी रिपोर्टों से इन मिशनों के कार्यात्मक एवं प्रशासनिक मुद्दों को सुव्यवस्थित बनाने में पर्याप्त योगदान मिला है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षणों की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाइयां भी की गई हैं।

गोल मार्केट स्थित विदेश मंत्रालय के हॉस्टल के नवीनीकरण का कार्य पूरा हो गया है। कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित हॉस्टल का ब्लाक बी और सी नवीनीकरण के लिए एनबीसीसी को सौंपा गया है। इसके फलस्वरूप, इन हॉस्टलों में रहन-सहन की स्थितियों में पर्याप्त सुधार आया है। कस्तूरबा गांधी मार्ग हॉस्टल में छः सूटों वाला नवनिर्मित ब्लॉक उपयोग के लिए पूर्णतः तैयार है, जिसका उपयोग भारत आने वाले मिशन प्रमुखों द्वारा किया जाएगा। पुष्प विहार में विदेश मंत्रालय पूल के आवासों की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। द्वारका स्थित आवासीय परिसर में रहन-सहन की स्थितियों में सुधार आने के साथ ही अब इस परिसर के 93 प्रतिशत से अधिक आवासों में लोग रह रहे हैं। विदेश मंत्रालय का चाणक्यपुरी आवासीय परिसर मार्च, 2009 में तैयार हो गया। इससे मंत्रालय के अधिकारियों की आवासीय आवश्यकता का हल ढूंढने में मदद मिली है।

उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए कलात्मक वस्तुओं के वार्षिक स्थल सत्यापन की प्रणाली शुरू की गई है। मंत्रालय में कलात्मक वस्तुओं के अंकीयकरण हेतु आरंभ किया गया कार्य अब पूर्ण होने वाला है। जिन कमरों में कलात्मक वस्तुएं रखी जाती हैं और जहां इनका आदान-प्रदान किया जाता है, उन सभी कमरों में नजर रखने के लिए सीसी टीवी कैमरे लगाए गए हैं। तोशाखाना में सभी वस्तुओं के वास्तविक सत्यापन का कार्य भी पूरा किया गया।

सरकारी वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु मिशनों के प्रत्यायोजित अधिकारों में संवर्धन किया गया है, जिससे कि इससे जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से बार-बार मंत्रालय को संदर्भित करने की प्रक्रिया में कमी लाई जा सके। कुछ चुनिंदा मिशनों को सैटेलाइट फोन मुहैया कराए गए हैं, जिससे कि आपातकालीन स्थितियों के दौरान सुचारु संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा संबंधी खतरों से बचाव के लिए उच्च जोखिम वाले कुछ चुनिंदा देशों में बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति भी की गई।

सरकार ने विदेशों में सरकारी परिसंपत्तियों तथा किराए पर ली गई परिसंपत्तियों के बेहतर रखरखाव हेतु एक नई प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे कि अनावश्यक कानूनी पचड़ों तथा सरकार को होने वाली वित्तीय हानि से बचा जा सके। इन मुद्दों से जुड़े नए नीतिगत दिशानिर्देश सभी मिशनों एवं केंद्रों को जारी किए गए। बेहतर आवासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक मिशनों में किराए की सीमा में संशोधन किया गया।

सरकारी कार्यालयों विशेष रूप से साउथ ब्लाक, अकबर भवन एवं पटियाला हाउस में स्वच्छता तथा रखरखाव की स्थिति में सुधार लाने के लिए मुख्यालय में अन्य उपाय भी किए गए। विदेश मंत्रालय के सभी कार्यालयों के लिए कार्यालय उपकरणों की खरीद और अनुरक्षण को और सुव्यस्थित बनाने के उपाय भी किए गए।

परियोजना प्रभाग

परियोजना प्रभाग विदेश मंत्रालय के उपयोग के लिए, इसके कार्यालयों एवं कर्मचारियों के आवासों हेतु भारत तथा विदेशों में भवनों के निर्माण एवं निर्मित भवनों की खरीद के लिए जिम्मेदार है। विदेशी स्टेशनों में सरकारी स्वामित्व वाले भवनों की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य भी परियोजना प्रभाग द्वारा देखा जाता है। अब तक विदेश में 77 स्टेशनों पर 80 चांसरी भवन, विदेश में 91 स्टेशनों पर मिशन/ केंद्र प्रमुखों के आवास तथा विदेश में 47 स्टेशनों पर अधिकारियें/ कर्मचारियों के लिए 635 आवास विदेश मंत्रालय के स्वामित्व में हैं। इसके अतिरिक्त 2 स्टेशनों पर सांस्कृतिक केंद्र तथा एक स्टेशन पर संपर्क कार्यालय की परिसम्पत्तियां भी सरकार के स्वामित्व में हैं। इस समय निर्माण/ पुनर्विकास/ नवीनीकरण की 53 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जहां तक विदेश में चल रही परियोजनाओं का संबंध है, भारतीय दूतावास परिसर मस्कट एवं टोक्यो (दूतावास आवास तथा अन्य आवास) के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। काबुल, काठमांडू, बीजिंग, लंदन इस्लामाबाद, सिंगापुर और बुडापेस्ट में चांसरियों और/ अथवा आवासों जैसी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है। अगले कुछ महीनों में ढाका, ब्राजीलिया, ताशकंद तथा वारसा की परियोजनाओं के भी निर्माण चरण में पहुंच जाने की आशा है। बेरुत, ब्रसेल्स एवं डब्लिन में नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। दमिस्क और पेरिस में नवीनीकरण परियोजनाओं का कार्य अगले कुछ महीने में सौंपे जाने की संभावना है।

हेम्बर्ग तथा डब्लिन में दूतावास आवास के लिए निर्मित परिसंपत्तियों की खरीद की गई है। जिन स्टेशनों में किराए की दर काफी अधिक है, वहां मंत्रालय निर्मित संपत्तियों की खरीद करने का जोरदार प्रयास कर रहा है। निर्मित परिसंपत्तियों की खरीद संबंधी प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैः हांगकांग एवं रबात में चांसरी, दुबई, बर्मिंघम, पारामारिबो, साओ पाउलो और बैंकूवर में दूतावास आवास तथा साओ पाउलो, पेरिस और वाशिंगटन में सांस्कृतिक केंद्र। इसके अतिरिक्त, विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों/ केंद्रों से परिसंपत्तियों की खरीद के अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं। वियतनाम और भारत के बीच परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान किए जाने के संबंध में समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। हनोई में चांसरी और दूतावास आवास हेतु दो भवनों के मूल्यांकन के उपरान्त वियतनाम दूतावास के लिए दिल्ली में एक भूखंड के साथ इनका विनिमय किया जाएगा।

भारत की परियोजनाओं में विदेश मंत्रालय के भावी मुख्यालय अर्थात जवाहरलाल नेहरू भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और जून, 2010 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए चाणक्यपुरी आवासीय परिसर, केनिंग लेन में ट्रांजिट आवास परियोजना तथा नई दिल्ली में विदेश सेवा संस्थान परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संघ के लिए नई दिल्ली में निर्मित किए जा रहे आल्को परिसर तथा कोलकाता में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य भी पूरा किया जा चुका है।

लागोस और डब्लिन में अतिरिक्त परिसंपत्तियों को बेचे जाने के संबंध में भी मंत्रालय में कार्रवाई चल रही है।

वर्ष 2009-10 के दौरान पूंजीगत परिव्यय के तहत 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अगले वित्त वर्ष में अनेक परियोजनाओं के लिए निर्माण कार्य आरंभ होने की प्रत्याशा में वर्ष 2010-11 के लिए बजट अनुमान 683.64 करोड़ रुपये का रखा गया है।

कल्याण विभाग

कल्याण विभाग मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य कल्याण से जुड़े सभी मामलों को देखता है। इन कार्यों में आपातकालीन प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराना तथा कार्मिकों की मृत्यु की स्थिति में टेलीग्राफिक संदेश भेजना शामिल है।

(1) शैक्षिक मामलेः कल्याण प्रभाग केंद्रीय विद्यालय संगठन में विदेश मंत्रालय के लिए आवंटित 60 सीटों के आधार पर केंद्रीय विद्यालयों में विदेश मंत्रालय के कार्मिकों के बच्चों के नामांकन को सुविधाजनक बनाता है। कल्याण विभाग ने मंत्रालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों के बच्चों को कालेजों में नामांकन कराने में सहायता प्रदान की। इसके साथ ही कल्याण प्रभाग ने मेडिकल/ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों पर भी कार्रवाई की है। वर्ष 2009-10 में मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 15 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से पांच का नामांकन के लिए चयन किया गया और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 52 बच्चों को इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया।

(2) कर्मचारी लाभ निधि कल्याण प्रभाग कर्मचारी लाभ निधि का भी प्रबंधन करता है, जिसका निर्माण पिछले अनेक वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त अंशदानों के आधार पर हुआ है। इसका उपयोग मुख्यतः विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु की स्थिति में दाह संस्कार पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। कल्याण प्रभाग की अनुशंसाओं पर विदेश मंत्रालय स्पाउसेज एसोसिएशन (ईएएसए) ने भी विदेश मंत्रालय के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 10,000 रुपये - 20,000 रुपये के चेक प्रदान किए।

(3) अनुकम्पा आधार पर नियुक्तः जब भी किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो कल्याण प्रभाग उस परिवार के सदस्यों की वित्तीय स्थिति तथा इस बात की जांच करता है कि क्या मृत व्यक्ति की पत्नी/ पति अथवा उसका कोई बच्चा समूह-'ग' अथवा समूह-'घ' के किसी पद पर नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त शैक्षिक अर्हता रखता है। परिवार की वित्तीय स्थिति के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की एक सूची कल्याण प्रभाग में रखी जाती है।

(4) सहायता अनुदानः कल्याण प्रभाग विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों एवं भारत के सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में मनोरंजन सुविधाओं एवं खेल संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान को प्रशासित करता है। यह प्रभाग अंतर्मंत्रालयी खेल गतिविधियों की व्यवस्था एवं वित्तपोषण भी करता है।

(5) पारिवारिक विवादः कल्याण विभाग परिवार के सदस्यों की शिकायतों, मतभेदों इत्यादि को सुनकर तथा ढांढस बंधाकर पारिवारिक जीवन जारी रखने की सलाह देकर पारिवारिक विवादों को निपटाने में भी सहायता करता है।

(6) झण्डा दिवसः कल्याण प्रभाग ने झण्डा दिवस, रेडक्रास दिवस, साप्रदायिक सद्भाव दिवस, सशस्त्र बल दिवस, जैसे कार्यक्रमों को मनाए जाने की व्यवस्था की और इन संगठनों के लिए निधियां एकत्र की गईं।

(7) कैंटीनः कल्याण प्रभाग अकबर भवन, साउथ ब्लाक तथा पटियाला हाउस में स्थित विदेश मंत्रालय की विभागीय कैंटीनों को भी प्रशासित करता है। जैसा कि आम तौर पर होता है, इन कैंटीनों ने मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराईं। इसके अतिरिक्त, इन कैंटीनों ने यात्रा पर आए राजनयिक कोर के सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी उत्कृष्ट सेवा मुहैया कराई। कैंटीन सेवाओं में और सुधार लाने के उद्देश्य से नवंबर, 2006 से ही साउथ ब्लाक में भारतीय रेल कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के द्वारा भी एक कैंटीन चलाई जा रही है।

(8) सामान्यः मिशनों से मुख्यालय वापस आने पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुधा सरकारी/ निजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन कराने, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड और टेलीफोन कनेक्शन इत्यादि प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कल्याण प्रभाग ने स्कूलों, एमटीएनएल इत्यादि को पत्र लिखे जिससे इन घरेलू सुविधाओं को प्राप्त करने में सुविधा मिली। कल्याण

प्रभाग के प्रमुख एक संयुक्त सचिव होते हैं, जिनकी सहायता के लिए एक निदेशक, एक अवर सचिव, एक अनुभाग अधिकारी, एक सहायक, एक अवर श्रेणी लिपिक तथा समूह-घ का एक कर्मचारी होता है।

सतर्कता

सतर्कता एकक, विदेश मंत्रालय की वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक रिपोर्टः

- 31.03.2009 तक की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्याः 134
- 1.4.2009 से 30.11.2009 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए मामलों की संख्याः 20
- 30.11.2009 तक मामलों की कुल संख्या उ (134+20) 154
- 30.11.2009 तक औपचारिक जुर्माना लगाकर बंद किए गए मामलों की संख्याः 14
- 30.11.2009 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि के कारण औपचारिक जुर्माना लगाए बिना बंद किए गए मामलों की संख्याः 12
- 30.11.2009 तक बंद किए गए कुल मामलों की संख्या उ(14+12)ः 26
- 30.11.2009 तक की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या उ(154-26)ः128

3.11.2009 से 7.11.2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों तथा विदेश मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित शपथ ली।

ई-शासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुवैत, टोरंटो एवं मैड्रिड जैसे भारतीय मिशनों एवं केंद्रों में पासपोर्ट एवं वीजा सेवाओं के कंप्यूटरीकरण का कार्य और भारतीय दूतावास मास्को एवं बैंकूवर में वीजा एवं पासपोर्ट सेवाओं की आउटसोर्सिंग का कार्य पूरा हो गया।

सूचना का अधिकार एवं मुख्य जन सूचना कार्यालय

'1 अप्रैल-31 दिसंबर, 2009 की अवधि के दौरान मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कुल 804 आवेदन प्राप्त हुए। ये आवेदन निम्नलिखित विषयों से संबंधित थे - प्रशासन, व्यक्तिगत शिकायत, हज यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, खाड़ी युद्ध मुआवजा, विदेश नीति, आर्थिक मुद्दे इत्यादि। इसी अवधि के दौरान इन आवेदनों में से 238 के लिए मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील आवेदन दायर किए गए। इसके अतिरिक्त, सीपीआईओ तथा मंत्रालय के नोडल अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सूचना आयोग में होने वाली सुनवाई में भी भाग लेते रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।'

■■

20 समन्वय

समन्वय प्रभाग की तीन शाखाएं हैं अर्थात् संसद अनुभाग, समन्वय अनुभाग और शिक्षा अनुभाग।

संसद अनुभाग

समन्वय प्रभाग विदेश मंत्रालय का संसद से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दु है; इन कार्यों में संसद के प्रश्न-उत्तर, आश्वासन, विदेश संबंधों पर बहस और दोनों सदनों के पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। यह प्रभाग विदेश मामलों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठकों का आयोजन भी करता है और विदेश मामलों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति तथा अन्य संसदीय समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय करता है।

समन्वय अनुभाग

समन्वय अनुभाग राज्यपालों, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा उपसभापति, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, न्यायपालिका के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों आदि द्वारा की जाने वाली विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक दृष्टि से अनापत्ति प्रदान करने के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करता है। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों, यात्रा के राजनैतिक एवं प्रकार्यात्मक औचित्य, की गई बैठकों और संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र की सिफारिश को ध्यान में रखने के बाद ही विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक अनापत्ति प्रदान की जाती है। चालू वर्ष के दौरान समन्वय प्रभाग ने इन दौरों के लिए वर्ष 2008 में 2539 की तुलना में 2706 राजनीतिक अनापत्ति जारी की हैं। इस अनुभाग ने विदेशी गैर-अनुसूचित उड़ानों तथा नौसैनिक जहाजों से यात्राओं के लिए राजनयिक अनापत्तियां प्रदान करने से संबंधित कार्यों को भी निपटाया। चालू वर्ष के दौरान समन्वय प्रभाग द्वारा विदेशी गैर-अनुसूचित उड़ानों के लिए वर्ष 2008 की इसी अवधि में 971 की तुलना में 996 अनापत्तियां जारी की गईं।

समन्वय अनुभाग ने विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भारतीय खिलाड़ियों और खेल-कूद टीमों की भागीदारी के लिए और विदेशी खिलाड़ियों/टीमों की भारत यात्रा के लिए बड़ी संख्या में अनुमोदन प्रदान करने की कार्रवाई की थी। यह अनुभाग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत एमेच्योर डब्ल्यू/टी लाइसेंस प्रदान करने, विदेशों में स्थित भारत विदेश सांस्कृतिक मैत्री और सांस्कृतिक सोसाइटियों के लिए सहायता अनुदान के वास्ते अनापत्ति देने के अनुरोधों की भी जांच करता है।

समन्वय अनुभाग विदेशी राष्ट्रिकों को पद्म अवार्ड प्रदान करने से संबंधित कार्यों का समन्वय करता है। समन्वय अनुभाग विदेश स्थित भारतीय मिशनों/कंद्रों से नामांकन प्राप्त करता है और मंत्रालय की सिफारिशों से गृह मंत्रालय को अवगत कराता है।

समन्वय प्रभाग द्वारा मंत्रालय और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों में आतंकवाद विरोधी दिवस (21 मई), सदभावना दिवस (20 अगस्त) और कौमी एकता सप्ताह/दिवस (19-25 नवंबर) भी मनाया गया; मुख्यालय में और विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों, दोनों स्थानों पर अधिकारियों को शपथ दिलाई गयी।

समन्वय अनुभाग फरवरी, 2010 में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले आगामी डिफेक्सपो भारत- 2010 के लिए मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के साथ तालमेल बैठाने में रक्षा मंत्रालय की सहायता करता रहा है।

समन्वय अनुभाग द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विविध अंतरमंत्रालयी बैठकों में प्रतिनिधित्व किया गया तथा मंत्रालय से संबंधित जानकारी दी गई; इसी प्रकार समन्वय अनुभाग ने महत्वपूर्ण विषयों पर दस्तावेज, टिप्पणी और सार-संक्षेप तैयार करने में मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से जानकारी हासिल की।

शिक्षा अनुभाग

शिक्षा अनुभाग इस मंत्रालय को क्रमशः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आबंटित सीटों पर स्व-वित्तपोषित विदेशी छात्र योजना के अंतर्गत एमबीबीएस/बीडीएस/बीई/बी.फार्मेसी और भारत की विभिन्न संस्थाओं से डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 63 मित्र, पड़ोसी एवं विकासशील देशों से विदेशी छात्रों के चयन, नामांकन और प्रवेश के संबंध में कार्रवाई करता है। इस अनुभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं और शोध पाठ्यक्रमों में चयनात्मक प्रशिक्षण/इंटर्नशिप सहित इंजीनियरी, चिकित्सा, प्रबंधन, अन्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक एवं परा-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले विदेशी छात्रों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रदान करने की भी कार्रवाई की गई।

शैक्षणिक वर्ष 2008-09 के लिए शिक्षा अनुभाग ने एमबीबीएस/बीडीएस और बीई/बी फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्रमशः 52 और 83 आवेदन प्राप्त किए और उन पर कार्रवाई की। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 1345 विदेशी आवेदकों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रदान की गई।

■■

विदेश प्रचार

21

विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ तालमेल के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत सरकार दृष्टिकोण/पक्ष को रखने का कार्य जारी रखा। यह नियमित एवं विशेष प्रेस ब्रीफिंग, वक्तव्यों, पृष्ठभूमि और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्टिंग के माध्यम से किया गया। प्रभाग के मुख्य कार्यकलाप अपने पड़ोसी देशों के साथ-साथ विश्व के प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों पर सूचना के प्रचार-प्रसार पर केंद्रित रहे। मुंबई में 26/11 के बर्बरतापूर्ण आतंकी हमलों के बाद हमारी सीमापार से उभरते आतंकवाद पर भारत की चिंताएं व्यक्त करने के लिए स्थाई प्रचार अभियान चलाया गया था। इसके अतिरिक्त, हमारी नई पहलों के एक भाग के रूप में अफ्रीकी देशों में कई नई परियोजनाएं पहुँचाने का कार्य प्रारंभ किया गया था जिसमें फ्लैगशिप 'इंडिया अफ्रीका कनेक्ट ' वेबसाइट शामिल है जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रभाग ने उर्दू और अन्य गैर-हिंदी मीडिया तक पहुँचने के अलावा अपने आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अनेक विदेशी पत्रकारों के समूह की मेजबानी भी की।

भारत आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों का प्रेस कवरेज

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के ठोस क्रिया-कलापों का प्रमाण विदेशों से गणमान्य व्यक्तियों के भारत दौरों की संख्या से मिला। दौरा करने वाले गणमान्य व्यक्तियों में उल्लेखनीय थेः भूटान, रूसी परिसंघ, डेनमार्क, अर्जेन्टिना, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान, बंगलादेश, कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य मलेशिया, टर्की, जर्मनी और नेपाल के राज्याध्यक्ष/शासनाध्यक्ष। प्रभाग ने इन यात्राओं से मिले अवसरों का उपयोग महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोणों का प्रचार-प्रसार करने में किया। प्रभाग ने आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त प्रेस बातचीत का आयोजन भी किया। मंत्रालय के प्रवक्ता और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा विशेष ब्रीफिंग का भी नियमित रूप से आयोजन किया गया ताकि मीडिया को अवगत करवाया जा सके।

भारत के गणमान्य लोगों के विदेश दौरों की प्रेस कवरेज

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री के विदेश दौरों के साथ जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सभी संभारतंत्रीय व्यवस्था, जिसमें कि पत्रकारों द्वारा कवरेज को फाइल करने की सुविधा से पूर्ण सुसज्जित मीडिया केंद्र स्थापित कर उसे प्रकार्यात्मक बनाना शामिल है, मीडिया ब्रीफिंग और अन्य व्यवस्था करना ताकि कार्यक्रम का समय पर मीडिया का कवरेज सुनिश्चित हो सके - प्रभाग के कार्य का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। वर्ष के दौरान राष्ट्रपति की स्पेन, पोलैंड, रूस, तजिकिस्तान, यू के और साइप्रस की यात्रा; प्रधानमंत्री की यू के (जी-20 शिखर बैठक), रूस (बी आर आई सी एवं एस सी ओ शिखर बैठक), यू एस ए (जी-20 शिखर बैठक), थाइलैंड (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स एण्ड ईस्ट एशियन सम्मिट्स), यू एस ए (राजकीय दौरा) और पोर्ट ऑफ स्पेन (कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट सम्मिट) की यात्रा; उप राष्ट्रपति की कुवैत और साउथ अफ्रीका की यात्रा और विदेश मंत्री की जापान, भूटान, थाइलैंड, नेपाल, आस्ट्रेलिया, कुवैत और अफगानिस्तान की यात्रा के दौरान मीडिया के लोग साथ गए।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ संपर्क

सरकारी प्रवक्ता के कार्यलय ने भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख घटनाक्रमों, आने और जाने वाली उच्च स्तरीय यात्राओं और दिन-प्रतिदिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नियमित ब्रीफिंग आयोजित कर पूरे वर्ष के दौरान भारतीय और विदेशी मीडिया के साथ संपर्क बनाए रखा। वर्ष के दौरान (21 जनवरी 2010 तक) विभिन्न विचारणीय मुद्दों पर 187 प्रेस विज्ञप्तियां, 63 प्रेस ब्रीफिंग और 34 संयुक्त प्रेस वक्तव्य और 60 मीडिया परामर्शी प्रभाग द्वारा जारी किए गए। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और टी.वी. संगठनों के साथ प्रधानमंत्री, विदेशमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए। ये मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखे गए हैं।

सरकारी प्रवक्ता का कार्यालय

सरकारी प्रवक्ता का कार्यालय भारतीय विदेश नीति के संचालन से संबंधित दिन-प्रतिदिन के घटनाक्रमों पर सूचना का प्रचार-प्रसार करने के केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। कार्यालय ने प्रवक्ता द्वारा नियमित मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की जिसे प्रेस विज्ञप्तियों, ब्रीफिंग मुद्दे एवं वक्तव्यों द्वारा संपूरित किया गया। अप्रैल-नवंबर, 2008 के दौरान सरकारी प्रवक्ता के कार्यलय द्वारा लगभग 91 प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान 200 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियां और वक्तव्य जारी किए गए। इन्हें ई-मेल के माध्यम से मीडिया में परिचालित किया गया और साथ-साथ मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया। मीडिया को ब्रीफिंग के बारे में और वेबसाइट अद्यतन

रखने के बारे में मीडिया को एसएमएस द्वारा अलर्ट करना प्रभाग ने जारी रखा। वर्ष के दौरान, विदेश मंत्री, विदेश सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष मीडिया समूह को संबोधित किया गया। इसके साथ-साथ मीडिया से जुड़े लोगों को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान कर सरकार की स्थिति और महत्व पर सूचना देने के नियमित प्रयास किए गए। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों और टीवी संगठनों के साथ प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए।

विदेश मंत्रालय की वेबसाइटः

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने उपयोगी साधन के रूप में प्रभाग के प्रचार-प्रसार के प्रयासों में कार्य करना जारी रखा। वेबसाइट के प्रेस खंड को प्रधानमंत्री, मंत्रियों द्वारा विदेश नीति पर दिए गए व्याख्यानों/साक्षात्कारों/वक्तव्यों तथा प्रेस विज्ञप्तियों, सरकारी प्रवक्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ब्रीफिंग के साथ नियमित रूप से अद्यतन किया गया। इस वेबसाइट का भारत के अंदर और बाहर लोगों द्वारा व्यापक उपयोग किया गया और विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र और विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट से हाइपरलिंक किया गया। प्रभाग ने विदेश मंत्रालय के सूचना पट्ट का प्रयोग करना जारी रखा ताकि विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों को भारत के विभिन्न पहलुओं पर स्थानीय मीडिया में प्रचार के उद्देश्य से व्यावसायिक रूप से लिखी सामग्री मिल सके। हमारे मिशनों/केंद्रों के उपयोग के लिए समाचार पत्रों से रुचि के समाचार कतरनों को दैनिक आधार पर बोर्ड पर भी अपलोड किया गया।

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के संबंध में नई पहलः

(क) विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में सुधार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट को अधिक उपयोगी बनाने एवं इसकी बनावट और भाव विचारों को बेहतर बनाने की दृष्टि से इसमें सुधार करने संबंधी परियोजना प्रारंभ कर दी गई है। जेनपैक्ट को इस परियोजना का कार्य सौंपा गया है, जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ख) मंत्रालय की वेबसाइट का हिन्दी खंडः वेबसाइट के हिन्दी खंड को लगातार अद्यतन किया जाता है ताकि जहां तक संभव हो इसे अंग्रेजी खंड के समरूप बनाया जा सके। चूँकि सभी मूल पाठ अंग्रेजी में हैं, वेबसाइट के हिन्दी खंड को अद्यतन किया जाना पूर्णतः अनुवाद कार्य पर निर्भर है, जिसे व्यावसायिक रूप से योग्य हिन्दी अनुवादकों के पैनल को सौंप दिया गया है। आम लोगों एवं हिन्दी प्रेमियों और भारतीय मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा वेबसाइट के हिन्दी खंड के काफी सराह गया है।

(ग) उर्दू रूपान्तरः प्रथम बार, विदेश मंत्रालय के प्रेस रिलीज के उर्दू रूपान्तर के लिए इसकी उर्दू वेबसाइट पर ए एन आई की व्यवस्था की गई है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे एक लिंक उपलब्ध करवाया गया है।

भारत-अफ्रीका संपर्क वेबसाइटः

विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा ने नई दिल्ली में 17 अगस्त, 2009 को 'भारत अफ्रीका संपर्क वेबसाइट प्रारंभ किया। विदेश प्रचार प्रभाग और भारतीय नवीन सेवा संघ द्वारा संयुक्त रूप से वेबसाइट विकसित की गई थी और यह हमारे अफ्रीकी समकक्षों के साथ संबंध बढ़ाने के प्रति समर्पित है और इसमें विकास सहयोग पर विशेष जोर देते हुए भारत और अफ्रीकी देशों के संबंध में समाचार, फीचर एवं आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध है। भारत और अफ्रीका के बीच निकट सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इस वेबसाइट को प्रारंभ किया गया था। इस वेबसाइट को http://www.indiaafricaconnect.in पर देखा जा सकता है और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट होम पेज पर भी एक लिंक उपलब्ध है।

भारत आस्थानी विदेशी मीडिया को संभारतंत्रीय सहायता

भारत में आस्थानी लगभग 300 से अधिक सशक्त विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गईं ताकि वे रुचि के विभिन्न विषयों पर संगत सूचना प्राप्त करने तथा प्रत्यय दस्तावेज, और आवासीय परमिट के मामलों में सहायता प्रदान करने के माध्यम से आसानी से अपना कार्य निष्पादन कर सकें। विदेशी पत्रकारों को वीजा विस्तार और/अथवा प्रत्यापन सुविधाएं भी प्रदान की गई।

विदेशी पत्रकारों द्वारा परिचय यात्रा

भारत में विदेशी पत्रकारों द्वारा की जाने वाली परिचय यात्राओं के दौरान आधुनिक भारत के विभिन्न आयामों और विचारों से उन्हें अवगत कराया जाना प्रभाग के प्रयासों का मुख्य हिस्सा है। इससे पत्रकार भारत की राजनीति, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति की अद्वितीय और प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करते हैं। विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों की सिफारिश पर प्रभाग ने अप्रैल-नवम्बर, 2008 की अवधि के दौरान भारत में 72 विदेशी पत्रकारों की परिचय यात्राएं आयोजित की। इन यात्राओं के दौरान प्रभाग द्वारा महत्वपूर्ण संस्थानों और भारत के उत्कृष्टता प्राप्त केंद्रों का दौरा कर सकने के लिए पत्रकारों को सभी संभारतंत्रीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। प्रभाग ने दौरे पर आने वाले विदेशी पत्रकारों के लिए और भारत में औद्योगिक उत्कृष्टता के चुनिंदा केन्द्रों का दौरा करने, तथा मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और व्यवसायिक प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठकें भी आयोजित की।

वृत्त-चित्र एवं फिल्में

प्रभाग के मुख्य कार्यों में विदेशी दृश्य-श्रव्य एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए वृत्त-चित्रों को मंजूरी प्रदान करना है। प्रभाग द्वारा विदेशी निर्माताओं द्वारा भारत में वृत्त-चित्र तैयार करने की अनुमोदन प्रक्रिया को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु कार्रवाई

की गई। अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के परिणामस्वरूप प्रक्रियाएं काफी सरल हो गई हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा अमरीका, यूके, जापान, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्वीडन, इटली, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और चीन से आए विदेशी निर्माताओं द्वारा वृत्त-चित्र निर्माण करने के 400 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन एवं विशेष कार्यक्रम

संबंधित क्षेत्रीय प्रभाग की सिफारिशों पर प्रभाग ने अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से आए मीडिया के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के परामर्श से तीन सप्ताह के विशेष डिजाइंड पाठ्यक्रम के लिए 10 ऐंग्लों फोन अफ्रीकी देशों से 19 पत्रकारों (8 ए आई और 11 प्रिंट) को भी आमंत्रित किया गया था। इस के दौरान इस प्रभाग ने बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, चीन, कजाखस्तान, इथियोपिया और खाड़ी देशों के पत्रकारों की भी मेजबानी की। उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों एवं शिक्षाविदों के साथ बैठकें आयोजित एवं उत्कृष्ट केन्द्रों के दौरे भी आयोजित किए गए। इस प्रभाग ने आपसी समझ बढ़ाने एवं सूचना के अंतर को पाटने के लिए चुनिंदा अफ्रीकी देशों में आई ए एन एस एवं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संवाददाताओं की तैनाती भी की।

आम चुनाव से संबंधित पुस्तिका

अप्रैल-मई, 2009 में आम चुनाव जिसे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानी गई है, के बारे में सही सूचना का प्रचार-प्रसार करने के वास्ते इस प्रभाग ने सुसंबद्ध एवं रंगीन पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें उपयोगी गणना शामिल करते हुए भारत में जिस प्रकार चुनाव कराये जाते हैं उसका ब्यौरा दिया। इसने विदेशी पाठकों, विशेषकर पत्रकारों के लिए सुलभ संदर्भ का काम किया। इस पुस्तिका के वेब लिंक को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखा गया।

प्रशासन/गृह-व्यवस्था

सामान्य कार्यकरण माहौल में सुधार लाने एवं सौंदर्यपर मनोहारी स्वरूप सृजित करने के लिए हाल ही में शास्त्री भवन में विदेश प्रचार प्रभाग की एक प्रमुख नवीकरण प्रक्रिया पूरी की गई थी। हरे भरे पौधों के साथ-साथ चुनिंदा ऐतिहासिक चित्रों के प्रदर्शन ने इस क्षेत्र को और भी प्रदर्शनीय एवं आकर्षक बना दिया है।

■■

22 लोक राजनय प्रभाग

लोक राजनय प्रभाग के कार्यकलापों में, अन्य बातों के साथ-साथ हमारे मिशनों को, भारत के विविध पक्षों को और अधिक प्रभावी ढंग से परिलक्षित करने में सक्षम बनाने के लिए, मुद्रित एवं दृश्य-श्रव्य सामग्रियां तैयार करना शामिल है। इसके अलावा प्रभाग ने कई आउटरीच कार्यकलाप भी आयोजित किए जिसका उद्देश्य भारतवर्ष और विदेशों, दोनों में भारत और उसकी विदेश नीति से संबंधित चिंताओं के प्रति अत्यधिक समझ पैदा करना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभाग ने, हमारी चिंताओं से संबंधित विषयों पर सम्मेलन एवं संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए प्रमुख आतंरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय विचार केंद्रों एवं अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित की है। प्रभाग भारत के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न देशों एवं संगठनों के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करता है। इसके अलावा प्रभाग ने, भारत की विदेश नीति पर और अधिक व्यापक चर्चा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के अंदर व्याख्यान माला एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए।

आउटरीच कार्यकलाप

प्रभाग ने भारत की विदेश नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर बल देने के लिए कई आउटरीच कार्यकलाप आयोजित किए जिनमें प्रतिनिधिमंडलों के दौरे, संगोष्ठी, सम्मेलन, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं के साथ तालमेल, विशिष्ट व्याख्यानमाला और फिल्मों की स्क्रीनिंग शामिल है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैः

आगंतुकों के दौरे

यूके कंजर्वेटिव पार्टी के फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा जुलाई 2009 में भारत का दौरा किया गया। प्रतिनिधिमंडल को लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल, विशेष पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के साथ हुई बैठकों के अलावा विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने कोची की भी यात्रा की, वहां उनकी राज्य सरकार के साथ बैठकें की और नौसेना अधिष्ठापनों का दौरा किया।

यूके से लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रैंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के एक प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर 2009 में भारत का दौरा किया। राज्य सभा के उप सभापति और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के साथ बैठकों के अलावा प्रतिनिधिमंडल को, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नीति अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन प्रशिक्षण संस्थान का भी दौरा किया।

स्लोवेनिया से भारत-स्लोवीन संसदीय मैत्री समूह के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2009 में भारत का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रणीत कौर, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री श्री व्यालार रवि और दिल्ली के मेयर के साथ हुई अपनी बैठकों के अलावा प्रतिनिधिमंडल ने फिक्की और आईबीईएफ के साथ विचार-विमर्श भी किया और सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वाले व्यापार संगठनों का दौरा भी किया। प्रतिनिधिमंडल ने लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाहियां भी देखी।

पीबीडी 2010 के दौरान जनवरी माह में 15 देशों के पीआईओ पत्रकारों का एक 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया। पीबीडी में भाग लेने के अलावा पत्रकारों को भारत की अर्थव्यवस्था, हमारे सुरक्षा परिदृश्य और भारत में समावेशी विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के प्रयासों पर सीआईआई, आईडीएसए और योजना आयोग द्वारा जानकारी दी गई। इस दल ने मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज और फिल्म सिटी का भी दौरा किया।

प्रशांत लघु द्वीप विकासशील राज्यों के स्थायी प्रतिनिधियों के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा 23-31 जनवरी 2010 को आयोजित किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा, पर्यावरण एवं वानिकी मंत्री श्री जयराम रमेश से मिलने के अलावा भारत के आर्थिक परिदृश्य पर सीआईआई से जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने गणतंत्र दिवस परेड, राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्यक्रम और बीटिंग रिट्रीट भी देखी। प्रतिनिधिमंडल ने अपने-अपने देशों से संबंधित सिंचाई एवं ऊर्जा संसाधनों में विशेषज्ञता प्राप्त व्यापार संगठनों का भी दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को इसरो स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रगति की भी जानकारी दी गई।

विदेशों के दौरे

महात्मा गांधी और उनकी शिक्षा पर व्याख्यान देने के लिए गुजरात विद्यापीठ के कुलपति प्रो. सुदर्शन आयंगर ने स्लोवोनिया की यात्रा की। प्रो. आयंगर ने स्लोवेनिया में महात्मा गांधी पर आयोजित एक सम्मेलन में भी भाग लिया।

संगोष्ठी/सम्मेलन/द्विपक्षीय वार्ता

पीडी प्रभाग ने भारतीय विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित संगोष्ठी एवं सम्मेलन के आयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई संगठनों के साथ साझेदारी की। इनमें निम्नलिखित शामिल हैः

(1) भारतीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद और सियोल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के फॉरम के साथ संयुक्त रूप से 20-21 मई 2009 को आयोजित आठवां भारत-कोरिया वार्ता।

(2) हिमालय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठान द्वारा 23-24 जुलाई 2009 को आयोजित 'काराकोरम हिमालय में समाज, संस्कृति और राजनीति' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(3) दी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा 6-7 अत्तूबर 2009 को आयोजित 'अफगानिस्तान में शांति और स्थिरताः आगे का मार्ग' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(4) सीआईआई द्वारा 25-26 नवंबर 2009 को आयोजित चतुर्थ सततता शिखर बैठक।

(5) ग्रामीण अनुसंधान एवं औद्योगिक विकास केंद्र, चंडीगढ़ द्वारा दिसंबर 2009 में आयोजित भारत-बांग्लादेश संबंधों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(6) भारत-जीसीसी संबंधों पर दुबई स्थित खाड़ी अनुसंधान केंद्र और भारतीय अध्ययन समूह की साझेदारी से जून 2009 में दुबई में और जनवरी 2010 में नई दिल्ली में संगोष्ठियां आयोजित की गईं।

(7) तृतीय आईआईएसएस-एमईए विदेश नीति वार्ता 22 फरवरी 2010 को लंदन में आयोजित हुई जिसमें बीज व्याख्यान विदेश सचिव द्वारा दिया गया।

(8) बिहार सरकार के सौजन्य से भारत-नेपाल संबंधों पर एक संगोष्ठी 25-27 फरवरी 2009 को पटना में आयोजित की गई।

(9) सीआरआरआईडी और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा 13-14 मार्च 2010 को चंडीगढ़ में संयुक्त रूप से आयोजित 'वीमेन गाइडिंग दी डेस्टिनी ऑफ साउथ एशिया' (क) मीडिया पर्सपेक्टिव बाई वीमेन जर्नलिस्ट्स (ख) वीमेन एज पार्टनर्स इन डेवलमेंट नामक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी।

(10) राजनीति शास्त्र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 24-25 मार्च 2010 को चंडीगढ़ में '21वीं सदी में भारतीय विदेश नीतः चुनौतियां एवं संभावना' पर एक संगोष्ठी।

विशिष्ट व्याख्यान माला

'भारतीय विदेश नीति पर विशिष्ट व्याख्यानमाला' की शुरूआत 17 फरवरी 2009 को 'विश्व शक्ति के रूप में भारत का उद्भवः संभावना एवं चुनौती' व्याख्यान के साथ बनारस हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणसी में हुई। देश भर में विश्वविद्यालय परिसरों में चर्चा को ले जाने के उद्देश्य से एक नई पहल के एक भाग के रूप में राजदूत (सेवानिवृत्त) ए.एन. राम द्वारा व्याख्यान दिया गया।

विश्वविद्यालयों/विचार केंद्रों तक आउटरीच

संयुक्त सचिव (पीडी) ने भारतीय विदेश नीति से संबंधित विषयों पर छात्रों एवं संकाय के साथ अंतःसक्रिय सत्र आयोजित करने और विशिष्ट व्याख्यान माला एवं अन्य पहलों हेतु एक मंच तैयार करने के लिए मुम्बई विश्वविद्यालय के परिसरों का दौरा किया।

अन्य आउटरीच कार्यकलाप

पीडी प्रभाग के सहयोग से कई मिशनों एवं केंद्रों ने समारोहपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आयोजित किया। इस अवसर पर आयोजित समारोहों में व्याख्यान, संगोष्ठी, सम्मेलन, फोटो प्रदर्शनी, फिल्म फेस्टीवल, वाद-विवाद, स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रम शामिल थे।

जलवायु परिवर्तन पर भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाने वाला पीडी प्रभाग का वृत्तचित्र 'नेगोशिएटिंग जस्टिस' की स्क्रीनिंग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, यूनाइटेड सर्विसेस इंस्टीट्यूट और अन्य प्रतिष्ठित स्थलों पर की गई। 4 फरवरी 2010 को यूएसआई में हुए स्क्रीनिंग के साथ कोपनहेगन शिखर सम्मेलन में भारत की स्थिति के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई।

चुनाव आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 24 जनवरी को और इसके साथ ही कई अवसरों पर पीडी प्रभाग का वृत्तचित्र 'इंडियन इलेक्शंसः ए मैमथ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज' की स्क्रीनिंग की गई।

भूटान के नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरों और भारत-भूटान संबंधों के विकास पर दुर्लभ पुरालेखीय तस्वीरों की प्रदर्शनी दिसंबर 2009 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, दिल्ली में लगाई गई। भा.सां.सं.परि. के अध्यक्ष डॉ. कर्णसिंह द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

दृश्य-श्रृव्य प्रचार-प्रसार

पूर्व की भांति प्रभाग ने विदेशों में भारत की छवि का उन्नयन और परिलक्षित करने के लिए वृत्तचित्रों को निरंतर जारी रखा। प्रभाग द्वारा श्रृव्य-दृश्य प्रचार-प्रसार हेतु शुरू किए गए अन्य कार्यकलापों में- विदेशों में फिल्म महोत्सव और भारतीय फिल्म सप्ताहों में भागीदारी, सांस्कृतिक एवं फोटो-प्रदर्शनियों का आयोजन प्रमुख था।

वर्ष के दौरान कई निम्नलिखित वृत्तचित्रों का निर्माण पूरा किया गयाः

(क) कैन यू हियर मी (सामुदायिक रेडियो क्रांति पर एक फिल्म)

(ख) थ्रू लेंस क्लियरलीः रघु राय का भारत

(ग) इंडियन इलेक्शन-ए मैमथ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज

(घ) कश्मीर इलेक्शंस 2008

(ड़) स्पिरीट ऑफ इंडिया (भारत के विभिन्न पक्षों को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म)

(च) रिलीजीयस लिंकेजेस बिटवीन भूटान एडं लद्दाख

(छ) वाटरिंग दी ग्रासरूट्स (माइक्रोफाइनांस पर एक फिल्म)

(ज) नेगोशिएटिंग जस्टिस (जलवायु परिवर्तन पर भारत के दृष्टिकोण पर एक फिल्म)

(झ) सिनेमा विद ए परपस (सिनेमा के माध्यम से मूल्यों के संचार पर एक फिल्म)

(ण) मस्त कलंदर (तीन सूफी संतों पर फिल्म)

(ट) पार्टनर्स इन प्रोगेसः इंडो-यूएस रिलेशंस

(ठ) इंडिया इन द मून (चंद्रायन-I)

(ड) सोल्जर्स ऑफ पीस (शांतिकाल में नागरिकों के साथ वर्दी वाले कर्मियों के क्रियाकलापों पर एक फिल्म)

(ण) फ्रेगमेंट्स ऑफ हिस्टरी (एमएस सुब्बालक्ष्मी के जीवन पर एक फिल्म)

मिशन/केंद्रों को पुस्तकालयों के लिए, फिल्म महोत्सवों में भाग लेने के लिए और प्रस्तुतिकरण के प्रयोजनों से बीटाकैम कैसेटों, सीडी-रोम, श्रृव्य एवं दृश्य सीडी, डीवीडी, 35 मिमी के फिल्म और कैसेट के रूप में श्रृव्य-दृश्य सामग्री भेजी जाती है।

विदेशी टीवी चैनलों/दूरदर्शन द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में कई वृत्तचित्रों को प्रसारित/स्क्रीन किया जाता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैः-

(क) आइटेक दिवस पर 19 मार्च, 2009 को नोम पेन्ह में वृत्तचित्र 'टाइमलेस इंडिया' और 'दी ज्वेल इन दी लोट्स' का फिल्मांकन किया गया।

(ख) भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री लंका के टीवी चैनलों द्वारा 'इंडिया विन्स फ्रीडम' और 'क्विट इंडिया' नामक वृत्तचित्रों का प्रदर्शन/श्री लंका के दूरदर्शन द्वारा अगस्त 2009 में 'सूफी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया' 'बिटिंग रीट्रीट' और बिस्मिल्ला एंड बनारस' का भी प्रसारण किया गया।

(ग) दूरदर्शन द्वारा मई/जुलाई 2009 में 'इंडियन इलेक्संश-ए मैमथ एक्सरसाइज' और 'स्पिरिट ऑफ इंडिया' नामक वृत्तचित्र का प्रसारण किया गया।

(घ) बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अत्तूबर 2009 में भारतीय उच्चायोग, बोगोटा द्वारा पीडी प्रभाग के वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग।

(ड़) तंजानिया के टीवी चैनल 'स्मार्ट' द्वारा सितंबर 2009 में वृत्तचित्रों 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2010' 'दी स्काई इज नॉट दी लिमिट', 'डिसमैंटलिंग दी डिजीटल डिवाइड', फ्रैंड्स फॉर एवरमोर' और 'बियांड ट्रेडिशन' का प्रसारण।

(च) गोवा में नवंबर/दिसंबर 2009 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लघु फिल्म केंद्र में 'दी स्टोरी ऑफ गीतांजलि' वृत्त चित्र की स्क्रीनिंग।

इसके अलावा अकरा, हो ची मिन्ह सिटी, मेक्सिको सिटी, अम्मान, रिकजाविक, तेल अवीव, मिंस्क और पेरिस स्थित हमारे मिशन/केंद्रों ने प्रभाग द्वारा भेजी गई 35 एमएम की हिंदी फिल्मों का फिल्म महोत्सव/स्क्रीनिंग आयोजित की।

भारत संदर्श पत्रिका

पिछले कुछ वर्षों में मंत्रालय की अपनी पत्रिका इंडिया पर्सपेक्टिव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यह पत्रिका विस्तृत क्षेत्र के विषयों जैसे कि भारत की प्रगति की कहानी, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, साहित्य, वन्यजीव, फिल्म उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि पर केंद्रित है। यह पत्रिका अरबी, बहासा, इंडोनेशियाई, बंगाली, अंग्रेजी, प्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियाई, पश्तो, पर्सियन, पुर्तगीज, रूसी, सिंहल, स्पेनिश, तमिल और उर्दू सहित 17 भाषाओं में प्रकाशित होती है और विश्व के सभी कोने में भेजी जाती है।

भारत सरकार की गृह पत्रिका पुरस्कार योजना के अंतर्गत पत्रिका के हिंदी संस्करण 'भारत संदर्श' को भारत की राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पत्रिका को फ्रेंकफर्ट पुस्तक मेले, टुरिन के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले, इटली, रूस, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरूग्वे के फिल्म महोत्सवों और साथ ही लंदन पुस्तक मेले में जहां भारत बाजार केंद्रित देश था, वितरित किया गया।

पुस्तकें और अन्य प्रकाशन

पुस्तकें और प्रकाशनों के माध्यम से भारत की छवि को विदेशों में प्रदर्शित करना प्रभाग की प्रचार-प्रसार रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। विदेश स्थित मिशनों को प्रस्तुतिकरण के प्रयोजन के साथ-साथ उनके पुस्तकालयों के उपयोग के लिए भारतीय अर्थ-व्यवस्था, विदेश नीति, कला व संस्कृति, इतिहास एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी इत्यादि पर पुस्तकें भेजी गई। हमारे अधिकांश मिशनों ने महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्तूबर, 2009 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। प्रभाग ने इस अवसर पर वितरण के लिए इन मिशनों को महात्मा गांधी पर लिखीं पुस्तकें भेजी। विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों को विभिन्न पत्रिकाएं भी भेजी गई।

इस अवधि के दौरान प्रभाग द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें/प्रकाशन मुद्रित कराए गएः

(क) हिमालय क्षेत्र की खूबसूरती को दर्शाने वाली श्री अशोक दिलवाली की 'हिमालय विद लेंस एंड पैशन' नामक एक कॉफी टेबल पुस्तक।

(ख) सुविख्यात लेखकों द्वारा भारत के विविध पहलुओं पर लेख एवं फोटोग्राफ वाले 'इंडिया फॉर ए बिलियन रीज़ंश' नामक एक कॉफी टेबल पुस्तक।

(ग) जलवायु परिवर्तन पर एक पुस्तिका 'दी रोड टू कोपेनहेगनः इंडियाज पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज इश्यूज'

(घ) प्रधानमंत्री की अमरीका एवं फ्रांस यात्रा पर एक पुस्तिका।

प्रभाग ने स्लोवीन भाषा में 'दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटस विथ ट्रूथ' और बुल्गारिया भाषा में 'ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' जैसी पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए बर्लिन, स्लोवेनिया, लंदन, सोफिया, बोगोटा और मिंस्क स्थित अपने मिशन/केंद्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की।

■■

विदेश सेवा संस्थान 23

भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण

भारत विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण विदेश सेवा संस्थान के मुख्य कार्यकलापों में से एक है। परिवीक्षाधीन अधिकारी विदेश सेवा संस्थान में एक-वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेते हैं, ताकि मुख्यालय तथा विदेश स्थित मिशनों व केन्द्रों में उनके व्यावसायिक कैरियर के दौरान उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले व्यापक स्तर के कार्यों को करने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके।

भारतीय विदेश सेवा के 2007 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा होने पर बैच के सर्वश्रेष्ठ परिवीक्षाधीन अधिकारी के लिए विमल सान्याल स्वर्ण पदक सुश्री सतवंत खनालिया को प्रदान किया गया था तथा सर्वश्रेष्ठ शोधपत्र के लिए रजत पदक डॉ. एन.नंद कुमार को प्रदान किया गया था। ये पदक 26 मई, 2009 को एफएसआई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किए गए थे।

भारतीय विदेश सेवा के 2008 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारी दिसंबर, 2008 से ही विदेश सेवा संस्थान में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते रहे हैं। एक वर्ष लम्बे प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन व्याख्यानों के साथ-साथ विभिन्न संस्थानों से संपर्क के माध्यम से किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध व विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, रक्षा व सुरक्षा, आर्थिक राजनय, सांस्कृतिक राजनय तथा सामाजिक विकास आदि जैसे कई विषयों पर मोड्यूल शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रशासन, स्थापना, लेखे, प्रोतोकाल, रिपोर्टिंग निपुणता, राजभाषा नीति, बाह्य प्रचार, प्रतिनिधितात्मक निपुणता इत्यादि से संबंधित व्यवहारिक निपुणता से संबंधित मोड्यूल भी शामिल हैं। परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए पहली बार भारत की सांस्कृतिक विरासत पर मोड्यूल शामिल किया गया था।

प्रशिक्षण में भारतीय सेना और वायु सेना के साथ सम्पर्क, पश्चिम नौसेना कमांड व मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई की यात्राएं तथा अग्रणी वित्तीय संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ आदान-प्रदान शामिल है। प्रबंधन नेतृत्व तकनीकों व आर्थिक मुद्दों पर निपुणता विकसित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए 2 महीनों की अवधि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया गया था।

परिवीक्षाधीन अधिकारी भारत दर्शन के दौरे पर भी गए, ताकि वे समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, विरासत तथा देश की आर्थिक व पर्यटन सक्षमताओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों की जानकारी प्रदान करने के लिए तथा भारत के निकटवर्ती पड़ोसियों के बारे में उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने मई-जून, 2009 को 2 समूहों में कोलम्बो व थिम्फू स्थित भारतीय मिशनों का दौरा भी किया।

भारतीय विदेश सेवा के 2009 बैच के परीवीक्षाधीन अधिकारियों ने दिसंबर, 2009 में संस्थान में प्रवेश किया तथा उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है।

मंत्रालय के अधिकारियों का प्रशिक्षण

संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए पहला मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय व्यापार विद्यालय, हैदराबाद तथा विदेश सेवा संस्थान के परिसर में दो चरणों में 12 अप्रैल-1 मई 2009 तक आयोजित किया गया था। संयुक्त सचिव स्तर के 36 अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व भारतीय विदेश नीति, भारत का सुरक्षा परिवेश, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक राजनय, रणनीतिक निर्णय लेने की शक्ति तथा कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।

संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए दूसरा मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय व्यापार विद्यालय, हैदराबाद और विदेश सेवा संस्थान के परिसर में 4 जनवरी-16 जनवरी, 2010 तक दो चरणों में आयोजित किया गया था। संयुक्त सचिव स्तर के 36 अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

1991 बैच के निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए ई-मेल आधारित मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम जून 2008 में पूरा किया गया। भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम पूरा होने के अंतिम चरण में है तथा 1993 बैच के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम अभी चल रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे व भारतीय परिदृश्य के पांच मोड्यूल शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा मोनोग्राफ लिखना भी अपेक्षित है।

मंत्रालय के संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम 6-10 जुलाई, 2009 को आयोजित किया गया। अधिकारियों को मीडिया का सामना

करने तथा पत्रकार सम्मेलन आयोजित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मंत्रालय के अनुभाग अधिकारियों के लिए दो पुनश्चर्या कार्यक्रम 15-24 जून, 2009 तथा 4-13 नवंबर, 2009 को आयोजित किए गए। सहभागियों को संचार कुशलता तथा विदेश स्थित मिशनों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। सहभागियों ने एकीकृत मिशन लेखांकन साफ्टवेयर (आईएमएएस) में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

मंत्रालय के सहायकों व लिपिकों के लिए आधारभूत व्यावसायिक कार्यक्रम (बीपीसी) 15-24 जुलाई, 14-23 सितंबर, तथा 7-15 दिसंबर, 2009 को आयोजित किया गया। सहभागियों को मिशन से संबंधित शीर्षकों के साथ-साथ एकीकृत मिशन लेखांकन साफ्टवेयर आईएमएएस पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

मंत्रालय के सीधी भर्ती वाले सहायकों के लिए पहला प्रवेश कार्यक्रम 5-16 अक्तूबर, 2009 को आयोजित किया गया था। हालांकि, इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सामान्य शीर्षकों पर प्रशिक्षण भारतीय सचिवालय प्रशिक्षण व प्रबंध संस्थान के संकायों द्वारा दिया गया था परंतु मंत्रालय से संबंधित शीर्षकों पर मंत्रालय के संबद्ध प्रभागों के अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया था।

सूचना के अधिकार से संबंधित एक दिवसीय पाठ्यक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के सहयोग से 20 जनवरी, 2010 को विदेश सेवा संस्थान में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय विदेश सेवा के 2009 बैच के प्रवीक्षणार्थियों सहित मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

अन्य मंत्रालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सम्पर्क का संवर्धन

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए चौथा सीधा आदान-प्रदान कार्यक्रम 2-6 फरवरी, 2009 को विदेश सेवा संस्थान में 'भारतीय विदेश नीति की मुख्य धाराएं ' शीर्षक पर आयोजित किया गया था। विभिन्न राज्य पुलिस सेवाओं, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल इत्यादि के अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

मंत्रिमंडल सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 21-30 जुलाई, 2009 को 3- दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें भारतीय विदेश नीति तथा विदेश मंत्रालय व विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्य व ढांचा, पासपोर्ट/वीजा/काउन्सलर व अप्रवासन मामले, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, वियना सम्मेलन, कश्मीर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का प्रभाव व विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मामले शामिल हैं।

विदेश सेवा संस्थान में, सेना व वायु सेना के 12 अधिकारियों के लिए 22 दिसंबर, 2009 को एक दिवसीय ब्रीफिंग आयोजित की गई थी, जोकि शीघ्र ही विदेश स्थित हमारे मिशनों में रक्षा अताशे के रूप में अपनी तैनाती पर चले जायेंगे।

आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के महासचिव के निमंत्रण पर विदेश सेवा संस्थान के एक संयुक्त सचिव ने 8 दिसंबर, 2009 को अकादमी की यात्रा की तथा राज्य सिविल सेवा तथा राज्य राजस्व सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 'भारतीय विदेश नीति की बाध्यताएं' पर सम्बोधित किया, जबकि एक अन्य संयुक्त सचिव ने 21-23 अक्तूबर, 2009 को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादम, मसूरी में आयोजित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के दसवें सम्मेलन में विदेश सेवा संस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

विदेशी राजनयिकों के लिए कार्यक्रम

विदेश सेवा संस्थान ने पूरे विश्व के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अपने प्रयासों के रूप में विदेशी राजनयिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखा।

विदेशी राजनयिकों के लिए 47वां व 48वां व्यावसायिक पाठ्यक्रम एफएसआई द्वारा क्रमशः 11 फरवरी से 23 मार्च तथा 4 नवंबर से 3 दिसंबर, 2009 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। विभिन्न देशों के 24 राजनयिकों ने 47वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा 25 देशों के 29 राजनयिकों ने 48वें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग लिया। विदेशी राजनयिकों के लिए 49वां व्यावसायिक पाठ्यक्रम 23 फरवरी-23मार्च, 2010 के दौरान आयोजित किए जाने की सम्भावना है।

संस्थान ने तीन विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिनमें से एक मालदीव के 15 राजनयिकों, दूसरा अफगानिस्तान के 21 राजनयिकों तथा तीसरा आसियान के 37 राजनयिकों के लिए था। विदेशी राजनयिकों के लिए दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा विशेष पाठ्यक्रम के दौरान विदेशी राजनयिकों को दिल्ली के आस-पास स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व औद्योगिक महत्व के विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया। उन्होंने आगरा, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, बौद्ध गया व गोआ आदि का दौरा भी किया।

विदेश स्थित समकक्ष संस्थानों के साथ संपर्क

भूटान से शाही सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री लियोनपो थिनले ग्यामशो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर, 2009 में दोनों संयुक्त सचिवों से मुलाकात की। प्रशिक्षण विभाग की अध्यक्ष सुश्री एलोना फिशर कामं के नेतृत्व में एक इस्त्रायली प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर, 2009 में संबंधित संयुक्त सचिव से मुलाकात की। पोलैण्ड से पोलिश अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्थान तथा पोलैण्ड के विदेश कार्य व राजनयिक अकादमी के उप निदेशक डॉ. एंडरेज-अनानिकज के नेतृत्व में एक 3-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर, 2009 में डीन (एफएसआई) से मुलाकात की।

■■

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार

24

मंत्रालय के पास मिशनों/केंद्रों को शामिल करके विदेशों में हिंदी के प्रचार के लिए एक सुसंगठित कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर हिंदी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, पत्रिकाएं, कम्प्यूटर पर हिंदी सीखने के लिए साफ्टवेयर, हिंदी सीखने की सीडी और शब्दकोश इत्यादि सहित हिंदी पाठन सामग्री, विदेश स्थित हमारे मिशनों और केंद्रों को भेजी जाती हैं, ताकि वे उनको हिंदी के प्रचार कार्य में लगे शैक्षणिक संस्थानों/संगठनों को दिए जा सकें। मंत्रालय विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से हिंदी से संबंधित कार्यकलापों के लिए विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। वर्ष 2009-10 के दौरान विदेश स्थित लगभग 70 मिशनों/केंद्रों को हिंदी पुस्तकें, पाठ्य सामग्री व साफ्टवेयर भेजे गए। विदेश स्थित लगभग 100 मिशनों/पोस्टों को हिंदी पत्रिकाओं की आपूर्ति की गई। बेलारूस, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका सूरीनाम, हंगरी तथा ब्राजील में हमारे मिशनों/केंद्रों द्वारा आयोजित कक्षाओं मे हिंदी पढ़ाने के लिए कई अध्यापकों को मानदेय का भुगतान भी किया गया। 4 मिशनों/केंद्रों को विदेशों में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए विविध अनुदान भी स्वीकृत किए गए।

मंत्रालय केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में अध्ययन करने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य का समन्वय करता है। प्रति वर्ष विदेशी छात्रों को 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान 70 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।

मंत्रालय द्वारा विभिन्न देशों में आयोजित क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन की मुख्य रूप से विदेशी विद्यार्थियों, हिंदी विद्वानों तथा अध्यापकों द्वारा सराहना की गई है। मार्च, 2009 में मस्कट में एक 2-दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जिन विभिन्न देशों के स्थानीय विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, उनमें नियमित आधार पर ऐसे सम्मेलन आयोजित करने की मांग है। मंत्रालय विश्व हिंदी सम्मेलन तथा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के कई प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता देता रहा है। द्विपक्षीय संधियों, करारों, समझौता-ज्ञापनों, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, संसद प्रश्न जैसे दस्तावेज तथा संसद के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार किए जाते हैं।

राजभाषा के रूप में हिंदी में प्रशिक्षण मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न भाग है। 21 जनवरी, 2009, 12 फरवरी, 2009, 24 मार्च, 2009, 18 जून, 2009, 16 जुलाई, 2009 तथा 15 सितम्बर, 2009 में ऐसे छः कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल 210 अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

मंत्रालय ने मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा व हिंदी दिवस आयोजित किया। पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण व आलेखन, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, हिंदी सामान्य ज्ञान तथा हिंदी कविता पाठ जैसी प्रतियोगताएं आयोजित की गई थीं। इस बार मंत्रालय के अधिकारियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक थी तथा उनकी सहभागिता आशा से बढ़कर थी। हिंदी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह साउथ ब्लॉक के समिति रूम में आयोजित किया गया था तथा समारोह की मुख्य अतिथि विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। विदेश सचिव ने अपने भाषण में विदेशों में हिंदी के प्रचार के लिए हिंदी अनुभाग के योगदान की सराहना की।

हिंदी पखवाड़ा, 2009 के अवसर पर हमारे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों ने हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी लेखन प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। विदेश स्थित हमारे मिशनों ने भी 14 सितम्बर, 2009 को हिंदी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। विदेश स्थित 25 मिशनों/केंद्रों को इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विशेष अनुदान स्वीकृत किए गए थे।

हिंदी अनुभाग ने अकबर भवन में मंत्रालय के प्रशासनिक अनुभागों में तैनात कर्मचारियों के लिए 10-14 नवम्बर, 2009 को एक हिंदी कार्यशाला आयोजित की। प्रतिभागियों को सरकार की राजभाषा नीति व हिंदी में टिप्पण व आलेखन जैसे अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया गया था। अंतिम दिन सह-भागियों को हिंदी पुस्तकें भी वितरित की गईं। फरवरी, 2010 में मंत्रालय के अवर सचिवों के लिए ऐसी और कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है।

प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विदेश स्थित हमारे सभी मिशन/केंद्रों के साथ-साथ मुख्यालय में भी 'विश्व हिंदी दिवस' आयोजित किया जाता है। विदेश स्थित 31 मिशनों/केंद्रों को 10 जनवरी, 2010 को विश्व हिंदी दिवस आयोजित करने के लिए विशेष अनुदान

स्वीकृत किए गए। मुख्यालय में विदेश सेवा संस्थान में विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर इस समारोह में मुख्य अतिथि थीं। मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा व दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माध्यम से विदेशी विद्यार्थियों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने एक लघु कवि सम्मेलन भी आयोजित किया।

वर्ष 2009-10 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने निरीक्षण के लिए विशाखापट्टनम, चेन्नई, पुणे, सूरत व गाजियाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का दौरा किया। इन यात्राओं से संबंधित कार्य का समन्वय मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान हिंदी अनुभाग के अधिकारियों ने हिंदी के प्रयोग की प्रगति का आंकलन करने के लिए मंत्रालय के 25 अनुभागों तथा दो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया। इन कार्यालयों के कर्मचारियों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

■■

विदेश राज्य मंत्री (श्रीमती प्रनीत कौर) विजेता विदेशी हिंदी छात्र/छात्राओं के साथ-साथ में अपर सचिव (प्रशा.) और संयुक्त सचिव (ओएसडी स्थापना) भी उपस्थित।

हिन्दी पखवाड़ा 2009 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर विदेश सचिव श्रीमती निरुपमा राव और अपर सचिव (प्रशासन) श्री दिनकर खुल्लर।

25 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक समझ स्थापित और सुदृढ़ करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 1950 में भारतीय सांस्कृतिक परिषद की औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी जैसा कि संस्था अंतर्नियमों में उल्लेख किया गया है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- भारत के विदेशी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में भागीदारी करना।
- दूसरे देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- अन्य देशों और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देना और उसे सुदृढ़ करना।
- संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित और विकसित करना।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परिषद ने निरंतर कार्य किया है।

परिषद के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

भारत सरकार और अन्य अभिकरणों की ओर से विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृति योजनाओं का प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का कल्याण, भारतीय नृत्य एवं संगीत सीखने के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं परिसंवादों का आयोजन एवं उनमें भाग लेना, विदेशों में मुख्य सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेना, विदेशों में 'भारत महोत्सव ' का आयोजन करना, मंचीय कलाकारों की मंडलियों का आदान-प्रदान, विदेशों में मंचीय कलाकारों द्वारा व्याख्यान-प्रदर्शन का आयोजन; विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत विदेशों के प्रसिद्ध व्यक्तियों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और आगंतुकों का विदेश कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विदेशों में व्याख्यान देना, पुस्तकों का प्रस्तुतिकरण करने, दृश्य-श्रव्य सामग्री, कला-वस्तुएं तथा संगीत यंत्र मुहैया कराने के लिए विशेषज्ञ भेजे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ के लिए जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार हेतु सचिवालय उपलब्ध कराना, वार्षिक मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान का आयोजन करना, मौलाना आजाद निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना, भारत तथा विदेशों में वितरण के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों को बनाए रखना एक समृद्ध पुस्तकालय और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पांडुलिपियों का रख-रखाव, दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटल बनाना।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 14 क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलूर, चंडीगढ़, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, पुणे, वाराणसी, शिलांग, कटक और गुवाहाटी में कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों में स्थानीय निकायों/संगठनों के साथ समन्वय और परिषद की छात्रवृत्ति योजना के तहत अध्ययन कर रहे विदेशी छात्रों को सहायता प्रदान करना शामिल है। क्षेत्रीय कार्यालय सांस्कृतिक शिष्टमंडलों और परिषद के विशिष्ट आगंतुकों को संभारिकी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं।

परिषद का प्राथमिक उद्देश्य भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ-बूझ को स्थापित, पुनर्जीवित तथा सुदृढ़ करना है। विदेशों में भारत की सामासिक सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरुकता और समझ के बढ़ाने के उद्देश्य से परिषद विदेश स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में पीठों को स्थापति किया है। इन पीठों में भारतीय प्रोफेसरों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर प्रतिनियुक्ति की जाती है।

फिलहाल परिषद द्वारा द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, विदेशों में हिन्दी प्रचार-प्रसार योजना और परिषद के अपने कार्यक्रमों के तहत 19 दीर्घावधिक पीठें भारतीय भाषाओं तथा भारत के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए संचालित की जा रही है। परिषद पोर्ट आफ स्पेन (ट्रिनिडाड टोबैगो), बुडापेस्ट (हंगरी), मास्को (रूस), वारसा (पोलैंड), सोफिया (बुल्गारिया), बीजिंग (चीन), अंकारा (टर्की), ब्रुसेल्स (बेल्जियम) और वालाडोलिड (स्पेन) में हिन्दी पीठें; संस्कृत पीठें बैंकाक (थाइलैंड) और पेरिस (फ्रांस) में; वारसा (पोलैंड) में एक तमिलपीठ; ओश (किर्गीस्तान) और ताशकंद (उजबेकिस्तान) में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पीठ; जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में शांति अध्ययन पीठ; पोर्ट आफ स्पेन (ट्रिनीडाड टोबेगो) में एक फिल्म/सिनेमा अध्ययन पीठ और बुखारेस्ट (रोमानिया), पारामारिबो (सूरीनाम) और जलालाबाद अफगानिस्तान में तीन शिक्षकों के लिए हिन्दी पीठें चला रही है।

परिषद 11 आवर्ती अल्पकालिक पीठ भी चला रही है, जो उलानबातर (मंगोलिया) में संस्कृत एवं बौद्ध अध्ययन, पेन्सिलवेनिया (यूएसए) में भारतीय साहित्य, जर्मनी के पांच विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन, पेरिस (फ्रांस) में भारतीय अर्थव्यवस्था, जोहांसवर्ग

(दक्षिण अफ्रीका) तथा गुआंमहु (चीन) में भारत चीन तुलनात्मक अर्थशास्त्र अध्ययनपीठ, तथा तेल अबीब (इजराइल) में मानविकी और सामाजिक विज्ञान अध्ययनपीठ के रूप में कार्य कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त परिषद ने विस्तार योजना के तहत निम्नलिखित पीठों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं- स्लोवेनिया (हिन्दी अल्पकालिक), यूके (अर्थशास्त्र, अल्पकालिक), दक्षिण कोरिया (अर्थशास्त्र अल्पकालिक), ग्रीस (अर्थशास्त्र, अल्पकालिक), जापान (मानविकी अल्पकालिक), क्रोएशिया (हिन्दी दीर्घकालिक), अमेरिका (हिन्दी दीर्घकालिक), तुर्कमेनिस्तान (हिन्दी दीर्घकालिक), डेनमार्क (अर्थशास्त्र अल्पकालिक), अमेरिका (अहिंसा/शांति अध्ययन दीर्घकालिक)।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को छात्रवृत्ति एवं कल्याण

भा.सां.स.प. की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है विदेशी छात्रों को डॉक्टोरल, स्नातकोत्तर, स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के साथ-साथ इंजीनियरी, फार्मेसी, व्यवसाय प्रशासन और लेखाशास्त्र जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन। भा.सां.स.प. प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत भारत में इस समय लगभग 1368 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। अप्रैल-नवंबर, 2009 के दौरान परिषद् ने अफगानी छात्रों के लिए 500 छात्रवृत्तियों सहित 2226 नई छात्रवृत्तियां दी हैं, जिसमें 675 छात्रवृत्तियां अफगान छात्रों के लिए तथा 526 अफ्रीकी छात्रों के लिए हैं।

परिषद विदेशी छात्रों के लिए नियमित रूप से 'शीत कालीन और ग्रीष्म कालीन शिविर' व 'अध्ययन दौरे' आयोजित करता है।

क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विदेशी छात्रों के लिए किए जा रहे क्रियाकलापों की समीक्षा करने और विदेशी छात्रों के कल्याण से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डॉ. कर्ण सिंह, अध्यक्ष, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने 26 जून, 2009 को आजाद भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की। मुख्यालय के सभी अनुभाग प्रमुखों ने भी बैठक में भाग लिया।

उन्मुखीकरण कार्यक्रम

परिषद द्वारा भा.वि.से. के 2008 बैच के परिवीक्षार्थियों के लिए 25-29 मई, 2009 तक एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके लिए व्याख्यानों/व्याख्यान-सह-प्रदर्शनों/संग्रहालयों दीर्घाओं और ऐतिहासिक स्थलों को देखने का भी प्रबंध किया गया है। विख्यात व्यक्तियों द्वारा भारतीय पारंपरिक एवं आधुनिक कला और कला प्रसार वास्तु धरोहर, संस्कृति तथा थियेटर रोमांच और फिल्मों जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए गए।

परिषद् ने कमानी आडिटोरियम, नई दिल्ली में 11 नवंबर, 2009 को **'संस्कृति के माध्यम से मैत्री'** नामक 17वां अंतर्राष्ट्रीय छात्र सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया। इसमें काफी लोगों ने भाग लिया और इसे अच्छा मीडिया कवरेज मिला।

भारत आने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत वर्ष के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विदेशी मंचीय कलाकारों के भारत-दौरों का आयोजन करती है। इन मंडलियों की मेजबानी द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत और साथ ही विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सिफारिशों और भारत स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों और सांस्कृतिक केन्द्रों के अनुरोधों पर की जाती है। अप्रैल-नवंबर, 2009 की अवधि के दौरान परिषद ने जिनेवा, मलेशिया, मारीशस, अमरीका, पाकिस्तान, यूके, उजबेकिस्तान, श्रीलंका, स्पेन, इजिप्ट, तंजानिया, पेरिग्वे, ब्राजील, ईरान, कोलंबिया, पुर्तगाल, पोलैंड, ट्रिनिडाड और टोबैबो तथा वेनेजुएला से 19 विदेशी सांस्कृतिक मंडलियों के दौरों की मेजबानी की। परिषद ने दिल्ली में ठुमरी उत्सव, मल्हार उत्सव और श्रीनगर में सूफी संगीत उत्सव सहित 17 विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए।

प्रकाशन

परिषद का अपना एक महत्वाकांक्षी प्रकाशन कार्यक्रम है, जिसमें वर्षों से निरंतर वृद्धि हुई है। परिषद ने पांच अलग-अलग भाषाओं में छः पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं जो इस प्रकार हैं- 'भारतीय क्षितिज' और 'अफ्रीका त्रैमासिक' (दोनों अंग्रेजी त्रैमासिक), 'गंगनांचल' (हिन्दी त्रैमासिक), 'पेपेल्स-डी-ला-इंडिया' (स्पेनिश अर्द्धवार्षिक), रेनकांटरे अवेक ले इंडे (फ्रेंच अर्द्धवार्षिक) और 'थकाफत-उल-हिंद' (अरबी त्रैमासिक)।

सम्मेलन एवं संगोष्ठियां

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद ने विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले बुद्धिजीवियों, मत निर्माताओं और शिक्षाविदों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सम्मेलन एवं संगोष्ठियों के आयोजन में सहयोग किया। इनमें निम्नलिखित शामिल थेः (क) जून 2009 में प्राग और बाली में इंडोलाजी सम्मेलन, (ख) दिल्ली में 'निकोलस रोयरिच' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, (ग) 24-26 सितंबर, 2009 इंडोलोजी कांफ्रेंस सोफिया और अल्माटी में (19-20 नवंबर, 2009) में। मेजबान देश भारत से आए यूरोप तथा मध्य एशिया से भारत विज्ञानियों ने इस सेमिनार में भाग लिया। (घ) परिषद् ने एक कोलम्बियाई सांस्कृतिक सप्ताह का भी आयोजन किया और नई दिल्ली में 20-26 अक्तूबर, 2009 में कोलंबिया दूतावास के सहयोग से दिल्ली और कोलकाता में कवियों के बातचीत का सत्र भी आयोजित किया गया। परिषद ने भारत में 17 अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित करने के लिए कई संगठनों और महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे आईआईटी, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जामिया मीलिया इस्लामिया को सहयोग दिया, जिसमें अनेक प्रमुख भारतीय और विदेशी विद्वानों ने भाग

लिया और उर्दू तथा पर्शियन भाषा सहित विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर विचार व्यक्त किए।

अर्ध प्रतिमाएं और प्रदर्शिनियाँ

परिषद द्वारा वेलेयू पुस्तकालय, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन राज्य, एस्ट्रेचकोना पार्क ओटावा (कनाडा) और पियाजा गांधी, सैन डोनेटो, मिलान इटली में महात्मा गांधी की तीन प्रतिमाएं भेजी गईं। महात्मा गांधी की तीन अर्धप्रतिमाएं पोर्टारिको विश्वविद्यालय, पीआर न्यूयार्क, विसेंजा, मिलान इटली और यूएनएसडब्ल्यू विश्वविद्यालय, सिडनी में स्थापित करने के लिए भेजी गई। परिषद ने रवीन्द्र नाथ टैगोर की दो प्रतिमाएं स्थायी रूप से लगाने के लिए उस्ट कामेनोगोर्स्क सिटी कजाकिस्तान और टैगोर म्यूजियम बंगलादेश भेजी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने श्री अरविंदो की एक प्रतिमा स्थायी रूप से यूनेस्को मुख्यालय में लगाने के लिए पेरिस भेजी।

भा.सा.स. परिषद् ने आठ प्रमुख प्रदर्शनियों (भा.सा.स.परि.का अपना संग्रह) जिसमें 'सेलेब्रेटिंग वुमन-अमृता शेरगिल रीविजिटेड' सियोल (कोरिया) अस्ताना (कजाकस्तान) और काबुल (अफगानिस्तान); 'वूमन बाई वूमन ' प्रदर्शनी अल्जीरिया, सार्क पेंटिंग प्रदर्शनी श्रीलंका, बंगलादेश और मालदीव एक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी 'द मुराल आफ इंडिया ' रोम, इटली एक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी 'लीगेसी आफ कम्पैशन ' लंदन, बर्लिन और केसाडीला इंडिया वैलाडोलिड (स्पेन) एक प्रदर्शनी (पहला सेट) 'कल्पना-मास्टरपीसेज आफ फिगरेटिव इंडियन कन्टेम्पौटरी पोंटोंस' लंदन; कैसा डी ला इंडिया, वालाडोलिड (स्पेन) और बर्लिन (जर्मनी) प्रदर्शनी का एक सेट पोर्ट आफ स्पेन और सूरीनाम तथा तीसरा सेट फिलीपींस भेजा गया।

परिषद ने कलाकारों द्वारा विदेश ले जाई जा रही प्रदर्शनियों को भी प्रायोजित किया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (क) सुश्री नंदिता पाल चौधरी और उनके सहयोगी डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में मई, 2009 में लगाई गई प्रदर्शनी 'मेक आर्ट-स्टॉप एड्स ' में शामिल होने के लिए, (ख) श्री आदित्य आर्य साथ में कुलवंत राय की फोटो प्रदर्शनी, 'हिस्ट्री इन द मेकिंग' मई/जून 2009 कनाडा और अमरीका; (ग) श्री आर.के. भटनागर पेंटिंग प्रदर्शनी के साथ सूरीनाम जून, 2009; (घ) सुश्री अपराजिता जैन, श्री सदाशिव कुनकोलियंकर, श्री सुशांत मंडल और सुश्री मिथुसेन अपनी प्रदर्शनी 'कांटेम्पोरेरी इंडियन आर्ट फेस्टिवल ' म्यूजियम कांटेम्पोरेरी आई (एमओसीए) शंघाई में जुलाई, 2009 में; (ड़) श्री तिलक गिताई और श्री प्रतीक गिताई 'रागमाला-द मिसिंग लिंक' के साथ जो नेहरू सेंटर लंदन और टैगोर सेंटर बर्लिन में अगस्त से सितंबर, 2009 तक लगाई गई। परिषद ने एक चार सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को वायुयान भाड़ा प्रदान किया जिसने 'चलो इंडियाः ए न्यू इरा ऑफ इंडियन आर्ट ' प्रदर्शनी में वियना में 1-3 नवंबर, 2009 में भाग लिया, डरबन और जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में 1 सितंबर-5 अक्तूबर 2009 तक लगाई जा रही प्रदर्शनी 'पेंटेडनरे टिव्स' के प्रदर्शकों को वायुयान भाड़ा दिया गया; सुश्री अनुराधा ऋषि को 'नेचर इन पीस '- महात्मा को श्रद्धांजलि नेहरू केन्द्र लंदन (यूके) 29 सितंबर-1 अक्तूबर 2009 को और गांधी जी पर फोटो प्रर्दशनी गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली में तैयार की गई तथा सितंबर, 2009 में क्रोएशिया भेजी गई प्रदर्शनी के लिए वायुयान भाड़ा प्रदान किया।

परिषद ने देश में आने वाली/स्थानीय नौ प्रदर्शनियों और यात्राओं को आयोजित कियाः

(1) प्रदर्शनीः संस्कृति मंत्रालय से पेंटिंग आफ कांटेम्पोटेरी आर्ट, मिस्र में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर आट्र्स नई दिल्ली में मई 2009; (2) प्रदर्शनी 'विनसम स्ट्रोक्स' सुश्री दीपा सेठ भांडो श्रीधरनी गैलरी, नई दिल्ली-110001, जून 2009 (3) फोटोग्राफिक प्रदर्शनी-सत्यजीत रे एनजीएमए द्वारा आरटीसी, आईसीसीआर, कोलकाता द्वारा जून 2009 में लगाई गई; (4) अक्तूबर 2009 में पेंटिंग प्रदर्शनी मिस्र के प्रसिद्ध चित्रकारों के दल द्वारा ललित कला अकादमी नई दिल्ली में; (5) प्रसिद्ध क्यूबायी चित्रकार सुश्री जैदा डेलरियो की प्रदर्शनी ललित कला अकादमी नई दिल्ली 2-7 नवंबर, 2009 (6) चित्रकला प्रदर्शनी 'दिस,दैट और देन' सुश्री सचि खन्ना रोमेन रोलैड, एलाएंस, फ्रैंचाइज नई दिल्ली 13-15 नवंबर, 2009। परिषद ने श्री लिम्पो सी.के. दोरजी, अध्यक्ष, रायल ग्रीवी परिषद के नेतृत्व में भूटान की टीम को भारत में ब्रांज कास्टिंग स्किल से परिचय के लिए की गई 3-7 नवंबर, 2009 की यात्रा को प्रायोजित किया। टीम भारतीय वास्तु कलाकारों और कलाकारों से मुलाकात की और उनकी कार्यशालाओं/स्टूडियों का कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और दिल्ली का दौरा किया। परिषद ने चित्रकला प्रदर्शनी की और रोमानिया के दो कलाकारों सुश्री विक्टोरिया लीना ड्रगो मिरेस्कू और सुश्री संडा वुटियो की यात्राओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की। प्रदर्शनी आरटीसी आईसीसीआर कोलकाता तथा आजाद भवन कलादीर्घा नई दिल्ली में 27 नवंबर-5 दिसंबर 2009 तक लगाई गई।

विदेश भेजे गए सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

अवधि के दौरान परिषद ने 63 (10 नवंबर, 2009 तक) सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों को प्रायोजित किया।

परिषद ने सुश्री गीता राधाकृष्णन (मोहिनीअट्टनम), सुश्री सुशीला मेहता (भरतनाट्यम), सुश्री अदिति मंगलदास (समकालीन नृत्य समूह 'दृष्टिकोण') सुश्री श्रुति बंधोपाध्याय (मणिपुरी नृत्य); सुश्री संगीता दास (ओडिसी), श्री हरि और सुश्री चेतना (कत्थक), सुश्री अरुसी मुद्गल (ओडिसी) पं. देवू चौधरी (सितार) श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन (गजल) के कार्यक्रमों को प्रायोजित किया।

परिषद द्वारा उत्कृष्ट कलाकारों के समन्वित नृत्य समूह- जिसमें उस्ताद अली अहमद हुसैन खान (शहनाई), सुश्री मोम गांगुली (मोहिनीअट्टम), सुश्री बाम्बे जयश्री रामनाथ (कर्नाटक गायन), श्री टी.एम. कृष्णा (कर्नाटक गायन), विश्व भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के गायक मंडल, सुश्री दक्ष सेठ नृत्य कंपनी,

केरल शामिल थे- को 38 यात्रा अनुदान प्रदान किये गये। श्री जयचन्द्रन पलाजी की अगुवाई में अट्टाकलारी सेंटर फार मूवमेंट एण्ड आर्ट्स के समसामयिक नृत्य समूह, श्री वी. पी. धनंजयन और सुश्री शांता धनंजयन की अगुवाई वाले भरतनाट्यम नृत्य समूह और शगुना पुरुषोत्तम की अगुवाई वाले गायन समूह को भी 50 यात्रा अनुदान प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा कई अन्य उत्कृष्ट कलाकारों जैसे श्री दीपक कुमार चक्रवर्ती (तबला), पं. विश्वमोहन भट्ट (मोहन वीणा) और सुश्री मनीषा गुल्यानी (कत्थक) को भी यात्रा अनुदान प्रदान किये गये।

भारत उत्सव

परिषद द्वारा भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और पारस्परिक समझ बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए गयेः-

रूस में भारत वर्ष

परिषद की उत्सव इकाई द्वारा 'रूस में भारत वर्ष' के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया गया, जिसका उद्घाटन आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉ. कर्ण सिंह और रूस के उप प्रधान मंत्री श्री झुकोव की उपस्थिति में मास्को स्थित न्यू बोल्सोई थियेटर में 31 मार्च, 2009 को किया गया। उद्घाटन समारोह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की अनवरत प्रस्तुतियों पर आधारित था और उसमें भारत के भिन्न-भिन्न भागों से आए आठ कलाकार समूहों ने हिस्सा लिया।

परिषद द्वारा राष्ट्रपति की रूस यात्रा के दौरान 3 सितंबर, 2009 को एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति भी आयोजित की गई, जिसमें पूरे भारत से आए लोक नर्तकों के 18 कलाकार समूह थ, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वर्ष के दौरान परिषद द्वारा रोसिजो फेडरल स्टेट एण्टिटी स्टेट म्यूजियम एण्ड इक्जबीसन सेंटर के सहयोग से निम्नलिखित चार प्रदर्शनियां आयोजित की गईं (1) लियो टालस्टाय और महात्मा गांधी': स्टेट लियो टालस्टाय म्यूजियम (मास्को) में एक विलक्षण विरासत जिसे लियो टालस्टाय के आवास लियो टालस्टाय यस्नया पोल्याना (तुला) के म्यूजियम-एस्टेट में प्रदर्शित किया गया; (2) आर्ट म्यूजियम में 'ए जर्नी आफ इंडियन सिनेमा ' जिसका नामकरण ए. तुगानोवा (नार्थ ओसेटिया ब्लादिकावकाज गणराज्य-अलानिया) के नाम पर किया गया यह आयोजन 10 नवंबर, 2009 को किया गया, (3) 'दि माडर्न आर्ट आफ इंडियाः विक्टोरियल ट्रैजेक्टरीज' (एनजीएमए, नई दिल्ली की कलाकृति संकलन); (4) 'डिवाइन्स एण्ड मार्टलस': रूस में भारत वर्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी (भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के संकलन से ली गई कलाकृतियां)।

परिषद द्वारा 'भारत वर्ष ' समारोहों में भाग लेने के लिए लगभग 38 कला समूहों को रूस भेजने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से 37 समूह पहले ही रूस में कार्यक्रम कर चुके हैं। उत्सव का औपचारिक समापन 7 दिसंबर, 2009 को किया गया। इस अवसर पर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान की विशेष प्रस्तुति आयोजित की गई।

अर्जेंटीना में भारत उत्सव

परिषद द्वारा दो नृत्य मंडलियों - सुश्री सैलजा की अगुवाई में एक पाँच सदस्यों वाले कुचीपुड़ी नृत्य समूह और गुजरात के श्री रजभाई सिडा की अगुवाई में एक 12 सदस्यों वाले डाण्डिया समूह को 4-15 नवंबर, 2009 को अर्जेंटीना में हुए भारत उत्सव के लिये प्रायोजित किया गया।

इण्डोनेशिया में भारत उत्सव

परिषद द्वारा श्री दलजीत सिंह की अगुवाई में 14 सदस्यों वाला भांगड़ा समूह, श्री सुबीर मलिक की अगुवाई में 10 सदस्यों का परिक्रमा बैण्ड ग्रुप और श्री विश्वमोहन भट्ट की अगुवाई में तीन सदस्यों का मोहन वीणा दल, इन तीन कलाकार समूहों को भेजकर इण्डोनेशिया में भारत उत्सव में भी भाग लिया।

विदेश के दौरा कार्यक्रम

परिषद द्वारा भारतीय प्रबुद्धजनों, विद्वानों, शिक्षाविदों ओर कलाकारों की यात्राओं को भी प्रायोजित किया जाता है, ताकि वे विदेशों में संगोष्ठियों, गोष्ठियों, अध्ययन दौरों और सम्मेलनों में हिस्सा ले सकें।

अप्रैल-नवंबर, 2009 की अवधि के दौरान परिषद द्वारा विश्व के विभिन्न हिस्सों के लिए 82 प्रबुद्ध विद्वानों की यात्राएं प्रायोजित की गईं।

प्रतिष्ठित आगन्तुक कार्यक्रम

भारत और दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और परस्पर समझ को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत बनाने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में परिषद द्वारा अपने प्रतिष्ठित आगन्तुक कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य देशों से विशिष्ट जनों और विज्ञ विद्वानों, प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों और कलाकारों की भारत यात्राओं को भी सहज बनाया जाता है। इस अवधि के दौरान परिषद द्वारा यूक्रेन, जापान, कोरिया गणराज्य, जर्मनी, हंगरी, अमेरिका और स्पेन जैसे भिन्न-भिन्न देशों से 11 प्रतिष्ठित आगन्तुकों की मेजबानी की।

पुरस्कार

भारत की राष्ट्रपति ने 14 जनवरी, 2010 को आयोजित विशेष समारोह में आइसलैंड के राष्ट्रपति डॉ. ओलाफुर रगनार ग्रिमसन को वर्ष 2007 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया।

■■

26 भारतीय विश्व कार्य परिषद

1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के दौरान भारतीय विश्व कार्य परिषद द्वारा आयोजित और नियोजित किए गए कार्यक्रम निम्नानुसार हैः

1 अप्रैल, 2009 से 29 जनवरी, 2010 के बीच आयोजित किए गए कार्यक्रमः

1)	व्याख्यान	7
2)	संगोष्ठियां	15
3)	द्विपक्षीय नीतिगत वार्ताएं	13
4)	समूह चर्चाएं/पृष्ठभूमि सार	3
5)	अन्य कार्यक्रम (पुस्तक विमोचन आदि)	2
कुल		40

कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैः

1) पूर्व विदेश सचिव श्री शिव शंकर मेनन की अध्यक्षता में 'भारत और चीनः अतीत और भविष्य ' विषय पर सुप्रसिद्ध चीनी विद्वान प्रोफेसर वी. पी. दत्त द्वारा व्याख्यान (4 सितंबर, 2009)।

2) विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर द्वारा 'भारत-यूरोपीय संघ मंचः प्रभावी बहुपक्षवाद के परिप्रेक्ष्य में' विषय पर मूल-सिद्धांत भाषण (8-9 अक्तूबर, 2009)।

3) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः 'उभरता हुआ चीनः एशिया में भागीदारी की संभावनाएं ' विषय पर एशियाई संबंध सम्मेलन श्रृंखला-उद्घाटन भाषण भारत के उप राष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी द्वारा और समापन भाषण विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर द्वारा दिया गया (21-23 नवंबर, 2009)। इस सम्मेलन में 25 विदेशी विद्वानों द्वारा संबोधन किया गया और शिक्षाविदों, राजनयिकों, अधिकारियों आदि सहित 300 से अधिक व्यक्तियों द्वारा हिस्सा लिया गया।

4) आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री श्री केविन रुड द्वारा रणनीतिक मामलों पर प्रमुख भाषण- युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. एम. एस. गिल द्वारा अध्यक्षता की गयी (12 नवंबर, 2009)।

5) लोवी इंस्टीट्यूट, आस्ट्रेलिया के साथ भारतीय विश्व कार्य परिषद का द्वितीय भारत-आस्ट्रेलिया गोल मेज (12-13 नवंबर, 2009)।

6) थाइलैंड के विदेश मंत्री श्री कैसिट पिरोम्या के साथ वार्ता (24 दिसंबर, 2009)।

7) प्रोफेसर लॉर्ड भीखू पारेख द्वारा 'विश्व में भारत का स्थान' विषय पर भारत विकास संघ (एआईडी) का वार्षिक व्याख्यान (8 जनवरी, 2010)।

भारतीय विश्व कार्य परिषद द्वारा आयोजित और नियोजित कार्यक्रमों की सूची संलग्न है (अनुबंध-XVI)।

भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए विश्वविद्यालयों तथा केंद्रों के साथ आउटरीच कार्यक्रमः

इस अवधि के दौरान विश्व कार्य परिषद द्वारा निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गएः

1) मनिपाल उच्च अनुसंधान समूह, मनिपाल विश्वविद्यालय

2) राजनीति शास्त्र विभाग, कला और सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय कालेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय

भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए विश्वविद्यालयों तथा केंद्रों के साथ आउटरीच कार्यक्रमः

अवधि के दौरान भारतीय विश्व कार्य परिषद द्वारा निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गएः

1) अर्जेंटिना अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिषद

2) यूरोपीय संघ सुरक्षा अध्ययन संस्थान (ईयूआईएसएस)

भारतीय विश्व कार्य परिषद में विदेशी प्रतिनिधियों के दौरे

उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित विदेशी प्रतिनिधियों की परिषद द्वारा मेजबानी की गयीः

1) डॉ. अहमद शहीद, मालदीव गणराज्य के विदेश मंत्रीः 29 जुलाई, 2009

2) श्री झला नाथ खनाल, अध्यक्ष नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टीः (6 नवंबर, 2009

3) डॉ. जैमे बर्मडेज, कोलंबिया गणराज्य के विदेश मंत्रीः 11 नवंबर, 2009

4) श्री केविन रुड, आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्रीः 12 नवंबर, 2009

5) श्री मनौचेहर मोट्टाकी, ईरान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्रीः 17 नवंबर, 2009

6) श्री कसिट पिरोम्या, थाइलैंड के विदेश मंत्रीः 24 दिसंबर, 2009

7) प्रोफेसर लॉर्ड भिखू पारेखः 8 जनवरी, 2010

भारतीय विश्व कार्य परिषद एक बौद्धिक संपदा और भारत में विदेशी मामलों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उपरोक्त अवधि के दौरान विकास करता रहा।

अवधि के दौरान, भारतीय विश्व कार्य परिषद ने निदेशक (अनुसंधान) और अनुसंधान अध्येताओं की नियुक्ति द्वारा अपने अनुसंधान स्कंध को मजबूत बनाया। वर्तमान में छह अनुसंधान अध्येता और एक अनुसंधान निदेशक जो क्षेत्र अध्ययन में विशेषज्ञ, अपनी-अपनी विशेषज्ञता के भौगोलिक क्षेत्रों में विदेश और घरेलू नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान स्कंध का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करना, क्षेत्र विशेष के बारे में भारत की विदेश नीति को समझना और रूस तथा यूरेशिया, चीन, जापान, दक्षिण एशिया जिसमें अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया-उत्तर अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया भी शामिल हैं। क्षेत्रों पर कार्य के लिए भारत के लिए नीतिगत विकल्पों को तैयार करना है। अनुसंधान स्कंध भारतीय विश्व कार्य परिषद की अनुसंधान समिति के साथ निकट सहयोग के साथ कार्य करता है। भारतीय विश्व कार्य परिषद अनुसंधान अध्येताओं ने संगोष्ठियों में नियमित भागीदारी की, व्याख्यान दिए और विभिन्न ख्यातिप्राप्त पत्रिकाओं में शोध प्रबंधों का योगदान किया।

अनुसंधान संकाय के माध्यम से भारतीय विश्व कार्य परिषद का उद्देश्य पूरे विश्व की विभिन्न घटनाओं पर आधारित पुस्तकों, मोनोग्राफों और लेखों सहित विभिन्न प्रकाशनों का संपादन करना है, जिन्हें नीति निर्माताओं द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

भारतीय विश्व कार्य परिषद की पत्रिका 'इंडिया क्वार्टरली' (आईक्यू) इस अवधि के दौरान नियमित तौर पर प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय विश्व कार्य परिषद भारतीय विदेश नीति पर चौथी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर, 2009) के लिए आईक्यू के विशेष अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने इस अंक के लिए मुख्य लेख दिया है, जिसमें भारतीय विदेश सेवा के ख्यातिप्राप्त सेवानिवृत्त सदस्यों द्वारा भेजे गए भारत के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर आधारित लेख प्रकाशित किए जाएंगे।

भारतीय विश्व कार्य परिषद ने अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 के दौरान आयोजित एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग संबंधी परिषद से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लियाः

1. 30 अप्रैल-2 मई 2009 तक बैंकाक, थाइलैंड में आयोजित परराष्ट्रीय अपराध हब संबंधी सीएससीएपी अध्ययन समूह बैठक में श्री सी. डी. सहाय ने हिस्सा लिया।

2. 25-26 मई, 2009 को सिंगापुर में आयोजित नौसेना विस्तार पर सीएससीएपी अध्ययन समूह बैठक में कैप्टन पी. के. घोष ने हिस्सा लिया।

3. 1 जून, 2009 से कुआलालाम्पुर, मलेशिया में आयोजित 31वीं संचालन समिति की बैठक में राजदूत श्री के. के. एस. राणा और डॉ. ए. वी. एस. रमेश चंद्रा ने भाग लिया।

4. 1-4 जून, 2009 तक कुआलालाम्पुर में आयोजित 23वीं एशिया प्रशांत गोलमेज बैठक में डॉ. पी. के. दधीच और श्री अजय साहनी ने भाग लिया।

5. 30-31 मई, 2009 को कुआलालाम्पुर में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर सीएससीएपी अध्ययन समूह बैठक।

6. 29 जून, 2009 को बीजिंग, चीन में आयोजित सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोके जाने संबंधी सीएससीएपी अध्ययन समूह बैठक और 1-2 जुलाई, 2009 को बीजिंग में आयोजित एआरएफ आईएसएम नाभिकीय निरशस्त्रीकरण पर हुई बैठक में राजदूत श्री दिलीप लाहिड़ी ने हिस्सा लिया।

7. 10-11 अक्तूबर, 2009 को फुकेट, थाइलैंड में आयोजित पराराष्ट्रीय अपराधी हब संबंधी सीएससीएपी अध्ययन समूह बैठक में श्री सीडी सहाय ने हिस्सा लिया।

8. 15-16 नवंबर, 2009 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित सीएससीएपी की 32वीं अध्ययन समूह बैठक और 7वें महासम्मेलन में राजदूत श्री दिलीप लाहिड़ी ने लिस्सा लिया।

9. फारचूना होटल, हनोई, वियतनाम में 6-8 दिसंबर, 2009 को आयोजित एशिया प्रशांत में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रयास का विरोध संबंधी सीएससीएपी अध्ययन समूह की 10वीं बैठक।

10. फारचूना होटल, हनोई, वियतनाम में 8-10 दिसंबर, 2009 को आयोजित सीएससीएपी निर्यात नियंत्रण विशेषज्ञ समूह की 5वीं बैठक।

भारतीय विश्व कार्य परिषद पुस्तकालय धीरे-धीरे विश्व मामलों से संबंधित सूचना और आंकड़ों के प्रमुख केंद्र के रूप में अपने विगत वर्षों के गौरव को पुनः प्राप्त कर रहा है। पुस्तकालय के सदस्यों की संख्या की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और जनवरी, 2010 में इसके सदस्यों की संख्या 627 थी। इस संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पुस्तकालय का प्रयोग करने वाले अनुसंधानकर्ताओं की अब हुई बढ़ोत्तरी इस स्थान की बढ़ती लोकप्रियता की साक्षी है। पुस्तकालय में आटोमेशन और कंप्यूटरीकरण 2009 के आरंभ में शुरू हुआ और लगभग

75000 पुस्तकों के नाम पहले ही सिस्टम में डाले जा चुके हैं। पुस्तकों का कैटेलॉग 31 जनवरी, 2010 तक ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अनुसंधानकर्ताओं को सप्रू हाउस के पुस्तक भंडार को जानने और उसका उपयोग कर पाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब सप्रू हाउस के सदस्यों, प्रबुद्ध संस्थाओं और ख्यातिलब्ध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकायों जैसे डेलनेट, आईएएसएलआईसी, आईएफएलए शामिल हो चुके हैं। हमारे अनुसंधान संकाय और अनुसंधान विद्यार्थियों के लिए सूचना प्राप्त करने या सामग्रियां उधार लेने के प्रयोजन से इन सदस्यों की क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया जाता है।

भारतीय विश्व कार्य परिषद को अमेरिकन सेंटर, ब्रिटिश काउंसिल, भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नेहरू स्मारक और म्यूजियम पुस्तकालय, केंद्रीय सचिवालय, डेलनेट और विभिन्न अन्य प्रख्यात पुस्तकालयों से दैनंदिन आधार पर प्रश्न प्राप्त होते हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के मीडिया कर्मी संदर्भ सूचना के लिए पुस्तकालय आते हैं। पुस्तकालय के पुस्तक भंडार में अनेक नई पुस्तकें जोड़ी जा रही हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण बिंदु और अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य, पूर्व और पश्चिम एशिया से संबंधित विदेश नीति और सुरक्षा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे विषयों पर पुस्तकें। प्रसिद्ध भारतीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और अनुसंधानकर्ता समान रूप से पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रेस क्लिपिंग का संदर्भ लेते हैं। भारतीय विश्व कार्य परिषद पुस्तकालय में उपलब्ध बेशुमार कोष का डिजिटल कांटेंट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। डिजिटाइजेशन के माध्यम से 10 लाख प्रेस-क्लिपिंगों, 1964 से 10 प्रमुख भारतीय दैनिकों के पेपरबद्ध खंड और 700 विलक्षण पुस्तकों को संरक्षित किया जाएगा तथा उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पाठकों को वेब पर एक विशेष खोज टूल उपलब्ध हो सकेगा और वे आईसीडब्ल्यूए में पहले से उपलब्ध जानकारी का एक बड़ा भंडार देख सकेंगे और पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण भंडार के रूप में प्रतिष्ठापित होगा।

■■

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली

27

पर्यवलोकन

अनुसंधान और सूचना प्रणाली विदेश मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली में स्थापित एक विचार केंद्र है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और विकासात्मक सहयोग में विशेषज्ञता प्राप्त है। इसे समय-समय पर सौंपे जाने वाली क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय सहयोग व्यवस्थाओं सहित बहुपक्षीय आर्थिक एवं सामजिक मुद्दों से संबंधित मामलों पर भारत सरकार के एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। आरआईएस को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के विचार केंद्रों में प्रभावशाली नीतिगत वार्ता एवं क्षमता-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में देखा जाता है।

अनुसंधान और सूचना प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत अनुसंधान आयोजित करता है और भारत सरकार को महत्वपूर्ण वार्ताओं के लिए और बैठकों के लिए तैयारी करने के लिए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करता है। अनुसंधान और सूचना प्रणाली की कार्य योजना का केंद्र बिंदु दक्षिण-दक्षिण सहयोग का संवर्धन करना और विकासशील देशों को विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय वार्ता करने में सहायता प्रदान करना रहा है। आरआईएस ने अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न गुट-निरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठकों, पूर्वी एशियाई शिखर बैठकों, सार्क सम्मेलन, इब्सा शिखर बैठक, बिमस्टेक शिखर बैठक, अंकटाड मंत्री स्तरीय सम्मेलन, डब्ल्यूटीओ मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है। अनुसंधान और सूचना प्रणाली विभिन्न क्षेत्रीय पहलों की ट्रैक-।। प्रक्रिया, जिसमें सेप्टा का ट्रेक-।। अध्ययन समूह सम्मिलित है, में संलग्न है। भिन्न-भिन्न देशों के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार निष्पादित करने और वार्ता प्रक्रिया के दौरान आरआईएस ने भारत सरकार को विष्लेषणात्मक सहायता भी प्रदान की है। एशिया के शीर्ष नीति विचार केंद्रों के साथ एक एशियाई आर्थिक समुदाय के लिए संगठन नीतिगत वार्ता कर रहा है। अनुसंधान और सूचना प्रणाली भारत और अन्य देशों दोनों में स्थित नीतिगत विचार केंद्रों के अपने गहन नेटवर्क के जरिए अंतर्राष्ट्रीय-आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत समरूपता को सुदृढ़ करने की इच्छा रखता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान अनुसंधान और सूचना प्रणाली के मुख्य-मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

सरकार को अनुसंधान व नीतिगत निविष्टियां प्रदान करना

आरआईएस विशेष रूप से अपने सहभागी देशों के साथ भारत के आर्थिक तालमेल के संदर्भ में नीति तैयार करने में सहयोग के लिए अनुसंधान अध्ययन आयोजित किया है। आरआईएस द्वारा प्रदत्त कुछ विशिष्ट निविष्टियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आसियान-भारतः 15वें आसियान-भारत कार्य दल, आसियान-भारत संयुक्त सहयोग समिति और विदेश मंत्रालय में आयोजित आसियान- भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों के दौरान-निविष्टियां प्रदान की गयी।
- सीईपीईएः सिडनी, आस्ट्रेलिया में मई, 2009 में आयोजित सीइपीईए पर ट्रैक-।। अध्ययन समूह की बैठक में आरआईएस ने भाग लिया और महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रस्तुत कीं।
- एशियाई सहयोग वार्ताः विचार केंद्र पहल का अध्ययन अद्यतन करने पर आठवीं एसीडी मंत्री स्तरीय बैठक के सिलसिले में ब्रीफिंग पेपर विदेश मंत्रालय को 6 अक्तूबर- 2009 को प्रस्तुत किए गए।
- सार्कः समय-समय पर विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ सार्थक सत्रों में सार्क से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निविष्टियां प्रदान कीं।
- चियांग-माई पहल और ईएएसः चियांग-माई पहल और ईएएस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी 2 अप्रैल, 2009 को विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत की गयी।
- आईओआर-एआरसीः विदेश मंत्रालय में बुलाई गयी आईओआर-एआरसी बैठक के दौरान निविष्टियां प्रदान की गयी।
- इंडोनेशिया न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त अध्ययन दलः वाणिज्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ समय-समय पर आयोजित सार्थक सत्रों में इन मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर निविष्टियां प्रदान की गयी।
- हेलीगेंडाम प्रक्रियाः प्रक्रिया-ला मडडालेना शिखर बैठक, 2009 संभावित डेलिवरेब्ल्स कुछ टिप्पणियां' पर एक नोट 4 अप्रैल, 2009 को विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। हेलीगेंडाम ला' आकिला प्रक्रिया पर निम्नलिखित टिप्पणी 1 अक्तूबर, 2009 को विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत की गयीः (1) 'परस्पर लाभ हेतु निवेश की स्वतंत्रता' कार्य के लिए प्रारूप कारकों पर टिप्पणी, (2) 'विकास' विषय वस्तु पर निविष्टियां, और (3) 'नवाचार एवं प्रौद्योगिकी' विषयवस्तु पर निविष्टियां।

नीतिगत वार्ता, सम्मेलन एवं संगोष्ठियां

वर्ष 2009-10 के दौरान आरआईएस ने विकासशील देशों के बीच बुद्धिजीवी वार्ता का प्रसार करने के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए कई नीतिगत वार्ताएं, सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित की है। इस अवधि के दौरान आयोजित कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

द्वितीय दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलन 11-12 दिसंबर, 2009: द्वितीय दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन एसएसीईपीएस, यूएनडीपी, ईएससीएपी, एडीबी और फिक्की के सहयोग से आरआईएस द्वारा 11-12 दिसंबर, 2009 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आईपीएस, सीपीडी, आईआईडीएस और एसएडब्ल्यूटीईई सहभागी संस्थान थे। आरआईएस के महानिदेशक डॉ. विश्वजीत धर के स्वागत भाषण से उद्घाटन सत्र के कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, प्रेसिडेंट सामाजिक विकास परिषद और अध्यक्ष, आरआईएस अनुसंधान- परामर्शदात्री परिषद ने की। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष (प्रचालन) श्री जियोआ झाओ ने विशेष व्याख्यान दिया और साथ ही दक्षिण एशिया में इंट्रारिजनल ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट पर एडीबी- अध्ययन पर भी जारी किया। सार्क चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री तारिक सईद ने एक विशेष प्रस्तुतिकरण पेश किया और डॉ. अजय छिब्बर, संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव कुएनडीची के सहायक प्रशासन और एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय ब्यूरो के निदेशक, यूएनडीपी इस अवसर पर उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान- 'दि ग्लोबल फाइनशियल क्राइसिस- एंड दि एशिया पैसिफिक रीज़न - 'पर यूएनडीपी आरसीसी अध्ययन और नवीनतम आरआईएस चर्चा का भी लोकार्पण किया गया।

भारत सरकार के निगमित मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सलमान खुर्शीद सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने एक विशेष व्याख्यान भी दिया और बांग्लादेश बैंक, ढाका के गर्वनर अतीउर रहमान ने विशेष सत्र की अध्यक्षता की। माननीय मंत्री जी के विशेष व्याख्यान के बाद सहभागियों ने खुली चर्चा में भाग लिया।

द्वितीय एसएईएस के भिन्न-भिन्न तकनीकी सत्रों की विषयवस्तु में शामिल हैं: विश्व आर्थिक संकट और दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण और विकास के प्रभाव; क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण: साफ्टा का सघन होना; दक्षिण एशिया में भौतिक संपर्कों का सुदृढ़ीकरण; दक्षिण एशिया एक समावेशी समाज की ओर; दक्षिण एशिया में परियोजना आधारित बहुपक्षीय सहयोग की संभावना; दक्षिण एशिया के लिए व्यापार, जलवायु परिवर्तन और खाद्यान्न सुरक्षा के मसले; दक्षिण एशिया में एलडीसी के प्रति विशेष और अंतर्राष्ट्रीय बर्ताव; प्रवसन एवं विकास; दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद; दक्षिण एशिया में एकीकरण और विकास का दृष्टिकोण। सार्क, काठमांडू के महासचिव डॉ. शीलकांत शर्मा ने समापन भाषण दिया। डॉ. विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस ने सभी सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

'आर्थिक संकट के अधीन, एशिया को कैसे और अधिक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए?' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, 24-25 सितंबर, 2009: 'आर्थिक संकट के अधीन, एशिया को कैसे और अधिक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए?' पर आरआईएस और जापान आर्थिक प्रतिष्ठान ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में 24-25 सितंबर, 2009 को किया। खुले मंच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रो. अर्जुन सेनगुप्ता, संसद सदस्य (राज्य सभा) और अध्यक्ष, आरआईएस ने की। डॉ. विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। जापान आर्थिक प्रतिष्ठान (जेईएफ) के अध्यक्ष और सीईओ श्री नोबोरू हाताकेयामा (अंतर्राष्ट्रीय मामलों के पूर्व उप-मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय, जापान) ने उद्घाटन भाषण दिया। माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉ. शशि थरूर ने बीज व्याख्यान दिया। डॉ. विश्वजीत धर, महासचिव, आरआईएस विषय-प्रवर्तक थे। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम में निम्नलिखित सत्र थे- वित्तीय एवं आर्थिक संकट और एफटीए-कैसे एफटीए के जरिए अंतरा-क्षेत्रीय निर्यात वृद्धि से संकट का सामना किया जा सकता है? प्रगतिशील एशियाई एफटीए- ईएएफटीए, सीईपीईए और टीपीपी का एक परिचय; पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का भावी स्वरूप क्या होगा? समापन सत्र की अध्यक्षता राजदूत एल.के. पोन्नपा, उपाध्यक्ष, आरआईएस और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार ने की। संगोष्ठी का सार-संक्षेपण श्री नोबोरू हाताकेयामा और डॉ. विश्वजीत धर ने किया। दूसरे दिन के कार्यक्रमों में विशेषज्ञों की एक अनौपचारिक गोलमेज चर्चा शामिल थी। मीडिया ब्रीफिंग सत्र का नेतृत्व डॉ. विश्वजीत धर और श्री नोबोरू हाताकेयामा ने किया। कार्यक्रम का समग्र समन्वयन डॉ. राम उपेंद्र दास, वरिष्ठ फैलो, आरआईएस ने किया।

'उभरता भारत और विश्व अर्थव्यवस्था' पर भारतीय आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन संघ की 18वीं द्विवार्षिक बैठक, 19-20 जून, 2009: आरआईएस ने भारतीय आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन संघ के साथ संयुक्त रूप से 19-20 जून, 2009 को नई दिल्ली में उभरता भारत और विश्व अर्थव्यवस्था पर भारतीय आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन संघ की 18वीं द्विवार्षिक बैठक आयोजित की। कार्यक्रम की शुरूआत प्रो. सुहास केतकर, अध्यक्ष, एआईईएफएस और डॉ. विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण से हुई। प्रो. अर्जुन सेनगुप्ता, सांसद (राज्य सभा) और अध्यक्ष, आरआईएस ने अध्यक्षीय संबोधन किया। प्रो. अभिजीत सेन, सदस्य योजना आयोग ने बीच व्याख्यान दिया। बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सत्र थे: वैश्विक मंदी और विकास वित्तपोषण पर अध्यक्षीय सत्र; भारतीय अर्थव्यवस्था पर संदर्श; उत्पादकता एवं व्यापार; वित्तीय क्षेत्र और वैश्विक वित्तीय संकट; कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की चुनौती; वैश्वीकरण के सामाजिक-आर्थिक परिणाम; वैश्विकरण एवं व्यापार। समापन सत्र में आरआईएस के महानिदेशक डॉ विश्वजीत धर ने प्रारंभिक विचार रखे। प्रो. सुहास केतकर, वांडरबिल्ट विश्वविद्यालय ने सार टिप्पणी प्रस्तुत की। राजदूत एल. के. पोन्नपा उपाध्यक्ष,

आरआईएस, उप राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार और सचिव, एनएससीएस ने समापन भाषण दिया। डॉ. राम उपेंद्र दास, वरीय फैलो, आरआईएस कार्यक्रम के समन्वयक थे।

स्वास्थ्य के लिए वैकल्पिक पेंटेंट व्यवस्था एवं पहुंच पर कार्यशाला, 25-26 मई, 2009: आरआईएस और चीन की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास अकादमी ने बीजिंग में 25-26 मई, 2009 को 'स्वास्थ्य के लिए वैकल्पिक पेंटेंट व्यवस्था एवं पहुंच' पर एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कास्टेड के उपाध्यक्ष और श्री मिल्टॉस लाडिकास, समन्वयक और इनोवा-पी 2 के स्वागत भाषण से उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। डॉ. सचिन चतुर्वेदी, वरीय फैलो, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यशाला में निम्नलिखित सत्र थेः भारत में ग्लोबल फार्मा एवं आर एंड डी प्राथमिकताओं पर पैनल; आईपीआर व्यवस्था की प्रवृत्तियां चीनः केंद्र बिदु स्वास्थ्य क्षेत्र; आईपीआर, स्वदेशीय ज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र; नीतिगत अनिवार्यताः भारत का विशेष अध्ययन; आईपीआर, स्वदेशीय ज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र; नीतिगत अनिवार्यताः चीन का विशेष अध्ययन; भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार की गत्यात्मकता; स्वास्थ्य तक पहुंच और आईपीः वैकल्पिक दृष्टिकोण एवं इनोवा पी-2-डब्ल्यूएचओ वर्क ओवर व्यूः चीनी परिप्रेक्ष्य एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य; और इनोवा के लिए आगे की कार्यसूची और संयुक्त परिप्रेक्ष्य- फार्मास्यूटिकल्स सर्वेक्षण के लिए केस अध्ययन और इनोवा पी-2 के लिए विश्लेषण।

पैन-एशियाई एकीकरणः पूर्वी और दक्षिण एशिया को जोड़ना और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय रणनीतः दक्षिण और पूर्व एशियाई केस अध्ययन, 20 नवंबर, 2009: उपर्युक्त विषय पर आरआईएस ने एडीबी के साथ संयुक्त रूप से 20 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की और पुस्तकों का लोकार्पण किया। डॉ. राम उपेंद्र दास, वरीय फैलो, आरआईएस के स्वागत भाषण से संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। डॉ. श्रीनिवास मधुर, वरिष्ठ निदेशक, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण कार्यालय एडीबी ने उद्घाटन भाषण दिया। दक्षिण एशिया को पूर्व एशिया के साथ जोड़ने की विषयवस्तुत पर डॉ. विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस ने सहभागियों को संबोधित किया। डॉ. ईशर अहलुवालिया, अध्यक्ष, आईसीआरआईईआर ने बीज व्याख्यान दिया। इसके पश्चात डॉ. गणेशन विघ्नराजा, मुख्य अर्थशास्त्री, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण कार्यालय, एशियाई विकास बैंक द्वारा पैन-एशियाई एकीकरणः मुख्य निष्कर्ष पुस्तक पर एक प्रस्तुति की गयी। इसके पश्चात खुली चर्चा में भी सहभागियों ने भाग लिया।

भारत-आसियान एफटीएः व्यापार के अवसर पर आरआई-आईटीपीओ सम्मेलन; 18 नवंबर, 2009: भारत और आसियान ने हाल ही में सामानों के व्यापार एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। 10 आसियान देशों और भारत की गतिशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ एक व्यापार संधि में जोड़ना उनके मालों, सेवाओं और निवेश के व्यापार के क्षेत्र में परस्पर भागीदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में न केवल एक महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में एक बृहत्तर ताने-बाने की दिशा में बढ़ता कदम भी था। इस पृष्ठभूमि में, आरआईएस ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), नई दिल्ली के साथ भारत-आसियान एफटीएः व्यापार के अवसर पर एक सम्मेलन नई दिल्ली में 18 नवंबर, 2009 को आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरूआत डॉ. सुबास पाणि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीपीओ और डॉ. विश्वजीत धर महानिदेशक, आरआईएस के टिप्पणी से हुई। श्री योगेंद्र कुमार, अपर सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री राजीव यादव, कार्यकारी निदेशक, आईटीपीओ ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके पश्चात भारत-आसियान सामानों के एफटीए पर पैनल चर्चा हुई। श्री पी. के. दास, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसकी अध्यक्षता की। पैनल में डॉ. राम उपेंद्र दास, वरिष्ठ फैलो, आरआईएस; प्रो. एन. चंद्रामोहन, आईआईएलएम शिक्षा संस्थान; मी. डी. मात्सुशिमा, वरिष्ठ निदेशक, जेईटीआरओ और श्री दिलीप चिनाय, महानिदेशक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्सचर्स (एसआईएएम), नई दिल्ली शामिल थे। इसके पश्चात खुली चर्चा हुई।

विकासशील एशिया के लिए भारत और चीन की उपस्थिति को बढ़ाने की प्रकृति और प्रभाव पर आइडियाज की आरआईएस कार्यशाला, 5-6 नवंबर, 2009: एशिया के विशेष संदर्भ में 'विश्व अर्थव्यवस्था में भारत और चीन की उपस्थिति का विस्तार करने की प्रकृति और प्रभाव की समझ' पर आरआईएस और अंतर्राष्ट्रीय विकास अर्थशास्त्र एशोसिएट्स (आइडियाज), नई दिल्ली, भारत ने एक कार्यशाला की मेजबानी 5-6 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में की। उन्होंने विकासशील एशिया के विभिन्न भागों से कार्यकर्ताओं, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को एक साथ एक स्थान पर एकत्र किया। निम्नलिखित विषयवस्तुओं पर कार्यशालाएं केंद्रित थीं। विश्व अर्थव्यवस्था में शक्ति केंद्रों के अंतरण के प्रश्न परः चीन और भारत की भूमिका; विकासशील एशिया पर चीन का प्रभावः विशेष अध्ययन; विकासशील एशिया के लिए भारत की महत्ताः व्यापार एवं निवेश संबंध; व्यापार, सहायता और निवेश के जरिए एकीकरण का एशिया का अनुभवः दक्षिण एशिया; व्यापार, सहायता और निवेश के जरिए एकीकरण का एशियाई अनुभवः दक्षिण-पूर्व एशिया; और भावी क्षेत्रीय एकीकरणः संभावित दिशा। कार्यशाला में मुख्य सहभागियों में प्रो. अभिजीत सेन, प्रो. प्रभात पटनायक, प्रो. मुचकुंद दूबे, राजदूत नवरेखा शर्मा और राजदूत एल. के. पोन्नपा शामिल थे। भारत में इंडोनेशिया के राजदूत ले. ज. (सेवानिवृत्त) एंडी मुहम्मद गालिब ने विशेष व्याख्यान दिया।

संरक्षणावाद के अपरिवर्तनीय दवाब संबंधी बैठक पर चर्चा, 18 दिसंबर, 2009: लंदन स्थित एक शैक्षिक एवं नीतिगत अनुसंधान विचार केंद्र आर्थिक नीति अनुसंधान केंद्र द्वारा समन्वित ग्लोबल ट्रेड अलर्ट ने 'दी अनरिलेंटिंग प्रेशर ऑफ प्रोटेक्शनिज्मः दी थर्ड जीटीए रिपोर्ट' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में नवंबर, 2008 में हुई प्रथम जी-20 संकट से संबंधित शिखर बैठक से कार्यरत संरक्षणवादी डाइनामिक्स पर नवीनतम आंकड़े दिए गए हैं और प्रक्रियाधीन कई व्यापार-विरोधी उपायों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में, विदेशी वाणिज्यिक हितों को प्रभावित कर सकने वाले सरकारी उपायों के 600 से अधिक पूरी हो चुकी जांच के महत्वपूर्ण साक्ष्य आधार पर मुख्य निष्कर्षों पर चर्चा की गयी है। रिपोर्ट को विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकास पर केंद्रित किया गया है, जिसमें कई निर्यात वाले पावरहाउसेस हैं।

आरआईएस ने 18 दिसंबर, 2009 को नई दिल्ली में तीसरी रिपोर्ट पर रिपोर्ट सह-चर्चा बैठक आयोजित की। रिपोर्ट के संपादक सेंट गालेन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर डॉ. सिमोन एवनेट ने रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति के दौरान बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने चर्चा में भाग लिया।

भारत के लिए आसियान के साथ करार एवं अवसर पर चर्चा बैठक, 19 जनवरी, 2010: आरआईएस ने 19 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में भारत के लिए आसियान प्लस करार एवं अवसर पर एक चर्चा बैठक आयोजित की। डॉ. मिया मिक्रीक, उप समन्वयक, एशिया प्रशांत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नेटवर्क (आर्टनेट), यूनेस्केप, बैंकाक ने चर्चा की शुरूआत की। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पूर्वी एशिया में आर्थिक एकीकरण पर आरआईएस- ईआरआईए गहन संगोष्ठी: इमर्जिंग लैंडस्केप, 22 जनवरी, 2010: आरआईएस ने ईआरआईए के सहयोग से 'इकोनोमिक इंटीग्रेशन इन ईस्ट एशियाः इमर्जिंग' की विषयवस्तु पर 22 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। राजदूत के. केशवापाणि, निदेशक आईएसईएएस, सिंगापुर ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की जो डॉ. विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस के स्वागत भाषण से शुरू हुआ। श्री हीदेतोशी निशीमुरा, कार्यकारी निदेशक, ईआरआईए, जकार्ता ने बीज व्याख्यान दिया।

आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली के महानिदेशक राजदूत एस.टी. देवरे ने प्रथम सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्वी एशिया में गहरे होते आर्थिक एकीकरण पर उन्होंने संबंधित किया। बिजनेस स्टैंडर्ड, नई दिल्ली के संपादक डॉ. संजय बारू ने विशेष व्याख्यान दिया। पैनल में श्री पी. एल. कंठ राव, निदेशक, सियाम, नई दिल्ली, श्री सुगतो सेन, वरिष्ठ निदेशक, सियाम, नई दिल्ली; और श्री डी. के नायर, महासचिव, सीआईटीआई, नई दिल्ली शामिल थे।

आसियान सचिवालय के उप महासचिव श्री पुष्पनाथन सुंदरम ने दूसरे सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें ईआरआईए अध्ययनः व्यापक विकास योजना पर प्रस्तुति हुई। डॉ. फुकुनारी किमुरा प्रधान अर्थशास्त्री, ईआरआईए जकार्ता मुख्य प्रस्तुतकर्ता थे। पैनल में श्री मानब मजूमदार सहायक महसचिव, फिक्की, नई दिल्ली और डॉ. रश्मि बांगा, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, अंकटाड, नई दिल्ली शामिल थे।

तीसरा सत्र 'पूर्वी एशियाई आर्थिक एकीकरण में भारत की भूमिका ' पर था। इस सत्र की अध्यक्षता द नेशन, बैंकाक के कार्यकारी संपादक श्री कवि चांगकित्तावार्न ने की। श्री पी. के. दास, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ने विशेष व्याख्यान दिया। पैनल में डॉ. राम उपेंद्र दास, वरिष्ठ फैलो आरआईएस और श्री दायसुक मात्सुशिमा, जेट्रो, नई दिल्ली शामिल थे।

पेटेंट रिजाइम एंड एक्सेस टू हेल्थ पर सेमिनार: डिफाइन स्ट्रेटीज अर्जेंटली 12 जून, 2009 पर आरआईएस और इंडिया हैबीटेट सेंटर ने 12 जून, 2009 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से एक संगोष्ठी आयोजित की। डॉ. विश्वजीत धर, महानिदेशक, आरआईएस और श्री आर. एस. लिब्रहान, निदेशक, इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली की प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ संगोष्ठी की शुरूआत हुई। संगोष्ठी के दौरान होने वाली चर्चाओं में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. सचिन चतुर्वेदी, वरिष्ठ फैलो, आरआईएस कार्यक्रम के समन्वयक थे।

भारत और चीन में तीव्र प्रगतिः वित्तीय संकट के संदर्भ में अमरीका में रोजगार के प्रभाव पर संगोष्ठी, 15 अप्रैल, 2009: आरआईएस ने 15 अप्रैल, 2009 को नई दिल्ली में उपर्युक्त विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। डॉ. नागेश कुमार, महानिदेशक, आरआईएस ने संगोष्ठी में आरंभिक वक्तव्य दिया। इस संगोष्ठी में इस विषय पर प्रो. अजीत सिंह, अनुसंधान निदेशक, वित्त ने अनुसंधान के लिए कैंब्रिज अभिदान, कैंब्रिज विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र पीठ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम बिजनेस स्कूल; और इमेरिटस प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज ने चर्चा की शुरूआत की। श्री आर गोपालन, अपर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सत्र की अध्यक्षता की। इसके पश्चात होने वाली खुली चर्चा में प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और वातावरण परिवर्तन: प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी आयाम विषय पर आईसीएसटीडी और आरआईएस द्वारा 30 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला अनौपचारिक संवाद।

आउटरीच सार्वभौमिक उपस्थिति और नेटवर्किंग

आरआईएस ने अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए विश्व समुदाय द्वारा सामना किए जा रहे महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहयोगात्मक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अन्य विकासशील देशों के विचार-केंद्रों के साथ कार्यकारी संबंध विकसित किए हैं। इस दिशा में आरआईएस ने दक्षिण-पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर; चीन विकास परिषद का विकास अनुसंधान केंद्र; नीति अध्ययन संस्थान, कोलंबो, मलेशियाई इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनामिज ऑफ जापान; इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड डिवलपमेंट, बैंकाक; सेंटर फॉर पॉलिसी डायलाग, ढाका; साउथ एशिया सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, काठमांडू; दक्षिण-दक्षिण तकनीकी सहयोग के लिए नाम केंद्र, जकार्ता; इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग इकोनामिज, जापान; इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया; और वियतनाम अकादमी ऑफ सोशल साइंसेज के साथ मजबूत सांस्थानिक संपर्क विकसित किया है। आरआईएस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, बैंकाक; एशिया डेवलपमेंट बैंक, मनीला; राष्ट्रमंडल सचिवालय, लंदन; साउथ सेंटर, जिनेवा; और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड ससटेनेबल डेवलपमेंट, जिनेवा सहित कई अंतर-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गहन सहयोग से भी कार्य करता है।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

- वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर क्षमता-निर्माण माड्यूल और सार्क के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय व्यापार खंडः विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय की ओर से आरआईएस ने मालदीव के राजनयिकों के लिए 3-4 अगस्त, 2009 को नई दिल्ली में वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर क्षमता निर्माण और सार्क के विशेष संदर्भ में एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया।

- भारत-आसियान सहयोग के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय व्यापार खंडों पर क्षमता-निर्माण कार्यक्रमः विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान की ओर से आरआईएस ने आसियान के राजनयिकों के लिए 26 अगस्त, 2009 को नई दिल्ली में भारत-आसियान सहयोग के विशेष संदर्भ में क्षेत्रीय व्यापार खंडों पर क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

- वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और भारत के क्षेत्रीय आर्थिक क्रियाकलापों पर भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान की ओर से आरआईएस ने 7-11 सितंबर, 2009 तक नई दिल्ली में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और भारत के क्षेत्रीय आर्थिक क्रियाकलापों पर भा.वि.से. के परिवीक्षार्थियों (बैच 2008) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- ग्रेविटी मॉडलिंग ऑफ ट्रेड फेसीलिटेशन एंड 'बिहाइंड दी बार्डर ' मीजर्स एफक्टिंग ट्रेड पर इस्केप ऑर्टनेट/आरआईएस अनुवर्ती कार्यशालाः ग्रेविटी मॉडलिंग ऑफ ट्रेड फेसीलिटेशन एंड 'बिहाइंड दी बार्डर ' मीजर्स अफेक्टिंग ट्रेड पर इस्केप आर्टनेट/आरआईएस अनुवर्ती कार्यशाला 21-25 सितंबर, 2009 को आरआईएस में आयोजित की गयी।

- वैश्विक प्रशिक्षण प्रणाली और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के समझ पर प्रशिक्षण माड्यूलः अकादमिक स्टाफ कॉलेज, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मीलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए संचालित यूजीसी पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ मिलकर आरआईएस ने 23 अक्तूबर, 2009 को वैश्विक प्रशिक्षण प्रणाली और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की समझ पर एक प्रशिक्षण माड्यूल आयोजित किया।

- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे और विकास नीति कार्यक्रम (आईईआईडीपी)-आईईआईडीपी कार्यक्रम नई दिल्ली में 15 फरवरी-12 मार्च, 2010 को आयोजित किया गया।

आरआईएस प्रकाशन

आरआईएस ने तीन नीतिगत संक्षिप्त सार प्रकाशित किए; 14 चर्चा पत्र; दक्षिण एशिया आर्थिक जरनल का एक अंक; जैव प्रौद्योगिकी एवं विकास समीक्षा के दो अंक; न्यू एशिया मॉनीटर के दो अंक; और आरआईएस मेकांग-गंगा नीति ब्रीफ का एक अंक प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, आरआईएस का एक संयुक्त अंक भी प्रकाशित किया गया (परिशिष्ट-XVI देखें)। आरआईएस प्रकाशनों को इसकी वेबसाइट- http:// www.ris.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

बजट

आरआईएस को विदेश मंत्रालय से वर्ष 2009-10 के दौरान 3.14 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्राप्त हुई।

■■

28 पुस्तकालय

मंत्रालय के पुस्तकालय में लगभग एक लाख पुस्तकें, समृद्ध स्रोत सामग्री और मानचित्रों का विशाल संग्रहण, माइक्रोफिल्में एवं सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। यह नीति नियोजन और शोध की सहायता के लिए आधुनिक उपकरणों से भी सुसज्जित है। पुस्तकालय लगभग 480 पत्रिकाओं, जर्नलों (ऑनलाइन जर्नलों एवं डेटाबेस सहित) और अखबारों की खरीददारी/प्राप्ति और रखरखाव करता है।

पुस्तकालय के पास एक आंतरिक कंप्यूटर प्रणाली है, जिसमें एक सर्वर और 12 पीसी टर्मिनल हैं। इस प्रणाली में हिन्दी में भी डाटा की एंट्री और पुनः प्राप्त कार्य किया जाता है। पुस्तकालय में विदेशी मामलों एवं वर्तमान मामलों पर सीडी-रोम डाटाबेस है। पुस्तकालय के पीसी में सीडी-राइटर और लेजर प्रिंटर भी लगे हैं। यहां एक रंगीन स्कैनर (ओसीआर क्षमता के साथ-साथ प्रतिबिंवों के संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति की सुविधा सहित), एक माइक्रोफिल्म/माइक्रोफिशे रीडर प्रिंटर, प्लेन पेपर फोटोकॉपियर और डेस्क टॉप पब्लिशिंग (डी.पी.टी.)साफ्टवेयर के साथ-साथ एक एच पी आफिस जेट प्रो-लेजर प्रिंटर भी है।

पुस्तकालय समिति पुस्तकों के क्रय और जर्नलों/आवधिक पत्रिकाओं को मंगवाने के साथ-साथ पुस्तकालयों के क्रिया-कलापों का प्रबंधन करती है। अप्रैल 2008 में विदेश सचिव ने पुस्तकालय समिति का पुनर्गठन किया। वर्तमान पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष संयुक्त सचिव (पीपी एंड आर) हैं, प्रादेशिक प्रभागों के तीन निदेशक सदस्य हैं और निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) इसके सदस्य-सचिव हैं।

पुस्तकालय प्रबंधन के समस्त पहलुओं को शामिल करते हुए एक एकीकृत पुस्तकालय साफ्टवेयर पैकेज लिबसिस तैयार कराकर समस्त प्रलेखन ग्रंथ सूची संबंधी सेवाओं एवं पुस्तकालय के अन्य कार्यों एवं सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। लिबसिस में मार्क के साथ-साथ नॉन-मार्क फार्मेट का प्रयोग किया जाता है और यह बूलियन आपरेटरों के प्रयोग से शब्द-आधारित फ्री टैक्स्ट सर्चिंग की सहायता करता है। यह डाटाबेस को अद्यतन करने से पहले इनपुट डाटा का ऑनलाइन सत्यापन भी करता है। पटियाला हाउस स्थित विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय के समस्त पीसी में इंटरनेट के माध्यम से समस्त पुस्तकों मानचित्रों, दस्तावेजों एवं 1986 से पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली पत्रिकाओं से चुने गए लेखों (और 1986 से पहले के अधिक उपयोग में आने वाले प्रकाशनों) की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। पुस्तकालय की जानकारी www.mealib.nic.in नामक विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइट पर भी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

पुस्तकालय में प्राप्त समस्त नए दस्तावेजों अर्थात् पुस्तकों, मानचित्रों, माइक्रोफिल्मों, पत्रिकाओं से चुने गए लेखों को विदेशी मामले संबंधी डाटाबेस में नियमित रूप से संग्रहित किया जाता है। इस डाटाबेस और सीडी-रोम डाटाबेसों का प्रयोग करके पुस्तकालय वर्तमान जागरूकता सेवा और ग्रंथ सूची एवं निर्देशिका सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय नियमित तौर पर निम्नलिखित जारी करता हैः

विदेशी मामलों से संबंधित प्रलेखन बुलेटिन (एफएडीबी): अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संबंधित विषयों पर चुनिंदा लेखों की एक सूची।

हाल ही में हुए परिवर्धनः पुस्तकालय में पुस्तकों/प्रकाशनों की विस्तृत सूची शामिल की गई।

घटनाक्रमः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण समाचार मदें।

पुस्तकालय नियमित रूप से दैनिक क्रोनिकल पुस्तक, सतर्कता और लेख सतर्कता सेवा प्रदान करता है, जिसमें विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय द्वारा मंगाए जाने वाले जर्नलों/आवधिक पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण लेखों के उद्धरण शामिल होते हैं, जो मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों में सभी विदेश सेवा अधिकारियों को ग्रुप ई-मेल आईडी के जरिए उपलबध होते हैं।

इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय का पुस्तकालय एक वास्तविक पुस्तकालय बन गया है, क्योंकि इसने नई दिल्ली में मुख्यालय तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों के प्रयोक्ताओं के लिए 'ईआईयू ऑनलाइन सेवा,' 'एमबीआईसी से डाटा मानीटर' और 'जेएसटीओआर' डेटाबेस मंगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पुस्तकालय 118 ऑनलाइन पत्र-पत्रिकाएं भी उनकी मुद्रित प्रतियों के साथ मंगा रहा है। ये ऑनलाइन डेटाबेस और पत्र-पत्रिकाएं प्रयोक्ता नाम तथा पासवर्ड के जरिए इंटरनेट पर सुलभ हो सकती हैं। ऐसे नामों की एक सूची मुख्यालय तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों में भी परिचालित की गई है तथा यह विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइटः www.mealib.nic.in पर उपलब्ध है।

एनआईसी के सहयोग से पुस्तकालय ने विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1948 से 1998-99 तक) तथा विदेश मंत्रालय के अभिलेख (1995 से 1999 (अगस्त)) के सी डी रोम रूपांतर का एक पूरा पाठ निकाला है। सीडी संबंधी सूचना किसी भी दिए हुए शब्द या शब्द युग्म पर बुलियन खोज सहित संयुक्त खोज के जरिए पुनः प्राप्त की जा सकती है। यह सीडी रोम रूपांतर

1 जनवरी, 2000 को उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार किया गया। पटियाला हाउस, नई दिल्ली स्थित पुस्तकालय में संदर्भ हेतु इस सीडी का उपयोग किया जा सकता है।

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय संबंधी अभिलेखों के पश्च-रूपांतरण एवं बार-कोडिंग की परियोजना को अनुमोदन मिल गया है। यह कार्य चल रहा है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।

यह पुस्तकालय समय-समय पर दिल्ली की विभिन्न संस्थाओं में पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

डॉ. एस. एस. ढाका, निदेशक (पुस्तकालय एवं सूचना) और श्री संजय कुमार बिहानी, एएलआईओ को आईएफएलए समितियों के लिए चुना गया है और उन्होंने उनकी बैठकों में भाग लिया। विदेश मंत्रालय का आईएफएलए और एसएलए सहित विभिन्न व्यावसायिक संगठनों और संघों के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों में भी प्रतिनिधित्व किया गया है। भारतीय उच्चायोग, क्वालालम्पुर के अनुरोध पर श्री संजय कुमार बिहानी, एएलआईओ भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, क्वालालम्पुर में पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए सितंबर-अक्तूबर, 2009 के दौरान एक महीने की अस्थायी ड्यूटी पर गए।

पुस्तकालय ने 17-18 वर्षों से अधिक के अंतराल के पश्चात् वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार श्रेणी-V पुस्तकालय के मामले पर भी कार्रवाई की है।

विदेश मंत्रालय के पुस्तकालय की वेबसाइट www.mealib.nic.in को अद्यतन किया जा रहा है। विदेश सचिव के अनुदेशों के अनुसार विदेश स्थित भारतीय मिशनों सहित मंत्रालय के सभी अधिकारियों को इस संबंध में एक परिपत्र भेजा गया है।

शोधकर्ताओं सहित पुस्तकालय प्रयोक्ताओं का सीडी-रोम डेटाबेस तथा विदेश मामलों संबंधी सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली (एमएआईआरएस) सहित पुस्तकालय तथा इसके डेटाबेस का लाभ उठाने के लिए स्वागत है। शोधकर्ताओं सहित सभी पुस्तकालय प्रयोक्ताओं के लिए फोटोग्राफी और कंप्यूटर प्रिंट सुविधाएं उपलब्ध हैं।

■■

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

वर्ष 2009-10 के दौरान मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों में संवर्ग संख्या (इनमें वाणिज्य मंत्रालय के बजट से प्रदान किए गए पद और संवर्ग बाह्य पद इत्यादि शामिल हैं)।

क्रम सं.	काडर/पद	मुख्यालय में पद	मिशनों में पद	कुल
1	ग्रुप I	5	28	33
2	ग्रुप II	6	40	46
3	ग्रुप III	38	122	160
4	ग्रुप IV	36	118	154
5	कनिष्ठ प्रशा. संवर्ग/वरिष्ठ वेतनमान	47	164	211
6	(i) कनिष्ठ वेतनमान	10	25	35
	(ii) परिवीक्षार्थी आरक्षित	62	-	62
	(iii) छुट्टी आरक्षित	15	-	15
	(iv) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	19	-	19
	(v) प्रशिक्षण आरक्षित	7	-	7
	कुल जोड़	**245**	**497**	**742**
भा.वि.से.(ख)				
7	(i) ग्रेड I	84	122	206
	(ii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	6	-	6
8	(i) एकीकृत ग्रेड II & III	147	236	383
	(ii) अवकाश आरक्षित	30	-	30
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	16	-	16
	(iv) प्रशिक्षण आरक्षित	25	-	25
9	(i) ग्रेड IV	189	416	605
	(ii) अवकाश आरक्षित	60	-	60
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	55	-	55
10	(i) ग्रेड V/VI	154	101	255
	(ii) अवकाश आरक्षित	60	-	60
	(iii) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	14	-	14
11	(i) साइफर संवर्ग के ग्रेड II	41	145	186
	(ii) अवकाश आरक्षित	24	-	24
12	(i) आशुलिपिक संवर्ग	142	488	630
	(ii) अवकाश आरक्षित	47	-	47
	(iii) प्राशिक्षण आरक्षित (हिन्दी)	10	-	10
	(iv) प्रतिनियुक्ति आरक्षित	12	-	12
13	दुभाषिया संवर्ग	7	26	33
14	एल एंड टी संवर्ग	14	1	15
	योग	**1137**	**1535**	**2672**
	कुल योग	**1382**	**2032**	**3414**

परिशिष्ट II

विदेश मंत्रालय में अप्रैल 2009 से नवम्बर 2009 तक सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति और सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ की गई भर्ती संबंधी आंकड़े।

समूह	रिक्तियों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			अनारक्षित
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
समूह क	4	-	-	-	4
समूह क (बाह्य संवर्ग)	3	-	-	-	3
समूह ख	85	4	8	4	69
समूह ग	15	-	-	1	14
कुल	**107**	**4**	**8**	**5**	**90**

परिशिष्ट III

विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की संख्या

भाषा	अधिकारियों की संख्या	भाषा	अधिकारियों की संख्या
अरबी	86	कोरियाई	1
बहासा मलेसिया	2	नेपाली	3
बहासा इंडोनेसिया	12	फारसी	19
बर्मी	1	पुर्तगाली	20
चीनी	56	रसियन	73
डच	1	सर्बो-क्रोशियन	3
फ्रेंच	65	सिंहली	1
जर्मन	30	स्पेनिस	55
हिब्रू	3	थाई	2
इटालियन	3	तुर्किस	6
जापानी	23	यूक्रेनियन	1
कज़ाक	1	वियतनामी	1
किसवाहिली	5		

परिशिष्ट **IV**

1 जनवरी से 30 नवंबर 2009 तक प्राप्त हुए पासपोर्ट आवेदन पत्रों और तत्काल योजना सहित जारी किए गए पासपोर्टों, विविध आवेदन पत्रों की संख्या और प्रदत्त सेवाएं एवं राजस्व (तत्काल योजना के तहत राजस्व सहित) और पासपोर्ट कार्यालयों के व्यय संबंधी आंकड़े को दर्शाने वाला विवरण।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/ पासपोर्ट कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	जारी पासपोर्टों की संख्या	प्राप्त हुए विविध आवेदनों पत्रों की संख्या	दी गई विविध सेवाएं	तत्काल सेवा के तहत जारी पासपोर्टों की संख्या	तत्काल सेवा के तहत प्राप्त राजस्व	कुल राजस्व	कुल व्यय
अहमदाबाद	273159	272593	8843	9012	-	26814750	298576250	54542707
अमृतसर	-	-	-	-	-	-	-	-
बंगलौर	272700	271191	24196	22327	38879	68826100	305016175	44064883
बरेली	60492	57412	1899	1735	2814	4521000	66497770	20389512
भोपाल	71912	59498	2001	1949	9358	14049500	85467969	17226803
भुवनेश्वर	40320	39062	2440	2025	17217	29033000	67036600	8418104
चंडीगढ़	234944	242228	28395	28534	14015	38866995	269538957	41433183
चेन्नई	216392	197792	24537	21563	666000	337979931	54038279	103794000
कोचीन	200835	203368	33633	32278	37126	94040900	264106053	46807634
कोएम्बटूर	-	-	-	-	-	-	-	-
देहरादून	38899	39892	2285	1983	4239	6994600	44713825	6543711
दिल्ली	261698	244967	21579	20798	53786	78537600	348050187	51920290
गाजियाबाद	107433	102807	4223	3973	5787	14229600	110481301	17859853
गुवाहाटी	38099	28906	4056	3518	5700	14790000	44954800	7597938
हैदराबाद	292675	255546	27304	26644	51255	137620900	392230849	67174629
जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
जालंधर	122193	134749	22505	22339	1942	3149700	146109559	51017224
जम्मू	18748	891	17554	819	97	138500	21612915	6793434
कोलकाता	212497	187564	15977	15166	11773	29687500	205614259	33080578
कोझीकोड	170672	173866	23609	23407	23372	39259000	214856920	36783246
लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-
मदुरई	116188	118668	8012	7595	9322	19323600	140848976	21574560
मालापुरम	134678	136951	19043	19043	11693	18124000	170918420	26037920
मुम्बई	251904	244640	15634	15381	14793	23287500	278644309	79544206
नागपुर	55489	53314	1337	1292	4471	5779750	61053612	6732122
पणजी	27528	26786	4279	4604	1353	2065500	31832821	6337767
पटना	13545	14700	877	1125	347	562500	14655530	2667748
पुणे	104725	103418	6181	6175	10327	15022500	105939975	17777495
रायपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
रांची	38998	37987	3796	3319	6930	10467500	40371910	5962118
शिमला	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रीनगर	-	-	-	-	-	-	-	-
सूरत	77429	77560	6529	6241	1207	1593500	79595600	13694877
थाने	137013	133507	4726	4878	5651	10004500	147263210	-
त्रिची	108711	118311	9411	9162	6413	9285000	253955615	-
त्रिवेन्द्रम	124964	122252	25008	24004	25715	39071500	174802720	17296287
विशाखापट्टनम	59147	61745	13477	11735	9221	14237000	184875776	19063230
कुल	**3883987**	**3762171**	**383346**	**352624**	**1050803**	**1107363926**	**4623661142**	**832136059**

परिशिष्ट V

विदेश मंत्रालय का वास्तविक व्यय और 2004-09, ब.प्रा. व सं.प्रा. (2009-2010) (राजस्व और पूंजी)

वर्ष	वास्तविक (करोड़ रुपये में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर
2004-2005	3756.15	12.31
2005-2006	4089.67	8.88
2006-2007	3949.68	-3.43
2007-2008	4572.39	15.77
2008-2009	6630.73	45.01
2009-2010 (ब.प्रा.)	6293.00	-5.09
2009-2010 (सं.प्रा.)	6333.00	0.64

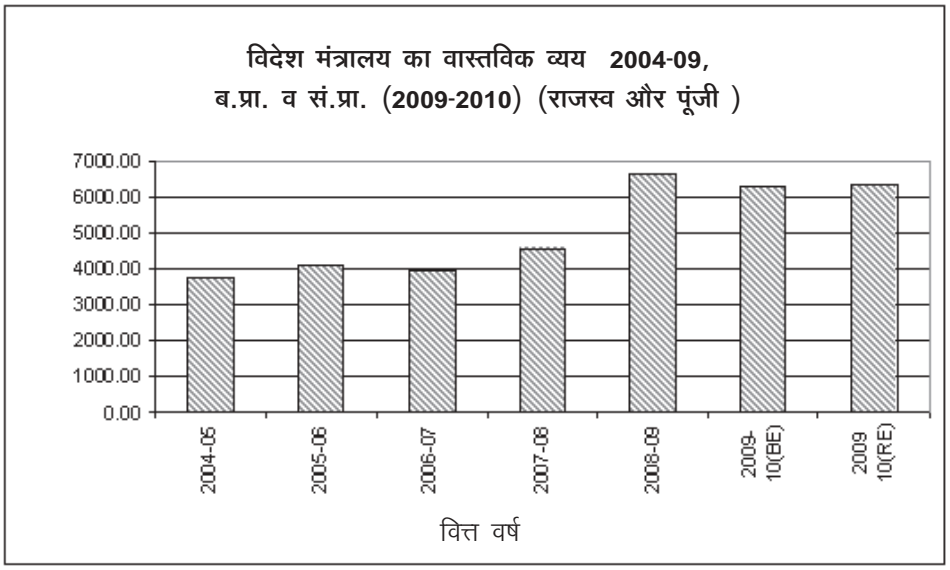

परिशिष्ट **VI**

वर्ष 2009-10 में मुख्य क्षेत्रवार आबंटन (संशोधित प्राक्कलन) (राजस्व और पूंजी)

क्षेत्र	कुल बजट का %	आबंटन (करोड़ रुपये में)
विदेश मंत्रालय सचिवालय	3.45	218.79
राजदूतावास और मिशन	20.34	1288.05
पासपोर्ट और उप्रवासन	6.49	410.84
विशेष राजनयिक खर्च	18.61	1178.40
तकनीकी और आर्थिक सहयोग	30.57	1936.29
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	3.11	19719
संस्थानो ंको अनुदान	2.53	160.36
पूंजी लागत	6.32	400.00
विदेशी सरकारों को ऋण और अग्रिम	6.67	422.50
अन्य	1.91	120.58
कुल	100.00	6333.00

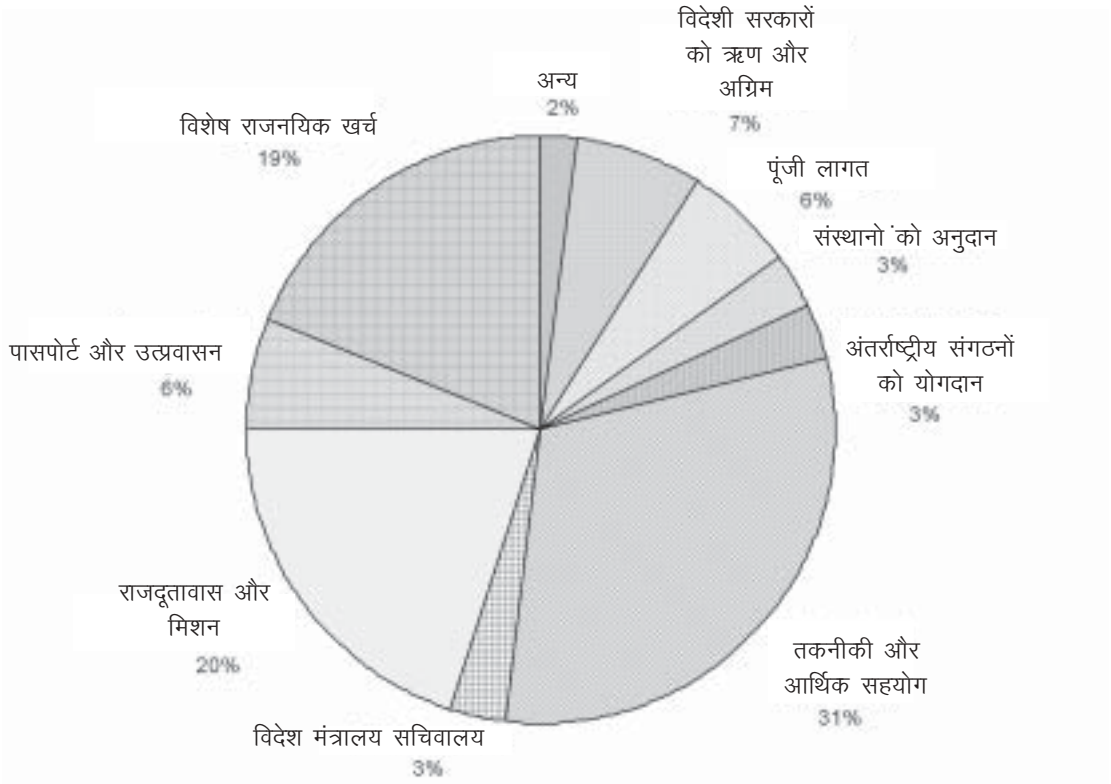

परिशिष्ट **VII**

भारत के सहायता कार्यक्रमों के मुख्य गंतव्य

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में हमारे सहायता और ऋण कार्यक्रमों के प्रधान लाभार्थी संशोधित प्राक्कलन 2009-10 में निम्नलिखित हैं

देशों को सहायता और ऋण	(करोड़ रुपये में)	भारत के कुल सहायता और ऋण बजट का %
भूटान	1301.98	55.20
अफगानिस्तान	287.00	12.17
नेपाल	150.00	6.36
अफ्रीकी देश	125.00	5.30
मंगोलिया	125.00	5.30
श्रीलंका	80.00	3.39
म्यामां	55.00	2.33
यूरेशियाई देश	20.00	0.85
बंगलादेश	3.76	0.16
मालदीव	3.50	0.15
लैटिन अमरीकी देश	2.00	0.08
अन्य	205.55	8.71
कुल	2358.79	100.00

1. भारत सरकार ने विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए भूटान तथा मंगोलिया सरकार को ऋण दिया है। वर्ष 2009-2010 के दौरान दोनों सरकारों को दिया गया ऋण 422.50 करोड़ रुपये रहा है।

2. विदेश मंत्रालय का बजट अनिवार्यतः गैर-योजनागत बजट है। तथापि 1996-97 से मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एक योजनागत शीर्ष स्थापित किया गया है। योजनागत शीर्ष से भारत के पड़ोसी देशों जैसे की भूटान, अफगानिस्तान तथा म्यामां की कुछ बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए है। ताला जल विद्युत परियोजना शुरू हो चुकी है। भूटान की कुछ अन्य परियोजनाएं जो योजनागत शीर्ष से वित्तपोषित की जा रही हैंः पुनात्सांगछू जल विद्युत परियोजना I व II, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना और डुंगसुंग सीमेंट संयंत्र परियोजना का निर्माण। अफगानिस्तान की काबुल से पुल-ए-खुमारी में दोहरी सर्किट ट्रंसमिशन लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस योजनागत के अतिरिक्त उपकरणों के तौर पर अफगानिस्तान में डोसी एवं चरीकार में दो उप-केन्द्रों का भी निर्माण होगा। योजनागत आबंटन से म्यामां में कलादान बहुविध परिवहन परियोजना तथा भारत में स्थापित किया जा रहा प्रस्तावित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविधालय भी वित्तपोषित की जा रही हैं।

3. विदेश मंत्रालय के मुख्यालय पर वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान अनुमानित व्यय 218.79 करोड़ रुपये है जो मंत्रालय के कुल अनुमानित 5096.00 करोड़ रुपये (गैर–योजनागत) राजस्व बजट का लगभग 4.29 औ है। विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों पर आने वाला कुल अनुमानित व्यय 1288.05 करोड़ रुपये होने की आशा है, जो कि मंत्रालय के कुल राजस्व व्यय का लगभग 25.28 औ है।

4. पासपोर्ट तथा वीजा शुल्क और अन्य प्राप्तियों के रूप में विदेश मंत्रालय का राजस्व 2009-10 के लिए 2334.20 करोड़ रुपये के लगभग हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि पासपोर्ट शुल्क 994 करोड़ रुपये और वीजा शुल्क 1240 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राप्तियां 100.20 करोड़ रुपये होंगी।

परिशिष्ट **VIII**

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विदेश मंत्रालय संबंधी रिपोर्ट से उद्घृत अंश

म्स्थानीय कर्मचारियों की अनियमित नियुक्त	जर्मन संघीय गणराज्य, हैमबर्ग के पूर्व महाकौंसुल ने विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में तीन स्थानीय पदों के विरुद्ध नियुक्तियां की और कर्मियों की नियुक्तियां सीधे भारत से कि जिसके परिणामस्वरूप 1.27 करोड़ रुपए की अनियमित व्यय हुआ।
तैनाती के कारण अतिरिक्त व्यय	वर्ष 2007-08 की समाप्ति के तीन वर्षों के दौरान तीन मिशनों दुशान्बे, कीव तथा ओस्लो में भारतीय कार चालकों की तैनात करने के परिणामस्वरूप 57.98 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। भारतीय कार चालकों को उनकी स्थानीय जानकारी, स्थानीय भाषा कौशल के अभाव के कारण शहरी सीमा के बाहर उनका उपयोग न करने की क्षमता अतिरिक्त व्यय के ऊपर अन्य मुद्दे थे। (2008-09 रिपोर्ट सं. सी.ए. 14)
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने सरकार की नीतियों का उल्लंघन करते हुए बिना पर्याप्त औचित्य के एक जनसंपर्क सलाहकार को 49.91 लाख रुपए का भुगतान किया। (2008-09 रिपोर्ट सं. सी.ए. 15)
लगातार अनियमितताएँ	अप्रैल, 2004 से मई, 2008 के दौरान आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों के संबंध में 58.10 लाख रुपए अनधिकृत व्यय। अगस्त 2002 से मार्च 2008 के दौरान अतिरिक्त शेष नकदी को विचार शून्य बनाए रखने की वजह से 50.85 लाख रु. ब्याज की हानि। लेखा परीक्षा के तर्ज पर 36.55 लाख रु. की विदेश स्थित 44 मिशनों/ केन्द्रों के कर्मचारियों को अधिक वेतन और भत्तों के भुगतान की वसूली। भारतीय मिशनों डर्बन, कम्पाला, काठमाण्डू और निकोसिया में वैट प्रतिदाय के अनुसरण में अनुचित दाखिल, अपर्याप्त निगरानी और कमी की वजह से अप्राप्त वैट प्रतिदाय का कुल 26.94 लाख। (2008-09 का रिपोर्ट सं. सी.ए.-14)

परिशिष्ट **IX**

की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी की स्थिति (वित्तीय वर्ष-2003-2009)

क्रम सं.	वर्ष	पैरा/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिस पर कि गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी लेखा परीक्षा के पुनर्निरीक्षण के बाद पी.ए.सी. को जमा कराई गई	पैरा/पी.ए. रिपोर्टों का विस्तृत विवरण जिन पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजी गई। की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणियों की संख्या	भेजी गई की गई कार्रवाई संबंधी लेकिन अवलोकन के बाद वापस हुई और लेखा परीक्षा उनकी मंत्रालय द्वारा दुबारा वापिसी की प्रतिक्षा कर रहा है।	की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की संख्या जिनका लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम पुनर्निरक्षण हुआ लेकिन मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को जमा नहीं करवाई गई
1.	2003	-	-	1	-
2.	2004	-	-	1	-
3.	2005	-	-	2	2
4.	2006	-	-	-	1
5.	2007	-	-	3	3
6.	2008	-	6	1	4
7.	2008-09	-	9	1	1

परिशिष्ट X

वर्ष 2009 में भारत द्वारा अन्य देशों के साथ संपन्न अथवा नवीकृत की गयी संधियां/अभिसमय/करार

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
क.	**बहुपक्षीय**			
1.	सी-142 मानव संसाधन विकास अभिसमय, 1975	25.03.2009	19.01.2009	25.03.2009
2.	अंतर्राष्ट्रीय मालों को हवाई जहाज द्वारा ले जाने से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण के लिए अभिसमय (मांट्रियल अभिसमय, 1999)		27.04.2009	
3.	**आशियान** भारत गणराज्य व्यापक आर्थिक भागीदारी सहयोग और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के बीच। समाज करार में व्यापार के साथ-साथ इसके अनुबंध भी, विवाद निपटान प्रणाली पर करार, ढांचागत करार में संशोधन के लिए प्रोतोकाल और सामग्री करार व्यापार पर करार के अनुच्छेद 4 पर समझौता	13.08.2009	16.12.2009	01.01.2010
ख.	**त्रिपक्षीय**			
1.	व्यापार नौवहन तथा अन्य समुद्री परिवहन संबंधित मामलों के क्षेत्र में भारत गणराज्य, ब्राजील गणराज्य के संघीय सरकार और द. अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच त्रिपक्षीय करार	13.09.2006	20.01.2009	
ग.	**द्विपक्षीय**			
1.	अर्जेंटीना बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित भारत और अर्जेंटीना के बीच ढांचागत करार	14.10.2000	20.01.2009	
2.	भारतीय भू-भाग सर्वेक्षण और अर्जेंटीना के सेगेमार के बीच समझौता ज्ञापन	14.10.09		
3.	खेल सहयोग पर भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और अर्जेंटीना गणराज्य के विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद अभिनब के बीच एस व टी में पी.ओ.सी.	14.10.09		
4.	खेल सहयोग के क्षेत्र में भारत गणराज्य की युवा और खेल मंत्रालय और अर्जेंटीना गणराज्य के खेल सचिवालय के बीच समझौता ज्ञापन	14.10.09		
5.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संवर्द्धन एवं प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और अर्जेंटीना गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	14.10.09		
6.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली और अर्जेंटीना गणराज्य के इण्टी के बीच समझौता ज्ञापन	14.10.09		
7.	ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल) और एनारसा के बीच समझौता ज्ञापन	14.10.09		

परिशिष्ट **X**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
8.	वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (कोनीसेट) अर्जेंटीना और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सी.एस.आई.आर. भारत के बीच करार	14.10.09		
9.	पांच साल के लिए मल्टीपल एंट्री मुफ्त वीजा, पत्रों का आदान-प्रदान	14.10.09		
10.	परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित भारत गणराज्य की सरकार और अर्जेंटीना सरकार के बीच करार	14.10.09		
11.	**बांग्लादेश** निवेश संवर्द्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और **बांग्लादेश गणराज्य** की सरकार के बीच करार	9.2.2009	26.3.2009	
12.	**बेलारूस** शारीरिक प्रशिक्षण और खेल के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय और बेलारूस गणराज्य की पर्यटन और खेल मंत्रालय के बीच करार	17.9.2009		17.9.2009
13.	**बेनिन** विचार-विमर्श के लिए भारत गणराज्य की विदेश मंत्रालय और **बेनिन गणराज्य** की विदेश मंत्रालय तथा अफ्रीकी एकीकरण के बीच प्रोतोकाल	04.03.2009		04.03.2009
14.	राजनीतिक,आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग पर भारत-बेनिन संयुक्त समिति के सृजन के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बेनिन गणराज्य की सरकार के बीच करार	04.03.2009		04.03.2009
15.	**बेनिन** गणराज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र (सीईटीआई) की स्थापना से संबंधित भारत गणराज्य की सरकार और बेनिन गणराज्य की सरकार के बीच	04.03.2009		
16.	2009 से 2012 के वर्षों में भारत गणराज्य की सरकार के और **बेनिन** गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आदान-प्रदान	23.09.2009		
17.	**बुर्किना फासो** राजनीतक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा समाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और **बुर्किना फासो** की सरकार के बीच करार	20.03.2009		20.03.2009
18.	**बुल्गारिया** राजनीतिक और सरकारी/सेवा पासपोर्ट धारकों को वीजा आवश्यकता से छुट से संबंधित भारत गणराज्य की सरकार और **बुल्गारिया गणराज्य** की सरकार के बीच करार	03.03.2009		
19.	2009-2011 की अवधि के लिए विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित भारत गणराज्य और **बुल्गारिया** गणराज्य की सरकार के बीच कार्यक्रम	03.03.2009		03.03.2009

परिशिष्ट **X**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
20.	**कनाडा** व्यापक आर्थिक भागीदारी करार की व्यवहार्यता की जाँच के लिए एक संयुक्त जाँच दल की स्थापना से संबंधित भारत गणराज्य की सरकार और **कनाडा** सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	17.11.2009		17.11.2009
21.	ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित विषय पर भारत गणराज्य के ऊर्जा मंत्रालय और **कनाडा** के प्राकृतिक संसाधन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन	17.11.2009		17.11.2009
22.	कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय और कनाडा के कृषि तथा कृषि-भोजन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन	13.01.2009		
23.	**चिली** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और **चिली गणराज्य** की सरकार के बीच करार	21.04.2008	27.03.2009	
24.	नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य और चिली गणराज्य के राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन	17.03.2009		17.03.2009
25.	**चीन** वर्ष 2010 में 'भारत महोत्सव' और 'चीन महोत्सव' को आयोजित करने संबंधी भारत गणराज्य की सरकार और चीन गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	16.04.2009		16.04.2009
26.	**कोलम्बिया** रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय और कोलम्बिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	04.02.2009		
27.	निवेश संवर्द्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य और कोलम्बिया गणराज्य के बीच करार	10.11.2009	27.11.2009	
28.	**कांगो** सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में भारत गणराज्य और **कांगो** लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच करार	29.10.2009		29.10.2009
29.	**केप वर्डे** विचार-विमर्श से संबंधित प्रोतोकाल पर भारत गणराज्य की विदेश मंत्रालय और **केप वर्डे** गणराज्य की विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	20.10.2009		20.10.2009
30.	सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना से संबंधित भारत गणराज्य की विदेश मंत्रालय और **केप वर्डे** के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	20.10.2009		20.10.2009
31.	**फ्रांस** सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और **फ्रेंच** गणराज्य की सरकार के बीच करार	30.09.2008		

परिशिष्ट **X**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
32.	**जर्मनी** सामाजिक बीमा के क्षेत्र में भारत गणराज्य और **जर्मनी** के संघीय गणराज्य के बीच करार	8.10.2008	19.03.2009	
33.	**हांगकांग** आपराधिक मामलों से संबंद्ध पारस्परिक विधिक सहायता के क्षेत्र में चीन लोक गणराज्य में भारत गणराज्य की सरकार और हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार के बीच करार	14.09.2009	19.10.2009	
34.	**इटली** रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और **इटली गणराज्य** की सरकार के बीच करार	03.02.2009	27.03.2009	
35.	**जॉर्डन** निवेश संवर्द्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य और जॉर्डन के हशमिते राज्य के बीच करार	01.12.2006	26.03.2007	22.01.2009
36.	**कज़ाकिस्तान** परमाणु ऊर्जा निगम, भारत और जे.एस.एन.ए.सी कजातोमप्रोम, **कज़ाकिस्तान** के बीच समझौता ज्ञापन	24.01.2009		24.01.2009
37.	अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र में भारत गणराज्य की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और कजाकिस्तान गणराज्य की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन	24.01.2009		24.01.2009
38.	भारत गणराज्य और **कजाकिस्तान गणराज्य** के बीच प्रत्यर्पण संधि	24.01.2009	13.02.2009	
39.	व्यापक आर्थिक भागीदारी के संबंद्ध में भारत गणराज्य और **कोरिया** गणराज्य के बीच करार	07.08.2009		
40.	**कुवैत** सांस्कृतिक और सूचना आदान-प्रदान के संबंद्ध में भारत गणराज्य की सरकार और **कुवैत राज्य** की सरकार के बीच कार्यकारिणी कार्यक्रम 2009 सक 2011	07.04.2009		07.04.2009
41.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और **कुवैत राज्य** की सरकार के बीच करार	07.04.2009		
42.	शिक्षा और अधिगम के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार के बीच कार्यकारिणी कार्यक्रम 2009-2011	07.04.2009		07.04.2009
43.	**लाइबेरिया** भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और लाइबेरिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श से संबंद्ध प्रोतोकाल	18.09.2009		18.09.2009
44.	**लीबिया** निवेश संवर्द्धन और संरक्षण से संबद्ध भारत और ग्रेट सोशलिस्ट पीपल्स लिबियन अरब जमाहिरिया के बीच द्विपक्षीय करार	25.05.2007	8.11.2007	25.03.2009

परिशिष्ट **X**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
45.	**माली** भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और माली गणराज्य के विदेश मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच विचार-विमर्श से संबद्ध प्रोतोकाल	09.10.2009	09.10.2009	
46.	राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और माली गणराज्य की सरकार के बीच करार	09.10.2009		09.10.2009
47.	**मैक्सिकन राज्य** भारत और संयुक्त राज्य **मैक्सिकन** के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता से संबद्ध करार	10.09.2007	28.09.2007	17.01.2009
48.	**मंगोलिया** वर्ष 2009 से 2012 के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मंगोलिया सरकार के बीच संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध कार्यक्रम	14.09.2009		14.09.2005
49.	परमाणु ऊर्जा और रेडियोधर्मी खनिजों का शांतिपूर्ण उपयोग से संबद्ध क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार की परमाणु ऊर्जा विभाग और **मंगोलिया** सरकार की परमाणु ऊर्जा एजेंसी, विनियामक एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन	14.09.2009		14.09.2009
50.	ऋण स्थिरीकरण सहायता से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और **मंगोलिया** सरकार के बीच करार	14.09.2009		14.09.2009
51.	स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध भारत गणराज्य के सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और **मंगोलिया** सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच करार	14.09.2009		14.09.2009
52.	सांख्यिकी मामलों में सहयोग से संबद्ध क्षेत्र में भारत सरकार की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और **मंगोलिया** के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्याक्रम के बीच समझौता ज्ञापन	14.09.2009		14.09.2009
53.	**मोजाम्बिक** पारस्परिक विदेश संवर्द्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और **मोजाम्बिक** गणराज्य के बीच करार	19.02.2009	18.05.2009	
54.	**म्यांमा** निवेश संवर्द्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और संघीय म्यांमा की सरकार के बीच करार	24.06.2008	01.10.2008	05.02.2009
55.	**नाइजीरिया** भारतीय मानक ब्यूरो और नाइजीरिया के मानक संगठन के बीच समझौता ज्ञापन	04.09.2009		04.09.2009
56.	**पोलैंड** स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और पोलैंड गणराज्य की सरकार के बीच करार	24.04.2009		

परिशिष्ट **X**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
57.	पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और पोलैंड गणराज्य की सरकार के बीच करार	24.04.2009		
58.	**कतर** भारत गणराज्य की सरकार और कतर राज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	14.11.2009		
59.	**रोमानिया** पारस्परिक निवेश संवर्द्धन और संरक्षण से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और **रोमानिया** सरकार के बीच करार में संशोधन से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और **रोमानिया** सरकार के बीच प्रोतोकाल	16.02.2009	06.05.2009	
60.	राजनयिक मिशन या कांसुली केन्द्र के परिवार के सदस्यों को लाभकारी व्यवसाय के लिए प्राधिकरण से संबद्ध भारत सरकार और **रोमानिया** सरकार के बीच करार			17.09.2009
61.	**स्कॉटलैंड** भारत-स्कॉटलैंड नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग से संबद्ध भारत गणराज्य सरकार की नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और स्कॉटलैंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	14.10.2009		14.10.2009
62.	**सर्बिया** निवेश संवर्द्धन और संरक्षण से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और संघीय यूगोस्लाविया गणराज्य की संघीय सरकार के बीच करार	31.01.2003	05.05.2003	24.02.2009
63.	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और **सर्बिया** गणराज्य की सरकार के बीच करार	03.03.2009		
64.	**साओ टोमे एंड प्रिन्सिपे** भारत गणराज्य के सरकार की विदेश मंत्रालय और साओ टोमे एंड प्रिन्सिपे गणराज्य की विदेश मंत्रालय, सहयोग तथा समुदाय के बीच विचार-विमर्श से संबद्ध प्रोतोकाल	01.12.2009		
65.	**सिंगापुर** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और **सिंगापुर** गणराज्य की सरकार के बीच करार	03.08.2009		03.08.2009
66.	**स्पेन** अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत गणराज्य की नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और स्पेन अधिराज्य के उद्योग पर्यटन तथा व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	07.10.2009		
67.	कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में भारत गणराज्य के कृषि मंत्रालय और स्पेन अधिराज्य के पर्यावरण, ग्रामीण तथा मरिन मंत्रालय	23.04.2009		23.04.2009
68.	**सीरिया** तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध भारत और **सीरिया** के बीच समझौता ज्ञापन	14.01.2009		

परिशिष्ट **X**

क्र. सं.	अभिसमय/संधि/करार का शीर्षक	हस्ताक्षर की तारीख	अनुसमर्थन/ अधिमिलन/ स्वीकार्यता संबंधी दस्तावेज जमा करने की तारीख	लागू होने की तारीख
69.	**सिएरा लिओन** राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध भारत गणराज्य और **सिएरा लिओन** गणराज्य की सरकार के बीच करार	13.01.2009		
70.	**ताजिकिस्तान** भारत गणराज्य और **ताजिकिस्तान** गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण करार	14.11.2003	10.06.2005	18.02.2009
71.	**संयुक्त राज्य अमेरिका** सौर ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सौर ऊर्जा केन्द्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशाला के बीच समझौता ज्ञापन	23.11.09		23.11.09
72.	पवन ऊर्जा, अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशाला के बीच समझौता ज्ञापन	23.11.09		23.11.09
73.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिनव, उद्यमशीलता तथा व्यावसायीकरण क्रियाकलाप के लिए संयुक्त अनुसंधान तथा विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना से संबंधित भारत गणराज्य की सरकार और **संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार** के बीच करार	20.07.2009		20.07.2009
74.	भारत गणराज्य की सरकार के न्याय क्षेत्र और/या नियंत्रण के तहत सभी सुविधाओं पर प्रौद्योगिकी सुरक्षा तथा अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से संबंधित भारत गणराज्य की सरकार और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच करार	20.07.2009		20.07.2009
75.	जैव ईंधन के विकास में सहयोग से संबद्ध क्षेत्र में भारत गणराज्य की नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन	03.02.2009		03.02.2009
76.	**वियतनाम** वियतनाम के पूर्ण बाजार आर्थिक दर्जा के मान्यता से संबद्ध भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	21.10.2009		

परिशिष्ट **XI**

1 जनवरी, 2009 से दिसंबर, 2009 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए पूर्ण अधिकार के दस्तावेज

क्रम सं	अभिसमय/संधि	पूर्ण अधिकार की तिथि
1.	जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार तथा ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	15.01.2009
2.	वर्ष दो हजार नौ में जनवरी के छब्बीसवें दिन बॉन में अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईरेजा) की संविधि को अपनाया	20.02.2009
3.	पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और मोजाम्बिक गणराज्य के बीच करार	06.05.2009
4.	आय कर करों के दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और फिनलैंड गणराज्य के बीच प्रोतोकाल	08.07.2009
5.	व्यापक आर्थिक भागीदारी के संबंध में भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच करार	14.07.2009
6.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार	14.07.2009
7.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास, अभिनव, उद्यमशीलता और व्यावसायीकरण क्रियाकलाप के लिए एक बोर्ड व स्थायी निधी की स्थापना के लिए भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच करार	15.07.2009
8.	श्रम गतिशीलता भागीदारी पर भारत गणराज्य और डेनमार्क साम्राज्य के बीच समझौता ज्ञापन	31.07.2009
9.	भारत गणराज्य और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोगः समान करार में व्यापार के साथ-साथ इसके अनुबंध भी, विवाद निपटान प्रणाली पर करार, ढांचागत करार में संशोधन के लिए प्रोतोकाल और सामग्री करार व्यापार पर करार के अनुच्छेद 4 पर समझौता	07.08.2009
10.	सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत गणराज्य और लक्जमबर्ग के बीच करार	10.08.2009
11.	वियतनाम के पूर्ण बाजार आर्थिक हैसियत के मान्यता पर भारत गणराज्य और वियतनाम के समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	10.08.2009
12.	भारत गणराज्य की सरकार और कतर राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	12.11.2009
13.	निवेश संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य और कोलंबिया गणराज्य के बीच करार	09.11.2009
14.	बांस के उपयोग और अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत गणराज्य सरकार और कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, कोलम्बिया गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	09.11.2009
15.	निवेश संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य और कोलम्बिया गणराज्य के बीच करार	10.11.2009
16.	सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत गणराज्य और स्विस परिसंघ के बीच करार	20.10.2009

परिशिष्ट **XII**

1 जनवरी, 2009 से दिसंबर, 2009 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेज

क्र.सं.	अनुसमर्थन/अधिमिलन दस्तावेज	अनुसमर्थन जारी करने की तारीख
1.	सी-142 मानव संसाधन विकास अभिसमय, 1975	19.01.2009
2.	व्यापार नौवहन तथा अन्य समुद्री परिवहन संबंधित मामलों के क्षेत्र में भारत गणराज्य, ब्राजील गणराज्य के संघीय सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच त्रिपक्षीय करार	20.01.2009
3.	भारत गणराज्य और कजाखिस्तान गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि	13.02.2009
4.	पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और रोमानिया सरकार के बीच करार को संशोधित करने संबंधी भारत गणराज्य की सरकार और रोमानिया सरकार के बीच प्रोतोकाल	06.05.2009
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य की सरकार तथा चीली गणराज्य की सरकार के बीच करार	27.03.2009
6.	रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के सरकार तथ इटली गणराज्य की सरकार के बीच करार	27.03.2009
7.	सामाजिक बीमा के क्षेत्र में भारत गणराज्य और जमनी की संघीय गणराज्य के बीच करार	19.03.2009
8.	निवेश संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और पीपुल्स बांग्लादेश गणराज्य की सरकार के बीच करार	26.03.2009
9.	अंतर्राष्ट्रीय मालों को हवाई जहाज द्वारा ले जाने से संबंधित कुछ नियमों के एकीकरण के लिए अभिसमय (मांट्रियल अभिसमय,1999)	21.04.2009
10.	पारस्परिक निवेश संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य और मोजाम्बिक गणराज्य के बीच करार	18.05.2009
11.	भारत गणराज्य की सरकार और स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) के बीच मेजबान देश करार	22.06.2009
12.	सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत गणराज्य की सरकार और फ्रेंच गणराज्य की सरकार के बीच करार	22.05.2009
13.	आपराधिक मामलों से संबंधित पारस्परिक विधि सहयोग के क्षेत्र में विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में पीपुल्स चीन गणराज्य में भारत गणराज्य की सरकार और हॉगकॉग सरकार के बीच सरकार	19.10.2009
14.	आपराधिक मामलों से संबंधित पारस्परिक विधि सहयोग के क्षेत्र में भारत गणराज्य तथा बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच संधि	27.11.2009
15.	निवेश संवर्धन और संरक्षण के क्षेत्र में भारत गणराज्य और कोलम्बिया गणराज्य के बीच करार	27.11.2009

परिशिष्ट **XIII**

अवधि के दौरान नीति नियोजन तथा अनुसंधान प्रभाग द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वित्त पोषित की गई संस्थाओं/ गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित/आयोजित सम्मेलन/संगोष्ठियां/अध्ययन परियोजनाएं

क्र.सं.	कार्यक्रम	संस्थान/लाभाथा
1.	मिशन प्रमुखों का सम्मेलन, नई दिल्ली	नीति नियोजन तथा अनुसंधान प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
2.	पाक अधिकृत कश्मीर पर अनुसंधान परियोजना (5 वर्ष)	रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली
3.	'26/11 का आतंकवादः भारतीय विदेश नीति के लिए प्रभाव' विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी	विद्या प्रसारक मंडल, मुंबई
4.	नेपाल, चीन तथा पाकिस्तान पर तीन दिवसीय संगोष्ठियां (1 वर्ष)	एशिया केन्द्र, बेंगलोर
5.	राजीव गांधी की निरशस्त्रीकरण पहलः वैश्विक और दक्षिण एशियाई संदर्भ विषय पर संगोष्ठी	मदनजीत सिंह विश्वविद्यालय, पाण्डीचेरी
6.	नेहरू के जन्मदिन को 'एशिया एकता दिवस' के रूप में मनाना	एशिया एकता संघ, नई दिल्ली
7.	'भारत और अफ्रीकाः एक उभरती हुई भागीदारी' विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी	हिन्दी महासागर अध्ययन सोसाइटी (एसआईओएस) नई दिल्ली
8.	रु. 75,00,000/- की एक मुश्त वित्तीय सहायता	भारतीय अध्ययन केन्द्र, बीजिंग विश्वविद्यालय, बीजिंग
9.	कलकत्ता विश्वविद्यालय परिसर, अलीपुर में विदेश नीति अध्ययन संस्थान की स्थापना	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता
10.	'उपजाऊ अर्द्धचन्द्रः भारत और महान शक्तियां' विषय पर तीन दिवसयी संगोष्ठी	पश्चिम एशिया तथा अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11.	'भारत-अरब संबंधों के नए आयम' विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी	महाराजा महाविद्यालय, एर्नाकूलम
12.	द्वितीय चीन-दक्षिण एशिया मंच	विकासशील सोसाइटी अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली
13.	'तटीय सुरक्षाः नए आयाम की जरूरत' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल
14.	'भारत और एशिया प्रशांतः विषय पर संगोष्ठी'	दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत अध्ययन केन्द्र, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति
15.	राष्ट्रहित परियोजना (20 विषय)	अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर), नई दिल्ली
16.	वर्ष 2009 के दौरान आयोजित मासिक बैठकों पर व्यय के लिए वित्तीय सहायता	भारतीय राजनयिक संघ (एड), नई दिल्ली

परिशिष्ट **XIV**

आइटेक भागीदार देशों की सूची

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
1.	अफगानिस्तान	40.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
2.	अलबानिया	41.	जीबोती
3.	अलजीरिया	42.	डोमिनिकन गणराज्य
4.	अंगोला	43.	पूर्व तिमोर
5.	अंग्यूला	44.	इक्वाडोर
6.	एंटिगुआ और बारबुडा	45.	मिस्र
7.	अर्जेंटीना	46.	एलसल्वाडोर
8.	आर्मेनिया	47.	भूमध्यवर्ती गिनी
9.	अजरबैजान	48.	इरिट्रिया
10.	बहामास	49.	इस्टोनिया
11.	बहरीन	50.	इथिओपिया
12.	बांग्लादेश	51.	फिजी
13.	बारबाडोस	52.	गैबोन
14.	बेलारुस	53.	गाम्बिया
15.	बेलीज	54.	जॉर्जिया
16.	बेनिन	55.	घाना
17.	भूटान	56.	ग्रेनेडा
18.	बोलिविया	57.	ग्वाटेमाला
19.	बोस्नियाहर्जेगोविना	58.	गिनी
20.	बोत्सवाना	59.	गिनी बिस्साउ
21.	ब्राजील	60.	गुयाना
22.	ब्रुनई दारूसलम	61.	हैती
23.	बुलगारिया	62.	होंडुरास
24.	बुरकिना फासो	63.	हंगरी
25.	बुंडी	64.	इंडोनेशिया
26.	कम्बोडिया	65.	ईरान
27.	कैमेरुन	66.	ईराक
28.	केप वरडे द्वीप	67.	आइवरी कोस्ट
29.	कैमेन द्वीप	68.	जमैका
30.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	69.	जॉर्डन
31.	चाड	70.	कजाखस्तान
32.	चिली	71.	केन्या
33.	कोलम्बिया	72.	किरीबाती
34.	डोमिनिका राष्ट्रमण्डल	73.	कोरिया (डी पी आर के)
35.	कॉमोरोस	74.	किर्गिस्तान
36.	कोस्टा रिका	75.	लॉओस
37.	क्रोसिया	76.	लातविया
38.	क्यूबा	77.	लेबनान
39.	चेक गणराज्य	78.	लेसेथो

परिशिष्ट **XIV**

क्र.सं.	देश	क्र.सं.	देश
79.	लाईबेरिया	119.	रूस
80.	लिबिया	120.	रवान्डा
81.	लिथुआनिया	121.	समोआ
82.	मैसिडोनिया	122.	सेनेगल
83.	मैडागास्कर	123.	सर्बिया
84.	मलावी	124.	सेशल्स
85.	मलेशिया	125.	सियरा लियोन
86.	मालदीव	126.	सिगापुर
87.	माली	127.	स्लोवाक गणराज्य
88.	मार्शल द्वीप	128.	सोलोमान द्वीप
89.	मॉरीतानिया	129.	दक्षिण अफ्रीका
90.	मॉरीशस	130.	श्रीलंका
91.	मैक्सिको	131.	सेंट किटस तथा नेविस
92.	माइक्रोनेशिया	132.	सेंट लुसिया
93.	मोलडोवा	133.	सेंट विंसेंट तथा ग्रेनाडाइन्स
94.	मंगोलिया	134.	सूडान
95.	मानटिनिग्रो	135.	सूरीनाम
96.	मांटसेराट	136.	स्वाजीलैंड
97.	मोरक्को	137.	सिरिया
98.	मोजाम्बिक	138.	ताजिकिस्तान
99.	म्यामां	139.	तंजानिया
100.	नामीबिया	140.	थाइलैंड
101.	नारु	141.	टोगो
102.	नेपाल	142.	टोंगा
103.	निकारागुआ	143.	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो
104.	नाइजर	144.	टयूनीसिया
105.	नाइजेरिया	145.	तुर्की
106.	ओमान	146.	तुर्कमेनिस्तान
107.	पलावु	147.	तुर्क एवं कैकोस द्वीप
108.	फिलीस्तीन	148.	तुवालु
109.	पनामा	149.	यूगांडा
110.	पापुआ न्यू गिनी	150.	यूक्रेन
111.	परागुवे	151.	उरुग्वे
112.	पेरू	152.	उज्बेकिस्तान
113.	फिलीपीन्स	153.	वानुआतू
114.	पोलैंड	154.	वेनेजुएला
115.	कतर	155.	वियतनाम
116.	कांगो गणराज्य	156.	यमन
117.	साओ तोमे गणराज्य	157.	जाम्बिया
118.	रोमानिया	158.	जिम्बाब्वे

परिशिष्ट **XV**

पैनल में शामिल आइटेक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम	शहर
1.	संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो	नई दिल्ली
2.	सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान	नई दिल्ली
3.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रणाली लेखा परीक्षा केन्द्र	नोएडा
4.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (भारतीय मानक ब्यूरो)	नोएडा
6.	अपटेक लिमिटेड	नई दिल्ली
7.	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग	मोहाली
8.	सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग	नोएडा
9.	दूरसंचार प्रौद्योगिकी व प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए केन्द्र	मुम्बई
10.	सी.एम.सी. लिमिटेड	नई दिल्ली
11.	एन.आई.आई.टी. लिमिटेड	नई दिल्ली
12.	यू.टी.एल. प्रौद्योगिकी लिमिटेड	बैंगलूर
13.	भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज	हैदराबाद
14.	अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
15.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	अहमदाबाद
16.	अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
17.	भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान	अहमदाबाद
18.	राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान	नोएडा
19.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम संस्थान	हैदराबाद
20.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान	हैदराबाद
21.	अंग्रेजी व विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	हैदराबाद
22.	मानव पुनर्वास प्रबंधन संस्थान	नई दिल्ली
23.	भारतीय जनसंचार संस्थान	नई दिल्ली
24.	अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केन्द्र	कोलकाता
25.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	पुणे
26.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान	चेन्नई
27.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना व प्रशासनिक विश्वविद्यालय	नई दिल्ली
28.	विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली	नई दिल्ली
29.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान	नोएडा
30.	केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण संस्थान	फरीदाबाद
31.	केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतिकरण संस्थान	हैदराबाद
32.	केन्द्रीय औजार अभिकल्प संस्थान	हैदराबाद
33.	केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन	नई दिल्ली
34.	तरल नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	केरल
35.	भारतीय उत्पाद प्रबंधन संस्थान	उड़ीसा
36.	भारतीय सूदुर संवेदन संस्थान	देहरादून
37.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	रूड़की
38.	राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	पंजाब
39.	राईटस(रेलवे कार्मिकों के लिए पाठ्यकम)	गुड़गावॉ
40.	दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघ	कोयम्बटूर
41.	दी बेयरफूट कॉलेज	तिलोनिया, राजस्थान
42.	टेरी (ऊर्जा अनुसंधान संस्थान)	नई दिल्ली

परिशिष्ट **XVI**

संगोष्ठियां/सम्मेलन/व्याख्यान/बैठकें: अप्रैल 2009- मार्च 2010

क्रम सं	दिनांक	कार्यक्रम
निम्नलिखित घटनाएं अप्रैल, 2009 से जनवरी, 2010 तक पहले ही आयोजित हो चुकी है।		
व्याख्यान		
1.	29 जुलाई, 2009	डॉ. अहमद शाहिद, मालदीव गणराज्य के विदेश मंत्री द्वारा 'मालदीव में लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में भारत-मालदीव के संबंधों की दूरदर्शिता' पर व्याख्यान।
2.	4 सितंबर, 2009	'भारत और चीनः अतीत और भविष्य' पर प्रो. वी.पी.दत्त द्वारा व्याख्यान। अध्यक्षताः श्री शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव।
3.	6 नवंबर, 2009	'नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन ' पर श्री झाला नाथ खलन, अध्यक्ष, नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी, (यूएसएल) द्वारा वार्तालाप।
4.	11 नवंबर, 2009 को 1600 बजे	'कोलम्बिया और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य' पर कोलम्बिया गणराज्य के विदेश मंत्री डॉ. जेम बरमूदज द्वारा व्याख्यान। अध्यक्षताः डॉ. शशि थरूर, विदेश राज्य मंत्री
5.	12 नवंबर, 2009 को 1500 बजे	ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री व सांसद श्री केविन रुड द्वारा सामरिक मामलों पर मुख्य सम्बोधन। अध्यक्षताः डॉ. एम.एस. गिल, युवा मामले एवं खेल मंत्री (नई दिल्ली में आस्ट्रेलियाई उच्चायोग के सहयोग से)
6.	17 नवंबर, 2009 को 1100 बजे	ईरान के इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री श्री मनोचेहर मोताकी द्वारा व्याख्यान।
7.	शुक्रवार, 8 जनवरी, 2010 को 4.30 अपराह्न	ए.आई.डी. के 'वार्षिक व्याख्यान' पर 'भारत का विश्व में स्थान' विषय पर प्रो. लॉर्ड भिखू पारेख द्वारा व्याख्यान। मूख्य अतिथिः डॉ. शशि थरूर, माननीय विदेश राज्य मंत्री।
संगोष्ठी/सम्मेलन		
1.	9-10 अप्रैल, 2009	'दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। (मणिपाल विश्वविद्यालय के भूराजनीति विभाग के सहयोग से) (मणिपाल विश्वविद्यालय में संगोष्ठी)
2.	5 जून, 2009	'नेपाल' पर संगोष्ठी
3.	12 जून, 2009	'श्रीलंका पर संगोष्ठी'
4.	13 जुलाई, 2009	'राष्ट्रपति ओबामा का नया पश्चिम एशियाई नीतः संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर संगोष्ठी।
5.	12 जुलाई, 2009	'वर्तमान नेपाल और भारत-नेपाल संबंधों ' विषय पर संगोष्ठी।
6.	25 जुलाई, 2009	'अफगानिस्तान में भू-राजनैतिक दण्ड और भारत के हितों पर इसका प्रभाव' विषय पर संगोष्ठी। (बेंगलरू में संगोष्ठी) भारतीय विश्व कार्य परिषद और एशिया केन्द्र, बेंगलुरु द्वारा आयोजित।
7.	31 जुलाई, 2009	'वर्तमान इंडोनेशियाः चुनाव पश्चात लोकतंत्र, सैन्य और इस्लाम के पुनर्मूल्यांकन' विषय पर संगोष्ठी। मुख्य वक्ताः श्री बामबैण्ग हरिमूर्ति मुख्य संपादक, जकार्ता का टेम्पो पत्रिका।
8.	12 अगस्त, 2009	'सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनः बदलते समाज में संस्कृति का भविष्य' विषय पर माले (मालदीव) में संगोष्ठी। माले में भारत-मालदीव मैत्री सप्ताह के दौरान आयोजित घटनाओं का एक भाग। माले, मालदीव में संगोष्ठी
9.	25 अगस्त, 2009	'ईरान-जीसीसी संबंधः वर्तमान सक्रियता समझ' पर संगोष्ठी।
10.	8 सितंबर, 2009	'जलवायु परिवर्तन' पर संगोष्ठी अध्यक्षः श्री श्यामसरन, प्रधानमंत्री के विशेष दूत।
11.	29 अक्तूबर, 2009	'भारत और इसके पड़ोसी संबंधों के बदलते प्रक्षेप-पथ' विषय पर ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के राजनीतिक विज्ञान विभाग के सहयोग से एक दिवसीय संगोष्ठी। (हैदराबाद में संगोष्ठी)
12.	21-23 नवंबर, 2009	एशियाई संबंधों के सम्मेलन शृंखला 'उभरता चीनः एशिया में भागीदारी के लिए संभावनाएं' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।उद्घाटन सम्बोधनः श्री एम. हामिद अंसारी, भारत के उप राष्ट्रपति। समापन सम्बोधनः डॉ. शशि थरूर, विदेश राज्य मंत्री। झ्रशिया विद्वान संघ नई दिल्ली के सहयोग से, (आई.सी. डब्ल्यू की स्थापना दिवस की स्मृति में)
13.	3 दिसंबर, 2009	'भारत-अजरबैजान सहयोगः संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर अजरबैजान के साथ संयुक्त सम्मेलन (अजरबैजान के राष्ट्रीय दिवस के वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में अजरबैजान मिशन के सहयोग से) अजरबैजान के उप विदेश मंत्री और भारत में अजेरी राजदूत ने भाग लिया।

परिशिष्ट **XVI**

क्रम सं	दिनांक	कार्यक्रम
14.	7-9 दिसंबर, 2009	आई.सी. डब्ल्यू ए. में चीनी अध्ययन संस्थान ने भारत-चीन-रूस त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया। 7 दिसंबर, 2009 को रात्रि भोज की मेजबानी आई.सी.डब्ल्यू.ए. के महानिदेशक द्वारा की गई।
15.	19 दिसंबर, 2009	'भारत की प्रभावीपूर्ण नीति' विषय पर हिन्द महासागर अध्ययन सोसाइटी (एसआईओएपफ) कलकत्ता चाप्टर और दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशियाई अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय के सहयोग से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। स्थानः कोलकाता।
द्विपक्षीय वार्ताएं		
1.	20 अप्रैल, 2009	अफ्रीकी सम्पादकों के साथ इंटरएक्टिव सत्र।
2.	8 जून, 2009	श्रीलंकाई संपादकों के साथ मेल-मिलाप
3.	11 अगस्त, 2009	बांग्लादेश से आए संपादकों के साथ आईसीडब्ल्यूए में मेल-मिलाप
4.	16 सितंबर, 2009	इंडोनेशियाई संसद सदस्यों के साथ मेल-मिलाप
5.	18 सितंबर, 2009 (आईआईएस)	लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई मिशन अध्यक्षों के साथ आई.सी.डब्ल्यू.ए. और उनके देश में मौजूद समकक्ष संस्थानों के बीच सहयोग पर आई.आई.सी. में चर्चा पश्चात भोजन।
6.	8-9 अक्तूबर, 2009	'प्रभावी बहुपक्षवाद' विषय पर भारत-यूरोप मंच। मुख्य सम्बोधनः श्रीमती प्रेनीत कौर, विदेश राज्य मंत्री। झ्यूरोपीय संघ सुरक्षा अध्ययन संस्थान तथा यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधिमंडल के सहयोग सेट
7.	12-13 अक्तूबर, 2009	लॉवी संस्थान, ऑस्ट्रेलिया के साथ आईसीडब्ल्यूए का द्वितीय भारत-आस्ट्रेलिया गोलमेज।
8.	8-12 दिसंबर, 2009	भारत-रूस वार्ता। राजदूत एस.जे.एस. छटवाल के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आईसीडब्लयूए-एस.डी.आई.एम.ओ के वार्षिक वार्ता के लिए मास्को का दौरा किया।
9.	14 दिसंबर, 2009	नेपाल से आए वरिष्ठ पत्रकारों (सम्पादकों व संवाददाताओं) के प्रतिनिधिमंडल के साथ मेल मिलाप
10.	24 दिसंबर, 2009	थाइलैंड के विदेश मंत्री श्री कासित पिरोम्या के साथ मेल-मिलाप
11.	29 दिसंबर, 2009	दक्षिण -पूर्व एशिया तथा पूर्व एशिया अध्ययन, अमेरिकी विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सेवा विद्यालय, वाशिंगटन डी.सी. के प्रो. डॉ. अमीतव आचार्य और अंतर्राष्ट्रीय सेवा विद्यालय, अमेरिकी विश्वविद्यालय वाशिंगटन डी.सी, अमेरिका के दस छात्रों के साथ मेल-मिलाप अध्यक्षताः राजदूत रोनेन सेज, अमेरिका के लिए भारत के पूर्व राजदूत।
12.	19 जनवरी, 2009	चीन से आए वरिष्ठ संपादकों/पत्रकारों के साथ मेल-मिलाप अध्यक्षः राजदूत के. रघुनाथ, भारत के पूर्व विदेश सचिव।
13.	27-29 जनवरी, 2009	सामरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, (आईएसआईएस), मलेशिया के साथ भारत मलेशिया सामरिक वार्ता। स्थानः क्वालालम्पुर
पैनलः चर्चाएं/पृष्ठभूमि सार		
1.	30 अप्रैल, 2009	'क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण-पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य 'विषय पर आईसीडब्ल्यूए के भागीदारी के साथ भारतीय राजनयिक संघ द्वारा कार्यालयी चर्चा।
2.	2 दिसंबर, 2009	फिलीस्तीनी लोगों के साथ एकता की अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर समारोह। मुख्य अतिथिः डॉ. शशि थरूर, विदेश राज्य मंत्री।
3.	5-7 जनवरी, 2009	'भारत-जीसीसी संबंधों पर खाड़ी अनुसंधान केन्द्र (जीसीसी) दुबई के सहयोग से संयुक्त अनुसंधान परियोजना की बैठक संयुक्त अरब अमीरात में जी.आर.सी. लोक राजनय प्रभाग (पीडी), विदेश मंत्रालय और आई.सी.डब्ल्यू.ए के बीच समन्वय किया जा रहा है। झ राजदूत श्री रंजीत गुप्ता के साथ समन्वित
पुस्तक विमोचन आदि		
1.	19 जून, 2009	'लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण तथा दक्षिण एशिया में शांतः चुनौतियां और संभावनाएं' झ प्रो. नलिनी कान्त इस समकालिन अध्ययन इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में चेयर फा. राजीव गांधी द्वारा संपादितट पुस्तक का राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के अध्यक्ष तथा राजेन्द्र प्रसाद अकादमी के मानद निदेशक प्रो. बिमल प्रसाद द्वारा विमोचन।
2.	21 दिसंबर, 2009	'एक नई ऊर्जा सीमांतः बंगाल की खाड़ी क्षेत्र' पुस्तक पर चर्चा। (राजदूत सुधीर टी. देवरे, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए द्वारा संपादित) अध्यक्षः डॉ. विजय एल. केलकर, अध्यक्ष, भारतीय वित्त आयोग।

परिशिष्ट **XVI**

क्रम सं	दिनांक	कार्यक्रम
नियोजित क्रियाकलाप (फरवरी–मार्च, 2010)		
1.	4 फरवरी, 2010	'पश्चिमी बाल्कन के शांति, स्थिरता और समृद्धि' विषय पर स्लोवेनिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. डनीलो तुर्क द्वारा व्याख्यान।
2.	6 फरवरी, 2010	'बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम और भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ' विषय पर एशिया केन्द्र बेंग्लूर के सहयोग से संयुक्त सम्मेलन।
3.	11 फरवरी, 2010	भारत-क्यूबा संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में क्यूबा के राजदूत द्वारा सम्बोधन।
4.	फरवरी 2010 के मध्य में	आईसीडब्ल्यूए में चीनी अध्ययन संस्थान (आईसीएस) द्वारा सम्मेलन
5.	जनवरी-फरवरी, 2010	आईसीडब्ल्यूए में 'अफ्रीकी केन्द्र' को दुबारा चलाना।
6.	फरवरी, 2010	'एडवांसड स्ट्रेटेजिक स्टडीज केन्द्र (सीएएसएस), पूर्ण विश्वविद्यालय के साथ सम्मेलन। स्थानः पूणे हम सीएएसएस के साथ चर्चा में लगे हुए है और दिनांक तथा सटीक विषय बाद में दिसंबर में तय किया जाएगा।
7.	फरवरी 2010 के अंत में	'भारत के परमाणु नीति' पर सम्मेलन। (तिथियों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है)
8.	फरवरी के अंत-मार्च 2010 के प्रारंभ में	नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर सम्मेलन। (आशा है कि अफगान सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत का राजदूतावास, काबुल के परामर्श से किए जा रहे सम्मेलन में भाग लेगा।)
9.	फरवरी-मार्च, 2010	'केरल अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र' के सहयोग से सम्मेलन। स्थानः तिरुवंनतपुरम।
10.	फरवरी-मार्च, 2010	'एशिया अध्ययन संस्थान' हैदराबाद के साथ सम्मेलन।
11.	मार्च, 2010	'भारत का एशिया-प्रशांत और उत्तर-पूर्व में संबंध ' विषय पर प्रस्तावित सम्मेलन और 2010 के मध्य में इसको अंतिम रूप देने के साथ-साथ आयोजन स्थल (शिलौंग या गुवाहाटी) के बारे में उत्तर-पूर्व शिक्षाविदों और विद्वानों के साथ प्रारंभिक चर्चा के लिए आईसीडब्ल्यूए के एक प्रतिनिधिमंडल का सिक्किम में सिक्किम विश्वविद्यालय का दौरा। (सिक्किम का दौरा मार्च, 2010 में होगा)
12.	25-26 मार्च, 2010	दूरदर्शिता समूह लंदनः वैश्वीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (टीबीसी) लंदन में एक बुद्धजीवी दी एफ्रेड हरहोसन सोहसाइटी (डच बैंक्स का एक मंत्र) तथा पॉलिसी नेटवर्क ने दिल्ली में 25-26 मार्च, 2010 में होने वाले सम्मेलन के लिए 'बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका' विषय का प्रस्ताव रखा है। अनेक देशों से आए 40-50 विद्वानों तथा नीति निर्माताओं के दौरें का आयोजन तथा भुगतान पॉलिसी नेटवर्क करेगा। भारत के विभिन्न शहरों से लगभग 75-100 भारतीय प्रतिभागी भी भाग लेंगे।
13.	मार्च-अप्रैल, 2010	राष्ट्रमंडल पत्रकार संघ (दक्षिण एशिया चैप्टर) का सम्मेलन। स्थानः आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली।
14.		विदेश मंत्री के सुविधाजनक किसी तारीख को आईसीडब्ल्यूए में विदेश मंत्री के संबोधन के लिए प्रस्ताव।
15.		'भारत-म्यांमा संबंधों' पर राजदूत श्री आलोक सेन द्वारा भाषण चर्चा। स्थानः आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली।
16.		सिक्किम के राज्यपाल माननीय श्री बी.पी.सिह द्वारा भाषण। स्थानः आईसीडब्ल्यूए, नई दिल्ली।
17.		तुर्की सामरिक अनुसंधान केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर- नई दिल्ली में तुर्की के राजदूत के साथ हस्ताक्षर।
18.	2010 के आरंभ में	तुर्की सामरिक अनुसंधान केन्द्र के साथ वार्ता के लिए तुर्की जाने के लिए आईसीडब्ल्यूए प्रतिनिधमंडल। ऐसे दौरों के लिए तारीख पर विचार एसआरसीटी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के बाद ही किया जाएगा।
19.	2010 के आरंभ में	नाइजीरिया अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्थान के साथ वार्ता के लिए नाइजीरिया जाने के लिए आईसीडब्ल्यूए का प्रतिनिधिमंडल । नाइजीरिया में हमारे उच्चायुक्त के समन्वय के साथ तारीख को अंतिम रूप दिया जाएगा।
20.	2010 के पहली तिमाही में	आईसीडब्ल्यू-आईसीईएएस, सिंगापुर वार्ता। अनुसंधान, प्रकाशन इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग के विकास पर अगले वर्ष के आरंभ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है। नालंदा-श्रीविजया परियोजना का कई संगठनों के साथ-साथ आईएसईएएस द्वारा लिया जाना आईएसईएएस के साथ जुड़ने के लिए एक उपयुक्त विषय हो सकता है।

परिशिष्ट **XVII**

आरआईएस द्वारा आयोजित संगोष्ठिया

आरआईएस प्रकाशन

नीति पक्षसार

#44 कृषि उद्योग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का 'महायान': एक विश्व जन्म की प्रतिक्षा में, जनवरा 2010

#43 क्षेत्रीय किनेजियमः समय की मांग और इसका वर्तमान भारत के लिए प्रासंगिकता, सितंबर 2009।

#42 आईपीआर, अनुसंधान व विकास क्षमता और स्वास्थ्य परिचर्या भारत के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे।

#41 वित्तीय संकट, वैश्विक आर्थिक शासन और विकासः एशिया और दक्षिण वैश्विक की प्रतिक्रिया, फरवरी 2009

विचार-विमर्श संबंधी कागजात

#146 विकासशील देशों में पशुधन औद्योगीकरण, व्यापार और सामाजिक-स्वास्थ्य पर्यावरण का प्रभावः भारतीय मुर्गी पालन क्षेत्रों का एक मामला, राजेश मेहता, क्लेयर ए. नारोड और मारिट्स एम. आइओंग्को के द्वारा।

#147 पूर्व एशिया में भारत की भूमिकाः सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों से जुड़े पाठ, ईलेन एल. फ्रोस्ट के द्वारा।

#148 भारत का चीन के तुलनात्मक परिप्रेक्षण में इस्पात उद्योग में बाहरी विदेश में प्रत्यक्ष निवेश, नागेश कुमार और अल्का चड्डा द्वारा।

#149 भारत में गरीबी उन्मूलनः सशक्तिकरण में प्रयोग से पाठ, नील पाण्डेय द्वारा।

#150 चीन तथा मैक्सिको में औद्योगिक नीति अधिशम, केवीन पी, गलाधर और एम. सफैदिन द्वारा।

#151 विकासशील देशों में पेटेंट प्रणाली कौन प्रयोग करता है? अर्जेंटीना में पेटेंट प्रवृत्ति का अध्ययन, 1992-2001, एएड्रेस लोपेज तथा यूजीनिया ओरलीकी द्वारा।

#152 कृषि व्यापार उदारीकरण के सीमित वादो टीमार्थी ए. वाईज द्वारा।

#153 जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक सम्पदा अधिकार, के. रवि श्रीनिवास द्वारा।

#154 व्यापार सरलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और एस.एम.ई.एसः भारत से उभरते तथ्य/सबूत, सचिन चतुर्वेदी द्वारा।

#155 वैश्वीकरण के दोषों पर संबोधन, जैन प्रौंक द्वारा

#156 यूरोपीय यूनियन का प्रस्तावित कार्बन समकारी प्रणाली क्या यह विश्व व्यापार संगठन के संगत हो सकता है?

#157 दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणः संभावनाएं और चुनौतियां, राम उपेन्द्र दास द्वारा।

#158 भारतीय अर्थव्यवस्था सामना करी जोखिम का प्रबंधनः एक बेहतर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य संतुलन की ओर, रामगोपाल अग्रवाल द्वारा।

#159 भारत का दवाइयों और फार्मेसी में व्यापारः उभरते आयाम, संभावनाएं और चुनौतियां रेजी के जोसेफ द्वारा।

#160 क्षेत्रीय अवसंरचना विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोगः दक्षिण एशिया के लिए चुनौतियां और नीति विकल्प, प्रवीर डे द्वारा।

पत्रिकाएं

1. दक्षिण एशिया आर्थिक पत्रिका (संकरणः 10 से-1), जनवरी-जून 2009
2. एशियाई जैव प्रौद्योगिकी तथा विकास समीक्षा, (संस्करणः 11(3) जुलाई, 2009
3. (संस्करणः 11 (2) मार्च, 2009
4. न्यू एशिया मॉनिटर, सं. 6, सं. 3, जुलाई, 2009
5. न्यू एशिया मॉनिटर, सं. 6, सं. 1-2 अप्रैल, 2009
6. मीकाँग-गंगा पॉलिसी, ब्रीफ सं. 4 मार्च, 2009

न्यूजलेटर

आर.आई.एस. डायरी, वोलूयम सं. 7 1-2 अप्रैल 2009

संक्षिप्तियाँ

आल्को	एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शी संगठन
एएमएम	आसियान मंत्रिस्तरीय बैठक
एआरएफ	आसियान क्षेत्रीय मंच
आसियान	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन
एएसईएम	एशिया यूरोप बैठक
एसोचैम	एसोसिएट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री
एयू	अफ्रीकी संघ
आयुष	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथिक
बिमस्टेक	बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल
सीसीआईटी	अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन
सीका	व्यापक आर्थिक सहयोग करार
सीईपी	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
चोगम	राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक
सीआईसी	केन्द्रीय सूचना आयोग
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएस	स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल
कोमेसा	पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार
कॉरपट	समन्वित गश्ती
सीओएससी	चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी
सीपीआईओ	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकार
सीपीवी	कोंसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा
सीआरआरआईडी	ग्रामीण और औद्योगिक विकास शोध केन्द्र
सीएससीएपी	एशिया प्रशांत सुरक्षा सहयोग परिषद
सीएसडी	व्यापक सुरक्षा वार्ता
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीएसएससी	रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज
डीटीएसी	दोहरा कराधान परिहार अभिसमय
ईएसी	पूर्व अफ्रीकी समुदाय
ईएएस	पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन
इकोवास	पश्चिम अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय
ईआईएल	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
ईएमएम	पूर्व एशिया मंत्री बैठक
ईयू	यूरोपीय संघ
एक्जिम	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ
एफआईपीबी	विदेश कार्यालय परामर्श
एफओसी	विदेश कार्यालय परामर्श
एफटीए	मुक्त व्यापार करार
गेल	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड
जीसीसी	खाड़ी सहयोग परिषद
जीएसटी	सामान एवं सेवा कर
एचएएल	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड
एचआईवी/एड्स	ह्यूमन ईम्यनो वायरस/एक्वयर्ड इम्यूनो डिफिसिएंसी सिण्ड्रोम
आईएईए	अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
आईएटीटी	अन्तर- एजेंसी कार्य दल
आईबीएफ	भारतीय व्यवसाय मंच
आईबीईएफ	इंडियन ब्रैंड इक्विटी मंच
आईसीसीआर	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
आईसीआरआईईआर	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईसीडब्ल्यूए	भारतीय मामलों की विश्व परिषद
आईडीएसए	रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान
आईएफएस	भारतीय विदेश सेवा
आईआईबीएफ	भारतीय बैंकिंग एवं विश्व संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
पीडीआईएल	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

संक्षिप्तियाँ

फार्म एक्जिम	भारतीय फार्मास्युटिकल निर्यात प्रोत्साहन परिषद
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएनएस	भारतीय नौसैनिक पोत
आईएनएसटीसी	अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-दीक्षण परिवहन गलियारा
आईएनटीओएसएआई	इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन आफ सुप्रिम आडिट इन्स्टीट्यूशंस
आईआरईएनए	अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी
आईओएनएस	इंस्टीट्यूट आफ नोएटिक साइसेंज
आईओआर-एआरसी	हिन्द महासागर परिधि क्षेत्रीय सहयोग संघ
आईएससीएस	अंतरराज्य परिषद सचिवालय
आईटेक	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्यकारी दल
एलएनजी	तरल प्राकृतिक गैस
मर्कोसुर	दक्षिणी शंकु देश बाजार
एमएफएन	अत्यंत अनुकूल राष्ट्र
एमओयू	समझौता ज्ञापन
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
नेफेड	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहयोग विपणन परिसंघ लिमिटेड
नाम	गुट-निरपेक्ष आन्दोलन
नास्कोम	राष्ट्रीय साफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ
नाटो	उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
एनईएलपी	नई दोहन लाइसेंसिंग नीति
नेपाड	अफ्रीकी विकास के लिए नई भागीदारी
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
एनएससी	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
एनएसजी	नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह
ओसीआई	भारतीय समुद्रपारीय नागरिकता
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओएनजीसी	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम
पीआईओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
राइट्स	रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस
आरटीआई	सूचना का अधिकार
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
एसएडीसी	दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय
साफ्टा	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एस्कैप	अफ्रीकी कार्यक्रम के लिए विशेष राष्ट्रमण्डल सहायता
एससीओ	शंघाई सहयोग संगठन
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेवा	स्व-नियोजित महिला संघ
एसईजेड	विशेष आर्थिक सत्र
एसएमई	लघु एवं मझोले उद्यम
एसटीपीआई	भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
टीम-9	टेक्नो-इकोनॉमिक अप्रोच फार अफ्रीका इण्डिया मूवमेंट
टेकेस	टेक्नोलाजियन केहीटा मिस्केस
टेरी	टाटा ऊर्जो अनुसंधान संस्थान
अंकटाड	व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यूनेस्को	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
यूएनजीए	संयुक्त राष्ट्र महासभा
यूएनएससी	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूपीए	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
वीएसएनएल	विदेश संचार निगम लिमिटेड
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन